

का. मार्क्स फ्रे. एंगेल्स

संकलित रचनाएं
तीन खण्डों में

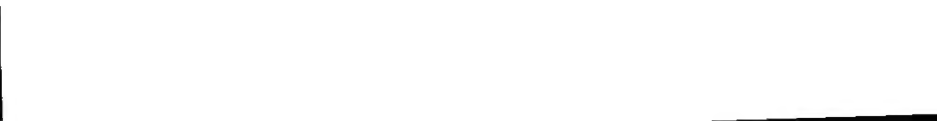
खण्ड २
भाग २

Q

2

3

4



दुनिया के मज़दूरो, एक हो!

अनुवादक और संपादक: सुरेन्द्र कुमार

□

प्रकाशक की ओर से

इस संग्रह में जो कृतियां शामिल हैं उनका अनुवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स की संकलित रचनाओं के तीन खण्डों वाले संस्करण (खण्ड २) के मुताबिक किया गया है।

पाठकों की सुविधा के लिए इस खण्ड को दो भागों में बांटा गया है।

К. МАРКС, Ф. ЭНГЕЛЬС

Избранные произведения

в 3-х томах,
том II, часть 2
на языке хинди

© हिन्दी अनुवाद • प्रगति प्रकाशन • १९७७

सोवियत संघ में मुद्रित

М $\frac{10101-133}{016(01)-77}$ 636-77

विषय-सूची

फ्रे० एंगेल्स। मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्रिया के बारे में। २१ सितंबर १८७१ को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के लंदन सम्मेलन में दिया गया भाषण	६
का० मार्क्स तथा फ्रे० एंगेल्स। इंटरनेशनल में कल्पित फूट। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जनरल कौंसिल का एक गुप्त परिपत्र	११
१	११
२	१५
३	२६
४	३५
५	५१
६	५४
७	५६
का० मार्क्स। पेरिस कम्यून की जयन्ती सभा के प्रस्ताव	६४
का० मार्क्स। भूमि का राष्ट्रीयकरण	६६
का० मार्क्स तथा फ्रे० एंगेल्स। हेग में हुई जनरल कांग्रेस के प्रस्तावों का एक अंश	७०
का० मार्क्स। हेग कांग्रेस। एम्स्टरडम में ८ सितम्बर १८७२ को आयोजित सभा में किये गये भाषण का सम्वाददाता द्वारा लिखित रूप	७१

फ्रे० एंगेल्स। आवास प्रश्न	७४
१८८७ के दूसरे संस्करण की भूमिका	७४
आवास प्रश्न	८६
भाग १। प्रुदों आवास प्रश्न किस तरह हल करते हैं	८६
भाग २। पूंजीपति वर्ग आवास प्रश्न किस तरह हल करता है	११०
१	११०
२	१२७
३	१४५
भाग ३। प्रुदों तथा आवास प्रश्न पर परिशिष्ट	१४६
१	१४६
२	१५५
३	१६६
४	१७२

फ्रे० एंगेल्स। सत्ता के सम्बन्ध में	१७८
---	-----

फ्रे० एंगेल्स। कम्यून के ब्लॉकीपथी 'उत्प्रवासियों का कार्यक्रम (' उत्प्रवासी साहित्य' लेखमाला का दूसरा लेख)	१८३
--	-----

फ्रे० एंगेल्स। रूस में सामाजिक सम्बन्धों के विषय में (' उत्प्रवासी साहित्य' लेखमाला का पांचवां लेख)	१६२
--	-----

'रूस में सामाजिक सम्बन्धों के विषय में' लेख का परिशिष्ट	२०६
---	-----

का० मार्क्स। बकूनिन की 'राज्यत्व तथा अराजकता' पुस्तक पर टिप्पणियों से	२२२
---	-----

का० मार्क्स तथा फ्रे० एंगेल्स। चिट्ठी-पत्रों	२२५
--	-----

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र, २३ फ़रवरी १८६५	२२५
लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र, ६ अक्टूबर १८६६	२३०
लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र, ११ जुलाई १८६८	२३२
लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र, १२ अप्रैल १८७१	२३४
लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र, १७ अप्रैल १८७१	२३६
फ्रेडरिक बोल्ते के नाम मार्क्स का पत्र, २३ नवम्बर १८७१	२३७

थियोदोर कुनो के नाम एंगेल्स का पत्र, २४ जनवरी १८७२	२४०
अगस्त बेबेल के नाम एंगेल्स का पत्र, २० जून १८७३	२४६
फ्रेडरिक अडोल्फ ज़ोर्गे के नाम एंगेल्स का पत्र, १२ [—१७] सितम्बर १८७४	२५१

टिप्पणियाँ	२५३
----------------------	-----

नाम-निर्देशिका	२७७
--------------------------	-----

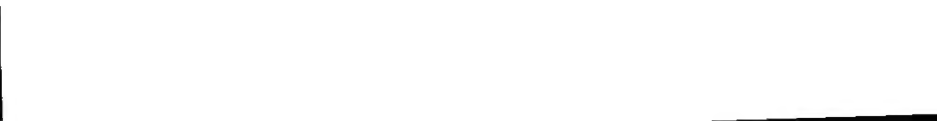
साहित्यिक और पौराणिक पात्रों की सूची	२६५
--	-----

Q

2

3

4



मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्रिया के बारे में

२१ सितंबर १८७१ को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के लंदन सम्मेलन में दिया गया भाषण^१

राजनीतिक क्रिया से सर्वथा विरत रहना असंभव है। विरतिवादी समाचारपत्र राजाना राजनीति में भाग लेते हैं। प्रश्न केवल यह है कि आप राजनीति में कैसे भाग लेते हैं और किस प्रकार की राजनीति में भाग लेते हैं। बाक़ी बात यह है कि हमारे लिए राजनीति से विरत रहना असंभव है। अब तक अधिकांश देशों में मजदूर वर्ग की पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करने लगी है, और हमारा काम यह नहीं है कि राजनीति से विरत रहने का प्रचार करके उसे चौपट कर डालें। जीवन्त अनुभव, मौजूदा सरकारों का राजनीतिक उत्पीड़न मजदूरों को राजनीति में दख़ल देने के लिए विवश करता है, चाहे वे इसे चाहें या न चाहें, चाहे वे ऐसा राजनीतिक लक्ष्यों के लिए करें या सामाजिक। उन्हें राजनीति से विरत रहने का उपदेश देकर हम उन्हें पूंजीवादी राजनीति के जाल में फंसा देंगे। पेरिस कम्यून के बाद, जिसने सर्वहारा की राजनीतिक क्रिया को आज की कार्यसूची में दाख़िल कर दिया, राजनीति से विरत रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

हम वर्गों का उन्मूलन चाहते हैं। इसे पूरा करने का क्या साधन है? इसका एकमात्र साधन सर्वहारा का राजनीतिक प्रभुत्व है। फिर भी अब, जब सभी इस बात को मानते हैं, हमसे कहा जाता है कि हम राजनीति में दख़ल न दें! विरतिवादी कहते हैं कि वे क्रांतिकारी हैं, यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी हैं। लेकिन क्रांति राजनीतिक क्रिया की पराकाष्ठा है और जो लोग क्रांति चाहते हैं वे उसे सम्पन्न करने के साधन, अर्थात् राजनीतिक क्रिया के प्रति उदासीन नहीं हो सकते। इस क्रिया से ही क्रांति के लिए ज़मीन तैयार होती है और मजदूरों

को वह क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त होता है, जिसके बिना वे लड़ाई के दूसरे ही दिन फ्राव तथा प्यात जैसे लोगों के धोखे में आये बिना नहीं रह सकते। मगर यह जरूर है कि हमारी राजनीति मजदूर वर्ग की राजनीति होनी चाहिए; मजदूर पार्टी को किसी पूँजीवादी पार्टी का दुमछल्ला कभी नहीं होना चाहिए; वह स्वाधीन होनी चाहिए, उसका अपना लक्ष्य, अपनी नीति होनी चाहिए।

राजनीतिक स्वातंत्र्य—सभा और संघ स्वातंत्र्य तथा प्रेस स्वातंत्र्य—ये हमारे अस्त्र हैं। जब कोई हमारे इन अस्त्रों को चुरा लेने की कोशिश करता है तब क्या हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और राजनीति से विरत रहें? कहा जाता है कि अगर हम कोई राजनीतिक कार्रवाई करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मौजूदा वस्तुस्थिति को स्वीकार करते हैं। परन्तु जब तक मौजूदा वस्तुस्थिति हमें उसका प्रतिवाद करने का साधन प्रदान करती है, तब तक इन साधनों को इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि हम मौजूदा वक्त में हावी व्यवस्था को स्वीकार करते हैं।

पहली बार 'कम्युनिस्ट
इंटरनेशनल' पत्रिका, अंक २६,
१९३४, में प्रकाशित।

अंग्रेजी से अनूदित।

इंटरनेशनल में कल्पित फूटें

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जनरल कौंसिल का एक गुप्त परिपत्र

जनरल कौंसिल इंटरनेशनल के आन्तरिक कलहों में हस्तक्षेप से अब तक बिल्कुल अलग रही है और उसने संघ के कुछ सदस्यों द्वारा उस पर दो वर्षों से अधिक समय से किये जा रहे प्रत्यक्ष प्रहारों का कभी सार्वजनिक रूप से उत्तर नहीं दिया।

परन्तु यदि बात इंटरनेशनल और एक ऐसी सोसायटी * के बीच, जो अपने जन्म से ही उसके प्रति वैरभाव रखती आ रही है, गलतफहमी कायम रखने की चन्द दस्तंदाजों की लगातार कोशिशों तक सीमित होती तो जनरल कौंसिल चुपपी साधे रहती, परन्तु अब ऐसे समय, जब इंटरनेशनल अपनी स्थापना के बाद से सबसे गम्भीर संकट के बीच से गुजर रहा है, उस सोसायटी द्वारा फैलायी जा रही बदनामी से यूरोपीय प्रतिक्रियावाद को प्राप्त समर्थन जनरल कौंसिल को विवश करता है कि वह इन तमाम तिकड़मों की ऐतिहासिक समीक्षा प्रस्तुत करे।

पेरिस कम्यून की पराजय के बाद जनरल कौंसिल ने पहला काम यह किया कि उसने फ्रांस में गृहयुद्ध ** के सम्बन्ध में अपनी चिट्ठी प्रकाशित की जिसमें उसने कम्यून की उन तमाम कार्यवाइयों का समर्थन किया जो उस समय यूरोप के

* समाजवादी जनवाद क अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध। - सं०

** देखें प्रस्तुत खण्ड। - सं०

पूँजीपति वर्ग, अखबारों तथा तमाम सरकारों के लिए परास्त पेरिसवासियों पर धिनौने से धिनौना कीचड़ उछालने का बहाना बनी हुई थीं। स्वयं मजदूर वर्ग के अन्दर कुछ लोग अब भी यह समझने में असमर्थ थे कि उनके ध्येय की पराजय हो चुकी है। कौंसिल ने यह तथ्य अन्य बातों के अलावा अपने दो सदस्यों, नागरिकगण ओडजर तथा लेक्राफ़्त के इस्तीफ़े से अनुभव कर लिया था जिन्होंने इस चिट्ठी के साथ एकजुटता को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। कहा जा सकता है कि पेरिस की घटनाओं के विषय में मजदूर वर्ग के बीच विचारों की एकता तमाम सभ्य देशों में चिट्ठी के प्रकाशन के समय से शुरू हुई थी।

दूसरी ओर इंटरनेशनल ने पूँजीवादी अखबारों और विशेष रूप से प्रमुख अंग्रेज़ी समाचारपत्रों को प्रचार का एक सशक्त साधन पाया, जिन्हें चिट्ठी ने जनरल कौंसिल के उत्तरों द्वारा चलाये जाते रहनेवाले वाद-विवाद में भाग लेने के लिए विवश किया।

बहुत बड़ी संख्या में कम्यून के उत्प्रवासियों के लन्दन में आगमन ने जनरल कौंसिल के लिए यह आवश्यक बना दिया कि वह स्वयं राहत समिति बन जाये और अन्य कर्त्तव्यों की पूर्ति के अलावा आठ माह से अधिक समय तक यह कार्य करे। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि कम्यून के परास्त तथा निर्वासित लोग पूँजीपति वर्ग से कोई आशा नहीं कर सकते थे। जहाँ तक मजदूर वर्ग का सम्बन्ध है, सहायता की अपीलें बहुत कठिन समय में की गयी थीं। उत्प्रवासी काफ़ी बड़ी तादाद में स्विट्ज़रलैंड तथा बेल्जियम में पहुँच चुके थे जिनके लिए उन्हें या तो गुज़र-बसर की व्यवस्था करनी पड़ती थी या लन्दन भोजना पड़ता था। जर्मनी, आस्ट्रिया और स्पेन में जमा की गयी धनराशियां स्विट्ज़रलैंड भेजी जाती रहीं। इंग्लैंड में नौ घंटे के कार्य-दिवस के लिए बहुत बड़ी लड़ाई ने, जो निर्णायक रूप से न्यूकैसल^२ में लड़ी गयी थी, मजदूरों के निजी चन्दों तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा स्थापित कोषों को खर्च कर दिया था, जिन्हें प्रसंगतः नियमानुसार केवल श्रम संघर्षों के लिए खर्च किया जाना चाहिए था। इस बीच कौंसिल परिश्रमपूर्वक कार्य करते हुए तथा चिट्ठियां भेजते हुए ज़रा-ज़रा कर धन जमा करने में सफल रही जिसे वह साप्ताहिक रूप में वितरित करती थी। अमरीकी मजदूरों ने उसकी अपील का उदारतापूर्वक उत्तर दिया। यह अफ़सोस की बात है कि कौंसिल को वह करोड़ों की पूँजी प्राप्त नहीं थी जिसके बारे में भयभीत पूँजीपति वर्ग का विश्वास था कि उसे इंटरनेशनल ने अपनी तिजोरियों में जमा कर रखा है!

मई १८७१ के बाद कम्यून के कुछ उत्प्रवासियों से कौंसिल में शामिल होने के लिए कहा गया जिसमें युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था। नये सदस्यों में इंटरनेशनल के कुछ पुराने लोग तथा अपनी क्रान्तिकारी स्फूर्ति के लिए प्रसिद्ध वे चन्द लोग थे जिनका चुनाव पेरिस कम्यून के प्रति श्रद्धांजलि था।

इन तमाम व्यस्तताओं के साथ कौंसिल को सम्मेलन^३ के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही थी जिसे बुलाने की उसने अभी-अभी घोषणा की थी।

इंटरनेशनल के विरुद्ध बोनापार्टी सरकार की उग्र दमनात्मक कार्यवाइयों ने पेरिस में सम्मेलन नहीं होने दिया जिसकी बाज़ेल कांग्रेस^४ के एक प्रस्ताव में व्यवस्था की गयी थी। जनरल कौंसिल ने नियमावली की धारा ४ में दिये गये अधिकार का उपयोग करके १२ जुलाई १८७० के अपने परिपत्र द्वारा कांग्रेस माईत्स में बुलाई। उसी समय विभिन्न संघों* के नाम भेजी गयी चिट्ठियों में उसने प्रस्ताव किया कि जनरल कौंसिल इंग्लैंड से किसी अन्य देश को स्थानान्तरित की जाये और उसने मांग की कि डेलीगेटों को इस आशय के निश्चित अधिदेश दिये जायें। संघों ने सर्वसम्मति से इस बात पर जोर दिया कि जनरल कौंसिल लंदन में ही रहे। चन्द दिन बाद शुरू होनेवाले फ्रांस-प्रशा युद्ध^५ ने कांग्रेस आयोजित करने के विचार का परित्याग करना आवश्यक बना दिया। फिर संघों ने, जिनसे हमने परामर्श किया था, हमें राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की अगली तिथि निश्चित करने का अधिकार दिया था।

ज्योंही राजनीतिक स्थिति अनुकूल हुई, जनरल कौंसिल ने १८६५ के सम्मेलन^६ तथा प्रत्येक कांग्रेस की गुप्त प्रशासनिक सभाओं के पूर्व उदाहरणों का अनुकरण करते हुए एक गुप्त सम्मेलन बुलाया। ऐसे समय, जब यूरोपीय प्रतिक्रियावाद आनन्दोत्सव मना रहा था; जब जूल फ़ाब्र तमाम सरकारों से, यहां तक कि ब्रिटिश सरकार से भी उत्प्रवासियों का साधारण मुजरिमों की तरह प्रत्यर्पण करने की मांग कर रहा था; जब दूफ़ो देहातियों की सभा^७ से इंटरनेशनल पर पाबन्दी लगाने का क़ानून पास करने का प्रस्ताव कर रहा था जिसका पाखण्डपूर्ण नकली रूप आगे चलकर मालू ने बेल्जियमवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया था; जब स्विट्ज़रलैंड में कम्यून के एक उत्प्रवासी को प्रत्यर्पण के बारे में संघीय सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा करते समय निरोधक नज़रबन्दी के अन्तर्गत बन्दीगृह में

* कार्ल मार्क्स, 'तमाम शाखाओं के लिए गुप्त सन्देश'। - सं०

रखा गया था ; जब इंटरनेशनल के सदस्यों का पीछा करना व्योइस्ट और बिस्मार्क के बीच संघर्षता का प्रत्यक्ष आधार था जिसकी इंटरनेशनल विरोधी दिशा को विक्टर-एमानुईल ने चटपट अंगीकार कर लिया था ; जब स्पेनिश सरकार अपने को पूरी तरह वेर्साई के वधिकों^८ के हाथों में सौंपते हुए मैड्रिड संघीय कौंसिल को पुर्तगाल में शरण ढूंढने के लिए विवश कर रही थी ; अन्ततः ऐसे समय जब इंटरनेशनल का प्रथम कर्त्तव्य अपना संगठन मजबूत बनाना और सरकारों द्वारा दी गयी चुनौती को स्वीकार करना था , ऐसे समय खुली कांग्रेस बुलाना असम्भव था और उसका केवल यही फल निकलता कि महाद्वीप के डेलीगेट सरकारों के हाथों में सौंप दिये जाते ।

जनरल कौंसिल के साथ नियमित सम्पर्क में रहनेवाली तमाम शाखाओं को सम्मेलन में भाग लेने के लिए ठीक समय पर आमंत्रित कर दिया गया था जिसे खुली बैठक न होने के बावजूद गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था । फ्रांस , निस्सन्देह आन्तरिक स्थिति के कारण कोई डेलीगेट चुनने में असमर्थ था । इटली में उस समय एकमात्र संगठित शाखा नेपल्स की थी परन्तु वह डेलीगेट चुनने ही वाली थी कि उसे सेना ने भंग कर दिया । आस्ट्रिया तथा हंगरी में सबसे सक्रिय सदस्य जेलों में ठूस दिये गये । जर्मनी में कुछ अधिक विख्यात सदस्यों को घोर राजद्रोह के अभियोग में दमन का शिकार बनाया गया , दूसरे जेलों में थे और पार्टी का कोष उनके परिवारों के सदस्यों को मदद देने पर खर्च किया गया । अमरीकियों ने हालांकि अपने यहां इंटरनेशनल की स्थिति पर सम्मेलन के नाम एक विस्तृत ज्ञापन भेजा , उन्होंने प्रतिनिधिमंडल पर होनेवाले व्यर्थ की राशि उत्प्रवासियों की सहायता देने के लिए इस्तेमाल की । वस्तुतः सभी संघों ने खुली कांग्रेस की जगह गुप्त सम्मेलन करने की आवश्यकता स्वीकार की ।

१८७१ में लन्दन में १७ से २३ सितम्बर तक हुए सम्मेलन ने जनरल कौंसिल को अपने प्रस्ताव प्रकाशित करने , प्रशासनिक अधिनियमों को संहिताबद्ध करने और उन्हें संशोधन तथा सुधार करने के बाद आम नियमावली * के साथ तीन भाषाओं में छापने , सदस्यता-कार्ड की जगह स्टाम्प्स लगाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने , इंग्लैंड में^९ इंटरनेशनल का पुनर्गठन करने और अन्ततः इन विविध उद्देश्यों के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करने का अधिकार दिया ।

* देखें प्रस्तुत संस्करण , खण्ड २ , भाग १।-सं०

सम्मेलन की कार्यवाही के प्रकाशन के बाद पेरिस और मास्को, लन्दन तथा न्यूयार्क के प्रतिक्रियावादी अखबारों ने मजदूर वर्ग की नीति-सम्बन्धी प्रस्ताव* की भर्त्सना करते हुए उसे ऐसे खतरनाक संसूचों से—«Times»¹⁰ ने तो उस पर “खूब सोची-समझी ढिठाई” दिखाने का आरोप लगाया—भरा हुआ बताया जो इंटरनेशनल को शीघ्रातिशीघ्र गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरी ओर, कपटपूर्ण संकीर्णतावादी शाखाओं¹¹ पर प्रहार करने वाले प्रस्ताव ने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस को मजदूरों की, जिन्हें वह जनरल काँसिल तथा सम्मेलन की घृणित निरंकुशता से बचाने का दम भरती थी, प्रतीयमान अप्रतिबन्धित स्वायत्तता के वास्ते शोरगुल द्वारा मुहिम चलाने का वह बहाना दिया जिसका देर से इन्तजार था। मजदूर वर्ग अपने को निस्संदेह जनरल काँसिल द्वारा “इतना अधिक उत्पीड़ित” अनुभव कर रहा था कि उसे यूरोप, अमरीका, आस्ट्रेलिया, ईस्ट इंडीज तक से इंटरनेशनल में नये सदस्यों की भर्ती तथा नयी शाखाओं की स्थापना के बारे में रिपोर्टें मिलती रहीं।

२

अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस के विलाप की तरह पूंजीवादी अखबारों में की गयी भर्त्सनाओं को हमारे संघ तक में सहानुभूतिपूर्ण प्रतिध्वनि प्राप्त हुई। संघ के अन्दर कुछ तिकड़में रची गयीं जो दिखावे के लिए जनरल काँसिल के विरुद्ध परन्तु वस्तुतः संघ के विरुद्ध लक्षित थीं। इन तिकड़मों की तह में हमेशा समाजवादी जनवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध होता जो रूसी मिखाईल बकूनिन का शिशु था। बकूनिन ने साइबेरिया से लौटने के बाद हर्ज़ेन की पत्रिका ‘कोलोकोल’ में अपने धम्बे अनुभव के बाद परिकल्पित सर्वस्लाववाद तथा नस्ल युद्ध के विचारों का प्रचार किया।¹² आगे चलकर स्विट्ज़रलैंड में अपने प्रवास के दौरान उन्हें इंटरनेशनल के मुकाबले में स्थापित शान्ति तथा स्वतंत्रता लीग¹³ की संचालन समिति का प्रधान मनोनीत किया गया। जब इस पूंजीवादी संस्था के हालात बिगड़ते चले गये, उसके अध्यक्ष श्री जी० फ्रोंट ने बकूनिन के सुझाव पर इंटरनेशनल की कांग्रेस से, जो सितम्बर १८६८ में ब्रसेल्स में हुई थी, प्रस्ताव किया कि वह लीग के साथ सहबंध करे। कांग्रेस ने सर्वसम्मति से दो विकल्प प्रस्तुत किये—या तो

* देखें प्रस्तुत खंड।—सं०

लीग उसी ध्येय का अनुसरण करे जो इंटरनेशनल का है—उस दशा में लीग के अस्तित्व के बने रहने के लिए कोई कारण नहीं रह जाता,—अथवा उसका ध्येय भिन्न होना चाहिए—उस दशा में सहबंध असम्भव होगा। चन्द दिन बाद बर्न में हुई लीग की कांग्रेस में बकूनिन ने पैतरा बदला। उन्होंने एक कामचलाऊ कार्यक्रम प्रस्तावित किया जिसे इस एक वाक्यांश से ही परखा जा सकता है—**“वर्गों का आर्थिक तथा सामाजिक समताकरण”**।¹⁴ एक अनुलेखनीय अल्पसंख्या का समर्थन प्राप्त करते हुए उन्होंने लीग से नाता तोड़ डाला ताकि वह इंटरनेशनल में शामिल हो सके। वह इस बात के लिए कمر कसे हुए थे कि इंटरनेशनल की ग्राम नियमावली के स्थान पर लीग द्वारा ठुकराये गये कामचलाऊ कार्यक्रम को और जनरल कौंसिल के स्थान पर अपनी वैयक्तिक तानाशाही को रखें। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक विशेष अस्त्र, **समाजवादी जनवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध** तैयार किया ताकि वह इंटरनेशनल के अन्दर एक और इंटरनेशनल बन जाये।

बकूनिन को इस संस्था के निर्माण के लिए उन लोगों के बीच से, जिनके साथ उन्होंने अपने इटली में प्रवास के दौरान सम्बन्ध कायम किये थे तथा रूसी उत्प्रवासियों के एक छोटे समूह के बीच से आवश्यक तत्त्व प्राप्त हो गये थे; ये उत्प्रवासी स्विट्जरलैंड, फ्रांस तथा स्पेन में बकूनिन के दूतों तथा इंटरनेशनल के सदस्य बनानेवाले लोगों के रूप में काम कर रहे थे। फिर भी बकूनिन ने अपनी नयी संस्था के नियमों को स्वीकृति के लिए जनरल कौंसिल के सामने प्रस्तुत करने का फैसला तभी किया जब बेल्जियम तथा पेरिस की फ्रेडरल कौंसिलें सहबंध को मान्यता देने से बार-बार इन्कार कर चुकी थीं। ये नियम “गलत समझे गये” बर्न कार्यक्रम के हू-ब-हू प्रतिरूप के अलावा और कुछ नहीं थे। कौंसिल ने २२ दिसम्बर १८६८ को उसका उत्तर निम्नलिखित परिपत्र द्वारा दिया :

समाजवादी जनवाद के अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध को जनरल कौंसिल की ओर से

लगभग एक माह पहले चन्द नागरिकों ने समाजवादी जनवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध नामक एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की केन्द्रीय पहल समिति की यह कहते हुए स्थापना की कि उनका “विशेष मिशन समता के भव्य सिद्धान्त के आधार पर राजनीतिक तथा दार्शनिक प्रश्नों का अध्ययन, आदि” करना है।

इस पहल समिति द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम तथा नियमावली अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जनरल कौंसिल के पास केवल १५ दिसम्बर १८६८ को ही भेजी गयी। इन दस्तावेजों के अनुसार कथित सहबंध "पूरी तरह इंटरनेशनल में घुला-मिला हुआ है" और साथ ही वह इस मजदूर संघ से पूरी तरह बाहर भी स्थापित है। इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के अलावा, जो क्रमशः जेनेवा, लोज़ांस¹⁵ तथा ब्रसेल्स कांग्रेसों में निर्वाचित हुई, पहल समिति द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप जेनेवा में एक और स्वयंनियुक्त जनरल कौंसिल भी होगी। इंटरनेशनल के स्थानीय ग्रुपों के अलावा सहबंध के भी स्थानीय ग्रुप होंगे, जो इंटरनेशनल के राष्ट्रीय कार्यालयों से स्वतंत्र अपने ही राष्ट्रीय ब्यूरो के जरिए "सहबंध के केन्द्रीय ब्यूरो से उन्हें इंटरनेशनल में भर्ती करने के लिए कहेंगे"; इस प्रकार सहबंध की केन्द्रीय समिति इंटरनेशनल में प्रवेश के अधिकार को स्वयं ग्रहण करती है। आखिरी चीज, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जनरल कांग्रेस का प्रतिरूप होगा सहबंध की जनरल कांग्रेस, क्योंकि—जैसा कि पहल समिति की नियमावली में कहा गया है—मजदूरों की वार्षिक कांग्रेस में समाजवादी जनवाद के अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध का प्रतिनिधिमंडल अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की एक शाखा के रूप में "एक पृथक भवन में अपनी बैठकें किया करेगा।"

इस बात को ध्यान में रखते हुए,

कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के अन्दर तथा बाहर काम करनेवाले एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व संघ के विघटन का सुनिश्चित माध्यम होगा;

कि कहीं भी लोगों के अन्य समूह को जेनेवा की पहल समिति का अनुकरण करने का और कम या ज्यादा विश्वसनीय लगनेवाले बहाने से दूसरे विशेष ध्येय वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के अन्दर लाने का अधिकार मिल जायेगा;

कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ इस तरह शीघ्र हर तरह के दस्तंवाजों के—वे चाहे किसी भी राष्ट्रीयता के या पार्टी के हों—हाथों में एक खिलौना बन जायेगा;

कि इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की नियमावली केवल स्थानीय तथा राष्ट्रीय शाखाओं को ही सदस्यता प्रदान करती है (देखें नियमावली की धारा १ तथा धारा ६);

कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की शाखाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की नियमावली तथा प्रशासनिक अधिनियमों के विपरीत नियमावली अथवा प्रशासनिक

अधिनियम स्वीकृत करने की मनाही है (देखें प्रशासनिक अधिनियमों की धारा १२) ;

कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की नियमावली तथा प्रशासनिक अधिनियमों को जनरल कांग्रेस तभी संशोधित कर सकती है जब इस प्रकार के संशोधन के पक्ष में उपस्थित डेलीगेटों का दो-तिहाई भाग मत दे (देखें प्रशासनिक अधिनियमों की धारा १३) ;

कि इस प्रश्न पर फ्रैंसला ब्रसेल्स में जनरल कांग्रेस में शान्ति लीग के विरुद्ध सर्वसम्मति से पास किये गये प्रस्तावों में पहले से ही मौजूद है ;

कि इन प्रस्तावों में कांग्रेस ने घोषित किया कि शान्ति लीग के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उसकी हाल की घोषणाओं के अनुसार उसके लक्ष्य तथा सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के लक्ष्यों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हैं ;

कि सहबंध के जेनेवा पहल ग्रूप के अनेक सदस्यों ने ब्रसेल्स कांग्रेस में डेलीगेटों के रूप में इन प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया था ;

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जनरल कौंसिल ने २२ दिसम्बर १८६८ की अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निश्चय किया कि :

१. समाजवादी जनवाद के अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध की नियमावली की तमाम धाराएं, जो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के साथ उसके सम्बन्धों की व्याख्या करती हैं, रद्द घोषित की जाती हैं ;

२. समाजवादी जनवाद के अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में उसकी शाखा के रूप में भर्ती नहीं होने दिया जाये ।

जी० ओडजर, बैठक के अध्यक्ष

रा० शा०, महामंत्री

लन्दन, २२ दिसम्बर १८६८

चन्द महीने बाद सहबंध ने फिर जनरल कौंसिल से अपील की और कहा कि वह इस बात का उत्तर “हां” या “न” में दे कि वह सहबंध के सिद्धान्तों को स्वीकार करती है या नहीं। यदि उत्तर “हां” में हो तो सहबंध इंटरनेशनल की शाखाओं में अपने को विलीन करने के लिये तैयार है। जनरल कौंसिल ने ६ मार्च १८६९ को अपने परिपत्र में उत्तर दिया :

१॥ विभिन्न “क्रान्तिकारी समितियों” के नामों की आड़ में अपना असली रूप ढाँधते हुए बकूनिन ने कालियोस्त्रो के ज़माने की सारी तिकड़मों तथा छल-प्रपंचों पर आधारित निरंकुश शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। इस संस्था के प्रचार का खास तरीका यह था कि वह निर्दोष लोगों को रूसी पुलिस की निगाह में गायब बनाने के लिए उन्हें जेनेवा से पीले लिफ़ाफ़ों में चिट्ठियाँ भेजा करती थी। इनके बाहर रूसी भाषा में लगी मुहर में लिखा रहता था: “गुप्त क्रान्तिकारी मार्गान”। नेचायेव के मुकदमे के बारे में प्रकाशित वृत्तान्त इंटरनेशनल के नाम * ५। नीचतापूर्ण दुरुपयोग का प्रमाण हैं।

सहबंध ने अब पहले लोवले से निकलनेवाले अख़बार «*Progrès*»¹⁷ को फिर जेनेवा से निकलने वाले रोमांस फ़ेडरेशन के आधिकारिक अख़बार «*Égalité*»¹⁸ में, जिसमें सहबंध के कई सदस्य बकूनिन के अनुयायी थे, जनरल कौंसिल के विरुद्ध वाद-विवाद शुरू कर दिया। जनरल कौंसिल, जो बकूनिन के आश्रितगत मुखपत्र «*Progrès*» में प्रकाशित आक्षेपों का तिरस्कार करती रही, «*Égalité*» में प्रकाशित आक्षेपों की उपेक्षा नहीं कर सकती थी, जिनके बारे में वह यह विश्वास करने के लिए विवश थी कि उन्हें रोमांस फ़ेडरल कमेटी की स्वीकृति प्राप्त है। इसलिए उसने १ जनवरी १८७० को ** एक परिपत्र प्रकाशित किया जिसमें उसने कहा:

“११ दिसम्बर १८६६ के «*Égalité*» में लिखा हुआ है:

“जनरल कौंसिल निस्सन्देह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा कर रही है। हम उसे अधिनियमों की धारा १ के अन्तर्गत उसके उत्तरदायित्वों की याद दिलाते हैं—जनरल कौंसिल कांग्रेस के प्रस्तावों को अमल में लाने के लिए **असंभव** है, आदि। हम जनरल कौंसिल के सामने इतने पर्याप्त प्रश्न कर सकते हैं कि उनके उत्तरों से एक लम्बी रिपोर्ट बन जाती। हम यह काम वाद में करते ... इस बीच, आदि।”

* नेचायेव के मुकदमे¹⁶ का एक अंश शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा। पाठक को उम्मीद है कि मूर्खतापूर्ण तथा धिनौने दोनों प्रकार के नियम मिल जायेंगे जिन्हें बकूनिन को दोस्तों ने इंटरनेशनल के मध्ये मड़ा है।

** देखें, कार्ल मार्क्स ‘रोमांस स्विट्ज़रलैंड की फ़ेडरल कौंसिल के नाम जनरल कौंसिल की ओर से’।—सं०

है। जनरल कौंसिल को यकीन है कि आप ऐसे शब्दों को अपने कार्यक्रम से निकालने के लिए उत्सुक होंगे जो इतनी खतरनाक गलतफ़हमी पैदा कर सकते हैं। हमारे संघ के सिद्धान्त प्रत्येक शाखा को अपना सैद्धान्तिक कार्यक्रम तैयार करने की इजाजत देते हैं, सिवाय ऐसे मामलों में जब हमारे संघ की आम नीति का उल्लंघन होता हो।

इसलिए सहबंध की शाखाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की शाखाओं में परिवर्तित करने की राह में कोई अड़चन नहीं है।

यदि सहबंध के विघटन तथा उसकी शाखाओं के इंटरनेशनल में प्रवेश का प्रश्न एक बार तय हो जाता है तो हमारे अधिनियमों के अनुसार प्रत्येक नयी शाखा के स्थान तथा उसकी सदस्य संख्या के बारे में कौंसिल को सूचित करना आवश्यक हो जायेगा।

६ मार्च १८६६ को जनरल कौंसिल की बैठक

सहबंध द्वारा ये शर्तें स्वीकार किये जा चुकने के बाद उसे जनरल कौंसिल ने, जो बकूनिन के कार्यक्रम पर किये गये कुछ दस्तखतों से गुमराह हो गयी थी, इंटरनेशनल में भर्ती कर लिया, वह यह समझी कि जेनेवा स्थित रोमांस फ्रेडरल कमेटी ने सहबंध को मान्यता दे दी है हालांकि इसके विपरीत उसने उससे कभी कोई सरोकार रखने से हमेशा इन्कार किया। इस तरह सहबंध ने अपने तात्कालिक लक्ष्य, बाजेल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व पाने के लक्ष्य को पूरा कर डाला। बकूनिन के समर्थकों द्वारा इस्तेमाल किये गये बेईगानीभरे हथकंडों, इंटरनेशनल की किसी कांग्रेस में इस तथा एकमात्र इस अवसर पर अपनाये गये इन हथकंडों के बावजूद बकूनिन कांग्रेस से जनरल कौंसिल को जेनेवा में स्थानान्तरित कराने तथा पुश्तैनी अधिकारों के तत्काल उन्मूलन के सेंट-साइमन के पुराने कूड़ा-करकट को, जिसे बकूनिन व्यावहारिक रूप में समाजवाद के लिए प्रस्थान-बिन्दु मानते थे, अधिकृत मान्यता दिलाने की अपनी प्रत्याशा में मात खा गये। यह जनरल कौंसिल के ही विरुद्ध नहीं, बल्कि इंटरनेशनल की उन तमाम शाखाओं के विरुद्ध, जिन्होंने इस संकीर्णतावादी गुट के कार्यक्रम को, विशेष रूप से राजनीति से पूर्ण विरति के सिद्धान्त को स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया था, खुले तथा अनवरत युद्ध का संकेत था।

बाजेल कांग्रेस से भी पहले जब नेचायेव जेनेवा पहुंचे थे, बकूनिन उनके साथ सम्पर्क में आये तथा उन्होंने रूस में छात्रों के बीच एक गुप्त संस्था बनायी

**समाजवादी जनवाद के
अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध की केन्द्रीय समिति को
जनरल काँसल की ओर से**

हमारी नियमावली की धारा १ के अनुसार संघ एक ही लक्ष्य के लिए — यानी पारस्परिक सुरक्षा, मजदूर वर्ग की प्रगति तथा पूर्ण मुक्ति के लिए काम करनेवाली मजदूर वर्ग की तमाम संस्थाओं को सदस्य बनाती है।

हर देश में मजदूर वर्ग के भाग अपने को विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पाते हैं, इससे स्वभावतया यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी सैद्धान्तिक रायें भी, जो वास्तविक आन्दोलन को प्रतिबिम्बित करती हैं, भिन्न-भिन्न होनी चाहिए।

परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा स्थापित एकसमान कार्यक्रम, विचार-विनिमय, जिन्हें विभिन्न राष्ट्रीय शाखाओं के मुखपत्रों ने सुगम बनाया है, तथा अतः जनरल कांग्रेसों में सीधी बहसें एकसमान सैद्धान्तिक कार्यक्रम को यकीनन जगम देंगी।

फलस्वरूप सहबंध के कार्यक्रम की समीक्षात्मक जांच-परख करना जनरल काँसल का काम नहीं है। हमें इस बात की जांच-परख नहीं करनी है कि यह सर्वहारा आन्दोलन की पर्याप्त अभिव्यक्ति है या नहीं। हमें तो बस इतना सिद्ध करना है कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमारे संघ की ग्राम पूर्णता के, अर्थात् मजदूर वर्ग की पूर्ण मुक्ति के विरुद्ध हो। आपके कार्यक्रम में एक वाक्य इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करती। धारा २ में कहा गया है—

“उसका” (सहबंध का) “लक्ष्य सर्वोपरि वर्गों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समताकरण है”।

वर्गों के समताकरण की यदि शाब्दिक रूप में परिभाषा की जाये तो उसका यह मतलब निकलता है—पूँजी तथा श्रम के बीच सामंजस्य, जिसका पूँजीवादी समाजवादी इतने आग्रहपूर्वक प्रचार करते रहते हैं। तर्कसंगति की दृष्टि से असम्भव वर्गों का समताकरण नहीं, वरन, इसके विपरीत, वर्गों का उन्मूलन,—यह है सर्वहारा आन्दोलन का सच्चा रहस्य, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का महान ध्येय।

फिर भी इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वर्गों का समताकरण जल्द इरतेमाल किये गये हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि यह महज लेखनी की भूल

जनरल कौंसिल को नियमावली अथवा अधिनियमों की किसी ऐसी धारा की जानकारी नहीं है जो उसे «*Égalité*» के साथ वाद-विवाद में पड़ने अथवा अखबारों में छपनेवाले “प्रश्नों के उत्तर” देने के लिए मजबूर करती हो। जनरल कौंसिल के समक्ष रोमांस स्विट्ज़रलैंड की शाखाओं का केवल जेनेवा स्थित फ़ेडरल कमेटी ही प्रतिनिधित्व कर सकती है। फ़ेडरल कमेटी यदि एकमात्र वैध माध्यम से, अर्थात् अपने सचिव के जरिए हमसे कोई अनुरोध करे या हमें झिड़की दे तो जनरल कौंसिल उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहेगी। परन्तु फ़ेडरल कमेटी को इसका कोई हक नहीं है कि वह «*Égalité*» अथवा «*Progrès*» के हक में अपने दायित्व का परित्याग करे अथवा इन अखबारों को अपने दायित्व हड़पने की इजाजत दे। आम तौर पर राष्ट्रीय तथा स्थानीय समितियों के साथ जनरल कौंसिल का पत्र-व्यवहार संध के आम हितों को आंच पहुंचाये बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप यदि इंटरनेशनल के दूसरे मुखपत्र «*Progrès*» और «*Égalité*» के उदाहरणों का अनुकरण करेंगे तो जनरल कौंसिल के सामने दो ही विकल्प रह जायेंगे—मौन साधकर या तो अपने को सार्वजनिक रूप से बदनाम करे अथवा सार्वजनिक रूप से उत्तर देकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करे। उधर «*Égalité*» ने «*Progrès*» के साथ मिलकर पेरिस के अखबार «*Travail*»¹⁹ को अपनी ओर से जनरल कौंसिल की भर्त्सना करने के लिए आमंत्रित किया। इस चीज़ ने उसे सार्वजनिक कल्याण लीग²⁰ के अनुरूप बना डाला है।

इस बीच रोमांस फ़ेडरल कमेटी ने परिपत्र पढ़ने से पहले ही सहबंध के समर्थकों को «*Égalité*» के सम्पादकमंडल से बाहर निकाल दिया।

२२ दिसम्बर १८६८ तथा ६ मार्च १८६९ के परिपत्रों की ही तरह १ जनवरी १८७० के परिपत्र को इंटरनेशनल की समस्त शाखाओं की स्वीकृति प्राप्त हो गयी।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सहबंध द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों में से कोई भी पूरी नहीं की गयी है। उसकी कल्पित शाखाएं जनरल कौंसिल के लिए रहस्य बनी हुई हैं। बकूनिन ने स्पेन तथा इटली में बिखरे पड़े चन्द ग्रुपों तथा नेपल्स की शाखा को, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल से पृथक् कर दिया था, अपने मातहत रखने का प्रयास किया। दूसरे इतालवी शहरों में उन्होंने मजदूरों के नहीं, वरन् वकीलों, पत्रकारों तथा अन्य पूंजीवादी मतवादियों के छोटे-छोटे गुटों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया। बार्सेलोना में उनके चन्द दोस्तों

ने उनके प्रभाव को कायम रखा। दक्षिणी फ्रांस के कुछ शहरों में सहबंध ने लियों के अल्बेर रिशार तथा गास्पर ब्लां के नेतृत्व में, जिनके बारे में हम आगे चलकर काफ़ी कुछ कहेंगे, पृथक्तावादी शाखाएं स्थापित करने का प्रयास किया। कहने का मतलब यह है कि इंटरनेशनल के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी काम करती रही।

सहबंध एक निर्णायक प्रहार—रोमांस स्विट्ज़रलैंड शाखा के नेतृत्व को सम्भालने का प्रयत्न—शो-दे-फ़ोन में हुई कांग्रेस में करने जा रहा था जो ४ अप्रैल १८७० को आरम्भ हुई।

संघर्ष सहबंध के डेलीगेटों के प्रवेश के अधिकार पर शुरू हुआ जिसका जेनेवा फ़ेडरेशन तथा शो-दे-फ़ोन की शाखाओं के डेलीगेटों ने विरोध किया।

स्वयं सहबंध के समर्थकों के अनुमान के अनुसार वे फ़ेडरेशन के सदस्यों के पांचवें हिस्से से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, फिर भी वे बाज़ेल में की गयी तिकड़मों की पुनरावृत्ति की वदौलत एक या दो मतों से बहुमत प्राप्त करने में सफल हो गये। यह बहुमत स्वयं उनके मुखपत्र के अनुसार (७ मई १८७० के «*Solidarité*»²¹ का अंक देखें) पन्द्रह शाखाओं से अधिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता था जबकि अकेले जेनेवा में वे तीस थे! इस मतदान के फलस्वरूप रोमांस कांग्रेस दो भागों में बंट गयी जिन्होंने स्वतंत्र रूप में अपनी बैठकें जारी रखीं। सहबंध के समर्थकों ने अपने को पूरे फ़ेडरेशन का प्रतिनिधि मानते हुए फ़ेडरल कमेटी का कार्यालय शो-दे-फ़ोन में स्थानान्तरित कर दिया तथा नेव्शातेल में अपना अधिकृत मुखपत्र «*Solidarité*» चालू किया जिसका सम्पादन नागरिक गिलोम कर रहे थे। इस नौजवान लेखक का विशेष कार्य जेनेवा के “कारख़ाने” के मज़दूरों²² की, इन धिनौने “पूँजीपतियों” की निन्दा करना, फ़ेडरेशन के अन्तर्गत «*Égalité*» के विरुद्ध संघर्ष चलाना तथा राजनीति से पूर्ण विरति की अवकलत करना था। इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण लेखक थे भासॅल में वास्तेलिका तथा लियों में सहबंध के दो बड़े स्तम्भ—अल्बेर रिशार तथा गास्पर ब्लां।

जेनेवा के डेलीगेटों ने वापस लौटने पर अपनी शाखाओं की एक आम सभा बुलायी जिसने शो-दे-फ़ोन में उनके कार्यों को बकूनिन और उनके दोस्तों के विरोध के बावजूद अनुमोदित किया। कुछ समय बाद बकूनिन तथा उनके अधिक सक्रिय अनुयायियों को पुराने रोमांस फ़ेडरेशन से बाहर निकाल दिया गया।

कांग्रेस ख़त्म हुई भी नहीं थी कि नयी शो-दे-फ़ोन समिति ने सचिव एफ़० राबर्ट तथा अध्यक्ष आंरी शेवाले के—इस व्यक्ति को दो माह बाद समिति के

मुखपत्र «Solidarité» ने अपने ६ जुलाई के अंक में चोर बताकर उसकी भर्त्सना की थी—हस्ताक्षर से एक पत्र भेजकर जनरल कौंसिल से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। दोनों पक्षों के मामलों की जांच करने के बाद जनरल कौंसिल ने २८ जून १८७० को निर्णय किया कि जेनेवा फ़ेडरल कमेटी को अपने पुराने काम पर रहने दिया जाये तथा नयी शो-दे-फ़ोन समिति को अपना कोई स्थानीय नाम रखने के लिए कहा जाये। इस निर्णय से अपनी योजनाएं विफल हो जाते देखकर शो-दे-फ़ोन समिति ने जनरल कौंसिल पर सत्तावादी होने का आरोप लगाया, यह भूलते हुए कि उसने ही उसके हस्तक्षेप की मांग की थी। रोमांस फ़ेडरल कमेटी का नाम हड़पने के लिए शो-दे-फ़ोन समिति ने निरन्तर प्रयत्न कर स्विस् फ़ेडरेशन के लिए जो मुसीबतें पैदा कीं, उन्होंने जनरल कौंसिल को शो-दे-फ़ोन समिति के साथ सारे सम्बन्ध भंग करने के लिए विवश किया था।

लूई बोनापार्ट ने ज़रा देर पहले सेदान में^{२३} अपनी सेना समेत आत्मसमर्पण किया था। चारों ओर से इंटरनेशनल के सदस्यों की ओर से युद्ध जारी रखे जाने के विरुद्ध आवाज़ उठायी गयी। जनरल कौंसिल ने ६ सितम्बर* की अपनी चिट्ठी में प्रशा की क़ब्ज़ाकारी योजनाओं का पर्दाफ़ाश करते हुए उसकी विजय से सर्वहारा ध्येय के लिए पैदा होनेवाले ख़तरे की ओर संकेत किया था और जर्मन मजदूरों को आगाह किया था कि वे ही इसके सबसे पहले शिकार बनेंगे। इंग्लैंड में जनरल कौंसिल ने सभाएं आयोजित कीं जिन्होंने राज-दरबार में प्रशा-पोषक प्रवृत्तियों की भर्त्सना की।^१ जर्मनी में मजदूरों ने—इंटरनेशनल के सदस्यों ने—प्रदर्शन संगठित किये जिनमें जनतंत्र को मान्यता देने तथा “फ़्रांस के लिए सम्मानजनक शान्ति” स्थापित करने की मांग की गयी...

इस बीच अपने उग्र स्वभाव के कारण सिरफ़िरे गिलोम के (नेव्शातेल के) दिमाग में यह शानदार विचार पैदा हुआ कि आधिकारिक समाचारपत्र «Solidarité» में परिशिष्ट के रूप में और उसकी आड़ में^{२४} एक गुमनाम घोषणापत्र प्रकाशित किया जाये, जिसमें प्रशियाइयों से लड़ने के लिए स्विस् स्वयंसेवक टुकड़ियां तैयार करने का आह्वान किया जाये; यह कुछ ऐसा काम था जिसे उसकी विरतिवादी आस्थाओं ने उसे निस्सन्देह कभी पूरा नहीं करने दिया।

लियों में विद्रोह भड़क उठा।^{२५} बकूनिन फ़ौरन वहां पहुंचे और अल्बेर रिशार, गास्पर ब्लां तथा वास्तेलिका की मदद से उन्होंने २८ सितम्बर को टाउन हाल

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

में अपने को प्रतिष्ठापित कर दिया, परन्तु यह सोचकर वहाँ कोई सन्तरी तैनात नहीं किया कि कहीं इसको राजनीतिक 'कार्रवाई' न मान लिया जाये। उन्हें राष्ट्रीय गार्ड के कुछ सैनिकों ने ठीक ऐसे समय अपमानजनक ढंग से बाहर निकाल दिया जब राज्य के उन्मूलन-सम्बन्धी उनकी आज्ञाप्ति घोर प्रसव-वेदना के बाद पैदा हो गई थी।

अक्टूबर १८७० को जनरल कौंसिल ने अपने फ्रांसीसी सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण नागरिक पाल राबिन को सदस्य सहयोजित किया, जो ब्रेस्त से आया हुआ उत्प्रासी, सहबंध का एक सबसे अधिक सुविदित समर्थक और यही नहीं, «*Égalité*» में जनरल कौंसिल पर कई प्रहारों का प्रणेता था। इसी समय से वह निरन्तर शो-दे-फ्रोन समिति के अधिकृत सम्वाददाता के रूप में काम करता रहा। उसने १४ मार्च १८७१ को सुझाव रखा कि स्विस झगड़े को निपटाने के लिए इंटरनेशनल की एक गुप्त कांग्रेस बुलाई जाये। कौंसिल ने पेरिस में आसन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को पहले ही देखते हुए कांग्रेस बुलाने से साफ़ इन्कार कर दिया। राबिन ने यह सवाल बार-बार उठाया और यहां तक सुझाव दिया कि कौंसिल झगड़े के बारे में कोई निश्चित फ़ैसला करे। जनरल कौंसिल ने २५ जुलाई को तय किया कि यह मामला सितम्बर १८७१ को आयोजित होनेवाले सम्मेलन में विचारणीय प्रश्नों में से एक होगा।

सहबंध ने, जो सम्मेलन द्वारा अपनी गतिविधियों की जांच किये जाने के लिए तैयार नहीं था, १० अगस्त को घोषणा की कि वह ६ अगस्त से विघटित हो चुका है। परन्तु १५ सितम्बर को वह फिर प्रकट हो गया और उसने निरीश्वरवादी समाजवादी शाखा के नाम से कौंसिल में प्रवेश के लिए अनुरोध किया। वाजेल कांग्रेस के प्रशासनिक प्रस्ताव संख्या ५ के अनुसार कौंसिल उसे जेनेवा फ़ेडरल कमेटी से, जो संकीर्णतावादी शाखाओं के विरुद्ध दो दर्जे के संघर्ष के बाद थक चुकी थी, परामर्श किये बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकती थी। यही नहीं, कौंसिल यंगमैन्स क्रिश्चियन असोसियेशन को पहले ही बता चुकी थी कि इंटरनेशनल धर्मशास्त्र-सम्बन्धी शाखाओं को मान्यता नहीं देती।

६ अगस्त को, जिस दिन सहबंध विघटित हुआ था, शो-दे-फ्रोन फ़ेडरल कमेटी ने कौंसिल के साथ आधिकारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए फिर से अनुरोध किया और कहा कि वह २८ जून के प्रस्ताव को नज़रअंदाज़ करती रहेगी, जेनेवा के सम्बन्ध में अपने को रोमांस फ़ेडरल कमेटी मानती रहेगी और "इस मामले पर फ़ैसला देना जनरल कांग्रेस का काम है।" ४ सितम्बर को उसी कमेटी ने

सम्मेलन की अधिकार-क्षमता पर आपत्ति की हालांकि उसी ने सबसे पहले उसे बुलाने का प्रश्न उठाया था। सम्मेलन पेरिस फ्रेडरल कमेटी की अधिकार क्षमता पर, जिससे पेरिस की घेराबन्दी से पहले शो-दे-प्रोन कमेटी ने स्विस् झगड़े में हस्तक्षेप करने के लिए कहा था, आपत्ति कर उत्तर दे सकती थी।²⁶ परन्तु उसने अपने को जनरल कौंसिल के २८ जून १८७० के निर्णय तक सीमित रखा (देखें जेनेवा के «*Égalité*» के २१ अक्टूबर १८७१ के अंक में प्रतिपादित प्रयोजन)।

३

स्विट्जरलैंड में चन्द फ्रांसीसी उत्प्रवासियों की, जिन्होंने वहाँ शरण ली थी, उपस्थिति ने सहबंध में फिर से कुछ जीवन संचारित कर दिया था।

इंटरनेशनल के जेनेवा सदस्यों ने उत्प्रवासियों के लिए भरसक सब कुछ किया। उन्होंने शुरू से ही उनकी मदद की, एक व्यापक अभियान शुरू करके स्विट्जरलैंड के अधिकारियों को उनका प्रत्यर्पण करने से रोका जिसकी वर्साई सरकार मांग कर रही थी। कुछ लोगों ने उत्प्रवासियों को सीमा पार करने में मदद देने के लिए फ्रांस जाकर खतरा मोल लिया। ज़रा जेनेवा के मज़दूरों के आश्चर्य का अनुमान तो लगाइये जब उन्होंने ब० मालोन * जैसे कई सरगनों को

* क्या ब० मालोन के दोस्त जो पिछले तीन माह से धिसे-पिटे ढंग से उसके बारे में यह प्रचार करते रहे हैं कि वह इंटरनेशनल का संस्थापक है, जिन्होंने उसकी पुस्तक को²⁷ कम्प्यून के विषय में एकमात्र वस्तुपरक कृति बताया है, यह जानते हैं कि फ़रवरी चुनावों के ठीक पहले बातिनोल के मेयर के इस सहायक ने क्या रख अपनाया था? उस समय मालोन ने, जिसे अभी कम्प्यून का पूर्वाभास नहीं हुआ था और जिसे राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव में अपनी सफलता के आगे और कुछ नहीं दिखायी देता था, चार समितियों की सूची में इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में अपना नाम शामिल कराने की तिकड़म की थी। इन मन्सूवों को पूरा करने के लिए उसने पेरिस फ्रेडरल कमेटी का अस्तित्व होने का धृष्टतापूर्वक प्रतिवाद किया और कमेटियों के समक्ष एक शाखा की, जिसकी उसने स्वयं बातिनोल में स्थापना की थी—इस तरह एक फ़ेहरिस्त पेश की मानो वह पूरे अन्तर्राष्ट्रीय संघ की ओर से आयी हो।—आगे चलकर १९ मार्च को उसने एक आधिकारिक दस्तावेज़ में एक दिन पहले हुई महान क्रान्ति²⁸ के नेताओं पर कीचड़ उछाला था। आज ऊपर से नीचे तक अराजकतावादी यह शब्द उस चीज़ को छाप रहा है या छाप चुका है जो वह चार समितियों से एक साल पहले कह

सहबंध के लोगों के साथ तत्काल सम्पर्क कायम करते और सहबंध के भूतपूर्व सचिव न० जुकोव्स्की की मदद से जेनेवा में, रोमांस फ़ेडरेशन के बाहर, नया "समाजवादी क्रान्तिकारी प्रचार तथा कार्रवाई शाखा"²⁹ कायम करने की कोशिश करते हुए देखा। उसकी नियमावली की पहली धारा में कहा गया है कि वह

"अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की आम नियमावली को स्वीकार करती है, साथ ही कार्यकलाप तथा पहल, जिसका वह संघ की नियमावली तथा कांग्रेसों द्वारा स्वीकार किये गये स्वायत्तता तथा संघ के सिद्धान्त के तर्कसंगत फल के रूप में हकदार है, की पूर्ण स्वतंत्रता अपने लिए आरक्षित रखती है।

दूसरे शब्दों में वह सहबंध का कार्य जारी रखने की पूर्ण स्वतंत्रता अपने लिए आरक्षित रखती है।

मालोन ने २० अक्टूबर १८७१ को जनरल कौंसिल को एक चिट्ठी भेजी जिसमें इस नयी शाखा ने इंटरनेशनल में प्रवेश के लिए फिर से तीसरी बार अनुरोध किया। बाजेल कांग्रेस के प्रस्ताव ५ के अनुसार कौंसिल ने जेनेवा फ़ेडरल कमेटी से परामर्श किया जिसने "तिकड़मों और फूट" के इस नये "अड्डे" को भाग्यता दिये जाने का घोर विरोध किया। कौंसिल ने पूरे फ़ेडरेशन को ब० मालोन तथा सहबंध के भूतपूर्व सचिव न० जुकोव्स्की की इच्छा से आबद्ध न कर सचमुच "गत्तावादी" ढंग से काम किया।

«Solidarité» बन्द हो जाने के कारण सहबंध के समर्थकों ने मदाम आन्द्रे लेओ के सर्वोच्च नेतृत्व में «Révolution Sociale»³⁰ की स्थापना की; यह शक्तिशाली लोसां शान्ति कांग्रेस में कुछ ही समय पहले कह चुकी थी कि

"राउल रिगो और फ़ेरे कम्यून की दो वीभत्स आकृतियां थे जो तब तक" (अन्यकों को फांसी पर लटकाये जाने तक) "रक्तपातपूर्ण कार्रवाइयों की - यह मांग है कि व्यर्थ ही - मांग करते रहे।

गत्ता था - "इंटरनेशनल - यह तो मैं हूँ!" ब० मालोन ने लूई चौवहवें तथा बाकलेट निर्माता पेरों की एकसाथ नक़ल उतारने का रास्ता ढूँढ़ निकाला है। यही ही वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि उसके चाकलेट एकमात्र खाने योग्य चाकलेट हैं।

अब्रुवार ने अपने पहले ही अंक से अपने को फ़ौरन «Figaro», «Gaulois», «Paris-Journal»³¹ और अन्य बदनाम पत्रों के स्तर पर पहुंचा दिया जो जनरल कौंसिल पर कीचड़ उछालते आये हैं। उसने समझा कि यह इंटर-नेशनल के अन्दर तक राष्ट्रीय घृणा की आग भड़काने का ठीक मौक़ा है। उसने जनरल कौंसिल को विस्मार्क सदृश दिमाग़ के नेतृत्व में काम करनेवाली जर्मन समिति बताया।*

निश्चयपूर्वक यह सिद्ध कर चुकने के बाद कि जनरल कौंसिल के कतिपय सदस्य “पहले और सर्वोपरि ग़ाल” होने का दावा नहीं कर सकते, «Révolution Sociale» यूरोपीय पुलिस द्वारा प्रचलित दूसरे नारे को अपनाने और कौंसिल की सत्तावादिता की भर्त्सना करने से बेहतर और कोई चीज़ नहीं कर पाया।

तो फिर वे तथ्य क्या थे जिन पर यह वचकाना बकवास आधारित थी? जनरल कौंसिल ने सहबंध को अपनी मौत मरने दिया और जेनेवा फ़ेडरल कमेटी की सहमति से उसे पुनरुज्जीवित नहीं होने दिया। यही नहीं, उसने शो-दे-फ़ोन कमेटी को एक ऐसा नाम ग्रहण करने की सलाह दी जिसके सहारे वह रोमांस स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल के सदस्यों की बहुसंख्या के साथ शान्तिपूर्वक रह सके।

इन “सत्तावादी” कार्रवाइयों के अलावा जनरल कौंसिल ने अक्टूबर १८६९ तथा अक्टूबर १८७१ के बीच बाज़ेल कांग्रेस से प्राप्त काफ़ी व्यापक अधिकारों का क्या उपयोग किया?

१) ८ फ़रवरी १८७० को पेरिस की “प्रत्यक्षवादी सर्वहारा सोसायटी” ने जनरल कौंसिल के समक्ष प्रवेश के लिए अर्ज़ी दी। कौंसिल ने उत्तर दिया कि प्रत्यक्षवादियों के सिद्धान्त, —सोसायटी के विशेष नियमों का पूंजी से सम्बन्धित भाग—आम नियमावली** की प्रस्तावना के सरासर विरुद्ध हैं; कि सोसायटी को इसलिए इन सिद्धान्तों को छोड़ना होगा तथा इंटरनेशनल में “प्रत्यक्षवादियों” के रूप में नहीं, बरन् “सर्वहाराओं” के रूप में शामिल होना होगा; वे अपने सिद्धान्तिक विचारों का संघ के आम सिद्धान्तों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए

* कौंसिल की राष्ट्रीय संरचना इस प्रकार है—२० अंग्रेज़, १५ फ़्रांसीसी, ७ जर्मन (जिनमें से ५ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं), २ स्विस, २ हंगेरियाई, १ पोल, १ बेल्जियन, १ आयरिश, १ डेनिश तथा १ इटालियन।

** देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

स्वतंत्र होंगे। इस निर्णय का औचित्य मानकर शाखा इंटरनेशनल में शामिल हो गयी।

२) लियों में १८६५ की शाखा तथा हाल में स्थापित उस शाखा में फूट पड़ गयी जिसमें ईमानदार मजदूरों के साथ सहबंध का प्रतिनिधित्व अल्बेर रिशार तथा गास्पर ब्लां कर रहे थे। जैसा कि ऐसे ही मामलों में पहले भी हो चुका है, स्विट्जरलैंड में स्थापित विवाचन-न्यायालय का फ़ैसला ठुकरा दिया गया। १५ फ़रवरी १८७० को हाल में स्थापित शाखा ने जनरल कौंसिल से वाञ्छेल कांग्रेस के प्रस्ताव ७ के बल पर झगड़ा निपटाने का अनुरोध ही नहीं किया, बल्कि उसे १८६५ की शाखा के सदस्यों की भर्त्सना करने तथा उन्हें सदस्यता से बाहर रखने के लिए एक तैयार प्रस्ताव भी भेजा और कहा कि वह इस पर हस्ताक्षर कर उसे जवाबी डाक से लौटा दे। कौंसिल ने इस तरह की अभूतपूर्व कार्रवाई की निन्दा की तथा आवश्यक कागजात पेश करने के लिए कहा। इसी अनुरोध के उत्तर में १८६५ की शाखा ने कहा कि अल्बेर रिशार के विरुद्ध आरोप-पत्र, जिन्हें विवाचन-न्यायालय में पेश किया गया था, बकूनिन के पास हैं और वह उन्हें सौंपने से इन्कार करता है। फलस्वरूप वह जनरल कौंसिल की इच्छा को पूर्णतः पूरा नहीं कर सकती। इस मामले पर ८ मार्च के कौंसिल के निर्णय पर किसी पक्ष की ओर से आपत्ति नहीं हुई।

३) लन्दन में फ़्रांसीसी शाखा, जिसने अपने बीच काफ़ी संदिग्ध लोगों को ले लिया, धीरे-धीरे एक ऐसी अनोखी शेयर संस्था बन गयी जिस पर श्री फ़ेलिक्स प्यात का लगभग पूरा नियंत्रण था। उसने लूई बोनापार्ट की हत्या की मांग का आह्वान करनेवाले हानिकारक प्रदर्शन संगठित करने और इंटरनेशनल की आड़ में अपने उपहासास्पद घोषणापत्रों का प्रचार करने के लिए इस संस्था का इस्तेमाल किया। जनरल कौंसिल ने अपने को संघ के मुखपत्रों में यह घोषित करने तक सीमित रखा कि श्री प्यात इंटरनेशनल के सदस्य नहीं हैं और वह उनकी कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती। तब फ़्रांसीसी शाखा ने घोषित किया कि वह न तो जनरल कौंसिल को और न कांग्रेसों को मान्यता देती है; उसने लन्दन की दीवारों पर पोस्टर चिपकाये जिनमें घोषणा की गयी थी कि उसे छोड़कर बाकी इंटरनेशनल क्रान्तिविरोधी संस्था है। षड्यंत्र के बहाने, जिसे वस्तुतः पुलिस ने रचा था और जिसे प्यात के घोषणापत्रों ने विश्वसनीय बना दिया था, जनमत संग्रह^{३२} के ठीक पहले इंटरनेशनल के फ़्रांसीसी सदस्यों की गिरफ़्तारी ने जनरल कौंसिल को «Marseillaise» तथा «Réveil»^{३३} में अपने १० मई १८७०

का प्रस्ताव प्रकाशित करने पर मजबूर किया जिसमें घोषणा की गयी थी कि तथाकथित फ्रांसीसी शाखा द्वा वर्ष से इंटरनेशनल में नहीं है और उसका आन्दोलन पुलिस एजेंटों की करतूत है। पेरिस फ्रेडरल कमेटी की इन्हीं अखबारों में प्रकाशित घोषणा तथा मुकदमे के दौरान इंटरनेशनल के पेरिस सदस्यों की घोषणा ने इस कदम की आवश्यकता की पुष्टि कर दी। इन दोनों घोषणाओं में कौंसिल के प्रस्ताव का जिक्र किया गया था। फ्रांसीसी शाखा युद्ध छिड़ने के समय लुप्त हो गयी परन्तु स्विट्जरलैंड के सहबंध की तरह वह नये साथियों और अन्य नामों के साथ पुनः लन्दन में प्रकट हो गयी।

कांफ्रेंस के अन्तिम दिनों में लन्दन में कम्यून के उत्प्रवासियों की “१८७१ की फ्रांसीसी शाखा” की स्थापना हुई जिसमें लगभग ३५ सदस्य शामिल थे। जनरल कौंसिल की पहली “सत्तावादी” कार्रवाई यह थी कि उसने इस शाखा के सचिव गुस्ताव दुरां को फ्रांसीसी पुलिस का जासूस बताकर उसकी भर्त्सना की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वे पुलिस का यह इरादा साबित करती हैं कि वह पहले दुरां को कांफ्रेंस में उपस्थित होने और फिर उसे जनरल कौंसिल की सदस्यता हासिल करने में मदद देना चाहती थी। चूंकि नयी शाखा की नियमावली सदस्यों को यह निर्देश देती थी कि वे “जनरल कौंसिल में अपनी शाखा के अलावा और किसी की ओर से नियुक्ति स्वीकार न करें”, नागरिक थेइस और वास्तेलिका कौंसिल से पृथक् हो गये।

१७ अक्टूबर को शाखा ने अनिवार्य अधिदेशों के साथ अपने दो सदस्य कौंसिल में भेजे—इनमें से एक और कोई नहीं, तोपखाना समिति का भूतपूर्व सदस्य श्री शोतार था। कौंसिल ने “१८७१ की शाखा” की नियमावली की जांच किये बिना उसे भर्ती करने से इन्कार कर दिया।* यहां बहस के, जिसे इस नियमावली ने जन्म दिया, सबसे मुख्य मुद्दे की चर्चा करना काफ़ी होगा। उसकी धारा २ में कहा गया है—

* कुछ समय बाद इसी शांतोत को, जिसे जनरल कौंसिल में रखने का प्रयास किया गया था, थियेर की पुलिस एजेंट बताकर शाखा से निकाल दिया गया। उस पर उन्हीं लोगों ने आरोप लगाया जो दूसरे तमाम लोगों की तुलना में उसे जनरल कौंसिल में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त पात्र मानते थे।

“शाखा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को अपनी आजीविका के साधनों के बारे में जानकारी देनी होगी, नैतिकता, आदि की गारंटी देनी होगी।”

जनरल कौंसिल ने १७ अक्टूबर १८७१ को अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया कि “अपनी आजीविका के साधनों के बारे में जानकारी देने” शब्द निकाल दिये जायें।

कौंसिल ने कहा: “संदिग्ध मामलों में कोई शाखा आजीविका के साधनों के बारे में जानकारी को ‘नैतिकता की गारंटी’ मान सकती है, जबकि दूसरे मामलों में, जैसे उत्प्रवासियों, हड़ताली मजदूरों, आदि के मामले में आजीविका के साधनों का अभाव नैतिकता की गारंटी हो सकता है। परन्तु इंटरनेशनल में प्रवेश के लिए आम शर्त के रूप में अपनी आजीविका के साधनों के बारे में उम्मीदवारों से जानकारी देने की मांग करना पूंजीवादी नवाचार होगा जो आम नियमावली के शब्दों तथा भावना के विपरीत है।” शाखा ने उत्तर दिया—

“आम नियमावली शाखाओं को अपने सदस्यों की नैतिकता के बारे में उत्तरदायी बनाती है और परिणामस्वरूप ऐसी गारंटियां, जो वे आवश्यक समझें, मांगने के उनके अधिकार को मान्यता देती है।”

जनरल कौंसिल ने ७ नवम्बर को यह उत्तर दिया—

“इस तर्क के आधार पर इंटरनेशनल की मध्य का सेवन न करनेवालों की कोई भी शाखा अपनी नियमावली में इस तरह की धारा शामिल कर सकती है— शाखा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को यह शपथ लेनी होगी कि वह सब तरह के मध्यपान से दूर रहेगा। दूसरे शब्दों में शाखाएं अपनी नियमावलियों द्वारा इंटरनेशनल में प्रवेश की सबसे बेतुकी तथा सबसे असंगत शर्तें सदैव इस बहाने से थोप सकती थीं कि वे इस तरह अपने सदस्यों की नैतिकता के विषय में आश्वस्त हों... ‘हड़तालियों की आजीविका का साधन’—१८७१ की फ्रांसीसी शाखा आगे कहती है—‘हड़ताल कोष है।’ इसका उत्तर यह कहकर दिया जा सकता है कि सर्वप्रथम यह कोष बहुधा कृत्रिम होता है ... इसके अलावा सरकारी आंग्ल प्रश्नावलियों ने साबित किया है कि अंग्रेज मजदूरों की बहुसंख्या... हड़तालों अथवा बेरोजगारी, अपर्याप्त मजदूरी अथवा अदायगी की शर्तों की वजह से और साथ ही कई दूसरी वजहों से अनवरत रूप से या तो सामान गिरवी रखने का या

फिर उधार का आश्रय लेती है। ये आजीविका के ऐसे साधन हैं जिनके बारे में किसी से उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हस्तक्षेप किये बिना जानकारी नहीं मांगी जा सकती। इस तरह दो विकल्प रह जाते हैं—या तो शाखा आजीविका के साधनों के जरिए केवल नैतिकता की गारंटियां हासिल करे—ऐसी स्थिति में जनरल कौंसिल का प्रस्ताव इस उद्देश्य की पूर्ति करता है... अथवा शाखा अपनी नियमावली की धारा २ में जानबूझकर यह कहती है कि सदस्यों को नैतिकता की गारंटियों के अलावा भी प्रवेश की शर्त के रूप में अपनी आजीविका के साधनों की जानकारी देनी होगी... ऐसी स्थिति में जनरल कौंसिल दृढ़तापूर्वक कहती है कि यह पूंजीवादी नवाचार है जो आम नियमावली के शब्दों तथा भावना के विपरीत है।”*

उनकी नियमावली की धारा ११ में कहा गया है—

“एक या अनेक डेलीगेट जनरल कौंसिल को भेजे जायेंगे।”

कौंसिल ने यह धारा हटाने के लिए कहा “क्योंकि इंटरनेशनल की आम नियमावली जनरल कौंसिल को डेलीगेट भेजने के शाखाओं के अधिकार को स्वीकार नहीं करती।” उसने आगे कहा—“आम नियमावली जनरल कौंसिल के सदस्यों के चुनाव के केवल दो तरीकों को मान्यता देती है—या तो उनका चुनाव कांग्रेस द्वारा हो अथवा उनका सहयोजन जनरल कौंसिल द्वारा किया जाये...”

यह सच है कि लन्दन स्थित कई शाखाएं जनरल कौंसिल को डेलीगेट भेजने के लिए आमंत्रित की गयी थीं; जनरल कौंसिल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आम नियमावली का उल्लंघन न हो, हमेशा निम्नलिखित ढंग से काम करती थी—वह पहले प्रत्येक शाखा द्वारा भेजे जानेवाले डेलीगेटों की संख्या निर्धारित कर लेती थी, ऐसा करते समय वह उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखती थी, यह चीज इस बात पर निर्भर करती थी कि जनरल कौंसिल उन्हें सौंपे जानेवाले आम कार्यों को पूरा करने के योग्य समझती है या नहीं। ये डेलीगेट अपनी शाखाओं द्वारा नामजदगी के बल पर जनरल कौंसिल के सदस्य नहीं बनते थे। वे इस अधिकार के बल पर सदस्य बनते

*कार्ल मार्क्स, ‘१८७१ की फ्रांसीसी शाखा के विषय में जनरल कौंसिल के प्रस्ताव का मसौदा’।—सं०

थे कि आम नियमावली कौंसिल को नये सदस्य सहयोजित करने का अधिकार देती थी। अन्तर्राष्ट्रीय संघ की जनरल कौंसिल तथा इंग्लैंड की केन्द्रीय कौंसिल के रूप में पिछली कांफ्रेंस में किये गये फ्रैंसले पर काम कर चुकने तक लन्दन कौंसिल ने सीधे सहयोजित सदस्यों के अलावा उन सदस्यों को भी भर्ती करने का निर्णय किया जिन्हें आरम्भ में उनकी अपनी शाखाओं ने नामजद करना उचित समझा था। जनरल कौंसिल की निर्वाचन कार्यपद्धति और पेरिस फ़ेडरल कौंसिल की, जो उदाहरण के लिए ब्रसेल्स फ़ेडरल कौंसिल अथवा मैड्रिड फ़ेडरल कौंसिल की तरह की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामजद राष्ट्रीय कौंसिल तक नहीं थी, निर्वाचन कार्यपद्धति को एक जैसा मान बैठना भूल होगी। पेरिस फ़ेडरल कौंसिल तो पेरिस शाखाओं का एक प्रतिनिधिमंडल मात्र थी... जनरल कौंसिल की निर्वाचन कार्यपद्धति की आम नियमावली में परिभाषा की गयी है... और उसके सदस्यों के लिए नियमावली तथा आम अधिनियमों के अलावा और कोई अनिवार्य अधिदेश विद्यमान नहीं है... यदि हम इससे पहले की धारा पर गौर करें तो पता चलेगा कि धारा ११ का अर्थ जनरल कौंसिल के गठन के पूर्ण परिवर्तन के अलावा और कुछ नहीं है, वह उसे आम नियमावली की धारा ३ के विपरीत लन्दन शाखाओं का प्रतिनिधिमंडल बना देती है जिसमें स्थानीय समूहों का प्रभाव पूरे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के प्रभाव का स्थान ले लेगा। आखिरी चीज, जनरल कौंसिल ने, जिसका पहला कर्तव्य कांग्रेसों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन है (देखें जेनेवा प्रशासनिक अधिनियमों की धारा १), घोषित किया कि वह “यह मानती है कि जनरल कौंसिल के गठन के सम्बन्ध में आम नियमावली की धाराओं में मूल परिवर्तन लाने के विषय में १८७१ की फ्रांसीसी शाखा द्वारा अभिव्यक्त विचारों का इस प्रश्न से कोई सरोकार नहीं है...”

इसके अलावा कौंसिल ने घोषित किया कि वह इस शाखा के दो प्रतिनिधियों को उन्हीं शर्तों पर कौंसिल में प्रवेश करने देगी जो लन्दन की अन्य शाखाओं के लिए रखी गयी हैं।

“१८७१ की शाखा” ने इस उत्तर से कतई सन्तुष्ट न होकर १४ दिसम्बर को एक “घोषणापत्र” प्रकाशित किया, जिस पर उसके नये सचिव समेत, जिसे शीघ्र ही उत्प्रवासियों के समूह से बदमाश बताकर निकाल दिया गया, तमाम शक्तियों के हस्ताक्षर थे। इस घोषणा के अनुसार जनरल कौंसिल पर आरोप लगाया गया कि उसने विधायी कार्य ग्रहण न कर “सामाजिक विचार को बुरी तरह तोड़ा-मरोड़ा” है।

इस दस्तावेज़ को तैयार करने में जिस नेकनीयती का परिचय दिया गया, उसकी चन्द मिसालें ये रहीं।

लन्दन कांग्रेस ने युद्ध के समय जर्मन मजदूरों के आचरण का अनुमोदन किया था। यह सर्वथा स्पष्ट था कि एक स्विस् डेलीगेट* द्वारा प्रस्तुत, एक बेल्जियन डेलीगेट द्वारा अनुमोदित तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत इस प्रस्ताव में इंटरनेशनल के जर्मन सदस्यों का ही जिक्र किया गया था जो युद्ध के समय अपने भ्रंशराष्ट्रवादविरोधी आचरण की कीमत जेलों में रहकर चुका रहे थे और अब भी चुका रहे हैं। यही नहीं, किसी गलत परिभाषा की सम्भावना रोकने के लिए जनरल कौंसिल के फ्रांस-सम्बन्धी सचिव** ने «*Qui Vive!*», «*Constitution*», «*Radical*», «*Emancipation*», «*Europe*», आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित एक पत्र में प्रस्ताव के वास्तविक अर्थ पर अभी-अभी प्रकाश डाला था। इसके बावजूद “१८७१ की फ्रांसीसी शाखा” के पन्द्रह सदस्यों ने आठ दिन बाद, २० नवम्बर १८७१ को «*Qui Vive!*» में जर्मन मजदूरों के विरुद्ध अपशब्दों से भरा एक “विरोध-पत्र” प्रकाशित कराया। उसमें कांग्रेस के प्रस्ताव को जनरल कौंसिल के “सर्वजर्मनवादी विचार” का अक्राट्य प्रमाण बताकर उसकी भर्त्सना की गयी थी। दूसरी ओर, जर्मनी के सामन्तों, उदारतावादियों तथा पुलिस के सारे अखबारों ने इस घटना का जर्मन मजदूरों के सामने यह साबित करने के लिए उपयोग किया कि उनके अन्तर्राष्ट्रीय सपनों पर किस तरह पानी फिर गया है। अन्ततः १८७१ की पूरी शाखा ने अपने १४ दिसम्बर के घोषणापत्र में २० नवम्बर के विरोध-पत्र को अनुमोदित कर दिया।

“जनरल कौंसिल सत्तावादिता की जिस खतरनाक ढलान में नीचे खिसकती जा रही थी”, उसे साबित करने के लिए घोषणापत्र ने “उसी जनरल कौंसिल द्वारा आम नियमावली के स्वयं उस द्वारा संशोधित आधिकारिक प्रकाशन” का हवाला दिया।

यह देखने के लिए नयी नियमावली पर एक नज़र डालना पर्याप्त है कि प्रत्येक नयी धारा के साथ एक परिशिष्ट है जिसमें उसकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेवाले मूल स्रोतों का हवाला दिया गया है! जहां तक “आधिकारिक प्रकाशन” शब्दों का सम्बन्ध है, इंटरनेशनल की पहली कांग्रेस ने तय किया था कि नियमावली

* निकोलाई उत्तिन। - सं०

** अगस्त सेर्राइये। - सं०

तथा अधिनियमों का “आधिकारिक तथा अनिवार्य” पाठ जनरल कौंसिल द्वारा प्रकाशित किया जायेगा (देखें “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की ३ सितम्बर से ८ सितम्बर १८६६ तक जेनेवा में हुई कार्यकारी कांग्रेस, पृष्ठ २७, टिप्पणी ”) ।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि १८७१ की शाखा का जेनेवा और नेवशातेल में असहमतिवादियों से निरन्तर सम्पर्क था। शालें नामक एक सदस्य फो, जिसने जनरल कौंसिल पर प्रहार करने में जितने ओज का परिचय दिया, उतना उसने कम्यून की रक्षा के समय कभी प्रदर्शित नहीं किया था, व० मालोन ने अप्रत्याशित रूप से पुनः प्रतिष्ठित कर दिया हालांकि मालोन कुछ ही समय पहले कौंसिल के एक सदस्य के नाम चिट्ठी में शालें के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगा चुके थे। परन्तु “१८७१ की फ्रांसीसी शाखा” अपना घोषणापत्र जारी कर भी नहीं पाया कि उसकी क्रतारों में गृहयुद्ध छिड़ गया। पहले थ्रेड्स, आवरियाल और कामेलिना अलग हुए। उसके बाद शाखा कई छोटे-छोटे समूहों में बंट गयी, जिनमें से एक के नेता श्री पियरे बेजिन्ये थे जिन्हें वालिन तथा दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए पहले जनरल कौंसिल से बाहर निकाला जा चुका था तथा बाद में १८६८ की ब्रसेल्स कांग्रेस द्वारा नियुक्त बेल्जियन आयोग द्वारा इंटरनेशनल से भिष्कासित कर दिया गया था। एक अन्य समूह व० लांदेक द्वारा स्थापित किया गया था जिन्हें पुलिस प्रीफेक्ट पियेती के एकाएक भाग जाने के कारण अपने शायित्व से मुक्त कर दिया गया था जिसकी वह

“ईमानदारी से पूर्ति कर रहा था, यानी वह आगे राजनीति में अथवा फ्रांस के इंटरनेशनल-संबंधी मामलों में हिस्सा न ले!” (देखें ‘पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का तीसरा मुकदमा’, १८७०, पृष्ठ ४) ।

दूसरी ओर लन्दन में फ्रांसीसी उत्प्रवासियों की बहुत बड़ी संख्या ने एक शाखा स्थापित की जिसका जनरल कौंसिल से पूरा तालमेल था।

सहबंध के लोगों ने, जो नेवशातेल फ़ेडरल कमेटी के पीछे छुपे हुए थे और इंटरनेशनल को विशृंखलित करने के लिए कहीं बड़े पैमाने पर एक और प्रयत्न करने के वास्ते कृतसंकल्प थे, १२ नवम्बर १८७१ को सोनविले में अपनी शाखाओं

की कांग्रेस आयोजित की। उनके अगुवा गिलोम ने अपने मित्र राबिन के नाम दो चिट्ठियों में जुलाई में ही जनरल कौंसिल को धमकी दे दी थी कि यदि वह “जेनेवा के डाकुओं के मुकाबले में” उन्हें सही नहीं मानेगी तो उसके विरुद्ध इस तरह का अभियान शुरू कर दिया जायेगा।

सोनविले कांग्रेस सोलह डेलीगेटों को लेकर बनी थी जो जेनेवा की नयी “समाजवादी क्रान्तिकारी प्रचार तथा कार्रवाई शाखा” समेत कुल मिलाकर नौ शाखाओं का प्रतिनिधि होने का दावा कर रहे थे।

सोलह ने अपना काम अराजकतावादी आज्ञाप्ति प्रकाशित कर प्रारम्भ किया जिसमें रोमांस फ्रेडरेशन के विघटन की घोषणा की गयी। उधर रोमांस फ्रेडरेशन ने सहबंध के सदस्यों को तमाम शाखाओं से बाहर निकालकर और इस तरह उन्हें “स्वायत्तता” दिलाकर बदला लिया। परन्तु कौंसिल को यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने सद्बुद्धि प्राप्त हो जाने के कारण लन्दन कांफ्रेंस द्वारा दिया गया जूरा फ्रेडरेशन नाम स्वीकार कर लिया।

इसके बाद सोलह की कांग्रेस ने “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के तमाम फ्रेडरेशनों के नाम एक परिपत्र” में कांफ्रेंस तथा जनरल कौंसिल पर प्रहार कर इंटरनेशनल का “पुनर्गठन” आरम्भ कर दिया।

परिपत्र के लेखकों ने जनरल कौंसिल पर मुख्यतया यह आरोप लगाया कि उसने १८७१ में कांग्रेस की जगह कांफ्रेंस बुलायी। पहले दी गयी कैफ़ीयत से पता चलता है कि ये प्रहार सीधे पूरे इंटरनेशनल के विरुद्ध लक्षित थे जो सर्वसम्मति से कांफ्रेंस आयोजित करने के लिए सहमत हो गया था, प्रसंगवश इस कांफ्रेंस में नागरिक राबिन तथा वास्तेलिका सहबंध का समुचित प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

प्रत्येक कांग्रेस में जनरल कौंसिल के अपने प्रतिनिधि थे; उदाहरण के लिए बाजेल कांग्रेस में वे छः थे। सोलह तो दावा करते हैं कि

“निर्णायक वोट वाले जनरल कौंसिल के छः डेलीगेटों के प्रवेश द्वारा कांफ्रेंस का बहुमत पहले ही धोखाधड़ी से सुनिश्चित कर दिया गया था।”

वस्तुतः कांफ्रेंस में जनरल कौंसिल के डेलीगेटों के बीच फ्रांसीसी उत्प्रासी और कोई नहीं, पेरिस कम्यून के प्रतिनिधि थे जबकि उसके अंग्रेज तथा स्विस् सदस्य विरले मौकों पर ही अधिवेशनों में भाग ले सकते थे, जिसकी पुष्टि कार्यवृत्तों से हो जाती है जो अगली कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। कौंसिल

के एक डेलीगेट के पास एक राष्ट्रीय फ़ेडरेशन का अधिवेश प्राप्त था। कांफ़्रेंस के नाम एक चिट्ठी के अनुसार एक दूसरे व्यक्ति का अधिवेश इसलिए रोक लिया गया था कि अख़बारों में उसकी मृत्यु का समाचार छप चुका था।* रह गया एक डेलीगेट। इस प्रकार अकेले वेल्जियम के डेलीगेटों और कौंसिल के डेलीगेटों का अनुपात ६ : १ था।

अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस ने, जो गुस्ताव दुरां के रूप में कांफ़्रेंस में नहीं घुस सकी, "गुप्त" कांफ़्रेंस का आयोजन कर आम नियमावली का उल्लंघन किये जाने की कटुतापूर्वक शिकायत की। वह हमारे आम अधिनियमों से इतनी परिचित नहीं थी कि उसे पता होता कि कांग्रेस की प्रशासनिक बैठकें तो गुप्त ही होनी चाहिए।

फिर भी इन शिकायतों को सोनविले के सोलह के बीच सहानुभूतिपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ, जो जोर-जोर से चिल्लाये—

“और इस सयसे बढ़ कर इस कांफ़्रेंस ने एक निर्णय घोषित किया है कि जनरल कौंसिल आगामी कांग्रेस का अथवा उसके स्थान पर कांफ़्रेंस का समय तथा स्थान स्वयं निश्चित करेगी; इस तरह हमें जनरल कांग्रेसों को, इंटरनेशनल के इन महान सार्वजनिक अधिवेशनों को ख़त्म कर दिये जाने की धमकी दी जाती है।”

सोलह यह समझने को राज़ी न थे कि इस निर्णय की अभिपुष्टि विभिन्न सरकारों को केवल यह बताने के लिए की गयी थी कि तमाम दमनकारी कार्रवाइयों के बावजूद इंटरनेशनल इस या उस रूप में अपनी आम बैठकें करने के लिए कृतसंकल्प है।

जेनेवा शाखाओं की २ दिसम्बर १८७१ को हुई आम सभा में नागरिकगण मालोन तथा लेफ़्रांसे ने, जिनका सभा में अप्रिय ढंग से स्वागत किया गया, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें सोनविले के सोलह लोगों द्वारा पास फ़रमानों की पुष्टि की गयी, जनरल कौंसिल की निन्दा की गयी और साथ ही कांफ़्रेंस को अशान्तिपूर्ण किया गया—। कांफ़्रेंस ने तय किया कि “कांफ़्रेंस के प्रस्ताव, जो प्रकाशित नहीं होनेवाले हैं, विभिन्न देशों की फ़ेडरल कौंसिलों के पास जनरल कौंसिल के सम्बन्धित सचिवों द्वारा भेज दिये जायेंगे।”

इस प्रस्ताव को, जो आम नियमावली तथा अधिनियमों के सर्वथा अनुरूप था, ७० मालोन तथा उनके मित्रों ने छलपूर्ण ढंग से इस तरह बदला कि उसका दूसरा रूप निम्नलिखित हो गया —

“कांफ्रेंस के कुछ प्रस्ताव केवल फ़ेडरल कौंसिलों के पास और सम्बन्धित सचिवों के पास भेजे जायेंगे।”

फिर उन्होंने जनरल कौंसिल पर आरोप लगाया कि उसने उन प्रस्तावों को, जिनका विशिष्ट उद्देश्य इंटरनेशनल को उन देशों में, जहां उस पर पाबन्दी है, पुनर्गठित करना था, “प्रचार” के जरिए पुलिस के हाथों में सौंपने से इन्कार कर “ईमानदारी के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है”।

नागरिकगण मालोन तथा लेफ़ांसे आगे शिकायत करते हैं कि

“इस कांफ्रेंस ने जनरल कौंसिल को उन सिद्धान्तों पर जिन पर संघ आधारित है, अथवा शाखाओं और फ़ेडरेशनों के सम्बन्धित हितों पर या अन्ततः समग्र रूप में संघ के आम हितों पर विचार करनेवाली शाखाओं या संघों के किसी भी मुखपत्र की निन्दा करने तथा उसे अनंगीकार करने का अधिकार देकर विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया है (देखें २१ अक्टूबर का «*Égalité*»)”।

सवाल उठता है कि २१ अक्टूबर को «*Égalité*» ने क्या प्रकाशित किया था? उसने एक प्रस्ताव प्रकाशित किया था जिसमें कांफ्रेंस “चेतावनी देती है कि आगे चलकर अपने को इंटरनेशनल का मुखपत्र कहने वाले उन तमाम अखबारों की खुले तौर पर निन्दा करना तथा उन्हें अनंगीकार करना जनरल कौंसिल के लिए अनिवार्य होगा जो «*Progrès*» और «*Solidarité*» के उदाहरणों का अनुकरण करते हुए पूंजीपति वर्ग के लोगों के सामने अपने कालमों में उन प्रश्नों पर बहस छेड़ेंगे जो विशिष्ट रूप से स्थानीय या फ़ेडरल कमेटियों और जनरल कौंसिल के लिए अथवा फ़ेडरल या जनरल कांग्रेसों की गुप्त और प्रशासनिक बैठकों के लिए आरक्षित हैं।”

७० मालोन के धिनौने विलाप का ठीक तरह मूल्यांकन करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यह प्रस्ताव ऐसे कुछ पत्रकारों की कोशिशों का रास्ता सदा-सर्वदा के लिए रोक देता है जो स्वयं इंटरनेशनल की मुख्य कमेटियों

का स्थान लेना चाहते हैं और उसमें वही भूमिका अदा करना चाहते हैं जिसे पत्रकारों के वोहेमियाई हल्के पूंजीवादी दुनिया में अदा कर रहे हैं। इसी तरह की एक कोशिश के फलस्वरूप जेनेवा फ़ेडरल कमेटी की नज़र में सहबंध के कुछ सदस्यों ने «*Égalité*» का, रोमांस फ़ेडरेशन के आधिकारिक मुखपत्र का इस ढंग से सम्पादन किया जो रोमांस फ़ेडरेशन के प्रति सर्वथा शत्रुतापूर्ण था।

प्रसंगतः, जनरल कौंसिल के लिए अख़बारों के अनुचित उपयोग की “सार्व-जनिक रूप से भर्त्सना करने तथा उन्हें अनंगीकार करने” के लिए लन्दन सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी थी क्योंकि वाज़ेल कांग्रेस ने निर्णय (प्रस्ताव २) किया था कि :

“शाखाओं को वे तमाम अख़बार, जिनमें संघ पर प्रहार किया जाता है, तत्काल जनरल कौंसिल के पास भेज देने चाहिए।”

रोमांस फ़ेडरल कमेटी २० दिसम्बर १८७१ के अपने घोषणापत्र में («*Égalité*», २४ दिसम्बर) कहती है, “यह स्पष्ट है कि यह धारा इसलिए स्वीकार नहीं की गयी कि जनरल कौंसिल संघ पर प्रहार करने वाले अख़बारों को अपनी फ़ाइलों में रख सके, उसे तो इसलिए स्वीकार किया गया कि वह उनका जवाब दे सके और जरूरत पड़ने पर कुत्साओं तथा द्वेषपूर्ण निन्दाओं के घातक प्रभाव को मिटा सके। यह भी स्पष्ट है कि यह धारा आम तौर पर सभी अख़बारों पर लागू होती है और यदि हम यह नहीं चाहते कि पूंजीवादी अख़बारों के प्रहारों को उनका उत्तर दिये बिना छोड़ दिया जाये तो अपनी मुख्य प्रतिनिधिमूलक संस्था, अर्थात् जनरल कौंसिल के जरिए उन अख़बारों को अनंगीकार करना और भी आवश्यक हो जाता है जो हमारे संघ की आड़ में हम पर प्रहार करते हैं।”

जब्रा इस बात पर गौर कर लें कि «*Times*» ने जो पूंजीवादी प्रेस का लेविथान है, «*Progrès*» (लियों के) ने, जो उदारतावादी पूंजीपति वर्ग का प्रकाशन है तथा «*Journal de Genève*»³⁴ ने, जो घोर प्रतिक्रियावादी अख़बार है, कांग्रेस के विरुद्ध बिल्कुल वैसे ही आरोप लगाये हैं जो नागरिकगण मालोन तथा लेफ़्रांसे ने लगाये हैं और प्रायः उनकी ही भाषा का उपयोग किया है।

सोलह के परिपत्र ने कांग्रेस के आयोजन को और आगे चल कर उसकी संरचना और उसके कथित गुप्त स्वरूप को चुनौती देने के बाद कांग्रेस के प्रस्तावों को चुनौती दी।

गवसे पहले यह कहते हुए कि बाज़ेल कांग्रेस ने

“जनरल कौंसिल को इंटरनेशनल की शाखाओं को प्रवेश देने अथवा प्रवेश देने से इन्कार करने और उन्हें मुअ्तिल करने का हक देकर”

अपने अधिकारों को त्याग दिया है, वह आगे कांफ़ेंस पर निम्नलिखित अपराध करने का आरोप लगाता है :

“इस कांफ़ेंस ने ... ऐसे निर्णय लिये हैं... जिनसे इंटरनेशनल, जो स्वायत्त शाखाओं का स्वतंत्र संघ है, अनुशासनबद्ध शाखाओं के सोपानिक और सत्तावादी संगठन में बदल सकता है जो पूरी तरह एक ऐसी जनरल कौंसिल के नियंत्रण में होगा जो अपनी इच्छा से उन्हें प्रवेश देने से इन्कार कर सकती है अथवा उनके कार्यकलाप को निलंबित कर सकती है!!”

आगे चलकर परिपत्र बाज़ेल कांग्रेस के सवाल को फिर उठाता है, जिसने मानो “जनरल कौंसिल के कार्यों के स्वरूप को विकृत किया है”।

सोलह के परिपत्र में अन्तर्विरोधों का सार इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है : १८७१ की कांफ़ेंस १८६९ की बाज़ेल कांग्रेस के प्रस्ताव के लिए उत्तरदायी है और जनरल कौंसिल नियमावली के पालन के लिए दोषी है जो उससे कांग्रेस के प्रस्तावों के कार्यान्वयन का तक्राज़ा करती है।

परन्तु कांफ़ेंस पर इन तमाम प्रहारों का वास्तविक कारण, वस्तुतः, अधिक गहन स्वरूप का है। पहली बात तो यह है कि उसने अपने प्रस्तावों द्वारा स्विट्ज़रलैंड में सहबंध के लोगों की तिकड़मों को विफल बना दिया। दूसरी चीज़ यह है कि सहबंध के प्रवर्तकों ने इटली, स्पेन तथा स्विट्ज़रलैंड के एक हिस्से और बेल्जियम में अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ के कार्यक्रम तथा बकूनिन के कामचलाऊ कार्यक्रम के बीच खूब सोची-समझी भ्रान्ति पैदा की तथा उसे आश्चर्यजनक धैर्य के साथ कायम रखा।

कांफ़ेंस ने सर्वहारा नीति तथा संकीर्णतावादी शाखाओं के सम्बन्ध में अपने दो प्रस्तावों में जानबूझकर पैदा की गयी इस भ्रान्ति की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पहले प्रस्ताव का उद्देश्य, जो बकूनिन के कार्यक्रम में प्रतिपादित राजनीतिक विरतिवाद की धज्जियां उड़ा देता है, अपने प्रस्तावना वाले अंशों में पूरी तरह

प्रस्तुत किया गया है जो ग्राम नियमावली, लोसां कांग्रेस के प्रस्ताव तथा अन्य पूर्ववर्ती उदाहरणों पर आधारित है।*

* मजदूर वर्ग की राजनीतिक कार्रवाई पर कांग्रेस का प्रस्ताव इस प्रकार है :

“यह ध्यान में रखते हुए

“कि नियमावली की प्रस्तावना में यह कहा गया है—‘मजदूर वर्ग की आर्थिक मुक्ति एक महान् ध्येय है, प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन को एक साधन के रूप में उसके अधीन होना चाहिए’;

“कि अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की उद्घाटन-घोषणा (१८६४) में कहा गया है—‘भूमि के प्रभु तथा पूंजी के प्रभु अपनी आर्थिक इजारेदारियों की रक्षा करने तथा उन्हें बरकरार रखने के लिए अपने राजनीतिक विशेषाधिकारों का सदैव उपयोग करते रहेंगे। इसलिए वे श्रम की मुक्ति को बढ़ावा देने के बजाय उसकी राह में हर सम्भव अड़चन डालना जारी रखेंगे... इसलिए राजनीतिक सत्ता हासिल करना मजदूर वर्ग का महान् कर्तव्य बन गया है’;

“कि लोसां कांग्रेस (१८६७) ने यह प्रस्ताव पास किया कि ‘मजदूरों की सामाजिक मुक्ति उनकी राजनीतिक मुक्ति से अविच्छेद्य है’;

“कि जनमतसंग्रह (१८७०) के ठीक पूर्व इंटरनेशनल के फ्रांसीसी सदस्यों की कथित साजिश के सम्बन्ध में जनरल कौंसिल की घोषणा में कहा गया है—‘निस्सन्देह हमारी नियमावली का भाव यही है कि इंग्लैंड, महाद्वीप तथा अमरीका में हमारी तमाम शाखाओं का विशेष ध्येय मजदूर वर्ग के संघर्ष के संगठन केन्द्रों के रूप में काम करना ही नहीं, बल्कि हमारे अन्तिम ध्येय की, मजदूर वर्ग की आर्थिक मुक्ति के ध्येय की सिद्धि की दिशा में अपने-अपने देशों में प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलन का समर्थन करना भी है’;

“कि मूल नियमावली के जाली अनुवादों ने विभिन्न परिभाषाओं को जन्म दिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के विकास तथा कार्यकलाप के लिए हानिकर हैं;

“वेलगाम प्रतिक्रियावाद को देखते हुए, जो मजदूरों द्वारा मुक्ति के लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रयास को उग्रतापूर्वक कुचल देता है तथा वर्गों के विरोध का तथा उससे उत्पन्न होनेवाले सम्पत्तिधारियों के राजनीतिक प्रभुत्व को पाशविक शक्ति द्वारा कायम रखने का प्रयास करता है;

“यह ध्यान में रखते हुए

“कि मजदूर वर्ग सम्पत्तिधारियों की इस सामूहिक शक्ति के विरुद्ध वर्ग के रूप में केवल उसी सूरत में कार्रवाई कर सकता है जब वह अपने को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित करे जो सम्पत्तिधारियों द्वारा बनायी गयी पहले की तमाम पार्टियों से भिन्न तथा उनके विरुद्ध हो;

आइये, अब संकीर्णतावादी शाखाओं की ओर बढ़ें।

पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध सर्वहारा के संघर्ष के पहले दौर का लाक्षणिक गुण संकीर्णतावादी आन्दोलन होता है। यह स्थिति ऐसे समय तर्कसंगत हुआ करती है जब सर्वहारा अभी वर्ग के रूप में कार्यवाही कर सकने लायक विकसित नहीं होता। कतिपय चिन्तक सामाजिक विरोधों की आलोचना करते हुए उनके लिए अजीबोगरीब समाधानों का सुझाव देते हैं जबकि मजदूर जनसमूह उनकी स्वीकृति, प्रचार तथा कार्यान्वयन करता है। इन प्रवर्तकों द्वारा स्थापित संकीर्ण पंथ स्वभाव से ही विरतिवादी होते हैं यानी समस्त वास्तविक कार्यकलाप, राजनीति, हड़तालों, संघबद्धताओं, कहने का मतलब है, कोई भी संयुक्त आन्दोलन उनके लिए विजातीय होता है। सर्वहारा जनसमूह उनके प्रचार के प्रति सदैव उदासीन रहता है, यही नहीं उनका विरोधी भी होता है। पेरिस और लियो के मजदूरों को सेंट-साइमनपंथी, फुरिएपंथी, इकारियाई³⁵ को उतने ही अस्वीकार्य थे जितने ओवेनपंथी चार्टिस्टों³⁶ तथा आंग्ल ट्रेड यूनियनपंथियों को थे। ये पंथ आरम्भ में आन्दोलन के उत्तोलक के रूप में काम करते हैं लेकिन ज्योंही आन्दोलन का आकार उनसे बड़ा हो जाता है, वे तुरन्त उसकी राह में बाधक बन जाते हैं; तब वे प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। ज़रा फ्रांस और इंग्लैंड में इन पंथों को और इधर जर्मनी में लासालपंथियों को देखिये जो वर्षों तक सर्वहाराओं के संगठन में अड़चन डालने के बाद अन्त में सीधे-सीधे पुलिस के हाथों के साधन बन गये। निष्कर्ष यह है कि हमारे सामने यह उसी तरह सर्वहारा आन्दोलन की शैशवावस्था है जिस तरह ज्योतिषशास्त्र तथा कीमियागीरी विज्ञान की शैशवावस्था हैं। इंटरनेशनल की स्थापना सम्भव हो जाने के लिए यह आवश्यक ही था कि सर्वहारा इस दौर के बीच से गुज़रता।

तरह-तरह की सनकों तथा प्रतिद्वन्द्विताओं वाले इन संकीर्णतावादी संगठनों के

“कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मजदूर वर्ग का यह गठन सामाजिक क्रान्ति और उसके अन्तिम ध्येय की, वर्गों के उन्मूलन के ध्येय की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है;

“कि शक्तियों के एकीकरण को जिसे अपने आर्थिक संघर्षों के ज़रिए मजदूर वर्ग पहले ही स्थापित कर चुका है, साथ ही ज़मींदारों और पूँजीपतियों की राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध अपने संघर्षों के उत्तोलक का भी काम करना चाहिए—

“कांफ्रेंस इंटरनेशनल के सदस्यों को स्मरण कराती है

“कि मजदूर वर्ग के संघर्ष में उसका आर्थिक आन्दोलन तथा उसकी राजनीतिक कार्यवाही एक दूसरे से अटूट रूप से सूत्रबद्ध हैं”।

विपरीत इंटरनेशनल समस्त देशों के सर्वहारा वर्ग का सच्चा तथा जुझारू संगठन है जो पूंजीपतियों तथा जमींदारों के विरुद्ध, राज्य के रूप में संगठित उनके वर्ग प्रभुत्व के विरुद्ध समान संघर्ष के सूत्र से बंधा हुआ है। इसलिए इंटरनेशनल की नियमावली मात्र साधारण "मजदूर सोसायटियों" की बात करती है जो सब एक ही लक्ष्य का अनुसरण करती हैं तथा सर्वहारा आन्दोलन की एक आम रूपरेखा प्रस्तुत करनेवाले एक ही कार्यक्रम को स्वीकार करती हैं जबकि इस रूपरेखा के सैद्धान्तिक निरूपण का कार्य व्यावहारिक संघर्ष की आवश्यकताओं पर तथा शाखाओं, उनके निकायों तथा कांग्रेसों में, जहां बिना किसी अपवाद के सारी समाजवादी आस्थाओं को अभिव्यक्त किया जाता है, विचार-विनिमय पर छोड़ दिया जाता है।

जिस तरह प्रत्येक नये ऐतिहासिक दौर में पुरानी गलतियां क्षणभर के लिए पुनः प्रकट होकर तुरन्त लुप्त हो जाती हैं, उसी तरह इंटरनेशनल के अन्दर भी संकीर्णतावादी पंथों का पुनरुज्जीवन हुआ, भले ही कम प्रत्यक्ष रूप में।

सहबंध, यह मानते हुए कि पंथों का पुनरुज्जीवन आगे की ओर एक बहुत बड़ा पग है, स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उनका वक्त गुजर चुका है क्योंकि जहां उनमें आरम्भ में प्रगति के तत्व थे, वहां सहबंध का कार्यक्रम "क्रान बिना मुहम्मद" ³⁷ की तरह ऐसे शब्दाडम्बरपूर्ण विचारों के अम्बार के अलावा और कुछ नहीं है जो बहुत पहले निष्प्राण हो चुके थे और जो या तो केवल पूंजीवादी मूर्खों को भयभीत करने की क्षमता रखते हैं अथवा इंटरनेशनल के सदस्यों पर मुकदमा चलानेवाले बोनापार्टपंथी या अन्य अभियोजकों के लिए उपयोगी प्रमाण का काम दे सकते हैं।*

सम्मेलन ने, जिसमें सब रंग के समाजवादियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, संकीर्णतापंथी शाखाओं के विरुद्ध प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया, उसका यह पूर्ण विश्वास था कि यह प्रस्ताव, जिसमें इंटरनेशनल के वास्तविक स्वरूप

* इंटरनेशनल के सम्बन्ध में पुलिस के हाल के प्रकाशन, जिनमें विदेशी सत्ताओं के नाम फ्रांसे का परिपत्र तथा दूफोर योजना पर देहाती सभा के सदस्य साकाज की रिपोर्ट शामिल हैं, सहबंध के शब्दाडम्बरपूर्ण घोषणापत्रों ³⁸ से लिये गये उद्धरणों से भरे पड़े हैं। इन संकीर्णतावादियों का, जिनका आमूल परिवर्तनवाद सर्वथा लफ्फाजी तक सीमित है, शब्दभंडार प्रतिक्रियावादियों के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए अतीव उपयोगी है।

पर एक बार फिर जोर दिया गया, उसके विकास की एक नयी मंजिल का द्योतक होगा। सहबंध के समर्थकों ने, जिन पर इस प्रस्ताव ने घातक प्रहार किया, इसे इंटरनेशनल पर जनरल कौंसिल की विजय मात्र माना, जिसके जरिए—जैसा कि उनके परिपत्र ने लक्षित किया—जनरल कौंसिल ने अपने कुछ सदस्यों के “विशेष कार्यक्रम का प्रभुत्व”, “उनका वैयक्तिक सिद्धान्त”, “कट्टरपंथी सिद्धान्त”, “आधिकारिक सिद्धान्त, संघ के अन्दर एकमात्र अनुमेय” सिद्धान्त सुनिश्चित बनाया। प्रसंगतः, यह उन चन्द सदस्यों का कसूर नहीं था, अपितु इस तथ्य का आवश्यक परिणाम, “अष्टकारी प्रभाव” था कि वे जनरल कौंसिल के सदस्य थे, क्योंकि

“ऐसे व्यक्ति के लिए नैतिक व्यक्ति बना रहना सर्वथा असम्भव है जिसे अपने साथियों पर अधिकार” (!) “प्राप्त है। जनरल कौंसिल तिकड़मों का सरगर्म अड्डा बनती जा रही है।”

सोलह की राय में इंटरनेशनल की आम नियमावली की इसलिए भर्त्सना की जानी चाहिए कि उसने जनरल कौंसिल को नये सदस्य सहयोजित करने का अधिकार देकर बहुत बड़ी गलती की है। उनका दावा है कि इस तरह अधिकार प्राप्त कर

“जनरल कौंसिल, जब जरूरत समझे, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का समूह सहयोजित कर सकती है जो कौंसिल के बहुमत तथा उसकी प्रवृत्तियों के स्वरूप को बदलने के लिए पर्याप्त होगी।”

वे यह सोचते प्रतीत होते हैं कि जनरल कौंसिल का सदस्य मात्र होना व्यक्ति की नैतिकता ही नहीं, वरन् उसकी विवेक-बुद्धि नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। वरना हम कैसे यह मान सकते हैं कि बहुमत स्वेच्छया सहयोजित होकर अपने को अल्पमत में बदल देगा?

कुछ भी हो, स्वयं सोलह इन सब बातों के बारे में पूर्ण आश्वस्त प्रतीत नहीं होते क्योंकि वे आगे शिकायत करते हैं कि जनरल कौंसिल

“उन्हीं लोगों को, बार-बार निर्वाचित होनेवाले लोगों को लेकर पांच साल के लिए गठित की गयी है”

और इसके फ़ौरन बाद वे यह दुहराते हैं—

“उनमें से अधिकांश नियमित अधिदेश प्राप्त लोग नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस द्वारा निर्वाचित नहीं हुए हैं।”

परन्तु तथ्य यह है कि जनरल कौंसिल का ढांचा निरन्तर बदलता रहता है हालांकि बेल्जियम, फ्रांसीसी स्विट्ज़रलैंड, आदि की फ़ेडरल कौंसिलों की तरह कुछ संस्थापक कौंसिल के सदस्य बने रहते हैं।

जनरल कौंसिल को यदि अपने अधिदेश का पालन करना है तो उसे तीन अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी। पहले, विविध कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए उसके पास सदस्य पर्याप्त संख्या में होने चाहिए; दूसरे, “अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ में प्रतिनिधित्व प्राप्त विभिन्न राष्ट्रों के मेहनतकश” उसके सदस्य हों; और आखिरी शर्त, उसमें मजदूर तत्व का प्रभुत्व हो। चूंकि मजदूरों के काम की अपेक्षाओं के कारण जनरल कौंसिल की सदस्यता में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वह सहयोजित करने के अधिकार के बिना इन तमाम अनिवार्य शर्तों को कैसे पूरा कर सकती है? फिर भी कौंसिल इस अधिकार की अधिक सूक्ष्म परिभाषा को आवश्यक मानती है, जैसा कि हाल की कांग्रेस में परिलक्षित किया गया।

एक के बाद दूसरी कांग्रेस में, जहां इंग्लैंड को निश्चित रूप से कम प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जनरल कौंसिल के आरम्भिक सदस्यों का पुनर्निर्वाचन स्पष्टतया यह सिद्ध करता है कि उसने उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्दर अपने कर्तव्य की पूर्ति की है। इसके विपरीत सोलह इसे “कांग्रेसों के अंधविश्वास” का एक प्रमाण मात्र मानते हैं जिसे बाज़ेल कांग्रेस में इस हद तक आगे बढ़ाया गया कि

“एक तरह जनरल कौंसिल के पक्ष में स्वेच्छया गद्दी छोड़ दी गयी।”

उनकी राय में जनरल कौंसिल की “सामान्य भूमिका मामूली पत्रव्यवहार तथा सांख्यिकीय कार्यालय” की होनी चाहिए। नियमावली के ग़लत अनुवाद से हासिल की गयी कई धाराओं के बल पर वे इस परिभाषा को उचित ठहराते हैं।

तमाम पूंजीवादी संस्थाओं की नियमावलियों के विपरीत इंटरनेशनल की आम नियमावली अपने प्रशासनिक संगठन को सरसरी तौर पर स्पर्श करती है। इसके विकास को वह व्यवहार पर तथा उसे नियमित बनाने के कार्य को भावी कांग्रेसों पर छोड़ देती है। फिर भी, विभिन्न देशों की शाखाओं की एकता तथा संयुक्त कार्रवाई ही चूंकि उन्हें वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर सकती थीं, इसलिए नियमावली संगठन के अन्य निकायों की तुलना में कौंसिल की ओर अधिक ध्यान देती है।

मूल नियमावली³⁹ की धारा ५ में कहा गया है:

“जनरल कौंसिल विभिन्न राष्ट्रीय तथा स्थानीय समूहों का एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है”

और इसके बाद उसमें इस बात के कुछ उदाहरण दिये गये हैं कि उसे किस तरह काम करना चाहिए। इन उदाहरणों में एक में कौंसिल से यह अनुरोध किया गया है कि “जब कभी तत्काल व्यावहारिक क्रम—उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के मामले में—उठाने की आवश्यकता हो, संघ से सम्बद्ध संस्थाओं की कार्रवाई एकसाथ और एक जैसी होनी चाहिए।”

धारा में आगे कहा गया है—

“जब कभी उपयुक्त समझा जाये, जनरल कौंसिल अपनी पहल पर विभिन्न राष्ट्रीय अथवा स्थानीय संस्थाओं के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।”

इसके अलावा नियमावली कांग्रेसों का आयोजन करने तथा उनकी व्यवस्था करने के बारे में कौंसिल की भूमिका की परिभाषा करती है तथा उसे कतिपय रिपोर्टें तैयार कर उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य सौंपती है। मूल नियमावली में विभिन्न समूहों के स्वतंत्र कार्यकलाप तथा समग्र रूप में संघ के कार्यकलाप की एकता के बीच इतना कम भेद किया गया था कि धारा ६ में कहा गया है—

“चूंकि प्रत्येक देश में मजदूर आन्दोलन की सफलता एकता तथा संगठन की शक्ति के बल पर ही हासिल की जा सकती है तथा दूसरी ओर इनसे जनरल कौंसिल का कार्यकलाप और अधिक कारगर होगा... इंटरनेशनल के सदस्य अपने-अपने देशों में मजदूरों की असम्बद्ध संस्थाओं को राष्ट्रीय संगठनों में, जिनका प्रतिनिधित्व केन्द्रीय राष्ट्रीय निकाय करें, सूत्रबद्ध करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करेंगे।”

जेनेवा कांग्रेस के प्रथम प्रशासनिक प्रस्ताव (धारा १) में कहा गया है—

“कांग्रेस के प्रस्तावों को अमल में लाने का दायित्व जनरल कौंसिल पर है।”

इस प्रस्ताव ने जनरल कौंसिल की उस स्थिति को वैधता प्रदान की है जिसे वह अपने जन्म से ही अपनाती आयी है—यह है संघ के कार्यकारी निकाय की स्थिति। किसी अन्य “स्वतंत्र रूप से मान्य सत्ता” के अभाव में किसी नैतिक “सत्ता” का उपयोग किये बिना आदेशों का कार्यान्वयन कठिन है। साथ ही जेनेवा कांग्रेस ने जनरल कौंसिल को “नियमावली के आधिकारिक तथा अनिवार्य पाठ को प्रकाशित करने का दायित्व सौंपा।”

इसी कांग्रेस ने तय किया (जेनेवा कांग्रेस का प्रशासनिक प्रस्ताव, धारा १४) —

“प्रत्येक शाखा को स्थानीय परिस्थितियों और अपने देश के कानूनों के अनुकूल अपनी नियमावली तथा अधिनियम तैयार करने का अधिकार है, परन्तु उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जो आम नियमावली तथा अधिनियमों के विपरीत हो।”

आइये, सबसे पहले इस ओर ध्यान दें कि सिद्धान्तों की किसी भी तरह की ऐसी विशेष घोषणाओं अथवा किसी भी प्रकार के ऐसे विशेष कार्यभारों की ओर लेशमात्र संकेत नहीं है जिन्हें इस या उस शाखा को उस समान लक्ष्य के अलावा, जिसका इंटरनेशनल के सभी ग्रूप अनुसरण करते हैं, अपने लिए निर्धारित करना चाहिए। मसला केवल आम नियमावली तथा अधिनियमों को “अपने देश की स्थानीय परिस्थितियों और अपने देश के कानूनों” के अनुकूल बनाने के शाखाओं के अधिकार से सम्बन्ध रखता है।

दूसरे, किसे यह तय करना है कि कोई विशेष नियम नियमावली के अनुरूप है या नहीं? जाहिर है, यदि कोई ऐसी “सत्ता” न हो, जिस पर इस कार्यभार का दायित्व सौंपा जाये, तो यह प्रस्ताव व्यर्थ हो जायेगा। संघ के अन्दर पुलिस की शाखाएं या वैरभाव रखनेवाली शाखाएं ही नहीं बनेंगी, अपितु उसके अन्दर ऐसे वर्गच्युत संकीर्णतावादी तथा पूंजीवादी लोकोपकारी तक घुस आयेंगे जो उसके स्वरूप को विकृत कर सकते हैं और ये तत्व कांग्रेसों में अपनी तादाद के बल पर मजदूरों को कुचल सकते हैं।

राष्ट्रीय तथा स्थानीय फ़ेडरेशन अपने जन्म से ही अपने-अपने देशों में यह देखते हुए कि नयी शाखाओं के नियम आम नियमावली के अनुरूप हैं या नहीं,

उन्हें प्रवेश करने देने या इससे इन्कार करने के अधिकार का उपभोग करते आये हैं। जनरल कौंसिल द्वारा इस कार्य की पूर्ति के लिए आम नियमावली की धारा ६ में व्यवस्था की गयी है जो स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं को, अर्थात् सम्बन्धित देश में फ़ेडरल निकाय के बाहर गठित संस्थाओं को जनरल कौंसिल के साथ सीधे सम्पर्क स्थापित करने का अधिकार देती है। सहबंध ने बाज़ेल कांग्रेस के डेलीगेटों के प्रवेश के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति कर सकने के लिए इस अधिकार का उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया था।

नियमावली की धारा ६ में कतिपय देशों में राष्ट्रीय फ़ेडरेशनों की राह में कानूनी अड़चनों की परिकल्पना की गयी है, फलस्वरूप वहाँ जनरल कौंसिल से फ़ेडरल कौंसिल के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया है (देखें लोसां कांग्रेस, आदि के कार्यवृत्त, १८६७, पृष्ठ १३⁴⁰)।

कम्यून की पराजय के उपरान्त विभिन्न देशों में कानूनी अड़चनें कई गुना बढ़ती जा रही हैं, इस कारण जनरल कौंसिल के लिए वहाँ ऐसी कार्रवाई करना और भी आवश्यक हो गया है जिससे संदिग्ध तत्व संघ से बाहर रखे जा सकें। यही कारण है कि फ़्रांसीसी समितियों ने हाल में पुलिस के भेदियों से छुटकारा पाने के लिए जनरल कौंसिल से हस्तक्षेप करने की मांग की और यही कारण है कि एक अन्य बड़े देश में * इंटरनेशनल के सदस्यों ने उससे अनुरोध किया कि वह किसी ऐसी शाखा को मान्यता न दे जो उनके प्रत्यक्ष अधिदेश द्वारा अथवा स्वयं उन द्वारा स्थापित न हुई हो। उनके अनुरोध को ऐसे छद्मउत्तेजकों से छुटकारा पाने की आवश्यकता ने प्रेरित किया था जिनका प्रबल उत्साह ऐसी शाखाओं की द्रुत गति से स्थापना में प्रकट हुआ जो अपने आमूल परिवर्तनवाद के मामले में अभूतपूर्व थीं। दूसरी ओर, तथाकथित सत्तावादविरोधी शाखाएं अपने बीच टकरावों को पैदा होते ही कौंसिल से अपील करने में संकोच नहीं करतीं, यही नहीं, वे उससे अपने विरोधियों के साथ सख्ती बरतने के लिए कहने में भी नहीं झिझकतीं, लियों की टकराव इसकी मिसाल है। अभी हाल ही में, सम्मेलन के बाद, तूरीन "मज़दूर फ़ेडरेशन" ने अपने को इंटरनेशनल की शाखा घोषित किया। उसके बाद पड़ी फूट के फलस्वरूप अल्पसंख्या ने "सर्वहारा मुक्ति" समाज⁴¹ की स्थापना की। यह संस्था इंटरनेशनल में शामिल हो गयी और उसने जूरा के लोगों के पक्ष में प्रस्ताव पास कर काम शुरू किया। उसके अखबार

* आस्ट्रिया। - सं०

«Proletario» के पन्ने सब तरह के सत्तावाद के विरुद्ध रोषपूर्ण शब्दों से रंगे पड़े हैं। समाज का चन्दा भेजते हुए सचिव* ने जनरल कौंसिल को आगाह किया कि शायद पुराना फ़ेडरेशन भी चन्दा भेजे। फिर वह लिखते हैं:

“जैसा कि आपने «Proletario» में पढ़ा होगा, सर्वहारा मुक्ति समाज ने... घोषित किया है कि वह... पूंजीपति वर्ग के साथ, जो मजदूरों के नकाब में मजदूर फ़ेडरेशन स्थापित कर रहा है, किसी भी तरह की एकजूटता स्वीकार नहीं करेगा”

और वह कौंसिल से प्रार्थना करते हैं कि वह

“इस प्रस्ताव को सारी शाखाओं के पास भेज दे तथा १० साल्तीम चन्दा भेजे जाने की सूरत में उसे लेने से इन्कार कर दे।”**

इंटरनेशनल के तमाम अन्य संगठनों की भांति जनरल कौंसिल से भी प्रचार करने की अपेक्षा की जाती है। यह कार्य उसने अपने घोषणापत्रों तथा प्रतिनिधियों के ज़रिए किया है जिन्होंने उत्तरी अमरीका, जर्मनी तथा कई फ़्रांसीसी नगरों में इंटरनेशनल के प्रथम संगठनों का आधार कायम किया।

जनरल कौंसिल का एक अन्य कार्य है हड़तालियों की मदद करना तथा पूरे इंटरनेशनल द्वारा उनके लिए समर्थन संगठित करना (देखें विभिन्न कांग्रेसों के समक्ष जनरल कौंसिल की रिपोर्टें)। निम्न तथ्य अन्य बातों के अलावा हड़ताल आन्दोलन में उसके हस्तक्षेप का महत्व लक्षित करता है। अंग्रेज़ फ़ाउंड्रीमैनों की प्रतिरोध संस्था स्वयं एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जिसकी अन्य देशों में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका में शाखाएं हैं। फिर भी अमरीकी फ़ाउंड्रीमैनों

* कार्लो तेज़ागो। - सं०

** उस समय ये सर्वहारा मुक्ति समाज के प्रतीयमान विचार थे, जिसका प्रतिनिधित्व उसका सह-सचिव, बकूनिन का दोस्त कर रहा था। वस्तुतः इस शाखा की प्रवृत्तियां सर्वथा भिन्न थीं। इस समाज ने दुरंगी चाल चलनेवाले इस व्यक्ति पर ग़वन करने और तुरीन पुलिस के प्रधान के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने का आरोप लगाकर उसे बाहर निकालने के बाद अपनी सफ़ाई दी जिसमें उसने अपने तथा जनरल कौंसिल के बीच सारी ग़लतफ़हमी दूर कर दी।

ने अपनी हड़ताल के दौरान अंग्रेज फ़ाउंड्रीमैनों को अमरीका पहुंचाने से रोकने के लिए जनरल कौंसिल का हस्तक्षेप आवश्यक समझा।

इंटरनेशनल के विकास ने जनरल कौंसिल तथा तमाम फ़ेडरल कौंसिलों के लिए पंच की भूमिका ग्रहण करना आवश्यक बना दिया।

ब्रसेल्स कांग्रेस ने निश्चय किया—

“फ़ेडरल कौंसिलों के लिए अपने प्रशासन तथा वित्तीय स्थिति के बारे में त्रिमाही रिपोर्ट जनरल कौंसिल को भेजना आवश्यक है (प्रशासनिक प्रस्ताव, नं० ३)।

अन्ततः बाज़ेल कांग्रेस ने, जो सोलह के घोर प्रकोप का पात्र बन गयी है, संघ के विकास के फलस्वरूप जन्म लेनेवाले प्रशासनिक सम्बन्धों का विनियमन करने तक ही अपने को व्यक्त रखा। यदि उसने जनरल कौंसिल के अधिकारों की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार किया तो इसके लिए यदि बकूनिन, श्विट्ज़गेबेल, एफ़० रावर्ट, गिलोम तथा सहबंध के अन्य डेलीगेट नहीं तो और कौन दोषी थे? वे यही चीज़ हासिल करने के लिए तो अत्यधिक उत्सुक थे। अथवा क्या वे स्वयं अपने ऊपर लन्दन जनरल कौंसिल में “आखें मूंद कर विश्वास” करने का आरोप लगायेंगे?

ये रहे बाज़ेल कांग्रेस के दो प्रस्ताव :

“४. गठित होनेवाली हर नयी शाखा या सोसायटी को, जो इंटरनेशनल में शामिल होना चाहती है, तत्काल जनरल कौंसिल को इसकी सूचना देनी चाहिए,”

और “५. जनरल कौंसिल को किसी भी नयी सोसायटी या ग्रूप को अपने साथ संलग्न करने का अथवा इससे इन्कार करने का अधिकार है; इस निर्णय के विरुद्ध अगली कांग्रेस में अपील की जा सकती है।”

जहां तक फ़ेडरल निकाय से बाहर स्थापित स्थानीय स्वतंत्र संस्थाओं का प्रश्न है, ये धाराएं उस व्यवहार की पुष्टि ही करती हैं, जिसका इंटरनेशनल स्थापित होने के समय से ही अनुशीलन किया जाता रहा है, और जिनका पालन संघ के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। परन्तु इस व्यवहार का विस्तार करना तथा उसे गठन की प्रक्रिया से गुज़र रही किसी शाखा या सोसायटी पर बिना सोच-समझे लागू करना सीमा का अतिक्रमण होगा। ये धाराएं जनरल कौंसिल के फ़ेडरेशनों के

आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का यक्रीनन अधिकार देती हैं, परन्तु जनरल कौंसिल ने इस अर्थ में उन्हें कभी लागू नहीं किया। जनरल कौंसिल का दावा है कि सोलह एक भी ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकते जो यह बताती हो कि अपने को भौजूद ग्रूपों या फ़ेडरेशनों के साथ संलग्न करने के लिए इच्छुक नयी शाखाओं के मामलों में जनरल कौंसिल ने कभी हस्तक्षेप किया।

ऊपर उद्धृत प्रस्ताव गठित हो रही शाखाओं की चर्चा करते हैं जबकि निम्नलिखित प्रस्ताव पहले ही गठित हो चुकी शाखाओं की चर्चा करते हैं—

“६. जनरल कौंसिल को आगामी कांग्रेस तक इंटरनेशनल की किसी शाखा को निलम्बित करने का भी अधिकार है।”

“७. किसी राष्ट्रीय ग्रूप की संस्थाओं या शाखाओं के बीच अथवा विभिन्न राष्ट्रीय ग्रूपों के बीच झगड़े पैदा हो जाने पर जनरल कौंसिल को झगड़ा निपटाने का अधिकार होगा; उसके निर्णय के विरुद्ध आगामी कांग्रेस में अपील की जा सकती है जिसे अपना अन्तिम निर्णय देना होगा।”

ये दो धाराएं किसी चरम अवस्था में ही आवश्यक होती हैं हालांकि अभी तक जनरल कौंसिल को कभी उनका आश्रय नहीं लेना पड़ा है। ऊपर प्रस्तुत समीक्षा बताती है कि जनरल कौंसिल ने कभी कोई शाखा निलम्बित नहीं की है और विवादों के उत्पन्न होने की दशा में दो पक्षों के बीच पंच के रूप में ही काम किया है।

हम अन्ततः उस कार्य पर पहुंचते हैं जिसे संघर्ष की आवश्यकताओं ने जनरल कौंसिल पर थोपा है। सहबंध के समर्थकों को चाहे कितना ही सदमा पहुंचे, यह एक तथ्य है कि सर्वहारा आन्दोलन के सभी शत्रुओं द्वारा जनरल कौंसिल पर किये जानेवाले प्रहारों की अनवरतता ने ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के मोर्चाओं के हरावल के स्थान पर पहुंचाया है।

इंटरनेशनल से उसके विद्यमान रूप में इस तरह निपट चुकने के बाद सोलह हमें बताते हैं कि उसे कैसा होना चाहिए।

सर्वप्रथम, जनरल कौंसिल को औपचारिक रूप में एक साधारण पत्रव्यवहार तथा सांख्यिकीय कार्यालय होना चाहिए। अपने संगठनात्मक कार्यों से मुक्त हो

जाने पर उसका पत्रव्यवहार संघ के अखबारों में प्रकाशित हो चुकी सूचनाओं को फिर से उद्धृत करना मात्र रह जायेगा। इस प्रकार पत्रव्यवहार कार्यालय अनावश्यक हो जायेगा। जहाँ तक सांख्यिकी का प्रश्न है, वह कार्य तभी सम्भव है जब एक मजदूर संगठन हो और विशेष रूप से जब ग्राम निर्देश व्यवस्था हो, जैसा कि मूल नियमावली में साफ़-साफ़ कहा गया है। चूंकि इस सब से बहुत अधिक "सत्तावाद" की गंध आती है, इसलिए एक कार्यालय का रखा जाना सम्भव है परन्तु सांख्यिकी किसी भी सुरत में नहीं। संक्षेप में, जनरल कौंसिल लुप्त हो जायेगी। इसी तर्क के बल पर फ़ेडरल कौंसिलें, स्थानीय समितियाँ तथा अन्य "सत्तावादी" केन्द्र भी खत्म हो जायेंगे। स्वायत्त शाखाएं ही बनी रहेंगी।

तो फिर इन "स्वायत्त शाखाओं का", मुक्त रूप से संघबद्ध, तमाम उच्च निकायों से, "मजदूरों द्वारा निर्वाचित तथा गठित उच्च निकाय तक" से सुखद रूप में छुटकारा पानेवाली इन "स्वायत्त शाखाओं" का क्या उद्देश्य होगा?

यहां सोलह की कांग्रेस के समक्ष जूरा फ़ेडरल कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को परिपत्र के साथ जोड़ना आवश्यक है।

"मजदूर वर्ग को मानवजाति के नये हितों का वास्तविक प्रतिनिधि बना सकने के लिए" उसके संगठन को "उस विचार से पथ-प्रदर्शन पाना चाहिए जो विजयी होकर रहेगा। इस विचार को हमारे युग की आवश्यकताओं, मानवजाति की जीवन्त आकांक्षाओं, सामाजिक जीवन के घटना-व्यापार के सुसंगत अध्ययन के जरिए विकसित करना, फिर इस विचार को हमारे मजदूरों के संगठनों तक पहुंचाना—हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, आदि।" अन्त में, "हमारी मजदूर आवादी के बीच एक वास्तविक क्रान्तिकारी समाजवादी विद्यालय" का निर्माण किया जाना चाहिए।

इस तरह स्वायत्त मजदूर शाखाएं पलक झपकते ही ऐसे विद्यालयों में बदल दी जाती हैं, जहां सहबंध के सज्जन अध्यापक होंगे। "सुसंगत अध्ययन" द्वारा, जो अपने पीछे कोई चिह्न नहीं छोड़ता, वे यह विचार विकसित करते हैं। फिर वे "इस विचार को हमारे मजदूर संगठनों के पास पहुंचाते हैं।" उनके लिए मजदूर वर्ग इस तरह की कच्ची सामग्री, ऐसी विशृंखलता है कि उस द्वारा आकार ग्रहण किये जाने के लिए उन्हें उसमें अपनी पुनीत आत्मा से पूंक भरनी होगी।

यह सब सहबंध के उस पुराने कार्यक्रम के पद-विन्यास के अलावा और कुछ नहीं है जो इन शब्दों से शुरू होता है—

“शान्ति तथा स्वतंत्रता लीग की समाजवादी अल्पसंख्या इस लीग से अपने को पृथक् करने के बाद एक नया समाजवादी जनवाद का सहबंध” स्थापित करनेवाली है... जिसका विशेष मिशन राजनीतिक तथा दार्शनिक प्रश्नों का अध्ययन करना होगा...”

यह रहा वह विचार जो “विकसित” किया जा रहा है !

“इस तरह की योजना... यूरोप तथा अमरीका के सच्चे समाजवादी जनवादियों को ऐसे साधन मुहैया करेगी जिनसे उन्हें समझा जा सकेगा और उनके विचारों की अभिपुष्टि हो सकेगी।”*

पूँजीवादी संस्था की अल्पसंख्या स्वयं उसकी स्वीकारोक्ति के अनुसार बाजेल कांग्रेस से कुछ ही समय पहले चुपके से इंटरनेशनल के अन्दर मात्र इस उद्देश्य को लेकर घुसी कि उसे वह मेहनतकश जनसाधारण के समक्ष एक गुप्त विज्ञान के उच्च पुरोहित के रूप में पेश करने के लिए साधनस्वरूप इस्तेमाल कर सकें, ऐसे विज्ञान के उच्च पुरोहित के रूप में पेश कर सकें जिसे चार वाक्यों में प्रतिपादित किया जा सकता है और जिसका चरम बिन्दु “वर्गों की आर्थिक तथा सामाजिक समता” है।

इस “सैद्धान्तिक मिशन” के अलावा इंटरनेशनल के लिए प्रस्तावित नये संगठन का एक व्यावहारिक पहलू भी है।

सोलह के परिपत्र में कहा गया है, “भावी समाज उस संगठन की सार्वत्रिकता के अलावा और कुछ नहीं होगा जो इंटरनेशनल अपने लिए स्थापित

*सहबंध के इन सज्जनों ने, जिन्होंने जनरल कौंसिल की ऐसी गुप्त कांग्रेस बुलाने के लिए भर्त्सना की है जब खुली कांग्रेस का आयोजन गद्दारी या मूर्खता की पराकाष्ठा होती, कोलाहल तथा प्रचार के इन घोर समर्थकों ने हमारी नियमावली की अवज्ञा करते हुए इंटरनेशनल के अन्दर एक गुप्त संस्था बनायी जो स्वयं इंटरनेशनल के विरुद्ध लक्षित थी, और जिनका उद्देश्य उसकी शाखाओं को, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, सर्वोच्च पुरोहित के, वकूनिन के हाथों में सौंपना था।

जनरल कौंसिल कतिपय देशों में—उदाहरण के लिए स्पेन में—इस गुप्त संगठन तथा उसके प्रवर्तकों के बारे में अपनी अगली कांग्रेस में जांच करने की मांग करने का इरादा रखती है।

करेगा। इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हम इस संगठन को जहां तक सम्भव हो अपने आदर्श के समीप लायें।

“यह कैसे आशा की जा सकती है कि एक सत्तावादी संगठन में से एक समतावादी तथा मुक्त समाज विकसित होगा? यह असम्भव है। इंटरनेशनल को, जो भावी मानव समाज का भ्रूण है, अब से मुक्ति तथा फ्रेडरेशन के हमारे सिद्धान्तों की सच्ची छवि बनना होगा।”

जिस तरह मध्ययुग के मठ दिव्य जीवन का चित्र प्रस्तुत करते थे, ठीक उसी तरह इंटरनेशनल को नव यरूशलम की छवि होना चाहिए जिसका “भ्रूण” सहबंध के गर्भ में विद्यमान है। पेरिस कम्यून के लोग यदि यह समझ लेते कि कम्यून “भावी मानव समाज का भ्रूण है” और यदि वे सारे अनुशासन तथा हथियारों को, अर्थात् उन तमाम वस्तुओं को, जिन्हें उस समय लुप्त हो जाना होगा जब कभी युद्ध नहीं होंगे, तिलांजलि दे देते तो वे विफल न होते।

परन्तु बकूनिन ने यह सिद्ध करना बेहतर मानते हुए कि सोलह ने अपने “सुसंगत अध्ययनों” के बावजूद इंटरनेशनल को उस समय, जब वह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, विसंगठित तथा निरस्त्र करने की यह तुच्छ योजना नहीं रची, इंटरनेशनल के संगठन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में उस योजना का मूल पाठ अभी-अभी प्रकाशित किया है (देखें «*Almanach du Peuple pour 1872*», जेनेवा)।

६

अब जूरा उस रिपोर्ट के पन्ने उलटें जिसे जूरा कमेटी ने सोलह की कांग्रेस में प्रस्तुत किया था।

उनका आधिकारिक मुखपत्र «*Révolution Sociale*» (१६ नवम्बर) कहता है, “रिपोर्ट पढ़ने से जूरा फ्रेडरेशन के सदस्यों से अपेक्षित निष्पत्ति तथा व्यावहारिक विवेक के ठीक-ठीक परिमाण का पता चल जायेगा।”

रिपोर्ट इन “भयंकर घटनाओं” को—फ्रांस-प्रशा युद्ध तथा फ्रांस में गृहयुद्ध को—इंटरनेशनल की शाखाओं के अन्दर... कुछ ह्रीसलापस्ती के प्रभाव का कारण बताते हुए शुरू होती है।

यदि यह एक तथ्य है कि फ्रांस-प्रशा युद्ध के परिणामस्वरूप शाखाएं इसलिए विघटित हुए बिना नहीं रह सकती थीं कि युद्ध के कारण मजदूर बहुत बड़ी संख्या में दोनों सेनाओं में भर्ती हुए, तो यह भी कम सत्य नहीं है कि साम्राज्य के पतन तथा क्रब्जाकारी युद्ध की बिस्मार्क द्वारा खुली घोषणा ने जर्मनी तथा इंग्लैंड में पूंजीपति वर्ग—जिसने प्रशियाइयों का पक्ष लिया—तथा सर्वहारा वर्ग के बीच—जिसने पहले किसी भी समय की तुलना में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय भावनाओं का अधिक परिचय दिया—उग्र संघर्ष उत्तेजित किया। अकेली यही चीज इंटरनेशनल के लिए दोनों देशों में आधार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होती। अमरीका में इसी तथ्य ने जर्मन सर्वहारा उत्पवासियों के विशाल समूह को विभक्त कर दिया, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी पक्ष ने अंधराष्ट्रवादी पक्ष से निश्चित रूप से नाता तोड़ दिया।

दूसरी ओर, पेरिस कम्यून के जन्म ने इंटरनेशनल के विस्तार को तथा उसके सिद्धान्तों के तमाम राष्ट्रों की शाखाओं द्वारा—जूरा शाखाओं को छोड़कर—समर्थन को अभूतपूर्व रूप से संवर्द्धित किया। समर्थन न देनेवाली इन जूरा शाखाओं की रिपोर्ट में कहा गया है—“विराट संघर्ष की शुरूआत के कारण... लोग फिर से सोचने लगे हैं... कुछ अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हट जाते हैं... बहुतों के लिए यह स्थिति” (अपनी क्रतारों के अन्दर) “जर्जरता का चिह्न है” परन्तु “इसके विपरीत... इस स्थिति में इंटरनेशनल को” उनके ढर्रे के अनुसार “पूरी तरह बदलने की क्षमता है”। यह विनम्र इच्छा ऐसी शुभ स्थिति का और गहन विवेचन करने के बाद समझ में आ जायेगी।

यदि विघटित सहबंध की, जिसका स्थान मालोन की शाखा ने ले लिया, बात छोड़ भी दी जाये तब भी समिति को बीस शाखाओं की स्थिति के विषय में रिपोर्ट पेश करनी थी। उनमें से सात ने सीधे-सीधे सहबंध की ओर से मुंह फेर लिया; इस बारे में रिपोर्ट का यह कहना है—

“ब्येन के बक्से बनानेवालों, नक्काशों और डिजाइनरों की शाखाओं ने हमारे एक भी सन्देश का उत्तर नहीं दिया है।

“नेवशतेल के कारीगरों—यानी बढ़इयों, बक्से बनानेवालों, नक्काशों और डिजाइनरों की शाखाओं ने फ़ेडरल कमेटी की चिट्ठियों का कोई उत्तर नहीं दिया है।

“हम वाल-दे-रूज से कोई समाचार प्राप्त नहीं कर सके हैं।”

“लोक्ले के नक्काशों और डिजाइनरों की शाखा ने फ़ेडरल कमेटी की चिट्ठियों का कोई उत्तर नहीं दिया है।”

यह है स्वायत्त शाखाओं का अपनी फ़ेडरल कमेटी के बीच मुक्त संसर्ग। एक दूसरी शाखा, याने

“कुर्तेलारी ज़िले के नक्काशों तथा डिज़ाइनरों की शाखा तीन वर्ष के अडिग अध्यवसाय के बाद... अब... एक प्रतिरोध संस्था में संगठित होने लगी है”

जो इंटरनेशनल से स्वतंत्र होगी, जो चीज़ उसे सोलह की कांग्रेस में दो डेलीगेट भेजने से ज़रा भी नहीं रोकती।

फिर चार पूर्णतः निर्जीव हो चुकी शाखाएं आती हैं—

“ब्येन की केन्द्रीय शाखा इस समय भंग हो गयी है; परन्तु उसके एक वफ़ादार सदस्य ने हमें हाल में लिखा था कि ब्येन में इंटरनेशनल के पुनर्जन्म की सारी आशाएं अभी मिटी नहीं हैं।

“सेंट-ब्लेज़ शाखा भंग हो गयी है।

“कातेबा शाखा को अपने भव्य अस्तित्व के बाद उन तिकड़मों के आगे झुक जाना पड़ा है जो इस ज़िले के मालिकों ने” (!) “इस बहादुर” (!) “शाखा को भंग करने के लिए रचे हैं।”

“अन्त में, कोर्जेमों शाखा भी मालिकों की तिकड़मों का शिकार बनी है।”

उसके बाद कुर्तेलारी ज़िले की केन्द्रीय शाखा आती है, जिसने “अपने कार्यकलाप निर्लम्बित करने का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया”; इस चीज़ ने उसे सोलह की कांग्रेस में अपने दो डेलीगेट भेजने से विचलित नहीं किया।

अब हमारे सामने वे चार शाखाएं आती हैं जिनका अस्तित्व कहीं अधिक द्विविधापूर्ण है।

“ग्रांज शाखा समाजवादी मजदूरों का एक छोटा-सा केन्द्रक बनकर रह गयी है... उनकी अल्प सदस्यता ने उनके स्थानीय कार्यकलाप को गतिहीन बना दिया है।

“नेवशतेल की केन्द्रीय शाखा को घटनाओं के कारण काफ़ी ज्यादा धक्का लगा है और यदि उसके कुछ सदस्य निष्ठावान तथा सक्रिय न होते तो वह अनिवार्यतः विघटित हो चुकी होती।

“लोवले की केन्द्रीय शाखा कुछ महीनों तक सिंदगी और भौत के बीच झूलने के बाद अन्त में विघटित हो गयी। परन्तु उसे अभी हाल में दुबारा संगठित किया गया है” —

आहिर है, उसे मात्र इस उद्देश्य के लिए दुबारा संगठित किया गया कि वह सोलह की कांग्रेस में अपने दो डेलीगेट भेज सके।

“समाजवादी प्रचार की शो-दे-फोन शाखा नाजुक हालत में है... उसकी हालत सुधरनी तो रही दूर, बिगड़ती ही जा रही है।”

इसके बाद दो शाखाएं—सेंट-इम्पे तथा सोनविल्ये की अध्ययन मंडलियां आती हैं जिनकी केवल सरसरी तौर पर चर्चा की गयी है और जिनकी परिस्थितियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

तब आदर्श शाखा रह जाती है, उसका केन्द्रीय शाखा नाम ही स्पष्ट कर देता है कि वह अन्य निर्जीव शाखाओं के अवशेष के अलावा और कुछ नहीं है।

“मुत्ये की केन्द्रीय शाखा को ही सबसे कम धक्का पहुंचा है... उसकी कमेटी का फ्रेडरल कमेटी से निरन्तर संपर्क रहा है... अभी कोई शाखाएं स्थापित नहीं हुई हैं...”

इसका निम्नलिखित कारण बताया गया है—

“मुत्ये की शाखा के कार्यकलाप के लिए परिस्थितियां विशेष रूप से अनुकूल हैं क्योंकि आज भी... लोक परम्पराएं सुरक्षित रखनेवाली मेहनतकश आवादी का उसके प्रति अनुकूल रुख है; हम चाहते हैं कि इस जिले का मजदूर वर्ग अपने को राजनीतिक तत्त्वों से और अधिक स्वतंत्र बनाये।”

वस्तुतः यह देखा जा सकता है कि यह रिपोर्ट

“उस निष्ठा तथा व्यावहारिक विवेक बुद्धि का, जिसकी हम जूरा फ्रेडरेशन के सदस्यों से अपेक्षा कर सकते हैं, सही-सही परिमाण प्रस्तुत करती है।”

वे इतना और कहकर बात खत्म कर सकते थे कि शो-दे-फोन के, जो उनकी समिति का मूल स्थान था, मजदूरों ने उनसे कोई सरोकार रखने से हमेशा इन्कार किया है। अभी हाल में, १८ जनवरी १८७२ को, उन्होंने लन्दन कांग्रेस के प्रस्तावों और साथ ही रोमांस कांग्रेस के मई १८७१ के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से पुष्टि करके सोलह के परिपत्र का उत्तर दिया जिसमें कहा गया कि

“बकूनिन, गिलोम और उनके समर्थकों को हमेशा के लिए इंटरनेशनल से बाहर कर दिया जाये।”

क्या इस तकली सोनविल्ये कांग्रेस के बारे में, जिसने अपने ही शब्दों में “इंटरनेशनल के अन्दर युद्ध, खुला युद्ध उत्पन्न किया”, कुछ और कहने की जरूरत है?

निस्सन्देह, इन लोगों को, जो अपनी हैसियत से ज्यादा शोर मचाते हैं, निर्विवाद सफलता मिली। सारे उदारतावादी तथा पुलिस के अखबारों ने खुलेआम उनका साथ दिया है; उन्हें जनरल कौंसिल पर कीचड़ उछालने में और इंटरनेशनल पर नीरस प्रहार करने में कई देशों के प्रतीयमान सुधारवादियों ने मदद दी—ये हैं इंग्लैंड में पूंजीवादी जनतंत्रवादी जिनकी तिकड़मों का इंटरनेशनल ने पर्दाफाश किया; इटली में जड़सूत्रवादी स्वतंत्र चिन्तक जिन्होंने स्तेफ़ानोनी के झंडे के नीचे अभी-अभी “सार्वत्रिक तर्कणावादी संस्था” की, जिसका स्थायी सदर-मुक़ाम रोम में है, एक “सत्तावादी” तथा “सोपानिक” संगठन की, निरीश्वरवादी भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए मठों की स्थापना की है जिसके नियमों में यह व्यवस्था है कि दस हजार फ़्रांक चन्दा देनेवाले प्रत्येक पूंजीपति की कांग्रेस के सभा भवन में संगमरमर की मूर्ति स्थापित की जाये; ⁴² अन्ततः जर्मनी में बिस्मार्कीय समाजवादी, जिन्होंने अपने पुलिस-मुखपत्र «*Neuer Social-Demokrat*» ⁴³ के अलावा प्रशा-जर्मन साम्राज्य के “सफ़ेद कुर्तधारियों” ⁴⁴ की भूमिका अदा की।

सोनविल्ये गुट इंटरनेशनल की तमाम शाखाओं से करुणाजनक ढंग से अपील करता है कि वे नागरिकगण मालोन तथा लेफ़ांसे के शब्दों में “लन्दन कौंसिल के निरन्तर अतिक्रमणों पर अंकुश लगाने के लिए” तत्काल कांग्रेस बुलाने की आवश्यकता पर जोर दें; परन्तु अपील का वास्तविक उद्देश्य यह था कि इंटरनेशनल का स्थान सहबंध ले। इस अपील की इतनी उत्साहप्रद प्रतिक्रिया हुई कि उन्होंने पिछली बेल्जियन कांग्रेस में स्वीकृत प्रस्ताव को तत्काल श्रुत ढंग से पेश करना शुरू कर दिया। उनका आधिकारिक मुखपत्र «*Révolution Sociale*», ४ जनवरी १८७२) लिखता है—

“आखिरी चीज़, और यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेल्जियन शाखाओं की २४ और २५ दिसम्बर को ब्रसेल्स कांग्रेस के समय बैठक हुई और उन्होंने जनरल कांग्रेस के आयोजन की आवश्यकता पर सोनविल्ये कांग्रेस की ही तरह का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया।”

यह ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि बेल्जियन कांग्रेस ने इससे बिल्कुल विपरीत प्रस्ताव पास किया था। उसने बेल्जियन कांग्रेस को जिसकी आगामी जून तक बैठक नहीं होने जा रही थी, इंटरनेशनल की आगामी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुतार्थ नयी नियमावली तैयार करने का काम सौंपा था।

इंटरनेशनल की भारी बहुसंख्या की इच्छा के अनुसार जनरल कौंसिल वार्षिक कांग्रेस सितम्बर १८७२ में ही आयोजित करेगी।

७

फ्रांस के कुछ सप्ताह बाद अल्बेर रिशार तथा गास्पेर ब्लां, सहबंध के सबसे प्रभावशाली तथा सबसे उत्कट सदस्य लन्दन पहुँचे। वे फ्रांसीसी उत्प्रेवासियों के बीच ऐसे सहायक भर्ती करने के लिए आये जो साम्राज्य के पुनःस्थापन का कार्य करने के लिए इच्छुक हों। उनके कथनानुसार थियेर से छुटकारा पाने और बेसहारेपन से बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। जनरल कौंसिल ने ब्रसेल्स फ्रेडरल कौंसिल समेत सबको उनकी बानापातेपंथी साजिश से सचेत कर दिया था।

जनवरी १८७२ को उन्होंने "साम्राज्य तथा नया फ्रांस। फ्रांसीसी अन्तःकरण का जनता तथा नौजवानों द्वारा आह्वान। लेखक अल्बेर रिशार तथा गास्पेर ब्लां। ब्रसेल्स, १८७२।" शीर्षक पुस्तिका प्रकाशित कर अपना नकाब उतार दिया।

सहबंध के धूर्तों की अभिलाक्षणिक विनम्रता के साथ वे यह ऊल-जलूल घोषणा करते हैं—

"हम लोग, जिन्होंने फ्रांसीसी सर्वहारा की महान सेना संगठित की है... हम लोग, जो फ्रांस में इंटरनेशनल के सबसे प्रभावपूर्ण नेता हैं,* ...

* १५ फरवरी १८७२ के «L'Égalité» (जेनेवा से प्रकाशित) के अंक में 'कठघरे की ओर!' शीर्षक में कहा गया था—

"दक्षिणी फ्रांस में कम्यून के आन्दोलन की पराजय की कहानी का वर्णन करने का अभी समय नहीं आया है; परन्तु आज हम, जिनमें से अधिकांश ३० अप्रैल को लियों के विप्लव की निन्दनीय पराजय के साक्षी रहे हैं, इतना घोषित कर सकते हैं कि विप्लव की विफलता का एक कारण गां० ब्लां की बुझदिली,

खुशकिस्मती से गोली से नहीं उड़ा दिये गये हैं और हम यहां इन लोगों (अर्थात् महत्वाकांक्षी सांसदों, आत्मतुष्ट जनतंत्रवादियों, हर रंग के मिथ्या जनवादियों) के सामने वह झंडा, जिसके नीचे हम लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठापित करने के लिए मौजूद हैं, विस्मित यूरोप के सामने वह आवाज बुलन्द करने के लिए मौजूद हैं जो हमारे अन्तःकरण से निकलती है और जो शीघ्र तमाम फ्रांसीसियों के दिलों में प्रतिध्वनित हो उठेगी, यह आवाज है 'सम्राट ज़िंदावाद !'

“अप्रमानित तथा तिरस्कृत नेपोलियन तृतीय को शानदार ढंग से पुनःप्रतिष्ठित किया जाना चाहिए”, -

और अल्बेर रिशार और गास्पर ब्लांक को जिन्हें आक्रमण तृतीय के गुप्त कोषों से धन दिया गया, पुनःप्रतिष्ठित करने का यह विशेष कार्य सौंपा जाता है।

प्रसंगतः वे स्वीकार करते हैं कि

“अपने विचारों के स्वाभाविक विकास ने हमें साम्राज्य का पक्षधर बनाया है।”

यह एक ऐसी स्वीकारोक्ति है जिससे सहबंध में उनके सहधर्मियों को हर्ष होना चाहिए। «*Salidarité*» की तरुणार्द्ध के दिनों की ही तरह अ० रिशार

गद्दारी और बटमारी है जिसने हर जगह घुसकर अपने को पर्दे के पीछे रखनेवाले अ० रिशार के आदेशों की पूर्ति की।

“पहले से ही खूब सोच-समझकर रची गयी तिकड़मों के जरिए इन धूर्तों ने इरादतन बहुत-से उन लोगों को फंसा दिया जिन्होंने विप्लव समितियों की तैयारी की कारवाइयों में भाग लिया था।

“यही नहीं, ये गद्दार लियों में इंटरनेशनल को इस हद तक बदनाम करने में सफल रहे कि पेरिस क्रान्ति के समय तक इंटरनेशनल को लियों के मजदूर अधिकतम अविश्वास के साथ देखने लगे। यही संगठन के अभाव का, यही विप्लव की विफलता का, ऐसी विफलता का कारण है जिसके अवश्यम्भावी परिणामस्वरूप कम्यून का पतन हुआ, जिसे अपनी ही अलग-थलग शक्तियों के सहारे छोड़ दिया गया! इस रक्तरेजित सबक्र के बाद ही हमारा प्रचार लियों के मजदूरों को इंटरनेशनल के झंडे के नीचे एकजुट कर सका है।

“अल्बेर रिशार बकूनिन और उनके चट्टे-बट्टों का प्रियजन और पैगम्बर था।”

तथा गा० ब्लांक "राजनीति से विरति" के बारे में फिर अपने पुराने फिक्रों को दुहराते हैं, जो "स्वाभाविक विकासक्रम" के सिद्धान्त के आधार पर केवल पूर्णतम निरंकुशतावाद के अन्तर्गत ही वास्तविकता बन सकती है, जिसमें मजदूर राजनीति में दस्तंदाजी से उसी तरह विरत होंगे जिस तरह क़ैदी धूप में घूमने से विरत रहता है।

वे कहते हैं, "क्रान्तिकारियों का समय गुज़र चुका है... कम्युनिज़म जर्मनी तथा इंग्लैंड तक, विशेष रूप से जर्मनी तक सीमित है। प्रसंगतः, वह वहीं दीर्घकाल से संजीदे रूप में विकसित हुआ है जहां से वह आगे चलकर पूरे इंटरनेशनल में फैला है, और संघ में जर्मन प्रभाव के इस चिन्ताजनक विस्तार ने उसके विकास में, बल्कि यूं कहें कि उसे मध्य तथा दक्षिणी फ्रांस में, जिन्हें किसी जर्मन ने कभी कोई नारा मुहैया नहीं किया, नयी दिशा देने में कोई कम योग नहीं दिया है।"

शायद यह स्वयं महानायक* की आवाज़ है जिसने सहबंध की स्थापना के समय से ही रूसी होने के नाते लैटिन नस्लों का प्रतिनिधित्व करने का विशेष मिशन ग्रहण किया है। अथवा क्या यह «*Révolution Sociale*» (२ नवम्बर १८७१) के "सच्चे मिशनरियों की" आवाज़ है जो

"इंटरनेशनल पर जर्मन तथा बिस्मार्कियन मनोवृत्ति थोपने का प्रयास कर रहे पशुचगमन की" निन्दा करती है।

परन्तु सौभाग्य से सच्ची परम्परा जीवित रह गयी है और श्री अल्बेर रिशार तथा गास्पर ब्लां को गोली से नहीं उड़ाया गया है! इस तरह उनका अपना "योगदान" यह है कि उन्होंने बोनापार्टपंथी शाखाओं की—तथ्यतः मूल रूप से "स्वायत्त" शाखाओं की—स्थापना के प्रयास के ज़रिए मध्य तथा दक्षिणी फ्रांस में इंटरनेशनल के लिए "एक नयी दिशा निर्धारित" की है।

जहां तक लन्दन कांफ्रेंस की सिफारिश के अनुसार सर्वहारा को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित करने का सम्बन्ध है,

* मि० बकूनिन।—सं०

“साम्राज्य के पुनःस्थापन के बाद हम लोग”—रिशार तथा ब्लां—“समाजवादी सिद्धान्तों से ही नहीं, वरन् जनसाधारण के क्रान्तिकारी संगठन के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित करने की सारी कोशिशों से जल्दी से निपटेंगे।” संक्षेप में “शाखाओं के” महान “स्वायत्त सिद्धान्त” का, जो “इंटरनेशनल की वास्तविक शक्ति है... विशेष रूप से लैटिन नस्ल वाले देशों में, उपयोग करते हुए”... (*«Révolution Sociale»*, ४ जनवरी),

ये सज्जन इंटरनेशनल में अराजकता को अपनी आशाओं का आधार बनाते हैं।

तो अराजकता उनके उस्ताद बकूनिन का जंगी घोड़ा है जिसने चन्द नारों को छोड़कर समाजवादी प्रणालियों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। सारे समाजवादी अराजकतावाद को इस कार्यक्रम के रूप में देखते हैं: सर्वहारा आन्दोलन के लक्ष्य की, अर्थात् वर्गों के उन्मूलन की एक बार पूर्ति हो जाने के बाद राज्य की सत्ता, जो उत्पादकों की बहुसंख्या को मुट्ठी भर शोषक अल्पसंख्या के अधीन रखने का काम करती है, लुप्त हो जाती है तथा सरकार के कार्य मात्र प्रशासनिक कार्य बन जाते हैं। सहबंध बिल्कुल उल्टी तस्वीर खींचता है। वह सर्वहाराओं की क्रतारों में अराजकता को शोषकों के हाथों में सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों के जमाव को भंग करने का सबसे अमोघ अस्त्र मानता है। इस वहाने की आड़ में वह इंटरनेशनल से ऐसे समय, जब पुरानी दुनिया उसे कुचलने का रास्ता ढूँढ़ रही है, अपने संगठन के स्थान पर अराजकता स्थापित करने के लिए कह रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस थियेरीय जनतंत्र को शाही चोगा *

* दूफ़ोर क़ानून-संबंधी रिपोर्ट में देहाती सभा के सदस्य साकाज़ सर्वोपरि इंटरनेशनल के “संगठन” पर प्रहार करता है। वह उस संगठन से निश्चित रूप से धृणा करता है। इस “ख़तरनाक संघ की बढ़ती लोकप्रियता” की पुष्टि कर चुकने के बाद वह आगे कहता है, “यह संघ... अपने से पहले के पंथों के गुप्त तरीक़ों को ठुकराता है। उसका संगठन बिल्कुल खुले तौर पर बनाया तथा परिवर्तित किया गया। इस संगठन ने अपनी शक्ति के बल पर... अपने कार्यकलाप तथा प्रभाव का दायरा निरन्तर बढ़ाया है। वह दुनिया भर में फैलता जा रहा है।” फिर वह “संगठन का संक्षिप्त विवरण” देता है और यह निष्कर्ष निकालता है: ऐसी है इस विशाल संगठन की चतुराई भरी एकता में निहित... उसकी योजना। उसकी शक्ति उसकी मूल अवधारणा में ही निहित है। वह अपने

पहिनाते हुए उसे बरकरार रखने के लिए बेहतर चीज की तलाश नहीं कर सकती।

लन्दन, ५ मार्च १८७२

३३, राटबोन प्लेस।

मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा

मध्य जनवरी और ५ मार्च

अंग्रेजी से अनूदित।

१८७२ के बीच लिखित।

१८७२ में जेनेवा में पुस्तिका के रूप में प्रकाशित।

समर्थकों की, जो अपने समान कार्यकलाप में सूत्रबद्ध हैं, बहुत बड़ी तादाद पर तथा अन्ततः उस अजेय संवेग पर अवलम्बित है जो उन्हें आन्दोलित करता है।”

पेरिस कम्यून की जयन्ती सभा के प्रस्ताव 45

७

१८ मार्च १८७१ की जयन्ती मनाने के लिए आयोजित सभा निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार करती है :

१

वह १८ मार्च को उद्घाटित कीर्तिमय आन्दोलन को महान सामाजिक क्रान्ति की प्रभातवेला के रूप में देखती है जो मानवजाति को वर्ग शासन से सदा-सर्वदा के लिए मुक्त कर देगी।

२

वह घोषित करती है कि मजदूर वर्ग के प्रति अपनी घृणा द्वारा पूरे यूरोप में एकीकृत बुर्जुआ वर्गों की अयोग्यता तथा अपराधों ने पुराने समाज को, जो किसी भी तरह की शासन व्यवस्था के—राजतन्त्रवादी अथवा जनतन्त्रवादी—अन्तर्गत हो, मौत की सजा दे दी है।

३

वह घोषित करती है कि इंटरनेशनल के विरुद्ध तमाम सरकारों के जेहाद तथा बेर्साई के हत्यारों और साथ ही उनके प्रशियाई विजेताओं का आतंक उनकी

सफलताओं के खोखलेपन को प्रकट करते हैं तथा इस बात का प्रमाण हैं कि वीर हरावल के पीछे, जिसे थियेर और प्रशा के विल्हेल्म की संयुक्त शक्तियों ने कुचल दिया है, पूरे संसार के सर्वहाराओं की भीमकाय सेना खड़ी है।

मार्क्स द्वारा १३ और १८ मार्च
१८७२ के बीच लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

२४ मार्च, १८७२ को «*La Liberté*» के अंक १२
तथा ३० मार्च, १८७२ को «*The International
Herald*» के अंक ३ में प्रकाशित।

भूमि का राष्ट्रीयकरण ⁴⁸

भूस्वामित्व सम्पूर्ण सम्पदा का मूल स्रोत है और वह एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या बन गया है जिसके समाधान पर मजदूर वर्ग का भविष्य निर्भर करता है।

यहां भूमि पर निजी स्वामित्व के पक्ष-समर्थकों—विधिशास्त्रियों, दार्शनिकों और राजनीतिक अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत सारे तर्कों का विवेचन करने का मेरा इरादा नहीं है, मैं यहां अपनी बात सबसे पहले यह कहने तक सीमित रखूंगा कि इन लोगों ने हस्तगतकरण के मूल तथ्य को “नैसर्गिक अधिकार” की आड़ में छुपाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया है। यदि हस्तगतकरण चन्द लोगों का नैसर्गिक अधिकार है तो अधिकतर लोगों को केवल इतना ही करना है कि वे उसे, जो उनसे छीन लिया गया है, पुनः प्राप्त करने का नैसर्गिक अधिकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शक्ति बटोरें।

इतिहास की अग्रगति में विजेताओं ने पाशविक बल द्वारा हासिल अपने मूल अधिकारों को स्वयं थोपे गये कानूनों के माध्यम से सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना सुविधाजनक पाया है।

फिर दार्शनिक आता है और यह सिद्ध करता है कि इन कानूनों का अर्थ मानवजाति की सार्वत्रिक सहमति है और वे उसे व्यक्त करते हैं। यदि भूमि पर निजी स्वामित्व सचमुच ऐसी सार्वत्रिक सहमति के आधार पर स्थापित है तो वह स्पष्टतया उस क्षण मिट जायेगा जिस क्षण समाज का बहुमत यह सहमति देने से इनकार कर देगा।

परन्तु स्वामित्व के तथाकथित “अधिकारों” की बात छोड़ते हुए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि समाज का आर्थिक विकास, आबादी की वृद्धि तथा जमाव-थे ठीक वे ही हालात हैं, जो पूँजीपति फार्मर को कृषि में सामूहिक तथा संगठित श्रम का उपयोग करने के लिए और मशीनों तथा ऐसे ही अन्य आविष्कारों का आश्रय लेने के लिए मजबूर करते हैं—भूमि के राष्ट्रीयकरण को अधिकाधिक “सामाजिक आवश्यकता” बना देंगे जिसके मुकाबले में स्वामित्व के अधिकारों की सारी बातें बेकार सिद्ध होंगी। समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तथा उनकी पूर्ति करनी होगी, सामाजिक आवश्यकताओं से जन्म लेनेवाले परिवर्तन अपना रास्ता बनाते जायेंगे और देर-सबेर कानून को अपने हित में ढालेंगे।

हमें जरूरत है नित्यप्रति बढ़ते हुए उत्पादन की। उसकी आवश्यकताएं चन्द लोगों को उसे अपनी सनकों और निजी स्वार्थों के अनुसार विनियमित करने अथवा अज्ञानवश मिट्टी की शक्ति ख़त्म कर देने की इजाजत देकर पूरी नहीं की जा सकती। सिंचाई, जल-निकास, भाप-चालित हलों, रासायनिक पदार्थों का उपयोग जैसी सारी आधुनिक विधियों को कृषि में बड़े पैमाने पर अमल में लाया जाना चाहिए। परन्तु हमारे पास जो वैज्ञानिक ज्ञान है और हमें कृषि के जो साधन—जैसे मशीनें—उपलब्ध हैं, उन्हें ज़मीन पर बहुत बड़े पैमाने की काश्त के बिना सफलतापूर्वक अमल में नहीं लाया जा सकता।

यदि बड़े पैमाने की काश्त (भले ही वर्तमान पूँजीवादी विधि के अन्तर्गत जो स्वयं काश्तकार को लहू जानवर की अधोगति में पहुँचा देती है) आर्थिक दृष्टि से छोटी तथा बिखरी हुई कृषि से कहीं श्रेष्ठ सिद्ध हो तो क्या वह राष्ट्रीय पैमाने पर व्यवहार में लाये जाने से उत्पादन को उत्प्रेरित नहीं करेगी?

एक ओर लोगों की सदा बढ़ती जानेवाली आवश्यकताएं तथा दूसरी ओर कृषि उपजों की सदा बढ़ती जानेवाली कीमतें इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि भूमि का राष्ट्रीयकरण सामाजिक आवश्यकता बन चुका है।

जब खेती राष्ट्र के नियंत्रण में और उसके लाभार्थ की जायेगी, व्यक्तिगत दुरुपयोग के फलस्वरूप कृषि उपजों का इस तरह घटना निस्सन्देह असम्भव हो जायेगा।

यहां बहस के दौरान इस प्रश्न पर जितने नागरिकों की बात मैंने सुनी है, उन सबने भूमि के राष्ट्रीयकरण का पक्ष-समर्थन किया है परन्तु उन्होंने उसे बहुत भिन्न दृष्टिकोण से देखा है।

फ्रांस की अक्सर मिसाल के तौर पर चर्चा की गयी परन्तु अपने कृषक स्वामित्व के कारण वह राष्ट्रीयकरण के मामले में इंग्लैंड से कोसों दूर है जहाँ ज़मींदारी है। यह सच है कि फ्रांस में ज़मीन उन सब को सुलभ है जो उसे खरीद सकते हैं, परन्तु इसी सुविधा ने उसे ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट दिया है जिसे बहुत कम साधन वाले लोग खरीदा करते हैं और जो स्वयं अपने व्यक्तिगत श्रम तथा अपने परिवारों के श्रम पर मुख्यतया निर्भर करते हैं। इस तरह का भूस्वामित्व तथा उसके कारण छोटे-छोटे खेतों पर काश्त जो आधुनिक कृषि सुधारों के सारे साधनों का उपयोग असम्भव बना देती है, स्वयं काश्तकार को सामाजिक प्रगति और सर्वोपरि ज़मीन के राष्ट्रीयकरण का कट्टर शत्रु बना देती है। वह ज़मीन से बंधा रहता है जिस से अपेक्षाकृत मामूली प्रतिफलों की प्राप्ति के लिए उसे अपनी सारी जीवन शक्ति नष्ट करनी पड़ती है; उसे अपनी उपज का बड़ा भाग राज्य को करों के रूप में, अदालती दुनिया को अदालती खर्चों के रूप में और सूदखोर को ब्याज के रूप में देना पड़ता है; वह अपने रोज़गार के तुच्छ क्षेत्र से बाहर होनेवाले सामाजिक आन्दोलनों से सर्वथा अनभिज्ञ रहता है; इन सब के बावजूद वह अपने खेत के छोटे-से टुकड़े से तथा उस पर नाममात्र के स्वामित्व से मतान्धतापूर्ण अनुराग के साथ चिपका रहता है। इस तरह फ्रांसीसी किसान को औद्योगिक मजदूर वर्ग का सर्वाधिक घातक विरोधी बना दिया गया है।

इस तरह, कृषक स्वामित्व के भूमि के राष्ट्रीयकरण की राह में सबसे बड़ी रुकावट होने के कारण फ्रांस अपनी वर्तमान अवस्था में यकीनन वह स्थान नहीं है जहाँ हमें इस विरत समस्या के समाधान की तलाश करनी चाहिए।

पूँजीपति वर्ग की शासन व्यवस्था के अन्तर्गत ज़मीन के राष्ट्रीयकरण से तथा उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग-अलग व्यक्तियों या मेहनतकश लोगों के संघों को सौंपने से स्वयं उनके बीच अंधाधुंध प्रतिद्वन्द्विता पैदा होगी और इसके फलस्वरूप लगान में वृद्धि होगी जो फिर हस्तगतकारियों को उत्पादकों का खून चूसने के लिए नयी सुविधाएं प्रदान करेगी।

१८६८ में ब्रसेल्स में हुई इंटरनेशनल की कांग्रेस में हमारे एक मित्र ने* कहा था—

* सीज़र द पाइप।—सं०

“भूमि पर निजी लघु स्वामित्व को विज्ञान का निर्णय तथा बड़े स्वामित्व को न्याय का निर्णय मृत्युदंड दे चुका है। केवल एक विकल्प रह जाता है : भूमि या तो ग्राम संघों की सम्पत्ति अथवा पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति बने। यह प्रश्न भविष्य तय करेगा।”

मैं इसके विपरीत कहूंगा : सामाजिक आन्दोलन इस निर्णय की ओर ले जायेगा कि भूमि पर केवल स्वयं राष्ट्र का ही स्वामित्व हो सकता है। भूमि संघवद्ध देहाती श्रमिकों को सौंपने का अर्थ समाज को उत्पादकों के केवल एक विशिष्ट वर्ग के अधीन करना होगा।

भूमि का राष्ट्रीयकरण श्रम तथा पूंजी के सम्बन्धों में पूर्ण परिवर्तन ले आयेगा और अन्ततोगत्वा उत्पादन का पूंजीवादी रूप—वह चाहे औद्योगिक हो या कृषक—ख़त्म कर देगा। फिर वर्ग विभेद तथा विशेषाधिकार उस आर्थिक आधार के साथ लुप्त हो जायेंगे जिस पर वे अवलम्बित हैं। दूसरों के श्रम के सहारे जीवित रहना अतीत की बात बनकर रह जायेगी। स्वयं समाज से भिन्न कोई सरकार या राजकीय सत्ता नहीं रह जायेगी ! कृषि, खनन, कारखाना उद्योग, संक्षेप में उत्पादन की तमाम शाखाएं सर्वाधिक सन्तोषजनक ढंग से संगठित की जायेंगी। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीय केन्द्रीयकरण स्वतंत्र तथा बराबरी का दर्जा प्राप्त उत्पादकों के ऐसे संघों को लेकर बननेवाले समाज का राष्ट्रीय आधार होगा जो समान तथा विवेकसम्मत योजना के आधार पर सामाजिक कारोबार किया करेंगे। ऐसा है वह मानवीय ध्येय जिसकी ओर १९वीं शताब्दी का महान आर्थिक आन्दोलन अग्रसर हो रहा है।

मार्क्स द्वारा मार्च-अप्रैल १८७२ में लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

«The International Herald» अखबार के
१५ जून १८७२ के अंक ११ में प्रकाशित।

हेग में हुई जनरल कांग्रेस के प्रस्तावों का एक अंश

२-७ सितम्बर १८७२^{४७}

७

१

नियमावली पर प्रस्ताव

लन्दन कांग्रेस (सितम्बर १८७१)^{४८} के प्रस्ताव ६ का सार प्रस्तुत करनेवाली निम्नलिखित धारा नियमावली की धारा ७ के बाद जोड़ी जाये।

धारा ७ क। सम्पत्तिधारी वर्गों की संयुक्त सत्ता के विरुद्ध अपने संघर्ष में सर्वहारा अपने को एक विशेष राजनीतिक पार्टी में गठित करके ही वर्ग के रूप में काम कर सकते हैं जो सम्पत्तिधारी वर्गों की तमाम पुरानी पार्टियों के विरुद्ध हो।

राजनीतिक पार्टी में सर्वहारा का यह गठन सामाजिक क्रांति की और उसके अन्तिम लक्ष्य—वर्गों के उन्मूलन के लक्ष्य—की विजय सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है।

मजदूर वर्ग की शक्तियों की संयुक्त ताकत को, जो आर्थिक संघर्ष द्वारा हासिल हो चुकी है, इस वर्ग के हाथों में अपने शोषकों की राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में उत्तोलक का काम भी करना होगा।

चूँकि भूमि तथा पूंजी के अधिपति अपनी आर्थिक इजारेदारियों को बरकरार रखने और श्रम को दास बनाने के लिए अपने राजनीतिक विशेषाधिकारों का सदैव उपयोग करते हैं, इसलिए राजनीतिक सत्ता विजित करना सर्वहारा का महान् कर्त्तव्य हो जाता है।

५ के विरुद्ध २६ मतों से अनुमोदित; ८ ने मतदान में भाग नहीं लिया...

मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा तैयार।

अंग्रेजी से अनूदित।

«Resolution du congrès général tenu a la Haye du 2 au 7 septembre 1872», Londres, 1872

नामक पुस्तिका के रूप में तथा «La Emancipacion», अंक ७२, २ नवम्बर १८७२ और «The International Herald» अंक ३७ में १४ दिसम्बर १८७२ को प्रकाशित।

हेग कांग्रेस

एम्स्टरडम में ८ सितम्बर १८७२ को आयोजित सभा में किये गये
भाषण का सम्वाददाता द्वारा लिखित रूप

मार्क्स ने कहा था—१८ वीं शताब्दी में राजा और महाराजा अपने राजवंशों के हितों पर विचार-विमर्श करने हेग में जमा हुआ करते थे।

सारे भय दिखाये जाने के बावजूद हमने यहीं मजदूरों की कांग्रेस आयोजित करने का निर्णय किया। हम सबसे प्रतिक्रियावादी आवादी के बीच अपने महान संघ के अस्तित्व, उसके विस्तार, भविष्य में उसकी आशाओं को अभिपुष्ट करना चाहते थे।

हमारा निर्णय सुनने के बाद कहा गया कि हमने मैदान साफ़ करने के लिए दूत भेजे थे। हम इस बात से इनकार नहीं करते कि हमारे दूत सब जगह फेले हुए हैं; परन्तु उनमें से अधिकांश से हम अपरिचित हैं। हेग में हमारे दूत वे मजदूर थे जिनका श्रम कमरतोड़ होता है; एम्स्टरडम में भी हमारे दूत मजदूर हैं जो १६ घंटे रोज़ मेहनत करते हैं। वे ही हमारे दूत हैं, और कोई नहीं। और समस्त देशों में, जहाँ हम पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि वे हमारा मित्रतापूर्वक स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि वे बहुत जल्द अनुभव कर लेते हैं कि उनकी दशा सुधारना ही हमारा ध्येय है।

हेग कांग्रेस ने तीन मुख्य कार्य किये:

उसने मेहनतकश वर्गों के लिए सामाजिक क्षेत्र की ही तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी पुराने, ढह रहे समाज के विरुद्ध संघर्ष करने की ज़रूरत पर जोर दिया। और हमें प्रसन्नता है कि लन्दन कांग्रेस का यह प्रस्ताव अब हमारी नियमावली *

* देखें प्रस्तुत खण्ड।—सं०

में शामिल कर लिया गया है। हमारे बीच एक ऐसा समूह बन गया था जो मजदूरों की राजनीति से विरति की वकालत कर रहा था।

हमने यह लक्षित करना अहत्वपूर्ण माना कि हमने इन सिद्धान्तों को अपने ध्येय के लिए कितना खतरनाक और अभिशापपूर्ण माना।

मजदूर को किसी न किसी दिन राजनीतिक सत्ता हासिल करनी होगी ताकि वह श्रम को नये ढर्रे पर संगठित कर सके। यदि मजदूर वर्ग यह नहीं चाहता कि वह प्रथम ईसाइयों की ही तरह, जो राजनीति की उपेक्षा करते थे तथा उससे घृणा करते थे, पृथ्वी पर अपने राज से सदा-सर्वदा के लिए वंचित रहें, तो उसे पुराने संस्थानों का समर्थन करनेवाली पुरानी नीति को परास्त करना होगा।

परन्तु हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह लक्ष्य एक जैसे साधनों से हासिल होगा।

हम जानते हैं कि विभिन्न देशों के संस्थानों, रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं को ध्यान में रखना आवश्यक है; और हम इस बात से इनकार नहीं करते कि अमरीका, इंग्लैंड जैसे देशों में—और यदि आपके संस्थानों के बारे में मेरा ज्यादा अच्छा ज्ञान हो तो मैं इन देशों में हालैंड को भी शामिल करता—मेहनतकश जनता अपना ध्येय शान्तिपूर्ण साधनों से पूरा कर सकती है। यदि यह सच है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि महाद्वीप के अधिकांश देशों में शक्ति को ही हमारी क्रान्तियों का उत्तोलक बनना होगा; यह शक्ति ही है जिसका हमें श्रम का राज स्थापित करने के लिए किसी न किसी दिन आश्रय लेना पड़ेगा।

हेग कांग्रेस ने जनरल काँसिल को नये तथा पहले से अधिक अधिकार दिये हैं। वास्तव में, ऐसे समय जब राजा लोग बर्लिन में जमा हुए हैं,⁴⁸ जहाँ सामन्ती व्यवस्था तथा पुराने जमाने के प्रतिनिधियों की इस सभा में हमारे विरुद्ध नयी तथा अधिक कठोर दमनात्मक कार्रवाइयाँ तय की जानेवाली हैं और जब दमन-चक्र घूमना शुरू हो चुका है, हेग कांग्रेस ने अपनी जनरल काँसिल के अधिकारों को बढ़ाना तथा शुरू होने ही वाले संघर्ष के लिए कार्रवाई का केन्द्रीयकरण करना, जिसे अलगाव निरर्थक बना देगा, आवश्यक तथा विवेकपूर्ण समझा है। इसके अलावा जनरल काँसिल की सत्ता हमारे दुश्मनों के अलावा और किसमें घबराहट पैदा कर सकती है? तो क्या उसके पास अपनी इच्छा थोपने के लिए नौकरशाही मशीन और सशस्त्र पुलिस है? क्या उसकी सत्ता विशुद्धता: नैतिक नहीं है? क्या वह अपने सारे निर्णय फ्रेडरेशनों के हवाले नहीं करती जिन्हें ये निर्णय क्रियान्वित करने का काम सौंपा जाता है? इन परिस्थितियों में, बिना सेना, बिना पुलिस, बिना

सरकारी अमले के राजाओं को यदि अपनी शक्ति मात्र नैतिक प्रभाव तथा नैतिक गत्ता पर अवलम्बित रखनी पड़े तो वे क्रान्ति के पथ में अत्यन्त क्षीण बाधक होंगे।

आखिरी चीज, हेग कांग्रेस ने जनरल कौंसिल का कार्यालय न्यूयार्क स्थानान्तरित कर दिया है। बहुत-से लोग, स्वयं हमारे कुछ दोस्त तक इस निर्णय से विस्मित हो गये प्रतीत होते हैं। तो क्या वे यह भूल रहे हैं कि अमरीका मुख्यतया मेहनतकश लोगों का संसार बनता जा रहा है, कि हर साल पांच लाख व्यक्ति—मेहनतकश लोग—वहां जाकर बस रहे हैं, कि ऐसी धरती पर, जहां मेहनतकश छाया हुआ हो, इंटरनेशनल को अपनी जड़ मजबूत बनानी चाहिए? और फिर कांग्रेस का निर्णय जनरल कौंसिल को ऐसे सदस्य सहयोजित करने का अधिकार देता है जिन्हें वह समान ध्येय के लाभार्थ आवश्यक तथा उपयोगी समझती हो। हमें आशा करनी चाहिए कि वह ऐसे लोग चुनने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करेगी जिनमें अपना कार्यभार ठीक तरह वहन करने की योग्यता होगी तथा जो यूरोप में हमारे संघ के झंडे को दृढ़तापूर्वक पकड़े रह सकेंगे।

नागरिकों, हमें इंटरनेशनल के मूल सिद्धान्त—एकजुटता—की बात सोचनी चाहिए। तमाम देशों के तमाम मेहनतकश लोगों के बीच इस जीवनदायी सिद्धान्त को दृढ़ आधार पर स्थापित करके ही हम अपने लिए निर्धारित महान लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। क्रान्ति को एकजुटता की जरूरत है और हमारे सामने इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल पेरिस कम्यून के रूप में मौजूद है जिसका पतन इसलिए हुआ कि तमाम केंद्रों में, बर्लिन में, मैड्रिड में तथा अन्यत्र एकसाथ एक ऐसे महान आन्तिकारी आन्दोलन की आग नहीं भड़की जो पेरिस के सर्वहारा के विप्लव के स्तर तक पहुंच पाता।

जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तमाम मेहनतकश लोगों के बीच भविष्य में भी यह फलप्रद एकजुटता स्थापित करने के लिए प्रयत्न करता रहूंगा तथा सक्रियतापूर्वक कार्य करता रहूंगा। मैं इंटरनेशनल से कदापि नहीं हट रहा हूं। और अपने पूर्व प्रयासों की तरह मेरा शेष जीवन भी सामाजिक विचारों की विजय के लिए अर्पित रहेगा जिनके परिणामस्वरूप—और आप इसे निश्चित समझें—सर्वहारा की विश्वव्यापी विजय होकर रहेगी।

१५ सितम्बर १८७२ को «*La Liberté*» के अंक ३७ अंग्रेजी से अनूदित।

२ तथा २ अक्टूबर १८७२ को «*Der Volksstaat*»

के अंक ७६ में प्रकाशित।

आवास प्रश्न

०

१८८७ के दूसरे संस्करण की भूमिका

“आवास प्रश्न” शीर्षक कृति में वे तीन लेख हैं जो मैंने १८७२ में लाइपज़िग के अख़बार «*Volksstaat*»^{५०} के लिए लिखे थे। यह ठीक उस समय की बात है जब करोड़ों फ़्रांसीसी फ़्रांक जर्मनी में प्रवाहित होने लगे थे^{५१}—सरकारी ऋणों की अदायगी की गयी, क़िलों और बैरेकों का निर्माण हुआ, हथियारों और युद्ध सामग्री के ज़ख़ीरों का नवीकरण किया गया; उपलब्ध पूंजी, प्रचलित मुद्रा की ही तरह, एकाएक विपुल मात्रा में बढ़ गयी; और यह सब ऐसे समय हुआ जब जर्मनी “संयुक्त साम्राज्य” के रूप में ही नहीं, बरन् एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति के रूप में विश्व मंच पर प्रकट हो रहा था। इन करोड़ों फ़्रांकों ने उसके नवजात बड़े उद्योग को सशक्त प्रेरणा दी; सर्वोपरि ये फ़्रांक ही युद्ध के बाद की अल्पकालीन, भ्रमों से परिपूर्ण समृद्धि काल के लिए तथा उसके फ़ौरन बाद, १८७३—१८७४ में उस ज़बर्दस्त दिवाला के लिए जिम्मेदार थे जिसके ज़रिए जर्मनी ने अपने को विश्व मंडी में अपने पांवों पर टिकने में समर्थ औद्योगिक देश सिद्ध किया।

जिस अवधि में पुरानी संस्कृति वाला कोई देश मैनूफ़ैक्चर तथा छोटे पैमाने के उत्पादन से बड़े पैमाने के उद्योग में संक्रमण करता है, ऐसा संक्रमण करता है जिसे इस तरह की अनुकूल परिस्थितियां त्वरित करती हों, वह “आवास की कमी” की भी अवधि होती है। एक ओर देहाती श्रमिक सहसा बहुत बड़ी तादाद में बड़े शहरों की ओर खिंचे आते हैं जो औद्योगिक केन्द्र बन जाते हैं; दूसरी ओर इन पुराने शहरों में मकान-निर्माण व्यवस्था बड़े पैमाने के नये उद्योग और

उसी हिसाब से बढ़नेवाले यातायात के अनुरूप नहीं रह जाती। सड़कें चौड़ी की जाती हैं, नयी सड़कें बनायी जाती हैं, ठीक शहरों के बीच रेलवे लाइनें बिछायी जाती हैं। ठीक उसी समय, जब मजदूरों की भारी भीड़ शहरों में पहुँचती रहती है, मजदूर बस्तियां बहुत बड़े पैमाने पर गिरा दी जाती हैं। इसलिए मजदूरों, छोटे व्यवसायियों और दस्तकारों के लिए, जो ग्राहकों के मामलों में मजदूरों पर निर्भर करते हैं, आवास की सहसा कमी हो जाती है। उन शहरों में, उदाहरण के लिए मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रैडफोर्ड, वार्मैन-एल्बेर्ट में, जो शुरू से ही औद्योगिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए, आवास की कमी सर्वथा अज्ञात होती है। दूसरी ओर लन्दन, पेरिस, बर्लिन, वियेना में इस कमी ने अपने समय में विकट रूप धारण किया था और तब से अधिकतर उसका यही स्वरूप कायम रहा है।

इसलिए उस समय से आवास की इसी विकट कमी को लेकर, जर्मनी में हो रही औद्योगिक क्रान्ति के इस लक्षण को लेकर अखबारों में "आवास प्रश्न" पर व्यापक बहस छिड़ गयी। इन्होंने हर तरह की सामाजिक नीम-हकीमी को जन्म दिया। इस तरह के लेखकों ने «*Volksstaat*» में भी स्थान प्राप्त कर लिया। अज्ञात लेखक ने, जो आगे चलकर व्युट्टेम्बेर्ग के अ० म्यूलबर्गर एम० डी० सिद्ध हुए, प्रूडों के सामाजिक-रासवाण के बारे में जर्मन मजदूरों को इस साधन के माध्यम से प्रबुद्ध करने के लिए यह अवसर अनुकूल समझा।⁵² मैंने ये विचित्र लेख प्रकाशन के लिए स्वीकार किये जाने के बारे में जब सम्पादकों के सामने आश्चर्य प्रकट किया तो उन्होंने मुझे उनका उत्तर देने की चुनौती दी जिसे मैंने स्वीकार कर लिया (देखें भाग १, 'प्रूडों आवास प्रश्न किस तरह हल करते हैं')। इस लेखमाला के तुरंत बाद एक दूसरी लेखमाला छपी जिसमें मैंने डा० एमिल शाक्स⁵³ की एक कृति के आधार पर इस प्रश्न के बारे में लोकोपकारी-पूँजीवादी दृष्टिकोण का विवेचन किया (देखें भाग २, 'पूँजीपति वर्ग आवास प्रश्न किस तरह हल करता है')। काफ़ी लम्बी चुप्पी के बाद डा० म्यूलबर्गर ने मेरे लेखों का उत्तर देने का मुझे सम्मान प्रदान किया⁵⁴ और इस चीज ने मुझे प्रत्युत्तर देने के लिए बाधित किया (देखें भाग ३, 'प्रूडों तथा आवास प्रश्न पर परिशिष्ट') ; इसके साथ वाद-विवाद तथा इस प्रश्न पर मेरा अध्ययन-कार्य समाप्त हो गया। यही इन तीन लेखमालाओं के मूल का इतिहास है जो पृथक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हो चुकी है। यदि अब इसका नया संस्करण निकालना आवश्यक हो गया है तो मैं इसके लिए निस्तान्देह जर्मन सरकार की शुभचिन्ता के लिए

आभारी हूँ जिसने उस पर पाबन्दी लगाकर स्वभावतया उसकी विक्री में ज़बर्दस्त वृद्धि कर दी। और मैं इस सुयोग का लाभ उठाकर उसे आदर के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैंने इस नये संस्करण के लिए पाठ सामग्री संशोधित की है; कुछ परिवर्द्धन किया है, टिप्पणियाँ भी जोड़ी हैं तथा पहले भाग में आर्थिक विषय-सम्बन्धी एक मामूली ग़लती शुद्ध की है जिसे मेरे विरोधी डा० म्यूलबर्गर दुर्भाग्य से नहीं देख पाये। इसे संशोधित करते समय मुझे यह आभास हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग आन्दोलन ने गत चौदह वर्षों के दौरान कितनी ज़बर्दस्त प्रगति की है। उस समय तक यह एक तथ्य था कि “बीस वर्षों तक रोमांस भाषाएं बोलनेवाले मज़दूरों के पास प्रूदों की कृतियों के अलावा और कोई मानसिक आहार नहीं था”* वशतः “अराजकतावाद” के जनक बकूनिन द्वारा, जिनकी दृष्टि में प्रूदों “हम सब के अध्यापक”, *notre maître à nous tous*, हैं, प्रूदोंपंथ की इकतरफ़ा व्याख्या को ध्यान में न रखा जाये। भले ही फ़्रांस में प्रूदोंपंथियों का मज़दूरों के बीच छोटा-सा पंथ रहा हो, केवल वे ही ऐसे लोग थे जिनके पास निश्चित रूप से निरूपित एक कार्यक्रम था और जो कम्प्यून के अन्दर आर्थिक क्षेत्र का नेतृत्व ग्रहण करने में समर्थ रहे। बेल्जियम में प्रूदोंपंथ का वालोन के मज़दूरों के बीच निर्विवाद बोलबाला था और स्पेन तथा इटली में मज़दूर वर्ग आन्दोलन में चन्द्र अपवादों को छोड़कर वह जो अराजकतावादी नहीं था, निर्विवाद रूप में प्रूदोंपंथी था। और आज? फ़्रांस में प्रूदोंपंथ का मज़दूरों के बीच से पूरी तरह सफ़ाया हो चुका है; उसके केवल आमूल परिवर्तनवादी पूंजीपतियों तथा निम्नपूंजीपतियों के बीच ही समर्थक हैं जो अपने को प्रूदोंपंथियों की ही तरह “समाजवादी” कहते हैं लेकिन जिनके विरुद्ध समाजवादी मज़दूर पूरे जोश के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बेल्जियम में फ़्लेमिंग्सों ने वालोनों को आन्दोलन के नेतृत्व से बाहर निकाल फेंका है, प्रूदोंपंथ को दूर फेंक दिया है और आन्दोलन का स्तर बहुत ऊपर उठा दिया है। इटली की तरह स्पेन में भी आठवें दशक की अराजकतावादी लहरें पीछे हट गयी हैं और वे अपने साथ प्रूदोंपंथ के अवशेषों को बहा ले गयी हैं। यदि इटली में नयी पार्टी अभी निर्माण की प्रक्रिया से गुज़र रही है तो स्पेन में छोटा-सा केन्द्रक—नया मैड्रिड फ़ेडरेशन—जो इंटरनेशनल की जनरल काँसिल के प्रति वफ़ादार रहा, अब विकसित होकर एक शक्तिशाली पार्टी

* देखें प्रस्तुत खण्ड।—सं०

वन गया है जो—जैसा कि स्वयं जनतंत्रवादी अखबारों से पता चलता है—मजदूरों पर पूंजीवादी जनतंत्रवादियों का प्रभाव अपने कोलाहलकारी अराजकतावादी पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं अधिक कारगर ढंग से नष्ट कर रहा है। लैटिन मजदूरों के बीच प्रदों की विस्मृत कृतियों का स्थान 'पूँजी', 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' तथा मार्क्सवादी चिन्तनधारा की कई अन्य कृतियों ने ले लिया है। मार्क्स की मुख्य मांग—एकच्छत्र राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सर्वहारा द्वारा समाज के नाम पर उत्पादन के समस्त साधनों का हस्तगतकरण—अब लैटिन देशों में भी पूरे क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग की मांग बन गयी है।

इसलिए यदि प्रदोंपंथ को लैटिन देशों के मजदूरों के बीच से अन्तिम रूप से मिटाया जा चुका है, यदि वह—अपनी वास्तविक नियति के अनुसार—फ्रांसीसी, स्पेनिश, इतालवी तथा बेल्जियाई पूंजीवादी आमूल परिवर्तनवादियों की पूंजीवादी तथा निम्न-पूँजीवादी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में केवल उनकी सेवा करता है तो आज फिर क्यों उसकी ओर लौटा जाये? इन लेखों को दुबारा छाप कर क्यों एक मृत शव से दुबारा लड़ा जाये?

सबसे पहले इसलिए कि ये लेख प्रदों तथा उनके जर्मन प्रतिनिधि के साथ वाद-विवाद तक सीमित नहीं हैं। मार्क्स तथा मेरे बीच विद्यमान श्रम विभाजन के फलस्वरूप हम लोगों के विचारों को पत्र-पत्रिकाओं में—इसलिए, खास तौर पर विरोधी दृष्टिकोणों के विरुद्ध संघर्ष में—प्रस्तुत करने का काम मेरे हिस्से आया ताकि मार्क्स को अपने महान आधारभूत कार्य के विशदीकरण के लिए समय मिल सके। दूसरी तरह के विचारों के विरुद्ध हमारे विचारों को अधिकतर वाद-विवाद के रूप में प्रस्तुत करना मेरे लिए आवश्यक बन गया। यही इस मामले में भी हुआ। भाग एक तथा तीन में प्रश्न के विषय में प्रदों की अवधारणों की आलोचना ही नहीं है अपितु उसमें हमारी अपनी अवधारणाएं भी प्रस्तुत की गयी हैं।

दूसरे, प्रदों ने यूरोपीय मजदूर वर्ग के आन्दोलन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि उन्हें आसानी से विस्मृति के गर्त में नहीं धकेला जा सकता। वह सिद्धान्त की दृष्टि से गलत साबित हो चुके हैं और व्यवहार की दृष्टि से निरस्त हो चुके हैं, फिर भी वह ऐतिहासिक दिलचस्पी का विषय बने हुए हैं। जो कोई आधुनिक समाजवाद का विस्तारपूर्वक अध्ययन करता है, उसे मजदूर आन्दोलन में “विजित दृष्टिकोणों” से परिचित होना चाहिए। प्रदों द्वारा सामाजिक सुधार के लिए व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से कई वर्ष पहले ही मार्क्स की रचना ‘दर्शन की दरिद्रता’ प्रकट हो चुकी थी। इसमें मार्क्स प्रदों के

विनिमय बैंक को भ्रूणावस्था में ही खोज सके तथा उसकी आलोचना कर सके थे। इसलिए इस दृष्टि से मेरी यह कृति मार्क्स की कृति का परिपूरक है हालांकि दुर्भाग्यवश यह पर्याप्त रूप से पूर्ण नहीं है। मार्क्स यह काम कहीं अधिक अच्छी तरह तथा कहीं अधिक आश्वस्तकारी ढंग से करते।

और आखिरी चीज़, पूंजीवादी तथा निम्न-पूंजीवादी समाजवाद को जर्मनी में ठीक इस घड़ी तक सशक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है। एक ओर, उनका प्रतिनिधित्व काटेडेर-समाजवादी⁵⁵ तथा सब रंगों के लोकोपकारी कर रहे हैं जिनके बीच मजदूरों की अपनी आवास स्थलियों का स्थायी स्वामी बनाने की इच्छा अब भी बड़ी भूमिका अदा कर रही है तथा इसलिए जिनके विरुद्ध मेरी पुस्तक अब भी सामयिक है। दूसरी ओर, स्वयं सामाजिक-जनवादी पार्टियाँ, यही नहीं राइख्स्टाग दल की क्रतारों तक में अब भी एक तरह के निम्न-पूंजीवादी समाजवाद को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। वह यह रूप इस तरह ग्रहण करता है—जहाँ आधुनिक समाजवाद के आधारभूत सिद्धान्तों को तथा उत्पादन के सभी साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व में रूपांतरित करना न्यायोचित माना जाता है, वहाँ यह भी घोषित किया जाता है कि इनकी पूर्ति दूर भविष्य में ही सम्भव है जो व्यवहारतः सर्वथा अगोचर है। इसलिए कहा जाता है कि फ़िलहाल तो सिर्फ़ सामाजिक पैक्ट लगाने का सहारा लेना पड़ेगा और परिस्थितियों के अनुसार “मेहनतकश वर्गों के” तथाकथित “उन्नयन” के लिए सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी प्रयत्नों तक के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की जा सकती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति का अस्तित्व जर्मनी में, *par excellence** कूपमंडूकता की धरती में सर्वथा अवश्यम्भावी है—विशेष रूप से ऐसे समय जब औद्योगिक विकास इस पुरानी तथा गहरी जड़ वाली कूपमंडूकता का उग्रतापूर्वक तथा बहुत बड़े पैमाने पर मूलोच्छेदन कर रहा है। परन्तु यह प्रवृत्ति हमारे मजदूरों की उस विलक्षण सहज बुद्धि को देखते हुए आन्दोलन के लिए सर्वथा हानिरहित है जिसका परिचय वे समाजवादविरोधी कानून,⁵⁶ पुलिस तथा अदालतों के विरुद्ध गत आठ वर्षों के संघर्ष के दौरान इतने शानदार ढंग से दे चुके हैं। परन्तु स्पष्ट रूप से यह अनुभव करना आवश्यक है कि यह प्रवृत्ति मौजूद है। और आगे चलकर यदि यह प्रवृत्ति अधिक दृढ़ आकार तथा अधिक निश्चित रूपरेखा ग्रहण कर लेती है,—जो आवश्यक ही नहीं, वांछनीय भी है,—तो उसे अपने कार्यक्रम के निरूपण के लिए अपने पूर्ववर्तियों के

* मुख्यतया।—सं०

पास वापस जाना पड़ेगा और ऐसा करते समय वह शायद ही भूदों को नज़रंदाज़ कर सके।

“आवास प्रश्न” के लिए बड़े पूंजीपतियों तथा निम्नपूंजीपतियों दोनों के समाधानों का सारतत्त्व यह है कि मज़दूर के पास रहने के लिए अपना घर होना चाहिए। परन्तु यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे पिछले बीस वर्षों के दौरान जर्मनी के औद्योगिक विकास ने बिल्कुल दूसरी रोशनी में दिखाया है। ऐसा और कोई देश नहीं है जहाँ उजरती मज़दूर के पास अपना घर ही नहीं, वरन् बाग़ या साथ ही खेत भी हो। इन मज़दूरों के अलावा ऐसे और बहुत-से मज़दूर भी हैं जिनके पास लगानदारों के रूप में घर, बाग़ या खेत भी हैं, जिन पर वे काफ़ी मज़बूती से क़ाबिज़ हैं। सागवाड़ी अथवा छोटे पैमाने की खेती के साथ मिलकर ग्रामीण घरेलू उद्योग जर्मनी के बड़े पैमाने के नये उद्योग का व्यापक आधार बना हुआ है। पश्चिम में मज़दूर अधिकतर अपने घरों के स्वामी हैं तथा पूर्व में ये मुख्यतया किरायेदार हैं। हम घरेलू उद्योग को सागवाड़ी तथा खेती के साथ, और इसलिए सुरक्षित आवास के साथ मिला हुआ पाते हैं, और ऐसा वहीं नहीं है जहाँ हथबुनाई अब भी यांत्रिक करघे के विरुद्ध संघर्ष से जूझ रही है—लोवर राइनलैंड और वेस्टफ़ालिया में, सैक्सन एर्ज़गेबेर्गे और साइलीशिया में ही नहीं, वरन् उन सब स्थानों में भी—उदाहरण के लिए टुरिंगियन वन तथा रोन क्षेत्र में—मीजूद है जहाँ कोई न कोई घरेलू उद्योग अपने को ग्राम्य व्यवसाय के रूप में प्रतिष्ठापित कर चुका है। तम्बाकू की इजारेदारी पर वाद-विवाद के समय पता चला कि सिगार बनाने का काम बड़े पैमाने पर ग्राम्य घरेलू उद्योग के रूप में चल रहा है। जहाँ कहीं छोटे किसान की तंगहाली बढ़ती है—जैसा कि उदाहरण के लिए चन्द साल पहले आइफ़ेल⁵⁷ इलाक़े में हुआ—पूँजीवादी अख़बार तुरन्त एकमात्र उपचार के रूप में उपयोगी घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए चीख़-पुकार मचाने लगते हैं। वस्तुतः जर्मन छोटे किसानों की बढ़ती हुई अभावग्रस्तता तथा जर्मन उद्योग में मीजूद आम स्थिति दोनों चीज़ें ग्राम्य उद्योग के सतत विस्तार का तक्राजा करती हैं। यह जर्मनी का विशिष्ट लक्षण है। अपवाद के रूप में ही हमें फ़्रांस में भी इस जैसी कोई स्थिति देखने को मिलती है, इस तरह का अपवाद उदाहरण के लिए फ़्रांस के रेशम उत्पादन प्रदेश हैं। इंग्लैंड में, जहाँ छोटे किसान नहीं हैं, ग्राम्य घरेलू उद्योग दिहाड़ीदार मज़दूरों के बीबी-बच्चों के श्रम पर अवलम्बित है। केवल आयरलैंड में ही हम पोशाक तैयार करनेवाले ग्राम्य घरेलू उद्योग को जर्मनी की तरह वास्तविक कृषक परिवारों द्वारा संचालित होते देखते

हैं। स्वभावतः हम यहां रूस तथा अन्य देशों की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें विश्व मंडी में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।

इस तरह उद्योग के मामले में जर्मनी के व्यापक भू-क्षेत्रों में ऐसी हालत मौजूद है जो पहली नज़र में मशीनों के प्रचलन से पूर्व सामान्यतया व्याप्त हालत से मिलती-जुलती दिखायी देती है। परन्तु केवल पहली ही नज़र में ऐसा दिखायी देता है। पूर्ववर्ती काल के ग्राम्य घरेलू उद्योग, जो सागवाड़ी और खेती से जुड़ा हुआ था, कम से कम उन देशों में, जहां उद्योग विकसित हो रहा था, मजदूर वर्ग के लिए सहनीय तथा यत्र-तत्र सुविधाजनक भौतिक स्थिति का आधार और साथ ही उसकी बौद्धिक और राजनीतिक नगण्यता का आधार था। हाथ की बनी वस्तु तथा उसकी लागत मंडी क्रीमत को निर्धारित किया करती थीं; श्रम उत्पादकता आज की तुलना में सर्वथा न्यून होने के कारण मंडी नियमतः पूर्ति की तुलना में अधिक तेज़ी के साथ विकसित होती थी। गत शताब्दी के लगभग मध्य तक इंग्लैंड में और अंशतः फ्रांस में—विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के मामले में—यही होता रहा। परन्तु जर्मनी में, जिसने उस समय तीसवर्षीय युद्ध⁵⁸ की तबाही के बाद अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत अपना पुनरुद्धार शुरू ही किया था, स्थिति निस्सन्देह सर्वथा भिन्न थी। उस समय जर्मनी का एकमात्र घरेलू उद्योग था लिनेन वस्त्र का बुनाई उद्योग, जो विश्व मंडी के लिए उत्पादन कर रहा था, वह करों तथा सामन्ती सेवाओं के भार से इतना दबा हुआ था कि उसने कृषक बुनकरों को शेष कृषक समुदाय के अत्यन्त निम्न जीवन स्तर से कभी ऊपर नहीं उठाया। फिर भी ग्रामीण औद्योगिक मजदूर उस समय कुछ हद तक सुरक्षापूर्ण अस्तित्व का उपभोग कर रहा था।

मशीनों के प्रचलन पर यह सब बदल गया। अब मशीनों से निर्मित वस्तुएं क्रीमतें निर्धारित कर रही थीं तथा इस क्रीमत के साथ घरेलू औद्योगिक मजदूर की उजरत घट गयी। परन्तु मजदूर को यह स्वीकार करना पड़ता था, वरना उसे किसी और काम की तलाश करनी पड़ती थी। और वह सर्वहारा बने बिना, अर्थात् अपना छोटा-सा घर, बाग या खेत—वह चाहे अपना हो या लगान पर हो—छोड़े बिना यह नहीं कर सकता था। विरले ही मामलों में वह इसके लिए तैयार होता। इस तरह हाथ से काम करनेवाले पुराने देहाती बुनकरों की सागवाड़ी तथा खेती ऐसा कारण बन गया जिसके परिणामस्वरूप जर्मनी में यांत्रिक करघे के विरुद्ध हथकरघे का संघर्ष इतने लम्बे समय तक चलता रहा और उसका कोई निर्णायक अन्त नहीं हो सका। इस संघर्ष में खास तौर पर इंग्लैंड में पहली बार

यह चीज सामने आई कि जो परिस्थितियाँ पहले मजदूर की—अपने उत्पादन गाधनों का स्वामी होने की—अपेक्षाकृत समृद्धि के आधार का काम देती थीं, वे ही अब उसके लिए अड़चन तथा बदकिस्मती का कारण बन गयीं। उद्योग के क्षेत्र में यांत्रिक करघे ने उसके हथकरघे को पराजित कर दिया, कृषि में छोटे पैमाने की खेती की तुलना में बड़े पैमाने की खेती का पलड़ा भारी हो गया। परन्तु जहाँ बहुत-से लोगों का सामूहिक श्रम तथा मशीनों और विज्ञान का उपयोग उत्पादन के दोनों क्षेत्रों में सामाजिक नियम बन गये, वहाँ मजदूर को उसके मकान, वास, खेत तथा हथकरघे ने निजी उत्पादन की पुरानी पड़ चुकी विधियों और हाथ से किये जानेवाले श्रम के साथ बांधा रखा। घर और बाग का स्वामित्व अब धर-उधर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता से कहीं कम लाभप्रद था। कोई भी कारखाना मजदूर हाथ से काम करनेवाले देहाती बुनकर की जगह लेने को तैयार नहीं था जो धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप से भूख से मर रहा था।

जर्मनी ने विश्व मंडी में देर से प्रवेश किया। हमारे बड़े पैमाने के उद्योग का इतिहास पाँचवें दशक से शुरू होता है। उसे पहली उत्प्रेरणा १८४८ की क्रांति से मिली और वह १८६६ तथा १८७० की क्रांतियों^{५९} द्वारा अपने रास्ते से सबसे बिकट राजनीतिक बाधाएँ दूर किये जाने के बाद ही पूरी तरह विकसित हो सका। परन्तु उसने दूसरों को विश्व मंडी पर पहले से ही काफ़ी हद तक छाया हुआ पाया। व्यापक ख़पत वाली वस्तुओं की इंग्लैंड तथा परिष्कृत विलास सामग्रियों की पूर्ति फ़्रांस कर रहा था। जर्मनी कीमत के मामले में इंग्लैंड को तथा गुण के मामले में फ़्रांस को परास्त नहीं कर सकता था। इसलिए फ़िलहाल इसके मलावा और कोई रास्ता नहीं था कि जर्मन उत्पादन के घिसे-पिटे रास्ते पर चल कर पहले अपनी उन वस्तुओं को लेकर विश्व मंडी में घुसे जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत घटिया और फ़्रांसीसियों के लिए बहुत ही अनगढ़ थीं। निस्सन्देह धोखा देने की जर्मन प्रथा को—पहले बढ़िया नमूने और फिर उसके बाद घटिया माल भेजना—जल्द विश्व मंडी में पर्याप्त रूप से कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ी और उसका लगभग परित्याग कर दिया गया। दूसरी ओर अत्युत्पादन में प्रतियोगिता के कारण विश्वसनीय अंग्रेज़ों तक को धीरे-धीरे घटिया किस्म के उत्पादन का शास्ता पकड़ना पड़ा और इस तरह जर्मनों को लाभप्रद स्थिति प्रदान प्राप्त हुई जिन्हें इस क्षेत्र में कोई हरा नहीं सकता। इस तरह हम अन्ततः बड़े पैमाने का उद्योग हासिल कर सके तथा विश्व मंडी में निश्चित भूमिका अदा कर सके। परन्तु हमारा बड़े पैमाने का उद्योग विशिष्ट रूप से घरेलू मंडी के लिए काम

करता है (लौह उद्योग को छोड़कर जो घरेलू मंडी की आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादित करता है) और हमारे अधिकांश निर्यात में विशाल परिमाण में छोटी-छोटी वस्तुएं होती हैं, जिनके लिए बड़े पैमाने का उद्योग हृद से हृद अर्द्धतैयार माल मुहैया करता है जबकि स्वयं इन छोटी वस्तुओं की पूर्ति मुख्यतया ग्राम्य घरेलू उद्योग करता है।

यहीं आधुनिक मजदूर के लिए मकान तथा भूस्वामित्व का "वरदान" अपनी पूरी भव्यता के साथ दिखायी देता है। जर्मन घरेलू उद्योगों में जितनी कम शर्मनाक मजदूरी दी जाती है, उतनी और शायद कहीं नहीं दी जाती, शायद आयरिश घरेलू उद्योगों तक में नहीं। मजदूर का परिवार अपने छोटे-से बाग या खेत से जो कुछ कमाता है, उसे पूंजीपति प्रतियोगिता का लाभ उठाकर मजदूर की श्रम शक्ति की कीमत से काट लेता है। मजदूर को जो भी उजरत दी जाती है उसे स्वीकार करने के लिए वह विवश होता है; एक तो इसलिए कि ऐसा न करने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और वे अपनी खेती की उपज के सहारे ही ज़िन्दा नहीं रह सकते और दूसरे इसलिए कि यही खेती तथा भूस्वामित्व उन्हें अपने स्थान से बांधे रखते हैं तथा कोई दूसरा रोजगार तलाश करने के लिए इधर-उधर नहीं देखने देते। यह है वह आधार जो छोटी-छोटी वस्तुओं की एक पूरी शृंखला में विश्व मंडी में प्रतियोगिता करने की जर्मन क्षमता को बरकरार रखता है। पूंजी पर पूरा मुनाफ़ा सामान्य मजदूरी से काटा जाता है तथा पूरा अतिरिक्त मूल्य खरीददार को भेंट किया जा सकता है। अधिकांश निर्यातित जर्मन वस्तुओं के असाधारण रूप से सस्ते होने का यही रहस्य है।

अन्य तमाम परिस्थितियों की तुलना में यही परिस्थिति अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी जर्मन मजदूरों की रहन-सहन की अवस्थाओं को पश्चिम यूरोपीय देशों से नीचे रखने के लिए अधिक उत्तरदायी है। श्रम की ऐसी कीमतों का, जिनमें श्रम-शक्ति के मूल्य से परम्परागत रूप से कहीं नीचे रखा जाता है, सारा भार शहरी मजदूरों, यहां तक कि बड़े शहरों तक में मजदूरों की मजदूरी को श्रम-शक्ति के मूल्य से नीचे दबाकर रखता है। यह इसलिए और भी ज्यादा होता है कि शहरों में भी निम्न मजदूरी वाले घरेलू उद्योग ने पुरानी दस्तकारियों का स्थान ले लिया है और यहां भी मजदूरी का आम स्तर और दब जाता है।

यहां हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पूर्ववर्ती ऐतिहासिक मंज़िल में जो वस्तु मजदूरों की अपेक्षाकृत समृद्धि का—अर्थात् कृषि का उद्योग से सम्बन्ध, मकान, बाग, खेत तथा निस्सन्देह आवास-स्थल के स्वामित्व का—आधार थी, वह आज,

बड़े उद्योग के प्रभुत्व के अन्तर्गत मजदूर के लिए सबसे विकट बाधक ही नहीं, वरन् पूरे मजदूर वर्ग के लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती भी बनती जा रही है, पृथक-पृथक ज़िलों में तथा उत्पादन की अलग-अलग शाखाओं में ही नहीं, वरन् पूरे देश में भी मजदूरी को सामान्य स्तर से बेमिसाल नीचे रखे जाने का आधार बनती जा रही है। इसलिए यदि बड़े तथा निम्नपूँजीपति, जो मजदूरी से इन असामान्य कटौतियों पर जीवित रहते हैं तथा उनसे श्रीमर बनते हैं, घरेलू उद्योग के लिए तथा इस बात के लिए उत्सुक हैं कि मजदूर अपने मकानों के मालिक हों और यदि वे यह मानते हैं कि नये घरेलू उद्योगों की स्थापना समस्त ग्रामीण विपत्तियों को दूर करने का एकमात्र उपचार है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है !

यह मामला का एक पहलू है, परन्तु इसका उल्टा पहलू भी है। घरेलू उद्योग जर्मनी के निर्यात उद्योग और इसलिए बड़े पैमाने के पूरे उद्योग का व्यापक आधार बन गया है। इस वजह से वह जर्मनी के व्यापक क्षेत्रों में फैला तथा अब भी रोज़ फैलता जा रहा है। छोटे किसान की बर्बादी, जो उस समय से अवश्यम्भासी भी जब से अपने इस्तेमाल के लिए उसके औद्योगिक घरेलू उत्पादन को सस्ते तैयारशुदा वस्त्र उत्पादों तथा मशीनी उत्पादों ने उसी तरह नष्ट किया जिस तरह मार्क-प्रणाली⁶⁰ की समाप्ति ने, समान मार्क और अनिवार्य सस्यावर्तन के खाते में उसके पशुधन को और इस कारण खाद-उत्पादन को नष्ट किया था—यह बर्बादी सूदखोर का शिकार बननेवाले छोटे किसान को बलपूर्वक आधुनिक घरेलू उद्योग के पास पहुंचाती है। आयरलैंड में ज़मींदार के लगान की तरह जर्मनी में गिरवी रखनेवाले सूदखोर का ब्याज भी ज़मीन की उपज से अदा नहीं किया जा सकता, उसे तो केवल औद्योगिक किसान की मजदूरी से ही चुकाया जा सकता है। घरेलू उद्योग के विस्तार के साथ एक के बाद दूसरा कृषक क्षेत्र वर्तमान युग के औद्योगिक विकास की ओर खिंचता आ रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा ग्राम्य क्षेत्रों का यही वह क्रांतिकरण है जो औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में जर्मनी में कहीं अधिक व्यापक क्षेत्र में फैला रहा है। यह हमारे उद्योग का एक अपेक्षाकृत निम्न स्तर ही उसके क्षेत्रीय विस्तार को और भी आवश्यक बना रहा है। यही कारण है कि इंग्लैंड तथा फ्रांस के विपरीत जर्मनी में क्रांतिकारी मजदूर वर्ग आन्दोलन विशिष्ट रूप से शहरी केंद्रों तक सीमित रहने के बजाय देश के अधिकांश भाग में इतने प्रचंड रूप से बढ़ा है। यही चीज़ आन्दोलन की शक्ति, निश्चित तथा अरोध्य अग्रगति के कारण पर प्रकाश डालती है। यह सर्वथा

स्पष्ट है कि जर्मनी में राजधानी तथा अन्य बड़े नगरों में विजयी विप्लव तभी सम्भव होगा जब अधिकांश छोटे शहर तथा ग्राम्य जिलों का अधिकांश भाग क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए परिपक्व हो जायेंगे। न्यूनाधिक सामान्य विकास की स्थिति में हम मजदूर वर्ग की वैसी विजयें हासिल करने की स्थिति में कभी नहीं होंगे जो १८४८ तथा १८७१ में पेरिसवासियों ने हासिल की थीं। लेकिन ठीक इसी कारण हमें प्रतिक्रियावादी प्रान्तों के हाथों क्रांतिकारी राजधानी की पराजय भी नहीं झेलनी पड़ेगी जो पेरिस ने दोनों मौकों पर झेली थी। फ्रांस में आन्दोलन का जन्म सदैव राजधानी से हुआ ; जर्मनी में उसका जन्म बड़े उद्योग, मैनूफ्रेक्चर तथा घरेलू उद्योग के जिलों में हुआ ; राजधानी पर बाद में ही विजय पायी गयी। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में भी शायद पहल फ्रांसीसियों के हाथ में रहे, लेकिन निर्णायक विजय जर्मनी में ही हो सकती है।

परन्तु यह ग्राम्य घरेलू उद्योग तथा मैनूफ्रेक्चर, जो अपने विस्तार के कारण जर्मन उत्पादन की निर्णायक शाखा बन गये हैं और इस तरह जर्मन कृषक समुदाय का अधिकाधिक क्रांतिकरण कर रहे हैं, आगे के क्रांतिकारी परिवर्तन की अभी प्रारम्भिक मंजिल ही हैं। जैसा कि मार्क्स सिद्ध कर चुके हैं (‘पूँजी’, खंड १, तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४८४-४९५), विकास की एक खास मंजिल पर मशीनों तथा कारखाना उत्पादन के कारण उसके लिए भी मौत की घड़ी बन जायेगी। और उस घड़ी की आवाज निकट ही है। परन्तु जर्मनी में ग्राम्य घरेलू उद्योग और मैनूफ्रेक्चर को मशीनों तथा कारखाना उत्पादन द्वारा नष्ट किये जाने का अर्थ है लाखों-लाख ग्राम्य उत्पादकों की आजीविका का चौपट किया जाना, छोटे जर्मन कृषक समुदाय के लगभग आधे भाग का सम्पत्तिहरण, घरेलू उद्योग का कारखाना उत्पादन में ही नहीं, अपितु कृषक अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने की पूँजीवादी कृषि में तथा छोटी भूसम्पत्ति का बड़ी जागीरों में रूपान्तरण—यह किसानों की बलि देकर पूँजी तथा बड़े भूस्वामित्व के पक्ष में औद्योगिक तथा कृषि क्रांति होगी। यदि जर्मनी की किस्मत में यही बदा है कि वह पुरानी सामाजिक अवस्थाओं के अन्तर्गत रहते हुए ही इस रूपान्तरण के बीच से गुजरे तो वह निर्विवाद रूप से एक परिवर्तन-बिन्दु होगी। यदि उस समय तक किसी और देश का मजदूर वर्ग पहल नहीं करेगा तो जर्मनी यकीनन पहले प्रहार करेगा और “यशस्वी सेना” के कृषक बेटे वीरतापूर्वक सहायता देने के लिए आगे बढ़ेंगे।

इस तरह पूँजीवादी तथा निम्न-पूँजीवादी कल्पना—जो प्रत्येक मजदूर को अपने छोटे-से घर का स्वामित्व प्रदान करेगी तथा इस तरह उसे अर्द्धसामन्ती ढंग

से अपने पूंजीपति विशेष के साथ बंधी हुई रखेगी—अत्यन्त भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। उसके साकार होने के बदले जो चीजें सामने आती हैं, वे हैं—सारे छोटे ग्राम्य मकान मालिकों का औद्योगिक घरेलू मजदूरों में रूपान्तरण; पुराने मलगाव का ध्वंस, उसके साथ छोटे किसानों की, जो “सामाजिक भंवर” में खींच लिये जाते हैं, राजनीतिक नगण्यता का ध्वंस; औद्योगिक क्रांति का ग्राम्य क्षेत्रों में विस्तार और इस तरह आवादी के सबसे गतिहीन तथा सबसे अनुदारवादी भाग का क्रांतिकारी सरगम अड्डे में रूपान्तरण; और इन सब के चरम बिन्दु के रूप में घरेलू उद्योग में जुटे किसानों का मशीनों द्वारा सम्पत्तिहरण, जिन्हें वे बलपूर्वक विप्लव की गोद में धकेलती हैं।

हम पूंजीवादी-समाजवादी लोकोपकारियों को अपने आदर्शों का तब तक सहर्ष आनन्द लेने दे सकते हैं जब तक वे इसे पूरा करने के लिए पूंजीपतियों के रूप में अपना सामाजिक कार्य अपने हितों के विरुद्ध और सामाजिक क्रान्ति के लाभार्थ तथा अग्रगति के हेतु जारी रखेंगे।

सन्दन, १० जनवरी १८८७

फ्रेडरिक एंगेल्स

१५ तथा २२ जनवरी १८८७ को «*Der Sozialdemokrat*» के अंक ३ तथा ४ में और फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक «*Zur Wohnungsfrage*» (Hottingen—Zürich, 1887) में प्रकाशित।

आवास प्रश्न

०

भाग १

प्रूदों आवास प्रश्न किस तरह हल करते हैं

«*Volksstaat*» के अंक १० तथा आगे के अंकों में आवास प्रश्न पर एक लेखमाला प्रकाशित हुई है जिसमें छः लेख हैं। ये लेख केवल इस कारण ध्यान देने योग्य हैं कि वे (पांचवें दशक की बहुत पहले ही विस्मृत कुछ अर्द्ध-गल्प-साहित्यिक रचनाओं को छोड़कर) प्रूदोंपंथ को जर्मनी में प्रत्यारोपित करने का पहला प्रयास है। यह जर्मन समाजवाद के पूरे विकास प्रवाह की, जिसने २५ वर्ष पहले ही ठीक प्रूदोंपंथी विचारों पर निर्णायक प्रहार किया था,* तुलना में उलटी दिशा में इतना बड़ा पग है कि इस प्रयास का तुरन्त उत्तर देना उचित है।

आवास की तथाकथित कमी, जिसकी ओर इन दिनों अखबारों में इतना अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इस तथ्य में निहित नहीं है कि मजदूर वर्ग सामान्यतया खराब, भीड़भरे तथा अस्वास्थ्यकर घरों में रहता है। यह कमी कोई वर्तमान युग की ही विशिष्टता नहीं है; यह कोई ऐसी एक तकलीफ भी नहीं है जो तमाम पूर्ववर्ती उत्पीड़ित वर्गों के विपरीत केवल आधुनिक सर्वहारा के लिए ही अभिलाक्षणिक हो। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि समस्त युगों में समस्त उत्पीड़ित वर्गों ने इसे भोगा है। आवास की इस कमी को दूर करने का एक ही साधन है—मेहनतकश वर्ग का सत्तारूढ़ वर्ग द्वारा किये जानेवाले शोषण तथा उत्पीड़न का पूरी तरह खात्मा कर देना। आज आवास की कमी का जां

* मार्क्स, 'दर्शन की दरिद्रता', ब्रसेल्स तथा पेरिस, १८४७।

अर्थ लगाया जाता है, वह है आवादी के सहसा बड़े शहरों की ओर बढ़ने के फलस्वरूप मजदूरों की यों भी खराब आवास अवस्थाओं का विशेष रूप से और बिगड़ जाना; मकान भाड़े में अपरिमित वृद्धि, पृथक-पृथक घरों में और ज्यादा भीड़-भाड़ तथा कुछ के रहने के लिए जगह पाना ही असम्भव हो जाना। आवास की इस कमी की केवल इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि यह मजदूर वर्ग तक सीमित नहीं है अपितु उसका निम्नपूजीपति वर्ग पर भी असर पड़ा है।

आवास की कमी, जिससे हमारे बड़े आधुनिक शहरों में मजदूर तथा निम्नपूजीपति वर्ग का एक भाग पीड़ित है, उन अनगिनत, अपेक्षाकृत छोटी, आनुवंशिक बुराइयों में से एक है जिन्हें उत्पादन की आधुनिक पूंजीवादी पद्धति जन्म देती है। यह पूंजीपति द्वारा मजदूर का मजदूर के रूप में शोषण का प्रत्यक्ष फल कदापि नहीं है। यह शोषण ही वह मूल बुराई है जिसे सामाजिक क्रान्ति उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति का उन्मूलन कर मिटा देना चाहती है। उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति की आधारशिला यह तथ्य है कि हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पूंजीपति को मजदूर की श्रम शक्ति को उसके मूल्य पर खरीदने परन्तु उससे कहीं अधिक वसूल करने में समर्थ बनाती है। इसे पूंजीपति मजदूर से उससे कहीं अधिक समय तक काम कराके हासिल करता है जो श्रम शक्ति के लिए चुकायी जाने-वाली क्रीमत के पुनरुत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इस ढंग से उत्पादित अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों और जमींदारों तथा उनके बेतनभोगी नौकर-चाकरों के बीच-पोप और सम्राट से लेकर रात को चौकीदारी करनेवालों, आदि के बीच-वितरित हो जाता है। हमारा यहाँ इस चीज से सरोकार नहीं है कि यह वितरण कैसे होता है। परन्तु इतना निश्चित है कि वे सब, जो काम नहीं करते, इस अतिरिक्त मूल्य से होनेवाली प्राप्ति के सहारे ही जीवित रह सकते हैं जो उनके पास किसी भी रूप में पहुँचती है। (कार्ल मार्क्स की 'पूँजी' देखें जिसमें इसे पहली बार प्रतिपादित किया गया था।)

मजदूर वर्ग जिस अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है तथा जो उसे कुछ भुगतान किये बिना उससे छीन लिया जाता है, उसका और मेहनतकश वर्गों के बीच अत्यन्त शिक्षाप्रद झगड़ों और पारस्परिक धोखाधड़ी के बीच वितरण होता है। चूंकि यह वितरण क्रय और विक्रय के माध्यम से होता है इसलिए इसकी एक प्रमुख विधि यह है कि बेचनेवाला खरीदनेवाले को ठगता है; और खास तौर पर बड़े शहरों में खुदरा व्यापार में यह चीज बेचनेवाले के अस्तित्व के लिए मूल शर्त बन गयी है। परन्तु अगर मजदूर को पंसारी या तानबाई क्रीमत में

या माल के गुण के मामले में ठगता है तो ऐसा उसके साथ मजदूर होने की खास हैसियत के कारण नहीं होता। इसके विपरीत ठगी की एक निश्चित मात्रा ज्यों ही किसी जगह सामाजिक नियम बन जाती है, वहाँ अन्ततोगत्वा उसकी पूर्ति मजदूरी में उसी हिसाब से वृद्धि करके करनी पड़ती है। मजदूर दुकानदार के सामने खरीददार के रूप में, यानी धन या उधार के पैसे के मालिक के रूप में पहुंचता है, मजदूर के यानी श्रम शक्ति बेचनेवाले के रूप में कदापि नहीं। ठगी दौलतमन्द सामाजिक वर्गों की तुलना में उस पर और पूरे सम्पत्तिहीन वर्ग पर अधिक चोट कर सकती है परन्तु वह ऐसी बुराई नहीं है जो केवल उसी पर चोट करती हो, उसके ही वर्ग के लिए विशिष्ट हो।

यही बात आवास की कमी पर लागू होती है। बड़े आधुनिक शहरों के विस्तार के कारण उनके कुछ भागों में, विशेष रूप से केन्द्रीय भागों में ज़मीन को कृत्रिम रूप से बढ़ाये गये मूल्य, अकसर अपरिमित रूप से बढ़े हुए मूल्य पर बेचा जाता है; इन इलाकों में बनी इमारतें इस मूल्य को बढ़ाने के बजाय उसे घटाती हैं क्योंकि ये इमारतें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नहीं रह जाती। उन्हें गिरा दिया जाता है तथा उनकी जगह नयी इमारतें बनायी जाती हैं। यह सर्वोपरि केन्द्रीय इलाकों में स्थित मजदूरों के मकानों के साथ होता है, जिनके किराये अधिकतम भीड़ के वावजूद एक निश्चित अधिकतम सीमा से या तो कभी बढ़ ही नहीं सकते या फिर बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं। ये मकान गिरा दिये जाते हैं और उनकी जगह पर दुकानें, गोदाम तथा सार्वजनिक इमारतें खड़ी की जाती हैं। बोनापार्टपंथियों ने पेरिस में अपने ओस्मान के जरिये इस ठगी के लिए और अपने को मालामाल बनाने के लिए इस प्रवृत्ति का भरपूर उपयोग किया था। परन्तु ओस्मान की भावना लन्दन, मानचेस्टर तथा लिवरपूल में भी पहुंची है और वह बर्लिन तथा वियेना में भी अपने लिए सर्वथा घर जैसा वातावरण अनुभव कर रही है। नतीजा यह है कि मजदूरों को शहरों के केन्द्रीय इलाकों से बाहरी भागों में खदेड़ा जा रहा है; मजदूरों के रहने के लिए घर, सामान्यतया छोटे घर दुर्लभ और महंगे, अकसर सर्वथा अप्राप्य बनते जा रहे हैं, क्योंकि इन परिस्थितियों के अन्तर्गत भवन निर्माण उद्योग, जिसे अधिक महंगे आवासगृह सट्टेबाजी के लिए कहीं बेहतर क्षेत्र मुहैया करते हैं, मजदूरों के लिए आवासगृहों का निर्माण अपवादस्वरूप ही करता है।

इसलिए आवास की यह कमी यकीनन मजदूर पर किसी भी अधिक खुशहाल वर्ग से ज्यादा चोट करती है परन्तु यह विशिष्ट रूप से मजदूर वर्ग पर बोझ

डालनेवाली वैसी ही बुराई है जैसी दुकानदार की ठगी है। जहां तक मजदूर वर्ग का सम्बन्ध है, यह बुराई जब एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तथा एक निश्चित स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, उसे भी उतना ही निश्चित आर्थिक सन्तुलन मिल जाता है।

मुख्यतया ठीक ये ही वे बुराइयां हैं, मजदूर वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के साथ, खास तौर पर निम्नपूँजीपति वर्ग के साथ मिलकर वहन की जानेवाली ये ही वे बुराइयां हैं जिनमें अपने को व्यस्त रखना निम्न-पूँजीवादी समाजवाद—जिसके प्रदों अनुयायी हैं—पसन्द करता है। इसलिए यह जर्रा भी संयोग की बात नहीं है कि हमारे जर्मन प्रदोंपंथी * मुख्यतया आवास प्रश्न को ग्रहण कर लेते हैं, जो—जैसा कि हम देख चुके हैं—कदापि विशिष्टतया मजदूर वर्ग का प्रश्न नहीं है; और यह भी कोई संयोग की बात नहीं है कि वह इसके विपरीत आवास प्रश्न को वास्तविक रूप से, विशिष्ट रूप से मजदूर वर्ग का प्रश्न मानते हैं।

“किरायेदार का मकान-मालिक के साथ सम्बन्ध उजरती मजदूर के पूँजीपति के साथ सम्बन्ध जैसा है।”

यह सरासर झूठ है।

आवास प्रश्न में हमारे सामने एक दूसरे के सामने खड़े दो पक्ष हैं—किरायेदार और मकानदार, यानी मकान-मालिक। किरायेदार मकान-मालिक के घर को प्रस्थायी उपयोग के लिए खरीदना चाहता है; उसके पास धन अथवा उधार का पैसा है, भले ही किराये में वृद्धि के रूप में भारी दर पर यह उधार स्वयं मकान-मालिक से लेना पड़ा हो। यह तो सामान्य माल बिक्री है; यह सर्वहारा तथा बुर्जुआ के बीच, मजदूर तथा पूँजीपति के बीच लेन-देन नहीं है। किरायेदार—भले ही वह मजदूर हो—धन वाले व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है; वह अपना माल,—ऐसा माल, जो विशिष्ट रूप में उसका अपना माल है, यानी अपनी श्रम शक्ति—पहले ही बेच चुका होगा ताकि वह रहने की जगह के इस्तेमाल के लिए खरीददार के रूप में प्रकट हो सके या फिर उसे अपनी श्रम शक्ति की आसन्न बिक्री की गारंटी देने की स्थिति में होना चाहिए। वे विशिष्ट परिणाम, जिन्हें पूँजीपति को श्रम शक्ति की बिक्री जन्म देती है, यहां सर्वथा

* आर्थर म्यूलबर्गर।—सं०

गायब होते हैं। पूंजीपति खरीदी गयी श्रम शक्ति से पहले अपना मूल्य, फिर अतिरिक्त मूल्य पुनरुत्पादित करेता है जो पूंजीपति वर्ग के बीच वितरण तक अस्थायी रूप से उसके हाथ में रहता है। इसलिए इस मामले में अतिरिक्त मूल्य उत्पादित होता है, विद्यमान मूल्य का कुल योग बढ़ता है। किराये के लेन-देन में स्थिति सर्वथा भिन्न होती है। मकान-मालिक किरायेदार से चाहे कितना ही वसूल ले, यह केवल मौजूद, पहले से उत्पादित मूल्य का ही हस्तान्तरण है और मकान-मालिक तथा किरायेदार दोनों के पास के मूल्यों का कुल योग पहले जितना बना रहता है। पूंजीपति श्रम का भुगतान चाहे उसके मूल्य पर, या उससे कम या ज्यादा करे, मजदूर के श्रम के उत्पाद का एक हिस्सा हमेशा ठग लिया जाता है; किरायादार तभी ठगा जाता है जब उसे रहने की जगह के मूल्य से ज्यादा किराया देने के लिए बाधित किया जाता है। इसलिए मकान-मालिक तथा किरायेदार के सम्बन्ध को मजदूर तथा पूंजीपति के सम्बन्ध के बराबर बनाने की कोशिश करना मकान-मालिक और किरायेदार के सम्बन्ध को सर्वथा गलत ढंग से प्रस्तुत करना है। इसके विपरीत हम यहां दो नागरिकों के बीच माल का सर्वथा सामान्य लेन-देन पाते हैं और यह लेन-देन आर्थिक नियमों के अनुसार होता है जो सामान्य रूप में माल की बिक्री और विशेष रूप से माल रूपी “भू-सम्पत्ति” की बिक्री को विनियमित करते हैं। मकान या मकान के एक भाग के निर्माण तथा रख-रखाव पर आनेवाली लागत का सबसे पहले हिसाब लगाया जाता है; फिर जमीन का मूल्य आता है जिसे मकान की अधिक या कम अनुकूल स्थिति निर्धारित करती है; समय विशेष पर विद्यमान पूर्ति तथा मांग के बीच सम्बन्ध अन्त में आता है। यह सामान्य आर्थिक सम्बन्ध हमारे प्रदोषवादी के मस्तिष्क में इस प्रकार प्रकट होता है -

“मकान एक बार तैयार हो जाने के बाद सामाजिक श्रम के एक निश्चिन अंश पर स्थायी कानूनी हक का काम देता है हालांकि मकान का वास्तविक मूल्य किराये के रूप में मकान-मालिक को पर्याप्त राशि से कहीं ज्यादा बहुत पहले ही अदा किया जा चुका होता है। इस तरह पता चलता है कि मकान, जो उदाहरण के लिए पचास वर्ष पहले निर्मित किया गया था, किराये से इस अवधि में अपनी मूल लागत से दो, तीन, पांच, दस, यही नहीं इससे अधिक गुना हासिल कर लेता है।”

यहां हमारे समक्ष प्रदोष सुस्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। सबसे पहली चीज, यह भुला दिया जाता है कि किराये से मकान की लागत पर ब्याज की वसूली ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि मरम्मत का खर्च, अशोध्य ऋणों तथा अप्रदत्त

किराये की औसत राशि और साथ ही उस रकम की भी वसूली होनी चाहिए जो समय-समय पर मकान के खाली होने से नहीं मिल सकती; अन्त में उससे मकान पर, जो समय गुजरने के साथ रहने लायक नहीं रह जाता तथा बेकार हो जाता है, लगी पूंजी की भी वार्षिक किश्तों में अदायगी होनी चाहिए। दूसरी चीज, यह भुला दिया जाता है कि किराये को उस जमीन के, जिस पर इमारत बनी है, बड़े हुए मूल्य पर व्याज की भी अदायगी करनी चाहिए और इस कारण इसका एक अंश जमीन का किराया होता है। यह सच है कि हमारे प्रदोषधी तत्काल ऐलान करते हैं कि चूंकि जमीन के मालिक द्वारा कुछ भी योग दिये बिना ही यह मूल्य-वृद्धि होती है, इसलिए उस पर उसका नहीं, वरन् पूरे समाज का अधिकार होता है। परन्तु वह इस तथ्य को नज़रअन्दाज़ कर बैठते हैं कि वे तो इस तरह वस्तुतः भू-स्वामित्व के उन्मूलन की ही मांग कर रहे हैं, परन्तु हम यहां इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम अपने विषय से बहुत दूर हट जायेंगे। अन्ततः वह इस तथ्य को नज़रअन्दाज़ कर बैठते हैं कि पूरा सौदा मकान-मालिक से मकान की खरीद का नहीं है, वरन् उससे कुछ समय के लिए मकान के उपयोग की खरीद का है। कोई आर्थिक घटना-व्यापार किन वास्तविक परिस्थितियों में घटित होता है, इसे देखने का प्रदों ने कभी कष्ट नहीं उठाया, इसलिए वह स्वभावतया यह बताने में भी असमर्थ हैं कि किसी मकान की मूल लागत-क्रीमत की कैसे कतिपय परिस्थितियों में पचास वर्षों के दौरान किराये के रूप में दस गुना अधिक अदायगी हो जाती है। इस प्रश्न का विवेचन करने के बजाय, जो आर्थिक दृष्टि से क़तई कठिन नहीं है, और यह सिद्ध करने के बजाय कि यह क्या सचमुच आर्थिक नियमों के विरुद्ध है और यदि विरुद्ध है भी तो कैसे, प्रदों अर्थशास्त्र से सीधे विधिशास्त्र के क्षेत्र में छलांग लगाते हैं—“मकान एक बार तैयार हो जाने के बाद” निश्चित वार्षिक अदायगी के “स्थायी क़ानूनी हक़ का काम देता है।” यह कैसे होता है, मकान कैसे क़ानूनी हक़ बन जाता है, इस पर प्रदों चुप्पी साध लेते हैं। और यही वह चीज है जो प्रदों को समझानी चाहिए थी। अगर उन्होंने इस प्रश्न की जांच की होती तो उन्हें पता चल जाता कि दुनिया में सारे क़ानूनी हक़—वे चाहे कितने ही स्थायी क्यों न हों—मकान को पचास वर्षों के दौरान किराये के रूप में अपनी दस गुना लागत-क्रीमत वसूलने में समर्थ नहीं बना सकते और यह काम केवल आर्थिक परिस्थितियां ही (जो क़ानूनी हक़ों के रूप में सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं) कर सकती हैं। ऐसा करने पर वह फिर वहीं पहुंच जाते जहां से वह चले थे।

पूरी प्रदोंवादी शिक्षा आर्थिक वास्तविकता से कानूनी शब्दावली में आत्म-रक्षात्मक छलांग लगाने पर आधारित है। हमारे साहसी प्रदों आर्थिक सम्पर्क से जितनी बार भटक जाते हैं—और हर गम्भीर समस्या के मामले में उनके साथ यही होता है—वह कानून का सहारा लेते हैं तथा शाश्वत न्याय की दुहाई देने लगते हैं।

“प्रदों पहले माल उत्पादन से मेल खानेवाले कानूनी सम्बन्धों से शाश्वत न्याय के अपने आदर्श की कल्पना प्राप्त करते हैं, और इस तरह वह सावित कर देते हैं—और इससे सभी कूपमंडूकों को सान्त्वना मिलती है—कि माल उत्पादन का रूप न्याय जैसा ही शाश्वत है। फिर वह उल्टे वास्तविक माल उत्पादन में और उससे मेल खानेवाले वास्तविक कानून में न्याय के इस आदर्श के अनुसार सुधार करना चाहते हैं। उस रसायनज्ञ के बारे में हमारी क्या राय होगी जो पदार्थ के संयोजन और अपघटन में आणुविक परिवर्तनों के वास्तविक नियमों का अध्ययन करने और उसकी बुनियाद पर निश्चित समस्याओं को हल करने के बजाय «naturalité» * और «affinité» ** का ‘शाश्वत विचारों’ की सहायता से पदार्थ के संयोजन और अपघटन का नियमन करने का दावा करता? जब हम यह कहते हैं कि सूदखोरी «justice éternelle» *** «équité éternelle» ****, «mutualité éternelle» ***** और अन्य «vérités éternelles» *) के खिलाफ जाती है, तब क्या हमें उससे सूदखोरी के बारे में सचमुच कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, जो धर्म के पितामहों की इन उक्तियों से प्राप्त होती है कि सूदखोरी «grâce éternelle», «foi éternelle» **) और «la volonté éternelle de Dieu» *** के प्रतिकूल है? ****) (मार्क्स, ‘पूँजी’।)

हमारे प्रदोंपंथी ***** का अपने गुरु से बेहतर हथ्र नहीं होता—

* स्वाभाविकता।—सं०

** बंधुता।—सं०

*** शाश्वत न्याय।—सं०

**** शाश्वत साम्य।—सं०

***** शाश्वत पारस्परिकता।—सं०

*) शाश्वत सत्य।—सं०

***) शाश्वत अनुकम्पा; शाश्वत विश्वास।—सं०

****) भगवान की शाश्वत इच्छा।—सं०

*****) कार्ल मार्क्स, ‘पूँजी’।—सं०

*****) आर्थर म्यूलबर्गर।—सं०

“किराया-करार उन हज़ारों विनियमों में से एक है जो पशु के शरीर में रक्त-संचार की तरह आधुनिक समाज के जीवन में आवश्यक होते हैं। यदि ये विनियम अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत हों, अर्थात् उन्हें सर्वत्र न्याय की कड़ी अपेक्षाओं के अनुसार अमल में लाया जाये तो यह, स्वभावतया, समाज के हित में होगा। कहने का मतलब है, समाज के आर्थिक जीवन को आर्थिक अधिकार की बुलन्दी तक पहुंचा देना चाहिए। परन्तु, जैसा कि हमें पता है, जो रहा है, वह इसके विपरीत है।”

क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि मार्क्स द्वारा प्रदोष्य की ठीक इसी दृष्टिकोण से इतने सार रूप में तथा इतने आश्वस्तकारी ढंग से विवेचित किये जाने के पांच साल बाद भी कोई जर्मन भाषा में ऐसी भ्रान्त सामग्री प्रकाशित करेगा? इस बेसिरपैर की बात का मतलब क्या है? इससे अधिक कुछ नहीं कि मौजूदा समाज को शासित करनेवाले आर्थिक नियमों के व्यावहारिक प्रभाव न्याय के विषय में लेखक की समझदारी के विपरीत हैं, और यह कि वह मन में यह सदाशयपूर्ण कामना संजोये हुए हैं कि इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है जिससे स्थिति ठीक हो सके। जी हां, यदि मेंढकों की पूंछ होती तो वे मेंढक न रह जाते! और फिर उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति क्या “अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत” नहीं है, यानी मजदूरों का शोषण करने के अपने विशेषाधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत नहीं है? और यदि लेखक हमसे यह कहते हैं कि यह अधिकार के बारे में उनकी अपनी अवधारणा नहीं है तो क्या हम एक पग आगे बढ़े हैं?

परन्तु चलिये, आवास प्रश्न की ओर लौटें। हमारे प्रदोष्यी अब “अधिकार की” अपनी “अवधारणा” को बेलगाम छोड़ देते हैं और हमारे सामने निम्नलिखित हृदयस्पर्शी ओजस्वी व्याख्यान देते हैं—

“हम यह दावा करने में संकोच नहीं करते कि हमारी स्तुत्य शताब्दी की पूरी संस्कृति पर इस तथ्य से बड़ा और कोई क्रूर व्यंग्य नहीं हो सकता कि बड़े शहरों में ६० प्रतिशत तथा इससे अधिक आबादी के पास ऐसा आवास नहीं है जिसे वह अपना कह सके। नैतिक तथा पारिवारिक अस्तित्व, घरबार का मूल बिन्दु सामाजिक भंवर में डूबता जा रहा है... इस मामले में हम वहशियों के बहुत नीचे हैं। कन्दरावासी के पास अपनी कन्दरा, आस्ट्रेलियाई के पास अपनी मिट्टी की झोंपड़ी, रेड इंडियन के पास अपना चौका-चूल्हा होता था, लेकिन आधुनिक सर्वहारा त्रिशंकु बना हुआ है”, आदि।

इस विलाप में प्रदोषपंथ अपने पूरे प्रतिक्रियावादी रूप में मौजूद है। आधुनिक क्रान्तिकारी वर्ग—सर्वहारा वर्ग—के निर्माण के लिए उस नाभि-रज्जु को काटना नितान्त आवश्यक था जिससे पुराने जमाने का मजदूर जमीन से जुड़ा हुआ था। हाथ से काम करनेवाला बुनकर, जिसके पास करघे के अलावा अपना छोटा-सा घर, बारा और खेत होता था, अपने सारे दुख-कष्टों तथा सारे राजनीतिक दबाव के बावजूद शान्त, सन्तुष्ट, “धर्मपरायण तथा प्रतिष्ठाप्राप्त” व्यक्ति था। वह अमीर, पादरी तथा पदाधिकारियों के आगे सिर झुकाया करता था और आन्तरिक रूप से पूरी तरह दास था। यह ठीक आधुनिक, बड़े पैमाने का उद्योग ही है जिसने श्रमिक को, जो पहले से जमीन से बंधा हुआ था, पूर्णतया सम्पत्ति-च्युत सर्वहारा बना दिया, उसे तमाम परम्परागत बेड़ियों से मुक्त कर दिया, एक «Vogelfrei»* सर्वहारा बना दिया; यह ठीक आर्थिक क्रान्ति ही है जिसने एकमात्र ऐसी अवस्थाओं का सृजन किया है जिनके अन्तर्गत पूँजीवादी उत्पादन के रूप में मेहनतकश वर्ग का शोषण अपने अन्तिम रूप समेत मिटाया जा सकता है। और तब विलाप करते हुए यह प्रदोषपंथी सामने आते हैं और मजदूरों को घर-बार से बाहर निकाले जाने पर इस तरह सिसकियां भरते हैं मानों यह उनकी बौद्धिक मुक्ति की ठीक पहली शर्त नहीं, बल्कि प्रतिगामी पग है।

२७ वर्ष पहले मैंने ‘इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति’ पुस्तक में इंग्लैंड में १८वीं शताब्दी में मजदूरों के अपने घर-बार से खदेड़े जाने की ठीक इस प्रक्रिया का वर्णन किया था। घृणित कृत्यों का, जिनके लिए जमीन तथा कारखानों के मालिक अपराधी थे, इस निष्कासन का सर्वोपरि सम्बन्धित मजदूरों पर अनिवार्यतः पड़नेवाले भौतिक तथा नैतिक दोनों प्रकार के हानिकर प्रभावों का भी उसमें यथोचित वर्णन किया गया है। परन्तु क्या मेरे दिमाग में इसे, जो परिस्थितियों को देखते हुए विकास की सर्वथा आवश्यक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, कोई ऐसी चीज मानने की बात पैदा हो सकती थी जो “वहशियों के नीचे” भी पहुँचानेवाला प्रतिगामी पग हो? असम्भव। १८७२ का अंग्रेज सर्वहारा अपने घर-बार वाले १७७२ के देहाती बुनकर से अपरिमित रूप से ऊँचे स्तर पर है। अपनी कन्दरा वाला कन्दरावासी, अपनी मिट्टी की झोपड़ी वाला आस्ट्रेलियाई या अपने चौंके-चूल्हे वाला रेड इंडियन क्या कभी जून विप्लव^१ सम्पन्न कर पाता अथवा पेरिस कम्यून को साकार बना पाता?

* दो अर्थों वाला शब्द—“पक्षी की तरह मुक्त”, “विधि-बहिष्कृत”।—सं०

बड़े पैमाने पर पूँजीवादी उत्पादन के प्रचलन के बाद मजदूरों की स्थिति भौतिक रूप से और बिगड़ी है, इस पर केवल पूँजीपति वर्ग संदेह करता है। परन्तु क्या हमें इसलिए पीछे मुड़कर मिस्र देश में मांस की हांडियों^{६२}, (वह भी इनेगिने), छोटे पैमाने के देहाती उद्योग की ओर, जो केवल दासवत् आत्माएं पैदा करता था, अथवा “वहशियों” की ओर ललचायी दृष्टि से देखना चाहिए? बात इसके विपरीत है। बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग द्वारा सर्जित, जमीन से बांधनेवाली बेड़ियों समेत विरासत में मिली सारी बेड़ियों से मुक्त और बड़े शहरों में झुंड के झुंड भरता जा रहा सर्वहारा ही महान सामाजिक रूपान्तरण का कार्य सम्पन्न कर सकता है जो समस्त वर्ग शोषण तथा समस्त वर्ग शासन का अन्त कर देगा। घर-बार वाले पुराने ग्रामीण वुनकर यह कभी न कर पाते; वे इस तरह के विचार को अमल में लाने की इच्छा करना तो रहा दूर, उसे विमर्श में भी नहीं ला सकते थे।

दूसरी ओर, प्रदों के लिए गत सौ वर्षों की औद्योगिक क्रान्ति, भाप शक्ति का प्रचलन तथा बड़े पैमाने का कारखाना उत्पादन, जो शारीरिक श्रम की जगह पर मशीनों की प्रतिस्थापना करता है और श्रम उत्पादकता को हजार गुना बढ़ाता है, अत्यन्त घृणित घटनाएं हैं, जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थीं। निम्न-पूँजीवादी प्रदों ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति तत्काल उपभोगयोग्य तथा मंडी में विनिमययोग्य स्वतंत्र तथा पृथक वस्तु उत्पादित करता है। फिर जब तक प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी वस्तु के रूप में अपने श्रम का पूर्ण मूल्य वापस मिलता रहता है, तब तक “शाश्वत न्याय” की पूर्ति होती रहती है तथा यथासम्भव सर्वोत्तम संसार का सृजन हो जाता है। परन्तु प्रदों के इस यथासम्भव सर्वोत्तम संसार को औद्योगिक विकास की अग्रगति ने भ्रूणावस्था में ही कुचल डाला है, उसे पांवों तले रौंद डाला है; यह औद्योगिक विकास उद्योग की तमाम बड़ी शाखाओं में व्यक्तिगत श्रम को पहले ही नष्ट कर चुका है और जो छोटी तथा उनसे और भी छोटी शाखाओं में उसे नित्यप्रति नष्ट करता जा रहा है, जो उसके स्थान पर मशीनों तथा प्रकृति की वश में की गयी शक्तियों का अवलम्बन प्राप्त उस सामाजिक श्रम को प्रतिष्ठित कर रहा है जिसका तत्काल विनिमययोग्य अथवा उपभोगयोग्य उत्पाद कई लोगों के, जिनके हाथों से वह गुजरता है, संयुक्त कार्य का फल है। ठीक यही औद्योगिक क्रान्ति है जिसने मानव श्रम की उत्पादक शक्ति को इतने ऊँचे स्तर पर पहुंचा दिया है कि मानवजाति के इतिहास में पहली बार—सबके मध्य श्रम का युक्तिसंगत विभाजन होने पर—

इतना उत्पादित करने की सम्भावना विद्यमान है जो समाज के तमाम सदस्यों के प्रचुर उपभोग के लिए तथा प्रचुर आरक्षित कोष के लिए ही नहीं, अपितु हर एक के वास्ते इतनी फुरसत सुझा कराने के लिए भी पर्याप्त होगा कि ऐतिहासिक रूप से धरोहर के रूप में प्राप्त संस्कृति में जो कुछ भी—विज्ञान, कला, संसर्ग के रूप—वास्तव में अक्षुण्ण रखने योग्य है, उसे अक्षुण्ण ही नहीं रखा जायेगा, अपितु उसे सत्ताधारी वर्ग की इजारेदारी से पूरे समाज की समान सम्पत्ति में बदला जा सकेगा और उसका आगे विकास भी किया जा सकेगा। यही निर्णायक बिन्दु है—मानव श्रम की उत्पादक शक्ति ज्योंही इस बुलन्दी पर पहुँचती है, सत्ताधारी वर्ग के अस्तित्व के पक्षसमर्थन का हर किस्म का बहाना खत्म हो जाता है। आखिर जिस अन्तिम आधार पर वर्ग विभेदों का पक्षसमर्थन किया जाता था, वह सदैव यही होता था—हमेशा एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जिसे रोज रोजी-रोटी कमाने की चिन्ता न करनी पड़े ताकि उसके पास समाज के बौद्धिक कार्यों की देखरेख के लिए समय रह सके। इस तरह की बकवास को, जिसे अब तक बहुत अधिक ऐतिहासिक औचित्य प्राप्त था, पिछले सौ वर्षों की औद्योगिक क्रान्ति ने जड़ से ही खत्म कर दिया है। सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व औद्योगिक उत्पादक शक्ति के विकास की राह में तथा उतना ही विज्ञान, कला और खास तौर पर सांस्कृतिक संसर्ग के अन्य रूपों के विकास की राह में नित्यप्रति अधिकाधिक बाधक बनता जा रहा है। इससे पहले ऐसे उजड़ु कभी नहीं थे जितने हमारे ये आधुनिक पूंजीपति हैं।

परन्तु मित प्रूदों से इस सब का कोई वास्ता नहीं है। वह तो “शाश्वत न्याय” चाहते हैं, और कुछ नहीं। हरेक को अपने उत्पाद के बदले अपने श्रम की पूरी आय, अपने श्रम का पूर्ण मूल्य प्राप्त करना है। परन्तु इसका आधुनिक उद्योग के उत्पाद में हिसाब लगाना पेचीदा मामला है। आधुनिक उद्योग कुल उत्पाद में व्यक्ति के विशेष भाग को ढंक देता है जो पुरानी व्यक्तिगत दस्तकारी में स्पष्टतया तैयार उत्पाद के रूप में प्रकट होता था। इसके अलावा आधुनिक उद्योग वैयक्तिक विनिमय को, जिस पर प्रूदों की पूरी प्रणाली निर्मित है, अर्थात् दो व्यक्तियों के बीच उस प्रत्यक्ष विनिमय को अधिकाधिक मिटाता जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के उत्पाद का उपभोगार्थ विनिमय करता है। इसी लिए पूरे के पूरे प्रूदोंपंथ में एक प्रतिक्रियावादी पुट विद्यमान है, वह है औद्योगिक क्रान्ति से घृणा और पूरे आधुनिक उद्योग को, भाप इंजनों, यांत्रिक करघों और दूसरी मुसीबतों को खत्म करने तथा पुराने, सम्मानजनक शारीरिक श्रम की ओर

लौटने की कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त इच्छा। इस तरह यदि हम अपनी उत्पादक शक्ति का एक हजार में से ९९९ अंश खो बैठें, यदि पूरी मानवजाति को निकृष्टतम दासवत् श्रम के गर्त में धकेल दिया जाये, यदि भुखमरी आम नियम बन जाये, तो भी इन सब से क्या बनता-बिगड़ता है यदि हम विनिमय को इस ढंग से संगठित कर दें कि हर एक को “अपने श्रम की पूरी आय” मिल जाये और “शाश्वत न्याय” को मूर्त रूप दे दिया जाये?

Fiat justitia, pereat mundus!

इन्साफ़ होना चाहिए, दुनिया जहन्नुम में जाये!

और यदि इस प्रदोषी प्रतिक्रान्ति को सम्पन्न करना ज़रा भी सम्भव हो तो दुनिया निश्चय ही जहन्नुम में पहुंच जायेगी।

परन्तु यह स्वयंसिद्ध है कि बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग वाले सामाजिक उत्पादन में भी हर व्यक्ति के लिए “अपने श्रम की पूरी आय की प्राप्ति”—यदि इस वाक्यांश का कोई अर्थ है—सुनिश्चित करना सम्भव है। और इस वाक्यांश का तभी अर्थ हो सकता है जब उसकी परिधि में यह भाव नहीं हो कि हर व्यक्ति “अपने श्रम की पूरी आय” का स्वामी बने, अपितु यह भाव शामिल हो कि पूरी तरह मजदूरों को लेकर बननेवाला सारा समाज अपने श्रम के कुल उत्पाद का स्वामी बनेगा जिसका एक भाग वह अपने सदस्यों के बीच उपभोग के लिए बांटेगा, एक भाग उत्पादन साधनों के प्रतिस्थापन और उनकी वृद्धि के लिए इस्तेमाल करेगा तथा एक भाग उत्पादन एवं उपभोग की आरक्षित निधि तैयार करने के लिए जमा करेगा।

* * *

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके बल पर हम पहले ही जान लेते हैं कि हमारे प्रदोषी इस महान आवास प्रश्न को किस तरह हल करेंगे। एक ओर हमारे सामने यह मांग है कि प्रत्येक मजदूर का अपना मकान हो ताकि हम आगे से “वहशियों के नीचे” न रहें। दूसरी ओर हमें वह यकीन दिलाते हैं कि किसी मकान की मूल लागत की किराये के रूप में दो, तीन पांच या दस गुनी वापसी—जैसा कि वस्तुतः होता है—क़ानूनी हक़ पर आधारित है और यह क़ानूनी हक़ “शाश्वत न्याय” के विरुद्ध है। इसका समाधान बिल्कुल सरल है—हम क़ानूनी हक़ मिटा देते हैं तथा शाश्वत न्याय के बल पर घोषित करते हैं कि चुकाया जानेवाला किराया स्वयं आवास की लागत की अदायगी है। यदि कोई अपनी

पूर्वस्थापनाओं को इस तरतीब से रखे कि उनमें निष्कर्ष पहले से मौजूद हो तो अपने झोले से पहले से तैयार किये हुए फल को प्रस्तुत करने और उसके परिणाम-गत अडिग तर्क की ओर गर्वपूर्वक इंगित करने के लिए निस्सन्देह उससे ज्यादा दक्षता की जरूरत नहीं होगी जो किसी भी कठ-वैद्य के पास होती है।

यहां भी यही होता है। मकानों को किराये पर उठाने की व्यवस्था का अन्त करना परम आवश्यक बना दिया जाता है तथा उसे इस मांग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि हर किरायेदार को अपने आवास का मालिक बना दिया जाये। परन्तु यह कैसे किया जाये? बहुत आसानी से—

“किराये पर उठाये जानेवाले मकानों का विमोचन हो जायेगा... पहले के मकान-मालिक को उसके मकान की एक-एक दमड़ी चुका दी जायेगी। किराया जहां पहले की तरह पूंजी के स्थायी हक के लिए किरायेदार द्वारा किया जानेवाला भुगतान बना रह जायेगा, वहां किराये पर उठाये जानेवाले मकानों के विमोचन की घोषणा के दिन से यह ठीक-ठीक निश्चित राशि, जो किरायादार चुकाता है, उस मकान की वार्षिक किश्त बन जायेगी जो उसकी अपनी सम्पत्ति बन जाता है... समाज... इस तरह मकानों के स्वतंत्र, आज़ाद स्वामियों का कुल योग बन जाता है।”

मकान-मालिक बिना काम किये ज़मीन का किराया ले सके और मकान में लगायी गयी पूंजी से ब्याज वसूल कर सके, इसे प्रदोषंथी* शाश्वत सत्य के विरुद्ध अपराध मानता है। वह फ़र्मान जारी करता है कि यह ख़त्म होना चाहिए, कि मकानों में लगायी गयी पूंजी से आगे ब्याज नहीं मिला करेगा, कि ज़मीन के किराये की भी—जहां तक वह ख़रीदी गयी भू-सम्पत्ति है—वसूली नहीं की जायेगी। अब हमने देख लिया है कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति, जो वर्तमान समाज का आधार है, इससे कदापि प्रभावित नहीं होती। मज़दूर के शोषण की धुरी है पूंजीपति के हाथों उसकी श्रम शक्ति की बिक्री तथा इस लेन-देन का पूंजीपति द्वारा किया जानेवाला उपयोग, यह तथ्य कि पूंजीपति मज़दूर को अपनी श्रम शक्ति के मूल्य से कहीं अधिक उत्पादित करने के लिए बाधित करता है। पूंजी-पति तथा मज़दूर के बीच यही लेन-देन वह सारा अतिरिक्त मूल्य उत्पादित करता है जो आगे चलकर नाना प्रकार के पूंजीपतियों तथा उनके चाकरों के बीच ज़मीन

* म्यूलबर्गर।—सं०

के किराये, वाणिज्यिक मुनाफ़े, पूंजी पर व्याज, कर, आदि के रूप में बंटता है। तब हमारे प्रदोष्यी सामने आते हैं और यह मानते हैं कि यदि हम एक ही किस्म के पूंजीपतियों को, जो सीधे श्रम शक्ति नहीं खरीदते तथा इस तरह जिनके कारण कोई अतिरिक्त मूल्य पैदा नहीं होता है, मुनाफ़ा कमाने अथवा व्याज कमाने से रोक दें तो यह कार्य आगे की ओर क्रदम होगा! मज़दूर वर्ग से प्राप्त किया जानेवाला विपुल अवेतन श्रम ठीक उतना ही बना रहेगा भले ही मकान-मालिक को कल ज़मीन का किराया और व्याज लेने की सम्भावना से वंचित कर दिया जाये। परन्तु यह चीज हमारे प्रदोष्यी को यह धोषणा करने से नहीं रोकती—

“किराये पर मकान उठाने की व्यवस्था का उन्मूलन इसलिए उन सबसे फलप्रद तथा भव्य आकांक्षाओं में से एक है जो क्रान्तिकारी विचार के गर्भ से जन्मी हैं और इसे सामाजिक जनवाद की एक प्रमुख मांग बन जानी चाहिए।”

यह उनके गुरु प्रदों की बाज़ारू चीख-पुकार की हू-व-हू नक़ल है जो उस सुर्गी की तरह है जिसकी कुड़कुड़ाहट अंडे के आकार के सर्वथा उलट होती है।

अब ज़रा उस मनोहारी स्थिति की कल्पना तो कीजिये जब प्रत्येक मज़दूर, निम्नपूँजीपति तथा पूँजीपति को वार्षिक किश्त देकर अपने घर का पहले आंशिक और फिर पूरा मालिक बनने के लिए विवश किया जाता है! इंग्लैंड के औद्योगिक जिलों में इसमें कुछ तुक हो सकता है जहां बड़े पैमाने का उद्योग है परन्तु मज़दूरों के अपने छोटे-छोटे घर हैं और जहां हर विवाहित मज़दूर के पास अपना छोटा-सा घर है। परन्तु पेरिस में तथा महाद्वीप के अधिकांश बड़े नगरों में छोटे पैमाने के उद्योग के साथ-साथ बड़े-बड़े घर हैं, जिनमें से प्रत्येक में दस, बीस या तीस परिवार साथ-साथ रहते हैं। मान लें कि विश्व-मुक्तिदायी आज़ाप्ति के जारी होने के दिन, जब किराये के मकानों के छुड़ाये जाने की घोषणा होगी, पीटर नामक व्यक्ति, जो बर्लिन के एक इंजीनियरी कारख़ाने में काम कर रहा है, एक साल बाद, हैम्बर्ग टोर के आस-पड़ौस में किसी मकान की पांचवीं मंज़िल पर एक छोटे-से कमरे के पन्द्रहवें भाग का मालिक बन जाता है। इतने में वह नौकरी खो बैठता है और शीघ्र हनोवर में पोटगोफ़ नामक स्थान में तीसरी मंज़िल में उसी तरह के फ़्लैट में पहुंच जाता है जहां से आंगन का बहुत सुन्दर दृश्य दिखायी देता है। वहां पांच माह रहने के बाद उसने इस सम्पत्ति का १/३६ भाग हासिल किया ही था कि हड़ताल हो जाती है और इस कारण वह म्यूनिख़ पहुंच जाता

है और ग्यारह माह तक वह ओबेर-आंगेरगास्ते में किसी मकान के अंधेरे-से तहखाने में ठीक ११/१८० हिस्से का मालिक बन जाता है। इसी तरह आगे हटाये जाते रहने से, जो आजकल मजदूरों के साथ अक्सर हो रहा है, उसके मत्थे ये और मड़ दिये जायेंगे—सेंट गालेन में ऐसे घर का ७/३६० हिस्सा, जो पहले से कम वांछनीय नहीं होगा, लीड्स में एक अन्य घर का २३/१८० हिस्सा तथा सेरेन में एक तीसरे घर का ३४७/५६२२३ हिस्सा—ठीक इस तरह आकलित कि “शाश्वत न्याय” का अतिक्रमण न हो। अब बताइये कि हमारे पीटर महाशय फ्लैटों के इन हिस्सों का क्या उपयोग करें? उसे इन हिस्सों का वास्तविक मूल्य कौन देगा? उसे अपने विभिन्न फ्लैटों में बाकी हिस्सों के मालिक या मालिक लोग कहाँ मिलेंगे? और किसी ऐसे बड़े मकान के मामले में सम्पत्ति सम्बन्ध क्या होंगे जिसकी मंजिलों में, मान लें, कुल मिलाकर २० फ्लैट हैं, और जिसके अलग-अलग हिस्सों के मालिक विमोचन की अवधि खत्म होने तथा मकानों को भाड़े पर उठाने की व्यवस्था के खत्म होने की दशा में शायद तीन सौ होंगे जो दुनिया भर में बिखरे हुए होंगे? हमारे प्रदोषवादी जवाब में कहेंगे कि उस समय तक प्रदोषों का विनिमय-बैंक अस्तित्व में आ जायेगा जो हरेक को किसी भी श्रम उत्पाद के लिए पूरी-पूरी श्रम आय किसी भी समय चुका दिया करेगा और इसलिए वह किसी फ्लैट में हिस्से का भी पूरा मूल्य चुका देगा। परन्तु हमारा यहां प्रदोषपंथी विनिमय-बैंक से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि पहले तो इसलिए कि आवास प्रश्न से सम्बन्धित लेखों में इसकी कहीं चर्चा नहीं है; दूसरी चीज यह है कि वह इस विचित्र भूल पर आधारित है कि यदि कोई माल बेचना चाहता है तो उसे अवश्य उसे पूरी कीमत पर खरीदनेवाला ग्राहक मिल जायेगा, और तीसरी चीज यह है कि प्रदोषों के आविष्कार से बहुत पहले ही श्रम विनिमय बाजार^{६३} के नाम से इसका एकाधिक बार दिवाला पिट चुका था।

मजदूर को अपना घर खरीदना चाहिए, यह पूरी अवधारणा, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं, मूलतया प्रतिक्रियावादी प्रदोषपंथी सिद्धान्त पर आधारित है जिसके अनुसार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग द्वारा पैदा की गयी अवस्थाएं एक घिनौनी रसौली हैं और समाज को बलपूर्वक उस प्रवृत्ति की ओर से, जिसका वह एक सौ वर्ष से अनुसरण करता आया है, मोड़कर ऐसी अवस्था की ओर लौटाना चाहिए जिसमें अलग-अलग व्यक्तियों के पुराने टिकाऊ दस्तकारी का बोलवाला होगा और जो साधारणतया छोटे पैमाने के उद्योग के, जो विध्वस्त हो चुका और होता जा रहा है, आदर्शोक्त पुनरुद्धार के अलावा और कुछ नहीं है। यदि

मजदूरों को एक बार फिर इन टिकाऊ परिस्थितियों की ओर पहुंचा दिया जाये और "सामाजिक भंडार" को यदि उपयुक्त ढंग से खत्म कर दिया जाये तो मजदूर निस्सन्देह "घर-बार" के स्वामित्व का उपयोग कर सकते हैं और उपरिलिखित विमोचन सिद्धान्त कम बेतुकी प्रतीत होने लगती है। परन्तु प्रूदों सिर्फ यह भूल जाते हैं कि यह सब सम्पन्न करने के लिए उन्हें विश्व इतिहास की घड़ी की सुइयों को सौ साल पीछे घुमाना होगा और ऐसी सूरत में वह समकालीन मजदूरों को अपने पितामहों और प्रपितामहों की तरह फिर संकीर्ण मनोवृत्ति वाली, धिधियानेवाली, चापलूसी करनेवाली दासवत् आत्माएं बना देंगे।

वैसे जहां तक आवास प्रश्न के प्रूदोंपंथी समाधान में कोई युक्तिसंगत तथा व्यवहार योग्य तत्व है, उसे पहले से ही मूर्त रूप दिया जा रहा है परन्तु यह "क्रान्तिकारी विचार के गर्भ" से उद्भूत नहीं होता, बल्कि... स्वयं बड़े पूंजीपतियों के बीच जन्म लेता है। आइये, जरा देखें मैड्रिड से निकलनेवाला बेहतरीन स्पेनी अखबार «*La Emancipacion*»⁶⁴ अपने १६ मार्च १८७२ के अंक में क्या कहता है—

"आवास प्रश्न को हल करने का एक और तरीका है, प्रूदों द्वारा सुझाया गया तरीका; पहली नज़र में वह चकाचौंध जरूर कर देता है, परन्तु अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वह अपनी पूर्ण पुंसत्वहीनता प्रकट कर देता है। प्रूदों ने सुझाव दिया कि किरायेदारों को किशतों में योजना के आधार पर खरीददार बना देना चाहिए, कि अदा किये जानेवाले वार्षिक किराये को आवास विशेष के मूल्य की किशतों में वापसी माना जाना चाहिए ताकि एक निश्चित समय के बाद किरायादार उसका मालिक बन सके। इस तरीके को तो, जिसे प्रूदों बहुत क्रान्तिकारी मानते थे, सट्टेबाजों की कम्पनियां तमाम देशों में अमल में ला रही हैं, जो किराया बढ़ाकर इस तरह मकानों का दुगुना और तिगुना मूल्य वसूल कर रही हैं। उत्तर-पूर्वी फ्रांस में श्री दोल्फुस तथा अन्य बड़े कारखानेदारों ने धन कमाने के लिए ही नहीं, वरन् एक राजनीतिक विचार को लेकर भी यह प्रणाली क्रियान्वित की है।

"सत्ताधारी वर्ग के सबसे चतुर नेताओं की कोशिशों का हमेशा यह लक्ष्य रहा है कि छोटे-छोटे सम्पत्ति स्वामियों की संख्या बढ़ती रहे ताकि सर्वहारा के विरुद्ध अपने लिए एक सेना तैयार की जा सके। गत शताब्दी की पूंजीवादी क्रान्तियों ने सामन्तों तथा चर्च की बड़ी-बड़ी जागीरों को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटा—ठीक उसी तरह जिस तरह स्पेनी जनतंत्रवादी अपने यहां अब भी मौजूद बड़ी जागीरों को बांटना चाहते हैं—और इस तरह उन्होंने छोटे भूस्वामियों का एक वर्ग पैदा कर दिया जो तब से समाज में सबसे प्रतिक्रियावादी तत्व तथा

शहरी सर्वहारा के क्रान्तिकारी आन्दोलन की राह में स्थायी बाधक बना हुआ है। नेपोलियन तृतीय का इरादा सरकारी ऋण के छोटी-छोटी राशियों के बांड जारी कर शहरों में ठीक ऐसा ही वर्ग तैयार करने का था, और श्री दोल्फुस तथा उनके सहयोगियों ने अपने मजदूरों को छोटे-छोटे घर वार्षिक किश्तों पर बेचकर उनकी सारी क्रान्तिकारी भावना का गला घोटने और साथ ही इस सम्पत्ति द्वारा मजदूरों को कारखाने से बांधने का प्रयास किया था। इस तरह प्रदों की योजना ने मजदूर वर्ग को राहत पहुंचाना तो रहा बहुत दूर, वह सीधे उनके ही विरुद्ध सिद्ध हुई।”*

तो फिर आवास प्रश्न किस तरह हल किया जाये? वर्तमान समाज में उसे किसी भी अन्य सामाजिक प्रश्न की तरह हल किया जाता है—मांग तथा पूर्ति के धीरे-धीरे आर्थिक समतलन के द्वारा, एक ऐसे हल द्वारा जो प्रश्न को फिर बार-बार पैदा करता है और इसलिए जो कोई हल है ही नहीं। इस प्रश्न को सामाजिक क्रान्ति कैसे हल करेगी, यह चीज हर मामले की परिस्थितियों पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु कहीं अधिक व्यापक प्रश्नों से भी जुड़ी हुई है जिनमें से एक प्रश्न शहर तथा देहात के बीच विरोध का उन्मूलन है। चूंकि भावी समाज के संगठन के लिए कोई काल्पनिक प्रणालियां रचना हमारा काम नहीं है, इसलिए यहां इस प्रश्न का विवेचन करना सर्वथा निरर्थक होगा। परन्तु एक चीज निश्चित

* मजदूर को अपने “घर” से बांधे रखकर आवास प्रश्न का यह समाधान बड़े या तेजी से उभरते जा रहे अमरीकी नगरों के आस-पड़ौस में किस तरह स्वतःस्फूर्त ढंग से जन्म ले रहा है, इसका पता २८ नवम्बर १८८६ को इंडियानापोलिस से एलिअोनोर मार्क्स-एवेलिंग की एक चिट्ठी के निम्नलिखित अंश से चल जाता है, “कन्ज़ास सिटी में, या कहिए कि उसके पास हमने अब भी वीरान पड़े इलाकों के बीच लकड़ी की बनी कुछ दयनीय, कोई तीन कमरों वाली झोंपड़ियां देखीं; ज़मीन की लागत ६०० डालर थी, वह बस इतनी बड़ी थी कि उस पर एक छोटा-सा घर खड़ा किया जा सकता है; उस दलदली वीरान भूमि पर खड़ी छोटी-सी झोंपड़ी पर, जहां शहर से आने-जाने में एक घंटे का समय लगता है, और ६०० डालर, यानी सब मिलाकर ४,८०० मार्क की लागत आयी।” इस तरह मजदूरों को घर हासिल करने के लिए भारी बंधक-ऋण वहन करना पड़ता है और वे वस्तुतः अपने मालिकों के गुलाम बन जाते हैं। वे अपने घरों से बंध जाते हैं, वे वहां से जा नहीं सकते, काम-काज की जो भी शर्तें उनके सामने रखी जायें, उन्हें उनसे सहमत होना पड़ता है। (१८८७ के संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी)

है—बड़े शहरों में यह सारी “मकानों की कमी” दूर करने के लिए मकान पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं वशर्ते उनका विवेकपूर्वक उपयोग किया जाये। यह स्वभावतः तभी हो सकता है जब मौजूदा मकान-मालिकों के मकानों को हस्तगत करके मौजूदा गृहहीन मजदूरों अथवा भीड़भरे घरों में रहनेवाले मजदूरों को उनमें बसा दिया जाये। सर्वहारा ज्योंही राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेगा, तब सामाजिक कल्याण के हितों से प्रेरित इस तरह का पग उठाना उतना ही सुगम होगा जितना आधुनिक राज्य द्वारा अन्य प्रकार के सम्पत्तिहरण तथा रिहायशी घरों को अपने अधिकार में किया जाना।

* * *

परन्तु हमारे प्रूदोंपंथी * आवास प्रश्न के मामले में अपनी पिछली उपलब्धियों से सन्तुष्ट नहीं हैं। उन्हें तो प्रश्न को ज़मीन से ऊपर उठाकर उच्च समाजवाद के क्षेत्र तक पहुँचाना है ताकि वह वहाँ भी अपने को “सामाजिक प्रश्न का” मूलभूत “भाग” सिद्ध कर सके—

“आइये, अब हम यह मान लें कि पूंजी की उत्पादकता की समस्या से, मिसाल के तौर पर, एक ऐसे संक्रमणकालीन क़ानून से सीधे-सीधे निपटा जाता है—और यह देर-सबेर करना ही होगा—जो सारी पूँजियों पर एक प्रतिशत ब्याज नियत करता है, परन्तु ध्यान रहे, उसमें ब्याज की इस दर को भी अधिकाधिक शून्य के बराबर तक पहुँचाने की प्रवृत्ति होगी ताकि अन्ततः पूँजी के आवर्त के लिए आवश्यक भ्रम से अधिक का भुगतान न करना पड़े। तमाम अन्य उत्पादों की ही तरह मकान तथा घर भी स्वभावतया इस क़ानून के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं... मालिक स्वयं अपने मकान की बिक्री के लिए तैयार हो जायेगा, अन्यथा उसका मकान खाली पड़ा रहेगा और उस पर लगी पूँजी बस बेकार पड़ी रहेगी।”

इस उद्धरण में प्रूदोंपंथी प्रश्नोत्तरी का एक मुख्य सूत्र निहित है और वह उसके अन्दर मौजूद भ्रम का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

“पूँजी की उत्पादकता” ऐसी बेतुकी चीज़ है जिसे प्रूदों पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों से आखें बन्द कर ग्रहण कर लेते हैं। यह सच है कि पूँजीवादी अर्थशास्त्री भी इस

कथन से शुरूआत करते हैं कि श्रम सारी सम्पदा का स्रोत तथा समस्त मालों के मूल्य का पैमाना है। परन्तु उन्हें यह भी समझाना होगा कि यह कैसे होता है कि पूंजीपति किसी औद्योगिक या दस्तकारी के व्यवसाय के लिए जो पूंजी देता है, उसके फल के रूप में उसे आखिर में मूल पूंजी ही नहीं, वरन् उसके अलावा मुनाफ़ा भी मिल जाता है। इसी कारण उन्हें सब तरह के विरोधों में उलझना पड़ता है तथा पूंजी में कुछ उत्पादकता भी बतानी पड़ती है। प्रदों पूंजीवादी विचारधारा के जाल में कैसे पूरी तरह उलझे हुए हैं, इसे स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने के लिए इससे बड़ा और कोई तथ्य नहीं है कि प्रदों ने पूंजी की उत्पादकता का यह वाक्यांश उससे ग्रहण किया है। हमने शुरू से ही देखा है कि तथाकथित “पूंजी की उत्पादकता” (वर्तमान सामाजिक सम्बन्धों के अन्तर्गत जिनके बिना वह पूंजी ही न रहेगी) उजरती मजदूरों के अवेतन श्रम को हड़पने में सक्षम होने के गुण के अलावा और कुछ नहीं है।

परन्तु प्रदों पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों से इस बात में भिन्न हैं कि वह इस “पूंजी की उत्पादकता” को पसन्द नहीं करते, बल्कि उलटे इसमें “शाश्वत न्याय” का उल्लंघन पाते हैं। यही उत्पादकता मजदूर को अपने श्रम की पूरी आय की प्राप्ति नहीं होने देती। इसलिए उसे मिटाया जाना चाहिए। परन्तु कैसे? अनिवार्य क़ानून बनाकर ब्याज की दर घटाकर तथा अन्ततः उसे शून्य पर पहुंचाकर। तब हमारे प्रदोंपंथी के अनुसार पूंजी उत्पादक नहीं रह जायेगी।

मुद्रा ऋण पूंजी का ब्याज मुनाफ़े का एक भाग मात्र है; मुनाफ़ा चाहे औद्योगिक पूंजी पर हो या वाणिज्यिक पूंजी पर, वह पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग से अवेतन श्रम के रूप में हस्तगत अतिरिक्त मूल्य का एक भाग मात्र है। ब्याज की दर का नियमन करनेवाले आर्थिक क़ानून अतिरिक्त मूल्य की दर का नियमन करनेवाले क़ानूनों से उतने ही स्वतंत्र हैं जितना एक ही रूप के समाज के क़ानूनों के मामले में सम्भव हो सकता है। परन्तु जहां तक व्यक्तिगत तौर पर पूंजीपतियों के बीच इस अतिरिक्त मूल्य के वितरण का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि उद्योगपतियों तथा तिजारतियों के लिए, जिनके कारोबार में दूसरे पूंजीपतियों की पूंजी बहुत बड़ी मात्रा में लगी हुई होती है, मुनाफ़े की दर—तमाम अन्य परिस्थितियों के समान होने की दशा में—उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए जिस हिसाब से ब्याज की दर घटती है। इसलिए ब्याज में कमी और उसके उन्मूलन से तथाकथित “पूंजी की उत्पादकता” की समस्या से वस्तुतः कभी “सीधे-सीधे नहीं निपटा जा सकता”। वे मजदूर वर्ग से हस्तगत किये जानेवाले

अदत्त अतिरिक्त मूल्य का व्यक्तिगत तौर पर पूंजीपतियों के बीच पुनर्वितरण की व्यवस्था करने से अधिक कुछ नहीं कर पायेंगे। वे औद्योगिक पूंजीपति के मुक्ताबले मजदूर को नहीं, वरन् किरायाजीवी के मुक्ताबले औद्योगिक पूंजीपति को लाभ पहुंचावेंगे।

प्रदों अपने कानूनी दृष्टिकोण से सारे आर्थिक तथ्यों की ही तरह व्याज की दर को भी सामाजिक उत्पादन की अवस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि राजकीय कानूनों द्वारा, जिनमें ये अवस्थाएं आम अभिव्यक्ति पाती हैं, समझाते हैं। इस दृष्टिकोण से, जिसमें राजकीय कानूनों तथा समाज में उत्पादन की अवस्थाओं के बीच अन्तस्सम्बन्ध की कोई गुंजायश तक नहीं है, ये राजकीय कानून अनिवार्यतः विशुद्ध रूप से मनमाने आदेश प्रतीत होते हैं जिनकी जगह किसी भी समय उनके ठीक विपरीत आदेश ले सकते हैं। इसलिए प्रदों के लिए ऐसी आज्ञाप्ति जारी करने है—यदि उन्हें इसका अधिकार मिल जाये—अधिक आसान और कोई काम नहीं है जो व्याज की दर घटाकर एक प्रतिशत कर दे। पर यदि समस्त अन्य सामाजिक अवस्थाएं वैसी ही रहें जैसी वे हैं तो यह प्रदोंपंथी आज्ञाप्ति मात्र कागजी कार्रवाई होगी। व्याज की दर का सारी आज्ञाप्तियों के बावजूद आर्थिक कानूनों द्वारा, जो उस पर आज लागू होते हैं, नियमन होता रहेगा। उधार चुका सकनेवाले लोग परिस्थितियों के अनुसार दो, तीन, चार या इससे भी अधिक प्रतिशत व्याज पर उधार लेते रहेंगे। अन्तर केवल इतना होगा कि किरायाजीवी बहुत सावधानीपूर्वक केवल उन लोगों को ही धन उधार देंगे जिनसे किसी तरह की मुक्तदमेबाजी की सम्भावना नहीं होगी। यही नहीं, पूंजी को उसकी “उत्पादकता” से वंचित करने की यह महान योजना आद्य मूल की है; वह सूदखोरी विषयक कानूनों जितनी पुरानी है जिनका लक्ष्य व्याज की दर सीमित करने के अलावा और कुछ नहीं था और जिन्हें आगे चलकर खत्म कर दिया गया क्योंकि व्यवहार में निरन्तर उनका या तो उल्लंघन होता रहा अथवा उनसे बचा जाता रहा। फिर राज्य को स्वीकार करना पड़ा कि वह सामाजिक उत्पादन के कानूनों के सामने असहाय है। इन मध्य-भूमीन और अव्यवहार्य कानूनों को फिर से प्रचलित करना क्या “पूंजी की उत्पादकता से सीधे-सीधे निपटना” है! प्रदोंपंथ की जितनी बारीकी से जांच की जाये, वह उतना ही ज्यादा प्रतिक्रियावादी रूप में प्रकट होता है।

और इस ढंग से व्याज की दर जब शून्य तक पहुंचा दी जायेगी और इसलिए पूंजी पर व्याज खत्म कर दिया जायेगा, तब “पूंजी के आवर्त्त के लिए आवश्यक धन से जरा भी ज्यादा भुगतान नहीं किया जायेगा।” इसका यह अर्थ होगा

कि व्याज का खात्मा मुनाफ़े के, यही नहीं, अतिरिक्त मूल्य के खात्मे के बराबर है। परन्तु किसी आज्ञाप्ति से यदि ऐसा करना सचमुच सम्भव होता तो उसका परिणाम क्या निकलता? किरायाजीवियों के वर्ग के लिए अपनी पूंजी उधार के रूप में देने के वास्ते कोई प्रलोभन न रह जाता और वे उसे अपने जोखिम पर अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर या ज्वायंट स्टॉक कम्पनियों पर लगाते। पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग से हस्तगत अतिरिक्त मूल्य का परिमाण उतना ही बना रहता; केवल उसका वितरण परिवर्तित होता और वह भी बहुत ज्यादा नहीं।

वस्तुतः हमारे प्रूदोंपंथी यह नहीं देख पाते कि इस समय भी पूंजीवादी समाज में माल की ख़रीद में “पूंजी के आवर्त्त के लिए आवश्यक श्रम” से ज्यादा भुगतान नहीं किया जाता (इसका इस तरह अर्थ लगाया जा सकता है—निश्चित माल के उत्पादन के लिए आवश्यक)। श्रम सारे मालों के मूल्य का पैमाना है। और वर्तमान समाज में—मंडी में उतार-चढ़ावों को छोड़कर—यह बिल्कुल असम्भव है कि कुल मिलाकर मालों के लिए उससे ज्यादा भुगतान किया जाये जो उनके उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जी नहीं, प्यारे प्रूदोंपंथी, कठिनाई तो सर्वथा अन्यत्र निहित है। वह इस तथ्य में निहित है कि “पूंजी के आवर्त्त के लिए आवश्यक श्रम” का (यदि आपके ही भ्रान्तिपूर्ण वाक्यांश को इस्तेमाल किया जाये) पूरी तरह भुगतान ही नहीं किया जाता! यह कैसे होता है, इसके लिए मार्क्स को पढ़ें (‘पूंजी’, खंड १, पृष्ठ १२८-१६०)।

परन्तु इतना ही नहीं। यदि पूंजी पर व्याज (Kapitalzins) ख़त्म कर दिया जाता है तो मकान का किराया (Mietzins)* भी उसके साथ ख़त्म हो जाता है क्योंकि “तमाम अन्य उत्पादों की तरह, मकान तथा घर भी स्वभावतया इस क़ानून के कार्यक्षेत्र में शामिल किये गये हैं।” यह बिल्कुल उस बूढ़े भेजर की मनोभावना के अनुकूल है जिसने एक रंगरूट अपने पास बुलाया और उससे कहा—

“सुना है कि तुम डाक्टर हो; समय-समय पर मेरे घर आया करो। जब घर पर पत्नी और सात बच्चे हों तो वहां कोई न कोई इलाज के लिए होगा ही।”

* Zins — व्याज। Mietzins — मकान-किराया। शाब्दिक अर्थ है किराया-व्याज।

रंगरूट, “पर, मेजर साहब, मैं तो दर्शनशास्त्र का डाक्टर हूँ!”

मेजर, “इससे क्या फर्क पड़ता है; डाक्टर डाक्टर में क्या फर्क है!”

हमारे प्रदोषधी भी इसी तरह पेश आते हैं। उनके लिए मकान का किराया हो या पूँजी पर ब्याज, दोनों एक ही चीज हैं। ब्याज ब्याज में क्या फर्क है, डाक्टर डाक्टर में क्या फर्क है!

हम ऊपर देख चुके हैं कि किराये का दाम, जिसे हम सामान्यतया मकान-किराया कहते हैं, जिन चीजों को लेकर बनता है, वे इस प्रकार हैं—१) एक हिस्सा जो ज़मीन के किराये का होता है, २) एक हिस्सा जो निर्माण पूँजी पर ब्याज का होता है, जिसमें निर्माता का मुनाफ़ा भी शामिल है, ३) एक हिस्सा जो मरम्मत तथा बीमे पर जाता है, ४) एक हिस्सा जिससे मुनाफ़ा समेत निर्माण पूँजी का, उस हिसाब से जिस हिसाब से मकान का धीरे-धीरे मूल्य-ह्रास होता है, वार्षिक प्रतिशोधन करना पड़ता है।

अब अंधे व्यक्ति के लिए भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि “सबसे पहले स्वयं मालिक अपने मकान की बिक्री के लिए तैयार हो जायेगा, अन्यथा उसका मकान खाली पड़ा रहेगा और उस पर लगी पूँजी सरासर बेकार पड़ी रहेगी।” बेशक। यदि उधार पूँजी पर ब्याज ख़त्म कर दिया जाये तो कोई भी मकान-मालिक आगे से अपने मकान के लिए किराये की एक दमड़ी भी प्राप्त नहीं कर पायेगा, सिर्फ़ इसलिए कि मकान-किराये को किराया-ब्याज का नाम भी दिया जा सकता है, इसलिए कि इसमें एक हिस्सा ऐसा है जो दरअसल पूँजी पर ब्याज है। डाक्टर डाक्टर में क्या फर्क है। हालांकि पूँजी पर सामान्य ब्याज से सम्बन्धित सूदखोरी विषयक कानूनों को उनका उल्लंघन करके ही प्रभावहीन बनाया जा सकता था, उन्होंने मकान-किराये की दर को कभी भी स्पर्श तक नहीं किया। प्रदोष ही यह कल्पना कर सकते थे कि सूदखोरी विषयक उनका नया कानून पूँजी पर सामान्य ब्याज का ही नहीं, वरन् आवास के जटिलताभरे मकान-किराये का भी बिना किसी कठिनाई के नियमन कर सकेगा तथा उसे धीरे-धीरे ख़त्म कर सकेगा। तो फिर मकान-मालिक को अच्छी-खासी रकम देकर उससे “सरासर बेकार” मकान क्यों ख़रीदा जाये, और मकान-मालिक इन परिस्थितियों के अन्तर्गत इस “सरासर बेकार” मकान से छुटकारा पाने के लिए क्यों न स्वयं पैसा दे ताकि वह मरम्मत कार्यों पर होनेवाले खर्चों से बच सके—यह हमारे लिए रहस्य बना हुआ है।

उच्च समाजवाद (गुरु प्रदों ने इसे «Suprasocialism»* का नाम दिया था) के क्षेत्र में इस शानदार उपलब्धि के बाद हमारे प्रदोंपंथी अपनी और भी ऊंची उड़ान को उचित ठहराते हैं—

“अब इतना और करना बाकी रह गया है कि कुछ निष्कर्ष निकाले जायें ताकि हमारे इतने महत्वपूर्ण विषय पर चारों ओर से पूरी रोशनी डाली जा सके।”

और ये निष्कर्ष क्या हैं? ये निष्कर्ष भी व्याज के खात्मे से मकानों के बेकार होने जैसे पूर्वोक्त निष्कर्षों से ज्यादा भिन्न नहीं हैं। यदि हमारे लेखक महाशय की वाक्यावली से उसका शाब्दिक चमत्कार तथा शब्दाडम्बर हटा दिया जाये तो उसका इससे ज्यादा और कोई अर्थ नहीं रह जायेगा कि किराये पर उठाये जानेवाले मकानों को छुड़ाने का काम सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित बातें वांछनीय हैं—१) विषय पर ठीक-ठीक आंकड़े, २) सफ़ाई की अच्छी-खासी जांच व्यवस्था, ३) नये मकानों के निर्माण का बीड़ा उठाने के लिए भवत-निर्माण मजदूरों की सहकारी संस्थाएं। ये सब चीजें बेशक अच्छी और बहुत बढ़िया भी हैं परन्तु सारे कोलाहलपूर्ण वाक्यों में प्रस्तुत किये जाने के बावजूद वे प्रदोंपंथी मानसिक भ्रान्ति के झुंघलेपन पर “पूरी रोशनी” कदापि नहीं डाल पातीं।

जो इतनी बड़ी चीजें हासिल कर चुका है, उसे जर्मन मजदूरों को एक गम्भीर समादेश के साथ सम्बोधित करने का अधिकार है—

“ये तथा इन जैसे प्रश्न, हमारी राय में, सामाजिक जनवाद के विचारार्थ सर्वथा उपयुक्त हैं... उसे यहां आवास प्रश्न की तरह उधार, राजकीय ऋण, निजी ऋण, कर, आदि दूसरे तथा समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्नों की स्पष्टता-पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करना चाहिए।”

इस तरह हमारे प्रदोंपंथी यहां हमसे “इन जैसे प्रश्नों” पर एक पूरी लेखमाला पेश करने का वचन दे रहे हैं। और यदि वह उन सब का उतनी ही पूर्णता के साथ चर्चा करेंगे जितनी पूर्णता के साथ उन्होंने मौजूदा “समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न” की चर्चा की तो «Volksstaat» अखबार के पास पूरे एक साल के लिए पर्याप्त सामग्री हो जायेगी। परन्तु हम पहले से कल्पना करने की स्थिति में हैं—वह सब वही है जो पहले कहा जा चुका है—पूँजी पर व्याज ख़त्म किया जायेगा, और उसके साथ राजकीय तथा निजी ऋणों पर व्याज लुप्त हो जायेगा,

* अधिसमाजवाद। — सं०

उधार मुफ्त होंगे, आदि। यही जादुई फार्मूला किसी भी तथा हर विषय पर लागू किया जाता है और प्रत्येक मामले में अटल तर्क के साथ एक ही विस्मयकारी परिणाम, अर्थात् यह परिणाम सामने आता है कि जब पूंजी पर व्याज मिटा दिया जायेगा, तब उधार लिये हुए धन पर कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा।

प्रसंगतः ये बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं जिनसे हमारे प्रदोषी हमें भयभीत कर रहे हैं—उधार! मजदूर को उसके अलावा और किस उधार की जरूरत है जो वह सप्ताह-प्रति सप्ताह या माल गिरवी रखनेवाली दुकान से हासिल करता है? यह उधार उसे व्याज पर या बिना व्याज के मिलता है, या यही नहीं माल गिरवी रखनेवाली दुकान से महाजनी दर तक पर मिलता है, इन सब से उसे क्या फर्क पड़ता है? और यदि वह, सामान्यतया, इससे कुछ फायदा हासिल कर भी लेता कहने का मतलब यह है कि यदि श्रम शक्ति की उत्पादन लागत घट भी जाये तो क्या श्रम शक्ति की कीमत अवश्यम्भावी रूप से नहीं गिरेगी? परन्तु पूंजीपति, कास तौर पर निम्नपूंजीपति के लिए उधार महत्वपूर्ण मामला है और यदि विशेष रूप से निम्नपूंजीपति बिना व्याज के किसी भी समय उधार हासिल कर सके तो वह उसके लिए बहुत अच्छी बात होगी।—राजकीय ऋण! मजदूर वर्ग जानता है कि ये ऋण उसने नहीं लिये हैं और जब वह सत्तारूढ़ होगा तो वह उनकी प्रवायगी का काम उन पर छोड़ देगा जिन्होंने वे ऋण लिये हैं।—निजी ऋण!—ऐसे उधार।—कर! यह ऐसा मामला है जिसमें पूंजीपतियों की बहुत ज्यादा परन्तु मजदूर की बहुत कम दिलचस्पी है। मजदूर करों के रूप में जो देता है, वह अस्तित्वगत श्रम शक्ति की उत्पादन लागत में चला जाता है, इसलिए उसकी पूर्ति पूंजीपति को करनी चाहिए। ये सब चीजें, जो हमारे सामने मजदूर वर्ग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, दरअसल केवल पूंजीपतियों और उनसे भी ज्यादा निम्नपूंजीपतियों के लिए ही मूलतः दिलचस्पी के विषय हैं। और प्रदोष के विपरीत हमारी यह मान्यता है कि इन वर्गों के हितों की रक्षा करना मजदूर वर्ग की जिम्मेवारी नहीं है।

उस महान प्रश्न के बारे में, जिसका मजदूरों से वस्तुतः सम्बन्ध है, पूंजीपति तथा उजरती मजदूर के बीच सम्बन्ध के प्रश्न के बारे में, पूंजीपति कैसे अपने मजदूरों के श्रम से अपने को समृद्ध बना लेता है, इस प्रश्न के बारे में हमारे प्रदोषी एक भी शब्द नहीं कहते। यह सच है कि उनके गुरु ने इस प्रश्न में ध्यान डाला था परन्तु मामले में स्पष्टता का कतई कोई समावेश नहीं किया। अपनी नवीनतम रचनाओं तक में वह मूलतः अपनी 'दरिद्रता का दर्शन' शीर्षक

रचना से आगे नहीं बढ़ पाये जिसकी मार्क्स १८४७ में ही खूब धज्जियां उड़ा चुके थे।*

दुर्भाग्य की बात है कि पचीस वर्षों तक लैटिन देशों के मजदूरों के पास “द्वितीय साम्राज्य के” इस “समाजवादी” की रचनाओं के अलावा प्रायः कोई अन्य समाजवादी बौद्धिक आहार नहीं था। और अगर प्रदोपंथी सिद्धान्त अब जर्मनी में भी प्रवाहित होने लगे तो यह और भी दुर्भाग्य की बात होगी। परन्तु इसका कोई डर नहीं है। जर्मन मजदूरों का सैद्धान्तिक दृष्टिकोण प्रदोपंथ से पचास वर्ष आगे है, और इस मामले में और मुसीबत से बचने के लिए इस एक प्रश्न को, आवास प्रश्न को ही उदाहरणस्वरूप लेना पर्याप्त होगा।

भाग २

पूँजीपति वर्ग आवास प्रश्न किस तरह हल करता है

१

आवास प्रश्न के प्रदोपंथी समाधान-सम्बन्धी अनुभाग में यह सिद्ध किया गया था कि इस प्रश्न में निम्नपूँजीपति वर्ग की कैसे प्रत्यक्ष दिलचस्पी है। परन्तु बड़े पूँजीपति वर्ग की भी उसमें बहुत दिलचस्पी है भले ही वह प्रत्यक्ष न हो। आधुनिक प्रकृति विज्ञान ने सिद्ध किया है कि तथाकथित “गरीब ज़िले”, जिनमें मजदूर ठसाठस भरे रहते हैं, किस तरह उन सारी महामारियों की जन्म-स्थली हैं जिनका समय-समय पर हमारे शहरों पर प्रकोप होता रहता है। हैजा, टाइफ़स, टाइफ़ाइड बुखार, चेचक तथा अन्य विनाशकारी बीमारियां मजदूर वर्ग के इन मुहल्लों की प्रदूषित हवा तथा जहरीले पानी में अपने रोगाणु फैलाती हैं। यहां रोगाणु कभी पूरी तरह नहीं मरते और अपने लिए परिस्थितियां अनुकूल होते ही वे महामारियों का रूप ग्रहण कर लेते हैं और फिर अपनी जन्म-स्थली के पार पहुंचते हुए शहर के उन अधिक हवादार और आरोग्यकर स्थानों में फैल जाते हैं जहां पूँजीपति बसे हुए हैं। पूँजीवादी शासन के लिए मजदूर वर्ग के बीच महामारियों को पैदा

* कार्ल मार्क्स, ‘दर्शन की दरिद्रता। श्री प्रदो की रचना ‘दरिद्रता के दर्शन’ का उत्तर’। - सं०

होने देना एक ऐसी ऐयाशी होगी जिसकी सज़ा से वह बच नहीं सकता ; उसके परिणाम उल्टे पूंजीपतियों पर भी मार करते हैं, यमराज उनके बीच उतना ही रौद्र रूप धारण करता है जितना मज़दूरों के बीच।

यह तथ्य ज्योंही वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित हुआ, लोकोपकारी पूंजीपति का रोम-रोम मज़दूरों की सेहत के लिए चिन्ता की होड़ की भावना से ओतप्रोत हो गया। बार-बार फैलनेवाली महामारियों के स्रोत बन्द करने के लिए संस्थाएं स्थापित की गयीं, पुस्तकें लिखी गयीं, प्रस्ताव तैयार किये गये तथा क़ानूनों पर बहसें हुईं तथा उन्हें पास किया गया। मज़दूरों के आवास की अवस्थाओं की जांच की गयी तथा सबसे असहनीय बुराइयों को दूर करने की कोशिशें की गयीं। खास तौर पर इंगलैंड में जोरदार सरगर्मियां शुरू हुईं जहां बड़े शहर सबसे ज्यादा संख्या में थे और जहां इस कारण स्वयं पूंजीपति वर्ग के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था। मज़दूर वर्गों की स्वच्छता-सम्बन्धी अवस्थाओं की जांच करने के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किये गये। उनकी रिपोर्टों ने, जो अपनी शुद्धता, पूर्णता तथा निष्पक्षता के मामले में तमाम प्रकाशित महाद्विपीय सामग्रियों की तुलना में श्रेष्ठ थीं, नये न्यूनाधिक आमूलवादी क़ानूनों का आधार प्रस्तुत किया। ये क़ानून अपूर्ण अवश्य हैं परन्तु इसके बावजूद वे उन सब कामों से असीम रूप से श्रेष्ठ हैं जो इस दिशा में महाद्वीप में अब तक किये गये हैं। फिर भी पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था इन बीमारियों को, जिनके इलाज की यहां चर्चा की गयी है, ऐसी अनिवार्यता के साथ बार-बार पैदा करती है कि इंगलैंड तक में उनके इलाज का काम एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाया है।

जर्मनी को अपने यहां महामारियों के स्थायी स्रोतों द्वारा ख़तरे की ऐसी सीमा पर, जहां निद्राग्रस्त बड़े पूंजीपति वर्ग को झकझोरना आवश्यक हो गया था, पहुंचने के लिए हमेशा की तरह कहीं अधिक लंबा समय लगा। परन्तु जो धीमे-धीमे चलता है, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और इस तरह हमारे बीच भी अन्ततः सार्वजनिक स्वच्छता तथा आवास प्रश्न पर पूंजीवादी साहित्य ने जन्म ले लिया है, वह अपने विदेशी, विशेष रूप से अंग्रेज़ पूर्ववर्तियों का दयनीय उद्धरण है जिसे कपटपूर्ण ढंग से तड़कीले-भड़कीले तथा लच्छेदार वाक्यों का लिवांस पहनाकर उच्च अवधारणा का रूप देने का प्रयास किया गया है। 'मेहनतकश वर्गों की आवास परिस्थितियां तथा उनका सुधार' शीर्षक पुस्तक इसी साहित्य का अंग है जिसे डा० एमिल जाक्स ने लिखा है तथा जो १८६६ में बियेना में प्रकाशित हुई है।

मैंने आवास प्रश्न पर पूंजीवादी दृष्टिकोण के प्रस्तुतीकरण के लिए यह पुस्तक केवल इसलिए चुनी है कि यह इस विषय पर पूंजीवादी साहित्य का यथासम्भव सामान्यीकरण करने की कोशिश करती है। और यह भी कितना बढ़िया साहित्य है जो हमारे लेखक के लिए "स्रोत" का काम देता है! अंग्रेज संसदीय रिपोर्टों में से, सही अर्थों में मुख्य स्रोतों में से केवल तीन की, जो सबसे पुरानी हैं, वस नाम देकर चर्चा कर दी गयी है। पूरी पुस्तक सिद्ध करती है कि लेखक ने उनमें से एक पर भी कभी नज़र नहीं डाली है। दूसरी ओर तुच्छ पूंजीवादी, सदाशयी कूपसंडूकतावादी तथा पाखंडपूर्ण लोकोपकारी रचनाओं की एक पूरी शृंखला प्रस्तुत की गयी है—ड्यूकपेसो, राबर्ट्स, होल, ह्यूबर की रचनाएं, समाज विज्ञान (यों कहें कि सामाजिक अनाप-शनाप) पर अंग्रेज कांग्रेस की कार्यवाहियां, मेहनतकश वर्गों के मंगल-कल्याण की प्रशियाई संस्था की पत्रिका, पेरिस में विश्व प्रदर्शनी पर आस्ट्रियाई सरकारी रिपोर्ट, इसी विषय पर बोनापार्टपंथी सरकारी रिपोर्टें, «*Illustrated London News*»,⁶⁵ «*Über Land und Meer*»⁶⁶ और अन्ततः "एक प्रामाणिक विशेषज्ञ", "प्रखर व्यावहारिक बुद्धि वाला", "प्रभावोत्पादक वक्ता", अर्थात् जूलियस फ़ाउहेर! सामग्री स्रोतों की इस सूची से वस ये ही नाम गायब हैं—«*Gartenlaube*»⁶⁷, «*Kladderadatsch*»⁶⁸ तथा फ़ूसिलिए कुचके⁶⁹।

अपने दृष्टिकोण के बारे में कोई गलतफ़हमी पैदा न हो, इसलिए श्री ज़ाक्स पृष्ठ २२ पर घोषित करते हैं—

"सामाजिक अर्थशास्त्र से हमारा तात्पर्य सामाजिक प्रश्नों पर लागू होनेवाले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त से है, या अधिक सटीक ढंग से कहें तो उन उपायों तथा साधनों की समग्रता से है जिन्हें यह विज्ञान इस समय विद्यमान समाज की व्यवस्था के ढाँचे के अन्तर्गत अपने 'लौह' क़ानूनों के आधार पर तथाकथित (!) सम्पत्तिहीन वर्गों को सम्पत्तिधारी वर्गों के स्तर पर पहुँचाने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है।"

हम इस भ्रान्त विचार पर बहस नहीं करेंगे कि सामान्यतया "राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का सिद्धान्त" अथवा राजनीतिक अर्थशास्त्र "सामाजिक" प्रश्नों के अलावा बाक़ी सारे प्रश्नों से सम्बन्ध रखता है। हम तुरन्त मुख्य बिन्दु पर ग़ौर करेंगे। डा० ज़ाक्स मांग करते हैं कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र के "लौह क़ानूनों को, इस समय विद्यमान समाज की व्यवस्था के ढाँचे को", दूसरे शब्दों में उत्पादन

की पूंजीवादी पद्धति को अपरिवर्तित रूप से जारी रहना चाहिए, तथापि “तथा-कथित सम्पत्तिहीन वर्गों को सम्पत्तिधारी वर्गों के स्तर पर” पहुँचाया जाना चाहिए। परन्तु उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति की एक अपरिहार्य प्रारम्भिक शर्त यह है कि सही मानों में—तथाकथित नहीं—एक सम्पत्तिहीन वर्ग का अस्तित्व हो, ऐसे वर्ग का अस्तित्व हो जिसके पास अपनी श्रम शक्ति के अलावा बेचने के लिए और कुछ नहीं होता और जो इस कारण अपनी श्रम शक्ति औद्योगिक पूंजीपतियों के हाथों में बेचने के लिए विवश होता है। इसलिए श्री ज़ाक्स द्वारा गढ़े गये नये विज्ञान का—सामाजिक अर्थशास्त्र का—कार्यभार एक ओर पूंजीपतियों, सारे कच्चे मालों, उत्पादन के औजारों तथा जीवन निर्वाह के साधनों के स्वामियों तथा दूसरी ओर सम्पत्तिहीन उजरती मजदूरों, केवल अपनी श्रम शक्ति को—और किसी भी चीज़ को नहीं—अपना कहनेवालों के बीच विरोध पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे उपायों तथा साधनों की तलाश करना है जिनके द्वारा इस सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सारे उजरती मजदूरों को उजरती मजदूर बनाये रखते हुए पूंजीपतियों में परिणत किया जा सके। श्री ज़ाक्स समझते हैं कि उन्होंने समस्या हल कर डाली है। परन्तु वह हमें यह बताने की कृपा करें कि फ्रांसीसी सेना के सारे सिपाहियों को, जिनमें से हरेक के झोले में नेपोलियन प्रथम के जमाने से ही मार्शल की छड़ी होती है, सिपाही बने रहने के साथ-साथ कैसे फ्रील्ड मार्शल बनाया जा सकता है। या यह कैसे सम्भव होगा कि जर्मन साम्राज्य के पूरे ४ करोड़ प्रजाजनों को जर्मन सम्राट बना दिया जाये।

मौजूदा समाज की सारी बुराइयों के आधार को बरकरार रखने और साथ ही स्वयं बुराइयों को मिटाने की इच्छा पूंजीवादी समाजवाद का सारतत्त्व है। जैसा कि ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ में पहले ही लक्षित किया जा चुका है, पूंजीवादी समाजवादी “पूँजीवादी समाज को बरकरार रखने के लिए समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते हैं”; वे चाहते हैं कि “पूँजीपति वर्ग हो, लेकिन सर्वहारा न हो।” हम देखते हैं कि श्री ज़ाक्स समस्या को ठीक उसी तरह निरूपित करते हैं। सामाजिक समस्या का समाधान वह आवास प्रश्न के समाधान में देखते हैं। उनकी राय है कि

“मेहनतकश वर्गों की आवास की स्थिति सुधार कर वर्णित शारीरिक तथा आत्मिक दुर्दशा का सफलतापूर्वक उपचार करना तथा इस तरह”—मात्र आवासीय अवस्थाओं में व्यापक सुधार लाकर—“इन वर्गों के बड़े भाग को प्रायः अमानवीय

अवस्थाओं के दलदल से बाहर निकालकर भौतिक तथा आत्मिक समृद्धि के निर्मल शिखरों तक पहुंचाना सम्भव होगा।” (पृष्ठ १४)

७

प्रसंगतः, यह तथ्य छुपाना पूंजीपति वर्ग के हित में है कि सर्वहारा वर्ग, जिसे पूंजीवादी उत्पादन सम्बन्ध जन्म देते हैं और जो फिर इन सम्बन्धों के सतत अस्तित्व को निर्धारित करता है, अस्तित्वमान है। इसलिए श्री ज़ाक्स हमसे कहते हैं (पृष्ठ २१) कि मेहनतकश वर्ग शब्द में वास्तविक मजदूरों के साथ ही साथ सारे “धनहीन सामाजिक वर्गों को” और “सामान्यतया दस्तकारों, विद्यवाओं, पेंशनरों (!), छोटे अधिकारियों, आदि जैसे छोटे लोगों को” शामिल माना जाना चाहिए। पूंजीवादी समाजवाद निम्न-पूंजीवादी समाजवाद की ओर अपना हाथ बढ़ाता है।

तो आवास की कमी कब से है? यह कैसे पैदा हुई? एक अच्छे पूंजीपति के रूप में श्री ज़ाक्स से यह जानने की अपेक्षा नहीं की जाती कि वह पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यक उपज है; कि वह ऐसे समाज में विद्यमान हुए बिना रह नहीं सकती जिसमें मेहनतकश जनसाधारण का बहुत बड़ा भाग उजरत पर ही, अर्थात् अपने अस्तित्व के लिए तथा अपनी वंशावली की निरन्तरता के लिए आवश्यक आजीविका के साधनों के परिमाण पर निर्भर करता है; जिसमें मशीनों में सुधार, आदि बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों को निरन्तर बेरोजगार बनाते रहते हैं; जिसमें उग्र तथा नियमित रूप से आवर्ती औद्योगिक उतार-चढ़ाव एक ओर बेरोजगारों की विशाल रिजर्व फ़ौज तैयार करते रहते हैं तथा दूसरी ओर मजदूरों के झुंडों को बेरोजगार कर बाहर धकेलते रहते हैं; जिसमें मजदूर बड़े शहरों में बड़े समूहों में उससे ज्यादा तेज़ रफ़्तार से ठूसे जाते रहते हैं जिस रफ़्तार से विद्यमान परिस्थितियों में उनके लिए मकान बनाये जाते हैं; जिसमें इस कारण गन्दे से गन्दे बाड़ों तक के लिए हमेशा किरायेदार मिल जायेंगे; और जिसमें अन्ततः मकान-मालिक को पूंजीपति की हैसियत से यह अधिकार ही नहीं है अपितु प्रतियोगिता के कारण उसका कुछ हद तक यह कर्तव्य भी है कि वह अपने मकान से वेरहमी से अधिक से अधिक भाड़ा कमाये। इस तरह के समाज में आवास की कमी कोई संयोग की बात नहीं है, यह तो एक आवश्यक संस्थान भी है और उसे सेहत, आदि पर पड़नेवाले तमाम कुप्रभावों समेत तभी मिटाया जा सकता है जब पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था के, जिससे वह जन्म लेती है, आधार का पूर्ण पुनर्गठन कर दिया जायेगा। परन्तु पूंजीवादी समाजवाद

यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आवास की कमी विद्यमान परिस्थितियों से पैदा होती है। इसलिए आवास की कमी का कारण समझाने के लिए उसके पास यह उपदेश देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि यह इन्सान की दुष्टता का फल है, यूँ कहिये कि आदि पाप का फल है।

“और हम यहां यह देखे बिना नहीं रह सकते—और फलस्वरूप हम इस बात का खंडन नहीं कर सकते” (साहसपूर्ण निष्कर्ष!)—“कि दोष... अंशतः स्वयं मजदूरों का है, जो रिहायशी घर चाहते हैं, और अंशतः—यह सच है कि ज्यादातर—उनका है जो इस आवश्यकता की पूर्ति का बीड़ा उठाते हैं या उनका अर्थात् सम्पत्तिधारी उच्च सामाजिक वर्गों का है जो अपने पास पर्याप्त साधन होते हुए भी इस आवश्यकता की पूर्ति करने का कोई प्रयास भी नहीं करते। उन्हें दोषी इसलिए ठहराया जा सकता है कि वे पर्याप्त संख्या में अच्छे रिहायशी घर मुहैया करने के लिए अपने को जिम्मेवार नहीं बनाते।”

जिस तरह प्रूदों हमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र से कानूनी क्षेत्र में ले जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे पूंजीवादी समाजवादी हमें यहां आर्थिक क्षेत्र से नैतिक क्षेत्र में ले जाते हैं। और यह सर्वथा स्वाभाविक भी है। जो कोई यह घोषित करता है कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति, वर्तमान पूंजीवादी समाज के “लौह कानून” अनुलंघनीय हैं, परन्तु साथ ही यह चाहता है कि उनके असुखद परन्तु आवश्यक परिणामों को मिटा दिया जाये, उसके लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता कि वह पूंजीपतियों को नैतिक उपदेश दे, ऐसे नैतिक उपदेश जिनका भावनात्मक प्रभाव निजी हित के असर और जरूरत पड़ने पर प्रतियोगिता का असर पड़ते ही तुरन्त लुप्त हो जाता है। ये नैतिक उपदेश वस्तुतः तालाब के किनारे पर खड़ी उस मुर्गी के उपदेशों से बिल्कुल मिलते हैं जो तालाब में चूजों को मजे से तैरते हुए देखती है। चूजे पानी में तैरते हैं हालांकि पानी में गहतीर नहीं हैं और पूंजीपति मुनाफ़े पर झपटते हैं हालांकि वह निर्दय है। “मुद्रा के मामले में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती”, यह वृद्ध हान्सेमान पहले ही कह चुके थे जिन्हें इस बारे में श्री जाक्स से ज्यादा जानकारी थी।

“अच्छे घर इतने महंगे होते हैं कि मजदूरों के बड़े भाग के लिए उनका उपयोग करना सर्वथा असम्भव है। बड़ी पूंजी... मेहनतकश वर्गों के लिए मकान

बनाने में संकोच करती है... और फलस्वरूप ये वर्ग अपनी आवास-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतर सट्टेबाजों के जाल में फँस जाते हैं।”

□

बिनामी सट्टेबाजी! बड़ी पूंजी स्वभावतया कभी सट्टेबाजी नहीं करती! परन्तु दुर्भाग्यवश नहीं, केवल अज्ञान बड़ी पूंजी को मजदूरों के मकानों पर सट्टेबाजी करने से रोकता है—

“मकान-मालिकों को पता ही नहीं है कि आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी बड़ी तथा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है; उन्हें पता ही नहीं है कि वे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं जब वे इतने अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उन्हें आम तौर पर खराब और नुकसानदेह घर देते हैं, और अन्ततः उन्हें पता ही नहीं है कि वे इस तरह खुद अपने पांवों पर कुलहाड़ी मार रहे हैं।” (पृष्ठ २७)

परन्तु आवास की कमी के पैदा होने के लिए पूंजीपतियों के अज्ञान के साथ मजदूरों के अज्ञान को भी जोड़ा जाना चाहिए। यह स्वीकार करने के बाद कि मजदूरों के “सबसे निचले हिस्से कहीं भी और किसी भी तरह रात गुजारने के लिए डेरा ढूँढ़ने के वास्ते विवश (!) होते हैं ताकि उन्हें रात खुले आकाश के ही नीचे न गुजारनी पड़े, और इस सिलसिले में वे सर्वथा अरक्षित तथा निस्सहाय हैं”, श्री ज़ाक्स हमसे कहते हैं—

“आखिरकार यह एक सुविदित तथ्य है कि उनमें से” (मजदूरों में से) “बहुत-से लापरवाही, या मुख्यतया अज्ञान के कारण अपने शरीरों को पारंगति के साथ विकास तथा स्वास्थ्यकर अस्तित्व से वंचित कर देते हैं, इसलिए कि उन्हें युक्तिसंगत स्वच्छता का और विशेष रूप से इस सम्बन्ध में आवास को प्राप्त अपार महत्व का लेशमात्र ज्ञान नहीं है।” (पृष्ठ २७)

परन्तु यहां पूंजीपति के गधे के कान सामने आ जाते हैं। जहां पूंजीपतियों का सम्बन्ध है, “दोष” अज्ञान में विलीन हो जाता है, परन्तु जहां मजदूरों का सम्बन्ध है, अज्ञान को उनके दोष का कारण बना दिया जाता है। ज़रा सुनिये—

“इस तरह” (अज्ञान के कारण ही) “होता यह है कि किराये की मद में कुछ बचा लेने के लिए वे अंधेरे, नमी से भरे, छोटे घरों में बस जाते हैं जो

संक्षेप में स्वच्छता के सारे तकाजों का मखौल है... कि अक्सर कई परिवार एक ही घर, यही नहीं, एक ही कोठरी किराये पर ले लेते हैं—यह सब किराये की मद पर कम से कम खर्च करने के लिए किया जाता है जबकि दूसरी ओर वे अपनी आय को शराब और हर क्रिस्म का निरर्थक मजा लूटने पर सही अर्थ में पापपूर्ण ढंग से उड़ा देते हैं।”

मजदूर द्वारा “शराब और तंबाकू पर गंवाया जानेवाला” पैसा (पृष्ठ २८) तथा “महखानों की जिंदगी और उसके सारे दुःखद कुपरिणाम, जो मजदूर के सीने से बंधे हुए भारी पत्थर की तरह उसे बार-बार दलदल में ला पटकते हैं”, वस्तुतः श्री ज़ाक्स के गले में लटके मौजूद भारी पत्थर की तरह है। विद्यमान परिस्थितियों के अन्तर्गत मजदूरों में शराब की लत, टाइफ़स, अपराध, परजीविता, मुकदमेबाजी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह उनके रहन-सहन की अवस्थाओं की आवश्यक उपज है, वस्तुतः इतनी आवश्यक उपज है कि शराबियों की औसत संख्या पहले ही आंकी जा सकती है, श्री ज़ाक्स इस तथ्य को भी जानने से इन्कार करते हैं। प्रसंगतः, मेरे वृद्ध स्कूल मास्टर कहा करते थे, “साधारण लोग महखानों में तथा बड़े लोग क्लबों में जाते हैं।” चूंकि मैं दोनों जगहों में जा चुका हूं, इसलिए मैं इसकी पुष्टि करने की स्थिति में हूं।

दोनों पक्षों के “अज्ञान” की यह सारी बकवास श्रम तथा पूंजी के हितों के सामंजस्य के विषय में पुराने रागों के अलावा और कुछ नहीं है। यदि पूंजीपतियों को अपने सच्चे हितों का ज्ञान हो तो वे मजदूरों को अच्छे मकान दे देते तथा उनकी स्थिति को सामान्यतया सुधारते; और यदि मजदूरों को अपने सच्चे हितों की समझ हो तो वे हड़ताल नहीं करते, सामाजिक-जनवाद का पल्ला नहीं पकड़ते, राजनीति का खेल न खेलते, बल्कि आज्ञाकारी बनकर अपने अग्रणी लोगों का, पूंजीपतियों का अनुसरण करते। परन्तु दुर्भाग्यवश दोनों पक्ष अपने हित श्री ज़ाक्स तथा उनके अनगिनत पूर्ववर्तियों के उपदेशों में नहीं, बरन् सर्वथा अन्यत्र देखते हैं। पूंजी तथा श्रम के बीच सामंजस्य के दिव्य सिद्धान्त का तो लगभग पूरे पचास वर्षों से प्रचार होता आ रहा है और पूंजीवादी लोकोपकारिता आदर्श संस्थानों का निर्माण कर इस सामंजस्य को सिद्ध करने पर बहुत बड़ी धनराशियां खर्च कर चुकी है। फिर भी हम आगे देखेंगे कि हम ठीक वहीं हैं जहां पचास साल पहले थे।

हमारे लेखक महाशय अब समस्या के व्यावहारिक समाधान की ओर अग्रसर होते हैं। मजदूरों को अपने घरों का मालिक बनाने का प्रदों का प्रस्ताव कितना

कम क्रान्तिकारी था, इसका पता इस तथ्य से चल सकता है कि पूंजीवादी समाजवाद ने उनसे पहले भी इसे अमल में लाने की कोशिश की थी और अब भी कर रहा है। श्री ज़ाक्स भी घोषित करते हैं कि आवास समस्या घरों का स्वामित्व मजदूरों के हाथों में सौंपकर ही पूर्णतया हल की जा सकती है (पृष्ठ ५८ तथा ५९)। यही नहीं, वह इस विचार से झूमने लगते हैं और अपने आनन्दातिरेक को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट करते हैं—

“जमीन का स्वामी बनने की इन्सान में अन्तर्निहित अभिलाषा में कुछ विलक्षणता है; यह ऐसी ललक है जिसे आज के कामकाजी जीवन की आपाधापी कम नहीं कर सकी है। यह आर्थिक उपलब्धि के, जिसका प्रतिनिधित्व भू-स्वामित्व करता है, महत्व की अचेतन अनुभूति है। इसके साथ व्यक्ति सुरक्षित स्थिति हासिल करता है; कह सकते हैं कि उसके पांव धरती पर मजबूती से जम जाते हैं, तथा प्रत्येक उद्यम” (!) “उसमें सबसे स्थायी आधार प्राप्त करता है। परन्तु भू-स्वामित्व के वरदान इन भौतिक लाभों की परिधि से कहीं अधिक व्यापक हैं। जमीन के किसी टुकड़े को अपना कहने का जिस किसी को सौभाग्य प्राप्त है, वह आर्थिक स्वतंत्रता की उच्चतम परिकल्पित मंजिल पर पहुंच चुकता है; उसके पास एक ऐसा भू-क्षेत्र है जिस पर वह प्रभुसत्ताप्राप्त अधिकार के साथ राज कर सकता है; वह स्वयं अपना स्वामी है; उसे कुछ सत्ता उपलब्ध होती है और ज़रूरत पड़ने पर निश्चित समर्थन मिल जाता है; उसका आत्मविश्वास तथा उसके साथ उसकी नैतिक शक्ति बढ़ती है। इसी कारण हमारे समक्ष मौजूद प्रश्न में स्वामित्व का गहन महत्व है... मजदूर को, जो आज आर्थिक जीवन के तमाम उतार-चढ़ावों के प्रहार के सामने असहाय है और अपने मालिक पर निरन्तर आश्रित रहता है, इस अस्थिर स्थिति से कुछ हद तक बचाया जा सकेगा; वह पूंजीपति बन जायेगा और उसकी स्थावर सम्पदा द्वारा उसके लिए उधार हासिल करने की सम्भावनाओं के द्वार खोले जाने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी तथा कार्य अक्षमता के खतरों से उसकी रक्षा की जायेगी। उसे इस तरह सम्पत्तिहीनों की पांतों से ऊपर उठाकर सम्पत्तिधारी वर्ग के बीच पहुंचाया जा सकेगा।” (पृष्ठ ६३)

श्री ज़ाक्स यह मानते प्रतीत होते हैं कि इन्सान मूलतः किसान है, अन्यथा वह हमारे बड़े शहरों के मजदूरों के दिल में जमीन पाने की वह अभिलाषा होने की बात न कहते जिसे और किसी ने उनमें नहीं पाया है। बड़े शहरों के हमारे मजदूरों के लिए स्थानान्तरण की स्वतंत्रता अस्तित्व की प्रथम शर्त है तथा भू-स्वामित्व उनके पांवों पर केवल बेड़ियों का ही काम देगा। उन्हें अपने मकान

दें, उन्हें फिर जमीन से बांध दें, बस इस तरह आप कारखानों के मालिकों द्वारा मजूरी में कटौती का उन द्वारा प्रतिरोध किये जाने की शक्ति को कुचल डालेंगे। कोई भी मजदूर मौका पड़ने पर शायद अपना मकान बेच सकेगा परन्तु बड़ी हड़ताल या आम औद्योगिक संकट की हालत में हड़ताली मजदूरों के सारे मकानों को बाज़ार में विक्री के लिए प्रस्तुत करना पड़ेगा और तब इस कारण उनके ग्राहक ही नहीं मिलेंगे और यदि मिलेंगे भी तो उन्हें उनकी लागत कीमत से कहीं कम पर बेचना पड़ेगा। और यदि उन सब के लिए ग्राहक मिल भी जायें तो श्री जाक्स का सारा महान आवास सुधार मिट्टी में मिल जायेगा तथा उन्हें फिर नये सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। हां, कवि लोग कल्पना लोक में रहते हैं, और श्री जाक्स भी वहीं रहते हैं जो यह कल्पना करते हैं कि भू-स्वामी “आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे ऊंची मंज़िल पर पहुँच चुका है”, कि उसे “निश्चित समर्थन” प्राप्त है, कि वह “पूँजीपति बन जायेगा और उसकी स्थावर सम्पदा द्वारा उसके लिए उधार हासिल करने की सम्भावनाओं के द्वार खोले जाने के परिणामस्वरूप बेरोज़गारी तथा कार्य अक्षमता के खतरों से उसकी रक्षा की जायेगी”, आदि। श्री जाक्स को फ्रांसीसी और स्वयं हमारे राजनी छोटे किसानों पर एक नज़र डालनी चाहिए। उनके मकान तथा खेत रेहनों के बोझ से दबे हुए हैं, उनकी फसलें काटे जाने से पहले ही उधार देनेवालों की हो जाती हैं, और वे नहीं, वरन् सूदखोर, वकील तथा अदालती कारिंदे उनके “भू-क्षेत्र” पर प्रभुसत्ताप्राप्त अधिकार के साथ राज करते हैं। यह यकीनन आर्थिक स्वतंत्रता की—सूदखोर के लिए—उच्चतम परिकल्पित मंज़िल है! और मजदूर अपने छोटे-से मकानों को जल्दी से जल्दी सूदखोर की उसी प्रभुता के अधीन कर सकें, इसके लिए हमारे सदाशयी श्री जाक्स होशियारी से उस उधार की ओर इशारा करते हैं जिसे वे बेरोज़गारी या कार्य अक्षमता के समय नगण्य संरक्षणत्व पर बोझ बनने के बजाय अपनी स्थावर सम्पदा से हासिल कर सकते हैं।

कुछ भी हो, श्री जाक्स ने शुरू में उठाये गये प्रश्न को हल कर डाला है—मजदूर अपना छोटा-सा घर हासिल कर “पूँजीपति बन जाता है”।

पूँजी दूसरों के अदत्त श्रम पर प्रभुत्व होती है। इसलिए मजदूर का छोटा-सा घर तभी पूँजी बन सकता है जब वह उसे तीसरे व्यक्ति को किराये पर देगा और इस तीसरे व्यक्ति से किराये के रूप में उसके श्रम उत्पाद का एक हिस्सा हड़पे। परन्तु ठीक इस तथ्य के कारण कि मजदूर स्वयं मकान में रहता

है, वह मकान उसी तरह पूंजी नहीं बन जाता, जिस तरह कोट ठीक उस क्षण से पूंजी नहीं रह जाता जिस क्षण में उसे दर्जी से खरीदता तथा पहनता हूँ। यह सच है कि एक हजार टेलर के मूल्य के छोटे-से मकान का मालिक सर्वहारा नहीं रह जाता परन्तु श्री ज़ाक्स ही उसे पूंजीपति मान बैठते हैं।

परन्तु हमारे मज़दूर के इस पूंजीवादी रूप का एक और भी पहलू है। आइये, यह मान लें कि किसी औद्योगिक इलाक़े में यह प्रथा है कि प्रत्येक मज़दूर का अपना छोटा-सा मकान है। ऐसी स्थिति में उस इलाक़े का मज़दूर वर्ग बिना किराये दिये रहता है; आवास व्यय अब उसकी श्रम शक्ति के मूल्य में शामिल नहीं होते। परन्तु श्रम शक्ति की उत्पादन लागत में हर कटौती, यानी मज़दूर की जीवनावश्यकताओं की कीमत में प्रत्येक स्थायी कटौती "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त के लौह कानूनों के आधार पर" श्रम शक्ति के मूल्य के ह्रास के समतुल्य होती है और इसलिए अन्ततोगत्वा मजूरी भी उसी अनुपात से घटेगी। इस तरह मजूरी में औसतन गिरावट किराये की मद में बचायी गयी औसत राशि के बराबर होगी, यानी मज़दूर अपने ही मकान के लिए किराया पहले की तरह नक़द रूप में मकान-मालिक को नहीं, वरन् कारख़ाना-मालिक को, जिसके लिए वह काम करता है, अदत्त श्रम के रूप में देता है। इस तरह मज़दूर की बचत, जिसे वह अपने छोटे-से मकान पर लगाता है, एक अर्थ में पूंजी बन जायेगी परन्तु यह पूंजी उसकी नहीं, वरन् उस पूंजीपति की होगी जिसके लिए वह काम करता है।

इस तरह श्री ज़ाक्स में अपने मज़दूर को महज़ काग़ज़ पर भी पूंजीपति बनाने की योग्यता का अभाव है।

प्रसंगतः, जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह उन तमाम तथाकथित सामाजिक सुधारों पर लागू होता है, जो बचत करने या मज़दूर की आजीविका के साधनों को सस्ता बनाने तक सीमित हैं। या तो ये सुधार सर्वव्याप्त हो जाते हैं और फिर मजूरी में सम्बन्धित कमी आती है या फिर वे बिल्कुल इक्के-दुक्के प्रयोग मात्र रह जाते हैं और फिर इक्के-दुक्के अपवादों के रूप में उनका अस्तित्व ही यह सिद्ध करता है कि व्यापक रूप में उनका कार्यान्वयन उत्पादन की वर्तमान पूंजीवादी पद्धति से मेल नहीं खाता। आइये, यह मान लें कि किसी एक इलाक़े में उपभोक्ता सहकारिताओं की आम शुरुआत मज़दूरों के जीवन निर्वाह साधनों की लागत २० प्रतिशत घटाने में सफल हो जाती है। इसलिए उस इलाक़े में अन्ततोगत्वा मजूरी में २० प्रतिशत गिरावट आयेगी, कहने का मतलब है, उसी

अनुपात से जिस अनुपात से जीवन निर्वाह साधन मजदूर के बजट में शामिल होते हैं। यदि मजदूर, उदाहरण के लिए, अपनी साप्ताहिक मजदूरी का तीन-चौथाई भाग इन जीवन निर्वाह साधनों पर खर्च करता है तो मजदूरी में अन्ततः गिरावट $\frac{3}{4} \times 20 = 15$ प्रतिशत के बराबर होगी। संक्षेप में, ज्योंही इस तरह का बचत-सम्बन्धी कोई सुधार सर्वव्याप्त हो जाता है, मजदूर की मजदूरी उसी अनुपात से घट जाती है जिस अनुपात से यह बचत उसे कम खर्च पर गुजर करने देती है। हरेक मजदूर के लिए बचत से हासिल होनेवाली ५२ टेलरों की स्वतंत्र आय की व्यवस्था करें, तो उसकी साप्ताहिक मजदूरी अन्ततः निश्चित रूप से एक टेलर घट जायेगी। इसलिए वह जितनी बचत करेगा, वह उतनी ही कम मजदूरी प्राप्त करेगा। इसलिए वह अपने हित में नहीं, वरन् पूंजीपति के हित में बचत करता है। “उसमें सबसे सशक्त ढंग से... प्राथमिक आर्थिक सद्गुण, मितव्ययिता प्रेरित करने के लिए” और किसी चीज की जरूरत है? (पृष्ठ ६४)

हां, श्री ज़ाक्स इसके फ़ौरन बाद कहते हैं कि मजदूरों को इतना अपने हितार्थ नहीं, जितना पूंजीपतियों के हितार्थ मकान-मालिक बनना चाहिए—

“कुछ भी हो, मजदूर वर्ग की ही नहीं, वरन् समग्र रूप से समाज की भी अपने अधिक से अधिक सदस्यों को भूमि से बंधा” (!) “हुआ देखने में दिलचस्पी है” (मैं श्री ज़ाक्स को कम से कम एक बार इस स्थिति में देखना चाहता हूं) ... “सामाजिक प्रश्न—सर्वहाराओं की कटुता, घृणा... विचारों की खतरनाक उलझन...—नामक ज्वालामुखी को, जो हमारे पांवों तले धधक रहा है, प्रज्वलित सारी गुप्त शक्तियों को, इन सब का प्रभातवेला के सूर्य के उदय से पूर्व कुहासे की तरह उस समय लुप्त हो जाना पड़ेगा जब... स्वयं मजदूर इस तरह सम्पत्तिधारी वर्गों की कतारों में प्रवेश करेंगे।” (पृष्ठ ६५)

दूसरे शब्दों में श्री ज़ाक्स को आशा है कि मकान के हस्तगत होने से अपनी सर्वहारा स्थिति में परिवर्तन होने के साथ-साथ मजदूर अपना सर्वहारा स्वरूप भी छोड़ बैठेंगे तथा इस तरह वे अपने पूर्वजों की तरह—वे भी मकान-मालिक थे—एक बार फिर आज्ञाकारी चाटुकार बन जायेंगे। प्रदोषणियों को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री ज़ाक्स का विचार है कि उन्होंने इस तरह समस्या हल कर डाली है—

“सम्पदा का अधिक न्यायपूर्ण वितरण—नारसिंह का रहस्य जिसे हल करने की कई लोग अब तक विफल चेष्टा कर चुके हैं—क्या यह अब हमारे सामने एक साकार तथ्य के रूप में विद्यमान नहीं है, क्या उसे इस तरह आदर्शों की दुनिया से वास्तविकता की दुनिया में नहीं लाया जा चुका है? और यदि यह किया भी जा चुका है तो क्या इसका अर्थ उच्चतम आदर्शों में से एक की पूर्ति नहीं है, एक ऐसे आदर्श को जिसे सबसे उग्र प्रवृत्ति वाले समाजवादी तक अपने सिद्धान्तों के चरम शिखर के रूप में प्रस्तुत करते हैं?” (पृष्ठ ६६)

यह वास्तव में सौभाग्य की बात है कि हम यहां तक पहुंच गये हैं क्योंकि विजय की यह चीख-चिल्लाहट श्री ज़ाक्स की पुस्तक का “शिखर” है। और यहां से हम फिर “आदर्शों की दुनिया” से धीरे-धीरे नीचे उतरते हुए सपाट मैदान में पहुंचते हैं; जब हम नीचे उतर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बदला है।

हमारे लेखक महाशय हमसे शिखर से नीचे उतरने के लिए पहला पग तब उठाते हैं जब वह हमें सूचित करते हैं कि मजदूरों के घरों की दो किस्म हैं—एक है कुटीर व्यवस्था जिसमें हर मजदूर परिवार एक छोटे-से मकान, यदि सम्भव हुआ तो इंगलैंड की तरह एक छोटे-से बाग़ का मालिक होता है, दूसरी है लम्बी-चौड़ी इमारतों की बैरक व्यवस्था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मजदूरों की कोठरियां होती हैं जैसे पेरिस, वियेना, आदि में। इन दो के बीच उत्तरी जर्मनी में विद्यमान व्यवस्था है। वह हमें बताते हैं—यह सच है कि कुटीर व्यवस्था एकमात्र सही तथा एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए मजदूर अपने आवास का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है; इसके अलावा, उनका तर्क है, बैरक व्यवस्था में स्वच्छता, नैतिकता तथा घरेलू सुख की दृष्टि से बहुत-सी खराबियां हैं। परन्तु अफ़सोस, अफ़सोस! — वह कहते हैं—कुटीर व्यवस्था को बड़े शहरों में, आवासीय कमी वाले केंद्रों में ज़मीन बहुत महंगी होने के कारण मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता, इसलिए यदि बड़े बैरकों की जगह चार से लेकर छः फ़्लैटों वाले मकानों का निर्माण हो सके और यदि निर्माण की विभिन्न कुशल युक्तियों द्वारा बैरक व्यवस्था की मुख्य वृष्टियां मिटायी जा सकें तो इस पर सन्तोष प्रकट करना चाहिए। (पृष्ठ ७१-६२)

परन्तु क्या हम सचमुच काफ़ी नीचे नहीं उतर चुके हैं? मजदूरों का पूंजीपतियों में रूपान्तरण, सामाजिक प्रश्न का समाधान, हर मजदूर के लिए अपना मकान—ये सब चीज़ें तो बहुत ऊपर, “आदर्शों की दुनिया” में छोड़ी

जा चुकी हैं। हमारे लिए बस करने को इतना रह जाता है कि हम देहात में कुटीर व्यवस्था प्रचलित कर दें तथा शहरों में बैरक व्यवस्था को यथासम्भव सहनीय बना दें।

इसलिए स्वयं अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार आवास प्रश्न का पूंजीवादी समाधान शहर और देहात के बीच विरोध के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और यहां हम समस्या के मर्म बिन्दु में पहुंच जाते हैं। आवास प्रश्न तभी हल किया जा सकता है जब समाज का इतना पर्याप्त रूप से रूपान्तरण हो जाये कि शहर तथा देहात के बीच विरोध मिट जाये जिसे वर्तमान पूंजीवादी समाज में चरम बिन्दु पर पहुंचा दिया है। इस विरोध को मिटाना तो रहा दूर, पूंजीवादी समाज उल्टे इसे नित्यप्रति उग्र बनाने के लिए विवश होता है। प्रथम समकालीन कल्पनाविवादी समाजवादी ओवेन तथा फुरिए ने इसे सही ढंग से पहचाना है। उनके प्रादर्श ढांचे में शहर तथा देहात के बीच यह विरोध नहीं रह जाता। फलस्वरूप यहां ठीक श्री ज़ाक्स के दावे के उलट होता है—आवास प्रश्न का समाधान सामाजिक प्रश्न का साथ ही समाधान नहीं करता, बल्कि सामाजिक प्रश्न के समाधान से ही, यानी उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के खात्मे से ही आवास प्रश्न का समाधान सम्भव हो जाता है। आवास प्रश्न के समाधान की अभिलाषा और साथ ही आधुनिक बड़े शहरों को बरकरार रखने की इच्छा वेतुकी चीज़ है। परन्तु आधुनिक बड़े शहरों को केवल उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के खात्मे से ही मिटाया जा सकता है, और एक बार यह काम शुरू हो जाने पर हर मजदूर के लिए एक छोटे-से घर का स्वामित्व प्रदान करने से सर्वथा भिन्न प्रश्न उठ खड़े होंगे।

परन्तु आरम्भ में प्रत्येक सामाजिक क्रान्ति को स्थिति को उसी रूप में ग्रहण करना होगा जिस रूप में वह उन्हें पाती है और अपने पास मौजूद साधनों की मदद से सबसे विकट बुराइयों से निपटना पड़ेगा। और हम पहले ही देख चुके हैं कि सम्पत्तिधारी वर्गों के वैभवपूर्ण निवास स्थानों के एक भाग को हस्तगत कर तथा शेष भाग में ज़बरदस्ती किरायेदार बसाकर आवास की कमी से तत्काल छुटकारा पाया जा सकता है।

यदि श्री ज़ाक्स आगे चलकर फिर बड़े शहरों की विद्यमानता को आधार मानकर अग्रसर होते हैं और शहरों के पास स्थापित होनेवाली मजदूर बस्तियों पर शब्दाडम्बरपूर्ण प्रवचन करने लगते हैं; यदि वह इन बस्तियों के सारे सौन्दर्यों का, उनमें सामुदायिक “जल-व्यवस्था, गैस की रोशनी, हवा या उष्ण जल

तापन, धोबीघर, कपड़े सुखाने के स्थान, स्नानघर, आदि” की व्यवस्था समेत, “शिशु सदन, स्कूल, पूजाघर” (!), “वाचनालय, पुस्तकालय... शराबखाना, बियरघर, हर तरह की सुविधा से युक्त नृत्य तथा संगीत सदन” समेत, भाषाशक्ति की व्यवस्था समेत, जिससे “उत्पादन कारखाने से कुछ हद तक फिर से घरेलू वर्कशाप को स्थानान्तरित किया जा सके”—बखाना करते हैं, तो भी इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। जिस बस्ती का वह वर्णन करते हैं, उसका विचार श्री ह्यूबर द्वारा समाजवादी ओवेन तथा फूरिए से उधार लिया गया है और उसमें जो कुछ समाजवादी है, उसे निकालकर उसे पूरी तरह पूंजीवादी बना दिया गया है। परन्तु इस तरह वह वस्तुतः पूरी तरह कल्पनाविद् बन गया है। इस तरह की बस्तियां स्थापित करने में किसी भी पूंजीपति की कोई दिलचस्पी नहीं होती। सच तो यह है कि फ्रांस में गीज़ को छोड़कर संसार में इस तरह की बस्ती और कहीं है ही नहीं। और गीज़ की उस बस्ती का भी निर्माण फूरिये के अनुयायी ने मुनाफ़ादेह सट्टेबाज़ी के लिए नहीं, वरन् समाजवादी प्रयोग* के लिए किया था। श्री ज़ाक्स अपनी पूंजीवादी परियोजना के पक्ष में ओवेन द्वारा पांचवें दशक के आरम्भ में हैम्पशायर में स्थापित तथा बहुत पहले ही बन्द हो चुकी कम्युनिस्ट बस्ती «Harmony Hall»⁷¹ का उदाहरण दे सकते थे।

कुछ भी हो, बस्तियों का निर्माण करने की ये सारी बातें “आदर्शों की दुनिया” में फिर से उड़ान भरने की दयनीय चेष्टा के अलावा और कुछ नहीं हैं, ऐसी कोशिशें हैं जिन्हें तत्काल पुनः तिलांजलि दे दी जाती है—हम फिर तेज़ी से नीचे लुढ़क जाते हैं। सरलतम समाधान अब यह है

“कि मालिकों, कारखानेदारों को उपयुक्त घर हासिल करने में मजदूरों की मदद करनी चाहिए जिनका वे खुद निर्माण कर सकते हैं अथवा मजदूरों को ज़मीन देकर, निर्माण पूंजी, आदि देकर उन्हें अपने घरों का स्वयं निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन तथा मदद दे सकते हैं।” (पृष्ठ १०६)

*और यह भी अन्ततः मजदूर वर्ग के शोषण का मात्र अड्डा रह गया है। देखें १८८६ का «Socialiste»⁷⁰ नामक पेरिस अख़बार। (१८८७ के संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी)

इसके साथ हम फिर बड़े शहरों से, जहाँ इस तरह की कोई चीज़ होने का सवाल ही नहीं उठता, बाहर निकल आते हैं और फिर से देहात में पहुँच जाते हैं। श्री जाक्स अब सिद्ध करते हैं कि अपने मजदूरों को गुजारे लायक घर हासिल करने में मदद देना स्वयं कारखानेदारों के हित में है क्योंकि एक ओर तो यह अच्छा लाभप्रद पूँजी निवेश है तथा दूसरी ओर अनिवार्य

“परिणाम के रूप में मजदूरों की स्थिति में सुधार के कारण उनकी शारीरिक तथा मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि होगी जो स्वभावतया... मालिकों के लिए कोई कम लाभप्रद नहीं है। इस तरह आवास प्रश्न के समाधान में मालिकों की शिरकत के बारे में सही दृष्टिकोण निर्धारित हो जाता है—यह शिरकत **अप्रत्यक्ष साहचर्य** के परिणाम के रूप में, अपने मजदूरों के शारीरिक और आर्थिक, आत्मिक और नैतिक मंगल-कल्याण के लिए मालिकों की चिन्ता के परिणाम के रूप में प्रकट होती है, ऐसी चिन्ता के रूप में जो अधिकतर मानवीय प्रयासों में छुपी होती है और जो अपने सफल परिणामों के रूप में स्वयं एक आर्थिक पुरस्कार है। ये परिणाम हैं—अध्यवसायी, कुशल, तत्पर, सन्तुष्ट तथा **निष्ठावान** मजदूरों का तैयार होना और क़ायम रहना। (पृष्ठ १०८)

“अप्रत्यक्ष साहचर्य” शब्द, जिनकी सहायता से ह्यूबर इस पूँजीवादी-लोकोपकारी बकवास में “उदात्त महत्व” का समावेश करने का प्रयत्न करते थे, स्थिति में लेशमात्र परिवर्तन नहीं लाते। इन शब्दों के बिना भी देहाती क्षेत्रों में, खास तौर पर इंग्लैंड में बड़े कारखानेदारों ने बहुत पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि मजदूरों के लिए आवास का निर्माण आवश्यकता मात्र, स्वयं कारखाने की विरचना का भाग मात्र ही नहीं है, वह तो बहुत अच्छी आय भी दिलाता है। इंग्लैंड में पूरे के पूरे गाँव इसी तरह प्रकट हुए हैं और आगे चलकर उनमें से कुछ विकसित होते हुए शहर बन गये हैं। परन्तु मजदूरों ने लोकोपकारी पूँजीपतियों का कृतज्ञ होने के बजाय इस “कुटीर व्यवस्था” पर सदैव बहुत आपत्ति की है। चूँकि कारखानेदारों के कोई प्रतियोगी नहीं हैं, इसलिए मजदूरों को इन मकानों के लिए मुंहमांगी क़ीमत ही नहीं चुकानी पड़ती अपितु इकतल शुरू होते ही वे बेघरबार हो जाते हैं क्योंकि कारखानेदार उन्हें बिना किसी कठिनाई के अपने मकानों से बाहर निकाल देता है और इस तरह किसी भी तरह का प्रतिरोध बहुत कठिन बना देता है। ‘इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति’ नामक मेरी पुस्तक के पृष्ठ २२४ तथा २२८ पर विवरण पढ़ने को मिल

सकते हैं। परन्तु श्री ज़ाक्स का ख़याल है कि इन आपत्तियों का “खंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है” (पृष्ठ १११)। और क्या वह मज़दूर को अपने छोटे-से घर का मालिक नहीं बनाना चाहते? यकीनन वह ऐसा चाहते हैं, परन्तु चूँकि “मालिकों को सदैव ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह घर ख़ाली करा सकें ताकि वे जब किसी मज़दूर को बर्खास्त कर दें तो उसके स्थान पर रखे जानेवाले दूसरे मज़दूर को रहने के लिए घर दे सकें”, इसलिए “स्वामित्व के ख़ात्मे के क़रार की व्यवस्था करने के अलावा” और कोई चारा नहीं रह जाता* (पृष्ठ ११३)

इस बार हम अप्रत्याशित शीघ्रता के साथ नीचे उतरे हैं। पहले यह कहा गया था कि मज़दूर के पास अपने घर के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। फिर हमें सूचित किया गया कि यह शहरों में असम्भव है और उसे केवल देहांत में ही पूरा किया जा सकता है। और अब हमें बताया जाता है कि देहांत में भी स्वामित्व “क़रार द्वारा ख़त्म किया जा सकता है”! मज़दूरों के लिए श्री ज़ाक्स द्वारा खोजे गये स्वामित्व के इस नये तरीक़े के साथ, मज़दूरों के पूंजीपतियों में इस रूपान्तरण के साथ, जिसे “क़रार द्वारा ख़त्म किया जा सकता है”, हम फिर सुख-चैन से चौरस मैदान में पहुंच गये हैं और अब हमें यहां इस बात की जांच करनी है कि पूंजीपतियों तथा अन्य लोकोपकारियों ने आवास प्रश्न को हल करने के लिए वस्तुतः क्या किया है।

* इस मामले में भी अंग्रेज़ पूंजीपतियों ने श्री ज़ाक्स की तमाम संजोयी हुई इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं की, वरन् कहीं अधिक अधिपूर्ति भी की। सोमवार, १८ अक्टूबर १८७२ को संसदीय निर्वाचकों की सूचियों पर निर्णय देनेवाली मोरपेथ अदालत को संसदीय मतदाताओं की सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिए २,००० खान-मज़दूरों की अर्ज़ों पर निर्णय देना पड़ा। पता चला कि इन खान-मज़दूरों में से अधिकतर उन खानों के, जिनमें वे काम करते थे, अधिनियमों के अनुसार उनके घरों के किरायेदार नहीं, बल्कि वहां दया पर टिके हुए लोग माने जा सकते थे, जहां से उन्हें कोई नोटिस दिये बिना किसी भी समय वेदख़ून किया जा सकता था (खान-मालिक तथा मकान-मालिक स्वभावतया एक ही व्यक्ति हुआ करता था)। अदालत ने फ़ैसला दिया कि ये लोग किरायेदार नहीं, वरन् नौकर थे और इसलिए उन्हें मतदाताओं की सूची में शामिल होने का अधिकार नहीं था (*«Daily News»*, १५ अक्टूबर १८७२)। (एंगेल्स की टिप्पणी)

यदि हमारे डा० जाक्स की बात पर विश्वास कर लिया जाये तो फिर ये सज्जन, पूंजीपति आवास की कमी को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं और यह प्रमाणित हो चुका है कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के आधार पर आवास प्रश्न हल किया जा सकता है।

सर्वप्रथम श्री जाक्स हमारे सामने... बोनापार्टपंथी फ्रांस की मिसाल रखते हैं! जैसा कि सुविदित है, लूई बोनापार्ट ने पेरिस विश्व प्रदर्शनी के समय प्रकटतया फ्रांस में मेहनतकश वर्गों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए परन्तु वास्तव में साम्राज्य की स्तुति के हेतु उनकी स्थिति को परमानन्दपूर्ण बताने के लिए एक आयोग स्थापित किया था और इसी आयोग की, जिसे बोनापार्टपंथ के सबसे भ्रष्ट ताबेदारों को लेकर गठित किया गया था, रिपोर्ट का श्री जाक्स विशेष रूप से इसलिए जिक्र करते हैं कि उसके कार्य के परिणाम “अधिकृत आयोग के अपने बयान के अनुसार फ्रांस के लिए परिपूर्ण हैं”! और ये परिणाम क्या हैं? ८६ बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों या ज्वायंट स्टॉक कंपनियों में से, जिन्होंने सूचना मुहैया की, ३१ ने मजदूरों के लिए कोई वस्ती बनायी ही नहीं थी। श्री जाक्स के अपने अनुमानानुसार निर्मित घरों में मुश्किल से ५०-६० हजार लोग रहते हैं और उनमें से प्रायः विशुद्ध रूप से ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक परिवार के पास दो से ज्यादा कमरे नहीं हैं!

यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक पूंजीपति को, जो अपने उद्योग की परिस्थितियों—जल-आपूर्ति, कोयला खानों, खनिज लोहे के निक्षेपों, दूसरी खानों की अवस्थिति, आदि—के कारण विशेष देहाती इलाक़ों से आवद्ध होते हैं, अपने मजदूरों के लिए घर बनाने पड़ेंगे यदि वे उपलब्ध न हों। इसमें “अप्रत्यक्ष साहचर्य” का सबूत, “प्रश्न के बारे में बढ़ती हुई समझदारी और उसके व्यापक अर्थ का ज्वलन्त प्रमाण” और “बहुत ही आशादायी शुरुआत” (पृष्ठ ११५) देखने के लिए जरूरी है कि अपने को धोखा देने की आदत बहुत ही विकसित हो। वैसे भिन्न-भिन्न देशों के उद्योगपति इस मामले में भी अपने राष्ट्रीय शक्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न हैं। उदाहरण के लिए श्री जाक्स हमें सूचित करते हैं (पृष्ठ ११७) —

“इंग्लैंड में इस दिशा में मालिकों की गतिविधियों में वृद्धि अभी बिल्कुल हाल में दृष्टिगोचर हुई है। यह बात खासकर देहाती इलाक़ों में दूर-दूर बसी

वस्तियों पर लागू होती है... मालिकों को अपने मजदूरों के लिए आवास का निर्माण करने की मुख्य प्रेरणा देनेवाली परिस्थिति यह है कि आवास न होने पर उन्हें निकटतम गांव से शहर तक पहुंचने के लिए अक्सर बहुत लम्बा सफ़र तय करना पड़ता है तथा काम पर पहुंचने तक वे इतने थक चुके होते हैं कि वे पर्याप्त कार्य नहीं कर पाते। परन्तु जिन लोगों में परिस्थितियों की गहरी समझदारी है और जो आवास सुधार के ध्येय के साथ अप्रत्यक्ष साहचर्य के न्यूनाधिक सभी तत्वों को मिलाते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है तथा ये ही वे लोग हैं जो इन फूलती-फलती वस्तियों की स्थापना के लिए श्रेय के पात्र हैं... इस मामले में हाइड में एशटन, टुर्टन में एशवर्थ, बरी में ग्रांट, बोलिंगटन में ग्रेग, लीड्स में मार्शल, बेलपेर में स्ट्रट, साल्टायर में साल्ट, कोप्ले में आकरायड, आदि अन्य लोगों के नाम पूरे यूनाइटेड किंगडम में सुविदित हैं”।

धन्य है यह भोलापन, उससे भी ज्यादा धन्य है यह अज्ञान! देहातों के अंग्रेज कारखानेदारों ने “अभी बिल्कुल हाल में” मजदूर वस्तियों का निर्माण करना शुरू किया है! जो नहीं, मेरे प्रिय श्री जाक्स, अंग्रेज पूंजीपति अपनी थैलियों के ही नहीं, बरन् अपने दिमाग के मामले में भी सचमुच बड़े उद्योगपति हैं। जर्मनी में वास्तव में बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना से बहुत पहले ही इन लोगों ने अनुभव कर लिया था कि देहाती इलाकों में कारखानों में उत्पादन के लिए मजदूरों के आवास पर खर्चा पूंजी के कुल निवेश का आवश्यक भाग है तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूप में बहुत लाभप्रद भी है। बिस्मार्क तथा जर्मन पूंजीपति वर्ग के बीच संघर्ष द्वारा जर्मन मजदूरों को संघबद्धता की स्वतंत्रता दिये जाने से बहुत पहले ही अंग्रेज कारखानेदारों, खानों तथा फ़ाउंड्रियों के मालिकों ने यह व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर लिया था कि यदि वे साथ ही अपने मजदूरों के मकान-मालिक भी हों तो वे हड़ताली मजदूरों पर किस तरह दबाव डाल सकते हैं। ग्रेग, एशटन और एशवर्थ जैसे लोगों की “फूलती-फलती वस्तियां” इतनी “हाल की” हैं कि ४० साल पहले ही पूंजीपति वर्ग ने उन्हें आदर्श बनाकर उनका गुणगान किया था और स्वयं मैंने २८ वर्ष पहले यह बात लिखी थी (‘इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति’। टिप्पणी, पृष्ठ २२८-२३०)। मार्शल तथा आकरायड (Akroyd—वह अपना नाम इसी तरह लिखते हैं) की वस्तियां उतनी ही पुरानी हैं तथा स्ट्रट की बस्ती तो और भी पुरानी है जिसकी गत शताब्दी में] शुरुआत हुई थी। चूंकि इंग्लैंड में मजदूर बस्ती की औसत उम्र ४० वर्ष आंकी जाती है, श्री जाक्स इन “फूलती-फलती वस्तियों की” आज की

जीर्णविस्था का हिसाब अपनी उंगलियों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन बस्तियों में से अधिकांश अब देहात में भी नहीं रह गये हैं। उद्योगों के अपरिमित विस्तार ने उन्हें चारों ओर से कारखानों तथा मकानों से इस तरह घेर डाला है कि वे अब २०-३० हजार या इससे भी ज्यादा निवासियों वाले गन्दे, धुएँदार शहरों के बीचोंबीच आ गये हैं। परन्तु यह सब जर्मन पूंजीवादी विज्ञान को, जिसका प्रतिनिधित्व श्री ज़ाक्स करते हैं, १८४० के अंग्रेज़ स्तुतिगानों की, जिनका आजकल के तथ्यों से कोई मेल नहीं रह गया है, अब भी निष्ठापूर्वक पुनरावृत्ति करते रहने से नहीं रोक पाता।

और रही हमारे समक्ष वृद्ध आकरायड के उदाहरण की बात। यह प्रशंसनीय महानुभाव निस्सन्देह उत्कृष्ट लोकोपकारी थे। वह अपने मजदूरों से, खास तौर पर अपनी मजदूरियों से इस हद तक प्यार करते थे कि यार्कशायर में उनके कम लोकोपकारी प्रतियोगी उनके बारे में कहा करते थे कि उनके कारखाने में विशुद्धतः उनकी सन्तान काम करती है! परन्तु श्री ज़ाक्स का दावा है कि इन दिनों इन फूलती-फलती बस्तियों में “नाजायज़ सन्तान उत्तरोत्तर कम होती जा रही है” (पृष्ठ ११८)। जी हाँ, बिना विवाह के जन्मी नाजायज़ सन्तान—बात यह है कि अंग्रेज़ औद्योगिक ज़िलों में ख़ूबसूरत लड़कियाँ बहुत कम उम्र में विवाह कर लेती हैं।

इंगलैंड में प्रत्येक बड़े देहाती कारखाने के समीप तथा साथ ही कारखाने के साथ मजदूरों की बस्तियों की स्थापना ६० तथा इससे भी अधिक वर्षों से एक आम परिपाटी रही है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कारखानों वाले इन देहातों में बहुत-से ऐसे केन्द्र बिन्दु बन गये हैं जिनके इर्दगिर्द आगे चलकर कारखानों वाले शहर उन तमाम बुराइयों के साथ विकसित हुए हैं जो हर किसी कारखाने वाले शहर के साथ आती हैं। इसलिए इन बस्तियों ने आवास प्रश्न हल नहीं किया है; इसके विपरीत उन्होंने अपने भूक्षेत्रों में इस प्रश्न को वस्तुतः सबसे पहले जन्म दिया।

दूसरी ओर, फ़्रांस में, खास तौर पर जर्मनी में, उन देशों में स्थिति सर्वथा भिन्न है जो बड़े पैमाने के उद्योग के क्षेत्र में केवल इंगलैंड के पीछे-पीछे अपने पाँच घसीटते हुए आगे बढ़े थे तथा जिन्हें वस्तुतः १८४८ के बाद ही पता चला कि बड़े पैमाने का उद्योग क्या होता है। यहां केवल विशाल धातुकर्म कारखानों तथा फ़ैक्टरियों ने—उदाहरण के लिए क्रेज़ो में शेड्डेर कारखाने तथा एस्सेन में कारखाने ने—काफ़ी हिचकिचाहट के बाद कुछ मजदूर बस्तियों का निर्माण

करने का निर्णय किया था। देहातों में उद्योगपतियों की भारी बहुसंख्या को इससे कोई मतलब नहीं था कि उनके मजदूर रोज़ गर्मी, बर्फ़ तथा वर्षा में अपने घर तथा कारख़ाने के बीच मीलें पैदल चलते हैं। यह बात ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाक़ों पर—फ़्रेंच तथा अल्प्सशिथन वोगेज़, वुप्पेर, जीग, आग्नेर, लेन्ने तथा अन्य राइनी-वेस्टफ़ालियई नदी घाटियों पर—लागू होती है। एर्ज़गेविर्ग में भी शायद स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। जर्मनों तथा फ़्रांसीसियों दोनों के बीच भी वही टुच्ची किस्म की कंजूसी दिखायी देती है।

श्री ज़ाक्स ख़ूब अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत ही आशादायी शुरुआत और साथ ही फूलती-फलती बस्तियों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अब वह पूंजीपतियों के सामने यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि वे मजदूरों की बस्तियों का निर्माण करके मनचाहा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह उन्हें मजदूरों को ठगने का एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं।

सर्वप्रथम, वह उनके सामने लन्दन की अनेक भवन निर्माण सोसायटियों का—अंशतः लोकोपकारी तथा अंशतः सट्टेबाज़—उदाहरण रखते हैं जिन्होंने ४ से लेकर ६ प्रतिशत और उससे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है। श्री ज़ाक्स के लिए हमारे सामने यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण पर पूंजी निवेश अच्छा मुनाफ़ा देता है। यदि पूंजीपति मजदूरों की बस्तियों के निर्माण पर उससे ज़्यादा धन नहीं लगाते जितना वे लगा रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि अधिक महंगे मकानों से उनके मालिकों को और भी ज़्यादा मुनाफ़ा मिलता है। अतः पूंजीपतियों को श्री ज़ाक्स जो नसीहत देते हैं, वह नैतिक प्रवचन के अलावा और कुछ नहीं है।

जहाँ तक लन्दन की इन भवन निर्माण सोसायटियों का सम्बन्ध है जिनकी शानदार सफलताओं का श्री ज़ाक्स इतने जोरों से ढोल पीटते हैं, तो उन्होंने स्वयं श्री ज़ाक्स के आंकड़ों के अनुसार—और यहाँ उन्होंने भवन निर्माण में हर तरह की सट्टेबाज़ी को शामिल किया है—कुल मिलाकर २,१३२ परिवारों तथा ७०५ अकेले पुरुषों को, याने १५,००० से कम व्यक्तियों को आवास मुहैया किया है! और क्या इस तरह के उपहासास्पद बचकानेपन को जर्मनी में बहुत बड़ी सफलता के रूप में प्रस्तुत करने की बात संजीदगी के साथ सोची जा रही है हालांकि लन्दन के अकेले ईस्ट एंड में दस लाख मजदूर आवास की घोर दयनीय अवस्थाओं में रहते हैं! ये सारी लोकोपकारी चेष्टाएँ इतनी बुरी तरह निरर्थक हैं कि मजदूरों

की हालत से सरोकार रखनेवाली अंग्रेज संसदीय रिपोर्टें उनकी कभी चर्चा तक नहीं करतीं।

हम यहां लन्दन के बारे में उपहासास्पद अज्ञान की बात नहीं करेंगे जिसका इस पूरे अनुभाग में परिचय दिया गया है। पर केवल एक मुद्दे की चर्चा करेंगे। श्री जाक्स की राय है कि सोहो में अकेले पुरुषों के रैन-बसेरों का अस्तित्व इसलिए खत्म हुआ कि इस इलाके में “बड़ी संख्या में ग्राहक मिलने की कोई आशा नहीं थी”। श्री जाक्स कल्पना करते हैं कि लन्दन का पूरा वेस्ट एंड एक बड़ा वैभवशाली नगर है। उन्हें पता ही नहीं है कि सबसे शालीन सड़कों के ठीक पीछे मजदूरों के सबसे गन्दे इलाके हैं जिनमें उदाहरण के लिए सोहो एक है। सोहो के आदर्श रैन-बसेरे में, जिसकी श्री जाक्स चर्चा करते हैं तथा जिसकी मुझे २३ वर्ष पूर्व ही जानकारी थी, शुरू-शुरू में बहुत लोग रहने के लिए जाते थे, परन्तु वह इसलिए बन्द हो गया कि एक भी व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाता था। और ध्यान रहे, यह घर सर्वोत्तम घरों में से एक था।

परन्तु अल्सास में मजदूरों की म्युलहाउसेन बस्ती—यह वस्तुतः सफलता नहीं है क्या ?

म्युलहाउसेन में मजदूरों की बस्ती महाद्वीपीय पूंजीपतियों के लिए उसी तरह प्रदर्शनयोग्य तथा गौरव की वस्तु है जिस तरह एक जमाने की एशटन, एशवर्थ, ग्रेग एंड कम्पनी की “फूलती-फलती बस्तियां” अंग्रेज पूंजीपतियों के लिए थीं। दुर्भाग्यवश म्युलहाउसेन बस्ती का उदाहरण “अप्रत्यक्ष” साहचर्य की नहीं अपितु फ्रांसीसी द्वितीय साम्राज्य तथा अल्सास पूंजीपतियों के बीच खुले साहचर्य की देन है। यह लुई बोनापार्ट के समाजवादी प्रयोगों में से एक थी जिसके लिए राज्य ने एक-तिहाई पूंजी उधार दी। १४ वर्षों में (१८६७ तक) ८०० छोटे-छोटे मकान एक ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली के अनुसार बनाये गये, जो लन्दन में असम्भव होती जहां लोग इन चीजों को बेहतर समझते हैं; ये मकान मजदूरों को दे दिये जाते हैं जो अतिरिक्त किराये की मासिक अदायगी करते रहने पर १३ से १५ वर्ष के बाद उनके मालिक बन जाते हैं। अल्सास के बोनापार्टपंथियों के लिए सम्पत्ति हासिल करने की यह विधि गढ़ने की जरूरत नहीं थी; जैसा कि हम देखेंगे, भ्रष्टाचार की सहकारी भवन निर्माण सोसायटियां इसे बहुत पहले लागू कर चुकी थीं। इंग्लैंड की तुलना में इन मकानों की खरीद के लिए अदा किया जानेवाला किराया काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए १५ वर्षों में ४,५०० फ्रांक किस्तों में अदा करने के बाद मजदूर को जो मकान मिलता है, उसकी कीमत १५ वर्ष

पूर्व ३,३०० फ्रांक थी। यदि मजदूर कहीं और जाना चाहता है या उस पर एक भी मासिक किश्त बकाया है (इस सूरत में उसे बेदखल किया जा सकता है) तो मकान के मूल मूल्य का $६\frac{२}{३}$ प्रतिशत वार्षिक किराये के रूप में (उदाहरण के लिए ३,००० फ्रांक के मूल्य के मकान के लिए १७ फ्रांक प्रति माह) वसूल किया जाता है और बाकी धन एक कौड़ी ब्याज दिये बिना उसे लौटा दिया जाता है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में सोसायटी “राजकीय सहायता” के बिना भी खूब फूलती-फलती है। यह भी सर्वथा स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में मुहैया किये जानेवाले घर स्वयं शहरों के अन्दर पुराने बैरक जैसे घरों से यदि और किसी बजह से नहीं तो केवल इसलिए बेहतर हैं कि वे शहर के बाहर अर्द्ध देहाती इलाक़ों में निर्मित किये गये हैं।

हमें जर्मनी में किये गये चन्द दयनीय प्रयोगों के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है; स्वयं श्री जाक्स ने पृष्ठ १५७ पर उनकी तुच्छता स्वीकार की है।

तो फिर ये उदाहरण वस्तुतः क्या साबित करते हैं? महज यह कि स्वच्छता के सारे क़ानून पैरों तले न रौंदे जाने के बाद भी मजदूरों के लिए घरों का निर्माण पूंजीवादी दृष्टिकोण से लाभप्रद होता है। परन्तु इस बात से तो कभी इन्कार नहीं किया गया, हम सब को यह बहुत पहले से मालूम था। विवेक सम्मत ढंग का कोई भी पूंजी निवेश, जो विद्यमान आवश्यकता की पूर्ति करता है, लाभप्रद होता है। परन्तु सवाल तो ठीक यही है कि आवास की कमी फिर भी क्यों बनी रहती है; पूंजीपति मजदूरों के लिए पर्याप्त रूप से स्वास्थ्यप्रद आवास की क्यों व्यवस्था नहीं करते? और श्री जाक्स के पास पूंजी को फिर नसीहत देने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है और वह हमें उत्तर देने में विफल रहते हैं। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर हम ऊपर दे चुके हैं।

पूंजी यदि आवास की कमी को मिटा भी सकती, वह उसे मिटाना नहीं चाहती; यह अब अन्तिम रूप से सिद्ध हो चुका है। इसलिए केवल दो रास्ते रह जाते हैं—मजदूरों द्वारा आत्म-सहायता तथा उन्हें राजकीय सहायता।

आत्म-सहायता के उत्कट आराधक श्री जाक्स आवास प्रश्न के क्षेत्र में भी इसके चमत्कारों का वर्णन करते हैं। दुर्भाग्यवश वह ठीक शुरू में ही यह मानने के लिए विवश होते हैं कि आत्म-सहायता वहीं कुछ कर सकती है जहां कुटीर व्यवस्था या तो पहले से ही विद्यमान हो या जहां वह सम्भव हो, याने वह केवल देहाती क्षेत्रों में कुछ कर सकती है। बड़े शहरों में, यहां तक कि इंग्लैंड में भी यह बहुत ही सीमित रूप में कारगर हो सकती है। श्री जाक्स फिर गहरी सांस लेते हैं—

“इस तरह” (आत्म-सहायता से) “सुधार केवल चक्करदार रास्ते से ही और इसलिए हमेशा आंशिक रूप में याने केवल उसी हद तक लागू किया जा सकता है जिस हद तक निजी स्वामित्व का सिद्धान्त इतना सशक्त हो जाये कि वह मकानों की गुणवत्ता पर असर डाल सके।”

यह भी सन्देहास्पद है; खैर कुछ भी हो, “निजी स्वामित्व के सिद्धान्त” ने लेखक की शैली की “गुणवत्ता” पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। इस सब के बावजूद इंग्लैंड में आत्म-सहायता ने ऐसे चमत्कार किये हैं “कि आवास प्रश्न को हल करने के लिए अन्य तरीकों के साथ इसकी बदौलत कहीं ज्यादा हासिल हुआ है”। श्री जाक्स अंग्रेज “भवन निर्माण सोसायटियों” का जिक्र कर रहे हैं तथा उन पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालते हैं, खास तौर पर इसलिए कि

“उनके स्वरूप तथा सामान्यतया उनकी गतिविधियों के विषय में बहुत अपर्याप्त अथवा गलत विचार प्रचलित हैं। अंग्रेज भवन निर्माण सोसायटियां कदापि... भवन निर्माण संघ अथवा भवन निर्माण सहकारिताएं नहीं हैं; उनके लिए... जर्मन भाषा में Hausarwerbvereine (मकान हासिल करनेवाले संघ) जैसे शब्द का उपयोग किया जा सकता है। वे ऐसे संघ हैं जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के मीयादी चन्दों से कोष जमा करना होता है ताकि फिर इन चन्दों से तथा उनकी राशि के अनुसार अपने सदस्यों को मकान खरीदने के लिए उधार दिये जा सकें... भवन निर्माण सोसायटी इस तरह अपने सदस्यों के एक भाग के लिए बचत बैंक तथा दूसरे भाग के लिए उधार बैंक है। भवन निर्माण सोसायटियां इसलिए रेहन उधार संस्थान हैं जो मुख्यतया... मजदूरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनायी गयी हैं, जो मुख्य रूप से... जमाकर्ता जैसे एक ही सामाजिक हैसियत वाले लोगों को मकान खरीदने या बनाने में मदद देने के लिए मजदूरों की बचत को... इस्तेमाल करती हैं। जैसा कि स्पष्ट है, इस तरह के उधार सम्बन्धित स्थावर सम्पदा को रेहन पर रखकर और इस शर्त पर दिये जाते हैं कि उनकी अदायगी थोड़े-थोड़े समय के अन्तर से किश्तों में की जायेगी जिनमें व्याज तथा विमोचन की राशि मिली होगी... व्याज जमाकर्ताओं को नहीं दिया जाता, वरन् हमेशा उनके खाते में चक्रवृद्धि व्याज के साथ जमा कर दिया जाता है... सदस्य एक महीने का नोटिस देकर जब चाहें, अपनी जमा की हुई धनराशि को व्याज के साथ लौटाने की मांग कर सकते हैं” (पृष्ठ १७०-१७२)। “इंग्लैंड में इस तरह की दो हजार से अधिक सोसायटियां हैं... उन द्वारा संचित कुल पूंजी लगभग डेढ़ करोड़ पाँड़ है। इस तरह लगभग एक लाख मजदूर परिवारों को अपना घरबार मिल गया है—यह ऐसी सामाजिक उपलब्धि है जिसकी यकीनन कोई दूसरी मिसाल नहीं है”। (पृष्ठ १७४)

दुर्भाग्यवश, यहां भी “परन्तु” शब्द लंगड़ाते हुए फ़ौरन सामने आ जाता है—

७

“परन्तु समस्या का सर्वांगपूर्ण समाधान इस तरह कदापि हासिल नहीं हुआ है, यदि और किसी कारण नहीं तो कम से कम इस कारण कि मकान हासिल करना केवल बेहतर स्थितिवाले मजदूरों के बूते की चीज है... खास तौर पर स्वच्छता की अवस्थाओं को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता।” (पृष्ठ १७६)

महाद्वीप में “इस तरह के संघों के लिए... विकास की कम ही गुंजाइश है”। वे कुटीर व्यवस्था की पूर्वकल्पना करते हैं जो केवल देहात में मौजूद होती है; और देहात में मजदूर अभी आत्म-सहायता के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं। दूसरी ओर, शहरों में, जहां वास्तविक भवन निर्माण सोसायटियां बनायी जा सकती हैं, उन्हें “विभिन्न प्रकार की बहुत ज्यादा कठिनाइयों का” सामना करना पड़ रहा है (पृष्ठ १७६)। वे केवल कुटीरों का निर्माण कर सकती हैं और बड़े शहरों में इससे काम नहीं चलेगा। संक्षेप में, “सहकारी आत्म-सहायता का यह रूप वर्तमान परिस्थितियों में—और शायद निकट भविष्य तक में—हमारे सामने खड़ी समस्या के समाधान में मुख्य भूमिका अदा” नहीं कर सकता। बात यह है कि ये भवन निर्माण सोसायटियां “अब भी अपनी अविकसित मंजिल” में हैं। “यही बात इंग्लैंड पर भी लागू होती है।” (पृष्ठ १८१)

इसलिए पूंजीपति नहीं चाहते तथा मजदूर नहीं कर सकते। इसके साथ हम इस भाग को यहीं खत्म कर देते यदि अंग्रेज भवन निर्माण सोसायटियों के बारे में, जिन्हें शुल्ज़े-डेलिच मार्का पूंजीपति हमारे मजदूरों के सामने हमेशा आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते रहते हैं, थोड़ी सूचना देना निहायत जरूरी न हो जाता।

ये भवन निर्माण सोसायटियां मजदूरों की सोसायटियां कदापि नहीं हैं और मजदूरों को मकान मुहैया करना भी उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऐसा अपवादस्वरूप ही होता है। ये भवन निर्माण सोसायटियां मूलतः सट्टेबाज स्वरूप वाले संगठन हैं, यही बात छोटी सोसायटियों पर, जो आरम्भिक सोसायटिया थीं, और उनकी नक़ल करनेवाली बड़ी सोसायटियों पर भी लागू होती है। किसी जलपान गृह में, आम तौर पर उसके मालिक की पहल पर, जिसके यहां आगे चलकर साप्ताहिक बैठकें होती हैं, नियमित ग्राहक और उनके दोस्त, दुकानदार, दफ़्तरों के क्लर्क, सफ़री एजेंट, छोटे दस्तकार तथा दूसरे छोटे पूंजीपति—कभी-

कभार शायद कोई मिस्तरी या कोई अन्य मजदूर जो अपने वर्ग के अभिजाततंत्र का सदस्य हो—आपस में मिलते हैं और भवन निर्माण सहकारी सोसायटी की स्थापना कर देते हैं। आम तौर पर तात्कालिक कारण यह होता है कि जलपान गृह के मालिक को आस-पड़ौस या कहीं और सस्ती जमीन का पता चल जाता है। अधिकांश सदस्यों का व्यवसाय ऐसा होता है कि वे किसी स्थान विशेष से बंधे नहीं होते। यही नहीं, बहुत-से दुकानदारों तथा दस्तकारों के शहर में केवल अपने कारोबार केन्द्र होते हैं, वहाँ उनका अपना निवास नहीं होता। जिस किसी में सामर्थ्य हो, वह धुण्डार शहर के बीचोंबीच रहने के बजाय उपनगरों में रहना चाहता है। भवन निर्माण के लिए जमीन खरीद ली जाती है तथा उस पर जितने सम्भव हों, उतने घरों का निर्माण कर लिया जाता है। अधिक समृद्ध सदस्यों के उधार से खरीद सम्भव हो जाती है और चन्द छोटे-छोटे उधारों के साथ साप्ताहिक चन्दों से निर्माण की साप्ताहिक लागत की पूर्ति की जाती है। जिन सदस्यों का उद्देश्य अपने लिए घर प्राप्त करना होता है, उन लोगों को मकानों का निर्माण पूरा होते ही मकान लाटरी डालकर दे दिये जाते हैं तथा निश्चित अतिरिक्त किराया खरीद-क्रीमत चुकाने का काम देता है। बाकी मकान तब या तो किराये पर उठा दिये जाते हैं या बेच दिये जाते हैं। भवन निर्माण सोसायटी का कारोबार यदि बहुत अच्छा होता है तो वह कमोबेश काफ़ी बड़ी धनराशि संचित कर लेती है। यह सदस्यों की सम्पत्ति बनी रहती है बशर्ते वे चन्दा देते रहें, उसे समय-समय पर अथवा सोसायटी के भंग होने पर सदस्यों के बीच बांट दिया जाता है। यह है दस में से नौ अंग्रेज़ भवन निर्माण सोसायटियों का इतिहास। बाकी अधिक बड़ी सोसायटियाँ होती हैं, जो कभी-कभी राजनीतिक अथवा लोकोपकारी बहानों की आड़ में स्थापित की जाती हैं परन्तु अन्ततः उनका लक्ष्य यही रह जाता है कि स्थावर सम्पदा की सट्टेबाजी के जरिए निम्नपूंजीपति वर्ग की बचतों के लिए ब्याज की अच्छी दर तथा लाभांशों की सम्भावना से बेहतर बन्धक निवेश सुनिश्चित किया जाये।

ये सोसायटियाँ किस तरह के ग्राहकों को ध्यान में रखती हैं, इसे उनमें से एक के प्रोस्पेक्ट में देखा जा सकता है जो यदि सबसे बड़ी नहीं तो सबसे बड़ी सोसायटियों में से एक जरूर है। बिक्रिबेक बिल्डिंग सोसायटी, २६ तथा ३०, साउथहैम्पटन बिल्डिंग्स, चांसरी लेन, लन्दन, जिसकी अपनी स्थापना से लेकर अब तक सकल प्राप्त राशि १,०५,००,००० पाँड (७,००,००,००० टेलर) से ज्यादा है, जिसकी बैंक में या सरकारी सिक्यूरिटियों में जमा राशि ४,१६,०००

पौंड से ज्यादा है और जिसके पास इस समय २१,४४१ सदस्य तथा जमाकर्ता हैं, अपना परिचय निम्नलिखित ढंग से देती है—

“बहुत-से लोग पियानो निर्माताओं की तथाकथित तीनवर्षीय प्रणाली से परिचित हैं जिसके अन्तर्गत तीन वर्ष के लिए पियानो किराये पर लेनेवाला व्यक्ति इस मीयाद के खत्म होने पर उसका मालिक बन जाता है। इस प्रणाली के प्रचलित होने से पूर्व सीमित आय वाले लोगों के लिए अच्छा पियानो हासिल करना उतना ही कठिन होता था जितना कठिन अपने लिए मकान हासिल करना होता था। इस तरह के लोग वर्ष प्रति वर्ष पियानो का किराया चुकाते जाते थे और पियानो की कीमत से दुगुनी या तिगुनी ज्यादा राशि खर्च कर बैठते थे। जो बात पियानो पर लागू होती है, वही मकान पर भी लागू होती है... परन्तु चूंकि मकान की कीमत पियानो से ज्यादा होती है... क्रय-मूल्य चुकाने में अधिक समय लगता है। इस कारण डायरेक्टरों ने लन्दन के विभिन्न भागों तथा उसके उपनगरों में मकान-मालिकों के साथ एक करार किया है जिसके बल पर डायरेक्टर बिक्रिबेक बिल्डिंग सोसायटी के सदस्यों तथा अन्य लोगों के सामने नगर के सर्वथा भिन्न-भिन्न भागों में ऐसे नाना प्रकार के मकान प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं जिनमें से वे अपने लिए मनपसन्द मकान चुन सकते हैं। डायरेक्टरों का बोर्ड जो प्रणाली अमल में लाना चाहता है, वह इस प्रकार है—इन मकानों को १२.५ वर्ष के लिए किराये पर दिया जाता है तथा इस मीयाद के खत्म पर किरायादार—बशर्ते वह किराया नियमित रूप से अदा करता आया हो—आगे किसी भी तरह के भुगतान के बिना मकान का पूर्ण स्वामी बन जायेगा... किरायादार चाहें तो वह ज्यादा किराया देकर यह मीयाद कम करा सकता है अथवा कम किराया देकर मीयाद बढ़वा सकता है... सीमित आय वाले लोग, क्लर्क, दुकानों के कर्मचारी तथा अन्य लोग बिक्रिबेक बिल्डिंग सोसायटी के सदस्य बनकर अपने को मकान-मालिकों से स्वतंत्र कर सकते हैं।”

बात बिल्कुल साफ है। मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है परन्तु सीमित आय वाले लोगों, क्लर्कों तथा दुकानों के कर्मचारियों आदि का जिक्र है। इसके अलावा यह मान लिया गया है कि ग्राहक सामान्यतः पहले से ही पियानो के मालिक हैं। वस्तुतः यहां मजदूरों से कोई वास्ता ही नहीं है, केवल निम्नपूजीपतियों तथा उन लोगों से वास्ता है जो इस तरह के लोग बनना चाहते हैं तथा बन भी सकते हैं; ऐसे लोगों से वास्ता है जिनकी आय—भले ही सीमित दायरे के अन्दर—धीरे-धीरे बढ़ती जाती है जैसे क्लर्क तथा इस तरह के अन्य कर्मचारी। इसके विपरीत मजदूर की आय की राशि जो नाम मात्र को एक जैसी ही रहती है,

परिवार जनों की संख्या तथा उनकी जरूरतों में वृद्धि के अनुपात से वस्तुतः घटती जाती है। दर-असल अपवादस्वरूप चन्द मजदूर ही इस तरह की सोसायटियों के सदस्य बन सकते हैं। एक ओर उनकी आय बहुत कम होती है तथा दूसरी ओर उनकी यह आय इतने अनिश्चित स्वरूप की होती है कि वे पहले ही १२.५ वर्ष का दायित्व ग्रहण नहीं कर सकते। जिन चन्द अपवादों पर यह चीज लागू नहीं होती तो वे या तो सर्वाधिक बेतनभोगी मजदूर या फ़ोरमैन होते हैं।*

वैसे सभी यह जानते हैं कि मजदूरों के म्युलहाउसेन बस्ती के बोनापार्टंपंथी निम्न-पूजीवादी इन अंग्रेज भवन निर्माण सोसायटियों की घटिया नक़ल करनेवालों

* इन भवन निर्माण संघों का, खास तौर पर लन्दन के भवन निर्माण संघों का किस तरह प्रबन्ध किया जाता है, इस बारे में हम यहां थोड़ा और कहना चाहते हैं। जैसा कि सुविदित है, उस पूरी ज़मीन पर, जिस पर लन्दन का निर्माण हुआ है, लगभग एक दर्जन अभिजातों का स्वामित्व है जिनमें ड्यूक आफ़ वेस्टमिंस्टर, ड्यूक आफ़ वेडफ़ोर्ड, ड्यूक आफ़ पोर्टलैंड, आदि प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने मूलतः मकानों के निर्माण के लिए पृथक-पृथक भूखण्ड ६६ वर्षों की अवधि के लिये किराये पर दे दिये थे और उस अवधि के ख़त्म होने पर उन्होंने उस ज़मीन को उस पर खड़ी तमाम चीज़ों समेत अपने अधिकार में ले लिया। फिर उन्होंने इन मकानों को कम मियाद के लिए, उदाहरण के लिए, ३६ वर्षों के लिए (मरम्मत की ज़िम्मेवारी के साथ पट्टे पर) दे दिये जिसके अनुसार मकान को ठीक-ठाक करने तथा उसे इसी हालत में रखने की ज़िम्मेवारी किरायेदार को सौंपी गयी। करार के सम्पन्न होने पर मकान-मालिक अपने वास्तुशिल्पी तथा ज़िला सर्वेयर को मकान की जांच करने तथा यह निश्चित करने के लिए भेजता है कि कितनी मरम्मत की आवश्यकता है। ये मरम्मत कार्य अक्सर बहुत ज्यादा होते हैं तथा मकान के आगे के पूरे हिस्से या छत, आदि की मरम्मत उनमें शामिल हो सकती है। किरायादार अब अपना पट्टा किसी भवन निर्माण संघ के पास ज़मानत के रूप में जमा कर देता है और अपने खर्च पर मकान की मरम्मत के लिए उस संघ से आवश्यक धन—१३० से १५० पौंड तक के वार्षिक किराये पर एक हजार या इससे भी अधिक पौंड—प्राप्त करता है। इस तरह ये भवन निर्माण संघ एक ऐसी प्रणाली की महत्वपूर्ण मध्यवर्ती कड़ी बन जाते हैं जिसका लक्ष्य यह है कि भू-अभिजातों के लिए किसी तरह की परेशानी के बिना तथा सार्वजनिक खर्च पर उनके लंदन वाले मकानों का निरन्तर नवीकरण होता रहे तथा उन्हें रहने योग्य रखने के लिए उनका रख-रखाव होता रहे।

और इसे मजदूरों के लिए आवास प्रश्न का समाधान माना गया है! (१८८७ के संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी)

के अलावा और कुछ नहीं हैं। एकमात्र अन्तर यह है कि बोनापार्टपंथी अपने लिए राजकीय सहायता मंजूर होने के बावजूद अपने ग्राहकों को भवन निर्माण सोसायटियों से कहीं ज्यादा ठगते हैं। कुल मिलाकर उनकी शर्तें इंग्लैंड में मौजूद औसत शर्तों से कहीं कम उदार हैं। जहां इंग्लैंड में प्रत्येक जमा-राशि पर व्याज तथा चक्रवृद्धि व्याज आंका जाता है और उसे एक माह के नोटिस पर वापस लिया जा सकता है, वहां म्युलहाउसेन के कारखानेदार व्याज तथा चक्रवृद्धि व्याज दोनों को अपनी जेबों में डाल देते हैं और मजदूर पांच-पांच फ्रांक के सिक्के गिन-गिनकर जो मूल राशि जमा करते हैं, उसे उससे एक भी कौड़ी ज्यादा नहीं लौटाते। और इस अन्तर पर श्री ज़ाक्स से ज्यादा हैरान और कोई नहीं होगा जिनकी पुस्तक में यह सब है पर जिनका उन्हें ज्ञान तक नहीं है।

इस प्रकार मजदूरों की आत्म-सहायता का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। रही राज्य सहायता की बात। इस मामले में श्री ज़ाक्स हमारे सामने क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? तीन चीजें—

“सर्वप्रथम, राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपने क़ानून तथा प्रशासन में वे सब चीजें, जिनके परिणामस्वरूप मेहनतकश वर्गों के बीच आवास की कमी किसी भी तरह उग्र होती है, ख़त्म हो जानी चाहिए या उन्हें उपयुक्त ढंग से सुधारा जाना चाहिए।” (पृष्ठ १८७)

अतः भवन निर्माण क़ानूनों को संशोधित किया जाये तथा निर्माण व्यवसायों को आज़ादी दी जाये ताकि निर्माण का काम सस्ता हो सके। परन्तु इंग्लैंड में तो ये भवन निर्माण क़ानून कम से कम कर दिये गये हैं तथा निर्माण व्यवसाय आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह स्वतंत्र है; फिर भी मकानों की कमी बरकरार है। इसके अलावा इंग्लैंड में निर्माण कार्य इतना सस्ता है कि मकान किसी घोड़ा-गाड़ी के गुज़रने पर ही हिलने लगते हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ मकान गिरते रहते हैं। कल ही (२५ अक्टूबर १८७२) मानचेस्टर में छः मकान एकसाथ ढह गये तथा छः मजदूर वुरी तरह घायल हो गये। इसलिए इससे भी कोई मदद नहीं मिलती।

“दूसरे, राजकीय सत्ता का काम है कि वह अलग-अलग व्यक्तियों को अपने संकीर्ण व्यक्तिवाद के कारण यह विपत्ति फैलाने या फिर से पैदा करने से रोके।”

इसलिए मजदूरों के घरों की सफाई और भवन निर्माण पद्धति-सम्बन्धी जांच ; जीर्ण-शीर्ण और अस्वास्थ्यकर मकानों में रहने की मनाही करने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को सौंपा जाना, जैसा कि इंग्लैंड में १८५७ से है। परन्तु यह वहां कैसे हुआ ? १८५५ का पहला कानून (अपद्रवण उन्मूलन कानून) स्वयं श्री जाक्स की स्वीकारोक्ति के अनुसार १८५८ के दूसरे कानून (स्थानीय स्वशासन कानून) की तरह “ निर्वीव कानून ” बना रहा (पृष्ठ १६७)। दूसरी ओर, श्री जाक्स का विश्वास है कि तीसरा कानून (दस्तकार आवास कानून), जो केवल १० हजार से ऊपर की आबादी वाले शहरों पर लागू होता है, “ सामाजिक मामलों के विषय में ब्रिटिश संसद की गहरी समझदारी का यत्कीन अनुकूल प्रमाण है ” (पृष्ठ १६६)। परन्तु वास्तविकता यह है कि यह दावा अंग्रेज “ मामलों ” के बारे में श्री जाक्स के घोर अज्ञान का भी उतना ही “ अनुकूल प्रमाण ” है। आम तौर पर “ सामाजिक मामलों ” में इंग्लैंड महाद्वीप से कहीं आगे है, यह स्वतःस्पष्ट है। इंग्लैंड बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग की जन्मभूमि है ; उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति का वहां सबसे मुक्त तथा व्यापक विकास हुआ है ; उसके परिणाम वहां अपने को सबसे ज्वलन्त रूप में प्रकट करते हैं और इसलिए वहीं पहले-पहल कानून के क्षेत्र में उनकी प्रतिध्वनि हुई। इसका सर्वोत्तम प्रमाण कारखाना कानून है। परन्तु श्री जाक्स यदि यह सोचते हैं कि किसी संसदीय कानून के लिए तत्काल व्यवहार में आने योग्य बनने के लिए कानूनी शक्ति प्राप्त करना पर्याप्त है तो वह भारी भूल कर रहे हैं। यही बात किसी भी संसदीय कानून की तुलना में (केवल वर्कशॉप कानून को छोड़कर) स्थानीय स्वशासन कानून पर ही ज्यादा लागू होती है। इस कानून को अमल में लाने का कार्य नगर प्रशासन को सौंपा गया जो प्रायः पूरे इंग्लैंड में इस तरह के भ्रष्टाचार, कुनबापरस्ती तथा jobbery* का सर्वमान्य केन्द्र है। इस नगर प्रशासन के एजेंट, जो अपने पदों पर

* किसी सार्वजनिक पद का सरकारी अधिकारी या उसके परिवार के लिए उपयोग किये जाने को jobbery कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी देश के राजकीय तार विभाग का डायरेक्टर किसी कागज कारखाने का गुप्त साझेदार बन जाता है, उस कारखाने को अपने जंगलों की लकड़ी मुहैया करता है और फिर फ़ैक्टरी को तारघरों के लिए कागज की आपूर्ति के आर्डर देता है तो वह निस्सन्देह छोटा होते हुए भी बढ़िया job है और jobbery के सिद्धान्तों की पूर्ण समझ-दारी प्रदर्शित करता है ; वैसे बिस्मार्क के जमाने में इसे आम और सर्वथा स्वाभाविक माना जाता था। (एंगेल्स की टिप्पणी)

हर तरह के पारिवारिक सम्बन्धों के कारण नियुक्त होते हैं, इस तरह के सामाजिक क़ानूनों को या तो लागू करने के लिए अयोग्य होते हैं या वे उन्हें लागू ही नहीं करना चाहते। दूसरी ओर, इंग्लैंड ही वह स्थान है जहां राजकीय अधिकारी, जिन्हें सामाजिक क़ानून तैयार करने तथा उन्हें अमल में लाने का दायित्व सौंपा जाता है, प्रायः अपनी गहरी कर्तव्यपरायणता के लिए सुविदित हैं हालांकि यह स्थिति आज २० या ३० वर्ष पहले से कम है। नगरपालिकाओं में सर्वत्र कमज़ोर तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों के मालिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जोरदार प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इन नगरपालिकाओं को छोटे-छोटे हल्कों के जरिये निर्वाचित करने की प्रणाली निर्वाचित सदस्यों को तुच्छ स्थानीय हितों तथा प्रभावों पर आश्रित बना देती है; कोई भी नगरपालिका सदस्य, जो दुबारा चुना जाना चाहता है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस क़ानून को लागू करने के पक्ष में मतदान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए यह समझ में आने योग्य चीज़ है कि इस क़ानून को प्रायः सारे स्थानीय प्रशासनों के कितने विरोध का सामना करना पड़ा होगा; कि इस समय तक उसे सबसे बदनामीभरे मामलों में लागू किया गया, और वह भी आम तौर पर किसी संक्रामक रोग के फैलने पर ही—जैसे गत वर्ष मानचेस्टर तथा सालफ़ोर्ड में चेचक के मामले में—लागू किया गया। गृह मंत्री की अब तक अपीलें केवल ऐसे ही मामलों में कारगर हुई हैं क्योंकि इंग्लैंड की हर उदारतावादी सरकार का यह सिद्धान्त रहा है कि वह केवल विवश होने पर ही सामाजिक सुधारों का प्रस्ताव किया करती है और जहां तक सम्भव हो, पहले से मौजूद क़ानूनों पर अमल से बचा करती है। इंग्लैंड के अन्य क़ानूनों की तरह सम्बन्धित क़ानून भी केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह ऐसी सरकार के हाथों में, जिस पर मज़दूरों का प्रभुत्व या दबाव हो, ऐसी सरकार के हाथों में, जो अन्ततः उसे सचमुच अमल में लायेगी, विद्यमान सामाजिक ढांचे में दरार डालने के लिए एक महत्वपूर्ण अस्त्र होगा।

“तीसरे”, श्री ज़ाक्स के अनुसार, राजकीय सत्ता का काम है कि वह “आवास की मौजूदा कमी को दूर करने के लिए अपने पास उपलब्ध सारे ठोस साधनों का व्यापकतम उपयोग करे।”

इसका मतलब यह है कि वह बैरकों का, “अपने अधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए” (परन्तु ये तो मज़दूर नहीं हैं!) “सही अर्थों में आदर्श इमारतों का निर्माण करे और मेहनतकश वर्गों की आवासीय अवस्थाएं सुधारने के

उद्देश्य के लिए नगरपालिकाओं, सोसायटियों तथा अलग-अलग व्यक्तियों तक को... उधार दे" (पृष्ठ २०३), जैसा कि इंग्लैंड में सार्वजनिक कार्य उधार कानून के अन्तर्गत किया जाता है तथा पेरिस और म्युलहाउसेन में लूई बोनापार्ट ने किया है। परन्तु सार्वजनिक कार्य उधार कानून भी केवल कागज में ही मौजूद है। सरकार कमिश्नरों को ५० हजार पाँड की अधिकतम धनराशि, यानी इतनी धनराशि सौंपती है जो अधिक से अधिक ४०० कुटीर बनाने के लिए, यानी ४० वर्ष में कुल मिलाकर १६ हजार कुटीर, यानी अधिक से अधिक ८० हजार व्यक्तियों के लिए घर बनाने के लिए पर्याप्त होती है—यह तो सागर में बूंद के बराबर है! यदि हम यह भी मान लें कि २० साल के बाद कमीशन की निधि उधार की अदायगी के फलस्वरूप दुगुनी हो जायेगी और इसलिए बाकी २० वर्षों में ४० हजार और व्यक्तियों के लिए घर बन जायेंगे तब भी यह सागर में बूंद के बराबर होगा। चूँकि कुटीरों की उम्र औसतन केवल ४० वर्ष की होती है इसलिए ४० वर्ष के बाद सबसे ज्यादा जीर्ण-शीर्ण, सबसे पुराने कुटीरों के पुनरुद्धार पर हर वर्ष ५० हजार या १ लाख पाँड का उपयोग करना पड़ेगा। यही, पृष्ठ २०३ पर श्री ज़ाक्स की घोषणानुसार, सिद्धान्त को सही तथा "व्यापकतम पैमाने पर" अमल में लाया जाना है! इस स्वीकारोक्ति के साथ कि इंग्लैंड में भी राज्य "व्यापकतम पैमाने पर" कुछ हासिल नहीं कर पाया है, श्री ज़ाक्स अपनी पुस्तक समाप्त करते हैं, परन्तु ऐसा वह सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को पहले एक और उपदेश दिये बिना नहीं करते।*

*अंग्रेज़ संसद के हाल के क़ानूनों में, जिनमें लन्दन के भवन निर्माण अधिकारियों को नयी सड़कों के निर्माण के लिए हस्तगतकरण का अधिकार दिया गया है, इस तरह अपने घरों से बेदखल किये जानेवाले मज़दूरों का कुछ ख़याल रखा गया है। यह धारा शामिल की गयी है कि निर्मित होनेवाली इमारतें आवादी की उन श्रेणियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए जो पहले वहाँ रहती थीं। इसलिए कम से कम कीमती निर्माण स्थलियों पर मज़दूरों के रहने के लिए ५-६ मंज़िल वाली आवासीय इमारतें खड़ी कर दी गयी हैं। इस तरह क़ानून की भावना का आदर किया गया है। यह तो भविष्य बतायेगा कि यह नयी व्यवस्था किस तरह काम करेगी क्योंकि मज़दूर उसके क़तरई अभ्यस्त नहीं हैं तथा ये इमारतें पुराने लन्दन की परिस्थितियों में सर्वथा विजातीय हैं। इससे हृद से हृद उन मज़दूरों के एक चौथाई भाग को नये घर मिल सकेंगे जो वस्तुतः भवन निर्माण कार्यों के फलस्वरूप बेदखल हुए हैं। (१८८७ के संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी)

यह सर्वथा स्पष्ट है कि समकालीन राज्य आवासीय विपदा को दूर करने में न तो समर्थ है और न वह उसे दूर करने के लिए कुछ करना ही चाहता है। राज्य शोषित वर्गों, किसानों तथा मजदूरों के विरुद्ध सम्पत्तिधारी वर्गों, ज़मींदारों तथा पूंजीपतियों की संगठित सामूहिक शक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जो पृथक्-पृथक् पूंजीपति (और यहां यह केवल इनका ही प्रश्न है क्योंकि इस मामले में ज़मींदार भी, जो इससे सम्बन्धित है, पूंजीपति की हैसियत से ही काम करता है) नहीं चाहता, वह उसका राज्य भी नहीं चाहता। इसलिए यदि अलग-अलग पूंजीपति आवास की कमी पर दुख तो प्रकट करे परन्तु यदि उसे उसके सबसे भयावह परिणामों पर सतही लीपापोती तक करने के लिए विचलित नहीं किया जा सकता, तो सामूहिक पूंजीपति, राज्य भी ज्यादा कुछ नहीं करेगा। वह हृद से हृद यह ध्यान में रखेगा कि सर्वत्र आम सतही लीपापोती ही एक समान रूप से की जाये। और हम देख चुके हैं कि ऐसा ही होता है।

परन्तु कोई यह आपत्ति कर सकता है कि जर्मनी में पूंजीपति वर्ग अभी राज नहीं कर रहा है; जर्मनी में राज्य अब भी कुछ हद तक समाज से स्वतंत्र रूप में उड़ान भर रहा है जो ठीक इस कारण किसी एक वर्ग का नहीं, वरन् समाज के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस तरह का राज्य ऐसा बहुत-कुछ कर सकता है जो पूंजीवादी राज्य नहीं कर सकता और उससे सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ सर्वथा भिन्न काम करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

यह प्रतिक्रियावादियों का दावा है। वास्तव में राज्य, जिस रूप में वह जर्मनी में नज़र आता है, उसी सामाजिक आधार की अनिवार्य उपज है जिससे उसका जन्म हुआ है। प्रश्न में—और प्रश्न इस समय निर्णायक भूमिका अदा कर रहा है—भू-स्वामी अभिजात वर्ग की, जो अब भी सशक्त है, बगल में अपेक्षाकृत तरुण और घोर कायर पूंजीपति वर्ग विद्यमान है जिसने अब तक न तो फ्रांस की तरह प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त किया है और न इंग्लैंड की तरह न्यूनाधिक परोक्ष प्रभुत्व। परन्तु इन दो वर्गों के साथ ही साथ तादाद की दृष्टि से तेज़ी से बढ़ता जा रहा सर्वहारा वर्ग भी है जो बौद्धिक दृष्टि से अत्यन्त विकसित है और दिनोदिन अधिकधिक संगठित होता जा रहा है। इसलिए पुराने निरंकुश राजतंत्र की मूल शर्त के—भू-स्वामी अभिजात वर्ग तथा पूंजीपति वर्ग के बीच सन्तुलन—साथ-साथ हम यहां आधुनिक बोनापार्टपंथ की मूल शर्त—पूंजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के बीच सन्तुलन—भी देखते हैं। परन्तु पुराने निरंकुश राजतंत्र की तरह आधुनिक बोनापार्टपंथी राजतंत्र में भी वास्तविक सरकारी सत्ता फ़ौजी अफ़सरों

तथा राजकीय अधिकारियों की एक खास श्रेणी के हाथों में है। प्रशा में इस श्रेणी में अंशतः उसकी अपनी क्रतारों से और अंशतः छोटे ज्येष्ठाधिकारी अभिजातों से संपूर्ति होती रहती है; उसमें उच्च अभिजात वर्ग से विरले ही और पूंजीपति वर्ग से तो सबसे कम संपूर्ति होती है। इस श्रेणी की स्वतंत्रता, जो समाज के बाहर और, कहना चाहिए, समाज के ऊपर विशेष स्थिति ग्रहण की हुई प्रतीत होती है, राज्य को समाज के सम्बन्ध में स्वतंत्रता का आभास प्रदान करती है।

इन परस्परविरोधी सामाजिक अवस्थाओं में से प्रशा में (तथा प्रशा के उदाहरण के बाद जर्मनी के नये राइख संविधान में भी) राज्य का जो रूप विकसित हुआ है, वह मिथ्या संविधानवाद है। इस राजकीय रूप में पुराने निरंकुश राजतंत्रवाद के विघटन का समकालीन रूप तथा बोनापार्टपंथी राजतंत्रवाद के अस्तित्व का रूप दोनों एकसाथ आ जाते हैं। प्रशा में १८४८ से १८६६ तक मिथ्या संविधानवाद ने निरंकुश राजतंत्रवाद के धीरे-धीरे क्षय को केवल छपाया तथा उसके धीरे-धीरे विघटन के लिए रास्ता साफ किया। परन्तु १८६६ से और खासकर १८७० से सामाजिक अवस्थाओं में उथल-पुथल तथा उसके साथ पुराने राज्य का विघटन सब की आंखों के सामने तथा अपरिमित पैमाने पर अग्रसर होते रहे हैं। उद्योग के और खास तौर पर शेयर बाजार में झांसा-पट्टी के द्रुत विकास ने सारे सत्ताधारी वर्गों को सट्टेबाजी के भंवर की ओर धकेल दिया है। फ्रांस से १८७० में अपरिमित रूप में आयातित भ्रष्टाचार अभूतपूर्व गति से विकसित हो रहा है। स्ट्रासबर्ग तथा पेरेडर एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाते हैं। मंत्री, जनरल, राजे-रजवाड़े तथा काउंट स्टाक एक्सचेंज के सबसे बड़े धूर्तों के साथ शेयर बाजार की सट्टेबाजी में प्रतियोगिता करते हैं तथा राज्य स्टाक एक्सचेंज के इन धूर्तों को अपरिमित रूप से सामन्ती उपाधियां प्रदान करके उनकी समानता को मान्यता देता है। देहाती अभिजात वर्ग, जो चुकन्दर तथा ब्रांडी के उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घकाल से उद्योगपति रहे हैं, अपने पुराने गौरवशाली दिनों को बहुत पहले पीछे छोड़ आये हैं और अब सब तरह की ठोस और कमजोर ज्वायंट स्टाक कम्पनियों के डायरेक्टरों की सूचियां उनके नामों से भरी पड़ी हैं। नौकरशाही अपनी आय बढ़ाने के एकमात्र साधन के रूप में ग़बन का अधिकाधिक तिरस्कार करने लगी है; वह राजकीय पदों की ओर से मुंह मोड़ते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रशासन में कहीं ज्यादा मोटी-मोटी तनख्वाहों के पीछे भागने लगी है; जो नौकरशाह अब भी राजकीय पदों पर हैं, वे अपने वरिष्ठों का अनुकरण कर रहे हैं तथा शेयरों की सट्टेबाजी कर रहे

हैं अथवा रेलवे, आदि में “शेयर हासिल कर रहे हैं”। यह मानना भी उचित होगा कि वेफ्टिनेंट भी कतिपय सट्टेबाजियों में जुटे हुए हैं। संक्षेप में, पुराने राज्य का क्षय तथा निरंकुश राजतंत्र का बोनापार्टपंथी राजतंत्र में संक्रमण पूरे जोरों से हो रहा है। अगले बड़े व्यापारिक-औद्योगिक संकट के साथ मौजूदा झांसा-पट्टी ही नहीं, वरन् पुराना प्रशियाई राज्य भी ढह जायेगा।*

और क्या यह राज्य, जिसमें गैरपूँजीवादी तत्व अधिकाधिक पूँजीवादी बनते जा रहे हैं, “सामाजिक प्रश्न” को, या फिर मात्र आवास प्रश्न को हल करने जा रहा है? बात इसके विपरीत है। तमाम आर्थिक प्रश्नों में प्रशियाई राज्य अधिकाधिक पूँजीपति वर्ग के प्रभाव में पहुँचता जा रहा है। और यदि आर्थिक क्षेत्र में १८६६ से कानून बनाने के काम को पूँजीपति वर्ग के हित में उससे ज्यादा नहीं ढाला गया है जितना वह वस्तुतः ढला है तो यह किसका दोष है? दोषी मुख्यतया पूँजीपति वर्ग है; इसकी पहली वजह यह है कि वह इतना कायर है कि अपनी मांगों पर सशक्त ढंग से जोर नहीं डाल सकता, दूसरी वजह यह है कि वह हर रियायत का विरोध करता है यदि वह रियायत भयावह सर्वहारा वर्ग के हाथों में नये हथियार सौंपती हो। और यदि राजकीय सत्ता, अर्थात् बिस्मार्क पूँजीपति वर्ग की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपने अंगरक्षक सर्वहारा को संगठित करने का यत्न करता है तो वह उस आवश्यक तथा सुविधित बोनापार्टपंथी नुस्खे के अलावा और क्या है जो राज्य को—जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है—चन्द सद्भावनापूर्ण वाक्यों तक तथा हृद से हृद लूई बोनापार्ट मार्का भवन निर्माण सोसायटियों के लिए राजकीय सहायता देने तक वचनबद्ध करता है?

मजदूर प्रशियाई राज्य से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसका सबसे बढ़िया प्रमाण फ्रांसीसी अरबों का उपयोग है जिन्होंने समाज के सिलसिले में प्रशियाई राजकीय यंत्र को थोड़ी और अवधि दी है। इस अरबों की राशि में से क्या एक टेलर भी बर्लिन के मजदूर वर्ग के उन परिवारों को शरण देने

* आज भी, १८८६ में, पुराने प्रशियाई राज्य तथा उसके आधार को—बड़े भू-स्वामियों तथा औद्योगिक पूँजी की संघबद्धता को जिसे संरक्षण शुल्क दृढ़ बनाये हुए हैं—जो चीज सूत्रबद्ध रखती है, वह है सर्वहारा का भय जिनकी संख्या तथा वर्ग चेतना में १८७२ से असीम वृद्धि हुई है। (१८८७ के संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी)

पर खर्च किया गया है जिन्हें घरों से बेदखल कर सड़कों में धकेल दिया गया ? बिल्कुल नहीं। पतझड़ ज्यों पास पहुंचा, राज्य ने उन दयनीय बैरकों तक को गिरा दिया जहां इन लोगों को गर्मियों में सिर छुपाने की जगह मिली थी। ये पांच अरब भी तेजी से घिसे-पिटे रास्ते पर—किलों, तोपों तथा सिपाहियों पर—बहते जा रहे हैं; और वागनेर की मूर्खतापूर्ण बातों⁷² के बावजूद तथा आस्ट्रिया के साथ श्विबेरियाई कांफ्रेंसों⁷³ के बावजूद अरबों की इस धनराशि में से जर्मन मजदूरों के लिए उससे कम मंजूर की जायेगी जो लूई बोनापार्ट द्वारा फ्रांस से चुरायी गयी करोड़ों की धनराशि में से फ्रांसीसी मजदूरों के लिए मंजूर की गयी थी।

३

वस्तुतः पूंजीपति वर्ग के पास आवास प्रश्न को हल करने के लिए अपने ढंग का एक ही तरीका है, यानी ऐसा तरीका कि हल समस्या को निरन्तर नूतन रूप से प्रस्तुत करता रहे। इस तरीके को “ओस्मान” तरीका कहते हैं।

“ओस्मान” शब्द से मेरा तात्पर्य विशिष्टतया पेरिसवासी ओस्मान के बोनापार्टपंथी ढंग से ही नहीं है—मजदूरों के घने बसे घरों के ठीक बीच से लम्बी, सीधी और चौड़ी सड़कों का निर्माण करना तथा उनके दोनों ओर बड़े-बड़े आलीशान इमारतें खड़ी करना, इसके पीछे बैरीकेडी लड़ाई को अधिक कठिन बनाने के सामरिक उद्देश्य के अलावा यह उद्देश्य भी छुपा हुआ था कि सरकार पर निर्भर करनेवाले विशिष्ट रूप से निर्माण कार्यरत सर्वहारा वर्ग को तैयार किया जाये तथा पेरिस को विशुद्धतया वैभवशाली नगर में परिणत किया जाये। “ओस्मान” से मेरा तात्पर्य इस अमल से भी है जो अब आम हो चुका है याने हमारे बड़े शहरों में खास तौर पर उनके केन्द्रीय इलाकों में मजदूर वर्ग के मुहल्लों के बीच किसी भी कारण को लेकर—सार्वजनिक स्वच्छता, खूबसूरती, केन्द्रीय इलाकों में व्यापारिक केन्द्रों के निर्माण की मांग अथवा रेलवे लाइनें बिछाने, सड़कें बनाने, आदि कारणों को लेकर—दरार डालना। कारण चाहे भित्तने ही भिन्न-भिन्न क्यों न हों, परिणाम सर्वत्र एक जैसा होता है—सबसे ज्यादा गन्दी गलियां और रास्ते लुप्त हो जाते हैं और इस जबर्दस्त सफलता के लिए पूंजीपति वर्ग बेहद आत्म-श्लाघा करता है परन्तु... ये गन्दी गलियां तथा रास्ते तुरन्त कहीं और, कभी-कभी तो बिल्कुल पास में ही प्रकट हो जाती हैं।

१८४३-१८४४ में मानचेस्टर कैसा था, इसकी तस्वीर मैंने 'इंग्लैंड में मजदूर वर्ग की स्थिति' पुस्तक में प्रस्तुत की थी। तब से नगर के मध्यवर्ती भाग में रेलवे लाइनों बिछायी जा चुकी हैं, नयी सड़कें तैयार हो चुकी हैं तथा बड़ी-बड़ी सार्वजनिक और निजी इमारतों का निर्माण हो चुका है, उपरिलिखित कतिपय सबसे खराब इलाकों को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है अथवा उन्हें सुधारा गया है, दूसरों में सब कुछ गिराया जा चुका है; इस तथ्य के बावजूद कि सफ़ाई विभाग द्वारा निरीक्षण पहले से अधिक कठोर हो गया है, बहुत-से इलाके अब भी पहले जैसी हालत में हैं, यही नहीं, कई तो पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा जीर्णविस्था में हैं। दूसरी ओर, नगर के, जिसकी आबादी अब आधे से ज्यादा बढ़ गयी है, अत्यधिक विस्तार की वदौलत उन इलाकों में जो पहले हवादार तथा साफ़ थे, अब उतना ही अतिनिर्माण हो चुका है, उनमें अब उतनी ही गन्दगी है, वहां उतनी ही घनी आबादी है जितनी पहले नगर के सबसे बदनाम हिस्से में पायी जाती थी। यह रहा गात्र एक उदाहरण—अपनी पुस्तक के पृष्ठ ८० पर तथा अन्यत्र मैंने मेडलाक नदी की घाटी के कुछ मकानों के एक समूह का वर्णन किया था जो लघु आयरलैंड के नाम से मानचेस्टर पर लम्बे अर्से से कलंक का धब्बा बना रहा। लघु आयरलैंड तब से लुप्त हो चुका है और उसकी जगह अब बहुत ऊंची नींव पर बना एक रेलवे स्टेशन है। पूंजीपति वर्ग ने गर्वपूर्वक लघु आयरलैंड की ओर संकेत कर उसके सुखद तथा अन्तिम रूप से उन्मूलन को बहुत बड़ी विजय बताया। अब पिछली गर्मियों में बहुत बड़ी बाढ़ आयी, और जैसा कि आम तौर पर होता है, तटबंधों के कारण हमारे नगरों में साल-दर-साल अधिकाधिक बाढ़ें आती हैं जिनके कारणों को आसानी से समझाया जा सकता है। तब पता चला कि लघु आयरलैंड को क़तई नहीं मिटाया गया। वह तो आक्सफ़ोर्ड रोड के दक्षिण की तरफ़ से उत्तर की तरफ़, केवल स्थानान्तरित हुआ है और वह अब भी फूल-फल रहा है। देखें इस बारे में मानचेस्टर के आमूल परिवर्तनवादी पूंजीपति वर्ग का मुखपत्र मानचेस्टर «Weekly Times» अपने २० जुलाई १८७२ के अंक में क्या कहता है—

“पिछले शनिवार को मेडलाक नदी की घाटी के निवासियों पर विपत्ति का जो पहाड़ टूटा, उसका—यह आशा की जानी चाहिए—एक सुपरिणाम निकलेगा यानी जनमत स्वच्छता के तमाम क़ानूनों की उस स्पष्ट उपहासास्पदता की ओर आकृष्ट होगा जिसे वहां हमारे म्युनिसिपल अधिकारियों तथा हमारी म्युनिसिपल

स्वच्छता समिति की आंखों के सामने इतने लम्बे समय से सहन किया जाता रहा है। हमारे दैनिक समाचारपत्र के कल के अंक में एक तीक्ष्णताभरे लेख में चार्ल्स स्ट्रीट तथा ब्रुक स्ट्रीट पर, जहां बाढ़ का पानी पहुंच गया था, कुछ तहखानों की शर्मनाक हालत पर प्रकाश डाला गया था—हालांकि उतने जोरदार ढंग से नहीं जितना होना चाहिए था। इस लेख में उल्लिखित अहातों में से एक के विस्तृत निरीक्षण के बल पर हम उनके बारे में सारे बयानों की पुष्टि कर सकते हैं तथा यह भी घोषित कर सकते हैं कि इस अहाते के तहखानों को बहुत पहले ही बन्द कर दिया जाना चाहिए था या, यों कहें, कि उन्हें इन्सान के आवास के रूप में कभी सहन नहीं किया जाना चाहिए था। स्वयार्ज कोर्ट में, जो चार्ल्स स्ट्रीट तथा ब्रुक स्ट्रीट के नुक्कड़ पर है, सात या आठ आवास गृह हैं। ब्रुक स्ट्रीट के सबसे निचले हिस्से तक में, जो रेलवे पुल के नीचे है, राहगीर रोज़ गुजरते हुए शायद ही कभी यह कल्पना करे कि उसके नीचे इन्सान गुफाओं के अन्दर रहते हैं। खुद अहाते दृष्टिगोचर नहीं होते और वहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिन्हें गरीबी कब्रिस्तान जैसे एकान्तवास में अरण ढूंढ़ने के लिए विवश करती है। मेडलाक नदी का साधारणतया निश्चल जल, जो तटबंध से घिरा हुआ है, यदि अपने सामान्य स्तर से ऊपर न भी उठे, तब भी इन घरों का फ़र्श पानी की सतह से मुश्किल से चन्द इंच ऊपर होगा। एक तेज़ झड़ी नालियों में दुर्गंधपूर्ण मतली लानेवाला पानी बहाने तथा कमरों को ऐसी विषैली गैसों से भरने के लिए पर्याप्त होती है जिन्हें हर बाढ़ अपने पीछे स्मृति-चिह्न के रूप में छोड़ जाती है... स्वयार्ज कोर्ट तो ब्रुक स्ट्रीट के गैरआबाद तहखानों से भी नीचे है... सड़क की सतह से बीस फ़ीट नीचे। और शनिवार को दुर्गंधपूर्ण पानी घरों की छतों तक पहुंच गया था। हम यह जानते थे तथा इस कारण आशा करते थे कि ये स्थान खाली होंगे अथवा वहां स्वच्छता समिति के कर्मचारी भरे हुए होंगे जो बदबू भरी दीवारें साफ़ कर रहे होंगे अथवा मकानों के अन्दर रोगाणु नष्ट कर रहे होंगे। इसके बदले हमने एक व्यक्ति देखा जो किसी नाई की तहखानानुमा कोठरी के अन्दर... एक किनारे पड़े हुए सड़ांधभरे मल-कचरे को एक ठेले में भर रहा था। नाई ने, जिसकी तहखानानुमा कोठरी कमोबेश साफ़ हो चुकी थी, हमें और भी नीचे खड़ी कोठरियों की ओर भेजा जिनके बारे में उसने कहा कि यदि उसे लिखना आता तो वह अखबारों को सूचित करता और उन्हें बन्द करने की मांग करता। अन्ततः हम स्वयार्ज कोर्ट में पहुंचे जहां हमने एक सुन्दर तथा हृष्ट-पुष्ट आयरिश औरत को कपड़े धोने में व्यस्त पाया। वह तथा उसका पति, जो रात को चौकीदारी का काम करता है, इस अहाते में ६ साल से रहते आये हैं तथा उनका बड़ा परिवार है... जिस घर को उन्होंने अभी खाली किया, उसमें पानी क़रीब-क़रीब छत तक पहुंच गया था, खिड़कियां टूट गयी थीं तथा फ़र्नीचर पूरी तरह नष्ट हो गया था। कोठरी में रहनेवाले व्यक्ति के अनुसार वह हर दो महीने में कोठरी की सफ़ेदी करके ही असहनीय दुर्गंध को रोका करता था... फिर हमारा

सम्बाददाता अहाते के अन्दरूनी भाग में पहुँचा, वहाँ उसे तीन कोठरियाँ मिलीं जिनके पिछवाड़े की दीवालें ऊपर चर्चित कोठरियों के पिछवाड़े की दीवालें से सटी हुई थीं। इन तीन कोठरियों में से दो आबाद थीं। वहाँ इतनी तेज़ बदबू थी कि स्वस्थ से स्वस्थ आदमी को भी चन्द मिनटों के अन्दर उलटियाँ आने लगतीं... इस घिनौने नरककुंड के अन्दर सात व्यक्तियों का परिवार रहता था; गुरुवार की रात को (बाढ़ के पहले दिन) वे सब के सब यहाँ सोये हुए थे। या यों कहना चाहिए कि कोई भी नहीं सोया था, जैसा कि औरत ने फ़ौरन अपनी गलती सुधारते हुए कहा, क्योंकि वह तथा उसका पति अधिकांश रात भयंकर दुर्गंध के कारण उलटियाँ करते रहे। शनिवार को वे बच्चों को वहाँ से ले जाने के लिए कमर तक पानी के बोच से गुज़रने के लिए मजबूर हुए। औरत की यह भी राय थी कि यह जगह तो सूअरों के रहने लायक भी नहीं है परन्तु किराया कम होने की वजह से—डेढ़ शिलिंग प्रति सप्ताह—उसने यह कोठरी ली क्योंकि उसका पति हाल में बीमारी की वजह से काफ़ी दिनों तक बेरोज़गार रहा। इस अहाते और मानों समय से पहले किसी मक़बरे में ठूसकर भर दिये गये यहाँ के लोगों को देखकर घोर बेबसी का भाव पैदा होता है। यहाँ प्रसंगतः हम यह भी परिलक्षित कर देना चाहते हैं कि स्क्वायरों कोर्ट, जो हो सकता है नितान्त परले सिरे का सामला हो, इस इलाक़े की अन्य बस्तियों की तुलना में विशिष्ट नहीं है जिनके अस्तित्व को हमारी स्वच्छता समिति न्यायोचित नहीं ठहरा सकती। यदि इन जगहों को भविष्य में भी किराये पर उठाया जाने दिया जायेगा तो इसकी पूरी जिम्मेवारी समिति पर होगी और आस-पास के पूरे इलाक़े के लिए महामारियों का ख़तरा पैदा हो जायेगा जिनकी गम्भीरता की आगे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है।”

यह इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि पूंजीपति वर्ग आवास प्रश्न का किस तरह व्यवहार में समाधान करता है। बीमारियों के पनपने की जगहें, कुख्यात कुंड और तहख़ाने, जहाँ उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति हमारे मजदूरों को निरन्तर रात काटने के लिए ढकेला करती है, मिटाये नहीं जाते, वे तो मात्र... अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं! जिस आर्थिक आवश्यकता ने उन्हें एक जगह जन्म दिया था, वही उन्हें दूसरे स्थान में भी जन्म देती है। जब तक उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति कायम रहेगी, आवास प्रश्न अथवा मजदूरों की दशा पर असर डालनेवाले किसी भी अन्य सार्वजनिक प्रश्न का समाधान करने की आशा करना मूर्खतापूर्ण है। समाधान तो उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के उन्मूलन में तथा स्वयं मजदूर वर्ग द्वारा जीवन निर्वाह के तमाम साधनों तथा श्रम के तमाम साधनों के हस्तगतकरण में निहित है।

प्रूदों तथा आवास प्रश्न पर परिशिष्ट

१

«*Volksstaat*» के अंक ८६ में अ० म्यूलबर्गर ने अपने को उन लेखों के लेखक के रूप में प्रकट कर दिया है जिनकी मैंने इस अखबार के अंक ५१ तथा आगे के अंकों में आलोचना की थी। * अपने उत्तर में वह मुझपर झिड़कियों की बौछार करते हैं और साथ ही सारे मसलों को इस तरह गड़ुमड़ु कर देते हैं कि मुझे ख़ाहमख़ाह उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं अपने उत्तर में—जो, खेद है, स्वयं म्यूलबर्गर द्वारा विवश किये जाने पर काफ़ी हद तक वैयक्तिक वाद-विवाद के क्षेत्र को ही स्पर्श करेगा—मुख्य मुद्दों को एक बार फिर तथा यदि सम्भव हो तो अधिक स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत कर उसे आम दिलचस्पी का बनाने का प्रयत्न करूँगा भले ही मुझे म्यूलबर्गर से फिर यह सुनने का जोखिम उठाना पड़े कि इस सब में “न तो उनके लिए और न «*Volksstaat*» के अन्य पाठकों के लिए मूलतः कोई नयी बात है।”

म्यूलबर्गर मुझ द्वारा की गयी आलोचना के रूप तथा सारतत्व के बारे में शिक्षायत करते हैं। जहाँ तक रूप का सम्बन्ध है, यह उत्तर काफ़ी होगा कि उस समय तो मुझे पता ही नहीं था कि सम्बन्धित लेख किसने लिखे हैं। इसलिए लेखक के प्रति किसी प्रकार के व्यक्तिगत “पूर्वाग्रह” का कोई प्रश्न ही नहीं उठता; आवास प्रश्न के लिए लेखों में प्रस्तुत समाधान के प्रति मेरा “पूर्वाग्रह” केवल इसी हद तक था कि मैं प्रूदों के ज़रिए इससे बहुत पहले ही परिचित हो चुका था तथा इस बारे में मेरी राय पक्की हो चुकी थी।

मैं मित्त म्यूलबर्गर से अपनी आलोचना के “लहजे” के बारे में झगड़ने नहीं जा रहा हूँ। जब आन्दोलन में किसी को इतना लम्बा अर्सा हो जाता है, जितना अर्सा मुझे हुआ है तो आक्षेपों के मामले में उसकी खाल ख़ूब मोटी हो जाती है और इसलिए वह आसानी से मान सकता है कि दूसरों के मामले में

भी ऐसा ही होता होगा। श्री म्यूलबर्गर की तुष्टि के लिए मैं इस बार अपने “लहजे” को उनकी खाल की संवेदनशीलता के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करूंगा।

म्यूलबर्गर विशेष कटुता के साथ यह शिकायत करते हैं कि मैंने उन्हें प्रदोषंथी बताया और वह विरोध करते हुए कहते हैं कि वह प्रदोषंथी नहीं हैं। स्वभावतया मुझे उनकी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। परन्तु मैं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि उनके चर्चित लेखों में—और मेरा केवल उनसे ही सम्बन्ध था—विशुद्ध प्रदोषंथ के अलावा और कुछ है ही नहीं।

परन्तु श्री म्यूलबर्गर के अनुसार मैंने प्रदोषों की भी “छिछोरे ढंग से” आलोचना की तथा उनके साथ बहुत अन्याय किया है—

“निम्नपूजीपति प्रदोषों का सिद्धान्त जर्मनी में स्वीकार्य जड़सूत बन गया है जिसे वे बहुत-से लोग भी अंगीकार करते हैं जिन्होंने उनकी रचनाओं की एक भी पंक्ति नहीं पढ़ी है।”

जब मैं इस बात पर खेद प्रकट करता हूँ कि रोमांस भाषाभाषी मजदूरों के पास बीस वर्षों तक प्रदोषों की कृतियों के अलावा और कोई मानसिक आहार नहीं था, तो म्यूलबर्गर इसके उत्तर में कहते हैं कि जहां तक इन मजदूरों का सम्बन्ध है, “प्रदोषों द्वारा निरूपित सिद्धान्त प्रायः सर्वत्र आन्दोलन की जीवन्त आत्मा है”। इससे मैं सहमत नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि मजदूर आन्दोलन की “जीवन्त आत्मा” कहीं भी “सिद्धान्तों” में निहित नहीं रही है, अपितु सर्वत्र बड़े पैमाने के उद्योग के विकास में और उसके प्रभावों में—एक ओर पूजी के संचय तथा संकेन्द्रण तथा दूसरी ओर सर्वहारा के संकेन्द्रण में—निहित रही है। दूसरे, यह कहना सही नहीं है कि रोमांस भाषाभाषी देशों में प्रदोषों के तथाकथित “सिद्धान्त” वह निर्णायक भूमिका अदा करते हैं जो म्यूलबर्गर बताते हैं; कि “अराजकतावाद के, Organisation des forces économiques, Liquidation Sociale,* आदि के सिद्धान्त वहां... क्रान्तिकारी आन्दोलन के सच्चे ध्वजवाहक बन गये हैं।” स्पेन तथा इटली की तो बात ही क्या, जहां प्रदोषंथी रामबाण ने और भी खराब बकूनिनपंथी रूप में कुछ प्रभाव हासिल कर लिया है, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के बारे में जाननेवाले हरेक व्यक्ति के लिए यह एक सुविदिन तथ्य है कि फ्रांस में भी प्रदोषंथी संख्या की दृष्टि से एक तरह से अनुत्प्रेक्षणीय पंथ है जबकि मजदूरों का विशाल समुदाय Liquidation sociale और

* आर्थिक शक्तियों का संगठन, सामाजिक विघटन।—सं०

Organisation des forces économiques शीर्षक से प्रूदों द्वारा तैयार की गयी सामाजिक सुधार योजना के साथ कोई भी सरोकार रखने से इन्कार कर रहा है। यह दूसरी चीजों के साथ कम्यून में भी स्पष्ट हो गया था। यद्यपि प्रूदोंपंथियों को कम्यून में जोरदार प्रतिनिधित्व प्राप्त था, प्रूदों के प्रस्ताव के अनुसार पुराने समाज को विघटित करने अथवा आर्थिक शक्तियों को संगठित करने की ज़रा भी कोशिश नहीं की गयी। इसके विपरीत, कम्यून के लिए यह बहुत बड़े गौरव की बात है कि उसके तमाम आर्थिक पगों की “जीवन्त आत्मा” सिद्धान्तों का कोई सेट नहीं, बल्कि सरल व्यावहारिक आवश्यकताएं थीं। इसीलिए ये पग—बेकरियों में रात्रिकालीन श्रम का अन्त, कारखानों में नक़द जुर्मानों पर पाबन्दी, तालाबन्द कारखानों और वर्कशापों का हस्तगतकरण और उन्हें मज़दूर संघों को सौंपना—प्रूदोंपंथी भावना के कदापि अनुरूप नहीं थे परन्तु वे यकीनन जर्मन वैज्ञानिक समाजवाद की भावना के अनुकूल थे। प्रूदोंपंथियों ने जो एकमात्र सामाजिक पग उठाया, वह था फ़्रांसीसी बैंक को हस्तगत न करने का फ़ैसला जो अंशतः कम्यून के पतन का कारण बना। इसी तरह जब तथाकथित ब्लांकीपंथियों ने अपने को मात्र राजनीतिक क्रांतिकारियों से एक निश्चित कार्यक्रम वाले समाजवादी मज़दूर दल में परिणत करने का प्रयत्न किया—जैसा कि लन्दन में ब्लांकीपंथी उत्प्रवासियों ने अपने ‘इंटरनेशनल तथा क्रांति’ घोषणापत्र में किया था,—तो उन्होंने समाज की मुक्ति के लिए प्रूदोंपंथी योजना के “सिद्धान्तों” को अंगीकार नहीं किया, बल्कि वग़ीं और उनके साथ राज्य के उन्मूलन में संक्रमण के रूप में सर्वहारा और उसके अधिनायकत्व द्वारा राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता को, ऐसे विचारों को जिन्हें ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’* में तथा तब से कई मौकों पर व्यक्त किया जा चुका है, अनुमोदित—और वह भी अक्षरशः—किया। यदि म्यूलबर्गर प्रूदों के प्रति जर्मनों के तिरस्कार से यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि “ठीक पेरिस कम्यून तक” के रोमांस आन्दोलन के प्रति समझदारी का अभाव रहा है तो उन्हें इस अभाव के प्रमाण के रूप में बताना चाहिए कि रोमांस साहित्य की किस कृति में कम्यून को उतनी अच्छी तरह समझा गया है अथवा लगभग उतने ही सही ढंग से वर्णित किया गया है जितने सही ढंग से जर्मन मार्क्स द्वारा लिखित फ़्रांस में गृहयुद्ध के बारे में इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल की चिट्ठी में उसे समझा और वर्णित किया गया है।**

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड १, भाग १।—सं०

** देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

बेल्जियम एकमात्र देश है जहाँ मजदूर आन्दोलन सीधे प्रदोषी "सिद्धान्तों" के प्रभाव में है। और ठीक इस बात के फलस्वरूप बेल्जियन मजदूर आन्दोलन—यदि हेगेल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाये—"शून्य से शून्य के बीच होते हुए शून्य तक चलता है।" 74

जब मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि लैटिन देशों के मजदूरों को बीस वर्षों तक प्रत्यक्षतः या परोक्षतः विशिष्ट रूप से केवल प्रदोषों द्वारा मुहैया किया गया बौद्धिक आहार दिया जाता रहा, तो मेरा तात्पर्य सुधार-सम्बन्धी प्रदोषी नुस्खे के सर्वथा कल्पित प्रभुत्व से—जिसे म्यूलबर्गर ने "सिद्धान्तों" का नाम दिया है—नहीं है, अपितु इस तथ्य से है कि विद्यमान समाज की उन द्वारा की गयी आर्थिक आलोचना सर्वथा मिथ्या प्रदोषी शब्दजाल से दूषित थी तथा उनकी राजनीतिक कार्यवाहियों को प्रदोषी प्रभाव ने गड़बड़ी में डाल दिया था। क्या "लैटिन देशों के प्रदोषी मजदूर" जर्मन मजदूरों की तुलना में, जिनकी जर्मन वैज्ञानिक समाजवाद के बारे में समझ अपने प्रदोषों के बारे में लैटिनों की समझ से निस्सन्देह असीम रूप से अधिक है, "क्रान्ति के अधिक साथ होते हैं", इस प्रश्न का उत्तर हम तभी दे सकेंगे जब हमें मालूम हो जायेगा कि "क्रान्ति के साथ" होने का वस्तुतः अर्थ क्या है। हमने लोगों के बारे में सुना है कि वे "ईसाई धर्म के साथ, सच्ची आस्था के साथ, ईश्वर की अनुकम्पा के साथ" रहते हैं, आदि। परन्तु क्रान्ति "के साथ", प्रचण्डतम आन्दोलन "के साथ" रहना! तो क्या क्रान्ति कोई "जड़सूत्रवादी धर्म" है जिसमें विश्वास करना ही पड़ता है?

आगे म्यूलबर्गर मुझे इस बात के लिए झिड़कते हैं कि मैंने उनके लेखों के सुस्पष्ट शब्दों की अवहेलना करते हुए यह कहा कि उन्होंने आवास प्रश्न को विशिष्ट रूप से मजदूर वर्ग का प्रश्न घोषित किया।

इस बार म्यूलबर्गर ने वस्तुतः सही बात कही है। मैंने सम्बन्धित अंश का नज़रन्दाज़ कर दिया था। इसे नज़रन्दाज़ करना मेरा अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य था क्योंकि यह तो उनके तर्क की पूरी प्रवृत्ति का सबसे बड़ा अभिलाक्षणिक गुण है। म्यूलबर्गर सीधे-सादे शब्दों में कहते हैं—

"चूँकि हम पर अक्सर तथा कई बार वर्ग नीति का अनुसरण करने तथा वर्ग प्रभुत्व, आदि के लिए प्रयत्नशील होने का बेहूदा आरोप लगाया जाता है, हम सबसे पहले तथा सुनिश्चित रूप से इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि

आवास प्रश्न मात्र ऐसा प्रश्न नहीं है जो विशिष्टतया सर्वहारा पर असर डालता हो, इसके विपरीत वह तो काफ़ी हद तक खुद मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों, निम्नपूँजीपति वर्ग तथा पूरी नौकरशाही से सरोकार रखता है ... आवास प्रश्न सामाजिक सुधार का ठीक वह बिन्दु है जो किसी अन्य की तुलना में एक ओर सर्वहारा के हितों तथा दूसरी ओर समाज के खुद मध्यम वर्गों के हितों की निर-पेक्ष आन्तरिक एकरूपता अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है। किराये के मकानों की यंत्रणादायी वेड़ियों से मध्यम वर्ग सर्वहारा वर्ग जितना ही और शायद उससे भी ज्यादा पीड़ित हैं ... आज मध्यम वर्गों को इस प्रश्न का सामना करना पड़ रहा है कि क्या वे ... तरुण, सशक्त तथा उत्साही मजदूर पार्टी के साथ संघबद्ध होकर समाज के रूपान्तरण की, ऐसे रूपान्तरण की प्रक्रिया में, जिसके वरदानों का सर्वोपरि वे उपभोग करेंगे, भाग लेने के लिए ... पर्याप्त शक्ति संचित कर सकते हैं।”

इस तरह मित्त म्यूलवर्गर यहां निम्नलिखित बातें सिद्ध करते हैं—

१. “हम” किसी “वर्ग नीति” का अनुसरण नहीं करते और “वर्ग प्रभुत्व” के लिए प्रयत्नशील नहीं हैं। परन्तु जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी, इसीलिए कि वह मजदूर पार्टी है, लाज़िमी तौर पर “वर्ग नीति” का, मजदूर वर्ग की नीति का अनुसरण करती है। चूँकि हर राजनीतिक पार्टी राज्य में अपने शासन की स्थापना करना चाहती है, इसलिए जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी भी लाज़िमी तौर पर अपना शासन मजदूर वर्ग का शासन—इसलिए “वर्ग प्रभुत्व”—स्थापित करना चाहती है। यही नहीं, अंग्रेज़ चार्टिस्टों से लेकर अब तक हर वास्तविक सर्वहारा पार्टी वर्ग नीति को, स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में सर्वहारा के संगठन को अपने संघर्ष की प्रमुख शर्त के रूप में तथा सर्वहारा के अधिनायकत्व को संघर्ष के तात्कालिक ध्येय के रूप में प्रस्तुत करती है। इसे “बेहूदा” बताकर म्यूलवर्गर सर्वहारा आन्दोलन की परिधि से बाहर आ जाते हैं तथा निम्न-पूँजीवादी समाजवाद के खेमे में जा पहुंचते हैं।

२. आवास प्रश्न का लाभ यह है कि वह विशिष्टतया मजदूर वर्ग का प्रश्न नहीं है अपितु ऐसा प्रश्न है जिसका “काफ़ी हद तक निम्नपूँजीपति वर्ग से सरोकार है”, क्योंकि आवास की कमी से “खुद मध्यम वर्ग सर्वहारा वर्ग जितना ही और शायद उससे भी ज्यादा पीड़ित हैं”। यदि कोई यह ऐलान करता है कि निम्नपूँजीपति वर्ग “शायद सर्वहारा से भी ज्यादा” तकलीफ़—भले ही एक मामले में—उठाता है तो वह यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसकी

निम्न-पूँजीवादी समाजवादियों में गिनती की जा रही है। तो क्या म्यूलबर्गर के पास शिकायत करने का कोई आधार है जब मैं यह कहता हूँ कि—

“अधिकतर इसी तरह की तकलीफों को लेकर, जिन्हें मजदूर वर्ग अन्य वर्गों और खास तौर पर निम्नपूँजीपति वर्ग के साथ झेलता है, निम्न-पूँजीवादी समाजवाद, जिसके प्रदों अनुयायी हैं, अपने को व्यस्त रखना पसन्द करते हैं। इसलिए यह कदापि संयोग की बात नहीं है कि हमारे जर्मन प्रदोंपंथी मुख्यतया आवास प्रश्न को अपना लेते हैं जो कदापि—जैसा कि हम देख चुके हैं—विशिष्टतया मजदूर प्रश्न नहीं है।”*

३. “समाज के खुद मध्यम वर्गों” के हितों तथा सर्वहारा के हितों के बीच “निरपेक्ष आन्तरिक एकरूपता” है। और सर्वहारा वर्ग नहीं, वरन् खुद ये मध्यम वर्ग ही समाज के रूपान्तरण की भावी प्रक्रिया के “वरदानों का सर्वोपरि उपभोग करेंगे”।

इसलिए मजदूर “सर्वोपरि” निम्नपूँजीपति वर्ग के हितार्थ भावी सामाजिक क्रान्ति करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, निम्नपूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग के हितों में “निरपेक्ष आन्तरिक एकरूपता” है। यदि निम्नपूँजीपति वर्ग के हितों की मजदूरों के हितों से आन्तरिक एकरूपता है तो मजदूरों के हितों की निम्नपूँजीपति वर्ग के हितों से आन्तरिक एकरूपता है। इस तरह निम्न-पूँजीवादी दृष्टिकोण को आन्दोलन में विद्यमान रहने का उतना ही अधिकार है जितना सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण को है। और अधिकार की समानता का ठीक यही दावा निम्न-पूँजीवादी समाजवाद के नाम से ज्ञात है।

इसलिए जब म्यूलबर्गर अपनी पुस्तिका के पृष्ठ २५ पर “छोटे उद्योग का समाज के वास्तविक अवलम्ब” के रूप में गुणगान करते हैं “क्योंकि अपने स्वरूप के कारण वह अपने अन्दर तीन तत्त्वों को, श्रम—अधिग्रहण—स्वामित्व को, मिलाता है, क्योंकि इन तत्त्वों को मिलाते हुए व्यक्ति के विकास की क्षमता के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करता” और जब वह विशेष रूप से आधुनिक उद्योग की इसलिए भर्त्सना करते हैं कि वह सामान्य मानव के इस संवर्द्धन-स्थल को नष्ट कर देता है और “एक प्रजननक्षम सशक्त वर्ग को लोगों के एक अचेतन ढेर में रूपान्तरित करता है जिसे यह पता ही नहीं होता कि वह अपनी चिन्ताभरी दृष्टि किस ओर केन्द्रित करे”, तो उनका यह कथन

* देखें प्रस्तुत खण्ड।—सं०

उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाता है। इस तरह म्यूलबर्गर के लिए निम्नपूँजीपति आदर्श मानव है तथा म्यूलबर्गर के लिए लघु उद्योग उत्पादन की आदर्श पद्धति है। इसलिए जब मैंने उन्हें निम्न-पूँजीवादी समाजवादियों की कोटि में रखा तो क्या मैंने उन्हें बदनाम किया ?

चूँकि म्यूलबर्गर प्रदों के सम्बन्ध में सारी ज़िम्मेवारी से इन्कार करते हैं, इसलिए यहां इस बात का आगे विवेचन करना निरर्थक होगा कि सुधार की प्रदों की योजनाओं का लक्ष्य समाज के तमाम सदस्यों को निम्नपूँजीपतियों तथा छोटे किसानों में रूपान्तरित करना है। इसी तरह निम्नपूँजीपतियों तथा मजदूरों के हितों की कथित एकरूपता की चर्चा करना भी अनावश्यक होगा। जो कुछ आवश्यक है, वह 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' में पहले से मौजूद है। (लाइपज़िग संस्करण, १८७२, पृष्ठ १२ तथा २१) *

इसलिए हमारे विवेचन का फल यह है कि "निम्नपूँजीपति प्रदोंसम्बन्धी मिथक" के साथ-साथ निम्नपूँजीपति म्यूलबर्गर सम्बन्धी असलियत भी प्रकट होती है।

२

अब हम एक मुख्य मुद्दे की ओर पहुँचते हैं। मैंने म्यूलबर्गर पर आरोप लगाया था कि उनके लेखों ने आर्थिक सम्बन्धों को कानूनी भाषा में अनूदित कर उनके साथ प्रदोंपंथी ढंग से जालसाजी की है। इसके एक उदाहरण के रूप में मैंने म्यूलबर्गर का निम्नलिखित वक्तव्य चुना था—

“मकान एक बार तैयार हो जाने पर सामाजिक श्रम के एक निश्चित अंश पर स्थायी कानूनी हक़ का काम देता है हालाँकि मकान के वास्तविक मूल्य से काफी ज्यादा मालिक को बहुत पहले ही किराये के रूप में भुगतान किया जा चुका होता है। तो होता यह है कि जो मकान, उदाहरण के लिए, पचास वर्ष पहले निर्मित हुआ था, वह अपने किराये के रूप में मूल लागत से दुगुना, तिगुना, पाँचगुना, दसगुना या इससे भी ज्यादा चुका देता है।”

म्यूलबर्गर को अब शिकायत है कि—

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड १, भाग २।—सं०

“यह सादा, संजीदा तथ्य-कथन एंगेल्स को मुझे इस आशय का ज्ञान देने का आधार प्रदान करता है कि मुझे यह समझाना चाहिए था कि मकान कैसे ‘क्रान्तनी हक’ बन जाता है—यही मेरे कार्य की परिधि के बिल्कुल बाहर की चीज थी ... वर्णन एक चीज और स्पष्टीकरण दूसरी चीज है। जब मैं प्रदों के साथ यह कहता हूँ कि समाज का आर्थिक जीवन अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत होना चाहिए तो मैं समकालीन समाज का एक ऐसे समाज के रूप में वर्णन कर रहा हूँ जिसमें यह सच है कि अधिकार की प्रत्येक अवधारणा लुप्त नहीं है परन्तु जिसमें क्रान्ति के अधिकार की अवधारणा लुप्त है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसमें स्वयं एंगेल्स स्वीकार करेंगे।”

चलिए, फ़िलहाल एक बार तैयार हो गये मकान तक ही अपने को सीमित रखा जाये। मकान एक बार बन चुकने पर अपने निर्माता को किराये के रूप में ज़मीन का किराया, मरम्मत की लागत, लगायी गयी निर्माण पूंजी पर ब्याज साथ ही उस पर हासिल मुनाफ़ा भी देता है; परिस्थितियों के अनुसार क्रमिक रूप से अदा किया जानेवाला किराया मूल लागत-कीमत का दुगुना, तिगुना, पांच-गुना या दसगुना तक हो सकता है। तो, मित्र म्यूलबर्गर, यह है “सादा, संजीदा तथ्य-कथन”, एक आर्थिक तथ्य; और यदि हम यह जानना चाहें कि यह “किस तरह होता है” कि यह तथ्य विद्यमान है, तो हमें आर्थिक क्षेत्र में जाँच करनी होगी। इसलिए आइये, इस तथ्य की ओर ज़रा और बारीकी से नज़र डालें ताकि कोई बच्चा तक इसे आगे ग़लत न समझ बैठे। जैसा कि सुविदिन है, माल की बिक्री इस तथ्य में निहित है कि उसका मालिक उसके उपभोग मूल्य का त्याग कर देता है तथा उसका विनिमय मूल्य पाता है। मालों के उपभोग मूल्य अन्य बातों के अलावा इस बात में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि उनके उपभोग के लिए आवश्यक कालों में भी भिन्नता होती है। रोटी की एक दिन में खपत हो जाती है, पतलून साल भर चलती है और मकान, कर्हें, सौ साल तक टिका रहता है। इसलिए टिकाऊ मालों के मामले में उनके उपभोग मूल्य को थोड़ा-थोड़ा करके और हर बार एक निश्चित अवधि के लिए बेचने की, अर्थात् किराये पर उठाने की सम्भावना पैदा होती है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके होनेवाली बिक्री से विनिमय मूल्य भी क्रमिक रूप से वसूल होता है। अग्रदत्त पूंजी और उससे प्राप्त होनेवाले मुनाफ़े की तत्काल अदायगी की मांग छोड़ने के बदले विक्रेता बड़ी हुई कीमत, ब्याज प्राप्त करता है जिसकी दर मनमाने ढंग से कदापि निर्धारित नहीं होती अपितु राजनीतिक अर्थशास्त्र के नियमों द्वारा

निर्धारित होती है। सौ वर्षों के अन्त में मकान का पूरा उपयोग हो चुका होता है, वह जर्जर हो चुका होता है तथा आगे रहने लायक नहीं रह जाता। यदि चुकाये जा चुके कुल किराये में से १) ज़मीन के किराये को सम्बन्धित अवधि में उसमें हुई किसी भी वृद्धि समेत तथा २) चालू मरम्मतों पर हुए खर्चों को काट लें तो हम देखेंगे कि शेष रह जानेवाली चीज़ों में औसतन ये होती हैं— १) मकान पर शुरू में लगायी गयी निर्माण पूंजी, २) इस पर मुनाफ़ा तथा ३) क्रमिक रूप से चुकायी जा रही पूंजी तथा मुनाफ़े पर व्याज। यह सच है कि इस अवधि के अन्त में किरायेदार के पास मकान नहीं होता परन्तु मकान-मालिक के पास भी तो मकान नहीं होता। मकान-मालिक के पास केवल ज़मीन का टुकड़ा (वर्तते वह उसका हो) और उस पर मौजूद निर्माण सामग्री रह जाती है जिसका अब वैसे मकान का रूप नहीं रह गया है। हो सकता है कि इस बीच मकान से इतनी राशि वसूल कर ली गयी हो जो “मूल लागत का पांचगुना या दसगुना” है, परन्तु हम देखेंगे कि उसका एकमात्र कारण ज़मीन के किराये में वृद्धि है। यह बात लन्दन जैसे शहरों में किसी से छुपी नहीं है जहां ज़मीन का मालिक तथा मकान का मालिक अधिकांश मामलों में दो पृथक-पृथक व्यक्ति होते हैं। किरायों में इतनी ज़बर्दस्त वृद्धि तेज़ी से बढ़ते हुए शहरों में होती है, गांवों में नहीं, जहां निर्माण स्थलियों का ज़मीन का किराया व्यवहारतः अपरिवर्तित रहता है। यह सुविदित है कि ज़मीन के किराये में वृद्धि को छोड़कर मकानों के किराये से मकान-मालिक को लगायी गयी पूंजी पर (मुनाफ़ा समेत) औसतन सात प्रतिशत से ज्यादा नहीं मिलता और इस राशि में से मरम्मत का खर्चा, आदि उठाना पड़ता है। संक्षेप में किराया-क्ररार माल का सर्वथा साधारण लेन-देन है जिसमें सिद्धान्ततः मज़दूर की दिलचस्पी माल के किसी भी अन्य लेन-देन की तुलना में—सिवाय उसके जो श्रम शक्ति के क्रय-विक्रय से सम्बन्धित होता है—म कम और न ज्यादा होती है; व्यवहारतः किराया-क्ररार मज़दूर के सामने पूंजीवादी ठगी के उन हज़ारों दूसरे रूपों में से एक है जिनके बारे में मैं एक पृथक प्रकाशन के पृष्ठ ४ पर कह चुका हूं।* जैसा कि मैंने उसमें सिद्ध किया था, इस रूप का भी आर्थिक नियमन होता है।

दूसरी ओर, म्यूलबर्गर किराया-क्ररार को विशुद्ध “मनमानेपन” के अलावा और कुछ मानते ही नहीं (उनकी कृति का पृष्ठ १६), लेकिन जब मैं यह सिद्ध

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड १, भाग २।—सं०

करता हूँ कि बात इसके बिल्कुल उलट है तो वह शिकायत करते हैं कि मैं उन्हें “केवल वे बातें” बता रहा हूँ “जिन्हें, खेद है, वह पहले से ही जानते हैं।”

परन्तु मकान-किराये की सारी जांच-पड़तालें भी हमें मकानों के किराये के खाते को उस आकांक्षा में परिणत करने में सक्षम नहीं बना सकतीं जो “क्रान्तिकारी विचार के गर्भ से अब तक जन्मे सबसे फलप्रद तथा सबसे भव्य आकांक्षाओं में से एक है।” इसे पूरा कर सकने के लिए यह जरूरी है कि हम इस सादे तथ्य को संजीदे राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र से विधिशास्त्र के कहीं व्यापक विचारधारात्मक क्षेत्र में ले जायें। मकान-किराया “मकान पर स्थायी कानूनी हक का काम करता है” और “इस तरह होता यह है” कि मकान का मूल्य किराये के रूप में दुगुना, तिगुना, पांचगुना या दसगुना ज्यादा बढ़ा किया जा सकता है। “कानूनी हक” हमें यह पता लगाने में रत्तीभर मदद नहीं देता कि यह वस्तुतः “किस तरह होता है”, और इसलिए मैंने कहा था कि मकान कैसे कानूनी हक बनता है, इसकी जांच करके ही म्यूलबर्गर यह पता लगा सकते थे कि “यह किस तरह होता है”। जैसा कि मैंने किया था, इसका पता हमें तभी चलता है जब हम मकान-किराये के आर्थिक स्वरूप की जांच करें, वजाय इसके कि उस कानूनी परिभाषा पर झगड़ा करें जिसके अन्तर्गत सत्ताधारी वर्ग इसकी इजाजत देता है। जो कोई किराये के खाते के लिए आर्थिक पग उठाने का इरादा करता है, उसे मकान-किराये के बारे में इससे कुछ ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि यह “वह नजराना है जो किरायदार पूंजी के स्थायी हक को देता है।” इसके उत्तर में म्यूलबर्गर फ़रमाते हैं—“वर्णन एक चीज़ है, स्पष्टीकरण दूसरी चीज़।”

इस तरह हमने मकान को, हालांकि वह स्थायी कदापि नहीं होता, मकान किराये पर स्थायी कानूनी हक में परिणत कर डाला है। यह चाहे “किसी तरह हो”, हम पाते हैं कि इस कानूनी हक के बल पर मकान अपनी मूल लागत का किराये के रूप में कई गुना लौटा देता है। कानूनी भाषा में अनुवाद की बदौलत खुशकिस्मती से हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र से इतनी दूर हो जाते हैं कि हमें इस घटना-व्यापार के अलावा और कुछ नहीं दिखायी देता कि किराये की राशि धीरे-धीरे मकान की लागत का कई गुना लौटा देती है। चूंकि हम कानूनी भाषा में बात कर रहे और सोच रहे हैं, हम इस घटना-व्यापार के लिए अधिकार तथा न्याय का पैमाना इस्तेमाल करते हैं और पाते हैं कि यह अन्यायपूर्ण है, कि यह “क्रान्ति के अधिकार की अवधारणा” से—इसका चाहे कुछ भी मतलब

हो—मेल नहीं खाता और इसलिए कानूनी हक्क बेकार है। हम आगे यह पाते हैं कि यही बात ब्याज देनेवाली पूंजी और पट्टे पर दी जानेवाली कृषि भूमि पर भी लागू होती है; और अब हमें स्वामित्व के इन वर्गों को दूसरे वर्गों से पृथक् करने और उनके साथ अलग से पेश आने का बहाना मिल जाता है। इसके फलस्वरूप ये मांगों की जाती हैं—१) मालिक को करार भंग करने का नोटिस देने के अधिकार तथा अपनी सम्पत्ति वापस मांगने के अधिकार से वंचित करना; २) पट्टेदार, देनदार या किरायेदार को वह वस्तु मुफ्त उपयोग के लिए देना जो उसे हस्तान्तरित की जाये परन्तु उसकी न हो; ३) मालिक को बिना ब्याज के लम्बी अवधि के दौरान अदायगी और इसके साथ हम इस क्षेत्र में प्रदोषी “सिद्धान्तों” को निबटा देते हैं। यही प्रदोषों का “सामाजिक विघटन” है।

प्रसंगतः यह सुस्पष्ट है कि यह पूरी सुधार योजना प्रायः विशिष्ट रूप से निम्नपूँजीपतियों तथा छोटे किसानों के लिए इस अर्थ में लाभप्रद है कि यह निम्नपूँजीपतियों तथा किसानों की उनकी स्थिति को मजबूत बनाती है। इस प्रकार “निम्नपूँजीपति प्रदोष”, जो म्यूलबर्गर के अनुसार एक मिथकीय आकृति हैं, यहां सर्वथा मूर्त्त ऐतिहासिक अस्तित्व धारण कर लेते हैं।

म्यूलबर्गर आगे कहते हैं—

“जब मैं प्रदोषों के साथ यह कहता हूँ कि समाज का आर्थिक जीवन अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत होना चाहिए तो मैं समकालीन समाज का एक ऐसे समाज के रूप में वर्णन कर रहा हूँ जिसमें यह सच है कि अधिकार की प्रत्येक अवधारणा लुप्त नहीं है परन्तु जिसमें क्रान्ति के अधिकार की अवधारणा लुप्त है, यह एक ऐसा तथ्य है जिसे स्वयं एंगेल्स स्वीकार करेंगे।”

दुर्भाग्यवश, मैं म्यूलबर्गर के लिए यह करने की स्थिति में नहीं हूँ। म्यूलबर्गर मांग करते हैं कि समाज अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत होना चाहिए और इसे वह वर्णन बताते हैं। यदि अदालत कर्ज चुकाने की मांग करने का समन लिये हुए अपना कारिन्दा भेजती है तो म्यूलबर्गर के अनुसार अदालत मेरा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णन करने के अलावा और कुछ नहीं करती जो कर्ज नहीं चुकाता! वर्णन एक चीज है तथा मांग दूसरी चीज है। ठीक इसी चीज में जर्मन वैज्ञानिक समाजवाद तथा प्रदोषों के बीच मूल अन्तर है। आर्थिक सम्बन्ध जिस रूप में हैं तथा जिस रूप में विकसित हो रहे हैं, हम उसी रूप में उनका

वर्णन करते हैं—और म्यूलबर्गर के कहने के बावजूद किसी वस्तु का वास्तविक वर्णन उस वस्तु का साथ ही स्पष्टीकरण भी होता है—तथा हम ठीक-ठीक आर्थिक दृष्टि से इस बात का प्रमाण पेश करते हैं कि उनका यह विकास साथ ही सामाजिक क्रान्ति के तत्त्वों का भी विकास है—यह एक ओर उस वर्ग, सर्वहारा वर्ग का विकास है जिसके जीवन की अवस्थाएं उसे लाजिमी तौर पर सामाजिक क्रान्ति की ओर धकेलती हैं तथा दूसरी ओर यह उत्पादक शक्तियों का विकास है जो पूंजीवादी समाज के ढांचे के अन्दर आगे न समा सकने के कारण उसे लाजिमी तौर पर तोड़ देंगी तथा जो साथ ही स्वयं सामाजिक प्रगति के हित में वर्ग-विभेद को सदा-सर्वदा के लिए मिटाने के साधन प्रस्तुत करती हैं। इसके विपरीत प्रूदों समकालीन समाज से मांग करते हैं कि वह अपने आर्थिक विकास के नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि न्याय के निर्देशों के अनुसार अपने को बदले (अधिकार की अवधारणा उनकी नहीं, बल्कि म्यूलबर्गर की है)। जहां हम सिद्ध कर देते हैं, वहां प्रूदों तथा उनके साथ म्यूलबर्गर प्रवचन तथा विलाप करते हैं।

“क्रान्ति के अधिकार की अवधारणा” क्या चीज है, यह समझने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूं। यह सच है कि प्रूदों “क्रान्ति” को एक तरह की देवी, अपने “न्याय” का साकार रूप तथा कार्यान्वयनकर्त्री बना देते हैं; ऐसा करते हुए वह १७८६-१७९४ की पूंजीवादी क्रान्ति को आगामी सर्वहारा क्रान्ति के साथ गड़मड़ करने की विचित्र श्रमती कर बैठते हैं। ऐसा वह लगभग अपनी सभी कृतियों में करते हैं, खास तौर पर १८४८ के बाद से। मैं उदाहरण के रूप में केवल एक को, अर्थात् ‘क्रान्ति का आम विचार’ नामक कृति को (१८६८, पृष्ठ ३६-४०) उद्धृत करने जा रहा हूं। लेकिन म्यूलबर्गर चूंकि प्रूदों के सम्बन्ध में सारी जिम्मेवारी से इन्कार करते हैं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि “क्रान्ति के अधिकार की अवधारणा” का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रूदों की ओर नज़र घुमाऊं, इसलिए मुझे धीरे अन्धकार में ही रहना होगा।

म्यूलबर्गर आगे कहते हैं—

“परन्तु न प्रूदों और न मैं विद्यमान अन्यायपूर्ण अवस्थाओं के स्पष्टीकरण के लिए ‘शाश्वत न्याय’ की दुहाई देते हैं और न—जैसा कि एंगेल्स मेरे बारे में कहते हैं—इस न्याय की दुहाई देकर इन अवस्थाओं में सुधार की अपेक्षा करते हैं।”

म्यूलबर्गर, जाहिर है, यह सोच रहे हैं कि “जर्मनी में प्रूदों सामान्यतया अज्ञात हैं।” प्रूदों अपनी तमाम कृतियों में तमाम सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रस्थापनाओं को “न्याय” के पैमाने से नापते हैं और उन्हें यह देखकर ठुकराते या स्वीकार करते हैं कि वे उसके अनुरूप हैं या नहीं जिसे वह “न्याय” कहते हैं। ‘आर्थिक अन्तर्विरोधों’ में इस न्याय को “शाश्वत न्याय”, «justice éternelle» कहते हैं। आगे चलकर शाश्वतता के बारे में और कुछ नहीं कहा जाता परन्तु विचार सारतः कायम रहता है। उदाहरण के लिए, उनकी कृति ‘क्रान्ति तथा धर्म में न्याय’ (१८५८) में निम्नलिखित अंश पूरे तीन खंडों में दिये गये प्रवचन का विषय है (खण्ड १, पृष्ठ ४२) —

“वह कौनसा मूल सिद्धान्त, समाजों का आंगिक, नियमनकारी, सार्वभौम मूल सिद्धान्त है, जो दूसरे सब को अपने अधीन करता है, जो तमाम विद्रोही तत्वों पर शासन करता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें दबाता है, सजा देता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कुचलता है? क्या है यह — धर्म, आदर्श या हित? ... मेरी राय में यह सिद्धान्त न्याय है। न्याय क्या है? यह तो मानवता का मूल सार है। विश्व की उत्पत्ति से लेकर अब तक यह क्या रहा है? कुछ भी नहीं। उसे क्या होना चाहिए? सब कुछ।”

न्याय, जो मानवता का मूल सार है, यदि शाश्वत न्याय नहीं है तो फिर क्या है? न्याय, जो समाजों का आंगिक, नियमनकारी, सार्वभौम मूल सिद्धान्त है, जो यह सब होते हुए भी अब तक कुछ भी नहीं रहा है, परन्तु जिसे सब कुछ होना चाहिए — यदि यह वह पैमाना नहीं है जिससे सारे मानवीय मामलों को नापा जाना चाहिए, यदि यह वह सबसे बड़ा पंच नहीं है जिससे सारे टकरावों में अपील की जानी चाहिए तो और क्या है? और क्या मैंने इसके अलावा और कोई दावा किया था कि प्रूदों राजनीतिक अर्थशास्त्र के बारे में अपने अज्ञान तथा बेवसी को छुपाते हुए तमाम आर्थिक सम्बन्धों को आर्थिक नियमों के पैमाने से नहीं, वरन् इस चीज से नापते हैं कि वे इस शाश्वत न्याय की उनकी अवधारणा से मेल खाते हैं या नहीं। और म्यूलबर्गर तथा प्रूदों में तब क्या अन्तर रह जाता है जब म्यूलबर्गर मांग करते हैं कि “आधुनिक समाज के जीवन में तमाम परिवर्तन... अधिकार की अवधारणा से ओतप्रोत होने चाहिए, अर्थात् उन्हें सर्वत्र न्याय की कड़ी अपेक्षाओं के अनुसार सम्पन्न किया जाना चाहिए”? तो क्या मुझे पढ़ना नहीं आता या म्यूलबर्गर को लिखना नहीं आता?

म्यूलबर्गर आगे कहते हैं —

“प्रूदों भी मार्क्स और एंगेल्स की ही तरह यह जानते हैं कि मानव समाज में न्यायिक नहीं, वरन् आर्थिक सम्बन्ध वास्तविक प्रेरक शक्ति हैं; वह यह भी जानते हैं कि किसी जनसङ्घ के अधिकार की अवधारणाएं किसी सम्बन्धित समय पर आर्थिक सम्बन्धों की, विशेष रूप से उत्पादन सम्बन्धों की अभिव्यक्ति, छाप, उपज हैं ... संक्षेप में प्रूदों के लिए अधिकार ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न होनेवाली आर्थिक उपज है।”

यदि प्रूदों यह सब (मैं म्यूल्बर्गर द्वारा प्रयुक्त अस्पष्ट अभिव्यंजनाओं को नज़रअन्दाज़ करने तथा उनके नेक इरादों को मानने के लिए तैयार हूँ), “मार्क्स तथा एंगेल्स की ही तरह यह जानते हैं”, तो फिर झगड़े के लिए रह क्या गया है? मुसीबत यह है कि प्रूदों के ज्ञान के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्न है। किसी सम्बन्धित समाज के आर्थिक सम्बन्ध अपने को सर्वप्रथम हितों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परन्तु प्रूदों अपनी अभी-अभी उद्धृत रचना में घुमा-फिरा कर यह कहते हैं कि “समाजों का आंगिक, नियमनकारी, सार्वभौम मूल सिद्धान्त, जो दूसरे सब को अपने अधीन करता है”, हित नहीं, वरन् न्याय है। और इसे वह अपनी तमाम कृतियों के तमाम निर्णायक अंशों में दुहराते हैं। यह सब म्यूल्बर्गर को यह कहने से नहीं रोकता—

“... आर्थिक अधिकार का विचार, जिस रूप में प्रूदों ने उसे सर्वोपरि ‘युद्ध तथा शान्ति’ में सर्वाधिक गहनतापूर्वक विकसित किया है, लासाल के मूल विचार से पूरी तरह मेल खाता है जिसे उन्होंने ‘हस्तगत अधिकारों की प्रणाली’ के लिए अपनी प्रस्तावना में इतने सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है।”

‘युद्ध तथा शान्ति’ प्रूदों की इतनी सारी अधकचरी कृतियों में शायद सबसे ज्यादा अधकचरी है। परन्तु मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इसे इतिहास की जर्मन भौतिकवादी अवधारणा के बारे में, जो समस्त ऐतिहासिक घटनाओं तथा विचारों, सारी राजनीति, दर्शन तथा धर्म पर सम्बन्धित ऐतिहासिक अवधि के जीवन की भौतिक, आर्थिक अवस्थाओं के दृष्टिकोण से प्रकाश डालती है, प्रूदों की कथित समझदारी के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। पुस्तक में इतनी कम भौतिकवादिता है कि वह स्रष्टा को मदद के लिए बुलाये बिना युद्ध के बारे में अपनी अवधारणा की रचना तक नहीं कर सकती—

“परन्तु स्रष्टा के, जिसने हमारे लिए जीवन का यह रूप चुना, अपने ही उद्देश्य थे।” (खंड २, पृष्ठ १००, १८६६ का संस्करण)

पुस्तक कैसे ऐतिहासिक ज्ञान पर आधारित है, उसका पता इस तथ्य से चल जाता है कि यह स्वर्ण युग के अस्तित्व में विश्वास करती है—

“आरम्भ में, जब मानवजाति पृथ्वी की सतह पर छितरे रूप में ही बसी हुई थी, प्रकृति बिना कठिनाई के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करती थी। यह था स्वर्ण युग, शान्ति तथा समृद्धि का युग।” (वही, पृष्ठ १०२)

प्रदों का आर्थिक दृष्टिकोण घोर माल्थुसपंथी दृष्टिकोण है—

“जब उत्पादन दुगुना हो जायेगा तो आबादी भी जल्द दुगुनी हो जायेगी।” (पृष्ठ १०६)

तो फिर इस पुस्तक में भौतिकवाद किसमें निहित है? इस चीज़ में कि यह घोषित करती है कि युद्ध का कारण सदैव और अब भी “कंगाली” है (उदाहरणार्थ पृष्ठ १४३)। चचा ब्रेसिंग* भी एक ऐसे ही निपुण भौतिकवादी थे जब उन्होंने अपने १८४८ के भाषण में बड़े सारगर्भित शब्द कहे थे—“बड़ी गरीबी का कारण बड़ी *pauvrete*** है।”

लासाल की कृति ‘हस्तगत अधिकारों की प्रणाली’ पर न्यायविद की ही नहीं, वरन् पुराने हेगेलपंथी की भी छाप है। पृष्ठ ७ पर वह सुस्पष्ट रूप से कहते हैं कि “अर्थशास्त्र में भी हस्तगत अधिकार की अवधारणा आगे के सारे विकास की प्रेरक शक्ति है” और वह यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं (पृष्ठ ११) कि “अधिकार एक तर्कपरक अंग है जो स्वयं अपने आप से विकसित होता है (और इसलिए आर्थिक पूर्वापेक्षाओं से नहीं)। लासाल के लिए प्रश्न अधिकार को आर्थिक सम्बन्धों से नहीं, वरन् “स्वयं इच्छा की अवधारणा से ग्रहण करने का है, जिसका अधिकार का दर्शन केवल विकास तथा प्रतिबिम्ब है” (पृष्ठ १२)। तो यह पुस्तक यहां कैसे आ गयी? प्रदों तथा लासाल में अन्तर सिर्फ इतना है कि लासाल वास्तव में विधिशास्त्री तथा हेगेलपंथी थे जबकि

* चचा ब्रेसिंग—जर्मन पूंजीवादी हास्य रस-लेखक तथा उपन्यासकार फ्रिट्ज शप्टर की कृतियों का एक हास्य-पात्र।—सं०

** कंगाली।—सं०

विधिशास्त्र तथा दर्शन दोनों में और साथ ही दूसरे सारे मामलों में भी प्रदों मात्र पल्लवग्राही थे।

मैं भली भांति जानता हूँ कि प्रदों, जो अपनी बात का स्वयं निरन्तर खंडन करते रहते हैं, समय-समय पर इस तरह का बयान दे बैठते हैं मानों उन्होंने विचारों का तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण किया हो। परन्तु ऐसे बयानों में कोई महत्व नहीं होता जब उनकी तुलना उनके मूल चिन्तन से की जाती है; और जहां वे मिलते भी हैं, वे बिल्कुल उलझे हुए होते हैं तथा उनमें अन्तर्निहित असंगतता होती है।

समाज के विकास की किसी खास, बहुत ही आरम्भिक मंजिल में यह आवश्यकता पैदा होती है कि वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा विनिमय की नित्य आवर्तक क्रियाओं को एक समान नियम के अन्तर्गत लाया जाये, यह सुनिश्चित किया जाये कि व्यक्ति अपने को उत्पादन तथा विनिमय की समान अवस्थाओं के मातहत करे। यह नियम, जो आरम्भ में रीति होता है, शीघ्र कानून बन जाता है। कानून के साथ ऐसे निकाय भी लाजिमी तौर पर प्रकट होते हैं जिन्हें इसके परिपालन की जिम्मेवारी सौंपी जाती है—याने सार्वजनिक सत्ता, राज्य। और अधिक सामाजिक विकास के साथ कानून न्यूनाधिक रूप में एक व्यापक कानूनी प्रणाली बन जाता है। यह कानूनी प्रणाली जितनी ज्यादा जटिल होती है, उसकी अभिव्यक्ति का रूप उससे उतना ही दूर होता जाता है जिसमें सामाजिक जीवन की सामान्य आर्थिक अवस्थाएं व्यक्त हुआ करती हैं। वह ऐसे स्वतंत्र तत्त्व के रूप में प्रकट होती है जो अपने अस्तित्व का तथा अपने आगे के विकास की नींव का औचित्य आर्थिक सम्बन्धों से नहीं, वरन् अपनी ही आन्तरिक आधारशिलाओं से या कहें “इच्छा की अवधारणा” से प्राप्त करता है। लोग भूल जाते हैं कि जिस तरह उन्होंने स्वयं अपने मूल को पशु-जगत से प्राप्त किया, उसी तरह उनके अधिकार ने अपना मूल जीवन की आर्थिक अवस्थाओं से प्राप्त किया था। कानूनी प्रणाली द्वारा विकसित होकर एक जटिल, व्यापक सम्पूर्ण इकाई का रूप ग्रहण करने के साथ श्रम का एक नया सामाजिक विभाजन आवश्यक हो जाता है: पेशेवर न्यायविदों की एक श्रेणी विकसित हो जाती है और इनके साथ ही विधिशास्त्र जन्म लेता है। और आगे विकास होने पर यह शास्त्र विभिन्न जनगण तथा विभिन्न कालों की कानूनी प्रणालियों की तुलना सम्बद्ध आर्थिक सम्बन्धों के प्रतिबिम्ब के रूप में नहीं, वरन् ऐसी प्रणालियों के रूप में करता है जो अपना प्रमाणीकरण अपने आप में पाती हैं। यह तुलना कुछ समान बिन्दुओं की पूर्वकल्पना

करती है और कानूनवेत्ता इन तमाम कानूनी प्रणालियों में न्यूनाधिक समान बिन्दुओं को नैसर्गिक अधिकार के नाम से पुकारते हैं। क्या कुछ नैसर्गिक अधिकार के क्षेत्र में आता है और क्या नहीं, यह मापने के लिए इस्तेमाल किया जानेवाला पैमाना स्वयं अधिकार की, सर्वाधिक अमूर्त अभिव्यक्ति है अर्थात् न्याय। इसलिए इसके आगे से कानूनवेत्ताओं तथा उन तमाम लोगों के लिए, जो उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं, अधिकार का विकास मानव अवस्थाओं को — जहां तक वे कानूनी भाषा में व्यक्त होती हैं — न्याय के आदर्श, शाश्वत न्याय के अधिक समीप लाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। और यह न्याय सदैव विद्यमान आर्थिक सम्बन्धों की कभी उनके अनुदारपंथी तो कभी उनके क्रान्तिकारी दृष्टिकोण से आदर्शीकृत, महिमामंडित अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं होता। यूनानियों तथा रोमनों का न्याय दासप्रथा को न्यायसंगत ठहराता था; १७८६ के पूंजीपति वर्ग के न्याय ने सामन्तवाद को इस आधार पर मिटाने की मांग की कि वह अन्यायपूर्ण है। प्रशियाई जमींदारों के लिए तो तुच्छ ज़िला कानून तक शाश्वत न्याय का उल्लंघन है।⁷⁰ इसलिए शाश्वत न्याय की अवधारणा देशकाल के अनुसार ही नहीं, वरन् सम्बन्धित लोगों के अनुसार भी भिन्न-भिन्न होती है और उसकी गिनती उन चीजों में होती है जिनके बारे में मूलबर्गर ने ठीक ही कहा है, “हरेक किसी चीज को अलग-अलग ढंग से समझता है।” जहां दैनंदिन जीवन में चर्चित सम्बन्धों के सारल्य को देखते हुए अधिकार, गलती, न्याय तथा अधिकार की भावना जैसी अभिव्यंजनाएं सामाजिक मामलों तक के संदर्भ में बिना किसी गलतफ़हमी के स्वीकार की जाती हैं, वहां वे, जैसा कि हम देख चुके हैं, आर्थिक सम्बन्धों की किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच में उसी तरह की घोर भ्रान्ति पैदा करती हैं जैसी उदाहरण के लिए आधुनिक रसायनशास्त्र में फ़्लोजिस्टीन सिद्धान्त की शब्दावली के बरकरार रखे जाने की सूरत में पैदा हो सकती है। यह भ्रान्ति उस समय और भी विकृत हो जाती है जब प्रूदों की तरह कोई इस सामाजिक फ़्लोजिस्टीन में, “न्याय” में विश्वास करे अथवा मूलबर्गर की तरह यह यकीन दिलाये कि फ़्लोजिस्टीन सिद्धान्त आक्सीजन सिद्धान्त से कम सही नहीं है।*

* आक्सीजन की खोज से पहले रसायनज्ञ वायुमंडलीय वायु में पदार्थों के दहन का कारण यह माना करते थे कि उसमें एक विशेष दहनशील पदार्थ, फ़्लोजिस्टीन विद्यमान है जो दहन की प्रक्रिया के दौरान गायब हो जाता है। भूकि उन्होंने देखा कि दहन के बाद सामान्य पदार्थ जलने से पूर्व की तुलना में

म्यूलबर्गर आगे शिकायत करते हैं कि मैंने उनके निम्नलिखित “जोरदार” बयान को प्रतिक्रियावादी विलाप बताया —

“हमारी बहुप्रशंसित शताब्दी पर इस तथ्य से बड़ा और कोई व्यंग्य नहीं हो सकता कि बड़े शहरों में ६० प्रतिशत और इससे भी बड़ी आबादी के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वे अपना कह सकें।”

निश्चय ही यदि म्यूलबर्गर ने अपने को, जैसा कि वह जताते हैं, “वर्तमान काल की विभीषिकाओं” तक सीमित रखा होता तो मैंने यकीनन “उनके तथा उनके विनम्र शब्दों के बारे में” एक भी शब्द न कहा होता। परन्तु असलीयत यह है कि वह सर्वथा भिन्न काम करते हैं। वह इन “विभीषिकाओं” को इस तथ्य का परिणाम बताते हैं कि मजदूरों के पास “कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे वे अपना कह सकें।” चाहे कोई “वर्तमान काल की विभीषिकाओं” पर इसलिए विलाप करे कि मकानों पर मजदूरों का स्वामित्व मिटा दिया गया है या चाहे जमींदारों की तरह इसलिए विलाप करे कि सामन्तवाद तथा शिल्प संघ मिटा दिये गये हैं, इनसे अवश्यम्भाविता के, ऐतिहासिक आवश्यकता के आगमन पर प्रतिक्रियावादी विलाप, शोकपूर्ण गीत के अलावा और कोई परिणाम निकलनेवाला नहीं है। इसका प्रतिक्रियावादी स्वरूप ठीक इसी तथ्य में निहित है कि म्यूलबर्गर मजदूरों के लिए मकानों पर निजी स्वामित्व की पुनःस्थापना करना चाहते हैं — यह ऐसा मामला है जिसे इतिहास बहुत पहले ही खत्म कर चुका है; कि वह मजदूरों में से हरेक को फिर से अपने मकान का स्वामी बनाने के अलावा उनकी मुक्ति के किसी और रास्ते की कल्पना नहीं कर सकते।

ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए उन्होंने घोषित किया कि फ्लोजिस्टीन में एक ऋणात्मक भार होता है जिसके फलस्वरूप फ्लोजिस्टीन से रहित पदार्थ फ्लोजिस्टीन के होने की तुलना में ज्यादा भारी होता है। इस तरह आक्सीजन के सारे मुख्य गुणों का कारण फ्लोजिस्टीन बताया गया, परन्तु पूर्ण विलोमित रूप में। जब यह खोज हो गयी कि दहन एक जलते पदार्थ का दूसरे पदार्थ — आक्सीजन — से संयोजन है और आक्सीजन मूल रूप में प्राप्त हो गया, तो इस खोज ने पुरानी मान्यता का अन्त कर दिया परन्तु इसका पुराने रसायनज्ञ लम्बे अर्से तक विरोध करते रहे। (एंगेल्स की टिप्पणी)

वह आगे कहते हैं—

“मैं पूरे जोर से घोषणा करता हूँ कि वास्तविक संघर्ष उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के विरुद्ध किया जाता है; केवल उसके रूपान्तरण से ही आवासीय परिस्थितियों में सुधार की आशा की जा सकती है। एंगेल्स तो इसमें से कुछ भी नहीं देख पाते ... मैं मकानों को किराये पर उठाने की व्यवस्था खत्म करने के लिए सामाजिक प्रश्न के पूर्ण समाधान की पूर्वकल्पना करता हूँ।”

दुर्भाग्यवश, मुझे अभी भी इसमें से कुछ नहीं दिखायी दे रहा है। मेरे लिए यह जानना अब भी असम्भव है कि कोई व्यक्ति, जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना, अपने मस्तिष्क के गुप्त खानों में क्या पूर्वकल्पना कर रहा है। मैं तो मात्र यही कर सकता था कि म्यूलबर्गर के छपे हुए लेखों को ही पकड़े रहूँ। और उनमें (पुस्तिका के पृष्ठ १५ और १६ पर) आज भी यही पढ़ने को मिलता है कि किराये पर मकान उठाने की व्यवस्था का उन्मूलन कर सकने के लिए म्यूलबर्गर ... किराये के मकानों के सिवाय और किसी चीज़ की पूर्वकल्पना नहीं करते। पृष्ठ १७ पर ही वह “पूँजी की उत्पादकता से सीधे-सीधे निपटते” हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अपने उत्तर में भी वह इसकी पुष्टि यह कहकर करते हैं—

“यह एक तरह इस चीज़ को प्रदर्शित करने का प्रश्न था कि विद्यमान परिस्थितियों से कैसे आवास प्रश्न का पूर्ण समाधान हासिल किया जा सकता था।”

“विद्यमान परिस्थितियों से” और “उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति के रूपान्तरण से” (इसे उन्मूलन पढ़ें) — ये तो निश्चय ही दो सर्वथा परस्परविरोधी वस्तुएं हैं।

स्वभावतः म्यूलबर्गर इस बात का रोना रोते हैं कि मैं श्री दोल्फुस और दूसरे कारखानेदारों द्वारा मजदूरों को अपने मकान हासिल करने में मदद देने की शोकोपकारी कोशिशों को म्यूलबर्गर की प्रदोष्यी योजनाओं का एकमात्र सम्भव व्यावहारिक मूल रूप मानता हूँ। यदि वह अनुभव कर लेते कि समाज की मुक्ति के लिए प्रदोष्य की योजना पूरी तरह पूंजीवादी समाज पर आधारित कल्पना की छद्मता है तो वह इस पर विश्वास नहीं करते। मैंने उनके नेक इरादों को कभी

चुनौती नहीं दी। परन्तु वह तब डा० रेशाउएर की इस बात के लिए क्यों प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने वियेना नगरपालिका से श्री दोल्फुस की योजनाओं का अनुकरण करने का प्रस्ताव किया? ७

म्यूलबर्गर आगे कहते हैं—

“जहां तक विशेष रूप से नगर तथा देहात के बीच विरोध का प्रश्न है, उसे मिटाने की इच्छा कल्पनाविलास है। यह विरोध नैसर्गिक है, यह कहना अधिक सही होगा कि इसका ऐतिहासिक रूप से प्रादुर्भाव हुआ है ... सवाल इस विरोध को मिटाने का नहीं, वरन् ऐसे राजनीतिक तथा सामाजिक रूप ढूंढने का है जिनमें यह हानिरहित होगा, यही नहीं, वस्तुतः फलप्रद भी होगा। इस तरह हितों के शान्तिपूर्ण तालमेल की, उनके धीरे-धीरे सन्तुलन की अपेक्षा करना सम्भव होगा।”

तो नगर तथा देहात के बीच विरोध मिटाना कल्पनाविलास है क्योंकि यह विरोध नैसर्गिक है, यह कहना ज्यादा सही होगा, कि इसका ऐतिहासिक रूप से प्रादुर्भाव हुआ है। आइये, इस तर्क को आधुनिक समाज के अन्य विरोधों पर लागू कर देखें कि हम कहां पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए—

“जहां तक विशेष रूप से” पूंजीपतियों तथा उजरती मजदूरों “के बीच विरोध का प्रश्न है, उसे मिटाने की इच्छा कल्पनाविलास है। यह विरोध नैसर्गिक है, यह कहना अधिक सही होगा कि इसका ऐतिहासिक रूप से प्रादुर्भाव हुआ है। सवाल इस विरोध को मिटाने का नहीं, वरन् ऐसे राजनीतिक तथा सामाजिक रूप ढूंढने का है जिनमें यह हानिरहित होगा, यही नहीं, वस्तुतः फलप्रद भी होगा। इस तरह हितों के शान्तिपूर्ण तालमेल की, उनके धीरे-धीरे सन्तुलन की अपेक्षा करना सम्भव होगा।”

और इस तरह हम फिर शूल्ज़े-डेलिच के पास पहुंच जाते हैं।

नगर तथा देहात के बीच विरोध को मिटाना पूंजीपतियों तथा उजरती मजदूरों के बीच विरोध को मिटाने से न कम और न ज्यादा कल्पनाविलास है। या! दिनोंदिन औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन की अधिकाधिक मांग बनता जा रहा है। इसकी जितनी जोरदार ढंग से मांग लिबिंग ने कृषि रसायन-सम्बन्धी अपनी कृतियों में की है उतनी और किसी ने नहीं की है; उन्होंने अपनी इन कृतियों में हमेशा सबसे पहले इस चीज की मांग की है कि इन्सान ज़मीन से जिनगा। पाता है, उतना उसे ज़मीन को वापस करना होगा; इन कृतियों में वह मांग

करते हैं कि केवल शहरों, खास तौर पर बड़े शहरों का अस्तित्व ही इसे नहीं होने देता। जब कोई यह देखता है कि यहां, अकेले लन्दन में पूरे सैक्सोनी राज्य में तैयार होनेवाली खाद से ज्यादा रोज़ भारी खर्चा कर समुद्र में बहा दी जाती है, और इस से पूरे लन्दन के लिए ज़हर न बनने देने के लिए कितने विशाल ढांचों की आवश्यकता पड़ती है तो नगर तथा देहात के बीच विरोध मिटाने के कल्पनाविलास को उल्लेखनीय व्यावहारिक आधार मिल जाता है। और बर्लिन तक का, जो अपेक्षाकृत छोटा है, कम से कम तीस साल से अपनी ही गन्दगी की बदबू में दम घुटता आया है। दूसरी ओर, किसानों को ज्यों का त्यों रखते हुए वर्तमान पूंजीवादी समाज को उभारने की प्रदों की तरह इच्छा करना पूर्णतया कल्पनाविलास है। पूरे देश में आबादी का यथासम्भव समरूप वितरण करके ही, औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम करके और इस तरह आवश्यक हो जानेवाले संचार साधनों का विस्तार करके ही, — निस्संदेह यह मानते हुए कि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति का उन्मूलन किया जायेगा — देहाती आबादी को उस अलगाव तथा जड़ता से छुटकारा दिलाना सम्भव होगा जिनके बीच वह हजारों वर्षों से प्रायः अपरिवर्तित रूप में पनपती रही है। यह मानना कल्पनाविलास नहीं है कि मानवजाति की उन बेड़ियों से, जिन्हें उसके ऐतिहासिक अतीत ने तैयार किया है, मुक्ति तभी पूर्ण होगी जब नगर तथा देहात के बीच विरोध मिटा दिया जायेगा; कल्पनाविलास तब शुरू होता है जब कोई “विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर” ऐसे रूप की पूर्वकल्पना करता है जिसमें विद्यमान समाज के इस या उस विरोध का समाधान किया जाना है। और आवास प्रश्न के हल के लिए प्रदोंपंथी फ़ार्मूला अपनाकर म्यूलबर्गर ठीक यही कर रहे हैं।

म्यूलबर्गर आगे यह शिकायत करते हुए कि मैंने “पूँजी तथा ब्याज के विषय में प्रदों के वीभत्स विचारों” के लिए कुछ हद तक उन्हें भी उत्तरदायी बना दिया है, घोषित करते हैं—

“मेरी यह पूर्वमान्यता है कि उत्पादन सम्बन्धों का परिवर्तन एक पूर्वसिद्ध तथ्य है तथा ब्याज की दर का नियमन करनेवाला संक्रमणात्मक क़ानून उत्पादन सम्बन्धों से नहीं, वरन् सामाजिक आवर्त से, संचलन के सम्बन्धों से ताल्लुक रखता है ... उत्पादन सम्बन्धों का परिवर्तन अथवा, जर्मन पंथ के अधिक सटीक शब्दों में, उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति का उन्मूलन निस्संदेह ब्याज ख़त्म करने के संक्रमणात्मक क़ानून के परिणामस्वरूप, जिसे एंगेल्स मेरे मुंह से कहलाने का

प्रयत्न करते हैं, सम्पन्न नहीं होगा अपितु मेहनतकश जनता द्वारा श्रम के सारे औजारों के वास्तविक अभिग्रहण, समग्र उद्योग के अभिग्रहण द्वारा सम्पन्न होगा। मेहनतकश जनता उस दशा में विमोचन की पूजा” (!) “करेगी या तात्कालिक हस्तगतकरण की, यह तय करना न मेरा और न एंगेल्स का काम है।”

मैं हैरान होकर अपनी आंखें मलता हूं। मैं म्यूलबर्गर के निबन्ध को शुरू से लेकर आखिर तक फिर पढ़ जाता हूं ताकि वह अंश ढूंढ सकूं जिसमें उन्होंने कहा हो कि किराये के आवास का विमोचन “मेहनतकश जनता द्वारा श्रम के सारे औजारों के वास्तविक अभिग्रहण, समग्र उद्योग के अभिग्रहण को” एक स्वतःसिद्ध तथ्य के रूप में पूर्वकल्पना करता है। परन्तु मुझे कहीं भी ऐसा अंश नहीं मिलता। वह है ही नहीं। कहीं भी “वास्तविक अभिग्रहण” की चर्चा नहीं है। अलबत्ता पृष्ठ १७ पर निम्नलिखित अंश अवश्य है—

“आइये, अब यह मान लें कि पूंजी की उत्पादकता से, उदाहरण के लिए, एक संक्रमणात्मक क़ानून द्वारा वस्तुतः सीधे-सीधे निपटा जाता है—जैसा कि देर-सबेर करना ही होगा—जो सारी पूंजियों पर एक प्रतिशत ब्याज निर्धारित करता है, परन्तु ध्यान रहे, इस प्रवृत्ति के साथ कि ब्याज की यह दर भी अधिकाधिक शून्य की ओर पहुंचेगी ... तमाम अन्य उत्पादों की तरह मकान और आवास भी स्वभावतया इस क़ानून के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं ... इसलिए हम देखते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी किराये के घरों का विमोचन सामान्यतया पूंजी की उत्पादकता के उन्मूलन का एक आवश्यक परिणाम है।”

इस तरह म्यूलबर्गर की नवीनतम पैतरेबाजी के विपरीत यहां सीधे-सादे शब्दों में यह कहा गया है कि पूंजी की उत्पादकता से—इन भ्रान्तिपूर्ण शब्दों से उनका निश्चित रूप से तात्पर्य उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति से है—वस्तुतः ब्याज ख़त्म करने के क़ानून द्वारा सीधे-सीधे निपटा गया है और ठीक इसी क़ानून के फलस्वरूप “किराये के घरों का विमोचन सामान्यतया पूंजी की उत्पादकता के उन्मूलन का एक आवश्यक परिणाम है।” अब म्यूलबर्गर कहते हैं—कतई नहीं। यह संक्रमणात्मक क़ानून “उत्पादन सम्बन्धों से नहीं, वरन् संचलन के सम्बन्धों से ताल्लुक रखता है।” इस घोर अन्तर्विरोध को, जो गेटे के शब्दों में “बुद्धिमानों के लिए उतना ही रहस्यमय है जितना मूर्खों के लिए”*, मेरे लिए केवल यही मानना शेष रह

* गेटे, ‘फ़ाउस्ट’, भाग १, अंक ६ ‘चुडैल की गुफा’ (पदान्वय)।—सं०

जाता है कि मेरा साबिक़ा दो पृथक-पृथक म्यूलबर्ग़रों से पड़ रहा है जिनमें से एक को यही शिकायत है कि मैंने “उसके मुंह से वह कहलाने” का यत्न किया जो दूसरे ने प्रकाशित करा दिया।

यह निस्सन्देह सच है कि मेहनतकश जनता न मुझसे और न म्यूलबर्ग़र से यह पूछेगी कि वास्तविक अभिग्रहण में उसे “विमोचन की पूजा करनी चाहिए या तात्कालिक हस्तगतकरण की”। पूरी सम्भावना इसी बात की है कि वह “पूजा” न करना ही ज़्यादा पसन्द करे। परन्तु मेहनतकश जनता द्वारा श्रम के सारे औज़ारों के अभिग्रहण का कभी कोई मसला ही नहीं उठा था; मसला तो केवल म्यूलबर्ग़र के इस दावे (पृष्ठ १७) का था कि “आवास प्रश्न के हल की सारी अन्तर्वस्तु विमोचन शब्द में निहित है।” अब यदि वह विमोचन को सरासर सन्देहास्पद मानते हैं तो फिर अपने को, मुझे तथा पाठकों को यह व्यर्थ कष्ट देने का मतलब ही क्या था?

इसके अलावा, यह परिलक्षित किया जाना चाहिए कि श्रम के सारे औज़ारों का “वास्तविक अभिग्रहण”, मेहनतकश जनता द्वारा समग्र उद्योग पर अधिकार प्रदोष्यी “विमोचन” के ठीक विपरीत है। दूसरे मामले में अलग-अलग मजदूर आवास, ज़मीन के टुकड़े तथा श्रम के औज़ारों का स्वामी बन जाते हैं; पहले मामले में “मेहनतकश जनता” मकानों, कारख़ानों तथा श्रम के औज़ारों की सामूहिक स्वामी बनी रहती है और लागत का हरजाना पाये बिना उन्हें अलग-अलग व्यक्तियों या संघों को कम से कम संक्रमण काल में इस्तेमाल करने की शायद ही इजाज़त दी जाये। इसी तरह भूमि पर स्वामित्व का उन्मूलन ज़मीन के किराये का उन्मूलन नहीं है, वरन् उसे समाज को स्थानान्तरित—भले ही संशोधित रूप में—करना मात्र है। इसलिए मेहनतकश जनता द्वारा श्रम के सारे औज़ारों का वास्तविक अभिग्रहण किराया सम्बन्धों के बरकरार रखे जाने की सम्भावना कतई ख़त्म नहीं करता।

सामान्यतया प्रश्न यह नहीं है कि सर्वहारा सत्तारूढ़ होने पर उत्पादन साधनों, कच्चा माल तथा आजीविका के साधनों पर बल प्रयोग द्वारा कब्ज़ा कर लेगा, उनका फ़ौरन मुआवज़ा देगा या वह छोटी-छोटी किश्तों में अदायगी कर सम्पत्ति का विमोचन करेगा। इस तरह के सवाल का पहले ही और तमाम परिस्थितियों के लिए उत्तर देने की चेष्टा करना कल्पनालोक का निर्माण करना होगा और इसे मैं दूसरों के लिए छोड़ देता हूँ।

म्यूलबर्गर की विविध पैतरेबाज़ियों के बीच से रास्ता ढूँढते हुए असल मसले तक, जिसका उत्तर देने से वह होशियारी से कतराते हैं, पहुंचने के लिए इतनी स्याही तथा कागज़ खर्च करना ज़रूरी था।

म्यूलबर्गर ने अपने लेख में कौनसी ठोस बातें कहीं?

पहली—कि “मकान, निर्माण स्थली, आदि की मूल लागत तथा उसके वर्तमान मूल्य में अन्तर” पर समाज का अधिकार है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस अन्तर को ज़मीन का किराया कहते हैं। प्रूदों भी इसे समाज के लिए हस्तगत करना चाहते हैं जैसा कि उनकी पुस्तक ‘क्रान्ति का आम विचार’ में—पृष्ठ २१६, १८६८ का संस्करण—पढ़ने को मिलता है।

दूसरी—कि आवास समस्या का हल इसमें निहित है कि हरेक अपने आवास में किरायेदार होने की जगह उसका स्वामी बने।

तीसरी—कि इस समाधान को एक ऐसा क़ानून पास कर मूर्त रूप दिया जायेगा जो किराये की अदायगी को मकान की ख़रीद की कीमत की किश्तों में परिणत कर देगा। इनमें से दूसरा और तीसरा मुद्दा प्रूदों से लिये गये हैं जिन्हें हरेक ‘क्रान्ति का आम विचार’ पुस्तक के पृष्ठ १६६ आदि में देख सकता है जबकि पृष्ठ २०३ पर सम्बन्धित क़ानून का मसौदा पहले से तैयार किया हुआ मिलता है।

चौथी—कि पूँजी की उत्पादकता की समस्या से सीधे-सीधे एक संक्रमणात्मक क़ानून द्वारा निपटा जाता है जो व्याज की दर घटाकर अस्थायी तौर पर एक प्रतिशत कर देता है तथा जिसमें उसे आगे चलकर और कमी करने का प्रावधान होता है। यह मुद्दा भी प्रूदों से प्राप्त किया गया है जिसे ‘आम विचार’ के पृष्ठ १८२ से लेकर १८६ तक विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है।

इनमें से हरेक मुद्दे के मामले में मैंने प्रूदों के उन लेखांशों को उद्धृत कर दिया है जिनमें म्यूलबर्गर द्वारा की गयी नक़ल का मूल मिल सकता है, और अब मैं पूछता हूँ कि मैंने एक ऐसे लेख के, जिसमें पूर्णतया प्रूदोंपंथी, केवल प्रूदोंपंथी विचार हैं, लेखक को प्रूदोंपंथी कहकर क्या सही बात नहीं कही है? फिर भी म्यूलबर्गर को सबसे अधिक कटु शिकायत इस बात से है कि मैंने उन्हें इसलिए प्रूदोंपंथी कहा कि मुझे “कुछ ऐसी चन्द अभिव्यंजनाएं मिलीं जो प्रूदों की विशिष्टता हैं!” बात इसके विपरीत है। सारी “अभिव्यंजनाएं” म्यूलबर्गर

की हैं तथा उनकी अन्तर्वस्तु प्रदों की है। और मैं जब इस प्रदोंपंथी लेख के साथ प्रदों को जोड़ता हूँ तो मूलवर्ग शिकायत करते हैं कि मैं प्रदों के “बीभत्स विचार” उनके बता रहा हूँ।

इस प्रदोंपंथी योजना का मैंने क्या उत्तर दिया था?

पहला—कि जमीन के किराये का राज्य को स्थानान्तरण जमीन पर निजी स्वामित्व के उन्मूलन के बराबर है।

दूसरा—कि किराये के घर के विमोचन तथा आवास का स्वामित्व ऐसे पक्ष को, जो अब तक वहाँ किरायादार था, हस्तान्तरित करने से उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति को ज़रा भी आंच नहीं आती।

तीसरा—कि बड़े पैमाने के उद्योग तथा नगर के आधुनिक विकास के कारण यह प्रस्ताव उतना ही बेतुका है जितना प्रतिक्रियावादी और प्रत्येक व्यक्ति के अपने आवास पर निजी स्वामित्व को फिर से लागू किया जाना प्रतिगामी पग होगा।

चौथा—कि पूंजी पर व्याज की दर की अनिवार्य कमी उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति पर कदापि प्रहार नहीं करेगी। इसके विपरीत यह—जैसा कि सूदखोरी विरोधी कानून सिद्ध करते हैं—पुरानी मांग जितनी ही असम्भव है।

पांचवाँ—कि पूंजी पर व्याज के खात्मे से मकानों के किराये की अदायगी कदापि ख़त्म नहीं होती।

मूलवर्ग अब दूसरे और चौथे मुद्दे से सहमत हो गये हैं। दूसरे मुद्दों का वह कोई उत्तर नहीं देते। परन्तु ठीक ये ही वे मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरा वाद-विवाद चल रहा है। वैसे मूलवर्ग का उत्तर प्रतिवाद नहीं है; यह उत्तर सारे आर्थिक मुद्दों से, जो अन्ततः निर्णायक हैं, बड़ी सावधानी से कतराता है। यह व्यक्तिगत शिकायत है, और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए उनकी शिकायत है कि मैं अन्य प्रश्नों, उदाहरणार्थ राजकीय ऋणों, निजी ऋणों तथा उधार से सम्बन्धित प्रश्नों के उनके घोषित समाधान की पहले से कल्पना कर लेता हूँ और कहता हूँ कि उनका समाधान आवास प्रश्न की ही तरह सर्वत्र एक जैसा होगा—व्याज का खात्मा, व्याज की अदायगी को किश्तों में परिणत कर पूंजी चुकाना तथा मुक्त उधार। इस सब के बावजूद मैं अब भी शर्त लगाकर कहता हूँ कि यदि मूलवर्ग के ये लेख कभी प्रकाश में आयें तो उनकी मूल अन्तर्वस्तु प्रदों के ‘आम विचार’ से (पृष्ठ १८२ पर उधार, पृष्ठ १८६ पर राजकीय ऋण, पृष्ठ १९६ पर निजी ऋण) उसी तरह मेल खायेगी जिस तरह आवास प्रश्न पर उनके लेख उसी पुस्तक से मेरे द्वारा उद्धृत किये गये अंशों से मेल खाते हैं।

म्यूलबर्गर इस मौके का लाभ उठाकर सूचित करते हैं कि कराधान, राजकीय ऋण, निजी ऋण तथा उधार का, जिनके साथ अब म्युनिसिपल स्वायत्तता का प्रश्न और जोड़ दिया गया है, किसान के लिए तथा देहात में प्रचार के लिए सबसे अधिक महत्व है। इससे कुछ हद तक मैं सहमत हूँ परन्तु १) अब तक किसान की कोई चर्चा नहीं हुई है और २) इन तमाम समस्याओं के प्रदोषी "समाधान" आवास प्रश्न के उनके समाधान की ही तरह आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल बेतुके तथा मूलतया पूँजीवादी हैं। मुझे म्यूलबर्गर के इस आरोप से अपना बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं किसानों को आन्दोलन में शामिल करने की आवश्यकता से इन्कार करता हूँ। लेकिन मैं इस उद्देश्य के लिए उनके वास्ते प्रदोषी नीम हक्रीमी की सिफारिश करना यकीनन मूर्खता मानता हूँ। जर्मनी में अब भी बड़ी-बड़ी जागीरें हैं। प्रदोषों के सिद्धान्त के अनुसार इन सब को छोटे-छोटे कृषक फार्मों में बांटा जाना चाहिए जो कृषि विज्ञान के वर्तमान स्तर को देखते हुए तथा फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी में ज़मीन के छोटे-छोटे खंडों में विभाजन के अनुभव के बाद निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी पग होगा। इसके विपरीत अभी विद्यमान बड़ी जागीरें हमें समूहबद्ध मेहनतकशों के ज़रिए बड़े पैमाने की खेती—कृषि की एकमात्र ऐसी प्रणाली जो सारे आधुनिक साधनों, मशीनों, आदि का उपयोग कर सकती है—करने के लिए तथा इस तरह छोटे किसानों को सहचारिता की मदद से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के लाभ प्रदर्शित करने के लिए एक तरह वांछनीय आधार प्रदान करेंगी। डेनिश समाजवादी, जो इस मामले में दूसरे सब लोगों से आगे हैं, इससे बहुत पहले अवगत हो गये थे।

मेरे लिए इस भर्त्सना से अपना बचाव करना भी सरासर अनावश्यक है कि मैं मज़दूरों की वर्तमान आवासीय अवस्थाओं को "महत्त्वहीन तफ़सील" मानता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने ही जर्मन साहित्य में सबसे पहले इन अवस्थाओं का उनके क्लासिकीय रूप में, जिसमें वे इंग्लैंड में विद्यमान हैं, वर्णन किया था; इसलिए नहीं कि वे "न्याय की मेरी भावना को ठेस पहुंचाते हैं", जैसा कि म्यूलबर्गर सोचते हैं—जो कोई अपनी न्याय की भावना को ठेस पहुंचानेवाले सारे तथ्यों के बारे में पुस्तकें लिखने का आग्रह करेगा, उसे बहुत दौड़धूप करनी होगी—बल्कि इसलिए कि—जैसा कि कोई भी मेरी पुस्तक की प्रस्तावना* में पढ़ सकता है—उस समय ऊपर उठ रहे और खोखले शब्दजाल पर अपनी शक्ति

* फ्रेडरिक एंगेल्स, 'इंग्लैंड में मज़दूर वर्ग की स्थिति'।—सं०

जाया कर रहे जर्मन समाजवाद के लिए बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग द्वारा पैदा की गयी सामाजिक अवस्थाओं का वर्णन करके तथ्यगत आधार प्रस्तुत कर सकूँ। परन्तु मेरे दिमाग में तथाकथित आवास प्रश्न को हल करने का यत्न करने की बात उसी तरह कभी नहीं आयी जिस तरह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की, खाद्य प्रश्न की तफ़्सीलों में अपने को व्यस्त रखने की बात नहीं आयी थी। यदि मैं यह सिद्ध कर सकूँ कि हमारे आधुनिक समाज में उत्पादन अपने तमाम सदस्यों को पूरा भोजन देने के लिए काफ़ी है और मेहनतकश जनसाधारण के लिए फ़िलहाल बड़े और स्वास्थ्यप्रद आवास मुहैया करने के लिये पर्याप्त मकान मौजूद हैं तो इससे मुझे सन्तोष हो जायेगा। भावी समाज भोजन तथा आवास के वितरण को किस तरह संगठित करेगा, इसकी अटकलवाजी लगाने का मतलब सीधे कल्पनालोक में पहुँचना होगा। हम आज तक की उत्पादन की तमाम पद्धतियों की बुनियादी अवस्थाओं के बारे में अपनी समझदारी के आधार पर हृद से हृद यह कह सकते हैं कि उत्पादन की पूँजीवादी पद्धति के पतन के साथ हस्तगतकरण के कतिपय रूप, जो समाज में अब तक विद्यमान रहे, असम्भव हो जायेंगे। संक्रमणात्मक पगों तक को सर्वत्र समय विशेष में विद्यमान सम्बन्धों के अनुरूप होना पड़ेगा। छोटी भूमि सम्पत्ति वाले देशों में वे उन देशों से सर्वत्र भिन्न होंगे जहाँ बड़ी भूमि सम्पत्ति विद्यमान है, आदि। म्यूलबर्गर स्वयं दूसरों की तुलना में इस बात के बेहतर प्रमाण हैं कि जब कोई आवास प्रश्न जैसे तथाकथित व्यावहारिक समस्याओं के लिए पृथक समाधान ढूँढने का यत्न करता है तो वह कहां पहुँच जाता है। उन्होंने पहले २५ पृष्ठ यह समझाने में रंग दिये कि “आवास प्रश्न के समाधान की सारी अन्तर्वस्तु विमोचन शब्द में निहित है”, फिर वह बुरी तरह फंस जाने पर संकोचपूर्वक हकलाते हुए कहते हैं कि यह सचमुच बहुत सन्देहास्पद है कि मकानों को वस्तुतः अपने अधिकार में कर लेने के बाद “मेहनतकश लोग विमोचन की ज्यादा पूजा करेंगे” या हस्तगतकरण के किसी अन्य रूप की।

म्यूलबर्गर मांग करते हैं कि हम व्यावहारिक बनें, कि “वास्तविक व्यावहारिक प्रश्नों से सामना” होने पर हमें “मात्र मृत तथा अमूर्त सूत्रों के साथ आगे” नहीं आना चाहिए, कि हमें “अमूर्त समाजवाद से निश्चित, ठोस सामाजिक सम्बन्धों के समीप पहुँचना चाहिए।” यदि म्यूलबर्गर ने यह किया होता तो शायद आन्दोलन की बड़ी सेवा कर देते। निश्चित, ठोस सामाजिक सम्बन्धों के समीप आने की दिशा में प्रथम पग यकीनन यह है कि उनका अध्ययन किया जाता

है, उनके विद्यमान आर्थिक अन्तस्सम्बन्धों के अनुसार उन्हें जांचा जाता है। परन्तु म्यूलबर्गर के लेखों में हमें क्या मिलता है? दो पूरे वाक्य, यानी—

१. “किरायेदार का मकान-मालिक के साथ सम्बन्ध उजरती मजदूर के पूंजीपति के साथ सम्बन्ध जैसा है।”

मैं पृथक प्रकाशन के पृष्ठ ६* पर यह सिद्ध कर चुका हूँ कि यह सरासर गलत है और म्यूलबर्गर के पास उत्तर देने के लिए एक भी शब्द नहीं है।

२. “जिस मामले” (सामाजिक सुधार में) “से सीधे-सीधे निपटा जाना है, वह राजनीतिक अर्थशास्त्र के उदारतावादी पंथ के शब्दों में पूंजी की उत्पादकता है जो वस्तुतः विद्यमान नहीं है परन्तु जो अपने प्रतीयमान अस्तित्व में उस सारी असमानता को छुपाने की आड़ का काम देती है जिसके बोझ से वर्तमान समाज दबा हुआ है।”

इस तरह जिस मामले से सीधे-सीधे निपटा जाना है, वह “वस्तुतः विद्यमान नहीं है” और इसलिए वह “मामला” नहीं है। बुराई उसमें नहीं, बरन् उसके प्रतीयमान अस्तित्व में है। इसके बावजूद “तथाकथित उत्पादकता (पूंजी की) जादू के थैले से मकान और शहर बाहर निकाल देती है”, जिनका अस्तित्व “प्रतीयमान” नहीं है (पृष्ठ १२)। और यह है वह व्यक्ति जो—यद्यपि वह मार्क्स की ‘पूंजी’ से भी “अच्छी तरह अवगत है”—पूंजी तथा श्रम के सम्बन्धों के बारे में इतने बेहद भ्रान्तिपूर्ण ढंग से बड़बड़ाता है और फिर भी जर्मन मजदूरों को नया और बेहतर रास्ता दिखाने का बीड़ा उठाता है और अपने को एक ऐसे “वास्तुशिल्पी” के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके दिमाग में “भावी समाज के वास्तुशिल्पीय ढांचे की, कम से कम उसकी मुख्य बाह्य रेखाओं की तस्वीर साफ़ है”!

और कोई भी व्यक्ति “निश्चित, ठोस सामाजिक सम्बन्धों के उतने समीप नहीं पहुंच पाया है” जितना मार्क्स अपनी ‘पूंजी’ में पहुंचे हैं। उन्होंने हर पहलू से उन्हें जांचने में २५ वर्ष बिताये तथा उनकी समीक्षा के परिणामों में तथाकथित समाधानों के, जहां तक वे आज सम्भव हैं, अंकुर भी मौजूद हैं। परन्तु मित्र म्यूलबर्गर के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये सब अमूर्त समाजवाद हैं, मृत तथा अमूर्त फार्मूला हैं। “निश्चित, ठोस सामाजिक सम्बन्धों का” अध्ययन करने के बजाय मित्र म्यूलबर्गर प्रूदों के चन्द ग्रंथों को पढ़कर सन्तोष कर लेते हैं जो यद्यपि

* देखें प्रस्तुत खण्ड।—सं०

उन्हें निश्चित, ठोस सामाजिक सम्बन्धों के बारे में कुछ भी नहीं बताते परन्तु जो इसके विपरीत उन्हें सारी सामाजिक बुराइयों के ठोस चमत्कारपूर्ण रामबाण जरूर देते हैं। फिर सामाजिक मुक्ति की इस तैयारशुदा योजना को, इस प्रूदोंपंथी प्रणाली को वह जर्मन मजदूरों के सामने इस बहाने प्रस्तुत करते हैं कि वह “सारी प्रणालियों से छुटकारा” पाना चाहते हैं जबकि मैं “उलटा रास्ता चुनता हूँ”! इसे समझ सकने के लिए मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं अंधा हूँ और म्यूलबर्गर बहरे हैं, इस तरह हमारे लिए एक दूसरे को समझना सर्वथा असम्भव है।

बस, काफ़ी हो गया। यह वाद-विवाद भले ही और कोई हितसाधन न करे, उसकी इतनी कीमत तो है ही कि उसने इस बात का प्रमाण दे दिया है कि इन स्वयम्भू “व्यावहारिक” समाजवादियों का व्यवहार वस्तुतः क्या है। तमाम सामाजिक बुराइयों के खात्मे के ये व्यावहारिक प्रस्ताव, ये सार्वत्रिक सामाजिक रामबाण सदैव और सर्वत्र उन पंथों के संस्थापकों के कार्य रहे हैं जो उस समय सामने आये जब सर्वहारा आन्दोलन अभी शैशवावस्था में था। प्रूदों भी उसी पंथ के हैं। सर्वहारा का विकास इन शिशु-परिधानों को एक ओर फेंक देता है और स्वयं मजदूर वर्ग में यह अनुभूति भरता है कि पहले से गढ़े हुए और सार्वत्रिक व्यवहार योग्य इन “व्यावहारिक समाधानों” से ज्यादा और कोई अव्यावहारिक नहीं है और व्यावहारिक समाजवाद उत्पादन की पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का उसके विभिन्न पहलुओं समेत सही ज्ञान प्राप्त करने में निहित है। मजदूर वर्ग को, जिसे इसका ज्ञान हो, इस बारे में किसी भी सूरत में कभी भी सन्देह नहीं रहेगा कि कौनसे सामाजिक संस्थान उसके प्रहारों के लक्ष्य होने चाहिए तथा ये प्रहार किस ढंग से किये जाने चाहिए।

फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा मई १८७२ और जनवरी १८७३ के बीच लिखित। अंग्रेजी से अनूदित।

«Der Volksstaat» समाचारपत्र के अंक ५१, ५२, ५३, १०३ तथा १०४ में २६ तथा २६ जून; ३ जुलाई, २५ और २८ दिसम्बर १८७२; अंक २, ३, १२, १३, १५ और १६ में ४ और ८ जनवरी; ८, १२, १६ तथा २२ फ़रवरी १८७३ को तथा लाइपज़िग में १८७२-१८७३ में तीन पृथक हिस्सों में प्रकाशित।

हस्ताक्षर — फ्रेडरिक एंगेल्स

सत्ता के सम्बन्ध में

०

इधर अनेक समाजवादियों ने उस चीज के खिलाफ बाकायदा एक जेहाद छेड़ दिया है जिसे वे सत्ता का सिद्धान्त के नाम से पुकारते हैं। उन द्वारा इस या उस कार्य की निन्दा करने के लिए उसे सत्तावादी बताना पर्याप्त है। कार्य-प्रणाली की इस संक्षिप्त विधि का इस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है कि उसकी ज़रा कुछ और बारीकी से जांच करना आवश्यक हो गया है। सत्ता शब्द का यहां जिस अर्थ में उपयोग किया गया है, उसका अर्थ है—दूसरे की इच्छा को हमारी इच्छा पर थोपा जाना; दूसरी ओर सत्ता मातहत की पूर्वकल्पना करती है। परन्तु ये दोनों शब्द चूँकि अच्छे नहीं लगते और जिस सम्बन्ध का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वह चूँकि मातहत पक्ष के लिए क्लेशकर होता है, इसलिए सवाल यह पता लगाने का है कि क्या उसे खत्म करने का कोई रास्ता है, क्या हम—वर्तमान समाज की परिस्थितियों के अन्तर्गत—ऐसी और कोई सामाजिक प्रणाली तैयार कर सकते हैं जिसके अन्तर्गत इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रखी जायेगी और फलस्वरूप जिसे लुप्त होना पड़ेगा। आर्थिक, औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी अवस्थाओं की, जिन्हें लेकर समकालीन पूँजीवादी समाज का आधार बना है, जांच करने पर हमें पता चलता है कि वे अलग-थलग व्यक्तियों के कार्यकलाप के स्थान पर लोगों के संयुक्त कार्यकलापों की ओर अधिकाधिक प्रवृत्त हैं। अपनी बड़ी-बड़ी फैक्टरियों और कारखानों समेत जहाँ सैकड़ों मजदूर भाप द्वारा चलनेवाली जटिल मशीनों का संचालन करते हैं, आधुनिक उद्योग ने पृथक्-पृथक् उत्पादकों के वर्कशापों का स्थान ले लिया है; राजपथों पर पुरानी घोड़ागाड़ियों की जगह रेलगाड़ियों ने ठीक उसी तरह ले ली है जिस तरह छोटे पालदार नौकाओं की जगह स्टीमरों ने ले ली है। कृषि तक मशीन और भाप के प्रभुत्व के

अन्तर्गत आ रही है ; ये धीरे-धीरे परन्तु निर्ममतापूर्वक छोटे भू-स्वामियों के स्थान पर बड़े पूंजीपतियों को ला रही हैं जो उजरती मजदूरों की मदद से विस्तृत भू-खंडों पर काय्य कर रहे हैं। संयुक्त कार्यकलाप, एक दूसरे पर आश्रित जटिल प्रक्रियाएं पृथक-पृथक व्यक्तियों के स्वतंत्र कार्यकलाप का स्थान ले रही हैं। परन्तु जो कोई संयुक्त कार्यकलाप की चर्चा करता है, वह संगठन की बात करता है ; तो क्या सत्ता के बिना संगठन सम्भव है ?

मान लें कि कोई सामाजिक क्रान्ति पूंजीपतियों का तख्ता उलट देती है जिनकी सत्ता इस समय सम्पदा के उत्पादन तथा संचालन पर है। मान लें कि सत्तावाद के विरोधियों का यह पूरा दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया जाता है कि भूमि तथा श्रम के औजार मजदूरों की सामूहिक सम्पत्ति बन गये हैं जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इससे सत्ता लुप्त हो जायेगी अथवा वह केवल अपना रूप बदलेगी ? आइये, देखें।

उदाहरण के लिए किसी कपास कटाई मिल को ले लें ! कपास को कम से कम ६ क्रमिक संक्रियाओं के बीच से गुजरना पड़ता है, तब कहीं वह सूत का रूप धारण करती है ; और ये सारी संक्रियाएं अधिकतर अलग-अलग कमरों में होती हैं। यही नहीं, मशीनों को चालू रखने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जो भाप इंजन की देखभाल करता है, रोजमर्रा की मरम्मत के लिए मिस्तरियों की जरूरत पड़ती है तथा कई अन्य मजदूरों की आवश्यकता होती है जिनका काम उत्पादों को एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाना, आदि होता है। ये सब मजदूर—पुरुष, स्त्रियां और बच्चे—काम के उन घंटों के दौरान काम शुरू करने तथा खत्म करने के लिए विवश होते हैं जिन्हें भाप की सत्ता नियत करती है और यह भाप की सत्ता व्यक्तिगत स्वायत्तता की कोई परवाह नहीं करती। इसलिए मजदूरों को सबसे पहले काम के घंटे नियत कर लेने चाहिए ; और एक बार ये घंटे नियत हो जायें तो बिना किसी अपवाद के सब द्वारा उनका पालन होना चाहिए। फिर हर कमरे में तथा हर घड़ी उत्पादन तथा सामग्रियों के वितरण, आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विशेष प्रश्न पैदा होते हैं जिन्हें फौरन हल करना होता है वरना सारा उत्पादन तत्काल रुक जायेगा ; ये प्रश्न श्रम की प्रत्येक शाखा के शीर्ष स्थान पर किसी डेलीगेट द्वारा अथवा—यदि सम्भव हुआ—बहुमत द्वारा तय किये जाते हैं, अलग-अलग व्यक्तियों की इच्छा सदैव मातहत रहनी होगी ; इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न सत्तावादी ढंग

से तय किये जाते हैं। किसी बड़ी फ़ैक्टरी की स्वचालित मशीन मजदूरों से काम लेनेवाले छोटे पूंजीपतियों से हमेशा कहीं अधिक स्वेच्छाचारी होती है। कम से कम काम के घंटों के मामले में इन फ़ैक्टरियों के द्वार पर ये शब्द लिखे जा सकते हैं—«Lasciate ogni autonomia, voi che entrate!»* यदि इन्सान ने अपने ज्ञान और आविष्कार करने की प्रतिभा की मदद से प्रकृति की शक्तियों को अपने मातहत कर लिया है तो प्रकृति की शक्तियाँ भी उसे—जहां तक वह उनका उपयोग करता है—वास्तविक स्वेच्छाचारिता के मातहत लाकर, जो सारे सामाजिक संगठन से बाहर होती है, उससे बदला लेती हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में सत्ता के उन्मूलन की कामना करना स्वयं उद्योग का उन्मूलन करने, चरखे की ओर लौटने के लिए यांत्रिक करघे को नष्ट करने के बराबर है।

एक और उदाहरण ले लें—रेलगाड़ियाँ। यहां भी असंख्य व्यक्तियों का सहयोग नितान्त आवश्यक है। यह सहयोग भी ठीक-ठीक निश्चित घंटों के अन्दर अमल में लाया जाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो। यहां भी काम की पहली शर्त प्रभुत्वशाली इच्छा है जो सारे मातहत प्रश्नों को तय करती है भले ही इस इच्छा का प्रतिनिधित्व एक डेलीगेट करे अथवा ऐसी कमेटी करे जिसे बहुसंख्या के प्रस्तावों के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया हो। दोनों ही मामलों में यह अत्यन्त सुस्पष्ट सत्ता है। और उस रवाना की जानेवाली पहली ही रेलगाड़ी का क्या होगा यदि माननीय यात्रियों पर रेलवे कर्मचारियों की सत्ता खत्म कर दी जाये?

परन्तु सत्ता—और वह भी पूर्ण शक्ति युक्त सत्ता—की आवश्यकता जितनी स्पष्ट खुले सागर पर चलनेवाले जहाज़ में होती है, उतनी और कहीं नहीं। वहां ख़तरे के समय सब का जीवन उन सब द्वारा एक व्यक्ति की इच्छा का तत्काल तथा निर्विवाद रूप में पालन किये जाने पर निर्भर करता है।

मैंने इस तरह के तर्क जब सबसे कट्टर सत्तावादविरोधियों के सामने रखे थे तो वे मुझे एकमात्र यही उत्तर दे सके—हां, यह सच है, लेकिन यहां मामला उस सत्ता का नहीं है जो हम अपने डेलीगेटों को सौंपते हैं, बल्कि सौंपे जानेवाले कुछ निश्चित कार्यभार का है। ये सज्जन सोचते हैं कि वे चीज़ों का नाम बदलकर स्वयं चीज़ों को बदल देते हैं। ये गहन चिन्तक पूरी दुनिया की इस तरह हसी उड़ाते हैं।

* “प्रवेश करनेवालो, सारी स्वायत्तता पीछे छोड़ जाओ!” दान्ते, ‘दिव्य कामेडी’, नरक, गीत ३ (पदान्वय)।—सं०

इस तरह हम देख चुके हैं कि एक ओर कुछ निश्चित सत्ता—वह चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो—तथा दूसरी ओर कुछ निश्चित मातृहृती, जो सारे सामाजिक संगठन से स्वतंत्र होती है, हमारे ऊपर उन भौतिक अवस्थाओं के साथ थोपी जाती हैं जिनके अन्तर्गत उत्पादन तथा उत्पादों का संचलन होता है।

दूसरी ओर हम देख चुके हैं कि बड़े पैमाने के उद्योग तथा बड़े पैमाने की कृषि के साथ उत्पादन तथा संचलन की भौतिक अवस्थाएं अवश्यम्भावी रूप से विकसित होती हैं तथा इस सत्ता के कार्यक्षेत्र के विस्तार की ओर उन्मुख होती हैं। इसलिए यह कहना उपहासास्पद है कि सत्ता का सिद्धान्त पूर्णतः बुरा है तथा स्वायत्तता का सिद्धान्त पूर्णतः अच्छा है। सत्ता तथा स्वायत्तता सापेक्ष वस्तुएं हैं जिनके कार्यक्षेत्र समाज के विकास के विविध दौरों के साथ बदलते जाते हैं। स्वायत्ततावादी यदि अपने को यह कहने तक सीमित रखते कि भविष्य का सामाजिक संगठन सत्ता को मात्र उन सीमाओं के अन्दर रखेगा जिनके अन्तर्गत उत्पादन की अवस्थाएं उन्हें अवश्यम्भावी बना देती हैं तो हम उनसे सहमत होते, परन्तु वे उन तमाम तथ्यों के मामले में अंधे हैं जो सत्ता को आवश्यक बनाते हैं, तथा वे शब्द के विरुद्ध आग्रहपूर्वक संघर्ष करते हैं।

सत्तावादविरोधी राजनीतिक सत्ता, राज्य के विरुद्ध चिल्लाने तक अपने को क्यों सीमित नहीं रखते? सारे समाजवादी इस बात पर सहमत हैं कि राजनीतिक राज्य का और उसके साथ राजनीतिक सत्ता का भावी सामाजिक क्रान्ति के फलस्वरूप लोप हो जायेगा, अर्थात् सार्वजनिक कार्य अपना राजनीतिक चरित्र खो बैठेंगे तथा समाज के हितों पर नज़र रखनेवाले सामान्य प्रशासनिक कार्यों में रूपान्तरित हो जायेंगे। परन्तु सत्तावादविरोधी यह मांग करते हैं कि सत्तावादी राजनीतिक राज्य का उसे जन्म देनेवाली सामाजिक अवस्थाओं को नष्ट किये जाने से पहले ही एक झटके में उन्मूलन कर दिया जाये। वे यह मांग करते हैं कि सामाजिक क्रान्ति का पहला काम यह होना चाहिए कि वह सत्ता का उन्मूलन करे। क्या इन सज्जनों ने कभी क्रान्ति देखी है? क्रान्ति निश्चित रूप से सर्वाधिक—जितनी कि कल्पना की जा सकती है—सत्तावादी वस्तु होती है। यह ऐसा कार्य है जिसमें आवादी का एक भाग राइफलों, संगीनों और तोपों के माध्यम से, चरम सत्तावादी साधनों के माध्यम से दूसरे भाग पर अपनी इच्छा थोपता है। और यदि विजयी पार्टी यह नहीं चाहती कि उसके प्रयत्न निष्फल रहें तो उसे ऐसे आतंक की मदद से अपना शासन कायम रखना होगा जिसे उसके श्रुतिधार प्रतिक्रियावादियों के मन में उत्पन्न करते हैं। यदि पेरिस कम्यून ने

पूँजीपति वर्ग के विरुद्ध सशस्त्र जनता की सत्ता इस्तेमाल न की होती तो क्या वह एक दिन भी टिक पाती? इसके विपरीत क्या हमें कम्यून की इसलिए भर्त्सना नहीं करनी चाहिए कि उसने इस सत्ता का पर्याप्त उपयोग नहीं किया?

इसलिए दो चीजों में से एक ही हो सकती है—या तो सत्तावादविरोधियों को यह पता नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं और यदि ऐसा है तो वे सिवाय भ्रम के और कुछ पैदा नहीं कर रहे हैं; अथवा उन्हें इसका पता है और यदि ऐसा है तो वे सर्वहारा आन्दोलन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। दोनों सूरत में वे केवल प्रतिक्रियावाद का हितसाधन कर रहे हैं।

फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा अक्टूबर १८७२—मार्च १८७३ अंग्रेजी से अनूदित।
में लिखित। दिसम्बर १८७३ में «*Almanacco
Repubblicano per l'anno 1874*» में प्रकाशित।

हस्ताक्षर—फ्रेडरिक एंगेल्स

कम्यून के ब्लांकीपंथी उत्प्रवासियों का कार्यक्रम

('उत्प्रवासी साहित्य' लेखमाला का दूसरा लेख)⁷⁶

प्रत्येक असफल क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति के उपरान्त बचकर विदेश चले जानेवाले उत्प्रवासियों की गतिविधियां बहुत जोर पकड़ लेती हैं। नाना रंगभेदों के पार्टी ग्रूप गठित हो जाते हैं जो एक दूसरे पर गाड़ी को दलदल में फँसाने, शहारी करने तथा दूसरे सारे महापाप करने का आरोप लगाते हैं। वे अपनी मातृभूमि के साथ सक्रिय सम्बन्ध बनाये रखते हैं, संगठित होते हैं, षड्यन्त्र रचते हैं, पर्चे और अखबार छापते हैं तथा शपथ लेते हैं कि अगले २४ घंटों में फिर से "शुरूआत" होगी, कि विजय सुनिश्चित है, और इस प्रत्याशा में सरकारी ओहदे बांटते हैं। स्वभावतया एक के बाद दूसरी निराशा हाथ लगती है जिसके लिए अनिवार्य ऐतिहासिक परिस्थितियों को नहीं, जिन्हें वे समझना नहीं चाहते, अपितु अलग-अलग व्यक्तियों की सांयोगिक गलतियों को दोषी ठहराया जाता है; पारस्परिक आक्षेप संचित होते जाते हैं और उनका परिणाम होता है आम कलह। ऐसा है १७९२ के शाही उत्प्रवासियों से लेकर आज तक के उत्प्रवासियों की सारी सोसायटियों का इतिहास; और जिन उत्प्रवासियों में समझ-बूझ तथा विवेक है, वे इस निरर्थक टटेबाज़ी से मौक़ा मिलते ही उपयुक्त ढंग से अलग हो जाते हैं तथा उस ओर मुड़ते हैं जो अधिक उपयोगी होता है।

कम्यून के उपरान्त फ़्रांसीसी उत्प्रवासी भी इस अवश्यम्भावी नियति से नहीं बच सके। सर्वयूरोपीय कुत्सापूर्ण मुहिम के कारण, जिसने सब पर समान रूप से तथा विशेष रूप से लन्दन स्थित फ़्रांसीसी उत्प्रवासियों पर—जिनका लन्दन में इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के रूप में अपना समान केन्द्र था—प्रहार किया,

वे कुछ समय तक अपनी आन्तरिक टूटबाज़ी को कम से कम बाहरी दुनिया से छुपाने के लिए विवश रहे। परन्तु पिछले दो वर्षों में उनके लिए अपने बीच विघटन की प्रक्रिया को छुपाना सम्भव नहीं रहा जो उनकी क्रतारों के बीच तेज़ी से विस्तृत होती जा रही थी। सर्वत्र खुला कलह भड़क उठा। स्विट्ज़रलैंड में उत्प्रवासियों का एक हिस्सा खास तौर से मालोन के, जो गुप्त सहबंध के संस्थापकों में से था, प्रभाव में बकूनिनपंथियों से मिल गया। फिर लन्दन में तथाकथित ब्लांकीपंथी इंटरनेशनल से अलग हो गये और उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रूप बना लिया जिसने अपना नाम “क्रान्तिकारी कम्यून” रख लिया। आगे चलकर दूसरे बहुत-से ग्रूप प्रकट हुए जो निरन्तर एक दूसरे में मिलते गये तथा पुनर्गठित होते रहे परन्तु जो घोषणापत्रों तक के मामले में कोई काम की चीज़ तैयार नहीं कर सके। परन्तु ब्लांकीपंथियों ने «Communeux» के नाम एक अपील जारी की है जिसमें उन्होंने दुनिया का ध्यान अपने कार्यक्रम की ओर आकृष्ट किया है।

वे ब्लांकीपंथी इसलिए नहीं कहलाते कि वे ब्लांकी द्वारा गठित ग्रूप के लोग हैं; ३३ हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से केवल चन्द ने ही कभी ब्लांकी से बातचीत की होगी। वे ब्लांकीपंथी इसलिए कहलाते हैं कि वे उनकी भावना के तथा उनकी परम्परा के अनुसार काम करना चाहते हैं। ब्लांकी मूलतया राजनीतिक क्रान्तिकारी हैं; वे समाजवादी तो केवल भावना के कारण हैं क्योंकि जनता के दुख-दर्द के प्रति उनकी सहानुभूति है। परन्तु उनके पास न तो कोई समाजवादी सिद्धान्त है और न सामाजिक सुधारों के लिए कोई व्यावहारिक प्रस्ताव। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के मामले में वह मूलतया “कर्मशील व्यक्ति” थे जो यह विश्वास करते थे कि यदि एक छोटी-सी, सुसंगठित अल्पसंख्या ठीक मौक़े पर क्रान्तिकारी विप्लव को मूर्त रूप देने का यत्न करे तो चन्द आरम्भिक सफलताएं हासिल करके जनसमुदाय को अपने साथ कर सकती है और इस तरह विजयी क्रान्ति सम्पन्न कर सकती है। लूई फ़िलिप के समय वह स्वभावतया यह नाभिक एक गुप्त सोसायटी के रूप में संगठित करने में सफल रहे और इस संगठन का वही हाल हुआ जो आम तौर पर षड्यंत्रों का होता है—क्रान्ति की शीघ्र शुरूआत के निरन्तर कोरे वचनों के दिये जाने से लोग तंग आकर अन्ततः सारा धैर्य खो बैठे और विद्रोही हो गये और तब दो ही विकल्प रह गये—या तो षड्यंत्र को धराशायी होने दिया जाये या बिना किसी बाह्य कारण के विद्रोह शुरू कर दिया जाये। विद्रोह शुरू हुआ (१२ मई १८३६), परन्तु उसे तत्काल कुचल दिया

गया। प्रसंगतः ब्लांकी का षड्यंत्र एकमात्र ऐसा षड्यंत्र था जिसका पुलिस सुराग लगाने में ज़रा भी सफल नहीं हो सकी थी। इसलिए विद्रोह पुलिस के लिए बिना मेघ के वज्रपात जैसा था।—चूँकि ब्लांकी हर क्रान्ति को एक छोटी-सी क्रान्तिकारी अल्पसंख्या द्वारा राज्य पर्युत्क्षेपण मानते थे, इसलिए इसका स्वभावतया यह अर्थ निकलता है कि इसकी सफलता के बाद अनिवार्यतः अधिनायकत्व की स्थापना होगी—परन्तु ध्यान रहे, पूरे क्रान्तिकारी वर्ग का, सर्वहारा का अधिनायकत्व नहीं, वरन् उन चन्द लोगों का अधिनायकत्व जिन्होंने विद्रोह सम्पन्न किया तथा जो स्वयं आरम्भ से ही एक या कई व्यक्तियों के अधिनायकत्व के अन्तर्गत संगठित होते हैं।

जाहिर है, ब्लांकी पुरानी पीढ़ी के क्रान्तिकारी हैं। क्रान्तिकारी घटना-प्रवाह के विषय में ये विचार, कम से कम जहाँ तक जर्मन मजदूर पार्टी का सम्बन्ध है, बहुत पहले पुराने पड़ चुके हैं और फ्रांस में भी उन्हें केवल कम समझदार अथवा अधिक अधीर मजदूरों की स्वीकृति मिल सकती है। हम यह भी देखेंगे कि चर्चित कार्यक्रम में ये विचार निश्चित सीमाओं में बांधे गये हैं। परन्तु हमारे लन्दन के ब्लांकीपंथी भी इस सिद्धान्त से पथ-प्रदर्शन पाते हैं कि क्रान्तियाँ स्वयं नहीं होती हैं,—वे की जाती हैं; कि उन्हें एक अपेक्षाकृत छोटी-सी अल्पसंख्या पहले से तैयार की गयी योजना के अनुसार सम्पन्न करती है; और अन्ततः यह कि किसी भी समय “शीघ्र शुरूआत” हो सकती है।

ऐसे सिद्धान्तों के कारण लोग स्वभावतया उत्प्रवासियों की सारी आत्म-प्रवचनाओं के ऐसे शिकार बन जाते हैं, जिनका उद्धार नहीं हो सकता और उन्हें मजबूरन एक के बाद दूसरी गलती के जाल में फँसना पड़ता है। सर्वोपरि वे “कर्मशील ब्लांकी” की भूमिका अदा करना चाहते हैं। परन्तु मात्र नेक इरादा यहाँ काफ़ी नहीं होता; ब्लांकी की क्रान्तिकारी सहजवृत्ति, शीघ्र निर्णय करने की उनकी योग्यता सब में नहीं होती; और हेमलेट कर्म की चाहे कितनी ही बात करे, वह हेमलेट ही रहेगा। यही नहीं, हमारे तैंतीस कर्मशील व्यक्ति जब देखते हैं कि इस क्षेत्र में करने के लिए वह कुछ भी नहीं है जिसे वे कर्म की बात कहते हैं तो हमारे ये तैंतीस ब्रूटस अन्तर्विरोध में, जो त्रासदीय से अधिक प्रहसनात्मक है, उस अन्तर्विरोध में फँस जाते हैं जिसमें उनकी उस उदास मुद्रा से त्रासदी नहीं बढ़ती है जिसे वे ऐसे धारण करते हैं मानो वे “बग़ल में छुरी दबाये मोरोस” हों, जो, प्रसंगतः, उनके दिमाग में पैदा तक नहीं होती। वे क्या कर रहे हैं? वे भविष्य के लिए नुस्खों की सूचियाँ तैयार करके कम्यून में भाग लेनेवाले लोगों

की कृतारों को शुद्ध (épuré) करने के लिए अगले “विस्फोट” की तैयारी कर रहे हैं; यही कारण है कि दूसरे उत्प्रवासी उन्हें शुद्ध (les purs) कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह उपाधि वे स्वयं ग्रहण करते हैं या नहीं, फिर भी यह उनमें से कुछ के लिए भी उपयुक्त नहीं बैठती। उनकी गुप्त बैठकें होती हैं, उनके निर्णय भी गुप्त रखे जाते हैं फिर भी वे अगली सुबह ही सारे फ्रांसीसी मुहल्ले में प्रतिध्वनित हो उठते हैं। और जैसा कि ऐसे गम्भीर कर्मशील व्यक्तियों के साथ हमेशा होता है, जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं रह गया तो उन्होंने अपने एक उपयुक्त विरोधी, पेरिस के तुच्छ अखबार के एक सबसे कुख्यात सदस्य, वेर्मेर्श नामक किसी व्यक्ति के साथ जो कम्यून के समय «Père Duchêne»⁷⁷ अखबार जो १७९३ में एबेर के अखबार की घटिया नकल था, निकालता था, पहले व्यक्तिगत और फिर साहित्यिक वाद-विवाद छेड़ दिया। इन लोगों के नैतिक रोष के उत्तर में इस महानुभाव ने अपने एक पर्व में उन्हें “ठग या ठगों का संगी” बताया तथा इन अपशब्दभरे आक्षेपों की झड़ी लगा दी—

“हर शब्द कूड़ादानी, और वह भी खाली नहीं”।*

और हमारे ये तैंतीस बूटस ऐसे विरोधी से झगड़ा मोल लेना उपयुक्त पाते हैं!

यदि कोई चीज निश्चित है तो वह यह है कि थका देनेवाले युद्ध के बाद, पेरिस में भुखमरी के बाद, खास तौर पर १८७१ में मई के दिनों के भयावह रक्तपातपूर्ण दिनों के बाद पेरिस के सर्वहारा को फिर से सशक्त होने के लिए काफ़ी लम्बे आराम की जरूरत है, कि विद्रोह की हर समयपूर्व चेष्टा का परिणाम केवल एक नयी और शायद पहले से भयंकर पराजय ही होगा। हमारे ब्लंकीपंथिया का भिन्न विचार है।

वेर्साई में राजतंत्रीय बहुमत का विघटन उनकी नज़र में जिस चीज का सूत्रपात करता है, वह है

“वेर्साई का पतन, कम्यून के लिए प्रतिशोध और यह कि हम एक महान ऐतिहासिक घड़ी की ओर, एक ऐसे बड़े संकट की ओर अग्रसर हो रहे हैं जय जनता, जो, लगता है, दम तोड़ रही है और जिसकी किस्मत में मौत बढ़ी हुई है, नयी शक्ति के साथ अपनी क्रान्तिकारी अग्रगति पुनः आरम्भ करेगी।”

* हाइने, ‘वाद-विवाद’।—सं०

दूसरे शब्दों में, पुनः शुरूआत, और यही नहीं शीघ्र ही शुरूआत होती है। “कम्यून के लिए प्रतिशोध”-सम्बन्धी आशा उत्प्रवासी भ्रम मात्र नहीं है, वह उन लोगों की आस्था का आवश्यक प्रतीक है जिन्होंने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली है कि वे उस समय ही “कर्मशील लोग” होंगे जब क्रान्ति भड़काने की दृष्टि से करने को कुछ नहीं रह जाता।

यह पुराना राग है। चूँकि शुरूआत होनेवाली है, इसलिए वे अनुभव करते हैं कि “वक्त आ गया है जब उत्प्रवासियों को, जिनमें ज़िंदगी की एक भी चिनगारी अब भी बाक़ी है, अपनी स्थिति निर्धारित करनी चाहिए।” और इस तरह ये तैतीस हमें बताते हैं कि वे १) निरीश्वरवादी, २) कम्युनिस्ट तथा ३) क्रान्तिकारी हैं।

हमारे ब्लांकीपंथियों और बकूनिनपंथियों में एक समान बुनियादी गुण यह है कि वे सबसे दूरगामी, सबसे उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। प्रसंगतः यही कारण है कि ब्लांकीपंथी जहाँ लक्ष्य के मामले में बकूनिनपंथियों का विरोध करते हैं, वहाँ वे साधनों के बारे में प्रायः उनसे सहमत होते हैं। इसलिए सवाल निरीश्वरवाद के सम्बन्ध में दूसरे सब की तुलना में अधिक आमूल परिवर्तनवादी होने का है। हमारे ज़माने में निरीश्वरवादी होना खुशकिस्मती से कठिन नहीं है। यूरोपीय मजदूर पार्टियों में निरीश्वरवाद कमोबेश स्वतःसिद्ध है भले ही कुछ यूरोपीय देशों में उसका स्वरूप उस स्पेनी बकूनिनपंथी के निरीश्वरवाद से मिलता हो जिसने घोषित किया था—भगवान पर विश्वास करना पूरे समाजवाद के विरुद्ध है परन्तु मरियम में विश्वास करना दूसरी बात है और हर शरीफ़ समाजवादी को उसमें विश्वास करना चाहिए। जहाँ तक जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूरों का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि उनके लिए निरीश्वरवाद की उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है; यह विशुद्ध निषेध उन पर लागू नहीं होता क्योंकि वे भगवान पर विश्वास का अब सैद्धान्तिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक विरोध करते हैं; उन्होंने बस भगवान को ताक पर रख दिया है; वे यथार्थ संसार में रहते तथा सोचते हैं और इसलिए भौतिकवादी हैं। शायद यही बात फ्रांस पर लागू होती है। यदि नहीं होती तो इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता कि मजदूरों के बीच पिछली शताब्दी का शानदार फ्रांसीसी भौतिकवादी साहित्य व्यापक पैमाने पर बांटा जाये जिसमें फ्रांसीसी आत्मा ने रूप तथा अन्तर्वस्तु दोनों दृष्टि से उदात्त अभिव्यक्ति पायी है और जो उस समय के विज्ञान के स्तर को ध्यान में रखते हुए आज भी अन्तर्वस्तु की दृष्टि से अतीव उदात्त तथा रूप की दृष्टि से अद्वितीय है। परन्तु यह चीज़ हमारे ब्लांकीपंथियों को उपयुक्त सिद्ध

नहीं होती। वे सबसे ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी हैं, यह सिद्ध करने के लिए १७६३ की तरह भगवान का फ़तवा देकर अस्तित्व ख़त्म कर दिया जाता है—

“कम्यून अतीत की इस विपदा के हाँवे को” (भगवान को), “उसकी वर्तमान विपदा के इस कारण को” (अस्तित्वहीन भगवान—कारण!) “सदा के लिए मुक्त कर देगी।—कम्यून में पुरोहितों के लिए कोई स्थान नहीं है, हर धार्मिक प्रवचन, हर धार्मिक संगठन पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिए।”

और लोगों को *par ordre du mufti** निरीश्वरवादी में परिणत करने की इस माँग पर कम्यून के दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं जिन्हें निश्चय ही यह पता लगाने के लिए काफ़ी मौक़ा मिला होगा कि पहले, कोई भी आज़्ञाप्ति कागज़ पर जारी की जा सकती है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि उसका कार्यान्वयन होकर रहेगा; दूसरे, यह कि सताना अवांछनीय आस्थाओं को दृढ़ बनाने का सर्वोत्तम साधन है! इतना तो निश्चित है—ईश्वर की आज भी जो एकमात्र सेवा की जा सकती है, वह यह है कि निरीश्वरवाद को आस्था का अनिवार्य प्रतीक बना दिया जाये और सामान्यतया धर्म पर पाबन्दी लगाकर बिस्मार्क के चर्चविरोधी *Kulturkampf*⁷⁸ को भी मात दे दी जाये।

कार्यक्रम का दूसरा मुद्दा कम्युनिज़्म है।

यहां हम अपने को अधिक परिचित आधारभूमि पर पाते हैं क्योंकि हम यहां जिस जलयान में सफ़र कर रहे हैं, उसका नाम ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ है जो फ़रवरी १८४८ में प्रकाशित हुआ था। १८७२ के शरद काल में ही इंटरनेशनल छोड़नेवाले पांच ब्लॉकीपंथी एक समाजवादी कार्यक्रम अंगीकार कर चुके थे जो अपनी समस्त मूल विशेषताओं के मामले में वर्तमान जर्मन कम्युनिज़्म से मिलता था और उन्होंने इंटरनेशनल से नाता तोड़ने का एकमात्र आधार यह बनाया कि उसने इन पांच के ढंग से क्रान्ति के साथ खिलवाड़ करने से इन्कार कर दिया था। अब तैंतीस की कौंसिल ने भी इस कार्यक्रम को इतिहास पर उसके सारे भौतिकवादी दृष्टिकोण समेत अंगीकार कर लिया है हालांकि इसके ब्लॉकीपंथी फ़्रांसीसी भाषा में अनुवाद की उन जगहों में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, जहां ‘घोषणापत्र’ के पाठ का लगभग शाब्दिक रूप प्रस्तुत नहीं किया गया है, उदाहरण के लिए यह वाक्य लें—

*मुफ़्ती के फ़तवे पर, ऊपर से आदेश पर।—सं०

“पूँजीपति वर्ग ने श्रम के शोषण से वे रहस्यमय पर्दे हटा दिये हैं जिनमें दासता के सारे रूपों की यह अन्तिम अभिव्यक्ति छुपी हुई थी—सरकारें, धर्म, परिवार, कानून, वर्तमान तथा अतीत दोनों के संस्थान इस समाज में, जो पूँजीपति तथा उजरती मजदूरों के विरोध पर आश्रित हैं, अन्ततः उत्पीड़न के साधनों के रूप में प्रकट होते हैं जिनकी सहायता से पूँजीपति वर्ग अपने शासन की रक्षा करता है तथा सर्वहारा को कुचलता है।”

आइये, ज़रा इसकी तुलना ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ के अनुभाग १ से करें, “एक शब्द में धार्मिक तथा राजनीतिक धोखे की टट्टी के पीछे छिपे शोषण के स्थान पर उसने नग्न, निर्लज्ज, प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण की स्थापना की है। जिन पेशों के सम्बन्ध में अब तक लोगों के मन में आदर तथा श्रद्धा की भावना थी, उनका प्रभामंडल पूँजीपति वर्ग ने छीन लिया। वकील, डाक्टर, पुरोहित, कवि और वैज्ञानिक, सभी को उसने अपना वेतनभोगी उजरती मजदूर बना दिया है। पूँजीपति वर्ग ने पारिवारिक सम्बन्धों के ऊपर से भावुकता का पर्दा उतार फेंका है और पारिवारिक सम्बन्ध को केवल द्रव्य के सम्बन्ध में बदल दिया है,” आदि।*

परन्तु ज्यों ही हम सिद्धान्त की ऊंचाई से व्यवहार के क्षेत्र में नीचे उतरते हैं, इन तैतीस सज्जनों की विशिष्टता सामने आ जाती है—

“हम इसलिए कम्युनिस्ट हैं कि हम बीच के पड़ावों में ठहरे बिना, समझौतेबाज़ी में पड़े बिना, जो केवल विजय को स्थगित ही करती है तथा दासता की अवधि बढ़ाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं।”

जर्मन कम्युनिस्ट इसलिए कम्युनिस्ट हैं कि वे तमाम बीच के पड़ावों और समझौतों के बीच, जिन्हें उन्होंने नहीं, वरन् ऐतिहासिक विकास ने रचा, अपने अन्तिम लक्ष्य को—वर्गों का उन्मूलन तथा ऐसे समाज की स्थापना जिसमें भूमि तथा उत्पादन साधनों पर कोई निजी स्वामित्व नहीं होगा—स्पष्ट रूप से देखते तथा उसका सदैव अनुसरण करते आये हैं। तैतीस ब्लांकीपंथी कम्युनिस्ट इसलिए हैं कि वे कल्पना करते हैं कि वे जैसे ही बीच के पड़ावों तथा समझौतेबाज़ी

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड १, भाग १।—सं०

को लांघने का इरादा कर लेंगे, मैदान फ़तह हो जायेगा और यदि—जैसा कि उनका दृढ़ विश्वास है—दो एक दिनों में “शुरूआत” होनेवाली है और वे कर्णधर हों तो परसों “कम्युनिज़म लागू हो जायेगा” और यदि वे ऐसा तुरन्त नहीं कर सकते तो वे कम्युनिस्ट हैं ही नहीं।

अधीरता को आश्वस्तकारी सैद्धान्तिक तर्क के रूप में प्रस्तुत करना कैसा बचकाना भोलापन है!

अन्ततः हमारे तैत्तीस “क्रान्तिकारी” हैं।

आडम्बरपूर्ण शब्दों के उपयोग के मामले में, जितना मानव के बूते की बात है, बकूनिनपंथी सब कुछ कर चुके हैं। परन्तु हमारे ब्लांकीपंथी उन्हें भी मात देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। परन्तु कैसे? यह सुविदित है कि लिस्बन तथा न्यूयार्क से लेकर बुडापेस्ट तथा बेलग्रेड तक समस्त समाजवादी सर्वहारा ने पेरिस कम्यून की कार्यवाइयों का en bloc* उत्तरदायित्व ग्रहण किया। परन्तु यह हमारे ब्लांकीपंथियों के लिए काफ़ी नहीं है—

“जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम जनता के दुश्मनों को प्राणदंड देने के” (कम्यून के समय) “उत्तरदायित्व में अपने भाग का दावा करते हैं” (मारे गये लोगों की सूची संलग्न है), “हम उस आगजनी के उत्तरदायित्व में अपने भाग का दावा करते हैं जिसने राजतन्त्रवादी या पूंजीवादी दमन के हथियारों को नष्ट किया था अथवा लड़ाई में जुटे लोगों की रक्षा की थी।”

हर क्रान्ति के समय और निस्सन्देह दूसरे तमाम अवसरों की तरह बहुत-सारी गलतियाँ अपरिहार्य होती हैं; और जब जनता इतनी स्थिरचित्त हो जाती है कि घटनाओं की आलोचनात्मक ढंग से समीक्षा कर सके तो वह ये निष्कर्ष निकालती है—हमने ऐसे बहुत-से काम किये हैं जिन्हें यदि न किया जाता तो बेहतर होता और हम ऐसे बहुत-से काम करने में चूक गये हैं जिन्हें यदि किया गया होता तो बेहतर होता, और बात विगड़ने का यही कारण है।

परन्तु आलोचनात्मक रुख के कितने अभाव की आवश्यकता होती है यह घोषित करने के लिए कि कम्यून से कोई गलती हुई ही नहीं, निश्चयपूर्वक यह कहने के लिए कि हर बार किसी मकान को लगायी गयी आग अथवा हर बार किसी बंधक बनाये हुए व्यक्ति को गोली से उड़ाने का मामला अक्षरशः वैसा

* समग्र रूप में।—सं०

था जैसा होना चाहिए था ! क्या यह दावा यह कहने जैसा नहीं है कि मई माह के उस सप्ताह में लोगों ने उतने ही व्यक्तियों को—एक भी अधिक नहीं—गोली से उड़ाया जितनों को गोली से उड़ाना जरूरी था, उन्होंने ठीक उन मकानों को ही—एक भी ज्यादा नहीं—जलाया जितनों को जलाना जरूरी था ? क्या यह दावा प्रथम फ्रांसीसी क्रान्ति के विषय में यह कहने जैसा नहीं है—जितने भी लोगों के सिर काटे गये, उन्हें अपना दंड मिला था, पहले उन्हें जिनका सिर रोबेसपिये ने कटवाया था और फिर स्वयं रोबेसपिये को ? ऐसी बचकाना बातें तब सामने आती हैं जब मूलतः अच्छे स्वभाव वाले लोग घोर नृशंस होने की इच्छा के वशीभूत हो जाते हैं।

चलिये, काफ़ी हो गया। उत्प्रवासियों की तमाम मूर्खतापूर्ण कार्रवाइयों और नन्हे कार्ल (या एदुअर्ड ?) * को भयावह दिखाने की हास्यकर चेष्टाओं के बावजूद हमें कार्यक्रम में कुछ निश्चित प्रगति अभिलक्षित होती है। यह पहला घोषणापत्र है जिसमें फ्रांसीसी मजदूर समकालीन जर्मन कम्युनिज्म के ध्येय के साथ एकजुट होते हैं। इतना ही नहीं, ये मजदूर ऐसी प्रवृत्ति के हैं जो फ्रांसीसियों को गोया क्रान्ति के लिए ही जन्मे लोग तथा पेरिस को क्रान्तिकारी यरूशलम मानते हैं। उन्हें वहां तक ले आने का निर्विवाद श्रेय बाइयां को है जो हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक हैं तथा जिन्हें—जैसा कि सर्वविदित है—जर्मन भाषा तथा जर्मन समाजवादी साहित्य का अच्छा ज्ञान है। जर्मन समाजवादी मजदूर, जिन्होंने १८७० में यह सिद्ध कर दिया था कि उनके लिए किसी भी तरह का अंधराष्ट्रवाद विजातीय है, इसे एक शुभ लक्षण मान सकते हैं कि फ्रांसीसी मजदूर सही सिद्धान्तिक स्थिति अपना रहे हैं भले ही ये सिद्धान्त जर्मनी से आते हों।

एंगेल्स द्वारा जून १८७४ में लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

«Der Volksstaat» समाचारपत्र के अंक ७३ में २६ जून १८७४ को तथा फ्रे० एंगेल्स की पुस्तक «Internationales aus dem «Volksstaat» (1871—1875)» बर्लिन में, १८९४ को प्रकाशित।

हस्ताक्षर—फ्रे० एंगेल्स

* इशारा एदुअर्ड बाइयां की ओर है।—सं०

रूस में सामाजिक सम्बन्धों के विषय में ⁷⁹

('उत्प्रवासी साहित्य' लेखमाला का पांचवां लेख)

श्री त्काचोव विषय विशेष के सम्बन्ध में जर्मन मजदूरों से कहते हैं कि रूस के सम्बन्ध में मुझे "मामूली ज्ञान" तक नहीं है, कि मेरे पास सिवाय "अज्ञान" के और कुछ नहीं है; और इसलिए वह वास्तविक स्थिति समझाने, इस बात का कारण बताने के लिए कर्तव्यवद्ध हैं कि ठीक इसी मौके पर रूस में सामाजिक क्रान्ति बिल्कुल आसानी से, पश्चिमी यूरोप की तुलना में कहीं ज्यादा आसानी से क्यों सम्पन्न की जा सकती है।

"हमारे पास शहरी सर्वहारा नहीं है, यह निस्सन्देह सच है। पर हमारे पास पूंजीपति वर्ग भी तो नहीं है... हमारे मजदूरों को केवल राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा—पूंजी की शक्ति तो हमारे यहां अभी भ्रूणावस्था में ही है। और, महानुभाव, आप इस बात से निस्सन्देह अवगत हैं कि पहले से टक्कर लेना दूसरे से कहीं ज्यादा आसान है।" ⁸⁰

आधुनिक समाजवाद जो क्रान्ति चाहता है, वह संक्षेप में पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की विजय तथा समस्त वर्ग-विभेदों को मिटाकर समाज के एक नये संगठन की स्थापना है। यह इस क्रान्ति को सम्पन्न करनेवाले सर्वहारा का ही नहीं, वरन् पूंजीपति वर्ग का भी तत्काज्जा करता है जिसके हाथों में समाज की उत्पादक शक्तियां इस हद तक विकसित कर चुकी हैं कि वर्ग-विरोधों का अन्तिम रूप से उन्मूलन करना सम्भव हो जाता है। बर्बरों तथा अर्द्धबर्बरों तक के बीच भी इसी तरह कोई वर्ग-विभेद नहीं होते तथा हर जनता इस प्रकार की अवस्था के

बीच से गुज़री है। इस अवस्था की पुनर्स्थापना की बात हमारे दिमाग में इस सीधी-सादी वजह से नहीं आ सकती कि समाज की उत्पादक शक्तियाँ ज्यों-ज्यों विकसित होती हैं, इस अवस्था से लाज़िमी तौर पर वर्ग-विरोध पैदा होते हैं। समाज की उत्पादक शक्तियों के एक खास स्तर पर ही, हमारी आधुनिक अवस्थाओं की दृष्टि से भी अधिक ऊँचे स्तर पर ही उत्पादन को इस हद तक बढ़ाना सम्भव होता है कि वर्ग-विभेदों के उन्मूलन में वास्तविक प्रगति हो सकती है, कि सामाजिक उत्पादन पद्धति में गतिरोध, यहां तक कि ह्रास लाये बिना स्थायी हो सकती है। परन्तु उत्पादक शक्तियाँ केवल पूँजीपति वर्ग के ज़रिए ही विकास के इस स्तर पर पहुँच सकी हैं। इसीलिए पूँजीपति वर्ग समाजवादी क्रान्ति की उतनी ही आवश्यक पूर्वशर्त है जितनी आवश्यक पूर्वशर्त स्वयं सर्वहारा वर्ग है। इसलिए जो व्यक्ति यह कहता है कि यह क्रान्ति ऐसे देश में आसानी से सम्पन्न की जा सकती है जहाँ भले ही सर्वहारा वर्ग न हो, वहाँ पूँजीपति वर्ग भी नहीं है, वह यही साबित करता है कि उसे अभी समाजवाद की वर्णमाला सीखनी होगी।

इसलिए रूसी मज़दूरों का—और ये मज़दूर, श्री त्काचोव के शब्दों में, “ज़मीन की काश्त करनेवाले हैं और इसलिए सर्वहारा नहीं, वरन् मालिक हैं”,—काम आसान है क्योंकि उन्हें पूँजी की शक्ति के विरुद्ध नहीं, वरन् “केवल राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध”, रूसी राज्य के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। और यह राज्य

“केवल बहुत दूर से एक शक्ति प्रतीत होता है... उसकी जनता के आर्थिक जीवन में जड़ें ही नहीं हैं; वह किसी खास सामाजिक श्रेणी के हितों का मूर्त रूप नहीं है... आपके देश में राज्य कोई काल्पनिक शक्ति नहीं है। वह मज़बूती से पूँजी पर टिका हुआ है; वह अपने अन्दर” (!!) “कतिपय आर्थिक हितों को मूर्त रूप देता है... हमारे देश में स्थिति बिल्कुल उलट है—हमारे समाज के रूप के अस्तित्व का स्रोत राज्य, कहना चाहिए, हवा में झूलता राज्य है, जिसमें और विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में कोई समानता नहीं है, जिसकी जड़ें अतीत में हैं, वर्तमान में नहीं।”

इस भ्रान्त धारणा पर कि आर्थिक हितों को राज्य की ज़रूरत होती है जिसका वे स्वयं निर्माण करते हैं ताकि वह मूर्त रूप प्राप्त कर सके, अथवा इस साहसिक दावे पर कि रूसी “सामाजिक रूप का” (जिसमें निस्सन्देह किसानों की सामुदायिक सम्पत्ति भी शामिल होनी चाहिए) “स्रोत राज्य है”, और इस

अन्तर्विरोध पर कि इस राज्य में और विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में, जो मानो उसकी ही रचना है, “कोई समानता नहीं है”, हमें ज़रा भी समय नहीं गंवाना चाहिए। इसके बजाय हमें तुरन्त इस “हवा में झूलते राज्य” की जांच कर लेनी चाहिए जो एक भी सामाजिक श्रेणी के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता।

यूरोपीय रूस में किसानों के पास १० करोड़ ५० लाख देस्यातीना और अभिजात वर्ग के पास (मैं यहां बड़े जागीरदारों को संक्षिप्तता की खातिर यह नाम दे रहा हूँ) १० करोड़ देस्यातीना ज़मीन है जिसमें से लगभग आधा भाग १५ हजार अभिजातों का है। फलस्वरूप प्रत्येक अभिजात के हिस्से में औसतन ३,३०० देस्यातीना ज़मीन आ जाती है। अतः किसानों की ज़मीन अभिजातों की ज़मीन से थोड़ी ही ज्यादा है। तो देखा आपने, अभिजातों की रूसी राज्य में, जो आधे देश पर उनके स्वामित्व की रक्षा करता है, ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है! चलिए, आगे बढ़ें। किसान अपने आधे भाग पर प्रति वर्ष १९ करोड़ ५० लाख रूबल लगान देते हैं तथा अभिजात १ करोड़ ३० लाख रूबल। अभिजातों की ज़मीन किसानों की ज़मीन से औसतन दुगुनी उपजाऊ है क्योंकि बेगारी के विमोचन के बन्दोबस्त के दौरान राज्य ने किसानों से ज़मीन का वड़ा ही नहीं, वरन् सबसे बढ़िया हिस्सा भी छीनकर उसे अभिजातों के हवाले कर दिया था और अपने पास रह जानेवाली यह सबसे ख़राब ज़मीन किसानों ने अभिजातों को सबसे बढ़िया ज़मीन देने की कीमत पर हासिल की।* और रूसी अभिजात वर्ग की रूसी राज्य में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है!

किसानों को—उनके विशाल जनसमुदाय को—विमोचन ने सबसे ज्यादा तंगहाली तथा पूरी तरह असह्य स्थिति में डाल दिया है। उनकी भूमि का सबसे बड़ा तथा सबसे अच्छा हिस्सा ही नहीं छीना गया जिससे देश के सबसे उपजाऊ इलाकों में किसानों की ज़मीन इतनी कम—रूसी कृषि परिस्थितियों के अनुसार—है कि उससे उनका गुज़ारा नहीं हो सकता। उनसे उसके लिए कसकर कीमत ही नहीं वसूली गयी जिसके लिए राज्य ने उन्हें उधार दिया और जिसके लिए उन्हें अब राज्य के मूलधन की अदायगी ब्याज समेत किश्तों में करनी पड़ रही।

*अपवाद पोलैंड है जहां सरकार अपने प्रति शत्रुता रखनेवाले अभिजात वर्ग को बर्बाद करना तथा किसानों को अपनी ओर करना चाहती थी। («Der Volksstaat» के पाठ में एंगेल्स की टिप्पणी, जिसे १८७५ तथा १८९४ के संस्करणों से निकाल दिया गया।)

है। भूमि कर का प्रायः पूरा बोझ उनपर धोपा ही नहीं गया है, इसके साथ ही अभिजात वर्ग उससे लगभग साफ़ बच गया है; अकेला यह भूमि कर ही कृषक की ज़मीन के किराये का पूरा मूल्य और उससे ज्यादा हड़प जाता है, तथा आगे के सारे भुगतान, जो किसान को करने पड़ते हैं तथा जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी आय के उस भाग से प्रत्यक्ष कटौतियाँ हैं जो उसकी मजदूरी है। इतना ही नहीं। भूमि कर के अलावा, राज्य द्वारा उधार दिये गये धन तथा व्याज की अदायगी के अलावा हाल ही में स्थानीय प्रशासन के आरम्भ होने के बाद प्रान्तीय तथा ज़िला शुल्क भी लागू किये गये हैं। इस “सुधार” का सबसे बड़ा परिणाम किसान पर नये करों का नया बोझ लादा जाना था। राज्य ने अपनी आय को पूरी तरह अपने पास रखा, परन्तु अपने व्यय के अधिकांश भाग की पूर्ति का दायित्व प्रान्तों तथा ज़िलों को सौंप दिया जिन्होंने उसकी पूर्ति के लिए नये कर लगाये, और रूस में यह एक नियम है कि ऊँची श्रेणियाँ करों से प्रायः मुक्त रहती हैं जबकि किसान को लगभग सारे कर देने होते हैं।

इस तरह की स्थिति मानो सूदखोर के लिए विशेष रूप से पैदा की गयी है, और निम्न स्तर पर व्यापार करने में, व्यापार की अनुकूल परिस्थितियों और उससे अटूट रूप से जुड़ी ठगी से फ़ायदा उठाने में रूसियों में प्रायः बेजोड़ प्रतिभा होने के कारण—पीटर प्रथम ने बहुत पहले ही कहा था कि एक रूसी तीन यहूदियों को मात दे सकता है—सूदखोर हर जगह प्रकट हो जाता है। कर चुकाने का ज्योंही वक़्त आता है, सूदखोर, कुलक—बहुधा उसी ग्राम समुदाय का अमीर किसान—प्रकट हो जाते हैं तथा नक़द मुद्रा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। किसान के पास हर सूरत में नक़द होना चाहिए और वह सूदखोर की शर्तों द्वारा भी बड़बड़ाहट किये बिना स्वीकार करने के लिए मजबूर होता है। इससे वह और ज्यादा शिकंजे में कस जाता है, और उसे अधिकाधिक नक़द मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। फ़सल की कटाई के समय अनाज का व्यापारी पहुंचता है; नक़द मुद्रा की आवश्यकता किसान को अनाज का, जिसकी उसे अपने तथा अपने परिवार का पेट भरने के लिए ज़रूरत होती है, एक हिस्सा बेचने के लिए मजबूर करती है। अनाज का व्यापारी झूठी अफ़वाहें फैलाता है, जिनसे क्रीमत घटती हैं, वह कम क्रीमत चुकाता है और यही नहीं अक्सर इसका एक हिस्सा भी सब तरह की महंगी चीज़ों के रूप में देता है क्योंकि रूस में जिन्स अदायगी प्रणाली बहुत विकसित है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि रूस द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज का निर्यात कृषक आबादी की प्रत्यक्ष भुखमरी पर आधारित है। किसान के शोषण का एक

और तरीका यह है—सट्टेवाज़ सरकारी जमीन लम्बे अर्से के लिए पट्टे पर ले लेता है और बिना खाद डाले उसपर स्वयं तब तक काश्त करता है जब तक उससे अच्छी फसल हासिल होती रहती है; फिर वह उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर इस अनुपजाऊ जमीन को बहुत ऊँचे लगान पर पड़ोस के किसानों को दे देता है जो अपनी जमीन की आय से गुज़ारा नहीं कर पाते। ऊपर वर्णित अंग्रेज़ जिन्स अदायगी प्रणाली की जगह यहां हमारे सामने ठीक आयरिश बिचौलिया है। संक्षेप में संसार में रूस के अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें बुर्जुवा समाज की आदिम बर्बरता के होते हुए भी पूंजीवादी परजीवीपन इतना विकसित हो कि उसने अपने जाल के अन्दर पूरे देश को, पूरा जनसमूह ले लिया हो, फंसा लिया हो। और किसानों के इन सारे रक्त-चूषकों की रूसी राज्य के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है जिसके कानून तथा अदालतें इनके चतुराई भरे तथा मुनाफ़ादेह कारोबार की रक्षा करती हैं!

पीटर्सबर्ग, मास्को, ओदेस्सा का बड़ा पूंजीपति वर्ग, जो पिछले दशक में मुख्यतया रेलों के निर्माण की बढौलत अभूतपूर्व द्रुत गति से विकसित हुआ है तथा पिछले संकट का जिस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, अनाज, सन, फ़्लैक्स और चरबी के निर्यातक, जिनका सारा कारोबार किसानों की तंगहाली पर आधारित है, पूरे का पूरा बड़े पैमाने का रूसी उद्योग जो राज्य द्वारा प्रदान किये जानेवाले संरक्षण शुल्क की ही बढौलत अस्तित्वमान है—आबादी के इन महत्वपूर्ण तथा तेज़ी से बढ़ते जा रहे तत्वों की क्या रूसी राज्य के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है? अधिकारियों की उस अनगिनत फ़ौज की तो बात ही क्या जो पूरे रूस में फैली हुई है, उसे लूटती है तथा एक वास्तविक सामाजिक श्रेणी बन चुकी है। और जब श्री त्काचोव हमें आश्वस्त करते हैं कि रूसी राज्य की “जनता के आर्थिक जीवन में जड़ें ही नहीं हैं”, कि वह “किसी खास सामाजिक श्रेणी के हितों का मूर्त रूप नहीं है”, कि वह “हवा में झूलता राज्य है”, तो हमें ऐसे लगता है कि रूसी राज्य नहीं, वरन् यों कहें कि स्वयं श्री त्काचोव हवा में झूल रहे हैं।

यह सुस्पष्ट है कि भूदासत्व से मुक्ति के उपरान्त रूसी किसानों की हालत असाध्य हो गयी है, कि यह हालत देर तर कायम नहीं रखी जा सकती, कि यदि और किसी कारण नहीं तो अकेले इस कारण क्रान्ति रूस में आसन्न है। प्रश्न केवल इतना है—इस क्रान्ति का परिणाम क्या हो सकता है, क्या होगा? श्री त्काचोव कहते हैं कि यह सामाजिक क्रान्ति होगी। यह विशुद्ध पुनरुक्ति है।

प्रत्येक वास्तविक क्रान्ति इस अर्थ में सामाजिक क्रान्ति भी होती है कि वह एक नये वर्ग को सत्ताखुद्द करती है, उसे समाज को अपनी कल्पना के अनुसार नये सिरे से ढालने का मौका देती है। परन्तु श्री त्काचोव यह कहना चाहते हैं कि यह क्रान्ति समाजवादी होगी, कि वह रूस में समाज का वह रूप प्रचलित कर देगी जो पश्चिम यूरोपीय समाजवाद का लक्ष्य है और ऐसा वह हम पश्चिम के लोगों से पहले ही कर देगी और वह भी समाज की ऐसी अवस्था में करेगी जिसमें सर्वहारा वर्ग तथा पूँजीपति वर्ग दोनों छितरे हुए रूप में प्रकट होते हैं तथा विकास की बहुत निचली मंजिल में हैं। और यह इसलिए सम्भव है कि रूसी गोया समाजवाद के लिए ही पैदा हुए लोग हैं और उनके पास आर्तेल और भूमि का समान स्वामित्व है।

आर्तेल की श्री त्काचोव ने प्रसंगतः चर्चा की है, परन्तु उसे हम यहां इसलिए शामिल कर रहे हैं कि हर्जेन के समय से ही बहुत-से रूसियों के लिए उसकी रहस्यमय भूमिका रही है। रूस में आर्तेल सहकारिता का व्यापकतम रूप, मुक्त सहकारिता का ऐसा सरलतम रूप रहा है जैसा शिकारी कबीलों में शिकार करने के लिए व्याप्त रहा है। नाम और अन्तर्वस्तु के मामले में वे स्लाव नहीं हैं, बल्कि तातार मूल के हैं। दोनों एक ओर किर्गिज और याकूत, आदि के बीच और दूसरी ओर लाप्पों, सामोयेदों तथा दूसरी फ़िनिश जातियों के बीच मिलते हैं।* यही कारण है कि आर्तेल दक्षिण-पश्चिम में नहीं, वरन् उत्तर और पूर्व में फ़िनों और तातारों के सम्पर्क में आने के कारण विकसित हुए। कठोर जलवायु विविध प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की अपेक्षा करती है और शहरी विकास की कमी तथा पूँजी के अभाव की पूर्ति, जहां तक सम्भव होता है, सहकारिता का यह रूप कर देती है। आर्तेल का एक सबसे अभिलाक्षणिक गुण—उसके सदस्यों का तीसरे पक्ष के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व—मूलतः प्राचीन जर्मनों के पारस्परिक उत्तरदायित्व (gewere) जैसे रक्त सम्बन्धों, रक्त प्रतिशोध, आदि पर आधारित था। यही नहीं, रूस में आर्तेल शब्द सामूहिक कार्यकलाप के लिए ही नहीं, वरन् सामूहिक संस्थान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

मजदूरों के आर्तेलों में हमेशा एक बुजुर्ग (starosta, starshina) चुना जाता है जो ख़ज़ांची, मुनीम, आदि का, और जहां तक ज़रूरी होता है, मेनेजर

* आर्तेल के बारे में देखें «Sbornik materialow ob Arteljach v Rossiji» (रूस में आर्तेलों पर सामग्री का संग्रह), सेंट पीटर्सबर्ग, १८७३, भाग १। (एंगेल्स की टिप्पणी)

का काम करता है तथा विशेष वेतन पाता है। ऐसे आर्तेल निम्नलिखित मौकों पर स्थापित किये जाते हैं—

१. अस्थायी उद्यमों के लिए, जो काम पूरा होने पर भंग कर दिये जाते हैं;

२. एक ही व्यवसाय के सदस्यों के, उदाहरण के लिए माल-वाहक, आदि के लिए;

३. स्थायी उद्यमों के लिए, वास्तविक अर्थ में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए।

ये एक करार द्वारा स्थापित किये जाते हैं जिस पर सारे सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। यदि ये सदस्य आवश्यक पूंजी—उदाहरण के लिए पानी और मत्स्य उद्यमों के मामले में (जाल, नाव, आदि के लिए)—जमा नहीं कर पायें—और यह अक्सर होता है—तो आर्तेल सूदखोर के चंगुल में फंस जाता है जो कम पड़ गयी धनराशि बहुत ज्यादा व्याज पर देता है और उसके बाद काम से होनेवाली आय का बड़ा हिस्सा अपनी जेब में भर लेता है। परन्तु इनसे भी ज्यादा शर्मनाक शोषण उन आर्तेलों का होता है जिनके सदस्य उजरती मजदूरों की हैसियत में अपने को भाड़े पर मालिक के हवाले कर देते हैं। वे अपनी औद्योगिक गतिविधियों का स्वयं संचालन करते हैं तथा इस तरह पूंजीपति का देखभाल पर होनेवाला खर्चा बचा देते हैं। पूंजीपति मजदूरों को रहने के लिए झोंपड़ियां तथा आजीविका के साधन कर्ज पर दे देता है जिससे सबसे वीभत्स जिन्स अदायगी प्रणाली जन्म लेती है। आखिर्गिल्स्काया गुबेर्निया में जंगलों में लकड़ी काटनेवालों, तारकोल उद्यमों में तथा साइबेरिया आदि में बहुत-से व्यवसायों में काम करनेवाले लोगों के साथ यही होता है (देखें फ्लेरोव्स्की, 'रूस में मजदूर वर्ग की दशा', सेंट पीटर्सबर्ग, १८६६)। इस तरह आर्तेल पूंजीपति द्वारा उजरती मजदूर का शोषण सुगम बनाता है। दूसरी ओर ऐसे भी आर्तेल हैं जो खुद उजरती मजदूर रखते हैं जो उनके सदस्य नहीं होते।

इस तरह यह देखा जा सकता है कि आर्तेल ऐसी सहकारी सोसायटी है जो स्वतःस्फूर्त रूप से उत्पन्न हुई है और इसलिए अब भी बहुत अल्पविकसित है तथा इस कारण न तो वह विशिष्ट रूप से रूसी है और न स्लाव ही है। ऐसी सोसायटियां हर उस जगह बन जाती हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है—उदाहरण के लिए स्विट्ज़रलैंड में डेरी फार्मों के बीच, इंगलैंड में मछुवाहों के बीच जहां वे अत्यन्त विविध रूप ग्रहण करती हैं। साइलेशियाई खुदाई मजदूर (पोल नहीं, जर्मन), जिन्होंने पांचवें दशक में इतनी सारी जर्मन रेलवे लाइनों का

निर्माण किया था, वास्तविक आर्तेलों में संगठित थे। रूस में इस रूप का प्रभुत्व निस्सन्देह रूसी जनता में सहचारिता के प्रति दृढ़ आकर्षण की विद्यमानता सिद्ध करता है। परन्तु वह कतई यह सिद्ध नहीं करता कि उनमें इस आकर्षण की मदद से आर्तेल से सीधे समाज की समाजवादी व्यवस्था में छलांग लगाने की योग्यता है। उसके लिए सर्वोपरि यह आवश्यक है कि स्वयं आर्तेल में विकास की क्षमता हो, कि वह अपने उस स्वयंस्फूर्त रूप का त्याग करे जिसमें—जैसा कि हम देख चुके हैं—वह मजदूर की कम तथा पूंजी की अधिक सेवा करता है; कि वह कम से कम पश्चिम यूरोपीय सहकारी सोसायटियों के स्तर तक ऊपर उठे। परन्तु यदि श्री त्काचोव की बात पर इस बार विश्वास (उपरिलिखित को देखते हुए यह यकीनन जोखिम भरा ही है) कर भी लिया जाये, तो बात कदापि ऐसी नहीं है। इसके विपरीत वह हमें ऐसे गर्व के साथ, जो उनके दृष्टिकोण का अत्यन्त अभिलाक्षणिक गुण है, यकीन दिलाते हैं—

“जहां तक रूस में कृत्रिम ढंग से रोपे जानेवाले जर्मन” (!) “नमूने की सहकारी तथा उद्योग सोसायटियों का सम्बन्ध है, उनकी ओर हमारे मजदूरों की बहुसंख्या ने पूर्ण उपेक्षा-भाव अपनाया है तथा वे लगभग सर्वत्र विफल रही हैं।”

आधुनिक सहकारी सोसायटी ने कम से कम यह सिद्ध तो कर दिया है कि वह स्वयं बड़े पैमाने के उद्योग को लाभप्रद ढंग से चलाने में समर्थ है (लंकाशायर में कताई तथा बुनाई)। आर्तेल यह करने में अब तक केवल असमर्थ ही नहीं रहा है; वह यदि और आगे विकसित नहीं होता तो बड़ा उद्योग उसे नष्ट तक कर देगा।

रूसी किसानों के सामुदायिक स्वामित्व का पता प्रशियाई सरकार के काउंसिलर हक्सटहाउजेन ने १८४५ में लगाया था और उन्होंने दुनिया के सामने उसका ढिंढोरा पीटते हुए उसे सर्वथा अद्भुत वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया था हालांकि उन्हें स्वयं अपनी वेस्टफेलियन मातृभूमि में उसके पर्याप्त अवशेष मिल जाते, और एक सरकारी अधिकारी होने के नाते इस बारे में पूरी तरह जानना उनका फ़र्ज भी था।^{१५} हक्सटहाउजेन से ही हर्जो को—खुद रूसी जागीरदार—पहले-पहल पता लगा था कि उनके किसानों के पास साझी भूमि है और उन्होंने यह तथ्य रूसी किसानों को समाजवाद का सच्चा वाहक, जीर्णमान, गलित यूरोपीय पश्चिम के मजदूरों के विपरीत, जिन्हें पहले कृत्रिम रूप से समाजवाद हासिल

करने की अग्नि-परीक्षा के बीच से गुजरना होगा, जन्मजात कम्युनिस्ट बताने के लिए इस्तेमाल किया। हर्जें से यह ज्ञान बकूनिन के पास और बकूनिन से त्काचोव के पास पहुंचा। आइये, ज़रा त्काचोव की बात सुनें—

०

“साझे स्वामित्व के सिद्धान्त... हमारी जनता की विशाल बहुसंख्या के रंग-रंग में हैं; कह सकते हैं कि वह अपने स्वभाव से ही, परम्परागत रूप से कम्युनिस्ट है। सामूहिक स्वामित्व का विचार रूसी जनता के पूरे विश्व-दृष्टिकोण से इस तरह गुंथा हुआ है” (यह हम अभी आगे देखेंगे कि रूसी किसान का विश्व कहां तक फैला हुआ है) “कि आज, जब सरकार यह समझने लगी है कि यह विचार ‘सुव्यवस्थित समाज’ के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता और इन सिद्धान्तों के नाम पर निजी स्वामित्व के विचार को जनता की चेतना तथा जीवन में बिठाना चाहती है, वह ऐसा केवल संगीन तथा कोड़े की मदद से ही कर सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जनता अपने अज्ञान के बावजूद पश्चिमी यूरोप के जनगण की तुलना में समाजवाद के कहीं समीप है हालांकि वे अधिक शिक्षित हैं।”

वास्तविकता यह है कि भूमि का सामुदायिक स्वामित्व स्वयं एक ऐसा संस्थान है जो भारत से लेकर आयरलैंड तक विकास के निचले स्तर वाले तमाम भारोपीय जनगण के बीच, यही नहीं भारत के प्रभाव में विकसित हो रहे मलयों के बीच—उदाहरण के लिए जावा में—पाया जाता है। १६०८ में ही नव विजित उत्तरी आयरलैंड में कानूनी रूप से प्रतिष्ठित भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व ने अंग्रेजों को ज़मीन स्वामीहीन घोषित करने तथा उसे ताज के लिए ज़ब्त करने के बहाने का काम दिया। भारत में सामुदायिक स्वामित्व के रूपों की एक पूरी शृंखला वर्तमान काल तक अस्तित्व में है। जर्मनी में यह आम था; वहां अब भी यत्न-तत्न मिलनेवाली सामुदायिक भूमि उसके ही अवशेष हैं; उसके विशिष्ट अवशेष—सामुदायिक भूमि के समय-समय पर पुनर्विभाजन आदि—अब भी पाये जाते हैं, खास तौर पर पहाड़ों में। प्राचीन जर्मन सामुदायिक स्वामित्व के विषय में अधिक सटीक संदर्भ तथा तफ़्सीलें मारेर की विभिन्न रचनाओं में मिल जाती हैं जो आज भी इस प्रश्न के सम्बन्ध में क्लासिकीय हैं। पोलैंड तथा लघु रूस⁸² समेत पश्चिम यूरोप में सामाजिक विकास की एक खास मंज़िल के दौरान यह सामुदायिक स्वामित्व कृषि उत्पादन के लिए एक बेड़ी तथा ब्रेक बन गया और उसका अधिकाधिक उन्मूलन किया गया। दूसरी ओर बृहद रूस में (यानी खासकर रूस में) यह आज भी बना हुआ है और इस तरह सर्वोपरि यह सिद्ध करता है कि

यहां कृषि उत्पादन तथा देहात में सामाजिक अवस्थाएं अब भी अविकसित हैं और स्थिति वस्तुतः ऐसी ही है। रूसी किसान केवल अपने समुदाय में रहता और काम करता है; शेष संसार का उसके लिए केवल उसी हद तक अस्तित्व है जिस हद तक वह उसके समुदाय के साथ हस्तक्षेप करता है। यह इस हद तक सच है कि रूस में «mir» शब्द के दो अर्थ हैं, एक ओर उसका अर्थ “विश्व” तथा दूसरी ओर उसका अर्थ “कृषक समुदाय” है। «Ves mir» — सारा विश्व — का किसान के लिए अर्थ समुदाय के सदस्यों की सभा है। इसलिए जब श्री त्काचोव रूसी किसानों के विश्व-दृष्टिकोण की बात करते हैं तो उन्होंने स्पष्टतः रूसी mir शब्द का गलत अनुवाद कर दिया है। अलग-अलग समुदायों का इस तरह एक दूसरे से पूरा अलगाव, जो पूरे देश में निस्सन्देह एक जैसे — परन्तु साझे बिल्कुल नहीं — हितों का सृजन करता है, प्राच्य निरंकुशतावाद का स्वाभाविक आधार है और भारत से लेकर रूस तक समाज के इस रूप ने — वह जहां कहीं प्रचलित रहा — सदैव उसे पैदा किया और उसमें सदैव अपना परिपूरक पाया है। सामान्य रूप में रूसी राज्य ही नहीं, बल्कि उसका विशिष्ट रूप, ज़ारशाही निरंकुशतावाद तक हवा में झूलता ही नहीं, बल्कि रूसी सामाजिक अवस्थाओं की, जिनमें तथा राज्य में श्री त्काचोव के अनुसार “कोई समानता नहीं है”, अनिवार्य तथा तर्कसम्मत उपज है! पूंजीवादी दिशा में रूस का आगे विकास यहां भी रूसी राज्य द्वारा “संगीन और कोड़े” से हस्तक्षेप के बिना सामुदायिक स्वामित्व को धीरे-धीरे नष्ट कर देता। यह इस कारण और भी होता क्योंकि रूस में सामुदायिक स्वामित्व की भूमि पर किसान इस तरह मिलकर खेती नहीं करते कि उपज का ही बंटवारा हो सकता, जैसा कि भारत के कई भागों में आज भी होता है; इसके विपरीत ज़मीन समय-समय पर विभिन्न परिवारों के प्रमुखों के बीच बांटी जाती रहती है और हरेक अपने हिस्से के टुकड़े पर ख़ुद काशत करता है। फलस्वरूप समुदाय के सदस्यों के बीच समृद्धि की मात्रा में बहुत अन्तर सम्भव है और वस्तुतः यह अन्तर है भी। लगभग सब जगह उनके बीच चन्द अमीर — यत्न-तत्न लखपति भी — किसान हैं जो सूदखोरी का काम करते हैं तथा किसानों के व्यापक जनसमुदाय का खून चूसते हैं। इसे श्री त्काचोव से बेहतर और कोई नहीं जानता। जहां वह चाहते हैं कि जर्मन मज़दूर इस बात पर यकीन करें कि “सामूहिक स्वामित्व का विचार” रूसी किसानों के, इन जन्मजात, परम्परागत कम्युनिस्टों के बीच से केवल “संगीन और कोड़े” से ही ख़त्म किया जा सकता है, वहां वह अपनी रूसी पुस्तिका में पृष्ठ १५ पर लिखते हैं —

“किसानों के बीच से सूदखोरों (kulakov) का एक वर्ग—किसान अभिजात वर्ग—पैदा हो रहा है जो किसानों और ज़मींदारों की ज़मीन ख़रीदता और उसे लगान पर उठाता है।”

□

ये उसी तरह के रक्त-चूषक हैं जिनका हम ऊपर पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन कर चुके हैं।

सामुदायिक स्वामित्व पर सबसे ज़्यादा चोट की बेगारी से विमोचन ने। ज़मीन का बढ़िया तथा बेहतर हिस्सा ज़मींदारों को दे दिया गया; किसान के पास मुश्किल से गुज़ारा चलाने लायक—और वह भी काफ़ी नहीं—ज़मीन बची। इसके अतिरिक्त वन ज़मींदारों के हवाले कर दिये गये; किसान ईंधन, औज़ारों तथा निर्माण के लिए पहले जो लकड़ी मुफ़्त ही प्राप्त कर लेते थे, उसे अब उन्हें ख़रीदना पड़ता है। इस तरह किसान के पास अब मकान, खाली ज़मीन के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं था और इस ज़मीन की काश्त के लिए उसके पास औज़ार नहीं थे; आम तौर पर उसके पास इतनी ज़मीन नहीं होती थी जो उसका और उसके परिवार का एक फ़सल से लेकर दूसरी फ़सल तक पेट भर सकती। ऐसी परिस्थितियों में, तथा करें और सूदखोरों के बोझ के नीचे ज़मीन का सामुदायिक स्वामित्व अब बरदान नहीं रह गया है, वह पांवों की बेड़ी बन गया है। किसान अक्सर ज़मीन छोड़कर सपरिवार या अकेले ही भ्रमणशील मज़दूरों के रूप में जीवनोपार्जन के लिए इस समुदाय से भाग जाते हैं।*

यह स्पष्ट है कि रूस में सामुदायिक स्वामित्व अपनी तरुणार्ई के दिन बहुत पीछे छोड़ आया है और सारे लक्षण इस बात के प्रमाण हैं कि वह अपने विघटन की ओर अग्रसर है। इसके बावजूद समाज के इस रूप को एक उच्चतर रूप में पहुंचाने की निर्विवाद रूप में सम्भावना विद्यमान है बशर्ते इसके लिए परिस्थितियों के परिपक्व होने तक यह टिका रहे, बशर्ते वह इस ढंग से विकसित होने की क्षमता प्रदर्शित कर सके कि किसान ज़मीन पर अलग-अलग नहीं, बरन् सामूहिक

* किसानों की दशा के बारे में देखें कृषि उत्पादन पर सरकारी आयोग की अधिकृत रिपोर्ट (१८७३) और साथ ही स्काल्दिन की कृति—‘दूर-दराज़ के स्थानों में तथा राजधानी में’, सेंट पीटर्सबर्ग, १८७०। दूसरी कृति एक नरम विचारों के अनुदारपंथी की है। (एंगेल्स की टिप्पणी)

रूप में काय्य करें; * कि वह इस ढंग से उच्चतर रूप में पहुँचने की क्षमता प्रदर्शित करे कि यह रूसी किसानों के लिए पूँजीवादी छोटी जोतों की मध्यवर्ती मंजिल से गुजरे बिना सम्भव हो। इस सामुदायिक स्वामित्व के विघटन से पहले पश्चिम यूरोप में ऐसी विजयी सर्वहारा क्रान्ति की आवश्यकता है जो रूसी किसानों के लिए इस प्रकार के संक्रमण के लिए आवश्यक अवस्थाओं को, विशेष रूप से ऐसे भौतिक साधनों को प्रस्तुत करे जिनकी उसे अपनी पूरी कृषि-प्रणाली से लाजिमी तौर पर जुड़ी हुई क्रान्ति सम्पन्न करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए श्री त्काचोव का यह दावा सरासर बकवास है कि रूसी किसान “मालिक” होते हुए भी पश्चिमी यूरोप के सम्पत्तिहीन मजदूरों की तुलना में “समाजवाद के अधिक समीप” हैं। बात ठीक इसके विपरीत है। यदि कोई चीज रूसी सामुदायिक स्वामित्व को अब भी बचा सकती है तथा उसे एक नये, वस्तुतः जीवन्त रूप में विकसित होने का मौका दे सकती है तो वह पश्चिमी यूरोप में सर्वहारा क्रान्ति ही है।

श्री त्काचोव राजनीतिक क्रान्ति के प्रति उतना ही गैरसंजीदा रख अपनाते हैं जितना वह आर्थिक क्रान्ति के प्रति अपनाते हैं। वह कहते हैं कि रूसी जनता अपनी दासता के विरुद्ध “धार्मिक सम्प्रदायों... कर देने से इन्कार... डाकुओं के गिरोहों (जर्मन मजदूरों को यह जानकर खुशी होगी कि इस हिसाब से शिंडेरहान्स ** जर्मन सामाजिक-जनवाद का पिता है) ... आगजनी... विद्रोहों के रूप में अनवरत विरोध करती है और इसलिए रूसी जनता को स्वभाव से क्रान्तिकारी माना जा सकता है।” इस तरह श्री त्काचोव को पूरा यकीन है कि “केवल इतना आवश्यक है कि कटुता तथा असन्तोष की सारी संचित भावना का, जो... हमारी जनता के मन में हमेशा खौलती रहती है, सर्वत्र एकसाथ बांध टूटे।” तब “क्रान्तिकारी शक्तियों की संघबद्धता अपने आप सम्पन्न हो जायेगी तथा संघर्ष का अन्त अनिवार्यतः जनता के ध्येय के पक्ष में होगा।

* पोलैंड में, विशेष रूप से ग्रोदो ग्वेर्निया में, जहाँ अधिकांश ज़मींदार १८६३ के विद्रोह के फलस्वरूप बर्बाद हो गये थे, किसान अब बहुधा ज़मींदारों से जागीरें खरीदते या पट्टे पर लेते हैं और उसे टुकड़ों में बाँटे बिना सामुदायिक लाभार्थ उस पर खेती करते हैं। और इन किसानों के पास शताब्दियों से कोई सामुदायिक स्वामित्व नहीं रहा तथा वे रूसी नहीं हैं अपितु पोल, लिथुआनियाई तथा वेलोरूसी हैं। (एंगेल्स की टिप्पणी)

** कुख्यात जर्मन डाकू जोहन बुक्लेर का उपनाम। - सं०

व्यावहारिक आवश्यकता, आत्म-रक्षा की सहजवृत्ति" तब सर्वथा स्वयं विरोधी ग्राम समुदायों के मध्य दृढ़ तथा अटूट सम्पर्क" का निर्माण कर देगी।

क्रान्ति की इससे अधिक सुगम तथा सुखद शर्तों पर कल्पना करना असम्भव है। तीन या चार स्थानों पर गाँवियाँ चलाना आरम्भ कर दें, बाकी काम "सहज क्रान्तिकारिता", "व्यावहारिक आवश्यकता" तथा "आत्म-रक्षा की सहजवृत्ति "स्वयमेव" कर देंगी। यदि यह इतना आसान हो तो फिर यह सर्वथा अवोधगम्य है कि क्रान्ति बहुत पहले क्यों नहीं हुई थी, जनता क्यों मुक्त नहीं की गयी थी तथा रूस का आदर्श समाजवादी देश में क्यों रूपान्तरण नहीं हुआ था।

वस्तुतः बात बिल्कुल विपरीत है। यह सच है कि रूसी जनता ने, इस "सहज क्रान्तिकारी" ने अभिजातों के खिलाफ़, पृथक्-पृथक् अधिकारियों के खिलाफ़ अनेक अलग-थलग संघर्ष किये लेकिन ज़ार के खिलाफ़ कभी नहीं, सिवाय उन मौकों के जब नक़ली ज़ार जनता का अगुआ बनकर सिंहासन पर दावा करने लगते। येकातेरीना द्वितीय के समय अन्तिम बड़ा कृषक विद्रोह केवल इसलिए सम्भव हुआ कि येमेल्यान पुगाचोव ने दावा किया कि वह उसका पति, पीटर तृतीय है जिसे उसकी पत्नी ने क़त्ल नहीं कराया था, बल्कि सिंहासन से हटाकर जेल में बन्द कर दिया था और वह अब वच निकला। ज़ार रूसी किसान के लिए पार्थिव ईश्वर है: ईश्वर बहुत ऊपर तथा ज़ार बहुत दूर है, -किसान संकट की घड़ी में उसका ही नाम लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कृषक आबादी के बहुत बड़े भाग की खास तौर पर बेगारी से विमोचन के बाद ऐसी हालत हो गयी है जो उसे सरकार तथा ज़ार के विरुद्ध लड़ने के लिए अधिकाधिक विवश करती है। परन्तु श्री त्काचोव को "सहज क्रान्तिकारी"-सम्बन्धी अपनी परी-कथा के लिए श्रोताओं की तलाश और कहीं करनी होगी।

और यदि यह मान भी लिया जाये कि रूसी किसानों का व्यापक जनसमुदाय इतना सहज क्रान्तिकारी था, यदि हम यह कल्पना भी कर लें कि क्रान्तियाँ उसी तरह आदेश देकर तैयार की जा सकती हैं जिस तरह कोई वेलबूटेदार कपड़ा या समोवर तैयार किया जा सकता है, तब भी यह पूछा जा सकता है—क्या बारह साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को क्रान्ति की धारा की ऐसे वचकाना ढंग से—जैसा कि हम यहां देख रहे हैं—कल्पना करना शोभा देता है? और याद रहे, इसे वकूनिन नमूने पर की गयी पहली क्रान्ति के, १८७३ की स्पेनी क्रान्ति की इतनी शानदार पराजय के बाद लिखा गया था। वहां भी विद्रोह अनेक स्थानों में एकसाथ शुरू किया गया था। वहां भी यह अनुमान लगाया गया था

कि व्यावहारिक आवश्यकता तथा आत्म-रक्षा की सहजवृत्ति विरोध करनेवाले समुदायों के बीच दृढ़ तथा अटूट सम्पर्क का निर्माण कर देंगी। परन्तु हुआ क्या ? प्रत्येक समुदाय ने, प्रत्येक शहर ने केवल अपनी रक्षा की, पारस्परिक सहायता का सवाल ही नहीं उठा। और अपने साथ केवल तीन हजार लोगों को लेकर पाविया ने एक पखवाड़े में एक के बाद दूसरे शहर पर कब्जा कर डाला और इस पूरी अराजकतावादी कीर्ति का अन्त कर डाला। (देखें, मेरा लेख 'कार्यरत वकूनिनपंथी', जहां इसपर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है)

रूस निर्विवाद रूप से क्रान्ति की देहरी पर खड़ा है। उसकी वित्तीय स्थिति सर्वथा विशृंखलित है। और ज्यादा कर लादने की गुंजाइश नहीं है, पुराने राजकीय ऋणों पर व्याज नये ऋण लेकर चुकाया जा रहा है, और हर नया ऋण पहले से अधिक कठिनाई से प्राप्त हो रहा है ; मुद्रा अब केवल रेलवे लाइनों के निर्माण के बहाने हासिल की जा सकती है। प्रशासन पहले ही ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, अफसर लोग अपने वेतनों से अधिक चोरी, घूसखोरी तथा लूट-खसोट पर आश्रित हैं। पूरा कृषि उत्पादन - रूस के लिए अधिकतम महत्वपूर्ण - १८६१ की विमोचन व्यवस्था द्वारा पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है ; बड़े ज़मींदारों को पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं, किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, वे करों के बोझ से झुके जा रहे हैं तथा सूदखोर उनका खून बुरी तरह चूस रहे हैं ; कृषि उत्पादन वर्ष प्रति वर्ष घटता जा रहा है। इन सब को बड़ी कठिनाई से और केवल बाहरी तौर पर एक ऐसा प्राच्य निरंकुशतावाद एक सूत्र में बांधे हुए है जिसको स्वेच्छाचारिता की पश्चिम में हम कल्पना तक नहीं कर सकते ; यह ऐसा निरंकुशतावाद है जिसका प्रबुद्ध वर्गों, विशेष रूप से तेज़ी से विकसित हो रहे राजधानी के पूंजीपति वर्ग के विचारों के साथ दिन प्रति दिन तीक्ष्ण टकराव ही नहीं हो रहा है अपितु जो अपने वर्तमान वाहक के रूप में अपना होश भी खो बैठा है, वह आज उदारतावाद को रियायतें देता है तो कल डर के मारे उन्हें रद्द कर देता है तथा इस तरह अपने को अधिकाधिक बदनाम कर रहा है। इसके साथ ही राजधानी में संकेंद्रित राष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग में यह अनुभूति बढ़ रही है कि यह स्थिति टिकनेवाली नहीं है, कि क्रान्ति आसन्न है, परन्तु साथ ही यह भ्रम भी विद्यमान है कि इस क्रान्ति को सुगम वैधानिक रास्ते में ले जाना सम्भव है। यहां क्रान्ति की सारी अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं ; राजधानी के ऊपरी वर्गों द्वारा तथा सम्भवतः स्वयं सरकार द्वारा शुरू की गयी इस क्रान्ति को किसानों को तेज़ी से आगे, पहले वैधानिक दौर के पार पहुंचाना होगा ; यह क्रान्ति यदि

और किसी कारण नहीं तो कम से कम इस कारण यूरोप के लिए सबसे अधिक महत्व की होगी कि वह पूरे यूरोपीय प्रतिनिध्यावाद की आरक्षित शक्ति को, जो अब तक अक्षुण्ण है, एक ही झटके में नष्ट कर देगी। यह क्रान्ति निस्सन्देह पास आती जा रही है। केवल दो घटनाएं इसे विलम्बित कर सकती हैं—तुर्की या आस्ट्रिया के विरुद्ध कामयाब लड़ाई जिसके लिए धन तथा दृढ़ संघबद्धता आवश्यक हैं, अथवा... विद्रोह का समयपूर्व प्रयास जो सम्पत्तिधारी वर्गों को फिर से सरकार की बांहों में पहुंचा देगा।

एंगल्स द्वारा अप्रैल १८७५ में लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

१६, १८ और २१ अप्रैल १८७५ को «Der Volksstaat» के अंक ४३, ४४ और ४५ में, तथा एक पृथक पुस्तिका «Soziales aus Rußland», लाइपज़िग, १८७५ तथा «Internationales aus dem «Volksstaat», बर्लिन, १८६४ में प्रकाशित।

हस्ताक्षर—फ्रे० एंगल्स

‘रूस में सामाजिक सम्बन्धों के विषय में’

लेख का परिशिष्ट

मुझे अपनी बात एक भूल सुधारने के साथ शुरू करनी चाहिए। बात यह है कि श्री त्काचोव—सही-सही कहा जाये—बकूनिनपंथी यानी अराजकतावादी नहीं थे, वह “ब्लांकीपंथी” होने का दावा करते थे। यह भूल सर्वथा स्वाभाविक थी क्योंकि श्री त्काचोव ने पश्चिम यूरोप के समक्ष उस समय के रूसी उत्प्रवासियों की रीति के अनुसार स्वयं घोषणा की थी कि उनकी सारे रूसी उत्प्रवासियों के साथ हमदर्दी है, साथ ही उन्होंने अपने एक पत्रों में मेरे द्वारा की गयी आलोचना के सिलसिले में बकूनिन और उनके संगी-साथियों की वकालत की थी और यह काम इस तरह किया मानों यह आलोचना स्वयं उनके विरुद्ध लक्षित हो।

रूसी कम्युनिस्ट ग्राम समुदाय के विचार, जिसकी उन्होंने मेरे साथ वाद विवाद में हिमायत की, मूलतः स्वयं हर्जेंन के थे। हर्जेंन ने, इस सर्वस्वाववादी लेखक ने, जिसे फुलाकर क्रान्तिकारी का रूप दिया गया, हवस्टहाउज़ेन की ‘रूस

का अध्ययन' शीर्षक कृति से यह सीखा था कि उसकी जागीर में काम करनेवाले भू-दासों का भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था तथा वे समय-समय पर कृषि भूमि तथा चरागाही जमीन का अपने बीच पुनर्वितरण किया करते थे। लेखक होने के नाते उन्हें वह चीज सीखने की आवश्यकता नहीं थी जो शीघ्र सर्वविदित हो गयी, अर्थात् भूमि का सामुदायिक स्वामित्व भूधारण का ऐसा रूप है जो आदिम काल में जर्मनों, केल्टों, हिन्दुस्तानियों, संक्षेप में सारे इंडो-यूरोपियन जनगण में प्रचलित था, जो हिन्दुस्तान में अब भी प्रचलित है, जिसे आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हाल ही में जबरन खत्म किया गया तथा जर्मनी में आज भी यत्र-तत्र देखने को मिलता है, कि यह भूधारण का लुप्त हो रहा रूप है जो वस्तुतः विकास की एक खास मंजिल में सारे जनगण के बीच विद्यमान एक समान घटना-व्यापार है। परन्तु सर्वस्वाववादी होने के नाते हर्जें ने जो हृद से हृद कथनी में समाजवादी होने का दावा करता था, ग्राम समुदाय को एक ऐसे नये बहाने के रूप में देखा जिससे वह सड़े-गले पश्चिम के सामने अपना "पुनीत" रूस और उसका मिशन—इस पूर्णतः भ्रष्ट तथा पुराने पड़ चुके पश्चिम का कायाकल्प करने तथा आवश्यक होने पर बल-प्रयोग के जरिए उसका पुनरुज्जीवन करने का मिशन—और भी तेज रोशनी में दिखा सकें। जो अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जर्जर फ्रांसीसी और अंग्रेज नहीं कर पाते, वह रूसियों के पास अपने घर में तैयार किया-कराया है।

“ग्राम समुदाय को कायम रखना तथा व्यक्ति को स्वतंत्रता देना, राष्ट्रीय एकता बरकरार रखते हुए ग्राम तथा वोलोस्त का स्वशासन शहरों और पूरे राज्य तक फैलाना,—ऐसा है रूस के भविष्य का प्रश्न, अर्थात् ठीक उस सामाजिक विप्रतिषेध का प्रश्न जिसके समाधान का विषय पश्चिम के मस्तिष्कों पर छाया हुआ है और जो उन्हें परेशान कर रहा है।” (हर्जें, लिंटन के नाम पत्र)

तो हो सकता है कि रूस में राजनीतिक प्रश्न अब भी विद्यमान हो, परन्तु उसके लिए “सामाजिक प्रश्न” हल हो चुका है।

हर्जें का अंधानुसरण करनेवाले त्काचोव ने भी वही सहज दृष्टिकोण अपनाया। यद्यपि वह १८७५ में यह दावा करने की स्थिति में नहीं रहे कि रूस में “सामाजिक प्रश्न” हल हो चुका है, उन्होंने इतना जरूर कहा कि रूसी किसान, सारे के सारे जन्मजात कम्युनिस्ट, समाजवाद के बहुत समीप हैं और यही नहीं, पश्चिम यूरोप के बेचारे, अभाग्य सर्वहाराओं की तुलना में उनका जीवन कहीं बेहतर

है। यदि फ्रांसीसी जनतंत्रवादी अपनी एक शताब्दी की क्रान्तिकारी गतिविधि के बल पर अपनी जनता को गोया राजनीतिक कार्यकलाप के लिए जन्मे लोग मानते थे तो उस जमाने के बहुत-से रूसी समाजकृदियों ने रूस को गोया सामाजिक कार्यकलाप के लिए जन्मी जनता घोषित कर दिया था; पश्चिमी यूरोपीय सर्वहारा का संघर्ष पुराने आर्थिक संसार का नवीकरण करने नहीं जा रहा था; नहीं, यह नवीकरण तो रूसी कृषक समुदाय की ठीक गहराइयों से आनेवाला था। मेरी आलोचना इसी बचकाना दृष्टिकोण की ओर लक्षित थी।

परन्तु रूसी ग्राम समुदाय ने उन लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, उन लोगों से मान्यता प्राप्त की जो हर्जनों तथा त्काचोवों से कहीं ऊंचे हैं। उनमें एक थे निकोलाई चेर्निशेव्स्की, वह महान चिन्तक, जिनका रूस इतना ऋणी है और साइबेरिया में याकूतों के बीच दीर्घकाल तक निर्वासन के कारण जिनका शनैः शनैः भय अलेक्सान्द्र द्वितीय “मुक्तिदाता” की स्मृति पर हमेशा के लिए कलंक का टीका बना रहेगा।

रूस और पश्चिमी यूरोप के बीच बौद्धिक अवरोध के कारण चेर्निशेव्स्की मार्क्स की कोई कृति नहीं पढ़ पाये थे और जब ‘पूजी’ प्रकाशित हुई तो उन्हें खेद-विल्यड्स्क में याकूतों के बीच रहते एक लम्बा अर्सा हो चुका था। उनका पूरा आत्मिक विकास इस बौद्धिक अवरोधक द्वारा पैदा की गयी परिस्थितियों के ही अन्तर्गत हो सकता था। ज़ारशाही संसार ने जो कुछ रूस के अन्दर नहीं आने दिया, उसका, जहाँ तक रूस का सम्बन्ध था, प्रायः अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए यदि हमें चेर्निशेव्स्की की रचनाओं में कहीं कोई कमजोरियां नज़र आती हैं तो आश्चर्य इस पर होता है कि उनकी कृतियों में इनकी बहुलता क्यों नहीं है।

चेर्निशेव्स्की ने भी रूसी ग्राम समुदाय को समकालीन सामाजिक रूप से विकास की एक ऐसी नयी मंज़िल में संक्रमण के रूप में देखा था जो एक ओर रूसी ग्राम समुदाय से और दूसरी ओर अपने वर्ग-विरोधों समेत पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी समाज से ऊंची है। रूस के पास ऐसा साधन है, जबकि पश्चिम के पास नहीं है, यही चेर्निशेव्स्की की राय में रूस को श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करती है।

“व्यक्ति के अधिकारों का असीमित विस्तार पश्चिमी यूरोप में बेहतर व्यवस्था की स्थापना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बन रहा है... व्यक्ति जिसके उपयोग का आदी हो गया है, उसके एक नगण्य भाग तक का परित्याग करना सुगम नहीं

है और पश्चिम में व्यक्ति असीमित वैयक्तिक अधिकारों के उपयोग का आदी है। पारस्परिक रियायत की उपयोगिता तथा आवश्यकता को केवल कटु अनुभव तथा लम्बे चिंतन से ही सीखा जा सकता है। पश्चिम में आर्थिक सम्बन्धों की बेहतर प्रणाली बलिदानों से जुड़ी हुई है और यही कारण है कि उसे स्थापित करना कठिन है। वह अंग्रेज तथा फ्रांसीसी किसानों की आदतों के विरुद्ध है।” परन्तु “जो एक देश में कल्पनाविलास प्रतीत होता है, वह दूसरे में एक तथ्य के रूप में विद्यमान है... अंग्रेज तथा फ्रांसीसी जिन आदतों को अपने राष्ट्रीय जीवन में अपनाना अत्यन्त कठिन पाते हैं वे वस्तुतः रूसियों के राष्ट्रीय जीवन में तथ्य के रूप में विद्यमान हैं... इस समय पश्चिम इतने कठिन तथा लम्बे मार्ग पर चलते हुए जिस व्यवस्था को लाने के लिए इच्छुक है, वह हमारे देश में ग्राम समुदाय के सशक्त रीति-रिवाजों में अब भी विद्यमान है... हम देख रहे हैं कि सामुदायिक भू-स्वामित्व के उन्मूलन के पश्चिम में कितने दुःखद परिणाम निकले हैं तथा पश्चिम के जनगण को वह लौटाना कितना कठिन है जिसे वे खो बैठे हैं। पश्चिम का उदाहरण हमारी नज़र से ओझल नहीं होना चाहिए।” (चेर्निशेव्स्की, कृतियां, जेनेवा संस्करण, खंड ५, पृष्ठ १६-१९, प्लेखानोव की कृति ‘हमारे मतभेद’, जेनेवा, १८८५ से उद्धृत)

वह उराल के कज़ाकों की चर्चा करते हैं जो मिलकर खेती करते थे तथा उत्पादों को पृथक-पृथक परिवारों में बांट लेते थे—

“यदि उराल के लोग अपनी वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत उस समय तक रह जायें जब कृषि मशीनों का प्रचलन शुरू हो जायेगा तो उन्हें अपने बीच ऐसी व्यवस्था के बने रहने में बहुत खुशी होगी जो सैकड़ों देस्यातीना भूमि को अपनी परिधि में लानेवाली बड़े पैमाने की खेती के लिए आवश्यक मशीनों का उपयोग करने देगी।” (वहीं, पृष्ठ १३१)

परन्तु यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि उराल के कज़ाक, जिनके यहां ज़मीन पर सामुदायिक काश्त होती है तथा जिसकी फ़ौजी कारणों से रक्षा की जा रही है (आखिर हमारे यहां भी तो वैरक कम्युनिज़्म है), रूस में बाक़ी सब लोगों से भिन्न हैं, वे मोसेल में बिल्कुल हमारे गृहस्थ समुदायों (Gehöferschaften) तथा उनके समय-समय पर हो रहे पुनर्वितरण की तरह हैं। और यदि वर्तमान व्यवस्था मशीनों के प्रचलन तक अक्षुण्ण रह जाती है तो लाभ उन्हें नहीं, वरन् रूसी फ़ौजी राजकोष को होगा जिसके वे चाकर हैं।

कुछ भी हो, तथ्य यह है—जहां पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी समाज विघटित हो रहा है और स्वयं अपने विकास के अपरिहार्य विरोधों के कारण उसके लिए

विनाश का खतरा पैदा हो गया है, वहां रूस में लगभग आधी ज़मीन साझे सम्पत्ति के रूप में ग्राम समुदायों के हाथ में है। यदि पश्चिम में समाज के एक नये संगठन के जरिए विरोधों के समाधान का अर्थ एक आवश्यक शर्त के रूप में यह है कि उत्पादन के तमाम साधनों को और फलस्वरूप ज़मीन को भी समग्र समाज के स्वामित्व के अन्तर्गत कर दिया जाये तो सवाल उठता है कि इस साझे स्वामित्व का जिसे पश्चिम में अभी स्थापित किया जाना है, तथा उस सामुदायिक स्वामित्व में क्या सम्बन्ध है जो पहले से या यों कहें कि अब भी रूस में विद्यमान है? क्या वह ऐसे जन आन्दोलन के लिए प्रस्थान-बिन्दु का काम दे सकता है जो पूरी पूंजीवादी अवधि को लांघकर रूसी किसान कम्युनिज्म को पूंजीवादी युग की समस्त तकनीकी उपलब्धियों से समृद्ध करके तुरन्त उत्पादन के तमाम साधनों के मामले में आधुनिक समाजवादी सामुदायिक स्वामित्व में रूपान्तरित करेगा? अथवा जैसा कि मार्क्स ने आगे उद्धृत की गयी चिट्ठी * में चैर्निशेव्स्की के विचारों को निरूपित किया था, "क्या रूस को, जैसा कि उसके उदारतावादी अर्थशास्त्री चाहते हैं, ग्राम समुदाय को नष्ट कर काम शुरू करना चाहिए ताकि वह पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवेश कर सके अथवा क्या वह अपनी ऐतिहासिक अवस्थाओं का विकास करते हुए इस व्यवस्था के फलों को उसकी यातनाएं झेले बिना प्राप्त कर सकता है?"

प्रश्न का इस तरह प्रस्तुतीकरण ही बताता है कि उसका समाधान कहां निहित है। रूसी समुदाय शताब्दियों से विद्यमान रहा है और इस पूरे अर्से में उसने अपने अन्दर एक बार भी ऐसा उत्प्रेरक उत्पन्न नहीं किया है जो उसके सामुदायिक स्वामित्व के उच्च रूप में रूपान्तरण कर सकता जैसा कि जर्मन मार्क, केल्ट कबीले तथा भारतीय और आदिम कम्युनिस्ट व्यवस्था वाले दूसरे समुदायों के साथ हुआ। ये सब समय के प्रवाह के साथ तथा माल के उत्पादन तथा विनिमय के प्रभाव के अन्तर्गत, जो अलग-अलग परिवारों तथा व्यक्तियों पर छाया हुआ था तथा जो उनके अन्दर विकसित हुआ तथा जिससे वे धीरे-धीरे ओत-प्रोत होते चले गये, अधिकाधिक अपने कम्युनिस्ट स्वरूप का चोगा उतारते गये तथा स्वतंत्र भू-स्वामियों के समुदायों के रूप में एक दूसरे से अलग-अलग होते गये। इसलिए यदि यह प्रश्न करना ही सम्भव हो कि क्या इससे भिन्न और बेहतर भविष्य रूसी समुदाय की प्रतीक्षा कर रहा है तो इसका कारण स्वयं इसके अन्दर

* देखें प्रस्तुत खण्ड। - सं०

नहीं, वरन् इस तथ्य में ही निहित है कि एक यूरोपीय देश में उसने अपनी सापेक्ष जीवन-शक्ति ऐसे समय तक बरकरार रखी है जब पश्चिमी यूरोप में सामान्यतया माल उत्पादन ही नहीं, वरन् उसके सर्वोच्च तथा अन्तिम रूप का—पूँजीवादी उत्पादन का—स्वयं उसके द्वारा निर्मित उत्पादक शक्तियों से अन्तर्विरोध हो गया है, जब उसने इन शक्तियों को संचालित करने में अपने को असमर्थ सिद्ध कर दिया है, और जब वह इन आन्तरिक अन्तर्विरोधों तथा तदनुसूची वर्ग विरोधों द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। अकेले इसी चीज से यह निष्कर्ष निकलता है कि रूसी समुदाय के अन्ततः रूपान्तरण की पहल कभी स्वयं उसकी ओर से नहीं आयेगी, वरन् केवल पश्चिम के औद्योगिक सर्वहारा की ओर से आयेगी। पश्चिमी यूरोपीय सर्वहारा की पूँजीपति वर्ग पर विजय तथा उसके फलस्वरूप पूँजीवादी उत्पादन के स्थान पर समाज द्वारा नियंत्रित अर्थतन्त्र—यही है रूसी समुदाय को विकास की उसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए आवश्यक पूर्वशर्त।

दरअसल कबायली प्रणाली से चले आनेवाले कृषक कम्युनिज्म ने अपने अन्दर से अपने विघटन के सिवाय कभी और कुछ पैदा नहीं किया है। स्वयं रूसी कृषक समुदाय १८६१ तक इस तरह के कम्युनिज्म का अपेक्षाकृत दुर्बल रूप था; ज़मीन की साझी काश्त को, जो भारत के कुछ भागों में तथा दक्षिण स्लाव गृह समुदायों (zadruga) के बीच अब भी प्रचलित है और जो शायद रूसी समुदाय का पूर्वज है, पृथक-पृथक परिवारों द्वारा काश्त के लिए जगह खाली करनी पड़ी; सामुदायिक स्वामित्व अब भी केवल अत्यन्त भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न कालान्तरों में होनेवाले भूमि के पुनर्वितरण में प्रकट होता था। ये पुनर्वितरण एक बार स्वयं अथवा किसी विशेष आज्ञापति के जरिए लुप्त हो जायें तो आपके सामने छोटे भूमिधारी किसानों का गांव रह जाता है।

परन्तु मात्र यह एक तथ्य कि रूसी ग्राम समुदाय के साथ-साथ विद्यमान पश्चिमी यूरोप का पूँजीवादी उत्पादन अपनी मृत्यु की घड़ी के समीप पहुंचता जा रहा है और खुद उसके भ्रूण में उत्पादन का एक ऐसा नया रूप है जिसके अन्तर्गत सामुदायिक स्वामित्व के नाते उत्पादन साधनों का योजनाबद्ध उपयोग होगा, मात्र यह तथ्य रूसी समुदाय को इतनी शक्ति नहीं देगा जो उसे अपने आप से एक नया सामाजिक रूप तैयार करने में मदद दे सके। स्वयं पूँजीवादी समाज द्वारा यह क्रान्ति सम्पन्न किये जाने से पहले वह पूँजीवादी समाज की विशाल उत्पादक शक्तियों को कैसे सामुदायिक स्वामित्व तथा सामाजिक साधन के रूप में अपने हाथों में ले सकता है? जब रूसी समुदाय खुद यह भूल गया

है कि अपनी भूमि पर सामुदायिक ढर्रे पर कैसे काश्त की जाती है तो वह दुनिया को कैसे दिखायेगा कि बड़े पैमाने के उत्पादन का सामाजिक ढर्रे पर संचालन कैसे किया जा सकता है? ०

यह सच है कि रूस में बहुत-से लोगों को पश्चिमी पूंजीवादी समाज और उसके घोर अन्तर्विरोधों तथा टकरावों का काफ़ी ज्ञान है और इस प्रतीयमान बंदगली से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें स्पष्ट रूप से मालूम है। परन्तु पहली बात तो यह है कि जो चन्द हजार लोग यह समझते हैं, वे ग्राम समुदायों में नहीं रहते जबकि रूस के लगभग ५ करोड़ व्यक्तियों को, जो अब भी भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के अन्तर्गत रहते हैं, इस बारे में लेशमात्र ज्ञान भी नहीं है। वे इन चन्द हजार लोगों के विचारों को उतना ही विजातीय तथा दुर्बोध पाते हैं जितना विजातीय तथा दुर्बोध १८००-१८४० के अंग्रेज सर्वहाराओं ने उनकी मुक्ति के लिए राबर्ट ओवेन द्वारा बनायी गयी योजनाओं को पाया था। ओवेन ने न्यू-लानार्क में अपनी फ़ैक्टरी में जितने लोगों को काम पर रखा था, उनमें से अधिकांश का विघटित होनेवाली कम्युनिस्ट क़बायली व्यवस्था की रीति-रिवाजों के अन्तर्गत, स्काटलैंड के केल्टिक क़बीलों में लालन-पालन हुआ था। परन्तु ओवेन इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहते कि इन लोगों ने उनके प्रति अधिक समझदारी का परिचय दिया। दूसरे, आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत निचली मंज़िल में रहनेवाले समाज के लिए उन कार्यभारों तथा टकरावों को हल करना ऐतिहासिक रूप से असम्भव है जो विकास की कहीं ऊंची मंज़िल में खड़े समाज में उत्पन्न हुए हैं और जो केवल वहीं उत्पन्न हो सकते थे। माल उत्पादन तथा निजी विनिमय के प्रकट होने से पहले उत्पन्न होनेवाले सारे क़बायली सामुदायिक रूपों तथा भावी समाजवादी समाज में केवल यही समानता है कि कतिपय वस्तुएं, उत्पादन के साधन सामुदायिक सम्पत्ति होते हैं और कतिपय समूह उनका मिलकर उपयोग करते हैं। परन्तु अकेले इस एक समान गुण में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह निचले सामाजिक रूप को भावी समाजवादी रूप में, पूंजीवादी समाज की इस अन्तिम उपज में विकसित कर सकें जिसे वह स्वयं पैदा करता है। प्रत्येक सम्बद्ध आर्थिक प्रणाली को अपने कार्यभारों को, अपने गर्भ से जन्मे कार्यभारों को स्वयं हल करना होगा, और दूसरे, सर्वथा विजातीय प्रणाली के समक्ष खड़े कार्यभारों को हल करने का यत्न करना सरासर मूर्खतापूर्ण होगा। यह चीज़ रूसी समुदाय पर उतनी ही लागू होती है जितनी वह दक्षिण स्लाव zadruga, भारतीय क़बायली समुदाय अथवा जांगल युग या बर्बर युग की किसी अवधि के सामाजिक

रूप पर लागू होती है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उत्पादन साधनों पर सामूहिक स्वामित्व है।

परन्तु यह सम्भव ही नहीं, वरन् अपरिहार्य भी है कि एक बार सर्वहारा विजयी हो जाये और उत्पादन साधनों पर पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों में सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित हो जाये तो वे देश, जो अभी-अभी पूंजीवादी उत्पादन आरम्भ कर सके हैं और जहां कबायली संस्थान तथा उनके अवशेष अब भी अक्षुण्ण हैं, सामुदायिक स्वामित्व के इन अवशेषों को तथा सम्बन्धित लोक रीति-रिवाजों को समाजवादी समाज की ओर अपनी अग्रगति की अवधि को काफ़ी घटाने तथा अपने को उन मुसीबतों और संघर्षों से, जिनके बीच से हम पश्चिमी यूरोप के लोगों को अपना रास्ता बनाना पड़ा है, बचाने के लिए सशक्त साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। परन्तु इसकी अनिवार्य शर्त है अब तक के पूंजीवादी पश्चिम का उदाहरण तथा सक्रिय समर्थन। जब अपनी जन्मभूमि तथा उन देशों में, जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनी भरपूर जवानी में है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अन्त कर दिया जायेगा, जब पिछड़े हुए देश इस उदाहरण से देख लेंगे कि “यह किस तरह होता है”, आधुनिक उद्योग की उत्पादक शक्तियों को समग्र समाज के लिए सामाजिक सम्पत्ति के रूप में काम करने के लिए कैसे विवश किया जाता है, केवल तभी पिछड़े हुए देश विकास की यह लघुकृत प्रक्रिया अपना सकेंगे। परन्तु तब उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। यह बात केवल रूस पर ही नहीं, वरन् उन तमाम देशों पर भी लागू होती है जो विकास की पूंजीवाद से पहले की मंज़िल में हैं। फिर भी यह काम रूस में अपेक्षाकृत अधिक सुगमता के साथ किया जा सकेगा जहां देश की आबादी का एक भाग पूंजीवादी विकास के बौद्धिक फलों को आत्मसात कर चुका है, जिससे क्रान्ति के दौरान उसका सामाजिक रूपान्तरण पश्चिम के साथ-साथ सम्पन्न करना सम्भव होगा।

यह सब मार्क्स और मैंने ‘कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र’ के प्लेखानोव द्वारा अनूदित रूसी संस्करण की भूमिका में २१ जनवरी १८८२ को ही कह दिया था। हमने कहा था—

“परन्तु रूस में हम तेज़ी से विकसित हो रही पूंजीवादी टगी तथा पूंजीवादी भू-सम्पत्ति के, जिसने अभी-अभी विकसित होना आरम्भ किया है, विलकुल सामने आधी से अधिक ऐसी भूमि पाते हैं जिसपर किसानों का समान स्वामित्व है। अब सवाल यह है—क्या रूसी ओबश्चिना, ” (समुदाय — सं०) “ जो बुरी तरह अन्तर्ध्वस्त होते हुए भी भूमि के आदिकालीन समान स्वामित्व का एक रूप है, सीधे कम्युनिस्ट ढंग

के समान स्वामित्व के उच्चतर रूप में प्रवेश कर सकती है? या इसके विपरीत उसे भी क्या विघटन की उसी प्रक्रिया के बीच से गुजरना पड़ेगा जो पश्चिम का ऐतिहासिक विकासक्रम बनी है? इस समय इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर यह है—यदि रूसी क्रान्ति पश्चिम में सर्वहारा क्रान्ति के लिए इस तरह घंटी बजाने लगे कि दोनों एक दूसरे के परिपूरक बन सकें तो भूमि का वर्तमान रूसी समान स्वामित्व कम्युनिस्ट विकास के लिए प्रस्थान-बिन्दु बन सकता है।”*

परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि रूसी सामुदायिक स्वामित्व के जिस काफ़ी विघटन का यहां उल्लेख किया गया था, वह तब से और आगे बढ़ चुका है। क्रीमियाई युद्ध⁸³ की पराजयों ने रूस के द्रुत औद्योगिक विकास की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया। प्राथमिक आवश्यकता रेलों की थी जिनका बड़े पैमाने के देशी उद्योग के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता। बड़े पैमाने के उद्योग की प्रारम्भिक शर्त किसानों की तथाकथित मुक्ति थी; इससे रूस में पूंजीवादी युग और साथ ही भूमि के सामुदायिक स्वामित्व के द्रुत क्षय का युग भी आरम्भ हुआ। किसान एक ओर विमोचन राशियों और पहले से बड़े करों के बोझ में इतने दबे हुए थे और दूसरी ओर उनके पास पहले से इतनी खराब और कम ज़मीन रहने दी गयी कि उन्होंने अपने को लाज़िमी तौर पर मूदख़ोरों के चंगुल में पाया जिनमें से अधिकांश ग्राम समुदाय के अमीर बन गये सदस्य थे। पहले के बहुत-से दूर-दराज़ इलाक़ों के लिए रेलों ने उनके अनाज के लिए मंडियों तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। परन्तु ये ही रेलें बड़े पैमाने के उद्योग के सस्ते उत्पाद भी लाने लगीं, और इन्होंने किसानों के घरेलू उद्योगों को अपदस्त कर दिया जो उस समय तक वे ही चीज़ें अंशतः अपनी खपत तथा अंशतः बिक्री के लिए उत्पादित कर रहे थे। प्राचीन काल से चले आ रहे आर्थिक सम्बन्ध विशृंखलित हो गये, सम्बन्ध-सम्पर्कों का विघटन शुरू हो गया, जो विनिमयहीन अर्थव्यवस्था से मुद्रा अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने पर हमेशा होता है, समुदाय के सदस्यों के बीच सम्पत्ति-सम्बन्धी बहुत बड़े विभेद प्रकट होने लगे—ग़रीब अमीरों के चंगुल में फंस गये। संक्षेप में, जिस प्रक्रिया ने सोलोन के ज़माने से कुछ ही समय पहले एथेन्स में मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के माध्यम से गोत्रों का विघटन किया था**, उसने ही रूसी समुदाय का विघटन आरम्भ किया। यह

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खंड २, भाग १।—सं०

** फ्रे० एंगेल्स, 'परिवार, निजी सम्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति'।—सं०

सच है कि सोलोन ने निजी स्वामित्व के अभी अपरिपक्व अधिकार में क्रान्तिकारी ढंग से प्रवेश करते हुए कर्जदारों का कर्जा महज मसूख करके उन्हें बंधनों से मुक्त कर दिया था। परन्तु वह प्राचीन एथेन्सीय गोत्रों को पुनरुज्जीवित नहीं कर पाया था और इसी तरह दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो रूसी समुदाय के विघटन के एक निश्चित चरम बिन्दु पर पहुंच चुकने के बाद उसे पुनरुज्जीवित करने में सक्षम हो। इसके अलावा रूसी सरकार ने समुदाय के सदस्यों के बीच १२ वर्ष में एकाधिक बार जमीन के पुनर्वितरण पर पाबन्दी लगा दी है ताकि जमीन का पुनर्वितरण करने की किसान की आदत खत्म की जा सके तथा उसे यह अनुभव कराया जाये कि वह अपने हिस्से में आयी जमीन का मालिक है।

मार्क्स ने रूस को १८७७ में भेजी गयी एक चिट्ठी में इसी भावना में अपनी बात कही थी। * श्री जुकोव्स्की नामक एक सज्जन ने—यह वही व्यक्ति हैं जिनके हस्ताक्षर राजकीय बैंक के कोषाध्यक्ष के रूप में इस समय रूसी बैंक नोटों पर अंकित रहते हैं—‘वेस्तनिक येब्रोपी’ (यूरोप का सन्देशवाहक) में मार्क्स के बारे में कुछ प्रकाशित किया था जिसका एक अन्य लेखक ने ** ‘ओतेचेस्त्वेन्निये ज़पीस्की’ में उत्तर दिया था।⁸⁴ लेखक के कथन में कुछ भूल-सुधार के रूप में मार्क्स ने इस पत्र के सम्पादक को एक चिट्ठी लिखी जो फ्रांसीसी मूल की पांडुलिपि की प्रतियों के रूप में रूस में दीर्घकाल तक प्रसारित होती रही और फिर १८८६ में जेनेवा में ‘वेस्तनिक नरोदोइ वोलि’ (जन-इच्छा का सन्देशवाहक) में तथा आगे चलकर वह खुद रूस में प्रकाशित हुई।⁸⁵ मार्क्स द्वारा लिखी गयी तमाम चीजों की तरह इस चिट्ठी ने भी रूसी क्षेत्रों का बहुत ध्यान आकृष्ट किया तथा उसकी सर्वथा विविध रूप में व्याख्या होती रही। यही कारण है कि मैं उसका यहां सार दे रहा हूं।

मार्क्स अपनी बात उन विचारों का खंडन करके शुरू करते हैं जो ‘ओतेचेस्त्वेन्निये ज़पीस्की’ ने उनके बताये थे मानो रूसी उदारतावादियों की ही तरह मार्क्स भी यह विश्वास करते हों कि रूस का सबसे तात्कालिक कार्य कृषक सामुदायिक स्वामित्व को नष्ट करना तथा पूंजीवाद में कूद पड़ना है। उन्होंने ‘पूँजी’ के प्रथम संस्करण के परिशिष्ट में हर्जेन के विषय में सरसरी तौर पर

* कार्ल मार्क्स, ‘ओतेचेस्त्वेन्निये ज़पीस्की’ (पितृभूमि की टिप्पणियां) के सम्पादकमंडल के नाम पत्र।—सं०

** न० क० मिखाइलोव्स्की।—सं०

जो कहा था, उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। उन्होंने जो कहा था, वह यह है, “यदि यूरोपीय महाद्वीप में पूंजीवादी उत्पादन का प्रभाव, जो मानवजाति को ध्वस्त करता है... इसी तरह विकसित होता गया जिस तरह वह अब तक होता आया है, और उसके साथ-साथ राष्ट्रीय सैनिक दलों, राष्ट्रीय ऋणों तथा युद्ध-कला के परिष्करण, आदि में प्रतियोगिता तीक्ष्ण होती चली गयी तो कोई और कल्मिक रक्त के अनिवार्य समावेश की सहायता से यूरोप का कायाकल्प अन्ततः सर्वथा अवश्यम्भावी हो जायेगा, जिसकी अर्द्धरूसी परन्तु पूरे मास्कोवासी हर्जेन इतने जोश से भविष्यवाणी करते आये हैं (प्रसंगतः ध्यान रहे, इस उपन्यासकार ने रूस में नहीं, वरन् प्रशियाई Regierungsrat हक्स्टहाउजेन की कृतियों में “रूसी कम्युनिज्म” के बारे में अपने आविष्कार किये थे) (‘पूँजी’, खंड १, प्रथम जर्मन संस्करण, पृष्ठ ७६३)। मार्क्स आगे कहते हैं, “अपने देश के लिए विकास का ऐसा मार्ग, जो उससे भिन्न हो जिस पर पश्चिमी यूरोप चल रहा है, ढूंढ़ने के रूसी जनता के” (आगे का उद्धरण मूल में रूसी भाषा में दिया गया है) “प्रयासों के बारे में इस वाक्यांश को मेरे विचारों की कदापि कुंजी नहीं माना जा सकता”, आदि। “‘पूँजी’ के द्वितीय जर्मन संस्करण के परिशिष्ट में मैं ‘महान रूसी विद्वान तथा आलोचक’” (वेनिशेन्स्की)* “की चर्चा गहन आदर के साथ करता हूँ जिसके वह पात्र हैं। अपने उल्लेखनीय लेखों में इस विद्वान ने इस प्रश्न का विवेचन किया है कि क्या रूस को, जैसा कि उसके उदारतावादी अर्थशास्त्री चाहते हैं, ग्राम समुदाय को नष्ट कर काम शुरू करना चाहिए ताकि वह पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवेश कर सके अथवा क्या वह अपनी ऐतिहासिक अवस्थाओं का विकास करते हुए इस व्यवस्था के फलों को उसकी यातनाएँ झेले बिना प्राप्त कर सकता है? वह दूसरी स्थिति के पक्ष में अपना विचार प्रकट करते हैं।”

“संक्षेप में, चूँकि मुझे ‘कोई चीज़ अटकलवाजी पर’ छोड़ना पसन्द नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के कहूँगा। रूस के आर्थिक विकास के विषय में जानकारी भरा निर्णय दे सकने के लिए मैंने रूसी सीखी थी तथा कई वर्षों तक मामले से सम्बन्धित सरकारी तथा अन्य प्रकाशनों का अध्ययन किया। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि रूस उस मार्ग पर अग्रसर होता रहा जिस पर वह १८६१ से चलता आया है तो वह ऐसा सर्वोत्तम अवसर खो बैठेगा

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।-सं०

जैसा इतिहास ने किसी जनता के समक्ष इससे पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया, और उसे पूंजीवादी व्यवस्था के सारे घातक उतार-चढ़ावों के बीच से गुजरना होगा।” *

मार्क्स आगे अपने आलोचक की चन्द और भूलें सुधारते हैं; हमारे प्रश्न से प्रसंग रखनेवाला एकमात्र वाक्यांश इस प्रकार है—

“तो मेरे आलोचक इस ऐतिहासिक रेखाचित्र को रूस पर लागू करने के लिए उसका क्या उपयोग कर सके हैं?” (तात्पर्य पूंजी के आदिम संचय से है) “केवल यह—यदि रूस में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों की तरह पूंजीवादी राष्ट्र बनने की प्रवृत्ति है—और पिछले चन्द वर्षों में उसने यह बनने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया है—तो वह अपने किसानों के अच्छे-खासे हिस्से को सर्वहारा में परिणत न किये जाने पर इस कार्य में विफल हो जायेगा; एक बार वह इसे कर लेता है और पूंजीवादी व्यवस्था की गोद में पहुँच जाता है तो वह सारे अन्य काफ़िर जनगण की तरह उसके अटल नियमों के अधीन हो जायेगा। वस।”

यह मार्क्स ने १८७७ में लिखा था। उस समय रूस में दो सरकारें थीं—ज़ार की सरकार तथा आतंकवादी षड्यंत्रकारियों की गुप्त कार्यवाही समिति⁸⁶ की सरकार। इस दूसरी, गुप्त सरकार की सत्ता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ज़ारशाही के तख्ते का उलटा जाना आसन्न प्रतीत होता था; रूस की क्रान्ति सारे यूरोपीय प्रतिक्रियावाद को अपने सबसे ठोस अवलम्ब से, अपनी विशाल आरक्षित सेना से वंचित करने जा रही थी और इस तरह पश्चिम में राजनीतिक आन्दोलन के लिए संघर्ष में कहीं अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करके उसे एक और सशक्त प्रेरणा देने जा रही थी। इसलिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं है कि मार्क्स ने अपने पत्र में रूसियों को पूंजीवाद में छलांग लगाने में बहुत जल्दबाज़ी न करने की सलाह दी।

रूस में कोई क्रान्ति नहीं हुई है। ज़ारशाही ने आतंकवाद पर विजय प्राप्त कर ली है जिसने फ़िलहाल तमाम “व्यवस्थाप्रेमी” सम्पत्तिधारी वर्गों को ज़ारशाही की बांहों में पहुँचा दिया है। मार्क्स के पत्र के बाद के १७ वर्षों में रूस में पूंजीवाद के विकास तथा ग्राम समुदाय के विघटन दोनों ने भीम डग भरे हैं। तो फिर आज, १८९४ में स्थिति क्या है?

चूँकि क्रीमियाई युद्ध की पराजयों तथा सम्राट निकोलाई प्रथम की आत्महत्या के बाद पुराना ज़ारशाही निरंकुशतावाद अपरिवर्तित रहा, केवल एक ही रास्ता

* शब्दों पर जोर एंगेल्स ने दिया था।—सं०

बचा हुआ था—पूँजीवादी उद्योग में द्रुततम गति से प्रवेश। साम्राज्य के विशाल विस्तार तथा सैनिक कार्रवाइयों के केन्द्र तक लम्बे अभियानों ने सेना को तहस-नहस कर दिया था ; इन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए सामरिक रेल लाइनों का जाल बिछाया जाना आवश्यक था। परन्तु रेल लाइनों के निर्माण का अर्थ है पूँजीवादी उद्योग की स्थापना तथा आदिम कृषि का क्रान्तिकरण। एक ओर सबसे दूर-दराज हिस्सों तक की कृषि उपज का विश्व मंडी से सीधा सम्पर्क हो जाता है ; दूसरी ओर रेल लाइनों के व्यापक जाल का निर्माण तथा उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक अपने पास रेल की पटरियाँ, इंजन, डिब्बे, आदि मुहैया करनेवाला देश का अपना उद्योग न हो। परन्तु बड़े पैमाने के उद्योग की एक शाखा को पूरी प्रणाली चालू किये बिना निर्मित करना असम्भव है ; अपेक्षाकृत आधुनिक कपड़ा उद्योग को, जिसकी जड़ें मास्को तथा व्लादीमिर गुबेर्नियाओं और वाल्टिक क्षेत्र में पहले ही जम चुकी थीं, नयी उत्प्रेरणा मिली। रेल लाइनों और कारखानों के निर्माण के बाद विद्यमान बैंकों का विस्तार हुआ तथा नये बैंकों की स्थापना हुई ; किसानों की भू-दासत्व से मुक्ति के फलस्वरूप स्थानान्तरण की स्वतंत्रता ने जन्म लिया, और यह अपेक्षित ही था कि इन किसानों का एक बहुत बड़ा भाग भू-स्वामित्व से भी मुक्त हो। इस तरह रूस में उत्पादन की पूँजीवादी पद्धति की नींव अल्पकाल में ही पड़ गयी। परन्तु इसके साथ ही रूसी ग्राम समुदाय की जड़ों पर भी कुठाराघात हुआ।

अब इसका दुखड़ा लेकर बैठने से कोई लाभ नहीं है। यदि क्रीमियाई युद्ध के बाद अभिजाततंत्र तथा नौकरशाही के प्रत्यक्ष संसदीय शासन ने ज़ारशाही निरंकुशतावाद का स्थान ले लिया होता तो यह प्रक्रिया शायद धीमी हो गयी होती ; परन्तु पनपता पूँजीपति वर्ग यदि सत्तारूढ़ हुआ होता तो यह प्रक्रिया यत्नीन तेज़ होती। विद्यमान परिस्थितियों में कोई और रास्ता नहीं था। फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य⁸⁷ और इंग्लैंड में फूलते-फलते पूँजीवादी उद्योग के रहते रूस से निश्चय ही यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वह अपने ग्राम समुदाय के आधार पर सीधे राजकीय-समाजवादी प्रयोग के मैदान में कूद पड़े। कुछ न कुछ होना चाहिए था। और परिस्थितियों को देखते हुए जो सम्भव था, वह हुआ भी ; जैसा कि माल उत्पादक देशों में हमेशा हुआ करता है, लोग अधिकतर अर्द्धचेतन रूप से अथवा पूर्णतः अचेत रूप से काम करते रहे, वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि क्या हो रहा है।

परन्तु इस बीच एक नयी अवधि का, ऊपर से क्रान्तियों की अवधि का आगमन हुआ, जिसका सूत्रपात जर्मनी ने किया था, और इसके साथ यूरोप के समस्त देशों में समाजवाद के द्रुत विकास की अवधि आयी। रूस ने इस आम आन्दोलन में भाग लिया। जैसा कि अपेक्षित था, उसके आन्दोलन ने ज़ारशाही निरंकुशतावाद पर प्रहार तथा राष्ट्र के बौद्धिक एवं राजनीतिक विकास की स्वतंत्रता की प्राप्ति का रूप ग्रहण किया। ग्राम समुदाय की, जिसके गर्भ में से सामाजिक पुनर्जन्म होना था, जादुई शक्ति में आस्था ने, — जैसा कि हम देख चुके हैं, स्वयं चेरनिशेव्स्की इस आस्था से स्वतंत्र नहीं थे, — इस आस्था ने वीर रूसी अग्रणी योद्धाओं को जगाने तथा अनुप्राणित करने में अपनी भूमिका अदा की। इन लोगों के साथ, जो कुछ सौ से ज्यादा नहीं थे, बल्कि जिन्होंने अपने साहस तथा आत्मा-त्याग के बल पर ज़ारशाही निरंकुशतावाद को ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां उसे आत्म-समर्पण की सम्भावना तथा उसकी शर्तों पर विचार करना पड़ा, इन लोगों के इस विश्वास से हमारा कोई झगड़ा नहीं है कि उनकी अपनी रूसी जनता गोया सामाजिक क्रान्ति के लिए पैदा हुई है। परन्तु हमारे लिए यकीनन यह जरूरी नहीं है कि हम उनकी भ्रान्तियों में सहभागी नवें। विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे लोगों का वक्त हमेशा-हमेशा के लिए लद चुका है।

जब यह संघर्ष चल रहा था, रूस में पूंजीवाद साहसपूर्वक प्रहार कर रहा था और उस लक्ष्य के समीपतर होता जा रहा था जिसे आतंकवादी पूरा नहीं कर सके थे। यह लक्ष्य था ज़ारशाही को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना।

ज़ारशाही को धन की जरूरत थी। राज-दरबार के ऐश्वर्य-वैभव, नौकरशाही और सर्वोपरि अपनी सेना तथा घूसखोरी पर आधारित अपनी विदेश नीति के लिए ही नहीं, वरन् विशेष रूप से अपनी दयनीय वित्तीय प्रणाली तथा रेल निर्माण के क्षेत्र में तदनु रूप बेतुकी नीति के लिए भी उसे धन की दरकार थी। बाह्य स्रोत ज़ार के सारे घाटों की पूर्ति करने के लिए अब या तो इच्छुक नहीं रह गये थे अथवा इसके लिए अक्षम थे। सहायता की अब देश में ही तलाश की जानी थी। रेलों के शेयरों का एक हिस्सा अब देश के अन्दर फैलाना और कुछ ऋण वहीं हासिल करना जरूरी हो गया था। रूसी पूंजीपति वर्ग की पहली विजय रेलवे कंसेशनों की प्राप्ति थी जिनके अन्तर्गत सारे भावी मुनाफ़े शेयर होल्डरों के पास जाने थे जबकि सारे भावी नुकसान राज्य को वहन करने थे। उसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए अनुदान तथा बोनस दिये जाने

लगे, देशी उद्योग के हितार्थ संरक्षण शुल्कों की व्यवस्था की गयी जिन्होंने बहुत-सी वस्तुओं का आयात प्रायः असम्भव बना दिया। रूसी राज्य की, जो अपरिमित ऋणों से दबा हुआ था तथा जिसकी विदेशों में साख प्रायः चौपट हो चुकी थी देशी उद्योग के कृत्रिम प्रसार में प्रत्यक्ष वित्तीय दिलचस्पी थी। विदेशी ऋणों का व्याज चुकाने के लिए उसे सोने की बराबर आवश्यकता रहती है। परन्तु रूस में स्वर्ण मुद्रा है ही नहीं, केवल कागजी मुद्रा है। सीमाशुल्क राजस्व लागू कर सोने की एक खास मात्रा की वसूली से कुछ सोना प्राप्त होता है। प्रसंगतः इसमें इन शुल्कों में ५० प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। परन्तु अधिकांश सोना तो रूसी कच्चे माल का निर्यात विदेशी औद्योगिक उत्पादों के आयात से अधिक होने से ही प्राप्त होना चाहिए; रूसी सरकार विदेशी हुंडियां खरीदकर और उनकी राशि के बराबर कागजी मुद्रा देकर सोना प्राप्त करती है। इसलिए यदि सरकार अपने विदेशी ऋणों के व्याज की अदायगी के लिए और ऋणों के वास्ते विदेशों से नये करार नहीं करना चाहती तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि रूसी उद्योग इतनी तेजी से विकसित हो कि वह मांगी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसीलिए यह मांग की जाती है कि रूस विदेशों से स्वतंत्र हो, आत्म-निर्भर औद्योगिक देश बने; इसीलिए सरकार रूस के पूंजीवादी विकास को चन्द वर्षों के अन्दर उच्चतम शिखर पर पहुँचाने के लिए इतनी व्यग्रतापूर्वक चेष्टा कर रही है। जब तक यही नहीं होता, तब तक दो ही रास्ते रहेंगे—या तो राजकीय बैंक और राजकीय कोष द्वारा जमा की गयी सामरिक स्वर्ण निधि का उपयोग किया जाये अथवा राज्य का दीवाला निकलने की स्थिति का सामना किया जाये। दोनों में से किसी भी रास्ते का अर्थ होगा रूस की विदेश नीति का अन्त।

एक बात साफ़ है—इन परिस्थितियों में राज्य किशोर रूसी पूंजीपति वर्ग की मजबूत जकड़ में है। राज्य को सारे महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों में उसकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा। वह जार तथा उसके अधिकारियों के निरंकुशतावादी राजतंत्र को यदि अब भी सहन करता है तो केवल इसलिए कि यह राजतंत्र अपनी नौकरशाही के अष्टाचार से नरम बनने के अलावा उसे किसी भी प्रकार के उन परिवर्तनों से ज्यादा गारंटियां मुहैया करता है, जो भले ही पूंजीवादी-उदारतावादी भावना के हों परन्तु रूस की विद्यमान परिस्थितियों में जिनके परिणामों के बारे में कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसलिए रूस का औद्योगिक पूंजीवादी राज्य में यह त्वरित रूपान्तरण, उम्मी

कृषक समुदाय के एक बड़े भाग का सर्वहाराकरण तथा पुराने कम्युनिस्ट समुदाय का क्षय होता जा रहा है।

मैं यह निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूँ कि यह समुदाय अब भी इतना अक्षुण्ण है या नहीं कि वह समय आने पर तथा पश्चिमी यूरोप में क्रान्ति के साथ मिलकर कम्युनिस्ट विकास का वह प्रस्थान-बिन्दु बनेगा जिसकी मार्क्स और मैं १८८२ में भी आशा कर रहे थे। परन्तु इतना तो निश्चित है—यदि इस समुदाय में से कुछ बचाया जाना है तो पहली आवश्यकता यह है कि ज़ारशाही निरंकुशतावाद का तख़्ता उलटा जाये, रूस में क्रान्ति हो। रूसी क्रान्ति राष्ट्र के अधिकांश को, किसानों को गांवों में, जो उनका *mir*, उनका विश्व है, उनके अलग-अलग से केवल बाहर ही नहीं निकालेगी; वह किसानों को केवल उस बड़े रंगमंच पर ही नहीं पहुंचायेगी जहां वे बाहरी दुनिया को, और इसके साथ अपने को, अपनी हालत को, अपनी वर्तमान दुर्दशा से बचने के साधनों को पहचानने लगेंगे—रूसी क्रान्ति पश्चिम के मजदूर आन्दोलन को भी नया संवेग प्रदान करेगी, उसके लिए संघर्ष की नयी तथा बेहतर अवस्थाएं पैदा करेगी तथा इस तरह आधुनिक औद्योगिक सर्वहारा की विजय को आगे बढ़ायेगी, उस विजय की ओर आगे बढ़ायेगी जिसके बिना समकालीन रूस समुदाय अथवा पूंजीवाद में से किसी के भी आधार पर समाज का समाजवादी रूपान्तरण हासिल नहीं कर सकता।

१८९४ के पूर्वार्द्ध में लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

फ्रेडरिक एंगेल्स की पुस्तक

«Internationales aus dem «Volksstaat»»

(1871-1875), बर्लिन, १८९४ में प्रकाशित।

बकूनिन की 'राज्यत्व तथा अराजकता' पुस्तक पर टिप्पणियों में से ⁸⁵

०

“उदाहरण के लिए, “крестьянская чернь” (साधारण किसानों, किसानों की भीड़) जिसके प्रति—जैसा कि सुविदित है—मार्क्सवादियों का खूब सद्भावनापूर्ण नहीं है और जिन पर—जो संस्कृति के निम्नतम स्तर पर हैं—सम्भवतः शहरों तथा कारखानों के सर्वहारा राज करेंगे।”

इसका मतलब यह है कि जहां कहीं किसानों के विशाल जनसमुदाय का निजी सम्पत्तिधारी के रूप में अस्तित्व है, जहां उसकी न्यूनाधिक रूप में बहुसंख्या है, जैसा कि पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप के तमाम देशों में है, जहां उसका लोप नहीं हुआ है, जहां, इंग्लैंड की तरह, उसका स्थान खेतिहर मजदूर ने नहीं लिया है, वहां ये चीजें हो सकती हैं—या तो वह मजदूरों की हर क्रान्ति को न होने दे और उसे ध्वस्त कर दे जैसा कि उसने अब तक फ्रांस में किया, अथवा सर्वहारा को (क्योंकि कृषक-स्वामी का स्थान सर्वहारा में नहीं है और जहां उसकी स्थिति उसे मजदूरन सर्वहारा के बीच पहुंचाती है, वहां भी वह यह सोचता है कि उसका स्थान वहां नहीं है) शासन करते समय ऐसे पग उठाने चाहिए जो किसान की हालत में प्रत्यक्ष सुधार लायेंगे तथा जो उसे क्रान्ति के पक्ष में ले आयेंगे। इन पगों को आरम्भ से ही निजी भू-स्वामित्व से सामूहिक भू-स्वामित्व में संक्रमण सुगम बनाना चाहिए ताकि किसान स्वयं आर्थिक साधनों के माध्यम से इसके पक्ष में आये; परन्तु यह सावधानी बरती जानी चाहिए कि उसे उदाहरण के लिए उत्तराधिकार तथा उसकी सम्पत्ति पर अधिकार के उन्मूलन जैसे पगों की घोषणा द्वारा विरोधी न बनाया जाये। इस तरह के पग केवल तभी उठाये जा सकते

हैं जब पूंजीपति-पट्टेदार ने किसान को अपदस्थ कर दिया हो और जहां वास्तविक काश्तकार उतना ही सर्वहारा, उजरती मजदूर हो जितना कि शहरी मजदूर और इसलिए जिसके उसके साथ एक जैसे प्रत्यक्ष हित हों, परोक्ष नहीं। बड़ी जागीरें सीधे किसानों के हवाले करके और इस तरह छोटे टुकड़ों का विस्तार करके भूमिधारण का दृढीकरण नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि बकूनिन के क्रान्तिकारी कार्यक्रम में है।

“अथवा हम यदि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करें तो हम यह मान सकते हैं कि जर्मनों के लिए स्लाव लोग उसी कारण जर्मन सर्वहारा की दासत्वपूर्ण अधीनता में रहेंगे जिस कारण जर्मन सर्वहारा अपने पूंजीपति वर्ग की दासत्वपूर्ण अधीनता में है” (पृष्ठ २७८)।

स्कूली बच्चों जैसी फ़िज़ूल की बात! आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक क्रान्ति आर्थिक विकास की निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ी हुई होती है; ये अवस्थाएं इस सामाजिक क्रान्ति की पूर्वावश्यकताएं होती हैं। इसलिए यह केवल वहीं सम्भव है जहां पूंजीवादी उत्पादन के साथ-साथ औद्योगिक सर्वहारा जनता का कम से कम काफ़ी बड़ा भाग हो। यदि वह विजय का मौक़ा हासिल करना चाहता है तो यह ज़रूरी है कि किसानों के लिए *mutatis mutandis** प्रत्यक्षतः कम से कम उतना ज़रूर करे जितना फ़्रांसीसी पूंजीपति वर्ग ने अपनी क्रान्ति के दौरान उस समय विद्यमान फ़्रांसीसी किसानों के लिए किया था। क्या कहने इस विचार के कि मजदूरों के शासन में खेतिहर श्रम का उत्पीड़न शामिल है! परन्तु ठीक इसी में बकूनिन का अन्तःतम विचार प्रकट होता है। उन्हें सामाजिक क्रान्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वह उसकी केवल राजनीतिक वाक्यावली जानते हैं। उसकी आर्थिक अवस्थाओं का उनसे कोई मतलब नहीं है। चूँकि पिछले तमाम आर्थिक रूपों में—वे चाहे विकसित रहे हों या नहीं—श्रमिक का दासकरण शामिल है (चाहे वह उजरती मजदूर, किसान, आदि के रूप में हो), इसलिए उनका विश्वास है कि इन तमाम रूपों के अन्तर्गत आमूल परिवर्तनवादी क्रान्ति सम्भव है। वह और आगे बढ़ते हैं। वह चाहते हैं कि यूरोपीय सामाजिक क्रान्ति, जिसका आर्थिक आधार पूंजीवादी उत्पादन है, की नींव रूसी या स्लाव कृषक और मवेशी

पालक जातियों के स्तर पर रखी जाये और उसे इस स्तर के ऊपर नहीं होना चाहिए ; वह इसे यह अनुभव करते हुए भी चाहते हैं कि जहाजरानी भाइयों में अन्तर पैदा कर देती है, परन्तु केवल जहाजरानी, क्योंकि यह ऐसा अन्तर है जिसे तमाम राजनीतिज्ञ जानते हैं ! उनकी सामाजिक क्रान्ति का आधार आर्थिक अवस्थाएं नहीं, इच्छा है।

मार्क्स द्वारा १८७४ में तथा १८७५ के आरम्भ में लिखित।

अंग्रेजी से अनूदित।

सबसे पहले 'मार्क्सवाद का वृत्तान्त' पत्रिका में (अंक ११, १९२६) प्रकाशित।

चिट्ठी-पत्र

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र

हैनोवर में

लन्दन, २३ फरवरी १८६५

प्रिय मित्र,

मुझे आपकी चिट्ठी, जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, कल ही मिली। अब मैं आपके पृथक-पृथक मुद्दों के उत्तर दूंगा।

सबसे पहले मैं लासाल के प्रति अपने रुख का संक्षेप में वर्णन करूंगा। जब तक वह प्रचार में जुटे रहे, हमारे बीच सम्बन्ध टूटे रहे क्योंकि: १) उनकी आत्म-प्रशंसा की प्रवृत्ति से शेखीबाजी टपकती है, जिसमें उन्होंने मेरी तथा दूसरे लोगों की रचनाओं से अत्यन्त निर्लज्जतापूर्वक की गयी साहित्यिक चोरी जोड़ दी है; २) मैंने उनकी राजनीतिक कार्यनीति की कड़ी निन्दा की; ३) उनके प्रचार आरम्भ किये जाने से पहले ही मैंने उन्हें यहां लन्दन में पूरी तरह समझाया तथा उनके सामने “सिद्ध किया था” कि “प्रशा राज्य” द्वारा प्रत्यक्ष समाजवादी हस्तक्षेप की बात वकवास है। उन्होंने मुझे भेजी गयी अपनी चिट्ठियों में (१८४८ से १८६३ तक) और मेरे साथ मुलाकातों के दौरान अपने को हमेशा पार्टी का समर्थक बताया जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा था। ज्यों ही उन्हें लन्दन में (१८६२ के अन्त में) यह यकीन हो गया कि वह मेरे साथ चालबाजी नहीं चल सकते, उन्होंने “मजदूर अधिनायक” के रूप में मेरे तथा पुरानी पार्टी के विरुद्ध मैदान में उतरने का फ़ैसला कर दिया। इन तमाम बातों के बावजूद प्रचारक के रूप में मैंने उनकी सेवाओं को मान्यता दी हालांकि उनके अल्पकालिक जीवनक्रम के अन्त में उनका प्रचार भी मुझे अधिकाधिक उभयार्थ रूप धारण

करता प्रतीत हुआ। उनकी सहसा मृत्यु, पुरानी दोस्ती, काउंटेस हात्सफ़ेल्ड की विलापपूर्ण चिट्ठियां, पूंजीवादी अखबारों की एक ऐसे व्यक्ति के प्रति कायरतापूर्ण उद्दंडता पर रोष जिससे वे उसके जीवित रहते इतना डरते थे—इन सब चीजों ने मुझे उस मनहूस ब्लॉड* के विरुद्ध एक छोटा-सा वक्तव्य प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया जिसमें वैसे लासाल के कार्यकलाप के सार की चर्चा नहीं की गयी थी। (हात्सफ़ेल्ड ने यह वक्तव्य «Nordstern»⁸⁹ को भेज दिया था)। इन्हीं कारणों से तथा ऐसे तत्वों को, जो मुझे खतरनाक लगे, हटाने की आशा में एंगेल्स और मैंने «Social-Demokrat»⁹⁰ में लिखने का फ़ैसला किया (उसने सन्देश** का अनुवाद प्रकाशित किया है तथा उसके अनुरोध पर मैंने प्रूदों की मृत्यु के अवसर पर उनके बारे में एक लेख लिखा था***); और जब श्वीट्ज़र ने अपने सम्पादकमंडल का सन्तोषजनक कार्यक्रम भेज दिया, मैंने अपने नामों का लेखक के रूप में उपयोग करने की इजाजत दे दी। व० लीबकनेख्त की सम्पादकमंडल में अनौपचारिक सदस्य के रूप में उपस्थिति हमारे लिए एक और गारंटी थी। परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया—इसके प्रमाण हमारे हाथ लग गये—कि लासाल ने वस्तुतः पार्टी के साथ शहरी की थी। उन्होंने बिस्मार्क के साथ नियमित करार स्थापित कर लिया था (निस्सन्देह अपने लिए किसी तरह की गारंटियों के बिना)। सितम्बर १८६४ के अन्त में उन्हें हैम्बर्ग जाना था और वहां (उस सनकी श्राम्म और प्रशियाई पुलिस जासूस मार के साथ मिलकर) बिस्मार्क को श्लेज़िग-होल्स्टेइन का सम्मेलन करने, अर्थात् “मजदूरों”, आदि के नाम पर उसके सम्मेलन की घोषणा करने के लिए “विवश करना था” जिसके बदले बिस्मार्क ने सार्वजनिक मताधिकार और कुछ समाजवादी ढोंगवाजी करने का वचन दिया। यह अफ़सोस की बात है कि लासाल इस प्रहसनात्मक नाटक में अपनी भूमिका अन्त तक नहीं निभा सके! उससे वह घोर उपहासास्पद तथा मूर्ख दिखायी देते और इस तरह की कोशिशों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता!

लासाल इसलिए इस ढंग से भटक गये कि वह श्री माइकेल की तरह के “व्यावहारिक राजनीतिज्ञ” थे, अन्तर केवल यह था कि वह और बड़े सांघे

* कार्ल मार्क्स, ‘स्टूटगर्ट के «Beobachter» अखबार के सम्पादक के नाम’।—सं०

** देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

*** वही।—सं०

में ढले हुए थे तथा उनके और बड़े उद्देश्य थे। (प्रसंगतः, मैं माइकेल को बहुत पहले ही पर्याप्त रूप में पहचानते हुए उनके आचरण के बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि राष्ट्रीय संघ^१ ने एक छोटे हैनोवरियाई वकील को अपनी चारदीवारी के बाहर जर्मनी में अपनी आवाज सुनाने और “प्रशियाई” तत्त्वावधान में! “हैनोवरियाई” मिराबो की भूमिका अदा करते हुए अपनी बढ़ी हुई “वास्तविकता” को फिर अपनी हैनोवरियाई भूमि में प्रतिक्षिप्त कराने के लिए बहुत बढ़िया मौका दिया।) जिस तरह माइकेल और उसके मौजूदा दोस्त प्रशियाई प्रिंस रीजेंट द्वारा उद्धोषित “नये युग”^२ पर झपटे ताकि राष्ट्रीय संघ में शामिल हो सकें और “प्रशियाई शीर्ष भाग” में पहुंच सकें, जिस तरह इन लोगों ने सामान्यतया प्रशियाई तत्त्वावधान में अपने “नागरिक गौरव” का विकास किया, ठीक उसी तरह लासाल चाहते थे कि वह उकेर्माक के फ़िलिप द्वितीय के साथ सर्वहारा के मार्किंक्स पोजा की^३ तथा बिस्मार्क उनके तथा प्रशियाई ताज के बीच कुटनी की भूमिका अदा करे। उन्होंने केवल राष्ट्रीय संघ के सज्जनों की नक़ल की। परन्तु जहां इन लोगों ने मध्यम वर्ग के हितार्थ प्रशियाई “प्रतिक्रियावाद” से अपील की, वहां लासाल ने बिस्मार्क के साथ सर्वहारा के हितार्थ हाथ मिलाया। राष्ट्रीय संघ के इन सज्जनों के पास लासाल से ज्यादा औचित्य था क्योंकि जहां पूंजीपति वर्ग अपने बिल्कुल सामने के हित को “वास्तविकता” मानने का आदी है और जहां वस्तुतः इस वर्ग ने सर्वत्र सामन्तवाद तक से समझौतेबाज़ी की है, वहां अपने स्वरूप के ही कारण मजदूर वर्ग को सच्चा “क्रान्तिकारी” होना चाहिए।

लासाल जैसे खोखले नाटकीय पात्र के लिए (हां, उन्हें किसी पद, मेयर का ओहदा जैसी नगण्य चीजों से नहीं ललचाया जा सकता था) यह एक बहुत प्रलोभनकारी विचार था—फ़र्दीनांद लासाल द्वारा सीधे सर्वहारा की ओर से सम्पन्न एक कार्य! दरअसल वह इस प्रकार के कार्य के लिए अपेक्षित वास्तविक आर्थिक अवस्थाओं से इतने अनभिज्ञ थे कि वह अपनी आलोचना नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर जर्मन मजदूर भी घृणित “व्यावहारिक राजनीति” के कारण, जिसने जर्मन पूंजीपति वर्ग को १८४६—१८५६ की प्रतिक्रियावाद को सहन करने तथा जनता की जड़ता का साक्षी बनने के लिए प्रेरित किया था, इतने “हौसलापस्त” हो गये थे कि वे ऐसे नीमहकीम रक्षक का अभिनन्दन किये बिना नहीं रह सकते थे जिसने उन्हें एक ही छलांग में स्वर्ग पहुंचाने का वचन दिया।

खैर, बात का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया जाये। «*Social-Demokrat*» स्थापित हुआ ही था कि यह स्पष्ट हो गया कि वृद्धा हात्सफ़ेल्ड अन्ततः लासाल

की "वसीयत" को पूरा करना चाहती थी। वह (*«Kreuz-Zeitung»*⁹⁴ के) वागेनेर के जरिए बिस्मार्क के सम्पर्क में थी। उसने ग्राम जर्मन मजदूर संघ⁹⁵, *«Social-Demokrat»*, आदि को उसके हाथों में सौंप दिया। श्लेज़्विग-होल्स्टेइन के सम्मेलन और बिस्मार्क को सामान्यतः संरक्षक के रूप में मान्यता दिये जाने की घोषणा *«Social-Demokrat»* में की जानी थी। इस सारी खूबसूरत योजना पर इसलिए पानी फिर गया कि बर्लिन तथा *«Social-Demokrat»* में लीबकनेख्त मौजूद थे। यद्यपि एंगेल्स और मैं अखबार के सम्पादकमंडल से—उसकी लासालीय चाटुकारिता, उसकी समय-समय पर बिस्मार्क के साथ इश्कबाजी, आदि से—खुश नहीं थे, फिर भी फिलहाल सार्वजनिक रूप से अखबार का साथ देना निस्सन्देह ज्यादा महत्वपूर्ण था ताकि वृद्धा हात्सफ्रेल्ड की साजिशें विफल बनायी जा सकें तथा मजदूर पार्टी को पूरी तरह बदनाम न होने दिया जाये। इसलिए हमने वह किया जिसे *bonne mine à mauvais jeu** कहते हैं हालांकि निजी तौर पर हम *«Social-Demokrat»* को हमेशा लिखते रहे कि उसे बिस्मार्क का उतना ही विरोध करना चाहिए जितना वह प्रगतिवादियों⁹⁶ का विरोध करता है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के विरुद्ध उस फूले हुए छैलविहारी बर्नहार्ड बेकर तक को सहन किया जो अपने नाम लासाल के वसीयतनामे को बहुत गम्भीर मानता है।

इस बीच *«Social Demokrat»* में श्री इवीट्ज़र के लेख अधिकाधिक बिस्मार्कपरस्त होते चले गये। मैं उन्हें पहले ही लिख चुका था कि "संघबद्धता के प्रश्न पर"⁹⁷ प्रगतिवादियों को डराया जा सकता है परन्तु प्रशियाई सरकार कभी भी किसी भी परिस्थिति में संघबद्धता कानूनों को पूरी तरह मिटाने के लिए राजी नहीं होगी क्योंकि उसका मतलब नौकरशाही के बीच दरार डालना होगा, मजदूरों को नागरिक अधिकार देना होगा, नौकर-चाकरों को अभिशासित करनेवाले नियमों⁹⁸ को विमृश्रलित करना होगा, देहात में अभिजातों द्वारा लोगों की कमर पर कोड़े लगाये जाने की परिपाटी का अन्त करना होगा, आदि, आदि, जिसकी बिस्मार्क कभी इजाजत नहीं देगा और जो प्रशियाई नौकरशाही राज्य से क़तई मेल नहीं खाता। मैंने यह भी लिखा था कि यदि सदन संघबद्धता कानूनों को मंसूख कर भी दे, सरकार शब्दजाल का (उदाहरण के लिए सामाजिक प्रश्न "अधिक गहन" पगों की अपेक्षा करता है, आदि) सहारा ले लेगी ताकि वह उन्हें

* गले पड़े को निभाना।—सं०

बरकरार रख सके। यह सब सही सिद्ध हुआ। और श्री वान श्वीट्ज़र ने क्या किया? वह विस्मार्क के पक्ष में एक लेख लिख बैठते हैं तथा अपनी सारी शूर-वीरता शुल्ज़े और फ़ाउहेर आदि कहीं छोटे लोगों के विरुद्ध संघर्ष के लिए आरक्षित रखते हैं।

मेरी राय में श्वीट्ज़र तथा दूसरे लोगों के नेक इरादे हैं, परन्तु वे “व्यावहारिक राजनीतिज्ञ” हैं। वे विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहते हैं तथा “व्यावहारिक राजनीति” का यह विशेषाधिकार माइकेल और उनकी मण्डली को विशिष्ट उपयोग के लिए सौंपने से इन्कार करते हैं। (माइकेल और उनकी मण्डली प्रशियाई सरकार के साथ घुलने-मिलने का अधिकार अपने लिए आरक्षित रखने के लिए इच्छुक प्रतीत होती है।) इन लोगों को पता है कि प्रशा में (और इसलिए शेष जर्मनी में भी) मजदूरों के अख़बार तथा मजदूरों का आन्दोलन मात्र पुलिस की कृपा से विद्यमान हैं। इसलिए वे हालात जैसे हैं, उन्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं और सरकार को नाराज़ नहीं करना चाहते, आदि, ठीक हमारे “जनतंत्रवादी” व्यावहारिक राजनीतिज्ञों की तरह जो होहेनज़ालर्न वंश के सम्राट को “अपने साथ रखने के लिए” इच्छुक हैं। परन्तु चूंकि मैं “व्यावहारिक राजनीतिज्ञ” नहीं हूँ, मैंने एंगेल्स के साथ मिलकर «*Social-Demokrat*» को एक सार्वजनिक वक्तव्य के माध्यम से (जिसे आप जल्द ही किसी अख़बार में पढ़ेंगे) उससे अलग होने का नोटिस देना ज़रूरी समझा है।

इसलिए आप शीघ्र यह भी समझ लेंगे कि इस समय मैं क्यों प्रशा में कुछ नहीं कर सकता। वहाँ सरकार ने प्रशा की नागरिकता वापस देने से साफ़ इन्कार कर दिया है।^{११}

मुझे वहाँ प्रचार करने की इजाज़त उसी सूरत में दी जा सकती है जब उसका रूप श्री विस्मार्क को स्वीकार्य हो।

मैं अपना प्रचार यहां अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के ज़रिए चलाना सौ गुना ज्यादा पसन्द करता हूँ। अंग्रेज़ सर्वहारा पर उसका प्रभाव प्रत्यक्ष और सर्वाधिक महत्व का है। हम यहां इस समय सार्वजनिक मताधिकार के प्रश्न पर आन्दोलन कर रहे हैं जिसका निस्सन्देह यहां महत्व प्रशा से सर्वथा भिन्न है।

कुल मिलाकर इस संघ की प्रगति यहां, पेरिस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड तथा इटली में सर्वथा आशातीत है। निस्सन्देह जर्मनी में लासाल के अनुयायी मेरा विरोध कर रहे हैं, १) जिन्हें अपना महत्व खो जाने का मूर्खतापूर्ण भय

है; २) जो यह जानते हैं कि मैं उसका खुला विरोधी हूँ जिसे जर्मन “व्यावहारिक राजनीति” के नाम से पुकारते हैं। (इसी क्रिस्म की “व्यावहारिकता” ने जर्मनी को अब तक तमाम सभ्य देशों से पीछे रखा है।)

चूँकि सदस्यता कार्ड के लिए एक शिलिंग देनेवाला कोई भी व्यक्ति संघ का सदस्य बन सकता है; चूँकि फ्रांसीसियों ने (बिल्कुल बेल्जियनों जैसा) व्यक्तिगत सदस्यता का यह रूप इसलिए चुना कि कानून उन्हें “सहचार” के रूप में हमसे सम्बद्ध होने से रोकता है; और चूँकि स्थिति जर्मनी से बिल्कुल मिलती है, मैंने जर्मनी में अपने दोस्तों से यह कहने का फ़ैसला किया है कि वे छोटी-छोटी सोसायटियाँ—सदस्यों की संख्या का कोई महत्व नहीं है—बनायें तथा हर सदस्य अंग्रेज़ सदस्यता कार्ड हासिल करे। चूँकि अंग्रेज़ सोसायटी वैध है, इस तरह की कार्यविधि का अनुसरण करने की राह में कोई रुकावट नहीं है, फ्रांस में भी नहीं। यदि आप तथा आपके दोस्त इस ढंग से लन्दन के सम्पर्क में आ सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी...

अंग्रेज़ी से अनूदित।

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र

हैनोवर में

लन्दन, ६ अक्टूबर १८६६

... मुझे जेनेवा में पहली कांग्रेस के बारे में बहुत आशंका थी, परन्तु मेरी अपेक्षा के विपरीत उसका काम कुल मिलाकर सुचारु रूप से हुआ। फ्रांस, इंग्लैंड तथा अमरीका में उसका प्रभाव आशातीत रहा। मैं वहाँ नहीं जा सकता था और न जाना चाहता था परन्तु मैंने लन्दन के डेलीगेटों के लिए कार्यक्रम लिख दिया था।* मैंने उसे जानबूझकर उन मुद्दों तक सीमित रखा जिन पर मजहदूर तत्काल सहमत हो सकें तथा संयुक्त कार्रवाइयाँ कर सकें और जो वर्ग-संघर्ष की आवश्यकताओं को तथा वर्ग के रूप में मजहदूरों के संगठन को प्रत्यक्ष पोषण सामग्री

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

तथा संवेग प्रदान करते हैं। पेरिस के सज्जनों के दिमाग में सबसे खोखली प्रदोंपंथी शब्दावली भरी हुई थी। वे विज्ञान के बारे में चढ़चढ़ करते हैं परन्तु उसके बारे में लेशमात्र नहीं जानते। वे सारी क्रान्तिकारी कार्रवाई, अर्थात् स्वयं वर्ग-संघर्ष से पैदा होनेवाली कार्रवाई को, सारे संकेन्द्रित, सामाजिक आन्दोलनों को और इसलिए उन आन्दोलनों को भी हिकारत की नज़र से देखते हैं जिन्हें राजनीतिक साधनों के माध्यम से चलाया जा सकता है (उदाहरण के लिए कार्य-दिवस को क़ानूनी तौर पर घटाना)। स्वतंत्रता के बहाने, सरकारविरोधवाद अथवा सत्तावाद विरोध—व्यक्तिवाद के बहाने, ये सज्जन—जो सोलह वर्षों से सर्वाधिक विकट निरंकुशतावाद को इतनी ख़ामोशी से सहन करते रहे और अब भी कर रहे हैं—वस्तुतः साधारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वकालत करते हैं, अन्तर केवल यह है कि इसे प्रदोंपंथी ढंग से आदर्शीकृत बनाया गया है! प्रदों ने अपरिमित शरारत की। उनकी नकली आलोचना तथा कल्पनावಾದियों के उन द्वारा नकली विरोध ने (प्रदों स्वयं मात्र निम्नपूँजीवादी कल्पनावामी हैं जबकि फ़ुरिए, ओवेन, आदि के कल्पनाविलास में एक नये संसार की पूर्वकल्पना तथा कल्पनामय अभिव्यंजना है) सबसे पहले Jeunesse brillante* को, छात्रों को और फिर मजदूरों को, खासकर पेरिस के उन लोगों को आकृष्ट तथा भ्रष्ट किया जिनका विलास सामग्रियों के व्यवसायों के मजदूरों के नाते अनजाने ही पुराने कूड़ा-कर्कट से दृढ़ अनुराग है। ये अज्ञानी, धमंडी, दंभी, बातूनी, लफ़्फ़ाज लोग सब कुछ बिगाड़ने ही वाले थे क्योंकि वे इतनी तादाद में कांग्रेस में आ धमके जिसका उनके सदस्यों की संख्या से कोई मेल ही नहीं था। मैं रिपोर्ट में इनका सीधे नाम न लेकर इनसे पूरा हिसाब-किताब चुकता करूँगा।

बाल्टिमोर में अमरीकी मजदूर कांग्रेस ने¹⁰⁰, जो लगभग उसी समय हुई, मुझे बहुत आनन्दित किया। वहाँ नारा था पूँजी के विरुद्ध संघर्ष के लिए संगठन। और यह उल्लेखनीय है कि जेनेवा के लिए मैंने जो मांगें निरूपित की थीं, उनमें से अधिकांश वहाँ भी प्रस्तुत की गयीं जिसका श्रेय मजदूरों की सही सहज प्रवृत्ति को है।

यहाँ का सुधार आन्दोलन, जिसे मूर्त रूप देने के लिए हमारी केंद्रीय कौंसिल ने आह्वान किया था (quorum magna pars fui)** , विशाल आकार ग्रहण कर

* ठाठ-बाट वाले तरुण।—सं०

** जिसमें मैंने बड़ी भूमिका अदा की (विर्जिलियस, 'एनेइड', दूसरी पुस्तक)।—सं०

चुका है और अरोध्य बन गया है¹⁰¹। मैं पूरे समय पृष्ठभूमि में रहा हूँ और चूँकि वह चल पड़ा है, मैं इसके बारे में अब चिन्ता नहीं करता...

०

अंग्रेजी से अनूदित।

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र

हैनोवर में

लन्दन, ११ जुलाई १८६८

... जहाँ तक «*Centralblatt*»¹⁰¹ का सम्बन्ध है, लेखक का विचार है कि वह यह स्वीकार करके मुझे अधिकतम रियायत दे रहा है कि यदि मूल्य की अवधारणा का कोई भी अर्थ निकलता है तो मैं जो निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। बदकिस्मत यह नहीं देखता कि यदि मेरी पुस्तक में “मूल्य”¹⁰² पर कोई अध्याय न भी होता तब भी वास्तविक सम्बन्धों का जो विश्लेषण मैंने किया है, उसमें वास्तविक मूल्य सम्बन्ध का प्रमाण तथा सम्पुष्टि होती। मूल्य की अवधारणा को सिद्ध करने की आवश्यकता की इस सारी बकवास का स्रोत विषय का, जिस पर विचार किया गया, तथा वैज्ञानिक विधि दोनों का अज्ञान है। हर बच्चा जानता है कि जो राष्ट्र एक वर्ष तो क्या चन्द सप्ताह भी काम नहीं करेगा, वह नष्ट हो जायेगा। हर बच्चा यह भी जानता है कि भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों के समूह समाज के भिन्न-भिन्न तथा परिमाणतः निर्धारित श्रम की अपेक्षा करते हैं। यह स्वतःस्पष्ट है कि सामाजिक श्रम के निश्चित अनुपातों में वितरण की इस आवश्यकता को सम्भवतः सामाजिक उत्पादन का कोई निश्चित रूप समाप्त नहीं कर सकता, बल्कि केवल उसकी अभिव्यक्ति के रूप को ही परिवर्तित कर सकता है। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक कानूनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐतिहासिक दृष्टि से भिन्न-भिन्न अवधियों में जो चीज़ बदल सकती है, वह केवल वह रूप है जिसमें ये कानून अपने लिए रास्ता बनाते हैं। और वह रूप, जिसमें श्रम का सानुपातिक वितरण अपने लिए रास्ता बनाता है, समाज की उस व्यवस्था के अन्दर, जहाँ सामाजिक श्रम का

अन्तःसम्बन्ध श्रम के पृथक-पृथक उत्पादों के निजी विनिमय में व्यक्त होता है, इन उत्पादों का ठीक विनिमय मूल्य हुआ करता है।

विज्ञान का कार्यभार यह प्रदर्शित करने में निहित है कि मूल्य का नियम कैसे अपना रास्ता बनाता है। इसलिए यदि कोई शुरु में ही सारे घटना-व्यापारों पर, जो प्रकटतः उस नियम का विरोध करते हैं, “प्रकाश डालना” चाहता है तो उसे विज्ञान के पहले विज्ञान को प्रस्तुत करना होगा। रिकार्डों की ठीक यही शलती है कि मूल्य पर अपने पहले अध्याय में वह तमाम सम्भव तथा आगे विकसित होनेवाले प्रवर्गों को पूर्व-दत्त मान लेते हैं ताकि मूल्य के नियम के साथ उनकी अनुरूपता सिद्ध कर सकें।

दूसरी ओर, जैसा कि आपने ठीक समझा, सिद्धान्त का इतिहास निश्चित रूप से यह प्रदर्शित करता है कि मूल्य सम्बन्ध की अवधारणा सदैव एक जैसी रही है, कमोबेश स्पष्ट रही है, कमोबेश भ्रान्तियों से उलझी रही है अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से कमोबेश निश्चित रही है। चूंकि चिंतन प्रक्रिया स्वयं कुछ विशेष अवस्थाओं के बीच से जन्म लेती है, स्वयं एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसलिए वस्तुतः ग्रहणशील चिन्तन सदैव एक जैसा होना चाहिए तथा उसमें विकास की परिपक्वता के अनुसार, और चिन्तनशील अंग के विकास के अनुसार भी धीरे-धीरे अन्तर आ सकता है। बाक़ी सब बकवास है।

बाज़ारू अर्थशास्त्री को इस बात का लेशमात्र ज्ञान नहीं है कि नित्यप्रति के वास्तविक विनिमय सम्बन्धों की मूल्य के आकारों से प्रत्यक्षतया समरूपता नहीं हो सकती। पूंजीवादी समाज का सार ठीक इसी में निहित है कि उसमें a priori* उत्पादन का कोई सचेतन सामाजिक नियमन नहीं होता। तर्कबुद्धि और स्वभावतया आवश्यकता केवल आंखें बन्द कर काम करनेवाले औसत के रूप में ही अपना रास्ता बना सकती हैं। और फिर बाज़ारू अर्थशास्त्री जब आन्तरिक सम्बन्ध के अनावरण की जगह गर्वपूर्वक यह घोषणा करता है कि अभिव्यक्ति में वस्तुएं भिन्न लगती हैं तो वह सोचता है कि उसने बहुत बड़ी खोज कर डाली है। वस्तुतः वह तो यह डींग हांकता है कि वह अभिव्यक्ति का दृढ़ समर्थक है, और वह उसे अन्तिम वस्तु मान बैठता है। तो फिर विज्ञान की जरूरत क्या है?

परन्तु मामले की एक और पृष्ठभूमि है। एक बार अन्तःसम्बन्ध को समझ लिया जाये, तो विद्यमान अवस्थाओं की स्थायी आवश्यकता में सैद्धान्तिक विश्वास

व्यवहार में उनके धराशायी होने से पहले ही धराशायी हो जाता है। इसलिए यहां सत्तारूढ़ वर्गों के नितान्त हित में है कि इस निरर्थक भ्रान्ति को कायम रखा जाये। और आखिर इन चाटुकार वाचालों को और किसलिए पैसा दिया जाता है जिनके पास इसके अलावा और कोई तुरूप नहीं है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र में सोचने की जरूरत ही नहीं है।

परन्तु *satis superque**। अलबत्ता इससे पता चलता है कि पूंजीपति वर्ग के इन पुरोहितों की क्या हालत हो गयी है—जहां मजदूर और कारखानेदार तथा तिजारती तक मेरी पुस्तक को** समझते हैं और उन्हें इसमें अपने लिए रास्ता मिलता है, वहां ये “विद्वान् कलमधिष्ठू” (!) यह शिकायत करते हैं कि मैं उनकी बुद्धि से जरूरत से ज्यादा तक्राजा कर रहा हूं।

अंग्रेजी से अनूदित।

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र

हैनोवर में

लन्दन, १२ अप्रैल १८७१

... कल हम लोगों को यह समाचार, जो चित्त स्थिर करनेवाला कदापि नहीं है, मिला कि लफ़ार्ग (लाउरा नहीं) इस समय पेरिस में है।

यदि मेरी ‘अठारहवीं ब्रूमे’*** के अन्तिम अध्याय को खोलो तो देखोगे कि उसमें मैंने कहा है कि फ्रांसीसी क्रान्ति का अगला पग पहले की तरह नौकरशाही-फ़ौजी मशीनरी को एक हाथ से दूसरे हाथ में कर देने का नहीं, बल्कि उसे चकनाचूर कर देने का होगा, और यही यूरोपीय महाद्वीप में किसी भी सच्ची जन क्रान्ति के सम्पन्न होने की प्रारम्भिक शर्त है। पेरिस में हमारे बहादुर पार्टी कामरेड यही कोशिश कर रहे हैं। कैसी नमनीयता, कैसी ऐतिहासिक पेशकदमी,

* बहुत हो गया।—सं०

** कार्ल मार्क्स, ‘पूँजी’।—सं०

*** देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १।—सं०

कुर्बानी की कैसी क्षमता इन पेरिस वालों में है! छः महीने तक भुखमरी और तबाही के बाद भी, जिसका कारण बाहरी दुश्मन से ज्यादा अन्दरूनी गहारी रहा है वे प्रशियाई संगीनों के साये के नीचे उठ खड़े हुए हैं मानो फ्रांस और जर्मनी में युद्ध कभी हुआ ही न हो और दुश्मन पेरिस के दरवाजे पर अब तक मौजूद न हो! ऐसी महानता इतिहास में बेमिसाल है! यदि वे पराजित हुए तो इसका कारण सिर्फ उनकी “भलमनसाहत” होगा। विनुआ और उसके साथ पेरिस राष्ट्रीय गार्ड के प्रतिक्रियावादी अंग पेरिस से भाग जाने के बाद, उन्हें फ़ौरन वेसर्ई पर चढ़ाई कर देनी चाहिए थी। अंतःकरण के संकोच के कारण उन्होंने यह सुयोग छोड़ दिया। वे गृहयुद्ध नहीं छेड़ना चाहते थे, गोया थियेर, वह दुष्ट नरपिशाच, पेरिस को निरस्त्र करने की चेष्टा करके गृहयुद्ध पहले ही नहीं छेड़ चुका था! दूसरी गलती: केन्द्रीय समिति ने, कम्यून के लिए स्थान रिक्त करने के लिए, बहुत जल्द अपनी सत्ता त्याग दी। यह भी अत्यधिक “भद्रतापूर्ण” नैतिक संकोच के कारण किया गया! जो भी हो, पेरिस का वर्तमान विद्रोह जून के पेरिस विद्रोह के बाद हमारी पार्टी का सबसे शानदार कारनामा है, भले ही पुराने समाज के भेड़िये, सूअर और नीच कुत्ते उसे कुचल डालें। स्वर्ग पर धावा बोलनेवाले इन पेरिस वालों की तुलना ज़रा जर्मन-प्रशियाई पवित्र रोमन साम्राज्य के गुलामों से, उसके प्राक्प्रलय स्वांगों से फ़ौजी बारिकों, चर्च, युंकरशाही और सर्वोपरि कूपमण्डूकता की कड़ी गन्ध आती है।

प्रसंगवश। लूई बोनापार्ट के खज़ाने से सीधे अनुदान पानेवालों की सरकार द्वारा प्रकाशित सूची में एक नोट है कि फ़ोर्ट को अगस्त १८५६ में ४०,००० फ़्रैंक मिले! लीबकनेख्त को मैंने यह सूचना दे दी है ताकि आगे इसका और उपयोग किया जा सके।

हक्सटहाउजेन की पुस्तक¹⁰⁴ तुम मेरे पास भेज सकते हो, क्योंकि इधर मुझे जर्मनी ही नहीं, बल्कि पीटर्सबर्ग से भी पैम्फ़लेट, आदि सुरक्षित अवस्था में मिलने लगे हैं।

उन विभिन्न अख़बारों के लिए धन्यवाद जो तुमने भेजे हैं (और अधिक अख़बार भेजो, क्योंकि मैं जर्मनी, राइख़स्टाग, आदि के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ)।

अंग्रेज़ी से अनूदित।

लुडविग कुगेलमन के नाम मार्क्स का पत्र

० हैनोवर में

[लन्दन], १७ अप्रैल १८७१

तुम्हारा पत्र मिल गया था। अभी मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ। इसलिए दो-चार शब्द ही लिखूंगा। १३ जून १८४६ जैसे निम्नपूँजीवादी प्रदर्शनों¹⁰⁵ की तुलना तुम पेरिस के वर्तमान संघर्ष से करते हो, यह बात मेरी समझ में बिलकुल ही नहीं आती।

अगर ऐसी अनुकूल अवस्था होने पर ही संघर्ष छेड़ा जाये जिसमें चूक की कोई गुंजायश न हो, तो सचमुच ही विश्व इतिहास की रचना अत्यंत सरल हो जायेगी। दूसरी ओर, यदि “संयोग” का इतिहास में योगदान न होता तो उसका चरित्र धीरे-धीरे रहस्यपूर्ण हो जाता। ये संयोग विकास के साधारण क्रम के संघटक अंग होते हैं, और अन्य संयोगों द्वारा संतुलित होते रहते हैं। पर तेज गति या देरी बहुत कुछ ऐसे “संयोगों” पर अवलम्बित होती है जिनमें यह “संयोग” भी सम्मिलित है कि आन्दोलन का पहले-पहल नेतृत्व करनेवाले लोग कैसा चरित्र रखते हैं।

इस बार का निर्णायक रूप से प्रतिकूल “संयोग” फ्रांसीसी समाज की आम अवस्थाओं में नहीं, बल्कि इस चीज़ में अन्तर्निहित है कि फ्रांस में प्रशियाई घुसे हुए हैं और पेरिस की ऐन देहरी पर खड़े हैं। पेरिसवासियों को इसका ख़ूबी पता था। पर इसका पता वेसाई की पूँजीवादी भीड़ को भी था। ठीक इसी कारण उन्होंने पेरिसवासियों को दो रास्तों में से एक चुनने को मजबूर किया— या तो लड़ें या बिना लड़े ही समर्पण कर दें। दूसरा रास्ता अपनाये जाने की सूरत में मजदूर वर्ग की पस्तहिम्मती बहुत सारे “नेताओं” के नष्ट होने से कहीं अधिक दुर्भाग्यजनक होती। पेरिस कम्यून के साथ पूँजीपति वर्ग और उसके राज्य के विरुद्ध मजदूर वर्ग के संघर्ष ने एक नये दौर में प्रवेश किया है। उसका तात्कालिक परिणाम चाहे जो भी हो, विश्वव्यापी महत्व का एक नया प्रस्थान-बिंदु पा लिया गया है।

अंग्रेजी से अनूदित।

फ्रेडरिक बोल्ट के नाम मार्क्स का पत्र

न्यूयार्क में

[लन्दन], २३ नवम्बर १८७१

... इंटरनेशनल की स्थापना समाजवादी और अर्द्धसमाजवादी पंथों के स्थान पर संघर्ष के लिए मजदूर वर्ग का एक सच्चा संगठन कायम करने के लिए की गयी थी। उसकी मूल नियमावली तथा उद्घाटन घोषणा* इस चीज की एकदम पुष्टि करती हैं। दूसरी ओर, यदि इतिहास की धारा ने पंथवाद को पहले ही चूर चूर न कर दिया होता तो इंटरनेशनल अपने को कायम नहीं रख सकता था। समाजवादी पंथवाद के विकास और असली मजदूर आन्दोलन के विकास में सदा से विलोम अनुपात रहा है, जिस अनुपात में एक बढ़ता है उसी अनुपात में दूसरा घटता है। पंथों का उस समय तक (ऐतिहासिक दृष्टि से) औचित्य रहता है, जब तक कि मजदूर वर्ग स्वतंत्र ऐतिहासिक आन्दोलन के लिए परिपक्व नहीं हो जाता। पर ज्यों ही उसमें यह परिपक्वता आ जाती है त्यों ही सभी पंथ सारभूत रूप में प्रतिगामी बन जाते हैं। इतिहास ने सभी जगह जो दिखाया है, उसकी पुनरावृत्ति इंटरनेशनल के इतिहास में भी हुई। जो पुराना पड़ जाता है, वह नव उपलब्ध रूप के अन्दर फिर पैर जमाने तथा अपनी स्थिति कायम करने की कोशिश करता है।

इंटरनेशनल का इतिहास मजदूर वर्ग के असली आन्दोलन के प्रतिकूल स्वयं इंटरनेशनल के भीतर अपनी स्थिति कायम रखने की कोशिश करनेवाले पंथों और शौक्तिया प्रयोगों के खिलाफ जनरल कौंसिल का निरन्तर संघर्ष रहा है। यह संघर्ष कांग्रेसों में चलाया जाता था। पर उससे भी कहीं अधिक वह अलग-अलग शाखाओं के साथ जनरल कौंसिल के निजी व्यवहार में चला करता था।

पेरिस में चूँकि प्रदोपंथी (परस्परवादी¹⁰⁶) संघ के सह-संस्थापकों में से थे इसलिए वहां पहले कुछ सालों में बागडोर स्वभावतया उनके ही हाथ में रही। बेशक बाद में उनके विरोध में सामूहिकतावादी और प्रत्यक्षवादी, आदि दल स्थापित किये गये।

* का० मार्क्स, 'अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की उद्घाटन घोषणा'।—सं०

जर्मनी में लासाल का गुट था। मैं खुद दो वर्षों तक कुख्यात श्वीट्ज़र के साथ पत्रव्यवहार करता रहा और मैंने उसके सामने अकाद्य रूप में प्रमाणित कर दिया कि लासाल का संगठन और कुछ नहीं, पंथवादी संगठन ही है और इस नाते इंटरनेशनल जिसके लिए प्रयत्नशील है उस असली मजदूर आन्दोलन के संगठन के विरुद्ध है। पर इसे न समझने के उसके अपने खास "कारण" थे।

१८६८ के अन्त में रूसी बकूनिन ने इस इरादे से इंटरनेशनल में प्रवेश किया कि वह उसके अंदर "समाजवादी जनवाद का सहबन्ध" नाम से एक दूसरा इंटरनेशनल कायम करें जिसके नेता वह खुद हों। सैद्धान्तिक ज्ञान से शून्य इस सज्जन ने यह दावा पेश किया कि उसकी अलग संस्था इंटरनेशनल के वैज्ञानिक प्रचार का प्रतिनिधित्व करेगी और इंटरनेशनल के अन्दर के इस दूसरे इंटरनेशनल का विशेष कार्य यह प्रचार करना होगा।

उनका कार्यक्रम खिचड़ी था। उसमें था - वर्गों की समानता (!), सामाजिक आन्दोलन के प्रस्थान-बिन्दु के रूप में उत्तराधिकार का उन्मूलन (यह सेंट-साइमनपंथी बकवास है), इंटरनेशनल के सदस्यों पर लादे जानेवाले जड़सूत्र के रूप में निरीश्वरवाद, आदि, और मुख्य जड़सूत्र राजनीतिक आन्दोलन से (प्रदोषंथी) परहेज।

यह बाल-पोथी इटली और स्पेन में, जहां मजदूर आन्दोलन की वास्तविक अवस्थाएं अभी तक विकसित नहीं हैं, पसन्द की गयी (वहां अब भी इसका कुछ असर है); लैटिन स्विट्ज़रलैण्ड तथा बेल्जियम के कुछ अहंकारी, महत्वाकांक्षी और खोखले मतवादियों को भी वह अच्छी लगी।

श्री बकूनिन के लिए उसका सिद्धान्त (जो प्रदोष, सेंट-साइमन, आदि में मांग कर इकट्ठा किया कूड़ा-कंकाट मात्र है) गौण वस्तु था और आज भी है। वह यह दिखलाने का जरिया मात्र है कि वह भी कुछ हैं। पर सिद्धान्तकार के रूप में नगण्य बकूनिन का षड्यंत्रकारी का रूप उनका सहज, प्रकृत रूप है।

जनरल कौंसिल को वर्षों तक इस षड्यंत्र से (जिसको एक हद तक, खासकर दक्षिण फ्रांस में फ्रांसीसी प्रदोषंथियों से समर्थन मिलता रहा) लोहा लेना पड़ा। अन्त में उसने सम्मेलन के प्रस्ताव १, २ और ३, IX, XVI और XVII द्वारा अपना वह वार किया जिसकी लम्बे अरसे से तैयारी की गयी थी¹⁰⁷।

प्रगट है कि जनरल कौंसिल यूरोप में जिस चीज के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, उसका ही अमरीका में समर्थन नहीं करेगी। प्रस्ताव १, २, ३ और IX न्यूयार्क कमेटी को अब वे कानूनी हथियार प्रदान करते हैं जिनसे वह सभी पंथवाद और

शौक्रिया जमातों का खात्मा कर सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निकाल बाहर कर सकती है...

मजदूर वर्ग के राजनीतिक आन्दोलन का अंतिम लक्ष्य निश्चय ही मजदूर वर्ग के लिए राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना है। स्वभावतया इसके लिए यह आवश्यक है कि मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष से उद्भूत उसका पहले से एक संगठन कुछ हद तक विकसित कर लिया गया हो।

पर दूसरी ओर बात यह भी है कि जिस भी आन्दोलन में मजदूर वर्ग एक वर्ग के रूप में शासक वर्गों के साथ मुकाबले पर आता है और उन्हें बाहरी दबाव के जरिये मजबूर करने की चेष्टा करता है, वह राजनीतिक आन्दोलन है। उदाहरणार्थ, किसी फ़ैक्टरी में या किसी व्यवसाय में भी, हड़तालों, आदि के जरिये अलग-अलग पूंजीपतियों को और अधिक छोटा कार्य दिवस मानने के लिए मजबूर करना विशुद्ध आर्थिक आन्दोलन है। दूसरी ओर, आठ घंटे के कार्य दिवस, आदि का क़ानून मनवाने का आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन है। इस तरह, मजदूरों के अलग-अलग आर्थिक आन्दोलनों से हर जगह एक राजनीतिक आन्दोलन विकसित हो जाता है, अर्थात् एक वर्ग का आन्दोलन विकसित हो जाता है जिसका उद्देश्य अपने हितों को एक सामान्य रूप में उपलब्ध करना है, ऐसे रूप में उपलब्ध करना है जिसकी विशेषता यह है कि वह पूरे समाज के लिए अनिवार्य हो। इन आन्दोलनों के लिए यदि कुछ हद तक पहले से संगठन का होना पूर्वमान्य है तो इसी तरह यह भी सही है कि ये स्वयं इस संगठन के विकास के साधन होते हैं।

जहां मजदूर वर्ग का संगठन इतना विकसित नहीं होता कि सामूहिक सत्ता के विरुद्ध, यानी शासक वर्गों की राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध निर्णायक अभियान छेड़ सके, वहां शासक वर्गों के विरुद्ध निरन्तर प्रचार करके तथा उनकी नीति के प्रति विरोधी रुख अख्तियार करके इस वर्ग को इसके लिए हर हालत में प्रशिक्षित तो करना ही चाहिए। वरना वह शासक वर्गों के हाथों का खिलौना बना रहेगा जैसा कि फ़्रांस की सितम्बर क्रान्ति¹⁰⁸ से जाहिर हुआ और जैसा कि एक हद तक इससे भी सिद्ध होता है कि ग्लैड्स्टन और उनकी मण्डली इंग्लैंड में आज तक सफलतापूर्वक अपना खेल खेले जा रही है।

थियोदोर कुनो के नाम एंगेल्स का पत्र

०

मिलान में

लन्दन, २४ जनवरी १८७२

...बकूनिन, जो १८६८ तक इंटरनेशनल के खिलाफ़ साजिशें रचते रहे, बेर्न कांग्रेस¹⁰⁹ के टांग-टांग फिस हो जाने के बाद उसमें शामिल हो गये और उसके अन्दर फ़ौरन जनरल कौंसिल के खिलाफ़ षड्यंत्र करने लगे। बकूनिन का अपना ही एक विचित्र सिद्धांत है, प्रदोषंथ तथा कम्पूनिज्म की खिचड़ी। मुख्य बात यह है कि वह पूंजी को, अर्थात् पूंजीपतियों और उजरती मजदूरों के बीच वर्ग-विरोध को नहीं, जो सामाजिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है, वरन् राज्य को वह मुख्य बुराई मानते हैं जिसे ख़त्म किया जाना चाहिए। जहां सामाजिक-जनवादी मजदूरों की बहुत बड़ी तादाद हमारे इस विचार को अगनाती है कि राजकीय सत्ता एक ऐसे संगठन के अलावा और कुछ नहीं है जिसको सत्तारूढ़ वर्गों ने—जमींदारों तथा पूंजीपतियों ने—अपने लिए स्थापित किया है ताकि वे अपने सामाजिक विशेषाधिकारों की रक्षा कर सकें। बकूनिन यह मानते हैं कि यह राज्य ही है जिसने पूंजी की रचना की है, कि पूंजीपति के पास केवल राज्य की कृपा से ही पूंजी होती है। इसलिए राज्य चूंकि मुख्य बुराई है, इसलिए सर्वोपरि राज्य को ही ख़त्म करना चाहिए और तब पूंजी ख़ुद जहन्नुम में पहुंच जायेगी। इसके विपरीत हम लोगों का कहना है—पूंजी को, उत्पादन के समस्त साधनों के चन्द हाथों में सकेन्द्रण को ख़त्म कर दें, और राज्य ख़ुद ढह जायेगा। अन्तर बुनियादी है—पहले सामाजिक क्रान्ति के बिना राज्य के उन्मूलन की बात बकवास है; ठीक पूंजी का उन्मूलन ही सामाजिक क्रान्ति है और उसमें उत्पादन की पूरी पद्धति में परिवर्तन निहित है। परन्तु बकूनिन के लिए चूंकि राज्य मुख्य बुराई है, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो राज्य को—अर्थात् किसी भी तरह के राज्य को, चाहे यह जनतंत्रीय हो या राजतंत्रीय अथवा कुछ और—जीवित रखे। इसलिए सारी राजनीति से पूरी विरति होनी चाहिए। कोई राजनीतिक कार्रवाई करना, खास तौर पर चुनाव में भाग लेना सिद्धांत के साथ गहरी करना होगा। काम यह है कि प्रचार किया जाये, राज्य को जी भर गालियां दी जायें, संगठन किया जाये और जब सब मजदूरों को, इसलिए बहुसंख्या को

अपने पक्ष में कर लिया जाये तो सत्ता के तमाम निकायों को विघटित कर दिया जाये, राज्य का उन्मूलन कर दिया जाये और उसके स्थान पर इंटरनेशनल का संगठन स्थापित कर दिया जाये। इस महान कृत्य को जिसके साथ स्वर्णयुग आरम्भ होता है, सामाजिक विघटन के नाम से पुकारा जाता है।

यह सब अतीव आमूल परिवर्तनवादी प्रतीत होता है और इतना सरल है कि इसे पांच मिनट में कण्ठस्थ किया जा सकता है। यही कारण है कि बकूनिनपंथी सिद्धांत को इटली तथा स्पेन में नौजवान वकीलों, डाक्टरों तथा अन्य मताग्रहियों के बीच इतनी तेजी से समर्थन प्राप्त हो गया। परन्तु मजदूर जनसाधारण कभी यह स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होंगे कि उनके देशों के मामले उनके अपने नहीं हैं; वे स्वभाव से राजनीतिक सक्रियता वाले लोग होते हैं और जो कोई उनसे इस बात पर यकीन कराने की चेष्टा करता है कि वे राजनीति का बिल्कुल त्याग करें, वह अन्ततः अपने को परित्यक्त पायेगा। मजदूरों को यह उपदेश देने का कि वे किसी भी परिस्थिति में राजनीति से विरत रहें, मतलब उन्हें पुरोहितों या पूंजीवादी जनतंत्रवादियों की बांहों में पहुंचाना होगा।

बकूनिन के अनुसार इंटरनेशनल चूंकि राजनीतिक संघर्ष के लिए नहीं, वरन् सामाजिक विघटन होते ही पुराने राजकीय संगठन का स्थान लेने के लिए गठित किया गया था, इसलिए उसे भावी समाज के विषय में बकूनिनपंथी आदर्श के अधिक से अधिक अनुरूप होना चाहिए। इस समाज में सर्वोपरि कोई सत्ता नहीं होगी क्योंकि सत्ता—राज्य—सरासर बुराई है। (लोग अन्तिम रूप से निर्णय देनेवाली किसी इच्छा के बिना, किसी व्यवस्था के बिना कैसे किसी कारखाने का संचालन करना चाहते हैं, कैसे कोई रेल चलाना चाहते हैं, कैसे किसी जलयान को आगे ले जाना चाहते हैं, यह वे निस्सन्देह हमें नहीं बताते।) अल्पमत पर बहुमत की सत्ता भी नहीं रह जाती; प्रत्येक व्यक्ति तथा प्रत्येक समुदाय स्वायत्तशासी है, परन्तु दो व्यक्तियों तक का समाज कैसे तब तक सम्भव है जब तक उसमें हरेक अपनी स्वायत्तता के कुछ अंश का त्याग न करे, इस पर भी बकूनिन मौन साधे हुए हैं।

तो इंटरनेशनल भी इसी ढर्रे पर गठित किया जाना चाहिए। प्रत्येक शाखा तथा प्रत्येक शाखा में प्रत्येक व्यक्ति स्वायत्तशासी होगा। जहन्नुम में जायें बाज़ेल प्रस्ताव¹¹⁰ जो जनरल कौंसिल को धातक और स्वयं उसका नैतिक पतन करने-वाली सत्ता प्रदान करते हैं! यदि यह सत्ता स्वेच्छया दी जाती है, तब भी वह खत्म होनी चाहिए क्योंकि वह सत्ता ही है!

यह है इस ठगविद्या के मुख्य मुद्दों का सार। परन्तु बाजेल प्रस्तावों की पहल करनेवाले लोग कौन हैं? स्वयं श्री बकूनिन और उनकी मंडली!

इन सज्जनों ने जब बाजेल कांग्रेस में देखा कि वे जनरल कौंसिल को जेनेवा में स्थानान्तरित करने, यानी उसे अपने हाथ में लेने की उनकी योजना सफल होने नहीं जा रही है तो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा। उन्होंने वृहत् इंटरनेशनल के अन्तर्गत समाजवादी जनवाद के सहबंध की, एक अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी की उस बहाने से स्थापना कर दी जो आपको आज इटली में बकूनिनपंथी अखबारों में, उदाहरण के लिए «*Proletario*» तथा «*Gazzettino Rosa*»¹¹¹ में फिर पढ़ने को मिलेगा: यह दावा किया गया है कि उत्तेजनशील लैटिन नस्लों को शान्तचित्त उत्तरवासियों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण कार्यक्रम की जरूरत है। यह दयनीय योजना विफल हो गयी क्योंकि जनरल कौंसिल ने इसका विरोध किया जो स्वभावतः इंटरनेशनल के अन्तर्गत और कोई पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सहन नहीं कर सकती थी। यह योजना इंटरनेशनल के कार्यक्रम के स्थान पर बकूनिन के कार्यक्रम को स्थापित करने की बकूनिन और उनके चेले-चांटों की लुकी-छुपी कोशिशों के रूप से भिन्न शक्ति तथा रूप में पुनः प्रकट हुई है। दूसरी ओर जब कभी इंटरनेशनल पर प्रहार करने का प्रश्न पैदा हुआ, जुल फ्रात्र और विस्मार्क से लेकर माज्जिनी तक सारे प्रतिक्रियावादियों ने सदैव बकूनिनपंथियों की खोखली लफ्फाजी पर चोट की। इसलिए माज्जिनी तथा बकूनिन के विरुद्ध मेरे ५ दिसम्बर के वक्तव्य की आवश्यकता पड़ी जो «*Gazzettino Rosa*» में भी प्रकाशित हुआ।

बकूनिनपंथियों का केन्द्रक जूरा के चन्द दर्जन लोगों को लेकर बना हुआ है जिनके मुश्किल से दो सौ मजदूर अनुयायी हैं। इटली में इनके हरावल तरुण वकील, डाक्टर तथा पत्रकार हैं जो अब सर्वत्र इटली के मजदूरों के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं; इस तरह के कुछ लोग वार्सेलोना तथा मैड्रिड में हैं और कभी-कभार कोई एक-दो लियों और ब्रसेल्स में मिल जायेंगे जिनमें से कोई मजदूर नहीं है; यहां* इनका एक ही नमूना है—राबिन।

परिस्थितिवश कांग्रेस की जगह जिसका आयोजन असम्भव हो गया था, जो कांफ्रेंस बुलायी गयी, उसने इन लोगों के लिए एक बहाने का काम दिया और चूंकि स्विट्जरलैंड में अधिकांश फ्रांसीसी उत्प्रवासी उनके पक्ष में इसलिए चले गये

* लन्दन में।—सं०

थे कि उन्हें (प्रदोपथियों को) अपने कई सजातीय लोग मिल गये थे, इस कारण और व्यक्तिगत प्रयोजनों के कारण भी उन्होंने अपना अभियान आरम्भ कर दिया। निस्सन्देह इंटरनेशनल में असन्तुष्ट अल्पमत और मान्यतारहित प्रतिभाएं सर्वत्र मिल सकती हैं, इन लोगों पर ही भरोसा किया गया और अकारण नहीं।

इस समय इनकी संघर्षशील शक्ति इस प्रकार है—

१) स्वयं बकूनिन—इस अभियान के नेपोलियन।

२) जूरा के २०० लोग तथा फ्रांसीसी शाखा के ४०-५० लोग (जेनेवा में उत्प्रवासी)।

३) ब्रसेल्स में हिन्स «Liberté»¹¹² के सम्पादक जो वैसे उनके पक्ष में खुलकर सामने नहीं आते।

४) यहां—१८७१ की फ्रांसीसी शाखा¹¹³ के अवशेष जिसे हमने कभी मान्यता नहीं दी थी और जो अब परस्पर शत्रुता रखनेवाले ३ भागों में बंट गयी है। इनके अलावा श्री वान श्वीटजर की क्रिस्म के लगभग २० लासालपंथी हैं जिन्हें जर्मन शाखा से निकाला जा चुका है (इंटरनेशनल से सामूहिक रूप से हटने का प्रस्ताव करने के कारण) और जो अतीव केन्द्रीकरण तथा कठोर संगठन के समर्थक होने के कारण अराजकतावादी और स्वायत्ततावादी संघ के लिए सोलहों आने उपयुक्त हैं।

५) स्पेन में बकूनिन के चन्द निजी दोस्त तथा अनुयायी जिन्होंने मजदूरों पर—खास तौर पर बार्सेलोना में—कम से कम सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत असर डाला है। परन्तु स्पेनवासी संगठन के लिए बहुत उत्सुक हैं और दूसरों में इसके अभाव को वे तुरन्त देख लेते हैं। यहां बकूनिन सफलता पर कितना भरोसा कर सकते हैं, यह अप्रैल में स्पेनी कांग्रेस से ही मालूम होगा; पर चूंकि वहां मजदूरों का प्रभुत्व होगा, इसलिए मेरे लिए चिन्ता का कोई कारण नहीं है।

६) अन्त में, जहां तक मुझे पता है, इटली में टूरिन, बोलोग्ना तथा गिर्गेन्ती शाखाओं ने घोषणा की है कि वे कांग्रेस समय से पहले बुलाने के पक्ष में हैं। बकूनिनपंथी अखबारों का दावा है कि २० इतालवी शाखाएं उनके साथ शामिल हो गयी हैं; मैं उन्हें नहीं जानता। अलबत्ता लगभग सब जगह नेतृत्व बकूनिन के दोस्तों तथा उनके चेलों के हाथ में है जो ज़बर्दस्त कोलाहल मचा रहे हैं। परन्तु सूक्ष्मतापूर्वक देखने पर पता चल सकता है कि उनके अनुयायियों की तादाद इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि अधिकांश इतालवी मजदूर अब भी माज्जिनीपंथी हैं और वे तब तक माज्जिनीपंथी रहेंगे जब तक वहां इंटरनेशनल तथा राजनीति से विरति को अभिन्न समझा जायेगा।

पक्ष में है ¹¹⁷। बेल्जियन कांग्रेस (२५-२६ दिसम्बर) ने मांग की है कि नियमावली में संशोधन किया जाये परन्तु ऐसा नियमित कांग्रेस में (सितम्बर) करने के लिए कहा है ¹¹⁸। फ्रांस से हमें रोज़ सहमति व्यक्त करनेवाले वक्तव्य प्राप्त हो रहे हैं। यहां, इंग्लैंड में, स्वभावतया इन सारी साजिशों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं है। जनरल कौंसिल यक्रीनन चन्द शेखीबाज़ षड्यंत्रकारियों को खुश करने के लिए असाधारण कांग्रेस बुलाने नहीं जा रही है। जब तक ये सज्जन अपने को कानूनी सीमाओं के अन्दर रखेंगे, कौंसिल उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने देगी—सर्वथा विविध तत्वों का यह मोर्चा जल्द ढह जायेगा; परन्तु ज्योंही वे नियमावली या कांग्रेस के प्रस्तावों के विरुद्ध कोई कार्य करने लगेंगे, जनरल कौंसिल अपना कर्तव्य पूरा करेगी।

यदि आप इस तथ्य पर विचार करें कि इन लोगों ने अपना षड्यंत्र ठीक ऐसे समय संगठित किया है जब इंटरनेशनल के विरुद्ध एक आम चीख-पुकार मचायी जा रही है तो आप यह सोचे बिना नहीं रह सकते कि अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस का इस खेल में हाथ होगा। ऐसा है भी। बेज़े में जेनेवा के बकूनिनपंथियों ने केन्द्रीय पुलिस कमिश्नर* को अपना सम्वाददाता चुना है। दो प्रमुख बकूनिनपंथी लियों के अल्बेर रिशार तथा लेब्लां यहां आये थे तथा उन्होंने लियों के ही शोल नामक एक मजदूर को, जिससे उन्होंने बातचीत की, बताया कि बोनापार्ट को फिर से सिंहासनारूढ़ करना थियेर को हटाने का एकमात्र रास्ता है, और वे उत्प्रवासियों के बीच बोनापार्ट को पुनः सिंहासनारूढ़ करने के पक्ष में प्रचार करने के लिए बोनापार्ट के धन से सफ़र कर रहे हैं! यह है वह चीज़ जिसे ये सज्जन राजनीति से विरति बताते हैं! बर्लिन में बिस्मार्क के अनुदान से चलनेवाला «*Neuer Social-Demokrat*» भी यही राग अलापता है। इसमें रूसी पुलिस कहां तक शामिल है, इसे मैं फ़िलहाल विवादास्पद प्रश्न के रूप में छोड़ देता हूं। परन्तु बकूनिन का नेचायेव-कांड से गहरा सम्बन्ध था (यह सच है कि वह इससे इन्कार करते हैं परन्तु हमारे पास यहां मूल रूसी रिपोर्ट है और चूंकि मार्क्स और मैं दोनों रूसी समझते हैं, वह हमारी आंखों में धूल नहीं झाँक सकते)। नेचायेव या तो रूसी जोखोंवाज़ है, या उसने कम से कम इस तरह का व्यवहार अवश्य किया है। वैसे बकूनिन के रूसी दोस्तों में सब तरह के संदिग्ध लोग हैं।

खैर, इटली में फ़िलहाल इंटरनेशनल में बकूनिनपंथियों की आवाज़ छापी हुई है। जनरल कौंसिल का इस बारे में शिकायत करने का कोई इरादा नहीं है; इतालवियों को सारी बेवकूफ़ियां करने का हक़ है, जनरल कौंसिल केवल शान्तिपूर्ण वाद-विवाद के ज़रिए इसका मुक़ाबला करेगी। इन लोगों को जूरा के लोगों के अर्थ में कांग्रेस बुलाने की घोषणा करने का भी अधिकार है हालांकि यह बहुत ही अजीब बात है कि जो शाखाएं अभी-अभी संलग्न हुई हैं तथा जो किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानतीं, उनसे तत्काल किसी एक का पक्ष लेने के लिए कहा जाये, खासकर विवाद से सम्बन्धित दोनों पक्षों के विचार सुनने से पहले ही! मैंने टूरिनियों को मामले के बारे में सीधी सच्ची बात बता दी है और इसी तरह की घोषणा करनेवाली दूसरी शाखाओं को भी बता दूंगा। इसलिए कि परिपत्र से संलग्नता की ऐसी प्रत्येक घोषणा परोक्ष रूप से परिपत्र में जनरल कौंसिल के विरुद्ध झूठे आक्षेपों तथा झूठी बातों का अनुमोदन है। प्रसंगतः जनरल कौंसिल शीघ्र इस मसले पर अपना ही एक परिपत्र* जारी करेगी¹¹⁴। यदि आप मिलान के लोगों को परिपत्र के प्रकाशित होने तक इस तरह की घोषणा करने से रोक सकें तो आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे।

सबसे मज़े की बात तो यह है कि ये ही टूरिनियन, जो अपने को जूरा के लोगों के पक्ष में घोषित करते हैं, और हमें सत्तावादी होने के लिए झिड़कते हैं, अब एकाएक मांग करते हैं कि जनरल कौंसिल टूरिन में उसके प्रतिद्वन्द्वी मज़दूर संघ के विरुद्ध इस तरह के सत्तावादी पग उठाये जो उसने पहले कभी नहीं उठाये, और बेगेल्ली को «Ficcanaso»¹¹⁵ से बहिष्कृत करे जो इंटरनेशनल का सदस्य तक नहीं है, आदि। और यह सब हम उस मज़दूर संघ की बात सुनने से पहले करें!

सोमवार** को मैंने आपके पास जूरा परिपत्र के साथ «*Révolution Sociale*» की एक प्रति, जेनेवा «*Egalité*» की एक प्रति (दुर्भाग्यवश मेरे पास उस अंक की एक भी प्रति नहीं रह गयी है जिसमें जेनेवा संघीय कमेटी¹¹⁶ का उत्तर है जो जूरा के लोगों से बीस गुना ज़्यादा मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करती है) तथा «*Volksstaat*» की एक प्रति भेजी थी जिससे आपको पता चलेगा कि इस मामले के बारे में जर्मन क्या सोचते हैं। सैक्सन कांग्रेस ने—६० इलाकों के १२० डेलीगेटों ने—सर्वसम्मति से घोषित किया कि वह जनरल कौंसिल के

* देखें प्रस्तुत खण्ड।—सं०

** २२ जनवरी।—सं०

हेपनर नहीं, बल्कि हेपनर के नाम यार्क के ख़त से जिस पर समिति के दस्तख़त हैं, हम लोगों को यह आशंका हुई कि तुम्हारे कारावास को पार्टी के अधिकारीगण, जो दुर्भाग्यवश सब के सब लासालपंथी हैं, «*Volksstaat*» को एक “सच्चे” «*Neuer Social-Demokrat*» बना डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यार्क ने तो साफ़-साफ़ क़बूल किया कि उनका यही इरादा था। और चूँकि समिति का दावा था कि सम्पादकों को नियुक्त करने और हटाने का उसे अधिकार है, इसलिए ख़तरा सचमुच काफ़ी बड़ा था। हेपनर के आसन्न निर्वासन से ये योजनायें और भी मज़बूत होती थीं। इस सूरत में हमारे लिए यह जानना परमावश्यक था कि स्थिति क्या है। यह चिट्ठी-पत्नी इसी लिए की जा रही है...

जहां तक लासालपंथियों के प्रति पार्टी के ख़ूब का सवाल है, तुम हम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से विचार कर सकते हो कि ख़ास-ख़ास मामलों में कौनसी कार्यनीति अपनानी चाहिए। लेकिन विचारने की बात यह भी है कि जब कोई तुम्हारी तरह एक हद तक आम जर्मन मज़दूर संघ के प्रतियोगी की स्थिति में हो तो वह बड़ी आसानी से अपने प्रतिद्वन्द्वी का बहुत ज्यादा लिहाज़ करने लगता है और इसकी आदत पड़ जाती है कि हमेशा सबसे पहले उसकी ही बात सोचे। लेकिन आम जर्मन मज़दूर संघ और सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी, ये दोनों ही अभी जर्मन मज़दूर वर्ग के अत्यन्त अल्पसंख्यक भाग हैं। हमारी राय (दीर्घ-कालीन व्यवहार द्वारा उसकी पुष्टि हो चुकी है) यह है कि प्रचार क्षेत्र में सही कार्यनीति यह है कि अपने विरोधियों में से अलग-अलग व्यक्तियों और जहां-तहां से कुछ सदस्यों को फुसलाकर साथ नहीं लाना चाहिए, बल्कि अभी तक निष्क्रिय आम जनसमुदाय के बीच काम करना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की अपरिष्कृत शक्ति, जिसे हमने ख़ुद आरम्भ से ही प्रशिक्षित करके तैयार किया है, दस लासालपंथी रंगे सियारों से ज्यादा मूल्यवान है, जो हमेशा अपने साथ पार्टी में ग़लत प्रवृत्तियों के बीज लेकर आते हैं। और अगर कहीं हमें आम जनता अपने स्थानीय नेताओं के बिना मिल सके, तो वह भी ठीक है। पर होता यह है कि हमें साथ ही साथ इन नेताओं की एक पूरी जमात को भी लेना पड़ता है। वे अपने भूतपूर्व विचारों से नहीं तो अपने भूतपूर्व सार्वजनिक वक्तव्यों से तो बंधे ही होते हैं, और वे यह साबित करने की सबसे ज्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमने अपने पुराने सिद्धान्तों का परित्याग नहीं किया है, बल्कि उलटे सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी सच्चे लासालपंथ का प्रचार करती है। आइज़ेनाख़¹¹⁹ में दुर्भाग्य से यही बात हुई गोकि सम्भवतः उस समय उससे बचा नहीं जा सकता था। लेकिन

इसमें ज़रा भी शक नहीं कि इन तत्त्वों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। मैं विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकता कि ये लोग पार्टी में अगर न आये होते तो पार्टी आज कम से कम उतनी हूी ताक़तवर न रहती जितनी कि वह है। जो भी हो, अगर इन तत्त्वों को नयी कुमक हासिल हुई तो मैं इसे दुर्भाग्य की बात समझूंगा।

“एकता” के नारे से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की ज़बान से यह शब्द सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, वे ही सबसे ज़्यादा फूट के बीज बो रहे हैं। उदाहरण के लिए, सारी फूटों को उकसानेवाले, स्विट्ज़रलैंड ज़ूरा के बकूनिनपंथी ही सबसे ज़्यादा एकता की गुहार कर रहे हैं। एकता की रट लगानेवाले ये जिहादी या तो ऐसे कम अक्ल लोग हैं जो सभी चीज़ों को एक ही हांडी में मिलाकर उसका एक बंदरंग झोल तैयार करना चाहते हैं, ऐसा झोल जो जहाँ वह बैठना शुरू हुआ नहीं कि अपना सारा अलगाव प्रगट कर देगा और ज़्यादा तीखेपन के साथ प्रगट कर देगा क्योंकि तब सब कुछ एक ही बर्तन के अन्दर होगा (इराकी बढ़िया मिसाल जर्मनी में वे लोग उपस्थित करते हैं जो मजदूरों और निम्नपूँजीपतियों के मेल-मिलाप की बातें करते हैं)। या ऐसे लोग एकता की रट लगाते हैं जो बिना जाने-बूझे (उदाहरणार्थ म्यूलबर्गर जैसे लोग) या जान-बूझकर आन्दोलन की विशुद्धता नष्ट करना चाहते हैं। इसी लिए सबसे बड़े संकीर्णतावादी और सबसे बड़े गुल-गपाड़िये तथा बदमाश कुछ ख़ास मौकों पर सबसे ज़्यादा गला फाड़कर एकता की दुहाई देते हैं। हमें अपनी जिन्दगी में एकता की गुहार मचानेवालों से ज़्यादा किसी ने परेशान नहीं किया है और न कोई इनसे ज़्यादा धोखेबाज़ निकला है।

स्वभावतः पार्टी का हर नेतृत्व सफलताएं चाहता है। और यह बहुत अच्छी चीज़ भी है। पर ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जब यह ज़रूरी हो जाता है कि अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए तात्कालिक सफलता निछावर कर देने का साहस दिखाया जाये। ख़ासकर यह हमारी जैसी पार्टी के लिए ज़रूरी है जिसकी अन्तिम सफलता परम सुनिश्चित है और जिसने अपने जीवनकाल में और हमारे देखते-देखते इतनी ज़बर्दस्त प्रगति की है; उसके लिए सदा ही और अनिवार्य तात्कालिक सफलता की कोई ज़रूरत नहीं है, उदाहरण के लिए इंटरनेशनल को ही लें। कम्यून के बाद उसे विपुल सफलता प्राप्त हुई। पूँजीपति वर्ग, जिसे लकवा मार गया था, उसे सर्वशक्तिमान मानने लगा था। इंटरनेशनल के सदस्यों की बहुत बड़ी संख्या विश्वास करने लगी थी कि यह अवस्था चिरकाल तक कायम

रहेगी। पर हम अच्छी तरह जानते थे कि बुलबुला जरूर फूटेगा। सभी ऐरे-गैरे-नत्थू-खैरे उसके साथ हो लिये थे। उसके अन्दर बैठे संकीर्णतावादियों की बन आयी। इस आशा से कि उन्हें नीच से नीच और मूर्खतापूर्ण से मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की इजाजत है, वे इंटरनेशनल का दुरुपयोग करने लगे। हमने यह नहीं होने दिया। हम बखूबी जानते थे कि बुलबुला एक दिन जरूर फूटेगा। इसलिए हमने इस बात की फ़िक्र नहीं की कि आफ़त टली रहे, बल्कि इस बात का ख़याल रखा कि इंटरनेशनल जब संकट से बाहर निकले, वह खरा, बेदाग़ हो और उसमें कहीं मिलावट न हो। हेग में बुलबुला फूटा और तुम जानते ही हो कि कांग्रेस के अधिकांश प्रतिनिधि निराश और पस्त होकर घर लौटे थे। और फिर भी इंटरनेशनल में विश्व बन्धुत्व और मेल-मिलाप का आदर्श पाने की कल्पना करनेवाले प्रायः इन सभी निराश लोगों के अपने घर में जो झगड़े थे वे हेग में हुए झगड़े से कहीं ज़्यादा कटुतापूर्ण थे! अब संकीर्णतावादी झगड़ेबाज़ मेल-मिलाप के उपदेश दे रहे हैं और हम लोगों पर कलहप्रिय और तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं! पर अगर हमने हेग में समझौते का रास्ता अपनाया होता, फूट दबा दी होती और फूट न पड़ने दी होती तो परिणाम क्या होता? संकीर्णतावादी, खासकर बकूनिनपंथी, एक वर्ष और पा जाते जिसमें वे इंटरनेशनल के नाम पर और भी बड़ी-बड़ी मूर्खताएं और कलंकपूर्ण कृत्य करते। सबसे विकसित देशों के मज़दूर उकताकर विमुख हो जाते। बुलबुला फूटता नहीं, बल्कि हलकी-हलकी खरोचें खाकर धीरे-धीरे पिचकता और अगली कांग्रेस, जिसमें संकट का सामना आना प्रत्येक दशा में अनिवार्य था, निकृष्टतम वैयक्तिक दंगों और फ़साद का अखाड़ा बनकर रह जाती, क्योंकि सिद्धान्त की तो हेग में ही कुरबानी दी जा चुकी होती! तब इंटरनेशनल सचमुच टुकड़े-टुकड़े हो जाता—“एकता” के कारण टुकड़े-टुकड़े हो जाता! इसके बदले, हमने ससम्मान सड़े-गले तत्त्वों से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। (अन्तिम और निर्णायक अधिवेशन में मौजूद कम्यून के सदस्यों का कहना है कि यूरोप के सर्वहारा वर्ग के इन ग़द्दारों का फ़ैसला सुनानेवाली कचहरी के अधिवेशन ने जितना ज़बर्दस्त असर उनके ऊपर डाला, उतना कम्यून के किसी अधिवेशन ने नहीं डाला था।) दस महीनों तक हमने उन्हें झूठ, कुत्सा एवं षड्यंत्रों में अपनी शक्ति व्यय करने दी, और आज कहाँ हैं वे? इंटरनेशनल के विशाल बहुमत के ये तथाकथित प्रतिनिधि आज स्वयं ऐलान करते हैं कि अगली कांग्रेस में आने की उनकी हिम्मत नहीं है (और तफ़्सीलें

«*Volksstaat*»* के लिए एक लेख में हैं जो इस चिट्ठी के साथ भेजा जा रहा है)। और अगर हमें यह काम दोबारा करना हो तो कुल मिलाकर, हम इससे भिन्न मार्ग नहीं अपनायेंगे। वेशक, कार्यनीतिक भूलें सदा होती ही रहती हैं।

जो भी हो, मेरा खयाल है कि लासालपंथियों के कार्यकुशल तत्त्व समय आने पर आप ही तुम्हारी ओर उन्मुख होंगे। इसलिए पकने के पहले ही फल को तोड़ लेना, जैसा कि एकतावादी चाहते हैं, बुद्धिमानी नहीं होगी।

वैसे तो वृद्ध हेगेल पहले ही फ़रमा चुके हैं : जो पार्टी अपने में फूट के लिए तैयार हो और उस फूट को झेल सके, वह यह सिद्ध करती है कि वह जीवनक्षम पार्टी है। सर्वहारा का आन्दोलन अनिवार्यतः विकास की विभिन्न मंजिलों से होकर गुजरता है। हर मंजिल में चलनेवालों का एक हिस्सा फंसकर रह जाता है और आगे बढ़ने में साथ नहीं देता। यही वजह है कि “सर्वहारा की एकता” एक दूसरे के विरुद्ध जीवन-मरण के संघर्ष (जैसा संघर्ष रोमन साम्राज्य में, घनघोर दमन के बीच, ईसाई पंथों के बीच चला करता था) में रत विभिन्न पार्टी दलों में सब जगह सचमुच निष्पन्न हो रही है।

तुम्हें यह भी हरगिज़ न भूलना चाहिए कि «*Neuer Social-Demokrat*» के ग्राहकों की संख्या «*Volksstaat*» के ग्राहकों से यदि अधिक है तो इसका कारण यह है कि प्रत्येक पंथ अनिवार्यतः अपने मत का दीवाना होता है और इसकी बदौलत, खासकर उन इलाकों में जहां वह नवोदित है—मसलन् श्लेज़विग-होल्स्टिन में आम जर्मन मजदूर संघ—पार्टी से (जो संकीर्णतावादी सनकों से मुक्त वास्तविक आन्दोलन का ही प्रतिनिधित्व करती है) अधिक तात्कालिक सफलताएं प्राप्त करता है। पर दूसरी ओर, दीवानापन बहुत दिन नहीं चलता।

पत्र ख़त्म करना है, क्योंकि डाक छूटनेवाली है। जल्दी में इतना और जोड़ दूं—मार्क्स फ़्रांसीसी अनुवाद** के समाप्त होने तक (यानी लगभग जुलाई के अंत तक) लासाल¹²⁰ के साथ नहीं उलझ सकते, अलावा इसके बहुत ज्यादा मेहनत करने की वजह से उन्हें आराम की सख़्त ज़रूरत है...

अंग्रेज़ी से अनूदित।

* फ़्रे० एंगेल्स, 'इंटरनेशनल में'।—सं०

** इशारा 'पूँजी' के पहले खंड की ओर है।—सं०

फ्रेडरिक अडोल्फ ज़ोर्गे के नाम एंगेल्स का पत्र

होबोकेन में

लन्दन, सितम्बर १२ [-१७] १८७४

...आपके इस्तीफे के साथ¹²¹ पुराने इंटरनेशनल का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया है। और यह अच्छा ही हुआ। वह दूसरे साम्राज्य के ज़माने का था जब सारे यूरोप में राज कर रहा उत्पीड़न मजदूर आन्दोलन को, जो उस समय जग ही रहा था, एकता तथा सारे आन्तरिक वाद-विवाद से विरति की आज्ञा दे रहा था। यह वह घड़ी थी जब सर्वहारा के साझे अन्तर्राष्ट्रीय हित उभरकर सामने आ रहे थे। जर्मनी, स्पेन, इटली तथा डेनमार्क आन्दोलन में अभी-अभी शामिल हुए थे या उसमें शामिल हो रहे थे। दसअसल १८६४ में आन्दोलन का सैद्धांतिक स्वरूप यूरोप में अभी सर्वत्र, अर्थात् जनसाधारण के बीच बहुत अस्पष्ट था। जर्मन कम्युनिज्म ने अभी मजदूर पार्टी के रूप में अस्तित्व ग्रहण नहीं किया था। प्रदोपंथ अभी इतना कमजोर था कि वह अपना सिक्का नहीं जमा सकता था, बकूनिन की नयी वक्तास ने अभी उसके सिर के अन्दर जन्म नहीं लिया था; ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों के नेता तक यह सोचते थे कि नियमावली की भूमिका* में निर्धारित कार्यक्रम उन्हें आन्दोलन में प्रवेश करने का आधार प्रदान करता है। प्रथम बड़ी सफलता तमाम गुटों के इस भोलेपन भरे सहयोग को अवश्यम्भावी रूप से ध्वस्त करती। यह सफलता कम्यून थी जो निस्सन्देह बौद्धिक रूप से इंटरनेशनल की संतान थी हालांकि उसे जन्म देने के लिए इंटरनेशनल ने उंगली तक नहीं हिलायी थी और इसके लिए इंटरनेशनल को कुछ हद तक सही उत्तरदायी ठहराया गया। जब कम्यून की वदौलत इंटरनेशनल यूरोप में नैतिक शक्ति बन गया, तुरन्त टुच्ची साजिशें शुरू हो गयीं। हर धारा इस सफलता को अपने हितार्थ इस्तेमाल करना चाहती थी। विघटन, जो अवश्यम्भावी था, शुरू हो गया। एकमात्र लोगों से, जो सचमुच पुराने व्यापक कार्यक्रम के आधार पर कार्य करने के लिए तैयार थे, जर्मन कम्युनिस्टों से, ईर्ष्या ने बेल्जियाई प्रदोपंथियों को बकूनिनपंथी दुस्साहसियों की बांहों में पहुंचा

* देखें प्रस्तुत संस्करण, खण्ड २, भाग १ - सं०

दिया। हेग कांग्रेस वस्तुतः दोनों पार्टियों की खात्मा थी। जिस एकमात्र देश में इंटरनेशनल के नाम पर अब भी कुछ किया जा सकता था, वह अमरीका था, और कार्यकारिणी समिति वहीं स्थानान्तरित कर दी गयी थी जो सुखद सहज-बुद्धि का फल थी। अब वहां भी उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी है और उसमें फिर से नया जीवन संचारित करना मूर्खता की बात होगी तथा वक्त जाया करना होगा। इंटरनेशनल दस वर्ष तक यूरोपीय इतिहास के एक पक्ष पर—उस पक्ष पर जिसमें भविष्य अन्तर्निहित है—हावी रहा और वह पीछे मुड़कर अपने कार्य को गर्वपूर्वक देख सकता है। परन्तु अपने पुराने रूप में उसकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। पुराने ढर्रे पर नये इंटरनेशनल की स्थापना, तमाम देशों की सभी सर्वहारा पार्टियों के सहबंध के लिए मजदूर आन्दोलन को इस तरह आम तौर पर दबाना जरूरी होगा जो १८४६-१८६४ में होता रहा। परन्तु इसके लिए सर्वहारा संसार अब अतीव विशाल, अतीव विस्तृत हो चुका है। मेरे विचार में अगला इंटरनेशनल—माक्स की रचनाओं द्वारा कुछ वर्षों तक अपना प्रभाव उत्पन्न किये जाने के बाद—विशुद्ध रूप से कम्युनिस्ट होगा और ठीक हमारे सिद्धांतों की उद्धोषणा करेगा...

अंग्रेजी से अनूदित।

¹ पहले इंटरनेशनल का लन्दन सम्मेलन १७ सितम्बर से लेकर २३ सितम्बर १८७१ तक हुआ। चूँकि वह पेरिस कम्यून की पराजय के बाद इंटरनेशनल के विरुद्ध कठोर दमनात्मक कार्रवाइयों के समय हुआ था, उसकी सदस्य-संख्या बहुत कम थी। उसमें २२ डेलीगेट ऐसे थे जिन्हें वोट देने का अधिकार था तथा १० ऐसे थे जो कार्रवाई में भाग तो ले सकते थे परन्तु वोट नहीं दे सकते थे। जो देश अपने डेलीगेट नहीं भेज सके, उनका प्रतिनिधित्व जनरल काँसिल के सहयोगी सचिवों ने किया। मार्क्स ने जर्मनी तथा एंगेल्स ने इटली का प्रतिनिधित्व किया।

लन्दन सम्मेलन मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा सर्वहारा पार्टी की स्थापना के लिये किये जानेवाले संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मंजिल थी। उसने 'मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्रिया के बारे में' एक प्रस्ताव पास किया जिसका मुख्य भाग इंटरनेशनल की हेग कांग्रेस के निर्णय पर अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की नियमावली में शामिल कर लिया गया। सम्मेलन के कई प्रस्तावों में सर्वहारा पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक तथा संगठनात्मक सिद्धांतों का निरूपण किया गया जिन्होंने संकीर्णतावाद तथा सुधारवाद पर कड़ा प्रहार किया।—पृ० ६

² १९ वीं शताब्दी के छठे दशक से अंग्रेज मजदूरों की एक बुनियादी मांग थी नौ घंटे का कार्य-दिवस चालू किया जाना। मई १८७१ में भवन-निर्माण मजदूरों तथा इंजीनियरी मजदूरों की न्यूकैसल में एक बहुत बड़ी हड़ताल शुरू हुई। उसकी अगुवाई नौ घंटे के कार्य-दिवस के लिए संघर्ष करनेवाली लीग कर रही

थी। यह लीग उन मजदूरों को पहली बार संघर्ष में ले आयी जो ट्रेड यूनियनों में नहीं थे। लीग के अध्यक्ष बार्नेट ने इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के नाम एक पत्र भेजा जिसमें उससे अनुरोध किया गया कि वह हड़तालतोड़कों को इंग्लैंड लाये जाने से रोके। जनरल कौंसिल की सक्रिय गतिविधियों के फलस्वरूप यह अनुरोध पूरा हुआ। अक्टूबर १८७१ में हड़ताल सफल हो गयी। मजदूरों के लिए ५४ घंटे का कार्य-सप्ताह स्वीकार कर लिया गया।—पृ० १२

^३ २५ जुलाई १८७१ को जनरल कौंसिल में एंगेल्स का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि सितम्बर १८७१ में इंटरनेशनल का एक गुप्त सम्मेलन लन्दन में आयोजित किया जाये। उस समय से मार्क्स तथा एंगेल्स ने सम्मेलन के लिए जोरदार ढंग से संगठनात्मक और सैद्धांतिक तैयारियाँ आरम्भ कर दीं। उन्होंने कार्यसूची तथा प्रस्तावों के मसौदे तैयार किये। उन पर पहले जनरल कौंसिल की बैठकों में विचार किया गया और फिर उन्हें लन्दन सम्मेलन में पेश किया गया (सम्मेलन के बारे में टिप्पणी १ पढ़ें)।—पृ० १३

^४ पहले इंटरनेशनल की बाजेल कांग्रेस ६-११ सितम्बर १८६९ तक हुई।—पृ० १३

^५ फ्रांस-प्रशा युद्ध १८७०-१८७१ में हुआ और उसमें फ्रांस की पराजय हुई।—पृ० १३

^६ यहां इशारा २५-२६ सितम्बर १८६५ तक हुए पहले लन्दन सम्मेलन की ओर है जिसने इंटरनेशनल की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की।—पृ० १३

^७ “देहातियों की सभा”—१८७१ की राष्ट्रीय सभा को दिया गया लक्रव; उस समय सभा का अधिवेशन बोर्दो नगर में हुआ करता था और उसके अधिकांश सदस्य प्रतिक्रियावादी राजतंत्रवादी—देहाती इलाकों से चुने गये ज़मींदार, अफसर, लगानजीवी और व्यापारी थे। सभा के ६३० प्रतिनिधियों में ४३० राजतंत्रवादी थे।—पृ० १३

^८ वेसई—पेरिस का उपनगर जहां पेरिस कम्यून के समय फ्रांसीसी प्रतिक्रान्तिकारी सरकार थी। यह शब्द प्रतिक्रान्ति का पर्याय बन गया।—पृ० १४

^९ लन्दन सम्मेलन ने मार्क्स के प्रस्ताव पर जनरल कौंसिल को इंग्लैंड के लिए एक फ़ेडरल कौंसिल स्थापित करने का आदेश दिया क्योंकि १८७१ के ग्रीष्म काल तक जनरल कौंसिल स्वयं इस प्रकार की कौंसिल का काम करती रही।

अक्तूबर १८७१ में इंटरनेशनल की अंग्रेज़ शाखाओं के प्रतिनिधियों को लेकर ब्रिटिश फ़ेडरल कौंसिल की स्थापना की गयी। परन्तु शुरू से ही हेल्स की अगुवाई में सुधारवादियों का एक दल कौंसिल के नेतृत्व में घुस आया और उसने जनरल कौंसिल तथा आयरिश प्रश्न के सम्बन्ध में उसकी सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रीयतावादी नीति के विरुद्ध एक अभियान शुरू कर दिया। हेल्स तथा अन्य सुधारवादियों ने इस संघर्ष में स्विस् अराजकतावादियों, अमरीकी पूँजीवादी सुधारवादियों, आदि के साथ मिलकर काम किया। १८७२ की हेग कांग्रेस के बाद ब्रिटिश फ़ेडरल कौंसिल के इस सुधारवादी भाग ने कांग्रेस के निर्णयों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया तथा उसने बकूनिनपंथियों से मिलकर जनरल कौंसिल तथा मार्क्स के विरुद्ध कुत्सापूर्ण अभियान छेड़ दिया। ब्रिटिश कौंसिल के अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया और मार्क्स तथा एंगेल्स का सक्रिय समर्थन किया। दिसम्बर १८७२ के आरम्भ में फ़ेडरल कौंसिल में फूट पड़ गयी; कौंसिल के कुछ सदस्यों ने, जो हेग कांग्रेस के फ़ैसलों के प्रति निष्ठावान थे, ब्रिटिश फ़ेडरल कौंसिल गठित की तथा जनरल कौंसिल के साथ, जिसे न्यूयार्क में स्थानान्तरित कर दिया गया था, सीधा सम्बन्ध स्थापित किया। इंटरनेशनल के ब्रिटिश फ़ेडरेशन का नेतृत्व हथियाने की सुधारवादियों की कोशिश इस तरह विफल हो गयी।

ब्रिटिश फ़ेडरल कौंसिल वस्तुतः १८७४ तक क्रायम रही। उसकी गतिविधियाँ इंटरनेशनल की गतिविधियों की समाप्ति तथा ब्रिटिश मजदूर आन्दोलन में अवसरवाद की अस्थायी विजय के साथ ख़त्म हो गयी।—पृ० १४

¹⁰ «The Times»—अनुदारपंथी दृष्टिकोण का प्रमुख ब्रिटिश दैनिक जिसका प्रकाशन १७८५ से लन्दन में आरम्भ हुआ था।—पृ० १५

¹¹ यहां इशारा १८७१ के दूसरे लन्दन सम्मेलन के प्रस्ताव—‘नेशनल कौंसिलों के नाम, आदि के सम्बन्ध में’—की ओर है जिसने इंटरनेशनल में विभिन्न संकीर्णतावादी दलों के प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी।—पृ० १५

¹² यहां इशारा बकूनिन के ‘रूसी, पोलिश तथा तमाम स्लाव भित्तों के नाम’ शीर्षक घोषणापत्र की ओर है जो ‘कोलोकोल’ (घंटा) में (अंक १२२—१२३, १५ फ़रवरी १८६२) परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ था।

‘कोलोकोल’—रूसी क्रान्तिकारी-जनवादी अख़बार जिसे हर्ज़ेन तथा ओगार्योव १८५७—१८६७ तक रूसी में तथा १८६८—१८६९ तक रूसी परिशिष्टों

के साथ फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित करते रहे ; १८६५ तक लन्दन और उसके बाद जेनेवा में प्रकाशित हुआ ।—पृ० १५

13 शान्ति तथा स्वतंत्रता लीग पूंजीवादी-शान्तिवादी संस्था जिसे १८६७ में विभिन्न निम्न-पूंजीवादी तथा पूंजीवादी जनतंत्रवादियों और उदारतावादियों ने स्विट्ज़रलैंड में स्थापित किया था ।—पृ० १५

14 यहां इशारा सितम्बर १८६८ में शान्ति तथा स्वतंत्रता लीग की बर्न में हुई कांग्रेस में बकूनिन द्वारा अपने खिचड़ीनुमा समाजवादी कार्यक्रम को (“वर्गों का सामाजिक तथा आर्थिक समताकरण”, राज्य और उत्तराधिकार का उन्मूलन, आदि) अनुमोदित कराने की ओर है। जब उनका प्रस्ताव बहुमत से ठुकरा दिया गया तो वह लीग से अलग हो गये और उन्होंने समाजवादी जनवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सहबंध की स्थापना की ।—पृ० १६

15 पहले इंटरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस ३-८ सितम्बर १८६६ तक हुई। लोजांस कांग्रेस २-८ सितम्बर १८६७ तक हुई ।—पृ० १७

16 नेचायेव का मुकदमा—गुप्त क्रान्तिकारी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छात्रों पर जुलाई-अगस्त १८७१ में चलाया गया मुकदमा। १८६९ में ही नेचायेव ने बकूनिन के साथ सम्बन्ध कायम कर लिये थे और ऐसी गतिविधियां तेज कर दी थीं जिनका उद्देश्य अनेक रूसी नगरों में “आमूलचूल विनाश” के अराजकतावादी विचारों का प्रचार करनेवाले “जन-प्रतिकार” नामक एक षड्यंत्रकारी संगठन की स्थापना करना था। क्रान्तिकारी विचारों वाले छात्र तथा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी नेचायेव के संगठन में शामिल हो गये क्योंकि वे ज़ारशाही हुकूमत की उस द्वारा की जानेवाली तीक्ष्ण आलोचना तथा उसके विरुद्ध डटकर संघर्ष करने की अपीलों के कारण उसकी ओर आकृष्ट हुए थे। नेचायेव को बकूनिन से “यूरोपीय क्रान्तिकारी संघ” के प्रतिनिधि का प्रमाण-पत्र मिल गया था। उसके बल पर वह अपने को इंटरनेशनल का प्रतिनिधि बताता रहा और इस तरह अपने संगठन के सदस्यों को गुमराह करता रहा। १८७१ में नेचायेव संगठन भंग हो गया तथा मुकदमे के दौरान उसकी दुस्साहसिकतावादी विधियां प्रकाश में आयीं।

लन्दन सम्मेलन ने उतिन को नेचायेव मुकदमे के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। इस तरह की रिपोर्ट के स्थान पर उतिन

ने १८७२ के अगस्त माह के अन्त में मार्क्स को इंटरनेशनल की हेग कांग्रेस के लिए बकूनिन तथा नेचायेव की इंटरनेशनलविरोधी गतिविधियों के बारे में एक विस्तृत गोपनीय रिपोर्ट भेजी।—पृ० २१

¹⁷ «*Le Progrès*» (प्रगति) — बकूनिनपंथी अखबार जो फ्रांसीसी भाषा में दिसम्बर १८६८ से अप्रैल १८७० तक गिलोम के सम्पादकत्व में लोकले में प्रकाशित होता रहा।—पृ० २१

¹⁸ «*L'Égalité*» (समानता) — स्विस् साप्ताहिक, इंटरनेशनल के रोमांस फ्रेडरेशन का मुखपत्र, जो जेनेवा में दिसम्बर १८६८ से दिसम्बर १८७२ तक फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित होता रहा। कुछ समय तक वह बकूनिन के प्रभाव में भी था। जनवरी १८७० में रोमांस फ्रेडरल कौंसिल बकूनिनपंथियों को सम्पादकमंडल से हटाने में सफल हो गयी। उसके बाद पत्र इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल की नीति का समर्थन करने लगा।—पृ० २१

¹⁹ «*Le Travail*» (श्रम) — इंटरनेशनल की पेरिस शाखाओं का साप्ताहिक पत्र; ३ अक्टूबर से १२ दिसम्बर १८६९ तक पेरिस में प्रकाशित होता रहा।—पृ० २२

²⁰ सामन्ती अभिजातों की इस संस्था की फ्रांस में १४६४ के अन्त में स्थापना हुई थी। उसने फ्रांस को एक केन्द्रीकृत राज्य में ऐक्यवद्ध करने की लूई ११ वें की नीति का विरोध किया। लीग के सदस्य फ्रांस के “सार्वजनिक कल्याण” के लिए काम करते रहे।—पृ० २२

²¹ «*Le Solidarite*» (एकता) — बकूनिनपंथी साप्ताहिक पत्र; फ्रांसीसी भाषा में अप्रैल से सितम्बर १८७० तक नेवशातेल में तथा मार्च से मई १८७१ तक जेनेवा में प्रकाशित होता रहा।—पृ० २३

²² जेनेवा तथा उसके आस-पास के इलाकों में बड़े तथा छोटे वर्कशापों में घड़ियां तथा जेवर बनानेवाले कारखानों को इसी नाम से पुकारा जाता था। इन वस्तुओं को घर पर बनानेवालों को भी इस नाम से पुकारा जाता था।—पृ० २३

²³ २ सितम्बर १८७० को सेदान की लड़ाई में फ्रांसीसी सेना, जिसकी कमान नेपोलियन तृतीय के हाथ में थी, प्रशियाई सेना द्वारा पराजित हुई और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सम्राट नेपोलियन तृतीय तथा सेनानायक बंदी बना

लिये गये और वे विल्हेल्म्सहोये (कासेल के निकट) में प्रशा के राजाओं के एक दुर्ग में ५ सितम्बर १८७० से १६ मार्च १८७१ तक क़ैद रहे। सेदान की पराजय ने द्वितीय साम्राज्य के पतन को त्वरित किया और उसके फलस्वरूप ४ सितम्बर १८७० को फ़्रांस में जनतंत्र की घोषणा की गयी। एक नई सरकार स्थापित हुई जिसे “राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की सरकार” नाम दिया गया। — पृ० २४

²⁴ यहां इशारा ‘इंटरनेशनल की शाखाओं के नाम’ ५ सितम्बर १८७० के उस घोषणापत्र की ओर है जिसे जेम्स गिलोम तथा गास्पर ब्लां ने लिखा था और जो नेवशातेल में «Solidarité» अख़बार के अंक २२ के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित हुआ था। — पृ० २४

²⁵ **लियों में विद्रोह** ४ सितम्बर १८७० को सेदान में पराजय की ख़बर मिलने के बाद शुरू हुआ था। १५ सितम्बर को बकूनिन लियों पहुँचे और उन्होंने आन्दोलन के नेतृत्व की वागडोर अपने हाथ में लेने तथा अपने अराजकतावादी कार्यक्रम को असल में लाने का प्रयत्न किया। उनके अनुयायियों ने २८ सितम्बर को राज्य-पर्युत्क्षेपण करने का यत्न किया। मजदूरों का समर्थन न मिलने तथा कार्रवाई की कोई निश्चित योजना पास न होने के कारण उनका प्रयत्न विफल हो गया। — पृ० २४

²⁶ अप्रैल १८७० में बकूनिन के एक अनुयायी पाल राबिन ने पेरिस फ़ेडरल कौंसिल को सुझाव दिया कि शो-द-फ़ोन में अराजकतावादियों की कांग्रेस द्वारा स्थापित फ़ेडरल कमेटी को रोमांस फ़ेडरल कमेटी के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। जनरल कौंसिल द्वारा पेरिस फ़ेडरल कौंसिल के सदस्यों को स्विट्ज़रलैंड में फूट का अर्थ समझा दिये जाने के बाद फ़ेडरल कौंसिल ने तय किया कि उमे मामले में दख़ल देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह मामला जनरल कौंसिल के कार्य-क्षेत्र में आ जाता है। — पृ० २६

²⁷ B. Malon, «La troisième défaite du prolétariat français», (ब० मालोन, ‘फ़्रांसीसी सर्वहारा की तीसरी पराजय’, नेवशातेल, १८७१)। — पृ० २६

²⁸ यहां इशारा १८७१ के पेरिस कम्यून की ओर है। — पृ० २६

²⁹ इस शाखा की स्थापना ६ सितम्बर १८७१ को जेनेवा शाखा के स्थान पर की गयी थी जिसे “समाजवादी जनवाद का सहबंध” के नाम से पुकारा जाता था और जिसे अगस्त में भंग कर दिया गया था। इस शाखा के भूतपूर्व सदस्य जुकोव्स्की, पेरो, आदि के अलावा ज० गेद तथा ब० मालोन जैसे कुछ फ्रांसीसी उत्प्रवासियों ने “समाजवादी क्रान्तिकारी प्रचार तथा कार्रवाई शाखा” संगठित करने में भाग लिया।—पृ० २७

³⁰ «*La Révolution Sociale*» (सामाजिक क्रान्ति)—जेनेवा में अक्तूबर १८७१ से जनवरी १८७२ तक प्रकाशित फ्रांसीसी साप्ताहिक; नवम्बर १८७१ से अराजकतावादी जूरा फ़ेडरेशन का मुखपत्र।—पृ० २७

³¹ «*Le Figaro*» (फ़िगारो)—पेरिस में १८५४ से प्रकाशित होनेवाला प्रतिक्रियावादी फ्रांसीसी अखबार, दूसरे साम्राज्य की सरकार से सम्बन्धित।
«*Le Gaulois*» (गाल)—अनुदारवादी-राजतन्त्रवादी दृष्टिकोण वाला दैनिक, बड़े पूँजीपति वर्ग तथा अभिजाततन्त्र का मुखपत्र; १८६७ से १९२६ तक पेरिस में प्रकाशित होता रहा।

«*Paris-Journal*» (पेरिस पत्र)—पुलिस से सम्बन्धित प्रतिक्रियावादी दैनिक; आंद्री दे पेन द्वारा पेरिस में १८६८ से १८७४ तक प्रकाशित; वह इंटरनेशनल तथा पेरिस कम्यून पर कीचड़ उछालता था।—पृ० २८

³² नेपोलियन तृतीय ने यह जनमत संग्रह मई १८७० में प्रगटतः इस उद्देश्य से किया था कि साम्राज्य के प्रति आम जनता के दृष्टिकोण की जांच की जा सके। इस जनमत संग्रह में प्रश्न इस रूप में पूछे गये थे कि द्वितीय साम्राज्य की नीति के प्रति विरोध प्रगट करना तब तक असंभव था जब तक कि साथ ही सभी जनवादी सुधारों का विरोध न किया जाये। फ्रांस में पहले इंटरनेशनल की शाखाओं ने इस वाक्छल की कलाई खोल दी और अपने सदस्यों को मतदान से अलग रहने का निर्देश किया। जनमत संग्रह के ठीक पहले पेरिस शाखा के सदस्यों पर नेपोलियन तृतीय के खिलाफ़ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस मिथ्या आरोप का इस्तेमाल कर सरकार ने फ्रांस के विभिन्न नगरों में इंटरनेशनल के सदस्यों के खिलाफ़ जोर-जुल्म का बाकायदा एक जेहाद छेड़ दिया। पेरिस शाखा के सदस्यों पर मुकदमे के दौरान, जो २२ जून से ५ जुलाई १८७० तक चला, षड्यंत्र के आरोप की

जालसाजी का पूरी तरह भंडाफोड़ हुआ। फिर भी इंटरनेशनल के कई सदस्यों को सिर्फ इसलिए सजायें दी गयीं कि वे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य थे। फ्रांस के मजदूर वर्ग ने जन-प्रतिवाद प्रकट करके इस जुल्म का जवाब दिया।—

पृ० २६

- ³³ «*La Marseillaise*» (मासैई का—वामपंथी जनतंत्रवादी दैनिक, जो पेरिस में दिसम्बर १८०६ से सितंबर १८७० तक प्रकाशित होता रहा। इसमें इंटरनेशनल के क्रिया-कलाप के तथा मजदूर आन्दोलन के बारे में सामग्री रहती थी।

«*Le Réveil*» (जागरण)—शार्ल देलेक्लूज द्वारा स्थापित एक वामपंथी जनतंत्रवादी समाचारपत्र, जो पेरिस में जुलाई १८६८ से जनवरी १८७१ तक प्रकाशित होता रहा। इसमें इंटरनेशनल की दस्तावेजें तथा मजदूर आन्दोलन से सम्बन्धित अन्य सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी।—पृ० २६

- ³⁴ «*Journal de Genève national, politique et littéraire*» (जेनेवा का राष्ट्रीय, राजनीतिक तथा साहित्यिक पत्र)—अनुदारपंथी अखबार, १८२६ से प्रकाशित।—पृ० ३६

- ³⁵ यहां इशारा फ्रांसीसी काल्पनिक कम्युनिज्म के अनुयायी काबे की ओर है जिन्होंने “इकारिया की यात्रा” पुस्तक लिखी थी।—पृ० ४२

- ³⁶ चार्टिज्म—१९वीं शताब्दी के चौथे तथा पांचवें दशक में ब्रिटिश मजदूरों का आम क्रान्तिकारी आन्दोलन। १८३८ में चार्टिस्टों ने संसद के सामने पेश करने के लिए एक अर्जी (पीपुल्स चार्टर) तैयार की। उसमें मांग की गयी कि २१ वर्ष से ऊपर के पुरुषों को सार्वजनिक मताधिकार प्रदान किया जाये, गुप्त मतदान की व्यवस्था हो, संसदीय उम्मीदवारों के लिए सांपत्तिक अर्हता खत्म हो, आदि। आन्दोलन बड़े-बड़े प्रदर्शनों तथा सभाओं के साथ शुरू हुआ जिनमें पीपुल्स चार्टर के कार्यान्वयन के लिए संघर्ष का नारा बुलन्द किया गया। २ मई १८४२ को चार्टिस्टों ने संसद को दूसरी अर्जी भेजी जिसमें इस बार कई सामाजिक मांगें (कार्य-दिवस कम करना, अधिक मजदूरी देना, आदि) पेश की गयी थीं। संसद ने अर्जी ठुकरा दी। इसके उत्तर में चार्टिस्टों ने आम हड़ताल संगठित की। १८४८ में उन्होंने तीसरी अर्जी लेकर संसद के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनायी परन्तु सरकार ने सैनिक बुला लिये

तथा प्रदर्शन नहीं होने दिया। अर्जी को ठुकरा दिया गया। १८४८ के बाद चार्टिस्ट आन्दोलन का प्रभाव कम होता चला गया।

चार्टिस्ट आन्दोलन की विफलता का मुख्य कारण सुस्पष्ट कार्यक्रम तथा कार्यनीति और सुसंगत क्रान्तिकारी नेतृत्व का अभाव था। फिर भी चार्टिस्टों का ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास और अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन पर ज़बर्दस्त प्रभाव पड़ा।—पृ० ४२

३७ क्रूरान बिना मुहम्मद—म० अ० वकूनिन।—पृ० ४३

३८ यहां इशारा फ्रांस के राजनयिक प्रतिनिधियों के नाम विदेश मंत्री के ६ जून १८७१ के परिपत्र की ओर है जिसमें जूल फ्रांज़ ने तमाम सरकारों का इंटरनेशनल के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया था। साथ ही ट्रूफोर बिल पर विचार करने के काम में जुटे आयोग की ओर से पेश साकाज़ की रिपोर्ट की ओर भी इशारा है। (देखें टिप्पणी ७)—पृ० ४३

३९ यहां तथा आगे मार्क्स इंटरनेशनल की नियमावली को उद्धृत करते हैं जिसे जेनेवा कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान की थी तथा जो लन्दन में अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई थी «*Rules of the International Working Men's Association*», १८६७)—पृ० ४६

४० यहां एक गलती है। आम नियमावली की धारा ६ १८६६ में इंटरनेशनल की जेनेवा कांग्रेस में स्वीकृत हुई थी। देखें—«*Congrès ouvrier de l'Association Internationale des Travailleurs tenu à Genève du 3 au 8 September 1866*», Genève 1866, p. 13—14 ('जेनेवा में ३-८ सितम्बर १८६६ में हुई अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जेनेवा मजदूर कांग्रेस', जेनेवा, १८६६, पृष्ठ १३-१४)—पृ० ४८

४१ मजदूर फ़ेडरेशन की स्थापना १८७१ के शरदकाल में टूरिन में हुई थी। उस पर माज़िनीपंथियों का प्रभाव था। जनवरी १८७२ में सर्वहारा तत्त्व फ़ेडरेशन से अलग हो गये और उन्होंने "सर्वहारा मुक्ति समाज" की स्थापना की। आगे चलकर उसे एक शाखा के रूप में इंटरनेशनल का सदस्य बना लिया गया। पुलिस का एक भेदिया तेज़ागी फ़रवरी १८७२ तक इस शाखा का प्रधान रहा।

«Il proletario» (सर्वहारा) — टूरिन में १८७२ से १८७४ तक प्रकाशित इतालवी अखबार। वह बकूनिनपंथियों का समर्थन करता था और जनरल कौंसिल तथा लन्दन सम्मेलन के प्रस्तावों का विरोध करता था। — पृ० ४८

⁴² नवम्बर १८७१ में पूंजीवादी जनवादी स्टेफ़ानोनी ने एक “सार्वत्रिक तर्कणावादी संस्था” की स्थापना करने की योजना पेश की। उसका कार्यक्रम पूंजीवादी-जनवादी विचारों तथा निम्न-पूंजीवादी कल्पनावादी समाजवाद (सामाजिक प्रश्न के समाधान के लिए कृषि बस्तियों की स्थापना, आदि) की खिचड़ी था। समाज का उद्देश्य था इंटरनेशनल की ओर से मजदूरों का ध्यान हटाना तथा इटली में उसका प्रभाव घटाना। साथ ही स्टेफ़ानोनी ने “समाजवादी जनवाद सहबंध” के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा की। स्टेफ़ानोनी के असल मन्सूबों और पूंजीवादी जनवादियों के साथ अराजकतावादियों के सीधे सम्बन्धों का पर्दाफाश करनेवाले मार्क्स तथा एंगेल्स के बयानों तथा स्टेफ़ानोनी की योजना के विरुद्ध इतालवी मजदूर आन्दोलन के कुछ नेताओं के वक्तव्यों ने इतालवी मजदूर आन्दोलन पर पूंजीवादी प्रभाव जमाने की स्टेफ़ानोनी की चेष्टाएं विफल बना दीं। — पृ० ५८

⁴³ «Neuer Social-Demokrat» — (नया सामाजिक-जनवादी) बर्लिन में १८७१ से १८७६ तक प्रकाशित होनेवाला जर्मन अखबार; लासालपंथी आम जर्मन मजदूर संघ का मुखपत्र; उसने बकूनिनपंथियों तथा दूसरी सर्वहाराविरोधी प्रवृत्तियों का समर्थन करते हुए इंटरनेशनल तथा जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी के मार्क्सवादी नेताओं के विरुद्ध प्रचार किया। — पृ० ५८

⁴⁴ “सफ़ेद कुर्तधारो” अथवा “सफ़ेद ब्लाउज” — दूसरे साम्राज्य के पुलिस प्रीफ़ेक्ट द्वारा संगठित गिरोह। मजदूर होने का दावा करनेवाले वर्गच्युत तत्वों को लेकर अने ये गिरोह असल मजदूर संगठनों का दमन करने के लिए अधिकारियों को मौका देने के वास्ते उकसावाभरे प्रदर्शन तथा उपद्रव करते थे। — पृ० ५८

⁴⁵ जनरल कौंसिल की २० फ़रवरी १८७२ की बैठक ने लन्दन में १८ मार्च को एक विशाल जन-सभा का आयोजन कर पेरिस कम्यून की पहली वर्षगांठ मनाने के युग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सार्वजनिक सभा नहीं हो सकी क्योंकि

सभा-भवन के मालिक ने ऐन मौके पर सभा-भवन सौंपने से इन्कार कर दिया। फिर भी १८ मार्च को इंटरनेशनल के सदस्यों तथा भूतपूर्व कम्यूनार्डों ने प्रथम सर्वहारा क्रान्ति की जयन्ती मनाने के लिए एक सभा की। उसमें उस विशेष अवसर के लिये मार्क्स द्वारा लिखे गये तीन संक्षिप्त प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।
—पृ० ६४

⁴⁶ 'भूमि का राष्ट्रीयकरण' नामक मार्क्स की पांडुलिपि कृषि प्रश्न पर एक महत्वपूर्ण मार्क्सवादी दस्तावेज है। इसे इंटरनेशनल की मानचेस्टर शाखा में भूमि के राष्ट्रीयकरण-सम्बन्धी प्रश्न पर बहस के सिलसिले में लिखा गया था। ३ मार्च को एंगेल्स के नाम अपनी चिट्ठी में दुपों ने कृषि प्रश्न पर शाखा के सदस्यों में विद्यमान भ्रान्तियों की चर्चा की तथा मार्क्स और एंगेल्स को अपनी भावी रिपोर्ट के पांच सूत्रों पर टिप्पणी करने के लिए कहा ताकि वह शाखा की बैठक से पहले उन्हें ध्यान में रख सकें। मार्क्स ने भूमि के राष्ट्रीयकरण के बारे में अपने विचारों पर पूरी तरह प्रकाश डाला और दुपों ने अपनी रिपोर्ट में उनका पूरा-पूरा उपयोग किया।—पृ० ६६

⁴⁷ अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की हेग कांग्रेस २-७ सितम्बर १८७२ तक हुई। उसमें १५ राष्ट्रीय संगठनों के ६५ डेलीगेटों ने भाग लिया। मार्क्स तथा एंगेल्स ने कांग्रेस की कार्रवाई का संचालन किया। मार्क्स, एंगेल्स तथा उनके अनुयायी मजदूर आन्दोलन में सब तरह के निम्न-पूँजीवादी संकीर्णतावाद के विरुद्ध वर्षों से जो संघर्ष चला रहे थे, वह कांग्रेस में विजय के साथ पूर्ण हुआ। अराजकतावादियों की संकीर्णतावादी गतिविधियों की निन्दा की गयी तथा उनके नेताओं को इंटरनेशनल से निकाल दिया गया। हेग कांग्रेस के निर्णयों ने विभिन्न देशों में मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों की स्थापना का पथ प्रशस्त कर दिया।—पृ० ७०

⁴⁸ यहां इशारा 'मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्रिया के बारे में' शीर्षक प्रस्ताव की ओर है।—पृ० ७०

⁴⁹ यहां इशारा तीन सम्राटों—विल्हेल्म प्रथम, फ्रांज़-जोसेफ़ तथा अलेक्सांद्र द्वितीय—की बर्लिन में सितम्बर १८७२ को हुई मुलाकात की ओर है।—पृ० ७२

⁵⁰ «Der Volksstaat» (लोकराज्य) — जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी

का मुखपत्र, जो लाइपजिग से २ अक्टूबर १८६६ से २६ सितम्बर १८७६ तक निकलता रहा। पत्र का सामान्य निर्देशन विल्हेल्म लीबकनेख्त के हाथों में था तथा अगस्त बेबल उसके मैनेजर थे। मार्क्स तथा एंगेल्स उसके लिए लेख लिखा करते थे तथा उसके सम्पादन में मदद देते थे।—पृ० ७४

⁵¹ १८७०-१८७१ के फ्रांस-प्रशा युद्ध में पराजित होकर फ्रांस ने अल्सास और लोरेन के प्रदेश जर्मनी के हवाले कर दिये और उसे वतौर हरजाने के ५०० करोड़ फ्रांक की रकम भी अदा की।—पृ० ७४

⁵² «Die Wohnungsfrage» (आवास प्रश्न) शीर्षक से म्यूलबर्गर के ६ लेख «Volksstaat» अखबार में ३, ७, १०, १४ और २१ फरवरी तथा ६ मार्च १८७२ को बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित हुए थे। आगे चलकर ये लेख «Die Wohnungsfrage. Eine sociale Skizze». Separat-Abdruck aus dem «Volksstaat» Leipzig, 1872 (आवास प्रश्न। सामाजिक रेखाचित्र) नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुए।—पृ० ७५

⁵³ E. Sax. «Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reformen», Wien, 1869 (ए० जाक्स, 'मेहनतकश वर्गों की आवासीय अवस्थाएं तथा उनका सुधार', वियेना, १८६९)।—पृ० ७५

⁵⁴ एंगेल्स के लेखों का म्यूलबर्गर द्वारा उत्तर २६ अक्टूबर १८७२ को «Volksstaat» में «Zur Wohnungsfrage (Antwort on Friedrich Engels von A. Mülberger)» (आवास प्रश्न के बारे में [फ्रेडरिक एंगेल्स को अ० म्यूलबर्गर का उत्तर]) शीर्षक से प्रकाशित हुआ था।—पृ० ७५

⁵⁵ काटेडेर-समाजवादी—१९वीं सदी के आठवें और दसवें दशक में पूंजीवादी विचारधारा की एक प्रवृत्ति। उसके प्रतिनिधि, मुख्यतया जर्मन विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर थे। वे अपने विश्वविद्यालयीय पीठों (जर्मन भाषा में Katheder) से समाजवाद की आड़ में पूंजीवादी सुधारवाद का प्रचार करते थे। काटेडेर-समाजवादियों का (अ० वागनेर, ग० स्मोल्लेर, ल० ब्रेंटानो, व० जोम्बार्ट, आदि) दावा था कि राज्य अधिवर्गीय संरचना है जो परस्परविरोधी वर्गों में मेल कराने और पूंजीपतियों के हितों को आंच पहुंचाये बिना समाजवाद प्रचलित करने में समर्थ है। उनका उद्देश्य था बीमारी और दुर्घटना की स्थिति

- के लिए बीमा की व्यवस्था कर तथा कारखाना-क़ानून पास कर मज़दूरों की हालत सुधारना। उनका मत था कि सुसंगठित ट्रेड यूनियनों राजनीतिक संघर्ष तथा मज़दूर वर्ग की राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता ख़त्म कर देती हैं।—पृ० ७८
- ⁵⁶ समाजवादविरोधी असाधारण क़ानून जर्मनी में २१ अक्टूबर १८७८ को लागू किया गया। उसके अनुसार सामाजिक-जनवादी पार्टी के सारे संगठनों, आम मज़दूर संगठनों तथा मज़दूरों के अख़बारों पर पाबन्दी लगा दी गयी, समाजवादी साहित्य ज़ब्त किया जाने लगा तथा सामाजिक-जनवादियों को जुल्म का शिकार बनाया गया। आम मज़दूर आन्दोलन के दबाव में यह क़ानून १ अक्टूबर १८९० को रद्द कर दिया गया।—पृ० ७८
- ⁵⁷ यहां इशारा १८८२ के दुर्भिक्ष की ओर है जिसने आइफ़ेल (प्रशा का रेइनी प्रान्त) के किसानों पर भारी विपत्तियां ढायीं।—पृ० ७९
- ⁵⁸ तीसवर्षीय युद्ध (१६१८-१६४८)—प्रोटेस्टेंटों तथा कैथोलिकों के बीच संघर्ष के फलस्वरूप होनेवाला आम यूरोपीय युद्ध। लड़ाई का मुख्य रंगमंच जर्मनी था। वह अत्यधिक फ़ौजी लूटमार तथा युद्धरत शक्तियों की विस्तारवादी आकांक्षाओं का शिकार बना।—पृ० ८०
- ⁵⁹ यहां “क्रान्तियों” से अर्थ १८६६ के आस्ट्रिया-प्रशा युद्ध तथा १८७०-१८७१ के फ़्रांस-प्रशा युद्ध से है जिनके फलस्वरूप प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का “ऊपर से” एकीकरण हुआ।—पृ० ८१
- ⁶⁰ मार्क-प्रणाली—प्राचीन जर्मन समुदाय।—पृ० ८३
- ⁶¹ यहां इशारा पेरिस के मज़दूरों के २३-२६ जून १८४८ के वीरत्वपूर्ण विद्रोह की ओर है जिसे फ़्रांसीसी पूंजीपति वर्ग ने घोर पाशविकता के साथ कुचल दिया था। यह विद्रोह सर्वहारा तथा पूंजीपति वर्ग के बीच पहला महान गृहयुद्ध था।—पृ० ९४
- ⁶² एंगेल्स यहां बाइबल की एक दंतकथा से ली गयी अभिव्यंजना—“मिस्र की मांस की हांडियों”—की ओर व्यंग्यपूर्ण ढंग से इशारा कर रहे हैं। इस दंतकथा के अनुसार मिस्र से यहूदियों के निष्क्रमण के दौरान उनके बीच जो बुज़दिल थे, वे यात्रा की कठिनाइयों और भूख से घबराकर बन्दी-अवस्था के उन दिनों

की कामना करने लगे जब उन्हें कम से कम भरपेट खाना तो मिलता था।—
पृ० ६५

⁶³ एंगेल्स यहां श्रम उत्पादों के न्यायोचित विनिमय के उन तथाकथित बाजारों की ओर इशारा कर रहे हैं जिन्हें इंग्लैंड के विभिन्न नगरों में ओवेनपंथी मजदूर सहकारी सोसायटियों ने स्थापित किया था। इन उत्पादों का वहां श्रम नोटों की मदद से विनिमय होता था जिनके मूल्य की इकाई श्रम का एक घंटा हुआ करती थी। ये उद्यम शीघ्र दिवालिया हो गये।—पृ० १००

⁶⁴ «*La Emancipacion*» (मुक्ति) — स्पेन के मजदूरों का साप्ताहिक जो मैड्रिड में १८७१ से १८७३ तक प्रकाशित होता रहा; इंटरनेशनल की शाखाओं का मुखपत्र; सितम्बर १८७१ से अप्रैल १८७२ तक स्पेनिश फ़ेडरल कौंसिल का मुखपत्र; स्पेन में अराजकतावादी प्रभाव के विरुद्ध संघर्ष करता रहा; १८७२ तथा १८७३ में उसने मार्क्स तथा एंगेल्स की रचनाएं प्रकाशित कीं।—पृ० १०१

⁶⁵ «*Illustrated London News*» — ब्रिटिश साप्ताहिक, १८४२ से निरन्तर प्रकाशित।—पृ० ११२

⁶⁶ «*Über Land und Meer*» (जल-स्थल) — जर्मन सचित्र साप्ताहिक, स्टुटगार्ट में १८५८ से १९२३ तक प्रकाशित।—पृ० ११२

⁶⁷ «*Gartenlaube*» (निकुंज) — जर्मन निम्न-पूँजीवादी साहित्यिक पत्रिका; लाइपज़िग में १८५३ से १९०३ तक तथा बर्लिन में १९०३ से १९४३ तक प्रकाशित।—पृ० ११२

⁶⁸ «*Kladderadatsch*» (क्लद्देरादाच) — एक सचित्र व्यंग्य-साप्ताहिक, जो बर्लिन में १८४८ से निकलना शुरू हुआ।—पृ० ११२

⁶⁹ फ़ूसिलिए अगस्त कुचके — जर्मन कवि गोटेहेल्फ़ होफ़मान का उपनाम, फ़्रांस-प्रशा युद्ध (१८७०-१८७१) के ज़माने के राष्ट्रवादी सैनिक गीत का रचयिता।—पृ० ११२

⁷⁰ «*Le Socialiste*» (समाजवादी) — फ़्रांसीसी साप्ताहिक, मजदूर पार्टी का मुखपत्र (१८८५-१९०२), फ़्रांस की समाजवादी पार्टी का मुखपत्र (१९०२-

१९०५), १९०५ से फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी का मुखपत्र। एंगेल्स इस अखबार के लिए लिखते रहे। गीज़ में वस्ती-सम्बन्धी लेख के लिए पत्र का ३ और २४ जुलाई १८८६ का अंक देखें।—पृ० १२४

⁷¹ «Harmony-Hall»—१८३९ के अंत में अंग्रेज़ कल्पनाविवादी समाजवादियों द्वारा जिनके नेता राबर्ट ओवेन थे, स्थापित कम्युनिस्ट वस्ती। वह १८४५ तक कायम रही।—पृ० १२४

⁷² एंगेल्स यहां वागनेर द्वारा अपनी अनेक पुस्तकों तथा वक्तव्यों में व्यक्त किये गये इस विचार की ओर इशारा कर रहे हैं कि फ्रांस-प्रशा युद्ध के बाद और खास तौर पर ५ अरब के हज़ारों के फलस्वरूप जर्मनी में उत्पन्न होनेवाली स्थिति से मज़दूर वर्ग की हालत सुधरेगी।—पृ० १४५

⁷³ यहां इशारा गास्टेइन में अगस्त १८७१ में तथा ज़ाल्सबर्ग में उसी वर्ष सितम्बर में जर्मन तथा आस्ट्रियाई सम्राटों और उनके चांसलरों के बीच समझौता-वार्ताओं की ओर है। एंगेल्स प्रशियाई राजनीतिक पुलिस के मुखिये श्टिबेर के नाम से इन कांफ्रेंसों को श्टिबेरियाई नाम से पुकारते हैं और इस तरह उनके पुलिस और प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर जोर देते हैं।—पृ० १४५

⁷⁴ देखें हेगेल, 'तर्क विज्ञान', भाग १, अनुभाग २।—पृ० १५२

⁷⁵ यहां इशारा १८७२ के प्रशा के प्रशासनिक सुधार की ओर है जिसने देहात में भूस्वामियों के पैतृक अधिकारों का अन्त कर दिया तथा स्थानीय स्वशासन के कतिपय तत्वों (लैंडराटों के अन्तर्गत ज़िला कौंसिल, समुदायों में निर्वाचित प्रधान, आदि) को प्रचलित किया।—पृ० १६५

⁷⁶ यह एंगेल्स की 'उत्प्रवासी साहित्य' नामक उस लेखमाला का दूसरा लेख है जो जून १८७४ और अप्रैल १८७५ के बीच «Volksstaat» में प्रकाशित हुई थी। फ्रांसीसी समाजवादी आन्दोलन में नयी प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए एंगेल्स ब्लांकीपंथी कम्यून उत्प्रवासियों की उन प्रमुख त्रुटियों को प्रकाश में लाते हैं जो उनकी पुस्तिका «Aux Communeux» (कम्यूनाडों के नाम) में प्रतिबिम्बित हुई थीं। एंगेल्स ने लन्दन में ब्लांकीपंथी उत्प्रवासियों के दृष्टिकोण में काफ़ी प्रगति-वैज्ञानिक कम्युनिज़्म की ओर उनके झुकाव-को लक्षित

किया परन्तु साथ ही उनकी षड्यंत्रकारी कार्यनीति, संकल्पवाद, सर्वहारा के क्रान्तिकारी संघर्ष के दौरान किसी भी समझौते की अस्वीकृति की तीक्ष्ण आलोचना की।—पृ० १८३ ७

77 «*Le Père Duchesne*» (पिता द्युशेन)—पेरिस में १७९० से लेकर १७९४ तक ज० एबेर द्वारा प्रकाशित फ्रांसीसी समाचारपत्र ; शहरों के अर्द्धसर्वहारा जनसाधारण के विचार प्रकट किया करता था।

«*Le Père Duchêne*» (पिता द्युशेन)—पेरिस में ६ मार्च से २१ मई १८७१ तक वेमेश द्वारा प्रकाशित फ्रांसीसी दैनिक ; उसकी नीति ब्लांकीपंथी अखबारों के निकट थी।—पृ० १८६

78 «*Kulturkampf*» (संस्कृति के लिए संघर्ष)—धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के लिए अभियान के झंडे के नीचे विस्मार्क की सरकार द्वारा १९वीं शताब्दी के आठवें दशक में उठाये गये पगों को पूंजीवादी उदारतावादियों द्वारा दिया गया नाम। यह अभियान कैथोलिक चर्च और मध्यमार्गी दल के विरुद्ध लक्षित था जो प्रशा के तथा दक्षिण-पश्चिमी जर्मनी के राज्यों के कैथोलिक प्रदेशों में भूस्वामियों, पूंजीपतियों और कृषक समुदाय के कतिपय भागों की पृथक्तावादी प्रशाविरोधी प्रवृत्तियों का समर्थन कर रहे थे। कैथोलिकविरोधी संघर्ष के बहाने विस्मार्क की सरकार ने प्रशा के चंगुल में फंसनेवाले पोलिश इलाकों में भी राष्ट्रीय उत्पीड़न को तेज कर दिया। इस नीति का लक्ष्य धार्मिक भावनाएं भड़काकर वर्ग-संघर्ष से मजदूरों का ध्यान हटाना भी था। नवें दशक के आरम्भ में मजदूर वर्ग के बढ़ते आन्दोलन को देखते हुए विस्मार्क ने इन कार्रवाइयों के एक अच्छे-खासे हिस्से को तिलांजलि दे दी ताकि प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मजबूत बनाया जा सके।—पृ० १८८

79 'रूस में सामाजिक सम्बन्धों के विषय में' शीर्षक लेख 'उत्प्रवासी साहित्य' नामक लेखमाला का पांचवां लेख है। इस लेख में तथा १८९४ में इसके लिए लिखे गये परिशिष्ट में लेखक ने १९वीं शताब्दी के आठवें दशक के आरम्भ में रूसी नरोद्वाद की, जिसका प्रतिनिधित्व उसके विचारधारात्मक नेता प० लात्रोव तथा प० त्काचोव कर रहे थे, और खासकर नवें तथा दसवें दशक के उदारतावादी नरोद्वाद की मुख्य प्रवृत्तियों की आलोचना की। एंगेल्स इतिहास के प्रति भाववादी, संकल्पवादी दृष्टिकोण को, जो नरोद्वादियों

का अभिलाक्षणिक गुण था, सामाजिक विकास के भौतिक आधार को समझने में उनकी असमर्थता को प्रकाश में लाये। १८६१ के बाद रूस में सामाजिक सम्बन्धों के आम विश्लेषण के आधार पर एंगेल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद का रूस में अधिकाधिक विकास होता जा रहा है और इस कारण देहात में सामुदायिक स्वामित्व विघटित हो रहा है।—पृ० १६२

⁸⁰ यहां तथा अन्यत्र एंगेल्स त्काचोव की पुस्तिका «*Offener Brief an Herrn Friedrich Engels*» (श्री फ्रेडरिक एंगेल्स के नाम खुला पत्र) का हवाला देते हैं जो १८७४ में ज्यूरिख में प्रकाशित हुई थी।—पृ० १६२

⁸¹ यहां एंगेल्स का इशारा हक्स्टहाउजेन की हनोवर तथा बर्लिन में १८४७—१८५२ में तीन भागों में प्रकाशित इस पुस्तक की ओर है—«*Studien über die innern Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Ruslands*» (रूस में जन जीवन के आन्तरिक सम्बन्धों और विशेष रूप से ग्रामीण व्यवस्था की जांच)—पृ० १६६

⁸² जारशाही रूस की आधिकारिक दस्तावेजों में लघु रूस—उक्रेन का पर्याय।—पृ० २००

⁸³ क्रीमियाई युद्ध (१८५३—१८५६)—निकट पूर्व पर प्रभाव हासिल करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की तथा सार्डिनिया के सहबंध और रूस के बीच युद्ध। युद्ध का केन्द्रबिन्दु क्रीमिया था। इसमें रूस की पराजय हुई।—पृ० २१४

⁸⁴ यहां इशारा 'वेस्तनिक येन्नोपी' (यूरोप का संदेशवाहक) पत्रिका की पुस्तक ६, १८७७, में यू० ग० जुकोव्स्की के 'कार्ल मार्क्स तथा पूंजी पर उनकी पुस्तक' शीर्षक लेख तथा 'ओतेचेस्त्वेन्निये जपीस्की' (पितृभूमि टिप्पणियां), अंक १०, १८७७ में नि० क० मिखाइलोव्स्की द्वारा 'कार्ल मार्क्स के बारे में यू० ग० जुकोव्स्की का फ़तवा' शीर्षक उत्तर की ओर है।

'वेस्तनिक येन्नोपी' (यूरोप का संदेशवाहक)—पूँजीवादी-उदारतावादी प्रवृत्ति का ऐतिहासिक-राजनीतिक तथा साहित्यिक मासिक; पीटर्सबर्ग में १८६६ से १९१८ तक प्रकाशित।

'ओतेचेस्त्वेन्निये जपीस्की' (पितृभूमि टिप्पणियां)—साहित्यिक-राजनीतिक पत्रिका जिसका प्रकाशन पीटर्सबर्ग में १८२० से शुरू हुआ था; १८३६ से

वह अपने जमाने की सर्वोत्तम प्रगतिशील पत्रिका बन गयी। पत्रिका पर सेंसर का लगातार वार होता रहा और अन्ततः अप्रैल १८८४ में उसे ज़ारशाही सरकार ने बन्द कर दिया। पृ० २१५

⁸⁵ 'वेस्तनिक नरोद्नोइ वोलि' (जन-इच्छा का संदेशवाहक) - जेनेवा में १८८३ से १८८६ तक जन-इच्छा संगठन की कार्यकारिणी समिति के रूसी उत्प्रवासी सदस्यों द्वारा प्रकाशित पत्रिका। कुल मिलाकर ५ अंक प्रकाशित हुए।

रूसी कानूनी प्रेस में मार्क्स की चिट्ठी अक्टूबर १८८८ के 'युरिदीचेस्की वेस्तनिक' (कानूनी संदेशवाहक) में छपी थी। - पृ० २१५

⁸⁶ यहां इशारा शायद नरोद्वादी संगठनों के नेतृत्वकारी निकायों की ओर है - "जेम्ल्या इ वोल्या" (भूमि तथा स्वतंत्रता) (१८७६ के शरदकाल से लेकर १८७६ के शरदकाल तक) तथा "नरोद्नाया वोल्या" (जन-इच्छा) (अगस्त १८७६ से लेकर मार्च १८८१ तक) जिसने आतंकवाद को राजनीतिक संघर्ष की मूल विधि धोषित किया। - पृ० २१७

⁸⁷ द्वितीय साम्राज्य - नेपोलियन तृतीय की शासन अवधि (१८५२-१८७०)। - पृ० २१८

⁸⁸ बकूनिन की पुस्तक 'राज्यत्व तथा अराजकता', जो १८७३ में प्रकाशित हुई थी, पर कार्ल मार्क्स की ये टिप्पणियां अनुपम आलोचनात्मक तथा शास्त्रार्थपूर्ण रचना हैं। उसमें अराजकतावादी सिद्धांतों की गहन आलोचना तथा इसके विपरीत राज्य, सर्वहारा अधिनायकत्व की ऐतिहासिक अनिवार्यता तथा समाजवादी क्रान्ति की विजय के लिए एक अपरिहार्य शर्त के रूप में मजदूर वर्ग तथा कृषक समुदाय के सहबंध के बारे में वैज्ञानिक कम्युनिज्म की प्रमुख प्रस्थापनाओं को प्रस्तुत किया गया है। ये प्रस्थापनाएं मार्क्स ने पांडुलिपि के सारांश में जोड़ी हैं जिनमें से एक प्रस्तुत खण्ड में शामिल की गयी है। - पृ० २२२

⁸⁹ «Nordstern» (उत्तरी तारा) - १८६० से १८६६ तक हैम्बर्ग में प्रकाशित होनेवाला जर्मन साप्ताहिक; १८६३ में उसने लासालपंथी लाइन अपनायी। - पृ० २२६

⁹⁰ «Social Demokrat» (सामाजिक-जनवादी) - लासालपंथी ग्राम जर्मन मजदूर संघ का मुखपत्र, जो बर्लिन में इस नाम से १५ दिसम्बर १८६४ से लेकर

१८७१ तक प्रकाशित होता रहा। १८६४-१८६७ में उसके सम्पादक श्वीटजर थे।—पृ० २२६

⁹¹ जर्मन राज्यों के पूंजीवादी उदारतावादियों की १५-१६ सितम्बर १८५६ को फ्रैंकफुर्ट-आन-मेन में कांग्रेस में राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। उसके संगठनकर्त्ताओं ने आस्ट्रिया को छोड़कर बाकी पूरे जर्मनी को प्रशा के नेतृत्व में ऐक्यबद्ध करने का कार्यभार अपने सामने निर्धारित किया था। उत्तर जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद ११ नवम्बर १८६७ को संघ ने अपने को भंग कर दिया।—पृ० २२७

⁹² १८५८ में प्रशा के प्रिंस रीजेंट ने मांटेइफ़ेल का मंत्रिमंडल भंग कर दिया तथा नरम विचारों वाले उदारतावादियों को सत्ता सम्भालने के लिए आमंत्रित किया। पूंजीवादी अखबारों में इस पग को “नये युग” का तड़कीला-भड़कीला नाम दिया गया। परन्तु वास्तविकता यह थी कि विल्हेल्म की नीति का लक्ष्य प्रशियाई राजतंत्र और जमींदारों की स्थिति को सुदृढ़ बनाना था। “नये युग” ने वस्तुतः बिस्मार्क के अधिनायकत्व का पथ प्रशस्त किया जिसने सितम्बर १८६२ में सत्ता की बागडोर सम्भाली।—पृ० २२७

⁹³ यहां फ़िलिप द्वितीय से तात्पर्य विल्हेल्म प्रथम से है। उकेमार्क—ब्रांडेनबुर्ग (प्रशा) प्रान्त का उत्तरी भाग, जो प्रतिक्रियावादी प्रशियाई युंकरों का गढ़ था।—पृ० २२७

⁹⁴ «Kreuz-Zeitung» (सलीब अखबार)—यह नाम जर्मन दैनिक «Neue Preussische Zeitung» (नया प्रशियाई पत्र) को दिया गया था क्योंकि उसके नाम पर सलीब का निशान हुआ करता था जो लैंडवेर का चिह्न था। उसका प्रकाशन बर्लिन में जून १८४८ में शुरू हुआ; प्रतिक्रान्तिकारी राजदरवारी गुट तथा प्रशियाई युंकरों का मुखपत्र।—पृ० २२८

⁹⁵ आम जर्मन मजदूर संघ जर्मन मजदूरों का १८६३ में स्थापित राजनीतिक संगठन जिसमें लासाल ने सक्रिय भाग लिया। यह संघ १८७५ तक क्रायम रहा जब गोथा में हुई कांग्रेस में लासालपंथी तथा आइजेनाहपंथी (वह पार्टी जिसके नेता लीब्लेन्हेख्त तथा बेबेल थे) मिलकर जर्मन समाजवादी मजदूर पार्टी में ऐक्यबद्ध हो गये।—पृ० २२८

- ⁹⁶ **प्रगतिवादी**—जून १८६१ में प्रशियाई पूँजीवादी पार्टी के प्रतिनिधि। इन लोगों ने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करने, अखिल जर्मन संसद बुलाने, प्रतिनिधि सदन के प्रति जिम्मेदार मंत्रिमंडल कायम करने की मांग की।—पृ० २२८
- ⁹⁷ इस प्रश्न पर संघबद्ध होने तथा हड़ताल करने पर पाबन्दी लगानेवाली उत्पादक अधिनियमों की धाराएं खत्म करने के लिए मजदूरों के प्रदर्शनों के सम्बन्ध में प्रशियाई लैंडस्टाग में १८६५ में विचार किया गया। प्रगतिवादियों ने धारा १८१ रद्द करने की मांग की। इसमें कारखाना-मालिकों को इस बात की मनाही की गयी थी कि वे मजदूरों के होश ठिकाने लगाने की खातिर उत्पादन रोक दें। परन्तु उन्होंने साथ ही जन-समर्थन प्राप्त करने के लिए धारा १८२ रद्द करने की भी मांग की जिसमें हड़ताल करने के लिए उकसाने के वास्ते मजदूरों को सजा देने की व्यवस्था थी। १४ फरवरी १८६५ को लैंडस्टाग ने केवल १८१ तथा १८२ धाराएं रद्द कीं और इस तरह मजदूरों की मांगें पूरी नहीं कीं।—पृ० २२८
- ⁹⁸ यह प्रशा में उस समय लागू उत्पादक नियमों को मार्क्स द्वारा दिया गया व्यंग्यात्मक नाम है। नौकर-चाकरों को अभिशासित करनेवाले तथाकथित नियम १८वीं शताब्दी में प्रशियाई प्रान्तों में लागू सामन्ती नियम थे जो ज़मींदारों को भूदास किसानों पर पूरा-पूरा अधिकार प्रदान करते थे।—पृ० २२८
- ⁹⁹ १८६१ के वसन्तकाल में मार्क्स ने फिर से प्रशियाई नागरिकता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। परन्तु प्रशियाई अधिकारियों ने उन्हें यह कहकर नागरिकता देने से इन्कार कर दिया कि उन्होंने प्रशियाई नागरिकता का “स्वेच्छया” परित्याग किया था।—पृ० २२६
- ¹⁰⁰ २०-२५ अगस्त १८६६ में वाल्टिमोर में हुई अमरीकी मजदूर कांग्रेस में कानून द्वारा आठ घंटे के कार्य-दिवस की स्थापना, राजनीतिक गतिविधियों, हड़तालों, आदि पर विचार-विमर्श हुआ था।—पृ० २३१
- ¹⁰¹ यहां इशारा १८६५-१८६७ के दूसरे मताधिकार-सुधार के लिए आम जनवादी आन्दोलन में ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों की आम शिरकत की ओर है।
मताधिकार-सुधार के समर्थकों की २३ फरवरी १८६५ को हुई सभा ने, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल की पहल पर तथा उसकी सक्रिय शिरकत

से एक रिफ़ार्म लीग (सुधार लीग) स्थापित करने का निर्णय किया, जो ब्रिटिश मजदूरों के दूसरे मताधिकार-सुधार आन्दोलन का संचालन करनेवाला राजनीतिक केन्द्र बन गया। मार्क्स के आग्रह पर रिफ़ार्म लीग ने पूरे देश की पुरुष आबादी के लिए सार्वजनिक मताधिकार की मांग पेश की। परन्तु लीग के नेताओं के बीच पूंजीवादी आमूल परिवर्तनवादियों के, जो जन-आन्दोलन से घबरा गये थे, कारण तथा अवसरवादी ट्रेड यूनियन नेताओं की समझौता-परस्त नीति के कारण लीग जनरल कौंसिल द्वारा निर्धारित लाइन पर अमल करने में विफल रही। ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग आन्दोलन में फूट डालने में सफल हो गया। १८६७ में सीमित पैमाने पर सुधार लागू किया गया, जिसमें केवल निम्नपूंजीपति वर्ग को तथा मजदूर वर्ग के सबसे ऊपरी भागों को मताधिकार दिया गया और अधिकांश आबादी को पहले की तरह मताधिकार से वंचित रखा गया।—पृ० २३२

¹⁰² «*Literarisches Centralblatt für Deutschland*» (जर्मनी की केन्द्रीय साहित्यिक समीक्षा) — लाइपज़िग में १८५०—१९४४ तक प्रकाशित होनेवाली विज्ञान-सूचना तथा समालोचना की जर्मन साप्ताहिक पत्रिका।—पृ० २३२

¹⁰³ यहां मार्क्स का इशारा 'पूँजी' के पहले जर्मन संस्करण में पहले अध्याय ('माल और मुद्रा') की ओर है।—पृ० २३२

¹⁰⁴ यहां इशारा हक्सट्राउजेन की बर्लिन में १८४२ में प्रकाशित इस पुस्तक की ओर है—«*Ueber den Ursprung und die Grundlagen der Verfassung in den ehemals slavischen Ländern Deutschlands im allgemeinen und des Herzogthums Pomern im besondern*» (सामान्यतया जर्मनी तथा खासकर पोमेरेनिया की डची में भूतपूर्व स्लाव इलाकों में सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति तथा उसके आधार)।—पृ० २३५

¹⁰⁵ १३ जून १८४६ को पेरिस में निम्न-पूँजीवादी पर्वत दल ने इटली में अन्तिम कुचलने के लिए फ़्रांसीसी सैनिकों के भेजे जाने के विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया। सैनिक टुकड़ियों ने प्रदर्शन भंग कर दिया। पर्वत दल के कई नेता गिरफ़्तार कर लिये गये, निर्वासित किये गये अथवा फ़्रांस छोड़ने के लिए विवश किये गये।—पृ० २३६

- ¹⁰⁶ **परस्परवादी**— १९ वीं शताब्दी के सातवें दशक में प्रदोंपंथी अपने को इस नाम से पुकारा करते थे क्योंकि उन्होंने पारस्परिक सहायता की (सहकारिताओं, पारस्परिक सहायता सोसायटियों की स्थापना, आदि) व्यवस्था के जरिए मेहनतकशों को स्वतंत्र करने की एक निम्न-पूँजीवादी योजना पेश की थी।— पृ० २३७
- ¹⁰⁷ यहां इशारा १८७१ के लन्दन सम्मेलन के इन प्रस्तावों की ओर है—‘राष्ट्रीय परिषदों के नाम, आदि’ (प्रस्ताव, II, धाराएं १,२,३), ‘मजदूर वर्ग की राजनीतिक क्रिया के बारे में’ (प्रस्ताव IX), ‘समाजवादी जनवादी सहबंध’ (प्रस्ताव XVI) तथा ‘रोमांस स्विट्ज़रलैंड में फूट’ (प्रस्ताव XII) — पृ० २३८
- ¹⁰⁸ ४ सितम्बर १८७० को सेदान में फ्रांसीसी सेना की पराजय की खबर मिलने पर विशाल जनसमुदाय ने क्रान्तिकारी कार्रवाइयों का आयोजन किया जिसके फलस्वरूप द्वितीय साम्राज्य का पतन हो गया तथा जनतंत्र की उद्घोषणा हुई। परन्तु नवस्थापित सरकार में राजतंत्रवादी तथा नरम विचारों वाले लोग भी थे। फ्राँजी गवर्नर लोशु तथा मुख्य प्रेरणादाता थियेर के नेतृत्व में इस सरकार ने फ्रांसीसी पूँजीपतियों तथा ज़मींदारों की पराजयवादी मनोवृत्ति और जन-साधारण से डर की भावना प्रतिबिम्बित करते हुए राष्ट्रीय गद्दारी का रास्ता अपनाया तथा विदेशी शत्रु के साथ सांठगांठ की।—पृ० २३६
- ¹⁰⁹ देखें टिप्पणी १४।—२४०
- ¹¹⁰ यहां इशारा संगठनात्मक प्रश्नों पर १८६६ की बाज़ेल कांग्रेस के प्रस्तावों की ओर है जिन्होंने जनरल कौंसिल के अधिकारों का विस्तार किया।—पृ० २४१
- ¹¹¹ «*Il proletario*»—देखें टिप्पणी ४१।
«*Gazzettino Rosa*» (लाल अख़बार)—इतालवी दैनिक, वामपंथी माज़िज़नीपंथियों का मुखपत्र, मिलान में १८६७ से १८७३ तक प्रकाशित होता रहा; १८७१ में उसने पेरिस कम्यून के समर्थन की घोषणा की तथा इंटरनेशनल की दस्तावेज़ें प्रकाशित कीं; १८७२ से वह बकूनिनपंथियों के प्रभाव में आ गया।—पृ० २४२
- ¹¹² «*La Liberté*»—(स्वतंत्रता) बेल्जियन जनवादी अख़बार जो १८६५ से

- १८७३ तक ब्रसेल्स में प्रकाशित होता रहा ; १८६७ से बेल्जियम में इंटर-नेशनल का मुखपत्र ।—पृ० २४३
- ¹¹³ १८७१ की फ्रांसीसी शाखा लन्दन में फ्रांसीसी उत्प्रवासियों द्वारा सितम्बर १८७१ में स्थापित की गयी । उसके नेताओं का स्विस बकूनिनपंथियों से घनिष्ठ सम्पर्क था तथा वे इंटरनेशनल के संगठनात्मक सिद्धांतों पर प्रहार करने में उनके साथ मिल गये । यह शाखा इंटरनेशनल में भर्ती नहीं की गयी क्योंकि उसकी नियमावली की कुछ धाराएं आम नियमावली का उल्लंघन करती थीं । आगे चलकर वह कई धड़ों में बंट गयी ।—पृ० २४३
- ¹¹⁴ यहां इशारा १२ नवम्बर १८७१ को सोनविल्ये में बकूनिनपंथी जूरा फ़ेडरेशन की कांग्रेस में अनुमोदित 'अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के तमाम फ़ेडरेशनों के नाम परिपत्र' की ओर है । परिपत्र ने लन्दन सम्मेलन के निर्णय तथा जनरल कौंसिल के अधिकार अस्वीकृत कर दिये तथा सुझाव दिया कि तमाम फ़ेडरेशनों को इंटरनेशनल की आम नियमावली में संशोधन करने और जनरल कौंसिल की निन्दा करने के लिए तत्काल कांग्रेस बुलाने की मांग करनी चाहिए ।—पृ० २४४
- ¹¹⁵ «*Ficcanaso*» (चालवाज़) — इटली का व्यंग्यप्रधान जनतन्त्रवादी दैनिक, वामपंथी मार्क्सिनीपंथियों का मुखपत्र, टूरिन में १८६८ से १८७२ तक प्रकाशित होता रहा ।—पृ० २४४
- ¹¹⁶ एंगेल्स यहां 'सोनविल्ये कांग्रेस में भाग लेनेवाले १६ व्यक्तियों के परिपत्र का रोमांस संघीय कमेटी द्वारा दिये गये उत्तर' की ओर इशारा कर रहे हैं ।—पृ० २४४
- ¹¹⁷ सामाजिक-जनवादियों की सैंक्सन कांग्रेस ६ और ७ जनवरी १८७२ को चेमनित्ज़ नामक स्थान में हुई । कांग्रेस ने अन्य विषयों के अलावा (मताधिकार, ट्रेड यूनियनों का संगठन) सोनविल्ये परिपत्र (देखें टिप्पणी ११४) पर तथा इंटरनेशनल के अन्दर अराजकतावादविरोधी संघर्ष पर विचार किया । कांग्रेस ने जनरल कौंसिल का सर्वसम्मति से समर्थन किया तथा १८७१ के लन्दन सम्मेलन के प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।—पृ० २४५
- ¹¹⁸ इंटरनेशनल के बेल्जियन फ़ेडरेशन की कांग्रेस ने, जो २४-२५ दिसम्बर १८७१ को ब्रसेल्स में हुई, सोनविल्ये परिपत्र पर विचार करते हुए आम कांग्रेस तत्काल

बुलाने की स्विस् अराजकतावादियों की मांग का समर्थन तो नहीं किया परन्तु बेल्जियन फ़ेडरल कौंसिल को आदेश दिया कि वह इंटरनेशनल की नयी नियमावली का मसौदा हेग कांग्रेस के विचारार्थ तैयार करे ।—पृ० २४५

¹¹⁹ जर्मनी, आस्ट्रिया तथा स्विट्ज़रलैंड के सामाजिक-जनवादियों की ७-६ अगस्त १८६६ को आइजेनाख में हुई अखिल जर्मन कांग्रेस में जर्मन सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी की स्थापना हुई। उसका कार्यक्रम मुख्यतया इंटरनेशनल द्वारा प्रस्तुत मांगों के अनुरूप था।—पृ० २४७

¹²⁰ १८७२-१८७३ में लीबकनेख्त तथा हेप्नेर ने मार्क्स से बार-बार अनुरोध किया कि वह लासाल के विचारों की आलोचना करते हुए एक पुस्तिका या फिर «*Volksstaat*» के लिए लेख लिखें।—पृ० २५०

¹²¹ ज़ोर्गे ने अगस्त १८७४ में जनरल कौंसिल से त्यागपत्र दे दिया तथा १४ अगस्त १८७४ को एंगेल्स को इस बारे में सूचित किया; उनका औपचारिक इस्तीफ़ा २५ सितम्बर १८७४ से लागू हुआ।—पृ० २५१

नाम-निर्देशिका

अ

अलेक्सान्द्र द्वितीय (१८१८-१८८१) - रूस के सम्राट (१८५५-१८८१)। - २०८।

आ

आवरियाल (Avrial), अगस्तीन (१८४०-१९०४) - फ्रांस के मजदूर आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, वामपंथी प्रौढवादी, इंटरनेशनल के सदस्य, पेरिस कम्यून के सदस्य, उत्प्रवासी। - ३५।

उ

उतिन, निकोलाई इस्साकोविच (१८४५-१८८३) - रूसी क्रान्तिकारी, छात्र-आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, उत्प्रवासी, इंटरनेशनल की रूसी शाखा के संस्थापकों में से एक, 'नरोदनोये देलो' ('जन-उद्देश्य') पत्र के सम्पादकमंडल के सदस्य (१८६८-१८७०), बकूनिनपंथियों से संघर्ष किया, नवें दशक के मध्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन से पृथक् हो गये। - ३४।

ए

एंगेल्स (Engels,) फ्रेडरिक (१८२०-१८९५) - ५५, १०२, १५६, १५९, १६२, १६९, १७०, २१७, २२६, २२८, २२९, २४०, २४६।

एबेर (Hebert), जाक रेने (१७५७-१७९४) - १८वीं शती की फ्रांसीसी पूँजीवादी क्रांति के कार्यकर्ता, वामपंथी जैकोबिनों के नेता। - १८६।

□

ओ

ओडजर (Odger), जार्ज (१८२०-१८७७) - अंग्रेज चर्मकार, ट्रेड-यूनियन नेता, सुधारवादी, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८६४-१८७१), उसके अध्यक्ष (१८६४-१८६७); १८७१ में पेरिस कम्यून की भर्त्सना की, जनरल कौंसिल से अलग हो गये, जिसने उन्हें गद्दार ठहराया। - १२, १८।

ओवेन (Owen), राबर्ट (१७७१-१८५८) - ब्रिटेन के विख्यात कल्पनावादी समाजवादी। - १२३, १२४, २१२, २३१।

ओस्मान (Haussmann), जार्ज एजेन (१८०९-१८९१) - फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ, बोनापार्टपंथी, सीन जिले के प्रीफेक्ट (१८५३-१८७०), पेरिस के पुनर्निर्माण-कार्य का संचालन किया। - ८८, १४५।

क

कामेलिना (Camélinat), जेफ्रीरिन (१८४०-१९३२) - फ्रांसीसी मजदूर तथा समाजवादी आन्दोलन के एक प्रमुख नेता, इंटरनेशनल की पेरिस शाखा के नेताओं में से एक, पेरिस कम्यून के सदस्य, १९२० से फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। - ३५।

कालियोस्ट्रो (Cagliostro), अलेस्सान्ड्रो (असल नाम जुझेप्पे बाल्सामो) (१७४३-१७९५) - इतालवी दुस्साहसिकतावादी। - २१।

कुगेलमन (Kugelman), लुडविग (१८३०-१९०२) - जर्मन चिकित्सक, १८४८-१८४९ की क्रांति में भाग लिया, इंटरनेशनल के सदस्य, इंटरनेशनल की कई कांग्रेसों में भाग लिया, मार्क्स परिवार के मित्र। - २२५, २३०, २३२, २३४, २३६।

कुनो (Cuno), फ्रेडरिक थियोडोर (१८४६-१९३४) - जर्मन तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के एक प्रमुख नेता, समाजवादी; पहले इंटरनेशनल के सक्रिय सदस्य, "नाइट्स आफ लेबर" नामक अमरीकी मजदूर संगठन के नेताओं में से एक, «New Yorker Volkszeitung» पत्र में लेख लिखते रहे। - २४०।

क्रुप्प (Krupp), अल्फ्रेड (१८१२-१८८७) - इस्पात तथा हथियारों के कारखानों के बड़े जर्मन मालिक। - १२६।

ग

गिलोम (Guillaume), जेम्स (१८४४-१९१६) - स्विस् अध्यापक, इंटरनेशनल के सदस्य, उसकी कांग्रेसों में भाग लिया, बकूनिनपंथी; हेग कांग्रेस (१८७२) के निर्णय पर फूटपरस्त नीति चलाने के कारण इंटरनेशनल से निष्कासित। - २३, २४, ३६, ५०, ५८।

गोटे (Goethe), जोहान वोल्फगांग (१७४९-१८३२) - जर्मनी के महाकवि तथा विचारक। - १७०, १७१।

ग्लैडस्टन (Gladstone), विलियम एवर्ट (१८०९-१८९८) - अंग्रेज राजनीतिज्ञ, १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में लिबरल पार्टी के नेता, वित्तमंत्री (१८५२-१८५५ तथा १८५९-१८६६) - तथा प्रधानमंत्री (१८६८-१८७४, १८८०-१८८५, १८८६, १८९२-१८९४)। - २३६।

च

चेर्निशेव्स्की, निकोलाई गाब्रीलोविच (१८२८-१८८९) - महान रूसी क्रान्तिकारी जनवादी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्य-समालोचक, रूसी सामाजिक-जनवाद के अग्रदूतों में से एक। - २०८, २०९, २१०, २१६, २१९।

ज

जाक्स (Sax), एमिल (१८४५-१९२७) - आस्ट्रियाई पूंजीवादी अर्थशास्त्री। - ७५, १११-१३३, १३८-१४१।

जुकोव्स्की, निकोलाई इवानोविच (१८३३-१८९५) - रूसी अराजकतावादी, उत्प्रवासी, गुप्त सहबंध के नेताओं में से एक। - २७।

जुकोव्स्की, यूलि गलाक्तिओनोविच (१८२२-१९०७) - रूस के बाजारू अर्थशास्त्री तथा पत्रकार; स्टेट बैंक के मैनेजर; 'कार्ल मार्क्स तथा पूंजी पर उनकी पुस्तक' शीर्षक लेख के लेखक, जिसमें उन्होंने मार्क्सवाद पर प्रहार किया। - २१५।

जोर्गे (Sorge), फ्रेडरिक अडोल्फ (१८२८-१९०६) - अन्तर्राष्ट्रीय और अमरीकी मजदूर तथा समाजवादी आन्दोलन की प्रमुख हस्ती; १८४८ की क्रान्ति में भाग लिया; इंटरनेशनल के सक्रिय सदस्य, न्यूयार्क में जनरल कौंसिल के सदस्य तथा उसके महासचिव (१८७२-१८७४); मार्क्सवाद के सक्रिय प्रचारक; मार्क्स तथा एंगेल्स के मित्र तथा सहयोगी।-२५१।

ड

ड्यूपेसो (Ducpetiaux), एडवर्ड (१८०४-१८६८) - बेल्जियन पत्रकार तथा सांख्यिकीविद, पूंजीवादी लोकोपकारवादी, जेलों तथा लोकोपकारी संस्थानों के निरीक्षक।-११२।

त

तेर्जागी (Terzaghi), कार्लो (जन्म अनुमानतः १८४५) - इतालवी वकील, टूरिन में "सर्वहारा मुक्ति" मजदूर समाज के सचिव; १८७२ में पुलिस का भेदिया।-४९।

त्काचोव, प्योत्र निकितिच (१८४४-१८८५) - रूसी क्रान्तिकारी, पत्रकार, नरोदवाद के एक सिद्धांतकार।-१९२, १९३, १९६, १९७, १९९-२०१, २०३, २०६-२०८।

थ

थियेर (Thiers), अडोल्फ (१७९७-१८७७) - फ्रांस का पूंजीवादी इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ, विधान सभा का सदस्य (१८४९-१८५१), आर्लियानिस्ट, जनतंत्र का राष्ट्रपति (१८७१-१८७३), पेरिस कम्यून का हत्यारा।-३०, ५९, ६२, ६५, २३५, २४५।

थेइस (Theisz), अल्बेर (१८३९-१८८०) - फ्रांसीसी मजदूर, प्रदोंवादी, पेरिस कम्यून के सदस्य, उत्प्रवासी, जनरल कौंसिल के सदस्य और खजानची।-३०, ३५।

द

द पाइप (De Paepe), सीजर (१८४२-१८९०) - बेल्जियन मजदूर तथा समाजवादी आन्दोलन के एक प्रमुख नेता, इंटरनेशनल के सदस्य, कई कांग्रेसों में प्रतिनिधि; १८७२ के बाद कुछ समय तक बकूनिनपंथियों के समर्थक, बेल्जियन मजदूर पार्टी के संस्थापकों में से एक। - ६८।

दान्ते आलिगियेरी (Dante Alighieri) (१२६५-१३२१) - इटली के महा-कवि। - १८०।

दुरां (Durand), गुस्ताव (जन्म १८३५) - फ्रांसीसी जौहरी, पुलिस का जासूस, अक्टूबर १८७१ में बेनकाब तथा इंटरनेशनल से निष्कासित। - ३०, ३७।

दूफोर (Dufaure), जूल आर्मान्द स्तानिस्ला (१७९८-१८८१) - फ्रांसीसी पूंजीवादी राजनीतिज्ञ, आर्लियानिस्ट, १८४८ में संविधान सभा के सदस्य, कैबेन्याक सरकार में गृहमंत्री (अक्टूबर-दिसम्बर १८४८)। - १३, ४३, ६२।

दोल्फुस (Dollfus), जान (१८००-१८८७) - अलसास का एक बड़ा कार-खानेदार, पूंजीवादी लोकोपकारवादी, म्युलुज का मेयर। - १०१, १०२, १६७, १६८।

न

निकोलाई प्रथम (१७९६-१८५५) - रूसी सम्राट (१८२५-१८५५)। - २१७।
नेचायेव, सेर्गेई गेन्नादियेविच (१८४७-१८८२) - रूसी क्रांतिकारी, षड्यंत्रकारी, १८६८-१८६९ में सेंट पीटर्सबर्ग में छात्र आन्दोलन में भाग लिया; १८६९-१८७१ में बकूनिन के घनिष्ठ साथी; 'जन-प्रतिशोध' नामक गुप्त संस्था के संस्थापक (१८६९); १८७२ में स्विस अधिकारियों ने उन्हें रूस सरकार के हवाले कर दिया; सेंट पीटर्सबर्ग में पीटर और पोल के दुर्ग में मृत्यु। - २०, २१, २४५।

नेपोलियन तृतीय (Napoleon III) (लूई नेपोलियन बोनापार्ट) (१८०८-१८७३) - नेपोलियन प्रथम के भतीजे, दूसरे जनतंत्र के राष्ट्रपति (१८४८-१८५१), फ्रांसीसी सम्राट (१८५२-१८७०)। - १३, २४, २६, ६०, ८८, १०२, १२७, १३१, १४१, १४४, १४५, २३५, २४५।

नेपोलियन प्रथम, बोनापार्ट (Napoleon I, Bonaparte) (१७६९-१८२१) -
फ्रांस के सम्राट (१८०४-१८१४ तथा १८१५)।-११३, २४३।

□

प

पाविया इ रोड्रिगेज़ (Pavia y Rodriguez), मैनुएल (१८२७-१८९५) -
स्पेनी जनरल तथा राजनीतिज्ञ, १८७३ में कार्लिस्टों के विरुद्ध जनतन्त्रीय
सेना का नेतृत्व किया, एंडालुसिया में कैटोनलिस्टों का विद्रोह कुचला।-२०५।

पियेत्री (Pietri), जोज़ेफ़ मारी (१८२०-१९०२) - फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ,
बोनापार्टपंथी, पेरिस के प्रमुख पुलिस अधिकारी (१८६६-१८७०)।-३५।

पीटर तृतीय (१७२८-१७६२) - रूसी सम्राट (१७६१-१७६२)।-२०४।

पीटर प्रथम (१६७२-१७२५) - १६८२ से रूसी ज़ार, १७२१ से रूस के
सम्राट।-१९५।

पुगाचोव, येमेत्यान इवानोविच (१७४२-१७७५) - १८वीं सदी में किसानों
तथा कज़ाकों के सबसे बड़े सामन्तवाद विरोधी विद्रोह के नेता।-२०४।

पेरेइर (Péreire), इस्साक (१८०६-१८८०) - फ्रांसीसी बैंकपति, बोनापार्टपंथी;
१८५२ में अपने भाई एमील पेरेइर के साथ मिलकर Credit Mobilier
नामक ज्वारंट-स्टॉक बैंक कायम किया।-१४३।

प्यात (Pyat), फ़ेलिक्स (१८१०-१८८९) - फ्रांसीसी पत्रकार तथा निम्नपूँजीवादी
जनवादी; १८४८ की क्रांति में भाग लिया; १८४९ से उत्प्रवासी; कई
वर्षों तक मार्क्स तथा इंटरनेशनल के विरुद्ध कुत्सापूर्ण प्रचार किया तथा इस
काम में लन्दन में फ्रांसीसी शाखा का उपयोग किया; पेरिस कम्यून के सदस्य।
-१०, २९।

प्रूदों (Proudhon), पियेर जोज़ेफ़ (१८०९-१८६५) - फ्रांसीसी पत्रकार,
अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, निम्नपूँजीवादी विचारधारा के प्रतिपादक तथा
अराजकतावाद के एक प्रवर्तक, १८४८ में संविधान सभा के प्रतिनिधि।-
७५-७७, ७९, ८६, ८९, ९०-९३, ९५, ९६, ९९-१०५, १०७-११०, ११५,
११७, १४९-१५२, १५४-१५६, १५९-१६५, १६७, १६९, १७२, १७३,
१७७, २२६, २३७, २३८, २५१।

प्लेखानोव, गेओर्गी वालेन्तीनोविच (१८५६-१९१८) - रूसी और अन्तर्राष्ट्रीय
मजदूर आंदोलन के एक प्रमुख नेता, दर्शनशास्त्री, रूस में मार्क्सवाद के प्रचारक,

पहले रूसी मार्क्सवादी संगठन—“श्रम मुक्ति दल”—के संस्थापक; १९वीं सदी के नौवें और दसवें दशकों में नरोदवाद के विरुद्ध संघर्ष किया, अन्तर-ष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन में अवसरवाद और संशोधनवाद के विरुद्ध लड़े; बाद में मेन्शेविक; पहले विश्वयुद्ध के दौरान सामाजिक-अंधराष्ट्रवादी रहे।—२०६, २१३।

फ

फाउहेर (Faucher), जूलियस (१८२०-१८७८)—जर्मन पत्रकार, मुक्त व्यापार के समर्थक, आवास प्रश्न संबंधी रचनाओं के लेखक, प्रगतिवादी।—११२, २२६।

फाव्रे (Favre), जूल (१८०६-१८८०)—फ्रांसीसी वकील तथा राजनीतिज्ञ, नरम विचारोंवाले पूंजीवादी जनतंत्रवादियों के नेताओं में से एक; विदेश-मंत्री (१८७०-१८७१) के रूप में पेरिस के समर्पण तथा जर्मनी के साथ शांति संधि की शर्तों पर समझौता-वार्ता की; पेरिस कम्यून के संहारकर्तृओं में से एक; इंटरनेशनल के विरुद्ध उकसावाभरी कार्रवाई की।—१०, १३, ४३, २४२।

फुरिए (Fourier), शार्ल (१७७२-१८३७)—फ्रांस के महान कल्पनावेदी समाजवादी।—१२३, १२४, २३१।

फेरे (Ferre), थियोफील शार्ल (१८४५-१८७१)—फ्रांसीसी क्रांतिकारी, ब्लंकीपंथी; पेरिस कम्यून के सदस्य, जन-सुरक्षा समिति के सदस्य, फिर अध्यक्ष, कम्यून के उप-महाभियोक्ता, वेसर्डीपंथियों द्वारा गोली से उड़ा दिये गये।—२७।

फोग्ट (Vogt), कार्ल (१८१७-१८६५)—जर्मन प्रकृतिविद, बाजारू भौतिकवादी, निम्नपूँजीवादी जनवादी; जर्मनी में १८४८-१८४९ की क्रान्ति में भाग लिया; छठे तथा सातवें दशक में उत्प्रवास के दौरान लूई बोनापार्ट का बेटनभोगी एजेंट।—२३५।

फोग्ट (Vogt), गुस्ताव (१८२६-१९०१)—स्विस अर्थशास्त्री, पूँजीवादी शान्तिवादी, शान्ति तथा स्वतंत्रता लीग के संगठनकर्तृओं में से एक; कार्ल फोग्ट के भाई।—१५।

फ्लेरोन्को—देखें बेर्वी, वासीली वासील्येविच।

ब

बकूनिन, मिखाईल अलेक्सान्द्रोविच (१८१४-१८७६) - रूसी जनवादी, पत्रकार, जर्मनी की १८४८-१८४९ की क्रान्ति में भाग लिया; अराजकतावाद के एक सिद्धान्तकार; पहले इंटरनेशनल में मार्क्सवाद के कट्टर विरोधी; १८७२ में हेग कांग्रेस में अपनी फूट डालनेवाली नीति के कारण इंटरनेशनल से निकाल दिये गये।-१५, १६, २०-२३, २६, ४०, ४६, ५३, ५४, ५८, ६०-६२, ७६, १५०, २००, २०६, २२२, २२३, २३८, २४०-२४३, २४५, २४६, २५१।

बास्तेलिका (Bastelica), आन्द्रे (१८४५-१८८४) - फ्रांस और स्पेन के मजदूर आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया; इंटरनेशनल के सदस्य, बकूनिन के अनुयायी।-२४, ३०, ३६।

बिस्मार्क (Bismark), ओटो, प्रिंस (१८१५-१८९८) - प्रशा तथा जर्मनी के राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ, प्रशा के जमींदारों के हितों के पक्षधर, प्रशा के मिनिस्टर-प्रेजिडेंट (१८६२-१८७१), जर्मन साम्राज्य के चांसलर (१८७१-१८९०)।-१४, २८, ५५, १२८, १३६, १४४, १८८, २२६-२२९, २४२, २४५।

बुके (Bousquet), अबेल - फ्रांसीसी अराजकतावादी, पुलिस अफसर होने के आरोप में इंटरनेशनल से निष्कासित।-२४५।

बुक्लेर (Bückler), जोहन (१७८०-१८०३) - जर्मन बटमार, शिंडेरहान्स (हान्स-क्रसाई) के नाम से विख्यात।-२०३।

बेकर (Becker), बर्नहार्ड (१८२६-१८९१) - जर्मन पत्रकार, लासालपंथी, जर्मन मजदूरों की आम संस्था के अध्यक्ष (१८६४-१८६५)।-२२८।

बेगेली (Beghelli), जुझेप्पे (१८४७-१८७७) - इतालवी पत्रकार, गैरीबाल्डी के अभियानों में भाग लिया, कई जनतंत्रीय अखबारों के सम्पादक।-२४४।

बेबेल (Bebel), अगस्त (१८४०-१९१३) - जर्मन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के एक प्रसिद्ध नेता, १८६७ से जर्मन मजदूर संघों की लीग के नेता, पहले इंटरनेशनल के सदस्य, १८६७ से राइख्स्ताग के सदस्य, जर्मन सामाजिक-जनवाद के संस्थापकों में से एक, मार्क्स तथा एंगेल्स के मित्र तथा सहयोगी, दूसरे इंटरनेशनल के प्रमुख नेता।-२४६।

बेर्वी, वासीली वासील्येविच (न० फ्लेरोव्स्की का छद्म नाम) - रूसी अर्थशास्त्री

तथा समाजशास्त्री, कल्पनावादी नरोदवादी समाजवाद के प्रतिनिधि, 'रूस में मजदूर वर्ग की स्थिति' पुस्तक के लेखक।-१९८।

बोल्ते (Bolte), फ्रेडरिक-अमरीकी मजदूर आन्दोलन में एक प्रमुख नेता; जर्मनी में जन्म; इंटरनेशनल की उत्तर अमरीकी शाखाओं की फ्रेडरल कौंसिल के सचिव (१८७२), जनरल कौंसिल के सदस्य (१८७२-७४); १८७४ में जनरल कौंसिल से निष्कासित।-२३७।

ब्योइस्ट (Beust), फ्रेडरिक, काउंट (१८०६-१८८६)-सैक्सन तथा आस्ट्रियाई प्रतिक्रियावादी राजनेता, विदेश मंत्री (१८६६-१८७१), आस्ट्रिया-हंगरी के चांसलर (१८६७-१८७१)।-१४।

ब्रूटस (Marcus Junius Brutus) (लगभग ८५-४२ ई० पू०)-रोम के राजनीतिक नेता, जूलियस सीज़र के खिलाफ षड्यंत्र का नेतृत्व किया।-१८५, १८६।

ब्लां (Blanc), गायर-फ्रांसीसी राइक-निर्माता, बकूनिनपंथी, १८७० के लियों विप्लव में भाग लिया।-२३, २४, २६, ५६, ६१, ६२।

ब्लांकी (Blanqui), लूई ओग्यूस्त (१८०५-१८८१)-फ्रांसीसी क्रान्तिकारी, कल्पनावादी कम्युनिस्ट; १८३० और १८४८ की क्रान्तियों में फ्रांस के जनवादी तथा सर्वहारा आन्दोलन के उग्र वामपक्ष का समर्थन किया; कई बार गिरफ्तार किये गये।-१८३-१८५।

ब्लौंड (Blind), कार्ल (१८२६-१९०७)-जर्मन पत्रकार, निम्नपूँजीवादी जनवादी, १८४८-१८४९ की क्रांति में भाग लिया, छठे दशक से लन्दन में जर्मन निम्नपूँजीवादी उत्प्रासियों के नेताओं में से एक, सातवें दशक से राष्ट्रीय उदारतावादी।-२२६।

म

माइकेल (Miquel), जोहन (१८२८-१९०१)-जर्मन राजनीतिक कार्यकर्ता, पांचवें दशक में कम्युनिस्ट लीग के सदस्य; बाद में राष्ट्रवादी-उदारवादी; अंतिम दशक में प्रशा के वित्त मंत्री।-२२६, २२७, २२९।

माज्जिनी (Mazzini), जुजेप्पे (१८०५-१८७२)-इटली के क्रान्तिकारी, पूँजीवादी जनवादी, इटली में राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के एक नेता, रोमन जनतंत्र की अस्थायी सरकार के प्रधान (१८४६); १८५० में लन्दन में यूरोपीय जनवाद

की केन्द्रीय समिति के संस्थापक ; पहले इंटरनेशनल की स्थापना के समय उन्होंने उसे अपने प्रभाव में आने का प्रयास किया ; इटली में स्वतंत्र मजदूर आन्दोलन में विकास की राह में बाधा डाली।—२४२।

मार (Marr), विल्हेल्म (१८१६-१९०४) — निम्नपूँजीवादी जर्मन पत्रकार ; १८६५-१८६६ में «*Beobachter an der Elbe*» अखबार के प्रकाशक ; सातवें दशक के आरम्भ में बिस्मार्क की नीति के समर्थक।—२२६।

मारेर (Maurer), गेओर्ग लुडविग (१७६०-१८७२) — जर्मनी के प्रसिद्ध पूँजीवादी इतिहासकार, प्राचीन तथा मध्ययुगीन जर्मनी की समाज-व्यवस्था के बारे में अनुसन्धान किया।—२००।

मार्क्स (Marx), एलिओनोर (टुस्सी) (१८५५-१८६८) — मार्क्स की सबसे छोटी बेटी ; आंग्ल तथा अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया ; १८८४ में एडवर्ड एवेलिंग से विवाह किया।—१०२।

मार्क्स (Marx), कार्ल (१८१८-१८८३) ७७, ७८, ८४, ८७, ६३, १०६, ११०, १५१, १६२, १७६, २०८, २१०, २१३, २१५-२१७, २२१, २२५, २३०, २३२, २३४, २३६, २३७, २४५, २४६, २५०, २५२।

मार्क्स (Marx), जेनी (१८४४-१८८३) — मार्क्स की सबसे बड़ी बेटी, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, १८७२ से आर्ल लोंगे की पत्नी।—२४६।

मालू (Malou), जूल (१८१०-१८८६) — बेल्जियाई राजनेता, वित्तमंत्री (१८४४-१८४७, १८७०-१८७८), मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष (१८७१-१८७८) ; कैथोलिक पार्टी के सदस्य।—१३।

मालोन (Malon), बेनुआ (१८४१-१८६३) — फ्रांसीसी समाजवादी, इंटरनेशनल और पेरिस कम्यून के सदस्य, उसके बाद उत्प्रवासी, अराजकतावादियों के साथ जा मिले ; आगे चल कर सम्भववादी नेताओं में से एक।—२६, २७, ३५, ३७-३६, ५५, ५८, १८४।

मिखाइलोव्स्की, निकोलाई कोन्स्तान्तीनोविच (१८४२-१९०४) — रूसी समाज-शास्त्री, पत्रकार और साहित्य के समीक्षक, उदारपंथी नरोदवाद के प्रख्यात सिद्धांतकार ; 'ओतेचेस्त्वेन्निये जपीस्की' और 'रुस्कोये बोगात्स्त्वो' पत्रिकाओं के एक संपादक।—२१५।

मिराबो (Mirabeau), ओनोरे गेन्नियल (१७४९-१७९१) - अठारहवीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रांति के सुविख्यात नेता; उन्होंने बड़े पूंजीपति वर्ग के तथा उन जमींदारों के हितों को अभिव्यक्त किया, जो पूंजीवादी बन गये थे; 'फ्रेडरिक महान के काल में प्रशियाई राजतंत्र के विषय में' पुस्तक के लेखक। - २२७।

म्यूलबर्गर (Mülberger), आर्थर (१८४७-१९०७) - जर्मन डाक्टर, निम्न-पूंजीवादी पत्रकार, प्रदोवादी। - ७५, ७६, ८९, ९२, १०३, १४९-१६२, १६५-१७६, २४८।

य

यार्क (Jork), थियोडोर (मृत्यु १८७५) - जर्मन मजदूर आन्दोलन के एक नेता, लासालपंथी; १८७१-१८७४ में जर्मनी की सामाजिक-जनवादी मजदूर पार्टी के सचिव। - २४७।

येकातेरीना द्वितीय (१७२९-१७९६) - रूस की सम्राज्ञी (१७६२-१७९६)। - २०४।

र

राबर्ट (Robert), रिज - स्विस् अध्यापक, इंटरनेशनल के सदस्य, बकूनिनपंथी। - २३, ५०।

राबर्ट्स (Roberts), हेनरी (मृत्यु १८७६) - अंग्रेज वास्तुशिल्पी, पूंजीवादी लोकोपकारवादी। - ११२।

राबिन (Robin), पाल (जन्म १८३७) - फ्रांसीसी अध्यापक, बकूनिनपंथी, समाजवादी जनवादी सहबंध के एक नेता, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८७०-१८७१), इंटरनेशनल की बाजेल कांग्रेस (१८६९) तथा लन्दन सम्मेलन (१८७१) में डेलीगेट। - २५, ३६, २४२।

रिकाडो (Ricardo), डेविड (१७७२-१८२३) - अंग्रेज अर्थशास्त्री, क्लासिकीय पूंजीवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के एक प्रमुख प्रतिनिधि। - २३३।

रिगो (Rigault), राउल (१८४६-१८७१) - फ्रांसीसी क्रान्तिकारी, ब्लांकी के अनुयायी, पेरिस कम्यून के सदस्य, जन-सुरक्षा समिति के प्रतिनिधि;

कम्यून के महाभियोक्ता (२६ अप्रैल से), २४ मई १८७१ को वेर्साईवालों ने गोली से उड़ा दिया।—२७।

रिशार (Richard), अल्बेर (१८४६-१९२५) — फ्रांसीसी पत्रकार, इंटरनेशनल की लियों शाखा के एक नेता, गुप्त सहबंध के सदस्य, १८७० में लियों में हुए विद्रोह में भाग लिया; पेरिस कम्यून की पराजय के बाद बोनापार्टपंथी।—२३, २४, २६, ५६-६२, २४५।

रेशाउएर (Reschauer), हेनरिक (जन्म १८३८) — आस्ट्रियाई पूंजीवादी लेखक तथा पत्रकार, उदारतावादी।—१६८।

रोबेसपियेर (Robespierre), मैक्सिमिलियन (१७५८-१७९४) — १८ वीं शताब्दी के अंत में हुई फ्रांसीसी पूंजीवादी क्रान्ति के प्रमुख नेता, जैकोबिन पार्टी के नेता, क्रान्तिकारी सरकार के अध्यक्ष (१७९३-१७९४)।—१९१।

ल

लफ़ार्ग (Lafargue), पाल (१८४२-१९११) — इंटरनेशनल मजदूर आन्दोलन की एक प्रमुख हस्ती, मार्क्सवाद के प्रचारक, इंटरनेशनल की जनरल काँसिल के सदस्य, स्पेन के लिए सह-सचिव (१८६६-१८६९); फ्रांस में (१८६९-१८७०) और स्पेन तथा पुर्तगाल में (१८७१-१८७२) इंटरनेशनल की शाखाएं संगठित करने में सक्रिय भाग लिया; हेग कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि (१८७२); फ्रांस में मजदूर पार्टी के संस्थापकों में से एक; मार्क्स तथा एंगेल्स के शिष्य तथा सहयोगी।—२३४।

लफ़ार्ग (Lafargue), लाउरा (१८४५-१९११) — फ्रांसीसी मजदूर आन्दोलन में एक प्रमुख हस्ती, पाल लफ़ार्ग की पत्नी, मार्क्स की बेटी।—२३४।

लान्देक (Landeck), बेनार (जन्म १८३२) — फ्रांसीसी जौहरी, इंटरनेशनल तथा १८७१ की फ्रांसीसी शाखा के सदस्य।—३५।

लासाल (Lassalle), फ़र्दीनांद (१८२५-१८६४) — जर्मन निम्नपूंजीवादी पत्रकार, वकील; १८४८-१८४९ में राइन प्रांत में जनवादी आंदोलन में भाग लिया; सातवें दशक के आरम्भ से मजदूर आंदोलन में भाग लेने लगे; आम जर्मन मजदूर संघ के संस्थापकों में से एक (१८६३); “ऊपर से”, प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की नीति के समर्थक; जर्मन मजदूर

आन्दोलन में अवसरवादी प्रवृत्ति के संस्थापक।-१६२, १६३, २२५-२२६, २३८, २४३, २५०।

लिंग्टन (Linton), विलियम जेम्स (१८१२-१८६७)-अंग्रेज़ नवकाश, कवि तथा पत्रकार, जनतंत्रवादी, «English Republic» पत्रिका के, जिसमें हर्जें के लेख प्रकाशित होते थे, सम्पादक; १८६६ में अमरीका जाकर बस गये।-२०७।

लिबिग (Liebig), जुस्टुस (१८०३-१८७३)-प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक, कृषि रसायनशास्त्र के जन्मदाताओं में से एक।-१६८।

लीबकनेख्त (Liebknecht), विल्हेल्म (१८२६-१९००)-जर्मन तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के नेता, १८४८-१८४९ की क्रान्ति में भाग लिया; कम्युनिस्ट लीग तथा पहले इंटरनेशनल के सदस्य; जर्मन सामाजिक-जनवादी पार्टी के नेताओं में से एक; मार्क्स तथा एंगेल्स के मित्र और सहयोगी।-२२६, २२८, २३५, २४६।

लूई चौदहवें (Louis XIV) (१६३८-१७१५)-फ्रांस के राजा (१६४३-१७१५)।-२७।

लूई नेपोलियन (Louis Napoleon)-देखिए **नेपोलियन तृतीय**।

लूई फ़िलिप (Louis Philippe) (१७७३-१८५०)-आर्लियां के ड्यूक, फ्रांस के बादशाह (१८३०-१८४८)।-१८४।

लूई बोनापार्ट (Louis Bonapart)-देखिए **नेपोलियन तृतीय**।

लेओ (Leo), आन्ड्रे (असल नाम लेओनी शाम्पसे) (१८२६-१९००)-फ्रांसीसी लेखिका, पेरिस कम्यून की सदस्या, बाद में उत्प्रवासी, बकूनिनपंथियों का समर्थन किया।-२७।

लेक्राफ़्त (Lucraft), बेंजामिन (१८०६-१८६७)-अंग्रेज़ मजदूर, ट्रेड-यूनियन नेता, सुधारवादी, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८६४-१८७१); १८७१ में पेरिस कम्यून के विरुद्ध थे, जनरल कौंसिल से पृथक हो गये। जनरल कौंसिल ने उन पर गद्दार होने का आरोप लगाया था।-१२।

लेफ़्रांसे (Lefrancais), गुस्ताव (१८२६-१९०१)-फ्रांसीसी अध्यापक, इंटरनेशनल तथा पेरिस कम्यून के सदस्य; वामपंथी प्रवृद्धवादी; स्विट्ज़रलैंड में बस गये, वहां अराजकतावादियों से जा मिले।-३७-३६, ५८।

लेब्लां (Leblanc), अलबेर्ट फ़ेलिक्स (जन्म १८४४)-इंटरनेशनल की पेरिस शाखा के सदस्य, बकूनिनपंथियों से जा मिले, पेरिस कम्यून के सदस्य; लियोन

में कम्यून के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ कम्यून की उद्घोषणा करने का प्रयास किया ; कम्यून के दमन के बाद इंग्लैंड चले गये, बोनापार्टपंथी । - २४५ ।

७

ब

वाइयां (Vaillant), एदुअर्द मारी (१८४०-१९१५) - फ्रांसीसी समाजवादी, ब्लांकी के अनुयायी ; पेरिस कम्यून तथा पहले इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८७१-१८७२) ; १८८६ की अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर कांग्रेस में भाग लिया ; फ्रांस की समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक (१९०१) ; प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सामाजिक अंधराष्ट्रवादी स्थिति अपनायी । - १९१ ।

वागनेर (Wagner), अडोल्फ (१८३५-१९१७) - जर्मनी के बाज़ारू अर्थशास्त्री, राजनीतिक अर्थशास्त्र के तथाकथित सामाजिक-कानूनी पंथ के प्रतिनिधि, काथेडर-समाजवादी । - १४५ ।

वागेनेर (Wagener), हेर्मान (१८१५-१८८६) - जर्मन पत्रकार तथा राजनीतिज्ञ, «*Neue Preussische Zeitung*» पत्र के सम्पादक (१८४८-१८५४), प्रशा के अनुदार दल के संस्थापकों में से एक, बिस्मार्क के समर्थक । - २२८ ।

वार्लिन (Varlin), एजेन (१८३६-१८७१) - फ्रांसीसी मजदूर आन्दोलन के ख्यातिप्राप्त नेता ; वामपंथी प्रदोवादी ; फ्रांस में इंटरनेशनल की शाखाओं के एक नेता ; राष्ट्रीय गार्ड की केन्द्रीय परिषद के तथा पेरिस कम्यून के सदस्य, वेर्साइवालों द्वारा गोली से उड़ा दिये गये । - ३५ ।

विक्टर-एमानुईल द्वितीय (१८२०-१८७८) - सार्डीनिया के राजा (१८४६-१८६१), इटली के राजा (१८६१-१८७८) । - १४ ।

विनुआ (Vinoy), जोज़ेफ़ (१८००-१८८०) - फ्रांसीसी जनरल, बोनापार्टपंथी, २ दिसम्बर १८५१ के राज्य-पर्युत्क्षेपण में भाग लिया ; २२ जनवरी १८७१ से पेरिस के गवर्नर ; कम्यून के संहारकों में से एक, वेर्साई रिज़र्व सेना के सेनापति । - २३५ ।

विर्जिलियस (Publius Vergilius Moro) (७०-१९ ई० पू०) - महान रोमन कवि । - २३१ ।

विल्हेल्म प्रथम (Wilhelm I) (१७९७-१८८८) - प्रशा के राजा (१८६१-१८८८), जर्मनी के सम्राट (१८७१-१८८८) । - ६५ ।

वेज़िन्ये (Vésinier), पियेर (१८२६-१९०२) - निम्नपूँजीवादी फ़्रांसीसी पत्रकार, इंटरनेशनल तथा पेरिस कम्यून के सदस्य; मार्क्स तथा इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल का विरोध किया। - ३५।

वेर्मेश (Vermersch), एजेन (१८४५-१८७८) - निम्नपूँजीवादी फ़्रांसीसी पत्रकार तथा प्रकाशक। - १८६।

श

शा (Shaw), राबर्ट (मृत्यु १८६९) - ब्रिटिश मज़दूर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८६४-१८६९) और उसके कोषाध्यक्ष (१८६७-१८६८), अमरीका के लिए सह-सचिव (१८६७-१८६९)। - १८।

शाले (Chalain), लूई देनी (जन्म १८४५) - फ़्रांसीसी मज़दूर, पेरिस कम्यून और उसके आयोगों के सदस्य; उत्प्रवासी, लन्दन में १८७१ की फ़्रांसीसी शाखा के सदस्य, बाद में अराजकतावादी। - ३५।

शुल्ज़े-डेलिट्ज़ (Schulze-Delitzsch), फ़्रांज़ हर्मन (१८०८-१८८३) - जर्मन राजनीतिज्ञ तथा पूँजीवादी बाज़ारु अर्थशास्त्र के प्रतिनिधि; प्रशा की राष्ट्रीय सभा के सदस्य (१८४८); सातवें दशक में पूँजीवादी प्रगतिवादी पार्टी के नेता; सहकारी समितियां स्थापित कर मज़दूरों को क्रान्तिकारी संघर्ष से भटकाने का प्रयास किया। - १६८, २२६।

शेवाले (Chevalley), आंरी - स्विस् दर्जी, अराजकतावादी। - २३।

शोतार (Chautard) - फ़्रांसीसी जासूस, लन्दन में १८७१ की फ़्रांसीसी शाखा का सदस्य; बेनकाब होने पर शाखा से निष्कासित। - ३०।

शोल (Scholl) - फ़्रांसीसी मज़दूर, इंटरनेशनल की लियों शाखा के सदस्य, लन्दन में उत्प्रवासी; १८७२ में साम्राज्य की पुनःस्थापना की बोनापार्टपंथी योजनाओं का समर्थन किया। - २४५।

स्टिबेर (Stieber), विल्हेल्म (१८१८-१८८२) - प्रशियाई पुलिस अधिकारी, प्रशियाई राजनीतिक पुलिस का प्रधान (१८५०-१८६०), कोलोन में कम्युनिस्टों पर मुक़दमे के संगठनकर्त्ताओं में से एक; १८७०-१८७१ में सैनिक पुलिस का प्रधान। - १४५।

श्नैदर (Schneider), यूजन (१८०५-१८७५) - बड़े फ्रांसीसी उद्योगपति, क्रेज़ो में धातुकर्म कारखानों के मालिक। - १२६।

श्राम्म (Schramm), कार्ल अगस्त - जर्मन सामाजिक-जनवादी, सुधारवादी, «*Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*» के सम्पादकों में से एक; १९वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में पार्टी से पृथक हो गये। - २२६।

श्वीत्सहेबेल (Schwitzgubel), अदेमार (१८४४-१८९५) - स्विट्ज़रलैंड के नवक्राश, इंटरनेशनल के सदस्य, गुप्त अलियान्स और उर फ़ेडरेशन के एक निदेशक, अराजकतावादी; १८७३ में इंटरनेशनल से निकाल बाहर किये गये। - ५०।

श्वीट्ज़र (Schweitzer), जोहान बैप्टिस्ट (१८३३-१८७५) - जर्मनी में लासालवाद के प्रसिद्ध प्रतिपादक तथा व्याख्याकार; आम जर्मन मज़दूर संघ के अध्यक्ष (१८६७-१८७१); जर्मन मज़दूरों को पहले इंटरनेशनल में शामिल होने से रोका, सामाजिक-जनवादी मज़दूर पार्टी के खिलाफ़ संघर्ष चलाया; १८७२ में प्रशियाई अधिकारियों के साथ अपने संबंध के कारण संघ से निकाले गये। - २२८, २२९, २३८, २४३।

स

साकाज़ (Sacase), फ्रांसुआ (१८०८-१८८४) - फ्रांसीसी अधिकारी, राजतंत्रवादी; १८७१ से राष्ट्रीय सभा के सदस्य। - ४३, ६२।

सेंट-साइमन (Saint-Simon), आंरी (१७६०-१८२५) - फ्रांस के महान कल्पनावादी समाजवादी। - २०, २३८।

सेराइल्लिये (Serraillier), अगस्त (जन्म १८४०) - फ्रांसीसी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, इंटरनेशनल की जनरल कौंसिल के सदस्य (१८६९-१८७२); १८७० में बेल्जियम तथा १८७१-१८७२ में फ्रांस के लिए सह-सचिव; पेरिस कम्यून के सदस्य; मार्क्स के सहयोगी। - ३४।

सोलोन (Solon) (६३८-५५८ ई० पू०) - प्रसिद्ध एथिनियाई विधायक; जनसाधारण के दबाव में अभिजात वर्ग के विरुद्ध कई सुधार लागू करने के लिए विवश हुए। - २१४, २१५।

स्काल्दिन (येलेन्योव फ़योदोर पाव्लोविच का छद्मनाम) (१८२८-१९०२) - रूसी लेखक, पत्रकार, १९वीं शताब्दी के सातवें दशक में पूंजीवादी उदारतावाद के प्रतिनिधि; 'ओतेचेस्त्वेन्निये ज़पीस्की' ('पितृभूमि की टिप्पणियाँ') पत्रिका में लेख लिखते थे, 'दूर-दराज क्षेत्रों तथा राजधानी में' शीर्षक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक; बाद में प्रतिक्रियावादी। - २०२।

स्ट्रासबेर्ग (Stroußberg), बेथेल हेनरी (१८२३-१८८४) - जर्मनी की रेलों का एक बड़ा ठेकेदार; १८७३ में दिवालिया हो गया। - १४३।

स्तेफ़ानोनी (Stefanoni), लुईजी (१८४२-१९०५) - इतालवी लेखक, निम्नपूँजीवादी जनवादी, बकूनिनपंथी। - ५८।

ह

हक्स्टहाउजेन (Haxthausen), अगस्त (१७६२-१८६६) - प्रशियाई अफ़सर तथा लेखक, रूस में कृषि सम्बन्धों में समुदाय-व्यवस्था के अवशेषों से सम्बन्धित कृति के रचयिता। - १६६, २०६, २१६, २३५।

हर्ज़ेन, अलेक्सांद्र इवानोविच (१८१२-१८७०) - महान रूसी क्रान्तिकारी जनवादी, भौतिकवादी दार्शनिक, पत्रकार तथा लेखक; १८४७ में हर्ज़ेन विदेश चले गये, वहाँ उन्होंने "स्वतंत्र रूसी छापाघर" की स्थापना की तथा 'पोल्यान्या ज़वेज़्दा' (ध्रुवतारा) और 'कोलोकोल' (घंटा) पत्रों का प्रकाशन किया। - १५, १६६, २००, २०६-२०८, २१६।

हाइने (Heine), हेनरिक (१७६७-१८५६) - जर्मन क्रान्तिकारी महाकवि। - १८६।

हाट्सफ़ेल्ड (Hatzfeld), सोफ़िया, काउंटेस (१८०५-१८८१) - लासाल की मित्र तथा अनुयायी। - २२६-२२८।

हान्सेमान (Hansemann), डेविड (१७६०-१८६४) - जर्मनी के बड़े पूँजीपति और बैंकपति, राइनी उदारतावादी पूँजीपति वर्ग के नेता, मार्च-सितम्बर १८४८ की अवधि में प्रशा के वित्तमंत्री। - ११५।

हिन्स (Hins), एजेन (१८३६-१९२६) - बेल्जियन अध्यापक, प्रदोवादी, आगे चल कर बकूनिनपंथी, इंटरनेशनल की बेल्जियन शाखा के संस्थापकों में से एक। - २४३।

- हेगेल (Hegel), गेओर्ग विल्हेल्म फ्रेडरिक (१७७०-१८३१) - क्लासिकीय जर्मन दर्शन के महानतम प्रतिनिधि, वस्तुपरक भाववादी। - १५२, २५०।
- हेपनर (Hepner), अडोल्फ (१८४६-१९२३) - जर्मन सामाजिक-जनवादी, «*Volksstaat*» के सम्पादक, इंटरनेशनल की हेग कांग्रेस (१८७२) में प्रतिनिधि, आगे चलकर सामाजिक-अंधराष्ट्रवादी बन गये। - २४७।
- होफ़मान (Hoffmann), गोटेहेल्फ़ (उपनाम अगस्त कुचके) (१८४४-१९२४) - जर्मन कवि। - ११२।
- होल (Hole,) जेम्स - अंग्रेज़ पूंजीवादी पत्रकार, मज़दूरों की आवासीय अवस्थाओं के बारे में एक पुस्तक के लेखक। - ११२।
- होहेनज़ालर्न (Hohenzollern) - ब्राण्डनबुर्ग राजाओं (१४१५-१७०१), प्रशा के राजाओं (१७०१-१९१८) और जर्मन सम्राटों (१८७१-१९१८) का राजवंश। - २२६।
- ह्यूबर (Huber), विक्टर (१८००-१८६६) - जर्मन पत्रकार, साहित्य के इतिहासकार, अनदारपंथी। - ११२, १२४, १२५।

पाठकों से

प्रगति प्रकाशन इस पुस्तक के अनुवाद और डिजाइन के बारे में आपके विचार जानकर अनुगृहीत होगा। आपके अन्य सुझाव प्राप्त करके भी हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। कृपया हमें इस पते पर लिखिये :

प्रगति प्रकाशन,

२१, जूबोव्स्की बुलवार,

मास्को, सोवियत संघ।

साहित्यिक और पौराणिक पात्रों की सूची

च

चचा ब्रेसिंग—रायटर की प्रहसनप्रधान कथाओं का मुख्य पात्र।—१६३।

प

पोजा, मार्क्विस्—शिलर की करुणाप्रधान रचना 'दान कार्लोस' का पात्र; एक उदात्त तथा स्वतंत्र चिन्तक राजदरबारी की छवि।—२२७।

क

फ़िलिप द्वितीय—शिलर की करुणाप्रधान रचना 'दान कार्लोस' का पात्र।—२२७।

म

मरियम—बाइबल के अनुसार ईसामसीह की जननी।—१८७।

मोरोस—शिलर की कविता का पात्र।—१८५।

ल

लेवियाथन (बाइबल)—राक्षस।—३६।

ह

हेमलेट—शेक्सपियर की त्रासदी का पात्र।—१८५।